

भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्य और कार्य - पद्धति



अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र और
हर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने वाला



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

अनुक्रमणिका

अध्याय सं.	विषय-वस्तु	पृष्ठ सं.
1	वैश्विक स्तर पर और भारत में केंद्रीय बैंकिंग का विकास	1
2	रिज़र्व बैंक के कार्यों के लिए कानूनी संरचना	7
3	मौद्रिक नीति ढांचा	17
4	बाजार परिचालन	29
5	वित्तीय स्थिरता	47
6	भारतीय वित्तीय प्रणाली का अवलोकन	55
7	वाणिज्यिक बैंकों का विनियमन	59
8	वाणिज्यिक बैंकों का पर्यवेक्षण	81
9	सहकारी बैंकों का विनियमन और पर्यवेक्षण	99
10	भारत में एनबीएफसी का विनियमन और पर्यवेक्षण	111
11	भारतीय रिज़र्व बैंक में प्रवर्तन	133
12	वित्तीय बाजारों का विकास और विनियमन	139
13	भुगतान और निपटान प्रणाली	163
14	मुदा प्रबंधन	179
15	बैंकों और सरकारों के बैंकर	195
16	आंतरिक ऋण प्रबंधन	207
17	आरबीआई के तुलन-पत्र को समझना	215
18	विदेशी मुद्रा प्रबंधन	233
19	विदेशी मुद्रा भंडार	245
20	उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण	253
21	वित्तीय समावेशन और विकास	263
22	संस्थाओं का विकास	279
23	अनुसंधान, सर्वेक्षण और डेटा प्रसार	283
24	फनटेक और भारतीय रिज़र्व बैंक	295
25	अंतरराष्ट्रीय संबंध	305

आमुख

"आरबीआई के कार्य और कार्यप्रणाली" पर 2024 संस्करण की पुस्तिका प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है, जो 2020 में प्रकाशित अंतिम संस्करण के चार साल बाद जारी जा रहा है। पहला संस्करण 2010 में प्रकाशित किया गया, जिसका उद्देश्य आम जनता में भारतीय रिज़र्व बैंक के विविध कार्यों के बारे में जागरूकता फैलाना था जिममें मुद्रा, वित्तीय बाजार और भुगतान प्रणालियों का प्रबंधन, वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, वित्तीय क्षेत्र का नियमन और पर्यवेक्षण करना और मौद्रिक नीति का संचालन आदि शामिल किया गया। इसके बाद के संस्करणों में वित्तीय क्षेत्र में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए विकासों और बैंक की इन विकासों के प्रति प्रतिक्रिया के आधार पर सामग्री को संर्वधित और अद्यतित किया गया है।

कोविड महामारी का देश के वित्तीय क्षेत्र और अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक विघटनकारी प्रभाव पड़ा। आर्थिक पुनः सुधार के लिए जो उपाय किए गए, उनमें प्रगतिशील मौद्रिक नीति उपाय शामिल थे, जिनमें अपरंपरागत उपाय जैसे लंबी अवधि की रिवर्स रेपो ऑपरेशंस (एलटीआरओ), लक्षित एलटीआरओ, सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम (जीएसएपी) और विशेष ओपन मार्केट ऑपरेशंस (ओएमओ), विशेष रिफाइनेंस सुविधाओं / क्रेडिट लाइनों का उद्घाटन आदि शामिल किए गए। पिछले चार वर्षों में वित्तीय परिदृश्य में डिजिटल परिवर्तन हुआ। डिजिटल भुगतान प्रणाली का विस्तार हुआ और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) का उपयोग बेतहाशा बढ़ा। भारतीय रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) को एक सहायक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया ताकि वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने में सहायता मिल सके। आरबीआईएच द्वारा किए गए एक प्रमुख परियोजना यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई) का उद्देश्य व्यक्तियों और व्यवसायों को बिना किसी रुकावट के कर्ज मुहैया कराना है। इस अवधि में, नियामक और पर्यवेक्षी मानदंड भी सुदृढ़ किए गए, और साइबर सुरक्षा तथा जोखिम प्रबंधन के लिए कड़े दिशा-निर्देश लागू किए गए। हाल ही में केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) की शुरुआत और रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया। स्थायी वित्त और जलवायु पहल भी प्रमुख हो गई हैं। इसलिए, यह महसूस किया गया कि पिछले संस्करण के प्रकाशन के बाद बैंक की यात्रा में हुए वर्तमान और अन्य प्रमुख गतिविधियों को शामिल करने के लिए एक नया संस्करण लाना आवश्यक है।

यह वर्तमान संस्करण विशेष है क्योंकि इसे भारतीय रिज़र्व बैंक की 90वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रकाशित किया जा रहा है। हमें आशा है कि यह अद्यतन संस्करण रिज़र्व बैंक को समझने में सहायक होगा और देश के आर्थिक विकास में बैंक की महत्वपूर्ण और लगातार बदलती भूमिका के साथ-साथ वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में इसकी भूमिका पर स्पष्टता प्रदान करेगा। हमें विश्वास है कि इस प्रकाशन का उपयोग और प्रासंगिकता केवल वित्त और अर्थशास्त्र के छात्रों तक ही सीमित नहीं होगी, बल्कि यह एक व्यापक पाठक वर्ग के ज्ञान को समृद्ध करेगा।

हम आरबीएससी की टीम के योगदान की सराहना करते हैं, विशेष रूप से संकाय सदस्यों और विभिन्न केंद्रीय कार्यालय विभागों के उनके अथक प्रयासों के लिए जिन्होंने इस सामग्री को तैयार करने और अद्यतन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम उप गवर्नर, आरबीआई, श्री स्वामीनाथन जे का भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने 4 नवंबर 2024 को इस नवीनतम संस्करण का उद्घाटन किया।

इसके अतिरिक्त, हम राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय और चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जिन्होंने हिंदी में सामग्री के अनुवाद में सहायता प्रदान की, ताकि हम इस प्रकाशन को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित कर सकें।

यह प्रकाशन दोनों हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है।

हमें आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा रहेगी जिससे हमें भविष्य के संस्करणों को संवर्धित करने और विषय वस्तु को प्रासंगिक बनाने में उपयोगी होगी, कृपया इन्हें principalrbsc@rbi.org.in पते भेजें।

माला सिन्हा
प्रधानाचार्य

संक्षिप्ताक्षरों की सूची

एए	लेखा समेकक
एबीपीएस	आधार ब्रिज भुगतान प्रणाली
एसीबी	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति
एसीडी	कृषि ऋण विभाग
एडी	अपर निदेशक
एडी / एपी	प्राधिकृत व्यापारी/ प्राधिकृत व्यक्ति
एडी बिल्ली	प्राधिकृत व्यापारी - श्रेणी (I/II/III)
एडीएफ	एसेट डेवलपमेंट फंड
आईपीएस	आधार समर्थित भुगतान प्रणाली
एएफए	अतिरिक्त कारक अधिप्रमाणन
एएफएस	बिक्री के लिए उपलब्ध
एजीएल	सकल अंतराल सीमा
एजीआर	वैकल्पिक शिकायत निवारण
एआई	कृत्रिम बुद्धि
एआईएफ	वैकल्पिक निवेश निधि
एआईएफआई	अखिल भारतीय वित्तीय संस्था
एआई-एमएल	कृत्रिम बुद्धि और मशीन अधिगम
एएमएल	धन-शोधन निवारण
एपीबी	आधार भुगतान सेतु
एआरसीएच	ऑटोरिग्रेसिव सशर्त हेटेरोस्केडास्टिसिटी
एआरसीएस	आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां
एसआईएसओ	स्वचालित स्वीप-इन और स्वीप-आउट
एटीबी	नीलामी ट्रेजरी बिल
बी2बी/ बी2सी	व्यवसाय से व्यवसाय / व्यवसाय से ग्राहक
बीबीपीसीयू	भारत बिल भुगतान केंद्रीय इकाई
बीबीपीओयू	भारत बिल भुगतान परिचालन इकाई
बीबीपीएस	भारत बिल भुगतान प्रणाली
बीसी	कारोबार प्रतिनिधि
बीसीबीएस	बैंकिंग पर्यवेक्षण बासेल समिति
बीसीएसबीआई	भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड
बीएफएस	वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड
बीएफ	कारोबार सुलभकर्ता
बीएचआईएम/ भीम	पैसे के लिए भारत इंटरफेस
बीआईएस	अंतरराष्ट्रीय निपटान के लिए बैंक
बीकेएसपीआई	बैंकिंग सेवा मूल्य सूचकांक
बीएलबीसी	ब्लॉक स्तरीय बैंकर्स समिति

बीएलएस	बैंक ऋण सर्वेक्षण
बीओपी	भुगतान-शेष
बीपीएसएस	भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड
बीआर अधिनियम	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949
बीएसपीआई	व्यापार सेवा मूल्य सूचकांक
बीएसआर	मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी
सीएएलसीएस	पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, चलनिधि, अनुपालन, प्रणाली एवं नियंत्रण
सीएएमईएलएस/ कैमल्स	पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, प्रबंध, अर्जन, चलनिधि, प्रणाली एवं नियंत्रण
सीबीडीसी/आर/डब्ल्यू	सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा सीबीडीसी - खुदरा/थोक
सीबीएस	कोर बैंकिंग प्रणाली
सीसीआईआर	व्यापक क्रेडिट सूचना रिपोजिटरी
सीसीपी	केंद्रीय प्रतिपक्षकार
सीसीएस	करेंसी चेस्ट
सीसीएस	उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण
सीडी	जमा प्रमाणपत्र / ऋण-जमा
सीडीईएस	मुद्रा वितरण और विनिमय योजना
सीडीआईएस	समन्वित प्रत्यक्ष निवेश सर्वेक्षण
सीडी	ऋण चूक स्वेप
सीईपीसी/ सीईपीडी	उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण कक्ष/ उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग
सीईटी 1	कॉमन इक्विटी टियर 1 पूंजी
सीएफ	आकस्मिकता निधि
सीएफएल	वित्तीय साक्षरता केंद्र
सीएफपीबी	उपभोक्ता वित्तीय संरक्षण ब्यूरो
सीएफआर	केंद्रीय फ्रॉड रजिस्ट्री
सीएफटी	आतंकवाद वित्तपोषण का मुकाबला करना
सीजीडी	डेरिवेटिव पर व्यापक दिशानिर्देश
सीजीआरए	मुद्रा एवं स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता
सीआईसी	संचलन में मुद्रा / कोर निवेश कंपनी / क्रेडिट सूचना कंपनियां
सीआईसी (आर) अधिनियम	प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005
सीआईएमएस	केंद्रीकृत सूचना प्रबंध प्रणाली
सीआईएन	चालान पहचान संख्या
सीआईआर	क्रेडिट सूचना रिपोर्ट
सीआईएस	क्रेडिट संस्थाएं
सीआईएसबीआई	बैंकिंग अवसंरचना संबंधी केंद्रीय सूचना प्रणाली
सीआईटी	मार्गस्थ नकदी/ रोकड़
सीएलएस	सतत सहबद्ध निपटान

सीएमबी	नकद प्रबंधन विधेयक
सीएमएस	शिकायत प्रबंध प्रणाली
सीएनपी	कार्ड मौजूद नहीं है
सीओए / सीओआर	प्राधिकरण प्रमाण पत्र / पंजीकरण प्रमाण पत्र
सीपी	कार्ड प्रेजेंट/ वाणिज्यिक पत्र
सीपीआई	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सीपीआईएन	सामान्य पोर्टल पहचान संख्या
सीपीआईएस	समन्वित पोर्टफोलियो निवेश सर्वेक्षण
सीपीएसएस	भुगतान और निपटान प्रणाली पर समिति
सीआरए	क्रेडिट रेटिंग एजेंसी
सीआरएआर	जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी अनुपात
सीआरसीएस	ऋण की स्थिति का सर्वेक्षण
सीआरसीएस	सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार
सीआरडीसी	मुद्रा अनुसंधान और विकास केंद्र
सीआरआईएलसी	बड़े ऋणों पर सूचना की केंद्रीय रिपोजिटारी
सीआरओएमएस	क्लियरकॉर्प रेपो ऑर्डर मिलान प्रणाली
सीआरपीसी	केंद्रीयकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र
सीआरआर	आरक्षित नकदी निधि अनुपात
सीएसडी	ग्राहक सेवा विभाग/ केंद्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार
सीएसएफ	समेकित ऋण-शोधन निधि
सीएसआईटीई/ सीसाइट	साइबर सुरक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी परीक्षा
सीटीएस	चेक ट्रंक्शन प्रणाली
सीवीपीएस	मुद्रा सत्यापन और प्रसंस्करण प्रणाली
सीडब्ल्यूबीएन	बेलनाकार वॉटरमार्कयुक्त बैंक नोट
डीबीआईई	भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी डेटाबेस
डीसीसी	जिला परामर्शदात्री समितियाँ
डीसीसीबी	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक
डीसीसी	जिला परामर्शदात्री समितियाँ
डीईए	जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता
डीएफएचआई	डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया लिमिटेड
डीजीआई	डेटा अंतराल संबंधी पहलें
डीएलए	डिजिटल ऋण ऐप
डीएलआरसी	जिला स्तरीय समीक्षा समिति
डीपीआई	डिजिटल भुगतान सूचकांक/ डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना
डीआरजी	विकास अनुसंधान समूह
डीएसएल	डेटा साइंस लैब
डीएसआर	कर्ज चुकौती अनुपात
डीवीपी	सुपुर्दगी-बनाम- भुगतान

ईसीबी	यूरोपीय सेंट्रल बैंक
ईसीबी	बाह्य वाणिज्यिक उधार
ईसीएल	प्रत्याशित ऋण हानि
ईसीएस	इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा
ईडीपीएमएस	निर्यात डेटा प्रसंस्करण और निगरानी प्रणाली
ईईएफसी	विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता
ईएमआई	समीकृत मासिक किश्तें
ईटीसीडी	एक्सचेंज में खरीदे-बेचे गए करेंसी डेरिवेटिव
ईटीएफ	एक्सचेंज में खरीदे-बेचे गए फंड
ईटीपी	इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म
ईयू	यूरोपीय संघ
ईवी	आर्थिक मूल्य
ईडब्ल्यूजी/ ईडब्ल्यूआई/	पूर्व चेतावनी समूह/ पूर्व चेतावनी संकेतक/ पूर्व चेतावनी संकेत
ईडब्ल्यूएस	
एक्जिम	भारतीय निर्यात आयात बैंक
एफएएमई	वित्तीय जागरूकता संदेश
एफएआर	पूरी तरह से सुलभ मार्ग
एफएटीएफ	वित्तीय कार्रवाई कार्यबल
एफएटीएस	विदेशी संबद्ध व्यापार सांख्यिकी
एफबीए	वित्तीय बेंचमार्क प्रशासक
एफबीआईएल	फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लिमिटेड
एफसी	वित्तीय प्रतिबद्धता
एफसीए	विदेशी मुद्रा आस्तिyaं
एफसीसीबी/ एफसीईबी	विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड/ विदेशी मुद्रा विनिमेय बांड
एफसीएनआर/ एफसीएनआर	विदेशी मुद्रा अनिवासी/ विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक)
(बी) खाता	
एफसीआरए	विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम
एफसीएस	भारतीय उद्योग सर्वेक्षण में विदेशी सहयोग
एफसीएस-ओआईएस	विदेशी मुद्रा में निपटान किए गए एकदिवसीय सूचकांकित स्वैप
एफसीवीए	विदेशी संविदा मूल्यांकन खाते
एफडीआई	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश / फेडरल जमा बीमा
फेरा/ फेमा	विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम / विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999
एफईटीईआरएस	विदेशी मुद्रा कारोबार-इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग प्रणाली
एफएफसीआर	निःशुल्क पूर्ण क्रेडिट रिपोर्ट
एफएफएमसी	संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक
एफजी	फार्वर्ड मार्गदर्शन
एफआई	वित्तीय समावेशन/ वित्तीय संस्था
एफआई	विदेशी निवेश

एफआईसीएनएस	जाली भारतीय मुद्रा नोट
एफआईएफ/ एफआई-इंडेक्स	वित्तीय समावेशन निधि/ वित्तीय समावेशन सूचकांक
एफआईपी	वित्तीय समावेशन योजना
फिम्डा/ एफआईएमएमडीए	भारतीय नियत आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्नी संघ
एफआईआरआरईए	वित्तीय संस्थाओं में सुधार, बहाली और प्रवर्तन अधिनियम
एफआईएसआईएम	अप्रत्यक्ष रूप से मापी गई वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं
एफआईटी	लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण
एफएलए/ फ्लेयर	विदेशी देयताएं और आस्तियां/ विदेशी देयताओं और आस्तियों संबंधी सूचना रिपोर्टिंग
एफएलसी/ एफएलडब्ल्यू	वित्तीय साक्षरता केंद्र/ वित्तीय साक्षरता सप्ताह
एफएलडीजी	प्रथम चूक हानि गारंटी
एफएमसी/ एफएमआई	वित्तीय बाज़ार समिति / वित्तीय बाज़ार अवसंरचना
एफपीसी	उचित व्यवहार संहिता
एफपीआई	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक/विदेशी पोर्टफोलियो निवेश
एफपीएस	त्वरित भुगतान प्रणाली
एफआर अधिनियम	फेक्टर विनियमन अधिनियम, 2011
एफआरए	वायदा दर समझौता
एफआरबीएम	राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध
एफआरबी/एफआरएसबी	अस्थायी दर बॉण्ड/ अस्थायी दर बचत बॉण्ड
एफआरआरआर	नियत दर रिवर्स रेपो
एफएसबी	वित्तीय स्थिरता बोर्ड
एफएसडीसी/ एफएसडीसी-एससी	वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद / वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की उप-समिति
एफएसआई/ एफएसयू	वित्तीय स्थिरता संस्थान / वित्तीय स्थिरता इकाई
एफ-टीआरएसी	वित्तीय बाज़ार व्यापार रिपोर्टिंग और पुष्टिकरण प्लेटफॉर्म
एफवीटीपीएल	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य
जीएएच	गिल्ट खाताधारक
जीएआरसीएच	सामान्यीकृत ऑटोरिग्रेसिव सशर्त हेटेरोस्केडास्टिसिटी
जीसीसी	जनरल क्रेडिट कार्ड
जीडीएएल	ब्योरेवार डेटा एक्सेस लैब
जीडीडीएस	सामान्य डेटा प्रसार प्रणाली
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीएफसी/ जीएफएसआर	वैश्विक वित्तीय संकट / वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
जीआरएफ	गारंटी मोचन निधि
जीएस अधिनियम	सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006
जी-एसएपी	सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम
जी-सेक	सरकारी प्रतिभूति

जीएसटी/ जीएसटीआईएन	माल और सेवा कर/ माल और सेवा कर पहचान संख्या
एचएफसी	आवास वित्त कंपनी
एचएफटी	ट्रेडिंग के लिए धारित
एचकेएमए	हांगकांग मौद्रिक प्राधिकरण
एचएलसी	उच्च स्तरीय समिति
एचपीआई	घर की कीमत सूचकांक
एचटीएम	परिपक्वता तक धारित
आईबीबीआई	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
आईबीसी	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता
आईबीएस	अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी
आईबीयू	आईएफएससी बैंकिंग इकाई
आईसीएपी	आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया
आईसीसी	निवेश और क्रेडिट कंपनियां
आईसीसीडब्ल्यू	अंतर-परिचालनीय कार्ड-रहित नकदी आहरण
आइसगेट	भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डेटा आदान-प्रदान गेटवे
आईसीएमटीएस	एकीकृत अनुपालन प्रबंध और ट्रेकिंग प्रणाली
आईडीबीआई	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
आईडीएफ	इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड
आईडीजी	अंतर-विभागीय समूह
आईडीपीएमएस	आयात डेटा प्रसंस्करण और निगरानी प्रणाली
आईई	भारतीय संस्था
आईईएसएच	परिवारों का मुद्रास्फीति प्रत्याशा संबंधी सर्वेक्षण
आईएफसी	अंतरराष्ट्रीय वित्त केंद्र
आईएफएमआईएस	एकीकृत वित्तीय प्रबंध और सूचना प्रणाली
आईएफआर	निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि
आईएफएससी/ आईएफएससीए	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र / अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण
आईएफएससी	भारतीय वित्तीय प्रणाली कूट
आईजीबी	भारतीय सरकारी बॉण्ड
आईआईपी	अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति
आईएलओ	अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन
आईएमई	अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यम
आईएमएफ	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
आईएमपीएस	तत्काल भुगतान प्रणाली
आईएनवीआईटीएस	अवसंरचना निवेश न्यास
आईओ	आंतरिक लोकपाल
आईओआरएस	इंटरऑपरेबल विनियामकी सैंडबॉक्स
आईओएस	औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण
आईओएससीओ	अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन

आइपीए	जारीकर्ता और अदाकर्ता एजेंट
आईआरए	निवेश पुनर्मूल्यांकन खाता
आईआरएसीपी	आय निर्धारण और संपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण
आईआरडी	ब्याज दर डेरिवेटिव
आईआरएफ	वित्तीय संगुट की निगरानी संबंधी अंतर-विनियामकीय मंच
आईआरओ / आईआरबीबी / आईआरएस	ब्याज दर ऑप्शन/ बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम/ ब्याज दर स्वैप
आईआरटीजी	अंतर-विनियामकीय तकनीकी समूह
आईएस	ब्याज सबवेंशन
आईटीआरएस	अंतरराष्ट्रीय लेनदेन रिपोर्टिंग प्रणाली
जेएम	जन धन योजना, आधार और मोबाइल
जेएलजी	संयुक्त देयता समूह
केसीसी	किसान क्रेडिट कार्ड
केएफएस	मुख्य तथ्य कथन
केवीआईसी	खादी और ग्रामोद्योग आयोग
केवाईसी	अपने ग्राहक को जानें
एलएबीएस	स्थानीय क्षेत्र के बैंक
एलएएफ	चलनिधि समाशोधन सुविधा
एलसीआर	चलनिधि कवरेज अनुपात
एलईआई	कानूनी संस्था अभिज्ञापक
एलईआरएमएस	उदारीकृत विनिमय दर प्रबंध प्रणाली
एलएलपी	सीमित देयता भागीदारी
एलआरएस	उदारीकृत विप्रेषण योजना
एलएसपी	ऋण सेवा प्रदाता
एलटीआरओ/ एलटीआरआरओ	दीर्घावधि रेपो परिचालन/ दीर्घावधि रिवर्स रेपो परिचालन
एलटीवी	मूल्य की तुलना में ऋण
एलवीपीएस	बड़ी राशि की भुगतान प्रणाली
एमएएनआई	मोबाइल समर्थित नोट अभिज्ञापक
एमबीपी	बाज़ार उधार कार्यक्रम
एमसीसी	व्यापारी श्रेणी कोड
एमसीजीडीएम	नकदी और ऋण प्रबंधन पर निगरानी समूह
एमसीवी	मोबाइल कॉइन वैन
एमडीए	सूक्ष्म डेटा विश्लेषण
एमएफआई	सूक्ष्म वित्त संस्थाएं
एमजीसी	बंधक गारंटी कंपनियां
एमआईबीओआर	मुंबई अंतर-बैंक एकमुश्त दर
माइकर/ एमआईसीआर	चुंबकीय स्याही चिह्न पहचान

एमआईएसएस	संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना
एमएमआईडी	मोबाइल धनराशि अभिज्ञापक
एमएमआईएफओ	संशोधित मुंबई अंतर-बैंक फॉरवर्ड एकमुश्त दर
एमएमओ	मुद्रा बाज़ार परिचालन
एमएनबीसी	विविध गैर-बैंकिंग कंपनियां
एमएनएसबी	बहुपक्षीय निवल निपटान बैच
एमपीसी/ एमपीआर	मौद्रिक नीति समिति/ मौद्रिक नीति रिपोर्ट
एमएससीएस	बहु-राज्य सहकारी समिति
एमएसडी और ई	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
एमएसई/ एमएसएमई	सूक्ष्म और लघु उद्यम/ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
एमएसएफ	सीमांत स्थायी सुविधा
एमएसएस	बाज़ार स्थिरीकरण योजना
एमटीडीएस/ एमटीएफ	मध्यम अवधि कर्ज प्रबंध काग्रनीति/ मध्यम अवधि ढांचा
एमटीएम	बाज़ार भाव पर दर्शाना
एनएसीएच	राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह
एनआईओ	गैर-प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र कार्यालय
एनएमसीएबीएस/ नामकैब्स	एमएसएमई क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए बैंकों की क्षमता निर्माण संबंधी राष्ट्रीय मिशन
एनबीबीएल	एनपीसीआई भारत बिलपे लिमिटेड
एनबीएफसी	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एनबीएफसी-आईसीसी	एनबीएफसी-निवेश और क्रेडिट कंपनी
एनबीएफसी-आईएफसी	एनबीएफसी-अवसंरचना वित्त कंपनी
एनबीएफसी-पी2पी	समकक्षीय उधार
एनबीएफआई	गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता / गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थ
एनसीएस	राष्ट्रीय सक्षम प्राधिकारी
एनसीडी	गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर
एनसीएफई	राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र
एनसीएमसी	नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड
एनडी	नामिती निदेशक
एनडीडीसी/ एनडीएफ	नॉन-डिलिवरेबल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट/ नॉन-डिलिवरेबल फॉरवर्ड
एनडीएस	तयशुदा लेनदेन प्रणाली
एनडीएस-ओएम	तयशुदा लेनदेन प्रणाली - ऑर्डर मिलान
एनडीएस-कॉल	तयशुदा लेनदेन प्रणाली-कॉल
एनडीएसआई-एनबीएफसी	प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार न करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
एनडीटीएल	निवल मांग और समय देयताएं
एनईएफटी/एनईटीसी	राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण/ राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक पथकर संग्रह
एनएफएस	राष्ट्रीय वित्तीय स्विच

एनजीएनएफ	गैर-सरकारी गैर-वित्तीय
एनएचबी अधिनियम	राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987
एनआई अधिनियम	परक्राम्य लिखत अधिनियम
एनआईसी	संचलन में नोट
एनआईआई	निवल ब्याज आय
एनओएफएचसी	गैर-परिचालनात्मक वित्तीय होल्डिंग कंपनी
एनओओपीएल	निवल ओवरनाइट ओपन एक्सचेंज पोजिशन लिमिट
एनपीए	अनर्जक आस्तियां
एनपीसीआई	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
एनआरडी-सीएसआर	अनिवासी जमाराशियां - समेकित एकल विवरणी
एनआरई/एनआरआई/एनआरओ	अनिवासी विदेशी/ अनिवासी भारतीय/ अनिवासी सामान्य
एनएसडीएल	नैशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड
एनएसएफई/एनएसएफआई	राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षण कार्यनीति/ राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन कार्यनीति
एनएसएफआर	निवल स्थिर निधीन अनुपात
एनएसओ	राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय
एनटीआरपी	गैर-कर रसीद पोर्टल संग्रह
एनयूसीएफडीसी	राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड
ओसीआई	भारत के विदेशी नागरिक
ओडीआई	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
ओडीआर	ऑनलाइन विवाद समाधान
ओईसीडी	आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
ओआई	विदेशी निवेश
ओएलटीएस/ ओल्टास	ऑनलाइन कर लेखांकन प्रणाली
ओएमएफपीआई	संगठित बाज़ार खाद्य मूल्य सूचकांक
ओएमओ	खुले बाज़ार के परिचालन
ओपीआई	विदेशी पोर्टफोलियो निवेश
ओएसएमओएस	परोक्ष निगरानी और चौकसी प्रणाली
ओटी	ऑपरेशन ट्विस्ट
ओटीसी	काउंटर पर
ओटीपी	एकबारगी पासवर्ड
पी2एम/ पी2पी	पीयर-टू-मर्चेन्ट / पीयर-टू-पीयर
पीए	भुगतान एग्रीगेटर
पीएसीएस	प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी
पीएएन	स्थायी खाता संख्या
पीबी	भुगतान बैंक
पीबीसी	प्रमुख व्यवसाय मानदंड
पीसीए	त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई
पीसीएआरडीबी	प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

पीसीएफ	त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचा
पीसीई	आंशिक क्रेडिट वृद्धि
पीडी	प्राथमिक व्यापारी
पीडीओ	लोक ऋण कार्यालय
पीएफएमआई	वित्तीय बाज़ार अवसंरचना के सिद्धांत
पीएफएमएस	सार्वजनिक निधि प्रबंध प्रणाली
पीजी	भुगतान गेटवे
पीआईडीएफ	भुगतान अवसंरचना विकास निधि
पीएमजेडीवाई	प्रधानमंत्री जन धन योजना
पीएमएल	धन शोधन निवारण
पीओएस	बिक्री केंद्र/ सेवा केंद्र
पीपीआई	प्री-पेड लिखतें
पीपीपी	सार्वजनिक निजी भागीदारी
पीआरआई	त्वरित चुकौती प्रोत्साहन
पीएसएल/ पीएसएलसी	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण/ प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र
पीएसपी	भुगतान प्रणाली प्रतिभागी
पीएसएस अधिनियम	संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007
पीटीपीएफसी	निर्बाध क्रेडिट के लिए पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म
क्यूसीवीएम	त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड-आधारित सिक्का वेंडिंग मशीन
क्यूआर कोड	त्वरित प्रतिक्रिया कोड
आरबीए	जोखिम आधारित दृष्टिकोण
आरबी-आईओएस	रिज़र्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना, 2021
आरबीआई-आरडी	भारतीय रिज़र्व बैंक-रिटेल डायरेक्ट
आरबीएस	जोखिम आधारित पर्यवेक्षण
आरसीए	मूल कारण विश्लेषण
आरसीबी	ग्रामीण सहकारी बैंक
आरसीएस	सहकारी समिति रजिस्ट्रार
आरडीजी खाता	रिटेल डायरेक्ट गिल्ट खाता
आरईआईटी	रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट
रेपो	पुनः क्रय करार
आरईएस	विनियमित संस्थाएं
आरएफसी/ आरएफसी (डी)	निवासी विदेशी मुद्रा खाता / निवासी विदेशी मुद्रा (घरेलू) खाता
आरएफआईडी	रेडियो आवृत्ति अभिज्ञापक
आरआईडीएफ	ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि
आरएमसीबी	बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसीबी)
आरएनबीसी	अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियां
आरओसी	कंपनी रजिस्ट्रार
आरआरबी	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरएस	विनियामकीय सैंडबॉक्स

आरटीजीएस	तत्काल सकल भुगतान
आरटीआई अधिनियम	सूचना का अधिकार अधिनियम
आरटीपी	रिज़र्व की मात्रा की स्थिति
एसएएआरसी/ सार्क	दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ
एसएसी	स्थायी परामर्शदात्री समिति
एसएएफ/ सैफ	पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा
एसएकेएआर/ साकार	केवाईसी/ एएमएल जोखिमों का पर्यवेक्षी मूल्यांकन
सरफेसी अधिनियम	वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्चना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002
एसबीएन	विनिर्दिष्ट बैंक नोट
एसबीआर	स्केल-आधारित विनियमन
एसबीएस	श्रेडिंग एवं ब्रिकेटिंग प्रणाली
एससीएआरएडीबी	राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एससीबी	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
एससीडी	छोटे सिक्कों का डिपो
एससी-एनईसी	राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की उप समिति
एसडीडीएस	विशेष डेटा प्रसारण मानक
एसडीएफ/ एसडीआर	विशेष आहरण सुविधा/ विशेष आहरण अधिकार
एसडीएफ	स्थायी जमा सुविधा
एसडीएमएक्स	सांख्यिकीय डेटा और मेटाडेटा एक्सचेंज
एसईएसीईएन	दक्षिण पूर्व एशियाई केंद्रीय बैंक
एसईएस	पर्यवेक्षित संस्थाएं
एसएफबी	लघु वित्त बैंक
एसएफडीबी	सार्कफाइनेंस डेटाबेस
एसएफजी	सतत वित्त समूह
एसजीबी	सरकारी स्वर्ण बॉण्ड
एसजीआरबी	सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड
एसजीएस	राज्य सरकार की प्रतिभूति
एसएचजी	स्वयं सहायता समूह
एसआईपीएस	प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली
एसआईएसएस	भारतीय स्टार्ट-अप क्षेत्र पर सर्वेक्षण
एसएलबीसी/एसएलसीसी	राज्य स्तरीय बैंकर समितियां/ राज्य स्तरीय समन्वय समितियां
एसएलएफ-एमएफ	म्यूचुअल फंड के लिए विशेष चलनिधि सुविधा
एसएलआर	सांविधिक चलनिधि अनुपात
एसएलटीआरओ	विशेष दीर्घकालिक रेपो परिचालन
एसएमएस	लघु संदेश सेवा
एसएनए- एसपीएआरएसएच/ स्पर्श	एकल नोडल एजेंसी - समयोचित प्रणाली अकीकृत शीघ्र हस्तांतरण
एसएनआरआर खाता	विशेष अनिवासी रुपया खाता

एसओसी
एसपीएआरसी/ स्पार्क
एसपीएआरएसएच/ स्पर्श
एसपीडी
एसपीएफ़
एसपीएमसीआईएल

सहयोग का वक्तव्य
जोखिम और पूंजी के आकलन संबंधी पर्यवेक्षी कार्यक्रम
पेंशन प्रशासन प्रणाली (रक्षा)
स्टैंडअलोन प्राथमिक व्यापारी
व्यावसायिक पूर्वानुमानकर्ताओं का सर्वेक्षण
सिक्क्यूरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.

एसआरओ
एसआरपीएचआई
एसआरवीए
एसएसएस
एसटीसीबी
एसटीसीआई
एसटीपी
एसटीआरआईपीएस/ स्ट्रिप्स

स्व-विनियामक संगठन
व्यक्तियों की खुदरा भुगतान प्रवृत्ति पर सर्वेक्षण
विशेष रुपया वोस्ट्रो खाता
प्रतिभूति निपटान प्रणाली
राज्य सहकारी बैंक
भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम
स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग
प्रतिभूतियों के पंजीकृत ब्याज और मूलधन की अलग-अलग
ट्रेडिंग

टैफकब/ टीएफसीयूबी
टी-बिल
टीजीएफआईएफएल
टीएलटीआरओ
टीआर
ट्रेड्स/ टीआरडीआईएस
टीआरआईपीएस
टीएसपी
यूएपी
यूएपीए
यूबीबी
यूसीबी
यूडीआई/ उदय
यूएलआई
यूएमपीटी
यूपीआई
यूएसएसडी
यूटीएलबीसी
वीआरआर
वीआरआर
डब्ल्यूएसीआर
डब्ल्यूजीएमएस
डब्ल्यूएलए/ डब्ल्यूएलएओ
डब्ल्यूएमए

शहरी सहकारी बैंकों के लिए कार्यबल
खजाना बिल
वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता तकनीकी समूह
लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन
ट्रेड रिपॉजिटरी
व्यापारिक प्राप्य-राशि भुनाई प्रणाली
त्रिपक्षीय रेपो डीलिंग प्रणाली
दूरसंचार सेवा प्रदाता
उद्यम सहायता प्लेटफॉर्म
विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम
एकसमान तुलन बही
शहरी सहकारी बैंक
उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना
एकीकृत ऋण इंटरफ़ेस
अपरंपरागत मौद्रिक नीति उपकरण
एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस
असंरचित पूरक सेवा डेटा
संघशासित क्षेत्र स्तरीय बैंकर समिति
परिवर्तनीय रिवर्स रेपो
स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग
भारित औसत मांग दर
मुद्रा आपूर्ति संबंधी कार्य-दल
व्हाइट लेबल एटीएम/ व्हाइट लेबल एटीएम परिचालक
अर्थोपाय अग्रिम

डब्ल्यूपीआई
डब्ल्यूएसए
डब्ल्यूएसएस
डब्ल्यूटीडी
एक्सबीआरएल
जेडएलबी

थोक मूल्य सूचकांक
स्थिति का साप्ताहिक विवरण
साप्ताहिक सांख्यिकी परिशिष्ट/ अनुपूरक
पूर्णकालिक निदेशक
एक्सटेंसिबल बिज़नेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज
शून्य-निम्नतर बॉण्ड

अध्याय 1: वैश्विक स्तर पर और भारत में केंद्रीय बैंकिंग का विकास

"समय की शुरुआत से लेकर तीन महान आविष्कार हुए हैं:

आग, पहिया और केंद्रीय बैंकिंग" - विल रोजर्स

केंद्रीय बैंकों के विकास-क्रम की शुरुआत सतरहवीं शताब्दी में देखा जा सकता है जब 1668 में स्वीडिश सेंट्रल बैंक रिक्सबैंक की स्थापना की गई थी। बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना 1694 में हुई थी। 1914 में स्थापित संयुक्त राज्य अमेरिका का सेंट्रल बैंक, फेडरल रिज़र्व, केंद्रीय बैंकिंग क्षेत्र में अपेक्षाकृत देर से प्रवेश करने वाला केंद्रीय बैंक था। भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत के केंद्रीय बैंक ने 1935 में अपना परिचालन शुरू किया। बीसवीं शताब्दी के मोड़ पर केवल अठारह केंद्रीय बैंक थे। आज, अधिकांश देशों में एक केंद्रीय बैंक है।

केंद्रीय बैंक नियमित बैंक नहीं हैं। वे अपने कार्यों और उद्देश्यों दोनों की दृष्टि से विशिष्ट हैं। शुरुआत में, केंद्रीय बैंकों की स्थापना सरकार को उनके युद्ध संबंधी खर्चों को पूरा करने और उनके ऋण का प्रबंधन करने के लिए वित्त प्रदान करने के प्राथमिक उद्देश्य से की गई थी। प्रारंभ में उन्हें निर्गम बैंक के रूप में जाना जाता था और उन्नीसवीं सदी में ही केंद्रीय बैंकिंग नामक शब्द की उत्पत्ति हुई। वे "विशेष" वाणिज्यिक बैंकों के रूप में स्थापित किए गए थे और बहुत बाद में सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के रूप में विकसित होने लगे। इन बैंकों की "विशेष" प्रकृति सरकारी चार्टर्स पर आधारित थी, जिसने उन्हें न केवल सरकार के मुख्य बैंकर बना दिया, बल्कि उन्हें नोट या मुद्रा जारी करने के लिए एकाधिकारी विशेषाधिकार भी प्रदान किए। केंद्रीय बैंकों ने अन्य बैंकों के खाते भी रखे, भले ही वे सामान्य वाणिज्यिक बैंकिंग गतिविधियों में लगे हुए हों। अपनी विशेष ओहदे और आकार के परिणामस्वरूप वे जल्द ही विभिन्न बैंकों के बीच लेनदेन प्रक्रिया को पूरा करने के साथ-साथ उन्हें बैंकिंग सेवाएं प्रदान करके बैंकरों के बैंक का रूप धारण करने लगे। अठारहवीं और उन्नीसवीं सदी में कई वित्तीय खलबली मच गई। चूंकि एक बैंक की विफलता अन्य बैंकों की विफलता का कारण बन सकती है, अतः इसके परिणामस्वरूप आतंक मचना एक गंभीर समस्या है। अपने तुलन-पत्रों की प्रकृति के कारण आतंक या अच्छी तरह से जानी जाने वाली बैंक रन की स्थिति से बैंकों को गुजरना पड़ता है। उनकी देयताएं अल्पकालिक और तरल होती हैं (बैंकों की प्रमुख देयताएं मांग जमा होती हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि जमाकर्ता अपने पैसे को कभी भी वापस मांग सकते हैं और इसलिए तुरंत देय हैं), जबकि आस्तियां दीर्घकालिक होती हैं और ये चलनिधि के रूप में शीघ्र परिवर्तनशील भी नहीं होती हैं (इसका तात्पर्य यह है कि उन्हें आसानी से बेचा नहीं जा सकता और जल्दी से नकदी के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है)। समाज में उपलब्ध संसाधनों के संग्रह को बचतकर्ताओं और उधारकर्ताओं के बीच प्रभावी तरीके से आबंटित करने की दृष्टि से बैंक इस तथाकथित परिपक्वता या तरलता रूपांतरण प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। जहां तक बैंकों की विफलता और वास्तविक अर्थव्यवस्था पर इसके संभावित प्रतिकूल प्रभाव का संबंध है यह सभी नीति निर्माताओं के लिए एक गंभीर चिंता का विषय रहा और है। 1873 में, इकोनॉमिस्ट पत्रिका के एक संपादक वाल्टर बैगेहॉट ने "लॉन्ग स्ट्रीट" नामक एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि आतंक से बचने के लिए, केंद्रीय बैंकों को "अंतिम ऋणदाता" की भूमिका निभानी चाहिए। बैजेट उक्ति के रूप में जाने जाने वाले सिद्धांत के अनुसार आतंक या संकट काल में केंद्रीय बैंक को उच्च स्तरीय संपार्श्विक आस्तियों पर और दंडात्मक ब्याज लगाते हुए निःशुल्क ऋण प्रदान करना चाहिए। इसका मकसद यह है कि जो बैंक अपने जमाकर्ताओं या अन्य उधारदाताओं के कारण "बैंक रन" की स्थिति का सामना कर रहा है, वह केंद्रीय बैंक से संपार्श्विक आस्ति के एवज में उधार लेकर दबाव के समय में अस्थायी

तरलता की समस्या से निपट सकता है। वह जमाकर्ताओं को भुगतान कर सकता है और स्थिति को संभालने के लिए उसे समय मिलेगा। चूंकि बैंक रन की स्थिति से स्वतः अवगत हो सकता है, अतः बैंक इस अवधि में दिवलिया हुए बिना संभाल सकें तो वे संकट की स्थिति से बच सकते हैं। यदि बैंक आहरण संबंधी मांगों को पूरा करने की दृष्टि से काबिल है तो धनराशि आहरित करने को लेकर अन्य जमाकर्ताओं को तसल्ली होगी और उन्हें ऐसा करने से रोका भी जा सकेगा। 'अंतिम ऋणदाता' (लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट) सुविधा के बिना, बैंक अपनी आस्तियों की संपत्ति की मजबूरन बिक्री के लिए बाध्य होंगे और वह भी काफी कम दाम में। इस प्रकार, सरकार और बैंकों के बैंकर होने के अलावा, केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता भी बनते हैं।

केंद्रीय बैंक का मुख्य मिशन समष्टि-आर्थिक स्थिरता और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना है। समष्टि-आर्थिक स्थिरता का तात्पर्य है स्थिर और सतत संवृद्धि को हासिल करना तथा मूल्यों को स्थिर रखना, अर्थात् मुद्रास्फीति को कम और स्थिर रखना। दूसरी ओर, वित्तीय स्थिरता से अभिप्रेत है वित्तीय प्रणाली को समुत्थानशील रखना और वित्तीय संकट से बचना। इन उद्देश्यों का सापेक्ष महत्व समय के साथ बदलता रहा है। सतत आर्थिक संवृद्धि और कम व स्थिर मुद्रास्फीति की स्थिति को हासिल करने का प्रयास उन्नीसवीं शताब्दी की शुरुआत से स्वर्ण मानक के अस्तित्व में आने के साथ केंद्रीय बैंकिंग गतिविधियों में मूलभूत कार्य रहा है, तथापि, वित्तीय स्थिरता का महत्व 1930 के दशक की महामंदी के बाद से अधिक ज्वलंत मुद्दा बन गया जब वैश्विक अर्थव्यवस्था को बड़े बैंकों की विफलता और गहरी मंदी का सामना करना पड़ा।

व्यापक आर्थिक स्थिरता और वित्तीय स्थिरता के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, केंद्रीय बैंकों के पास कुछ उपकरण हैं। आर्थिक स्थिरता को प्राप्त करने के लिए, केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति का उपयोग करते हैं। अल्पकालिक ब्याज दरों में बदलाव करके, यानी, ब्याज दरों को बढ़ाकर या कम करके वे अर्थव्यवस्था में धनराशि की आपूर्ति और मांग को नियंत्रित करते हैं और इस तरह आर्थिक गतिविधि और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और मुद्रास्फीति अधिक है, तो केंद्रीय बैंक, बैंकों को उधार के रूप में दी जाने वाली धनराशि पर लिए जाने वाले ब्याज की दरों को बढ़ा सकता है। उच्च ब्याज दरें अन्य दरों को प्रभावित करेंगी, जैसे आवास ऋण, उपभोक्ता ऋण, आदि। जैसे-जैसे उधार की लागत बढ़ती है, तो यह खपत और निवेश को हतोत्साहित करता है, जिससे संवृद्धि और मुद्रास्फीति कम होती है। वहीं, यदि अर्थव्यवस्था बहुत धीमी गति से बढ़ रही है या मुद्रास्फीति बहुत कम है, तो केंद्रीय बैंक ब्याज दर में कटौती करेगा। इसका प्रभाव अन्य दरों पर पड़ेगा तथा खर्च और निवेश को प्रोत्साहित करेगा जिससे आर्थिक संवृद्धि और मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलेगा। इसका तात्पर्य है सतत संवृद्धि के साथ-साथ निम्न व स्थिर मुद्रास्फीति को हासिल करना। व्यापार की चाल सतत विकास और कम और स्थिर मुद्रास्फीति को प्राप्त करना है। इस प्रकार, कभी-कभी, केंद्रीय बैंकिंग के बारे में बताया जाता है कि वह "न तो विज्ञान है और न ही कला, बल्कि एक शिल्प" है।

वित्तीय स्थिरता को हासिल करने के लिए, केंद्रीय बैंक के पास मुख्य उपकरण है चलनिधि का प्रावधान। जैसा कि पहले बताया गया है इस उपकरण को "अंतिम ऋणदाता" कहा जाता है। कुछ केंद्रीय बैंक, जो अपनी अर्थव्यवस्था में बैंकिंग विनियामक भी हैं, वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक अन्य उपकरण, नामतः विनियमन और पर्यवेक्षण का भी उपयोग करते हैं। विवेकपूर्ण नियमों और सिद्धांतों को निर्धारित करके तथा यह जांच व निगरानी करते हुए कि क्या बैंकों द्वारा इन नियमों व सिद्धांतों का पालन किया जा रहा है कि नहीं, केंद्रीय बैंकों का लक्ष्य एक स्वस्थ और मजबूत बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली बनाना है। एक समुत्थानशील व सुरक्षित बैंकिंग प्रणाली वित्तीय संकट का सामना करने की संभावनाओं को कम करेगी। कई देशों में नियामक और पर्यवेक्षी भूमिकाएं अलग-अलग एजेंसियों द्वारा निभाई जाती हैं, अतः ये भूमिकाएं केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्य के अंतर्गत नहीं आती हैं।

वाणिज्यिक बैंकिंग गतिविधि के अंतरराष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप कई जोखिम उभरकर आए। 1974 में दो बैंकों, नामतः संयुक्त राज्य अमेरिका में फ्रैंकलिन नेशनल बैंक और जर्मनी में बैंक हर्स्टेट, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समस्या पैदा हुई थी, की विफलता ने केंद्रीय बैंकों के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग और समन्वय की आवश्यकता को रेखांकित किया। परिणामस्वरूप बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बासेल समिति (बीसीबीएस) की स्थापना की गई। यह समिति अंतरराष्ट्रीय विनियामकीय मानकों को निर्धारित करती है, जिसे बेसल मानकों के रूप में जाना जाता है, जो सभी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग नियमों के लिए आधार बनाता है।

वर्ष 2007-08 में वित्तीय संकट के प्रादुर्भाव से, केंद्रीय बैंकों के टूलबॉक्स को मजबूत किया गया है। इन उपकरणों या उपायों को लोकप्रिय रूप से "अपरंपरागत नीतियों" के रूप में जाना जाता है, जो असाधारण परिस्थितियों में उनके उपयोग को दर्शाते हैं। मात्रात्मक या क्रेडिट शिथिलता, नकारात्मक ब्याज दरें, आगे का मार्गदर्शन, आदि, केंद्रीय बैंकों द्वारा संकट और उसके परिणामी प्रभावों से निपटने के लिए अपनाए जाने वाले कुछ उपकरण हैं। बाजारों के निष्क्रिय हो जाने के कारण केंद्रीय बैंक भी संकट के दौरान "अंतिम उपाय के तौर पर बाजार निर्माता" का धारण करने लगे। इन अवधारणाओं को अगले अध्यायों में समझाया जाएगा।

एक और घटना जो केंद्रीय बैंकों के विकास की दिशा बदल दी थी, वह है कोविड-19 महामारी का सहस्राब्दिक प्रकोप। वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंकों के कामकाज का परीक्षण करने या आकार देने वाले कई अन्य संकटों के विपरीत, इसकी शुरुआत वित्तीय क्षेत्र के हुई थी। तथापि, इसने केंद्रीय बैंकों को संबंधित सरकारों के साथ एक जुट होकर सर्वश्रेष्ठ कार्यनिष्पादन दिखाते हुए मजबूर किया और सरकारों को वास्तविक अर्थव्यवस्थाओं पर महामारी के प्रभावी को कम करने के लिए प्रयास करने के लिए मजबूर किया। कई केंद्रीय बैंक लगातार प्रतिक्रिया दिखाते रहे लेकिन उनका दृष्टिकोण काफी विविध रहा। जाहिर सी बात थी कि केंद्रीय बैंकों ने अपने सारे उपकरणों का प्रयोग किया, लेकिन प्रतिक्रियाएं प्रत्येक देश के तनाव के स्वरूप और उनके वित्तीय प्रणालियों के विकास के स्तर या संरचना के अनुरूप थीं। केंद्रीय बैंकों ने बाजार की निष्क्रियता से निपटने के लिए सोच-समझकर कार्य करते हुए तुरंत ही अपनी नीति में नरम रुख अपनाया। साथ ही, इसके पूरक के रूप में उन्होंने बैंकों की क्षमता और उधार देने के अभिप्राय का समर्थन करने के लिए विनियामकीय सहनशीलता और पर्यवेक्षी उदारता वाला दृष्टिकोण अपनाया। विभिन्न देशों की सरकारों की तरफ से भी की राजकोषीय नीतिगत प्रतिक्रिया भी तेजी से और मजबूत तरीके से दिखाई पड़ी। बहाली तो तेजी से हुई लेकिन उसी के साथ मुद्रास्फीति बेकाबू होकर चौंकाने लगी।

महामारी के बाद, कई केंद्रीय बैंक भी डिजिटल मुद्रा सहित डिजिटल भुगतान के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने लगे। इसी तरह, जैसा कि फिनटेक वित्तीय परिदृश्य को बदल रहा है, विनियमन की प्रकृति को समायोजित करना होगा। फिनटेक फर्मों द्वारा किए जाने वाले कार्यों में भारी विविधता को देखते हुए विनियामकीय परिधि में बदलाव करना आवश्यक है। विनियमन के दृष्टिकोण को भी विनियमित की जा रही इकाई के प्रकार के अनुरूप ढलने की आवश्यकता है। इसी प्रकार की गतिविधियों के ज्यादातर मामलों पर समान विनियमन लागू होते हैं, तथापि, बड़े टेक फर्मों की वित्तीय गतिविधियों को संभालने के लिए संस्था-आधारित विनियमन की तुलना में गतिविधि-आधारित विनियमन का प्रभाव कम रहेगा। समग्र तौर पर वित्तीय जोखिमों की तुलना में साइबर सुरक्षा जोखिम का महत्व काफी बढ़ने की संभावना है। बड़े वित्तीय बाजार बुनियादी ढांचे की संस्थाओं या बिगटेक को संभालते समय प्रणालीगत जोखिम, परिचालन जोखिम और प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने वाले जोखिम का महत्व काफी बढ़ जाता है। देशों को गोपनीयता, सुरक्षा और डेटा के मुद्रीकरण से संबंधित आशंकाओं को दूर करने में रहने वाली विधायी और विनियामकीय खामियों को दूर करने की आवश्यकता है। डेटा मुद्दों से संबंधित विनियमों को एक ऐसी संरचना के अनुकूल

बनाने की आवश्यकता है जहां वित्तीय और गैर-वित्तीय फर्मों के बीच की सीमाएं तेजी से धुंधली हो रही हैं या भौगोलिक सीमाएं अब बाधा नहीं हैं। (बीआईएस पेपर सं 11733)।

जलवायु परिवर्तन को लेकर पैदा होने वाले जोखिमों का प्रबंधन कार्य केंद्रीय बैंकों का ध्यान अधिक आकर्षित कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन हमारे दीर्घकालिक विकास और समृद्धि के लिए खतरा है। यह मौद्रिक स्थिरता, विकास, वित्तीय स्थिरता, विनियमित संस्थाओं की सुरक्षा और सुदृढ़ता को बाधित करने की क्षमता रखता है। कई देशों में, जिनमें भारत भी शामिल है, केंद्रीय बैंकों को सांविधिक अधिदेश के अंतर्गत कतिपय उद्देश्यों को हासिल करने का जिम्मा सौंपा गया है। इसका मतलब है कि उन्हें उन जोखिमों और खतरों को दूर करना होता है जो उनके मुख्य मिशन को प्रभावित करते हैं। जलवायु परिवर्तन इस तरह का जोखिम पैदा करता है। अतः उन्हें उन परिणामों का प्रबंधन करना होता है जो वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और वित्तीय संस्थाओं की सुरक्षा और सुदृढ़ता को प्रभावित कर सकते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले जोखिम भौगोलिक सीमाओं को लांघकर विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। इस वजह से, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक समन्वय और सहयोग की आवश्यकता है। इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, आईएमएफ जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन और बीसीबीएस और एफएसबी जैसे मानक निर्धारित करने वाले निकाय जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर की जा रही कार्रवाई में तेजी ला रहे हैं।

वैश्विक स्तर पर, जी-20 के तत्वावधान में पहले से ही कई कदम उठाए जा रहे हैं। विभिन्न मानक निर्धारण निकाय जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले मुद्दों को दूर करने के लिए संकेंद्रित कार्य कर रहे हैं। वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) ने "जलवायु परिवर्तन से वित्तीय जोखिमों से निपटने की रूपरेखा" प्रकाशित की थी, जिसे जुलाई 2021 में जी20 द्वारा अंगीकृत किया गया था और तब से इसे अद्यतन किया जाता रहा है। इस रूपरेखा में जलवायु से संबंधित वित्तीय जोखिमों को दूर करने के लिए एक व्यापक और समन्वित योजना निर्धारित की गई है और चार क्षेत्रों को शामिल किया गया है, अर्थात्, फर्म-स्तरीय प्रकटीकरण, डेटा, कमजोरियां, तथा विनियामकीय व पर्यवेक्षी प्रथाएं और उपकरण।

भारतीय रिज़र्व बैंक का विकास

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की उत्पत्ति 1926 में देखी जा सकती है, जब भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन - जिसे हिल्टन-यंग कमीशन के रूप में भी जाना जाता है - ने सरकार से मुद्रा और क्रेडिट के नियंत्रण को अलग करने और पूरे देश में बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भारत के लिए एक केंद्रीय बैंक के निर्माण की सिफारिश की थी। 1934 के भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के तहत रिज़र्व बैंक की स्थापना की गई और 1935 में इसके परिचालन की शुरुआत कई कार्रवाइयों के सिलसिले से हुई। उसके बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय क्षेत्र के स्वरूप में हुए बदलाव के अनुरूप रिज़र्व बैंक की भूमिका और कार्यों में बदलाव होता रहा है। रिज़र्व बैंक की शुरुआत निजी शेयरधारकों के बैंक के रूप में की गई थी, लेकिन 1949 में इसे राष्ट्रीयकृत किया गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की प्रस्तावना, जिसके तहत इसका गठन किया गया था, में इसके उद्देश्य को निम्नानुसार उल्लिखित किया गया है - "भारत में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने की दृष्टि से बैंकनोटों के निर्गम को विनियमित करना तथा प्रारक्षित निधि को बनाए रखना और सामान्य रूप से देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली संचालित करना"। जैसा कि अधिनियम में देखा जा सकता है, आरबीआई की प्राथमिक भूमिका मौद्रिक स्थिरता को साकार करना है, अर्थात्, देश की मुद्रा के मूल्य के प्रति विश्वास को बनाए रखना या मुद्रा की क्रय शक्ति को संरक्षित करना। अंततः, इससे अभिप्रेत है मुद्रास्फीति की कम और

स्थिर प्रत्याशा, चाहे वह मुद्रास्फीति घरेलू स्रोतों से पैदा हुई हो या मुद्रा के मूल्य में बदलाव से या आपूर्ति की कमी से हुई हो या मांग के दबाव से। इसके अलावा, आरबीआई के पास दो अन्य महत्वपूर्ण अधिदेश हैं, समावेशी संवृद्धि और विकास, साथ ही वित्तीय स्थिरता।

जिस देश में समाज का एक बड़ा हिस्सा अभी भी गरीब है, वहां समावेशी विकास का महत्व काफी बढ़ जाता है। गरीबी उन्मूलन और आय असमानता को कम करने के लिए वित्त तक पहुंच आवश्यक है। अतः भारतीय रिज़र्व बैंक का एक प्रमुख कार्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है जिससे समावेशी विकास होता है। एक विकासशील देश के केंद्रीय बैंक के रूप में, आरबीआई की जिम्मेदारियों में वित्तीय बाजारों और संस्थानों का विकास करना भी शामिल है। वित्तीय बाजारों को व्यापक और विकसित करना और उनकी चलनिधि व आघात-सहनीयता को इस प्रकार बढ़ाना आरबीआई का एक प्रमुख उद्देश्य है जिससे कि वे भारत के विकास के वित्तपोषण में आने वाले जोखिमों से निपटने और उन्हें अवशोषित करने में मदद कर सकें।

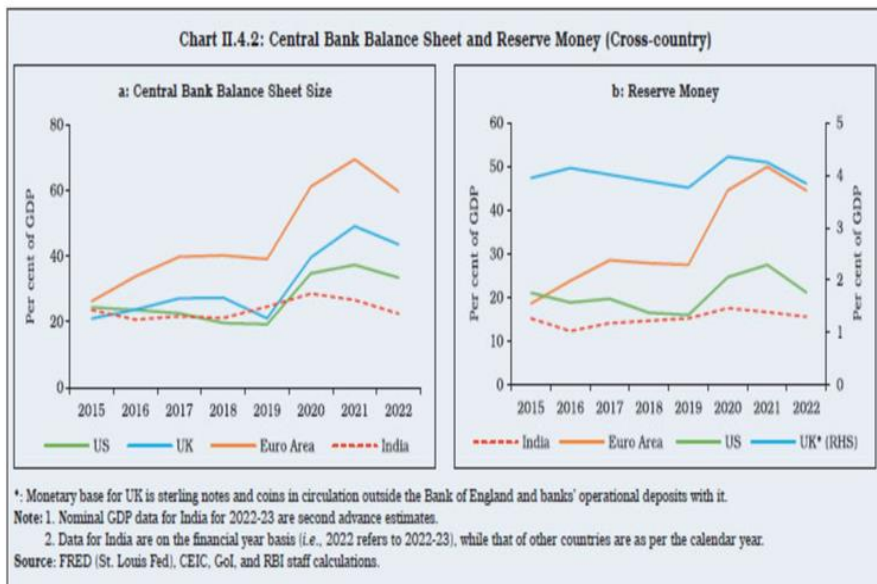
भारत की वित्तीय प्रणाली में बैंकों का वर्चस्व है। इसलिए उनका विनियमन और पर्यवेक्षण जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा और वित्तीय स्थिरता को संरक्षित करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आरबीआई को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 से शक्तियां प्राप्त होती हैं और यह भारत में परिचालनरत बैंकों के लिए विनियामकीय नीतिगत ढांचे की अभिकल्पना और कार्यान्वयन करता है। कालांतर में गैर-बैंकिंग संस्थाओं को भी शामिल करने के लिए विनियमन और पर्यवेक्षण के दायरे का विस्तार किया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और बाद में वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं ने सरकारों की भूमिका और आबंटन के जरिए विदेशी मुद्रा को संरक्षित करने की आवश्यकता पैदा की। प्रारंभ में, आरबीआई ने भारत के रक्षा नियमावली, 1939 और बाद में, 1947 के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के तहत विदेशी मुद्रा लेनदेनों का विनियमन किया। कालांतर में जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था परिपक्व हुई, विदेशी मुद्रा विनियमन से विदेशी मुद्रा प्रबंधन की ओर अंतरित करते हुए इसकी भूमिका में परिवर्तन हुआ।

1991 का भुगतान संतुलन और विदेशी मुद्रा संकट भारत के आर्थिक इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना थी। देश की मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली के केंद्र में होने के नाते आरबीआई संकट का प्रबंध करने तथा आवश्यक बाज़ार व विनियामकीय सुधारों में मदद करने के लिए प्रमुख समर्थनकारी भूमिका अदा करता है। सुधार युग के तहत दृष्टिकोण में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को बल देना और मौजूदा व उभरती संस्थाओं और बाजार सहभागियों को सुदृढ़ बनाने के लिए संकेंद्रित प्रयास किया जाना शामिल था। रिज़र्व बैंक ने नए नीतिगत ढांचे को प्रभावी बनाने के लिए विवेकपूर्ण विनियमन, बैंकिंग प्रौद्योगिकी, मौद्रिक नीति संबंधी लिखतों की विविधता, विदेशी क्षेत्र प्रबंधन और मुद्रा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाएं अपनाईं।

केंद्रीय बैंक देश की भुगतान और निपटान प्रणाली के केंद्र में होते हैं। " मुद्रा के प्रति जनसाधारण में विश्वास को संरक्षित करना केंद्रीय बैंकों का एक प्रमुख कार्य है। यह विश्वास भुगतान और निपटान प्रणालियों के माध्यम से आर्थिक एजेंटों द्वारा धनराशियों और वित्तीय लिखतों का लेनदेन करने में सक्षम बनाने पर निर्भर करता है"।¹ आरबीआई ने पिछले कुछ वर्षों में एक मजबूत तथा अत्याधुनिक भुगतान और निपटान प्रणाली के निर्माण में कई पहलें की हैं जो न केवल वित्तीय प्रणाली की "संचालन-व्यवस्था" में सुधार करती हैं बल्कि इसकी स्थिरता को भी बनाए रखती हैं।

पिछले ढाई दशकों में विश्व के साथ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली का एकीकरण भी बढ़ा है। वैश्विक एकीकरण के बढ़ते स्तर से एक ओर भारतीय अर्थव्यवस्था की संवृद्धि को गति मिलती है तो दूसरी ओर इससे भारत को वैश्विक झटकों का सामना भी करना पड़ता है। वर्ष 2007-08 के संकट ने अन्य अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय अस्थिरता का हलका सा प्रभाव छोड़ा था, जबकि उसने हमारी वित्तीय स्थिरता के लिए भी खतरा पैदा किया। अतः वित्तीय स्थिरता को संरक्षित करना आरबीआई के लिए और भी महत्वपूर्ण अधिदेश बन गया है। वित्तीय बाजारों और अर्थव्यवस्था के विशिष्ट क्षेत्रों में कोविड-19 के कारण पैदा

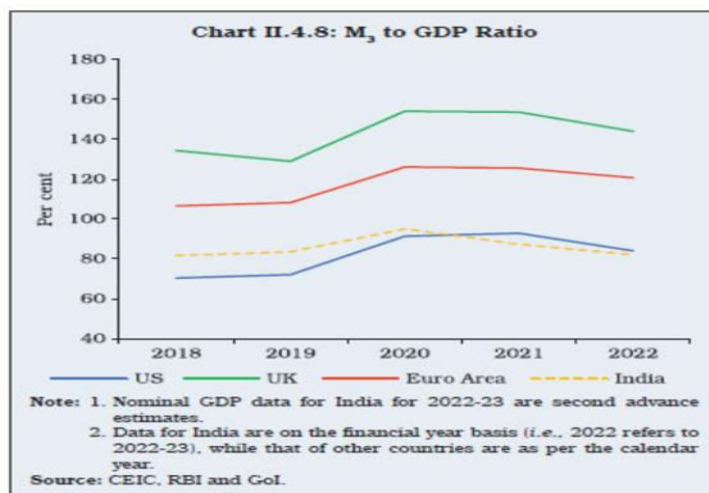
हुए तनाव को कम करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने अपरंपरागत मौद्रिक नीतियों के हिस्से के रूप में कई लक्षित और प्रणाली-स्तरीय चलनिधिगत उपायों का उपयोग किया था, जिसके कारण इसके तुलन-पत्र का आकार लगातार बढ़ता रहा। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में देखें तो रिज़र्व बैंक के तुलन-पत्र का आकार 2019-20 के 24.6 प्रतिशत के स्तर से बढ़कर 2020-21 में 28.6 प्रतिशत हो गया, जो आगे 2021-22 में गिरावट दर्ज करते हुए 26.7 प्रतिशत पर पहुंचा और 2022-23 में और कम होकर 22.5 प्रतिशत हो गया (चार्ट II.4.2 ए और बी)। तथापि, जहां तक रिज़र्व बैंक के तुलन-पत्र का आकार का



सवाल है वह अमेरिका, ब्रिटेन और यूरो क्षेत्र की तुलना में अपेक्षाकृत कम रहा। इसी अवधि के दौरान, भारत में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में रिज़र्व धनराशि (केंद्रीय बैंक के तुलन-पत्र/आधार मुद्रा में मौद्रिक देयताओं का स्टॉक) भी अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में स्थिर रही क्योंकि चलनिधिगत उपायों को सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था और उनके लिए टर्मिनल तारीखों को

लक्ष्य के रूप में रखा गया था, जिससे कोविड के बाद की अपरंपरागत नीतियां बंद किए जाने संबंधी चुनौतियों को कम किया जा सका।¹

इसके अलावा, मुद्रा आपूर्ति, जिसे आम तौर पर आर्थिक गतिविधि – अर्थात मौद्रिक जीडीपी अनुपात में एम3 का हिस्सा – के संदर्भ में व्यापक मुद्रा (एम3 – जनता के पास उपलब्ध मुद्रा, बैंकों के पास मांग और सावधि जमा राशियों और रिज़र्व बैंक के पास रखी हुई अन्य जमा राशियों का जोड़) के रूप में दर्शाया जाता है, से यह पता चलता है कि भारत ने कोविड-19 की अवधि में किए गए प्रोत्साहनकारी उपायों के कारण दर्ज हुए स्तर से महामारी से पूर्व में व्याप्त स्तर को तेजी से बहाल किया, जबकि अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति इसके ठीक विपरीत रही (चार्ट II.4.8)।



¹ भुगतान और निपटान प्रणाली का बैंक निरीक्षण, बीआईएस, मई 2005

अध्याय 2: रिज़र्व बैंक के कार्यों के लिए कानूनी संरचना

केंद्रीय बैंकों की संरचना, भूमिकाएं और जिम्मेदारियां देशों के बीच भिन्न होती हैं, जो उनके मूल और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की विविधता से बहुत स्पष्ट है। केंद्रीय बैंकों की स्थापना और जनादेश को नियंत्रित करने वाले कानून भी एक समान नहीं हैं, भले ही वे दुनिया भर में केंद्रीय बैंकों के कार्यों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भारत में, आरबीआई भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 ('आरबीआई अधिनियम') द्वारा गठित केंद्रीय बैंकिंग प्राधिकारी है, और इसके कर्तव्य और जिम्मेदारियां उस कानून से आती हैं। तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए जा रहे कार्यों की श्रेणी न केवल भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत शामिल है² बल्कि विभिन्न अन्य संविधियों के अंतर्गत भी शामिल है। इस प्रकार, भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यों के लिए कानूनी समर्थन कई संविधियों में फैला हुआ है। इस अध्याय में, हम भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदान किए जाने वाले विविध कार्यों की तुलना में कानूनी प्रावधानों की विस्तार से चर्चा करेंगे।

भारतीय रिज़र्व बैंक – कानूनी पृष्ठभूमि

भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन की सिफारिश के अनुसरण में, 1927 में भारत में एक केंद्रीय बैंक बनाने के लिए विधानसभा में एक विधेयक पेश किया गया था, जिसे बाद में लोगों के विभिन्न वर्गों में सहमति के अभाव में वापस ले लिया गया था। इसके बाद, भारतीय सांविधिक सुधारों (1933) पर श्वेत पत्र ने भारत में रिज़र्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की। तदनुसार, विधान सभा में एक नया विधेयक पेश किया गया, जिसे पारित किया गया और 6 मार्च, 1934 को गवर्नर जनरल की सहमति प्राप्त हुई³। फलस्वरूप, आरबीआई अधिनियम लागू हुआ और आरबीआई ने 1 अप्रैल 1935 को निजी शेयरधारकों के बैंक के रूप में देश के केंद्रीय बैंक के रूप में पांच करोड़ रुपये की चुकता पूंजी के साथ अपना परिचालन शुरू किया।

लक्ष्य और उद्देश्य – प्रस्तावना

जिन उद्देश्यों के लिए आरबीआई को भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में स्थापित किया गया है, उन्हें आरबीआई अधिनियम (संशोधित) की प्रस्तावना में निम्नानुसार रेखांकित किया गया है:

- १) भारत में मौद्रिक स्थिरता हासिल करने और आम तौर पर देश की मुद्रा और क्रेडिट प्रणाली को देश के हित में संचालित करने की दृष्टि से बैंक नोटों का निर्गमन विनियमित करना, आरक्षित निधि रखना; और
- २) तेजी से जटिल होती अर्थव्यवस्था की चुनौती का सामना करने के लिए आधुनिक मौद्रिक नीति संरचना का होना आवश्यक है और मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है।

इस प्रकार, वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा संशोधित आरबीआई अधिनियम की प्रस्तावना में यह प्रावधान है कि मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना और तेजी से जटिल होती अर्थव्यवस्था की चुनौती का सामना करना है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम में भारतीय रिज़र्व बैंक के प्राधिकृत कार्य के

² भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17

³ स्रोत: आरबीआई की वेबसाइट, "भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास"

रूप में न केवल उस अधिनियम के अंतर्गत बल्कि उस समय लागू किसी अन्य कानून के अंतर्गत भी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का निष्पादन करने की परिकल्पना की गई है⁴। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक जो कार्य कर रहा है, वे केवल भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के प्रावधानों के भीतर ही सीमित नहीं हैं, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों जैसे बैंकों का विनियमन और पर्यवेक्षण, उपभोक्ता संरक्षण, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन, सरकारी प्रतिभूतियों का प्रबंधन, भुगतान प्रणालियों का विनियमन और पर्यवेक्षण आदि तक भी फैले हुए हैं, जिनके लिए विभिन्न कानूनों से शक्तियां ली गई हैं। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 आदि जैसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 आदि के माध्यम से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के माध्यम से विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के माध्यम से भारतीय प्रतिभूति अधिनियम, 1999 के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

सामान्य प्रशासन - कानूनी पृष्ठभूमि

भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यों और कारोबार का सामान्य अधीक्षण और निर्देशन केंद्रीय बोर्ड (आरबीआई अधिनियम की धारा 7) को सौंपा गया है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशकों सहित आरबीआई अधिनियम की धारा 8 के तहत नियुक्त निदेशक शामिल हैं। आरबीआई के बोर्ड का नेतृत्व गवर्नर करता है और चार उप गवर्नर इसकी सहायता करते हैं। बोर्ड सभी शक्तियों का प्रयोग करता है और आरबीआई द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सभी कार्य और चीजें करता है।

बैंकिंग और अन्य कार्य - कानूनी पृष्ठभूमि

आरबीआई अधिनियम की धारा 17 आरबीआई को बैंकिंग व्यवसाय करने में सक्षम बनाती है, जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय प्राधिकारी, बैंकों और किसी अन्य व्यक्तियों से ब्याज के बिना जमा स्वीकार करना। अन्य व्यवसाय, जो आरबीआई कर सकता है, का भी उक्त प्रावधान में उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि आरबीआई स्थायी जमा सुविधा योजना के तहत बैंकों या किसी अन्य व्यक्ति से ब्याज के साथ देय जमा के रूप में निधि स्वीकार कर सकता है, विनिमय बिलों की खरीद, बिक्री और पुनर्भुगतान, बैंकों और अन्य संस्थानों को अल्पकालिक ऋण और अग्रिम प्रदान कर सकता है, राष्ट्रीय ग्रामीण क्रेडिट फंड में वार्षिक योगदान प्रदान कर सकता है, डेरिवेटिव्स में सौदा कर सकता है, सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, (ख) सरकार ने रेपो अथवा रिवर्स रेपो में सौदा करने, विदेशी प्रतिभूतियों सहित प्रतिभूतियों को उधार देने अथवा उधार लेने, भारतीय स्टेट बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम आदि के शेयरों की खरीद और बिक्री, विशिष्ट प्रयोजनों के लिए भारतीय स्टेट बैंक के पास जमाराशियां रखने, बैंक नोट बनाने और जारी करने आदि के लिए भारतीय स्टेट बैंक के पास जमा राशि का प्रयोग किया है।

धारा 18 आरबीआई को 'अंतिम उपाय के ऋणदाता' के रूप में कार्य करने की सुविधा प्रदान करती है। धारा 19 में उन व्यवसायों के प्रकारों को सूचीबद्ध किया है जिन्हें आरबीआई लेनदेन नहीं करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 20 और 21 के अंतर्गत, भारतीय रिज़र्व बैंक का दायित्व और अधिकार है कि वह केंद्र

⁴ भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (15A)।

सरकार के खाते के लिए धनराशि स्वीकार करे और खाते में जमा राशि तक भुगतान करे और संघ के लोक ऋण प्रबंधन सहित अपने विनियम, विप्रेषण और अन्य बैंकिंग परिचालन करे। राज्य सरकारों के मामले में, उक्त बैंकिंग कार्य आरबीआई अधिनियम की धारा 21-ए में किए गए प्रावधान के अनुसार आरबीआई और संबंधित राज्य सरकार के बीच एक समझौते के माध्यम से किए जाते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक और राज्य सरकारों के बीच किए गए ये करार सांविधिक हैं क्योंकि इन्हें बनते ही संसद के समक्ष रखा जाना अपेक्षित है।

निर्गम के कार्य - कानूनी पृष्ठभूमि

बैंक नोट जारी करना प्रमुख केंद्रीय बैंकिंग कार्यों में से एक है जिसे करने के लिए आरबीआई अधिकृत और अधिदेशित है। आरबीआई अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत भारत में बैंक नोट जारी करने का एकाधिकार आरबीआई को प्रदान किया गया है। बैंक नोटों का निर्गम, निर्गम विभाग द्वारा संचालित किया जाना चाहिए, जिसे बैंकिंग विभाग से अलग करके पूर्णतः पृथक रखा जाना चाहिए (धारा 23)। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम आरबीआई को केंद्र सरकार को बैंक नोटों के मूल्यवर्ग की सिफारिश करने में सक्षम बनाता है, जो दो रुपये, पांच रुपये, दस रुपये, बीस रुपये, पचास रुपये, एक सौ रुपये, पांच सौ रुपये, एक हजार रुपये, पांच हजार रुपये और दस हजार रुपये या अन्य मूल्यवर्ग जो दस हजार रुपये से अधिक नहीं हो सकता है (धारा 24)। बैंक नोटों के डिजाइन, स्वरूप और सामग्री को भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिशों (धारा 25) पर केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। प्रत्येक बैंक नोट भारत में किसी भी स्थान पर एक वैध मुद्रा होगी, हालांकि, केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश पर, केंद्र सरकार किसी भी मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की किसी भी श्रृंखला को वैध मुद्रा (धारा 26) घोषित कर सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक केवल स्वच्छ नोटों को प्रचलन में लाने के लिए प्रतिबद्ध है (धारा 27)। एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य कटे-फटे या फटे नोटों का आदान-प्रदान है, जो आरबीआई अधिनियम के तहत अनुग्रह का विषय है (धारा 28) अधिकार का नहीं है। आरबीआई द्वारा जारी किए जा रहे बैंक नोटों को स्टॉप शुल्क (धारा 29) के भुगतान से छूट दी गई है। अधिनियम में, निर्गम विभाग की आस्तियों और देयताओं का वर्णन किया गया है (धारा 33 और 34)। सिक्कों और मुद्रा के विभिन्न रूपों की आपूर्ति के संबंध में दायित्व क्रमशः धारा 38 और 39 में दिए गए हैं। डिजिटल करेंसी की शुरुआत को सुविधाजनक बनाने के लिए, अधिनियम को वर्ष 2022 में संशोधित किया गया था (i) धारा 22 के तहत बैंक द्वारा जारी किए गए नोट का अर्थ स्पष्ट रूप से "बैंक नोट" को परिभाषित करना, चाहे वह भौतिक या डिजिटल रूप में हो; और (ii) कुछ ऐसे प्रावधान करना जो बैंक नोटों के डिजिटल रूप पर लागू न हों (धारा 22A)।

मौद्रिक नीति कार्य - कानूनी पृष्ठभूमि

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अध्याय III-एफ में मौद्रिक नीति ढांचे और मौद्रिक नीति समिति के कामकाज के लिए सांविधिक आधार प्रदान किया गया है। केंद्र सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करेगी जिसे सरकारी राजपत्र (धारा 45जेडए) में अधिसूचित किया जाना अनिवार्य है। इसी प्रकार, केंद्र सरकार को भारत के सरकारी राजपत्र (धारा 45जेडबी) में अधिसूचना द्वारा एक मौद्रिक नीति समिति का गठन करना चाहिए। मौद्रिक नीति समिति में (क) आरबीआई के गवर्नर; (ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर जो मौद्रिक नीति के प्रभारी हों; (ग) भारतीय रिज़र्व बैंक का एक अधिकारी जिसे केन्द्रीय बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा; और (घ) केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले तीन व्यक्ति शामिल होने चाहिए। मौद्रिक नीति समिति को

मुद्रास्फीति लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपेक्षित नीतिगत दर निर्धारित करने का सांविधिक कर्तव्य सौंपा गया है। मौद्रिक नीति समिति का निर्णय आरबीआई के लिए बंधनधारक है और आरबीआई मौद्रिक नीति समिति (धारा 45जेड जे) के निर्णयों को लागू करने के लिए इसके द्वारा किए जाने वाले उपायों को स्पष्ट करते हुए एक दस्तावेज़ प्रकाशित करेगा। यह क़ानून का उद्देश्य रहा है कि एक समिति-आधारित दृष्टिकोण मौद्रिक नीति निर्णयों में बहुत अधिक मूल्य और पारदर्शिता जोड़ देगा। एमपीसी की बैठकें वर्ष में कम से कम चार बार आयोजित की जाएंगी और यह प्रत्येक ऐसी बैठक (धारा 45जेडके) के बाद अपने निर्णयों को प्रचारित करेगी।

लोक ऋण कार्य - कानूनी पृष्ठभूमि

भारत की संसद ने सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 ('जीएस अधिनियम') को "भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों और इसके प्रबंधन से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने" (अधिनियम की प्रस्तावना) के उद्देश्य से लागू किया। जीएस अधिनियम केंद्र सरकार या राज्य सरकार (जीएस अधिनियम की धारा 1) द्वारा बनाई और जारी की गई सरकारी प्रतिभूतियों पर लागू होता है। जीएस अधिनियम लोक ऋण के प्रबंधन में आरबीआई द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और तौर-तरीकों को निर्धारित करता है और आरबीआई को विभिन्न शक्तियां भी प्रदान करता है, जिसमें सरकारी प्रतिभूति के लिए शीर्षक निर्धारित करने की शक्ति शामिल है, यदि भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में कोई संदेह है (जीएस अधिनियम की धारा 12)। इसके अतिरिक्त, जीएस अधिनियम की धारा 18 में यह प्रावधान है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उस अधिनियम के अधीन किए गए किसी भी आदेश को उसमें उल्लिखित कारणों से किसी न्यायालय द्वारा प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। जीएस अधिनियम के अधिनियमन से पूर्व, भारतीय रिज़र्व बैंक के उक्त लोक ऋण कार्य लोक ऋण अधिनियम, 1944 के प्रावधानों द्वारा शासित होते थे। जीएस अधिनियम के लागू होने से लोक ऋण अधिनियम, 1944 का पूरी तरह से निरस्त नहीं हुआ है। यह जीएस अधिनियम की धारा 31 से स्पष्ट है जिसमें कहा गया है कि लोक ऋण अधिनियम, 1944, उन सरकारी प्रतिभूतियों पर लागू नहीं होगा जिन पर यह अधिनियम लागू होता है और उन सभी मामलों के लिए जिनके लिए जीएस अधिनियम के तहत प्रावधान किए गए हैं।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन - कानूनी पृष्ठभूमि

विदेशी व्यापार और भुगतान, भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के विकास और रखरखाव के संबंध में शक्तियां और जिम्मेदारियां आरबीआई को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 ("फेमा") के प्रावधानों के तहत प्रदान की जाती हैं। फेमा की धारा 10 आरबीआई को किसी भी व्यक्ति को विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रतिभूतियों में, प्राधिकृत डीलर, मनी चेंजर या ऑफशोर बैंकिंग यूनिट या किसी अन्य तरीके से, जैसा वह उचित समझे, व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में जाने जाने के लिए प्राधिकृत करने का अधिकार देती है। इसी प्रकार, यह भारतीय रिज़र्व बैंक को जनहित में किसी प्राधिकृत व्यक्ति को जारी प्राधिकार को रद्द करने का अधिकार देता है, या यदि प्राधिकृत व्यक्ति उन शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है जिनके अधीन प्राधिकार प्रदान किया गया था या उसने फेमा के किसी प्रावधान या उसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम, विनियम, अधिसूचना, निदेश या आदेश का उल्लंघन किया है। तथापि, प्राधिकार का प्रतिसंहरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा फेमा में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद किया जाना चाहिए। फेमा की धारा 13 में उन उल्लंघनों का विवरण दिया गया है जिनका न्यायनिर्णयन और दंड प्राधिकारी (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा किया जाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक को इस

संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार फेमा की धारा 15 के अंतर्गत कतिपय उल्लंघनों को संयोजित करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

बैंकिंग विनियमन और पर्यवेक्षण - कानूनी पृष्ठभूमि

भारत में कई प्रकार के बैंक हैं, जैसे बैंकिंग कंपनियां (बैंक जो कंपनियां हैं और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा विनियमित हैं), भारतीय स्टेट बैंक (भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 द्वारा गठित), राष्ट्रीयकृत बैंक (बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970/1980 द्वारा गठित), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम के तहत गठित, (ग) सहकारी बैंकों (बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 अथवा राज्य सहकारी समिति अधिनियमों के अधीन गठित) और सहकारी बैंकों (बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 अथवा राज्य सहकारी समिति अधिनियमों के अधीन गठित) के अंतर्गत सहकारी बैंकों के गठन के संबंध में सहकारी बैंकों के साथ सहकारी समितियां गठित की गई हैं। यद्यपि आरबीआई को देश में सभी प्रकार के बैंकों को विनियमित करने और पर्यवेक्षण करने का कार्य सौंपा गया है, लेकिन विभिन्न बैंकों के प्रति इसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां समान नहीं हैं।

बैंकिंग कंपनियों को विनियमित और पर्यवेक्षण करने की शक्ति बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम, 1949) के प्रावधानों द्वारा आरबीआई को प्रदान की गई है। बीआर अधिनियम, 1949 की प्रस्तावना में कहा गया है कि यह बैंकिंग से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम है और बैंकिंग नीति (बीआर अधिनियम की धारा 5 (सीए)) तैयार करने के लिए आरबीआई की शक्तियां, बैंकिंग व्यवसाय को विनियमित और पर्यवेक्षण करने आदि के लिए, बीआर अधिनियम, 1949 में बिखरी हुई हैं। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (सीए) में कहा गया है कि बैंकिंग नीति का अर्थ ऐसी कोई भी नीति है, जो समय-समय पर आरबीआई द्वारा बैंकिंग प्रणाली के हित में या मौद्रिक स्थिरता या सुदृढ़ आर्थिक विकास के हित में निर्धारित की जाती है, जिसमें जमाकर्ताओं के हितों, बैंक की जमा राशियों और अन्य संसाधनों की मात्रा और न्यायसंगत आवंटन की आवश्यकता और इन जमा राशि के कुशल उपयोग की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है और संसाधन। किसी बैंकिंग कंपनी के अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति या बर्खास्तगी तब तक प्रभावी नहीं होगी, जब तक कि रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन (बीआर अधिनियम की धारा 35 बी) से ऐसा न किया गया हो। इसी प्रकार, प्रबंधन पर नियंत्रण के एक भाग के रूप में, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36-एबी भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंकिंग कंपनियों के बोर्डों में अतिरिक्त निदेशक नियुक्त करने का अधिकार देती है। बीआर अधिनियम, 1949 की धारा 36-एए आरबीआई को कुछ शर्तों के तहत बैंकिंग कंपनी के अधिकारियों, अधिकारियों और कर्मचारियों को हटाने में सक्षम बनाती है। इसके अलावा, आरबीआई को बीआर अधिनियम, 1949 के तहत बैंकिंग कंपनियों के बोर्डों (बीआर अधिनियम की धारा 36एसीए) को अधिक्रमित करने का अधिकार दिया गया है।

यद्यपि बैंकों के कार्यों का सूक्ष्म प्रबंधन करना रिज़र्व बैंक की भूमिका नहीं है, तथापि इसके पास बैंकिंग कंपनियों द्वारा दिए गए अग्रिमों को नियंत्रित करने की शक्तियां हैं (बीआर अधिनियम की धारा 21)। बीआर अधिनियम, 1949 की धारा 22 भारतीय रिज़र्व बैंक को लाइसेंस जारी करने और बैंकिंग कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने की शक्ति प्रदान करता है। एक अन्य महत्वपूर्ण नियामक शक्ति जो आरबीआई में निहित है, वह बैंकिंग कंपनियों को निर्देश जारी करने की शक्ति है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क के अंतर्गत, भारतीय रिज़र्व बैंक को जनहित में अथवा बैंकिंग नीति के हित में बैंकिंग कंपनियों को निदेश जारी करने अथवा जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल अथवा बैंकिंग कंपनी के हितों के प्रतिकूल

तरीके से अथवा किसी बैंकिंग कंपनी का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने से रोकने की शक्ति प्राप्त है।

बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2017 ने आरबीआई को किसी भी बैंकिंग कंपनी को केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत होने पर डिफॉल्ट के संबंध में दिवालिया समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए निर्देश जारी करने (बीआर अधिनियम की धारा 35 ए) और तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान (बीआर अधिनियम की धारा 35 एबी) के संबंध में बैंकिंग कंपनियों को निर्देश जारी करने की शक्तियां प्रदान की हैं। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (धारा 35) के प्रावधानों के अंतर्गत पर्यवेक्षी शक्तियों के भाग के रूप में, आरबीआई को स्वयं अथवा केंद्र सरकार के कहने पर बैंकिंग कंपनियों का निरीक्षण करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। "इस प्रकार, मौद्रिक स्थिरता और आर्थिक विकास में सुधार के साथ-साथ जमाकर्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए, एक बैंकिंग कंपनी की भलाई का पता लगाने की एक समग्र जिम्मेदारी" को भारतीय रिज़र्व बैंक (जनता सहकारी बैंक लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य (एआईआर 1993 बॉम्बे 252)) के साथ छोड़ दिया गया है। केवल बैंक अधिनियम के वे प्रावधान जो बीआर अधिनियम की धारा 51 में उल्लिखित हैं, भारतीय स्टेट बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर लागू होंगे। सहकारी बैंकों के मामले में, बीआर अधिनियम के प्रावधानों का लागू होना उसी अधिनियम की धारा 56 में उल्लिखित संशोधनों के अधीन होगा।

एनबीएफसी का विनियमन और पर्यवेक्षण - कानूनी पृष्ठभूमि

गैर-बैंकों का विनियमन और पर्यवेक्षण उन महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है जो आरबीआई को सौंपा गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45जेडए में प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी को ऐसे गैर-बैंकिंग वित्तीय कारोबार शुरू करने से पहले आरबीआई से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने और सरकारी राजपत्र में आरबीआई द्वारा विनिर्दिष्ट निवल स्वाधिकृत निधि रखने का अधिदेश दिया गया है। इसके अलावा, गैर-बैंकों के विनियमन और पर्यवेक्षण के एक भाग के रूप में, आरबीआई को गैर-बैंकिंग संस्थानों द्वारा निधि जमा करने की मांग करने वाले प्रॉस्पेक्टस या विज्ञापनों के मामलों को विनियमित या प्रतिबंधित करने के लिए सांविधिक शक्तियां (आरबीआई अधिनियम की धारा 45जे), नीति निर्धारित करने और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को निर्देश जारी करने की शक्ति, आदि (आरबीआई अधिनियम की धारा 45जेए) प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45-एल के अंतर्गत सूचना मांगने तथा उसमें उल्लिखित कारणों के संबंध में वित्तीय संस्थाओं को निर्देश जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। गैर-बैंकों पर पर्यवेक्षी नियंत्रण के भाग के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-एन के अंतर्गत गैर-बैंकिंग संस्थाओं का निरीक्षण करने की शक्ति प्राप्त है। 2019 में वित्त अधिनियम संशोधन के अनुसरण में, आरबीआई को एनबीएफसी के बोर्ड से एक निदेशक को हटाने (धारा 45 आईडी) और/या एनबीएफसी के बोर्ड को अधिक्रमित करने का अधिकार दिया गया है यदि बैंक संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में या जमाकर्ताओं या लेनदारों के हितों के लिए हानिकारक तरीके से एनबीएफसी के मामलों को रोकने के लिए (धारा 45 आईइ)। बैंक, उपर्युक्त के अलावा, वित्तीय स्थिरता के हित में, एनबीएफसी को विभिन्न इकाइयों (धारा 45 एमबीए) में समामेलित या पुनर्निर्माण या विभाजित कर सकता है। ऐसे परिदृश्य में, बैंक एक ब्रिज इंस्टीट्यूशन, योजना के तहत बनाई गई अस्थायी संस्थागत व्यवस्था भी स्थापित कर सकता है, ताकि एनबीएफसी की गतिविधियों की निरंतरता को संरक्षित किया जा सके जो वित्तीय प्रणाली के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण हैं।

सहकारी बैंकों का विनियमन और पर्यवेक्षण – कानूनी पृष्ठभूमि

भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार, संघ और राज्य की विधायी शक्तियां संविधान की सातवीं अनुसूची की क्रमशः तीन सूचियों अर्थात् संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में दी गई हैं। सहकारी समितियों के निगमन, विनियमन और समापन से संबंधित प्रविष्टि राज्य सूची में आती है जबकि बैंकिंग से संबंधित प्रविष्टि संघ सूची में आती है। इसके परिणामस्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा सहकारी बैंकों पर अधिकार क्षेत्र का दोहरा नियंत्रण होता है।

जनता सहकारी बैंक लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना है कि "हालांकि सहकारी समिति के प्रबंधन पर नियंत्रण जहां यह सहकारी बैंकिंग सोसाइटी है या अन्यथा सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार में निहित है, लेकिन जहां तक बैंकिंग का संबंध है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 56 के आधार पर, (ग) पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 35क के साथ पठित 1949 के प्रावधानों के अनुसार यह एक ऐसा विषय होगा जिसके साथ भारतीय रिज़र्व बैंक को पूर्ण शक्ति प्राप्त है।

बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 (जिसने 27 जून, 2020 को प्रख्यापित बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश 2020 की जगह ली) ने सहकारी बैंकों पर इसकी प्रयोज्यता के संबंध में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन किया। इस संशोधन के आधार पर, बैंकों के प्रबंधन और कामकाज पर नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों सहित बीआर अधिनियम के कुछ प्रावधान अर्थात् धारा 10, 10ए, 10बी, 10बीबी, 10सी, 10डी, 35बी आदि सहकारी बैंकों पर लागू किए गए थे, जो पहले लागू नहीं थे। किन्हीं अन्य कानूनों के साथ किसी प्रकार के विरोध की स्थिति में इसके अंतर्गत प्रावधानों को प्रधानता देने के लिए धारा 56 को भी संशोधित किया गया है। संशोधित अधिनियम में कहा गया है कि बीआर अधिनियम प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और सहकारी समितियों पर लागू नहीं होगा, जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि विकास के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण है, यदि ये समितियां अपने नाम पर या अपने व्यवसाय के संबंध में 'बैंक', 'बैंकर' या 'बैंकिंग' शब्दों का उपयोग नहीं करती हैं और चेक के अदाकर्ता के रूप में कार्य नहीं करती हैं। संशोधित अधिनियम में प्रावधान है कि सहकारी बैंक अपने सदस्यों या अपने परिचालन क्षेत्र में रहने वाले किसी अन्य व्यक्ति को अंकित मूल्य पर या प्रीमियम पर इक्विटी शेयर, अधिमान शेयर या विशेष शेयर जारी कर सकता है। इसके अलावा, यह भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के पूर्व अनुमोदन और आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट किसी भी अन्य शर्तों के अधीन ऐसे व्यक्तियों को दस या अधिक वर्षों की परिपक्वता के साथ असुरक्षित डिबेंचर या बांड या इसी तरह की प्रतिभूतियां जारी कर सकता है। संशोधित अधिनियम में कहा गया है कि किसी राज्य की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत सहकारी बैंक के मामले में, आरबीआई को संबंधित राज्य सरकार के साथ परामर्श के बाद निदेशक मंडल को अधिक्रमित करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, धारा 53क को नया अंतस्थापित किया गया है और सहकारी बैंकों पर लागू किया गया है, जिसके द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक किसी सहकारी बैंक अथवा सहकारी बैंकों के किसी वर्ग को अधिसूचना के माध्यम से ऐसी समयावधि और ऐसी शर्तों के अधीन जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अधिनियम के कतिपय प्रावधानों से छूट दे सकता है। जैसा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 49बी और 49सी को बैंकिंग विनियमन (संशोधित) अधिनियम, 2020 के बाद सहकारी बैंकों पर लागू किया गया है, सहकारी बैंक के नाम या उपनियमों में किसी भी बदलाव के लिए रिज़र्व बैंक से लिखित

प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है, जिसमें सहकारी समितियों के केंद्रीय/राज्य रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदन से पहले अनापत्ति की पुष्टि की जाती है।

डेरिवेटिव, मनी मार्केट इंस्ट्रुमेंट्स में लेनदेन का विनियमन - कानूनी पृष्ठभूमि

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में संशोधन करके 09 जनवरी, 2007 से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम में अध्याय III-डी अंतस्थापित किया गया था। उक्त अध्याय में, भारत की संसद ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा व्युत्पन्न, मुद्रा बाजार लिखतों, प्रतिभूतियों आदि से संबंधित लेनदेन के विनियमन से संबंधित प्रावधानों को प्रस्तुत करना उचित समझा। आरबीआई अधिनियम की धारा 45यू की उप-धारा (ए) व्युत्पन्न को भविष्य की तारीख में तय किए जाने वाले एक साधन के रूप में परिभाषित करती है, जिसका मूल्य ब्याज दर, विदेशी विनिमय दर, क्रेडिट रेटिंग या क्रेडिट सूचकांक, प्रतिभूतियों की कीमत (जिसे 'अंतर्निहित' भी कहा जाता है) में परिवर्तन से प्राप्त होता है, या उनमें से एक से अधिक के संयोजन और ब्याज दर स्वैप शामिल हैं, वायदा दर करार, विदेशी मुद्रा स्वैप, विदेशी मुद्रा-रुपया स्वैप, विदेशी मुद्रा विकल्प, विदेशी मुद्रा रुपया विकल्प या ऐसे अन्य लिखत जो समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। इसी प्रकार, मुद्रा बाजार लिखतों को कॉल या नोटिस मनी, मीयादी निधि, रेपो, रिवर्स रेपो, जमा प्रमाणपत्र, वाणिज्यिक उपयोग बिल, वाणिज्यिक पत्र और एक वर्ष तक मूल या प्रारंभिक परिपक्वता के ऐसे अन्य ऋण लिखतों को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है जैसा कि आरबीआई समय-समय पर निर्दिष्ट करता है। अभिव्यक्ति "प्रतिभूतियों" को केंद्र सरकार या राज्य सरकार की प्रतिभूतियों या केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट स्थानीय प्राधिकारी की प्रतिभूतियों के रूप में परिभाषित किया गया है और कॉर्पोरेट बांड और डिबेंचर को शामिल करने के लिए 'रेपो' और 'रिवर्स रेपो' के उद्देश्य से। व्युत्पन्न, मुद्रा बाजार लिखतों आदि में लेनदेन को विनियमित करने के लिए आरबीआई की शक्ति आरबीआई अधिनियम की धारा 45डबल्यू के तहत प्रदान की गई है, जिसमें कहा गया है कि आरबीआई, सार्वजनिक हित में या देश की वित्तीय प्रणाली को अपने लाभ के लिए विनियमित करने के लिए, ब्याज दरों या ब्याज दर उत्पादों से संबंधित नीति निर्धारित कर सकता है और सभी एजेंसियों या उनमें से किसी को उस संबंध में निर्देश दे सकता है, प्रतिभूतियों, मुद्रा बाजार लिखतों, विदेशी मुद्रा, व्युत्पाद, या इसी तरह की प्रकृति के अन्य उपकरणों में काम करना, जैसा कि आरबीआई समय-समय पर निर्दिष्ट कर सकता है। धारा 45वीं यह भी प्रदान करती है कि आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट व्युत्पन्न में लेनदेन वैध होंगे, यदि लेनदेन के लिए पार्टियों में से कम से कम एक पक्ष आरबीआई के नियामक दायरे में आने वाली इकाई है, इस प्रकार ऐसे अनुबंधों की कानूनी वैधता को निश्चितता प्रदान करता है।

भुगतान और निपटान कार्य - कानूनी पृष्ठभूमि

भारत की संसद ने भारत में भुगतान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए प्रदान करने और उस उद्देश्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को प्राधिकारी के रूप में नामित करने और उससे जुड़े या आकस्मिक मामलों के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 ('पीएसएस अधिनियम, 2007') को अधिनियमित किया। पीएसएस अधिनियम, 2007 की धारा 4 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्राधिकार के बिना भुगतान प्रणाली शुरू या प्रचालित नहीं करेगा। इसी प्रकार, पीएसएस अधिनियम, 2007 की धारा 8 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को किसी व्यक्ति को प्रदान किए गए प्राधिकार को रद्द करने की शक्ति है, यदि वह पीएसएस अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है अथवा

विनियमों का अनुपालन नहीं करता है अथवा आरबीआई द्वारा जारी आदेशों अथवा निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है अथवा उन शर्तों के विपरीत भुगतान प्रणाली का प्रचालन करता है जिनके अधीन प्राधिकार जारी किया गया था। पीएसएस अधिनियम, 2007 के अध्याय IV के प्रावधानों के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक को भुगतान प्रणालियों का विनियमन और पर्यवेक्षण प्रदान किया गया है। विनियामक और पर्यवेक्षी नियंत्रणों में संदाय प्रणालियों के कार्यकरण के लिए मानक निर्धारित करने की शक्ति, विवरणी, दस्तावेज अथवा अन्य सूचना मंगाने की शक्ति, भुगतान प्रणाली में प्रवेश करने और निरीक्षण करने की शक्ति, लेखा परीक्षा और निरीक्षण करने की शक्ति, निदेश जारी करने की शक्ति आदि शामिल हैं।

क्रेडिट सूचना कंपनियों का विनियमन कार्य

रिज़र्व बैंक को ऋण सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत ऋण सूचना कंपनियों के विनियमन और पर्यवेक्षण का कार्य सौंपा गया है। तीन संस्थान अधिनियम के आवश्यक स्तंभ हैं, अर्थात् क्रेडिट सूचना कंपनियां, क्रेडिट संस्थान और निर्दिष्ट उपयोगकर्ता। अधिनियम रिज़र्व बैंक को ऋण सूचना कंपनियों को निर्देश जारी करने और उनका निरीक्षण करने का अधिकार देता है। ऋण सूचना कंपनियों के कामकाज के संबंध में नीति निर्धारित करने के लिए रिज़र्व बैंक को क़ानून द्वारा भी अधिकृत किया गया है।

उपभोक्ता संरक्षण और संवर्धन कार्य - कानूनी पृष्ठभूमि

जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना भारतीय रिज़र्व बैंक के महत्वपूर्ण अधिदेशों में से एक है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 आदि के विभिन्न प्रावधानों *जमाकर्ताओं के हित में* जहां कहीं भी यह भारतीय रिज़र्व बैंक को शक्तियां सौंपता है, जैसे वाक्यांशों से भरे पड़े हैं। जमाकर्ताओं के अलावा, अपनी विनियमित संस्थाओं के साथ काम करने वाले ग्राहकों की शिकायतों का समाधान भी भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों, एनबीएफसी और भुगतान प्रणालियों के परिचालन को कवर करने के लिए तीन लोकपाल योजनाएं तैयार की हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने अपनी तीन पूर्ववर्ती लोकपाल योजनाओं अर्थात् (i) बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006, (ii) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018, और (iii) डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना, 2019 को 12 नवंबर, 2021 से एक योजना - 'रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 (योजना/RB-IOS, 2021)' में एकीकृत किया। यह योजना बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों (पीएसपी) और क्रेडिट सूचना कंपनियों जैसी विनियमित संस्थाओं (आरई) के ग्राहकों को एक केंद्रीकृत संदर्भ बिंदु पर अपनी शिकायतें दर्ज करने में सक्षम बनाकर आरबीआई में शिकायत निवारण प्रक्रिया को सरल बनाती है। इस योजना का उद्देश्य आरई की ओर से सेवा में कमी वाली ग्राहक शिकायतों का त्वरित, लागत प्रभावी और संतोषजनक तरीके से समाधान करना है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अपनी संवर्धनात्मक और विकासात्मक भूमिकाओं को अत्यधिक महत्व देता है। आरबीआई अधिनियम की धारा 17 के खंड (8एए) में कहा गया है कि किसी भी वित्तीय संस्थान को बढ़ावा देना, स्थापित करना, समर्थन करना - चाहे वह उसकी सहायक कंपनी हो या अन्यथा, एक व्यवसाय है जिसे रिज़र्व बैंक द्वारा किया जा सकता है। उस अधिनियम की धारा 54 ग्रामीण विकास के मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक की विकासात्मक भूमिका की ओर इशारा करती है। इसमें प्रावधान है कि रिज़र्व बैंक ग्रामीण ऋण और विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ स्टाफ रख सकता है और विशेष रूप से यह (i) राष्ट्रीय बैंक को विशेषज्ञ मार्गदर्शन और सहायता दे सकता है; और (ii) ऐसे क्षेत्रों में

विशेष अध्ययन करना जो एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए ऐसा करना आवश्यक समझे।

फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम 2011 - अधिनियम प्राप्तियों के असाइनमेंट के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है, जिसमें शामिल सभी पक्षों के अधिकारों और दायित्वों को रेखांकित किया जाता है। आरबीआई की भूमिका में कारकों को विनियमित और पर्यवेक्षण करना, कारकों को निर्देश जारी करना और उनसे जानकारी एकत्र करना शामिल है।

एमएसएमई अधिनियम 2006 - अधिनियम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने और विकास को सुविधाजनक बनाने और उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए प्रदान करता है। अधिनियम के प्रावधानों में कहा गया है कि आरबीआई का एक वरिष्ठ अधिकारी, जो कार्यपालक निदेशक के पद से नीचे का नहीं है, को एमएसएमई के लिए राष्ट्रीय बोर्ड में शामिल किया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि एमएसएमई क्षेत्र के लिए नीति-निर्माण प्रक्रिया में आरबीआई की महत्वपूर्ण भूमिका है। आरबीआई एमएसएमई को ऋण के सुचारू प्रवाह के लिए जिम्मेदार है, ताकि ऐसे उद्यमों के बीच रुग्णता की घटनाओं को कम किया जा सके और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया जा सके।

निष्कर्ष

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 तथा राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 में संशोधनों के परिणामस्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक की शक्तियों और कार्यों में और विस्तार हुआ है। सरफेसी अधिनियम के प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक को आस्ति पुनर्गठन कंपनियों के विनियमन और पर्यवेक्षण के संबंध में सशक्त बनाते हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के प्रावधानों में वर्ष 2019 में किए गए संशोधनों ने आवास वित्त कंपनियों पर कुछ नियामक शक्तियों को राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) से भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को हस्तांतरित कर दिया। तदनुसार, एचएफसी को विनियामक उद्देश्यों के लिए एनबीएफसी की श्रेणियों में से एक के रूप में माना जा रहा है। संशोधन के परिणामस्वरूप, आरबीआई ने आरबीआई अधिनियम और एनएचबी अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एनबीएफसी-एचएफसी को निर्देश जारी किए हैं। परिवर्तन का उद्देश्य आवास वित्त क्षेत्र की स्थिरता और दक्षता को बढ़ाना है।

यद्यपि, भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना का उद्देश्य और उद्देश्य, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की प्रस्तावना में देखा जा सकता है, बैंक नोटों के निर्गम को विनियमित करना और मौद्रिक स्थिरता सुनिश्चित करने की दृष्टि से भंडार रखना और विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से मौद्रिक नीति तैयार करना है। विभिन्न विधानों के माध्यम से आरबीआई को सौंपे गए विविध कार्य बताते हैं कि देश के केंद्रीय बैंक के पास आरबीआई अधिनियम, 1934 की प्रस्तावना में संक्षेप में दिए गए जनादेश की तुलना में बहुत व्यापक जनादेश हैं। बैंकों, गैर-बैंकों, सहकारी बैंकों का विनियमन और पर्यवेक्षण, मुद्रा का प्रबंधन, संघ और राज्य के लोक ऋण का प्रबंधन, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन, बैंकों के लिए बैंकर के रूप में कार्य करना, सरकारों के लिए बैंकर, जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा, वित्तीय साक्षरता का प्रसार आदि सभी आरबीआई अधिनियम, 1934 की प्रस्तावना में निहित सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने का हिस्सा हैं।

अध्याय 3: मौद्रिक नीति ढांचा

I. भारत में मौद्रिक नीति निर्माण

परिभाषा, उद्देश्य और उपकरण

दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों की स्थापना मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए की गई थी। उनके पास मुद्रा जारी करने और सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करने जैसे कई अन्य कार्य भी थे, लेकिन समय के साथ मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता केंद्रीय बैंकों का मुख्य उद्देश्य बनी रही। केंद्रीय बैंकों के कार्यों को कानून में लिखा गया ताकि उन्हें अपने दायित्वों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए सशक्त बनाया जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, जिसमें रिजर्व बैंक का व्यापक उद्देश्य मूल प्रस्तावना में इस प्रकार वर्णित है: “भारतीय रिजर्व बैंक का गठन करना इस दृष्टि से उपयुक्त है कि भारत में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने की दृष्टि से बैंकनोटों के निर्गम को विनियमित तथा प्रारक्षित निधि को बनाए रखा जा सके और सामान्य रूप से देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली संचालित किया जा सके।”

मौद्रिक नीति का तात्पर्य केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में मौद्रिक साधनों के उपयोग से है, जिनके माध्यम से ब्याज दरों, मुद्रा आपूर्ति और ऋण की उपलब्धता जैसे चर को प्रभावित किया जाता है, ताकि नीति के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। इसी के अनुसार, मौद्रिक नीति के उद्देश्यों का विकास मूल्य स्थिरता बनाए रखने और अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों में ऋण के पर्याप्त प्रवाह को सुनिश्चित करने के रूप में हुआ। आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण के बढ़ते प्रभाव के साथ, वित्तीय बाजारों में सुव्यवस्थित परिस्थितियों को बनाए रखना एक अतिरिक्त नीति उद्देश्य बन गया। इस प्रकार, समय के साथ, भारत में मौद्रिक नीति की भूमिका मूल्य स्थिरता, आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता के बीच एक संतुलन बनाए रखने के लिए विकसित हुई। हालांकि, मई 2016 में आरबीआई अधिनियम, 1934 में संशोधन के बाद, मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य मूल्य स्थिरता बनाए रखना है, जबकि विकास के उद्देश्य को भी ध्यान में रखा गया है। संशोधित प्रस्तावना इस प्रकार है:

“भारत में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने की दृष्टि से बैंकनोटों के निर्गम को विनियमित करना तथा प्रारक्षित निधि को बनाए रखना और सामान्य रूप से देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली संचालित करना,”

“और चूंकि एक तेजी से जटिल होती अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक आधुनिक मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क आवश्यक है;

और चूंकि मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य मूल्य स्थिरता बनाए रखना है, जबकि विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखना भी अनिवार्य है।”

II. भारत में मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क का विकास

मौद्रिक नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक सुसंगत नीति ढांचे का होना आवश्यक है। व्यापक रूप से, मौद्रिक नीति ढांचा उद्देश्यों, संचालन प्रक्रिया और शासन व्यवस्था से मिलकर बना होता है।

- उद्देश्य मौद्रिक नीति के लक्ष्य होते हैं, जो दीर्घकालिक होते हैं और सामान्यतः केंद्रीय बैंक के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं होते। इसलिए, केंद्रीय बैंक इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उन उपकरणों का उपयोग करते हैं जो उनके प्रत्यक्ष नियंत्रण में होते हैं, या वे मध्यवर्ती और संचालन लक्ष्यों को अप्रत्यक्ष रूप से लक्षित करते हैं, जो अंतिम उद्देश्यों के साथ स्थिर संबंध रखते हैं। संचालन लक्ष्य का चयन महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह मौद्रिक संचरण तंत्र की प्रक्रिया की शुरुआत का संकेत

देता है। इसी तरह, मध्यवर्ती लक्ष्यों का चयन संचरण के चैनलों पर निर्भर करता है – यानी वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से मौद्रिक नीति की कार्यवाहियां अंतिम उद्देश्यों को प्रभावित करती हैं।

- संचालन प्रक्रिया मुख्य रूप से इस बात से संबंधित है कि केंद्रीय बैंक अपने तरलता प्रबंधन परिचालनों के माध्यम से संचालन लक्ष्य और फिर मध्यवर्ती लक्ष्य को कैसे प्रभावित करने का इरादा रखता है। इसलिए, संचालन प्रक्रिया मूलतः मौद्रिक नीति के समग्र दृष्टिकोण के अनुरूप तरलता स्थितियों का दैनिक प्रबंधन है। इसे मौद्रिक नीति का "नट्स और बोल्ट्स" या "वास्तुकला की प्लंबिंग" भी कहा जाता है (पात्रा एट अल., 2016)।
- शासन व्यवस्था मुख्य रूप से निर्णय लेने की प्रक्रिया से संबंधित है और मौद्रिक प्राधिकरण की जिम्मेदारियों, शक्तियों और उत्तरदायित्वों पर ध्यान केंद्रित करती है।

वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक रूप से बैंक रिजर्व और अल्पकालिक ब्याज दरें दो प्रमुख संचालन लक्ष्यों के रूप में विकसित हुई हैं। हालांकि, 1990 के दशक की शुरुआत में, बाजार आधारित मौद्रिक नीति ढांचे को अपनाने के साथ ध्यान अल्पकालिक ब्याज दरों पर केंद्रित हो गया, जो नियमन मुक्त वातावरण में विकसित होते बाजारों के कारण मौद्रिक संचरण तंत्र में ब्याज दरों के बढ़ते महत्व को दर्शाता है। इसके परिणामस्वरूप, ओवरनाइट रेट मौद्रिक नीति के संचालन में सबसे सामान्य रूप से अपनाया जाने वाला संचालन लक्ष्य बन गई।

भारत का मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क वर्षों में कई बदलावों से गुजरा है, जो अंतर्निहित मैक्रोइकोनॉमिक और वित्तीय परिस्थितियों को दर्शाता है। 1971-1985 के दौरान, राजकोषीय घाटे का मुद्रीकरण मौद्रिक नीति के संचालन पर प्रमुख प्रभाव डालता था। सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा संसाधनों की प्राथमिकता और उच्च सार्वजनिक व्यय के मुद्रास्फीति प्रभावों ने मौद्रिक विस्तार के द्वितीयक प्रभावों को निष्प्रभावी करने के लिए बार-बार नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) का सहारा लेना आवश्यक बना दिया। ब्याज दर नियंत्रण, सांविधिक प्राथमिकताएं और निर्देशित ऋण के रूप में वित्तीय दमन ने आंशिक रूप से निजी क्षेत्र को ऋण बाजार से बाहर कर दिया। इसी पृष्ठभूमि में, मौद्रिक प्रणाली के कार्य की समीक्षा के लिए गठित समिति (अध्यक्ष: डॉ. सुकमय चक्रवर्ती, 1985) ने एक नई मौद्रिक नीति ढांचे की सिफारिश की। इस ढांचे में फीडबैक के साथ मौद्रिक लक्ष्य निर्धारण को आधार बनाया गया, जो मुद्रा की मांग के लिए एक स्थिर कार्य का अनुभवजन्य प्रमाण प्रदान करता है।

मौद्रिक लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्क

इस फ्रेमवर्क के तहत, व्यापक मुद्रा (ब्रॉड मनी) को मध्यवर्ती लक्ष्य बनाया गया, जबकि आरक्षित मुद्रा (रिजर्व मनी) व्यापक मुद्रा की वृद्धि पर नियंत्रण पाने के लिए मुख्य संचालन उपकरणों में से एक थी। इसके अनुसार, मौद्रिक (एम3) प्रक्षेपण को संभावित वास्तविक जीडीपी वृद्धि और सहनीय मुद्रास्फीति स्तर के अनुरूप बनाया गया। तकनीकी रूप से, यदि अपेक्षित वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6 प्रतिशत थी, मुद्रा की मांग के लिए आय लोच 1.5 थी, और सहनीय मुद्रास्फीति 5 प्रतिशत थी, तो एम3 वृद्धि का लक्ष्य 14 प्रतिशत निर्धारित किया गया था:

एम3 वृद्धि = $1.5(6) + 5 = 14$ प्रतिशत (मोहंती, 2010)। यह फ्रेमवर्क 1980 के दशक के मध्य से 1997-98 तक प्रभावी था। मौद्रिक लक्ष्य निर्धारण प्रणाली के दौरान मुद्रा वृद्धि के परिणामों का विश्लेषण दर्शाता है कि लक्ष्यों को शायद ही कभी प्राप्त किया गया। मौद्रिक लक्ष्य निर्धारण के सबसे बड़े अवरोधक में से एक था केंद्रीय सरकार को आरबीआई के क्रेडिट पर नियंत्रण की कमी, जो रिजर्व मनी के निर्माण का अधिकांश हिस्सा था। 1990 के दशक में आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के साथ, सरकार और वाणिज्यिक क्षेत्र को वित्तपोषित करने के लिए बाजार आधारित ब्याज दरों और विनिमय दर पर बढ़ती निर्भरता

के साथ बदलाव आया। आरबीआई प्रत्यक्ष उपकरणों से हटकर अप्रत्यक्ष बाजार आधारित उपकरणों पर आ गई। 1997 तक सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) और नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) को क्रमशः शुद्ध मांग और समय देयताओं (एनडीटीएल) के 25 प्रतिशत और 9.5 प्रतिशत तक घटा दिया गया। इसके अलावा, 1990 के दशक में व्यापार और वित्तीय उदारीकरण की गति तेज होने के साथ, मध्यवर्ती लक्ष्य के रूप में व्यापक मुद्रा की प्रभावशीलता का पुनर्मूल्यांकन किया गया। वित्तीय नवाचारों और पूंजी प्रवाह में उतार-चढ़ाव, विनिमय दर की अस्थिरता और वैश्विक व्यापार चक्रों से उत्पन्न बाहरी झटकों ने मुद्रा की मांग को अस्थिर बना दिया। साथ ही, ब्याज दर और विनिमय दर की मात्रा चर की तुलना में बढ़ती महत्वता के साथ मौद्रिक नीति के अंतर्निहित संचरण तंत्र में बदलाव के प्रमाण मिले। इसी पृष्ठभूमि में, भारत में एक वैकल्पिक मौद्रिक ढांचे की खोज 1998-99 में "एकाधिक संकेतक दृष्टिकोण" पर स्विच करने के बाद समाप्त हुई।

एकाधिक संकेतक दृष्टिकोण

आरबीआई ने अप्रैल 1998 में 'एकाधिक संकेतक दृष्टिकोण' को अपनाया, जिसमें मौद्रिक नीति निर्माण के लिए मात्रात्मक उपकरणों की तुलना में दर-आधारित चैनलों पर अधिक जोर दिया गया। इस दृष्टिकोण के तहत, मौद्रिक नीति परिप्रेक्ष्य तैयार करने के लिए कई मात्रात्मक चर जैसे मुद्रा, ऋण, उत्पादन, व्यापार, पूंजी प्रवाह और राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ दर आधारित चर जैसे विभिन्न बाजारों में प्रतिफल की दरें, मुद्रास्फीति दर और विनिमय दर का विश्लेषण किया गया। 2000 के दशक की शुरुआत से इस दृष्टिकोण को आरबीआई के औद्योगिक दृष्टिकोण, ऋण स्थितियों, क्षमता उपयोग, पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं, मुद्रास्फीति अपेक्षाओं और उपभोक्ता विश्वास से संबंधित सर्वेक्षणों से प्राप्त अग्रदृष्टि संकेतकों द्वारा सुदृढ़ और निर्देशित किया गया। हालांकि, आरबीआई ने प्रमुख मौद्रिक समुच्चयों के सांकेतिक प्रक्षेपण जारी रखना जारी रखा, क्योंकि मुद्रा को एक महत्वपूर्ण सूचना चर माना गया।

1998-99 से 2008-09 तक, 'एकाधिक संकेतक दृष्टिकोण' ने औसतन 7.1 प्रतिशत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर और थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) दोनों के संदर्भ में लगभग 5.5 प्रतिशत की औसत मुद्रास्फीति के साथ अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि, इसके बाद उच्च मुद्रास्फीति और कमजोर विकास की सह-अस्तित्व जैसी स्थितियों के कारण, जिसे "स्टैगफ्लेशन" के स्पष्ट संकेत माना गया, इस ढांचे की प्रभावशीलता और यहां तक कि इसकी विश्वसनीयता पर सार्वजनिक बहस बढ़ने लगी। संकेतकों के एक बड़े पैनल का उपयोग भी मौद्रिक नीति के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित नाममात्र एंकर प्रदान करने में विफल रहा। यह नीति विश्लेषकों के लिए यह समझना कठिन बना देता था कि आरबीआई नीति निर्णय लेते समय किन कारकों पर ध्यान देता है। वास्तव में, 2007 के बाद से भारत में कई उच्चस्तरीय समितियों ने यह उजागर किया कि आरबीआई को मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण की ओर स्थानांतरित होने पर विचार करना चाहिए।

लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण

इस संदर्भ में, रिजर्व बैंक ने 12 सितंबर, 2013 को मौद्रिक नीति ढांचे को संशोधित और मजबूत करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष: डॉ. उर्जित आर. पटेल) का गठन किया, जिसका उद्देश्य मौजूदा मौद्रिक नीति ढांचे को संशोधित और मजबूत करने के लिए आवश्यक कदमों की सिफारिश करना था, ताकि इसे, अन्य बातों के अलावा, पारदर्शी और अनुमानित बनाया जा सके। विशेषज्ञ समिति ने जनवरी 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और भारत में मौद्रिक नीति के रूप में लचीले मुद्रास्फीति

लक्ष्यीकरण (एफआईटी) ढांचे को अपनाने की दिशा में कदम बढ़ाने की शुरुआत की। एफआईटी ढांचे में, मौद्रिक नीति (रेपो) दर को मौजूदा और विकसित हो रहे आर्थिक परिदृश्य के आकलन के आधार पर निर्धारित किया जाता है (आरबीआई, 2014)। इसका उद्देश्य व्यावसायिक चक्र के दौरान औसतन मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करना है, जबकि अल्पावधि में वृद्धि की चिंताओं को ध्यान में रखा जाता है। एक बार जब रेपो दर की घोषणा कर दी जाती है, तो आरबीआई द्वारा डिज़ाइन किया गया संचालन ढांचा दैनिक आधार पर तरलता प्रबंधन को लागू करता है। इसका लक्ष्य संचालन लक्ष्य—वेटेड एवरेज कॉल मनी रेट (डब्ल्यूएसीआर)—को रेपो दर के आसपास बनाए रखना होता है। मौद्रिक नीति के परिचालन ढांचे का विवरण अगले अध्याय "बाजार संचालन" में विस्तृत रूप से दिया गया है। धन बाजार दरों में इन परिवर्तनों का प्रभाव पूरे वित्तीय तंत्र पर पड़ता है, जो बदले में समग्र मांग को प्रभावित करता है – जो मुद्रास्फीति और विकास का एक प्रमुख निर्धारक है।

मई 2016 में आरबीआई अधिनियम में संशोधन से पहले, उपरोक्त समिति द्वारा अनुशंसित लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण ढांचा भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के बीच फरवरी 2015 में हुए एक समझौते द्वारा संचालित था। मई 2016 में आरबीआई अधिनियम के संशोधन ने इस लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण ढांचे को लागू करने के लिए कानूनी आधार प्रदान किया। संशोधित अधिनियम के अनुसार मुद्रास्फीति का लक्ष्य संपूर्ण भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के संदर्भ में परिभाषित किया जाएगा और यह लक्ष्य भारत सरकार द्वारा आरबीआई से परामर्श कर हर पांच वर्षों में एक बार तय किया जाएगा। मुद्रास्फीति लक्ष्य प्राप्त करने में विफलता तब मानी जाती है जब (क) औसत मुद्रास्फीति किसी भी तीन लगातार तिमाहियों के लिए लक्ष्य की ऊपरी सहनशीलता सीमा (6%) से अधिक हो जाती है, या (ख) औसत मुद्रास्फीति किसी भी तीन लगातार तिमाहियों के लिए निचली सहनशीलता सीमा (2%) से कम हो जाती है। मुद्रास्फीति लक्ष्य प्राप्त करने में विफलता की स्थिति में, आरबीआई को भारत सरकार को एक रिपोर्ट सौंपनी होती है जिसमें (क) विफलता के कारण, (ख) प्रस्तावित सुधारात्मक कदम, और (ग) मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने की अनुमानित समयावधि का उल्लेख होता है। 2022 में पहली बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, जब लगातार तीन तिमाहियों तक मुद्रास्फीति 6% के ऊपरी सहनशीलता स्तर से ऊपर रही। इसके परिणामस्वरूप, नवंबर 2022 में मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने सरकार को रिपोर्ट भेजी। संशोधित अधिनियम के अनुसार, आरबीआई को हर छह महीने में एक मौद्रिक नीति रिपोर्ट प्रकाशित करनी होती है, जिसमें (क) मुद्रास्फीति के स्रोतों का विवरण, और (ख) अगले 6 से 18 महीनों की मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान शामिल होता है। संशोधित आरबीआई अधिनियम जून 2016 में प्रभावी हुआ। इसके तहत, भारत सरकार ने अगस्त 2016 में आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी की, जिसमें 5 अगस्त 2016 से 31 मार्च 2021 की अवधि के लिए 4% CPI मुद्रास्फीति लक्ष्य, 6% की ऊपरी सहनशीलता सीमा और 2% की निचली सहनशीलता सीमा को निर्धारित किया।

संशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB के अनुसार, केंद्र सरकार को मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के गठन के लिए राजपत्र में अधिसूचना जारी करनी होती है। इसी के तहत, 29 सितंबर 2016 को एक छह-सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया जिसमें 3 आंतरिक सदस्य तथा 3 बाहरी सदस्य थे। इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नीतिगत दर निर्धारित करना है। संशोधित अधिनियम के तहत, एमपीसी को साल में कम से कम 4 बार बैठक करनी होती है। बाहरी सदस्य 4 वर्षों के लिए नियुक्त किए जाते हैं। प्रत्येक सदस्य के पास 1 वोट होता है। यदि मतदान में बराबरी (टाई) की स्थिति आती है, तो आरबीआई गवर्नर के पास दूसरा या निर्णायक वोट होता है। प्रत्येक बैठक के बाद, एमपीसी द्वारा अपनाया गया प्रस्ताव अधिनियम के अध्याय III-F के प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित किया जाता है। नीति घोषणा के 14वें दिन, एमपीसी बैठक की कार्यवाही के मिनट्स प्रकाशित किए जाते हैं, जिनमें शामिल होते हैं (क) MPC द्वारा अपनाया

गया प्रस्ताव, (ख) प्रत्येक सदस्य का प्रस्ताव पर मतदान और उसके पीछे का तर्क और (ग) प्रस्ताव पर प्रत्येक सदस्य का बयान। अगस्त 2024 तक, एमपीसी ने अक्टूबर 2016 में अपनी पहली बैठक के बाद से कुल 50 बैठकें आयोजित की हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक का मौद्रिक नीति विभाग (एमपीडी) मौद्रिक नीति तैयार करने में मौद्रिक नीति समिति की सहायता करता है। नीति दर निर्णय लेने की प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था के प्रमुख हितधारकों के विचार और भारतीय रिज़र्व बैंक का विश्लेषणात्मक कार्य शामिल होते हैं। वित्तीय बाजार समिति दैनिक बैठक करती है ताकि तरलता और वित्तीय बाजार की स्थितियों की समीक्षा की जा सके। वित्तीय बाजार संचालन विभाग MPC द्वारा लिए गए मौद्रिक नीति निर्णयों को लागू करता है। इसका मुख्य कार्य दैनिक तरलता प्रबंधन संचालन के माध्यम से सुनिश्चित करना है कि संचालन लक्ष्य) – यानी भारतीय मुद्रा बाजार दर (डब्ल्यूएसीआर) – को नीति रेपो दर के करीब रखा जाए।

जैसा कि ऊपर समझाया गया है, भारत में मौद्रिक नीति निर्माण समय के साथ विकसित हुआ है। पिछले तीन दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ते आकार और वित्तीय बाजारों के बढ़ते परिष्कार ने मौद्रिक लक्ष्य निर्धारण ढांचे से एक बहु-सूचक दृष्टिकोण और अंततः लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण (एफआईटी) को अपनाने की दिशा में धीरे-धीरे परिवर्तन को संभव बनाया है।

मौद्रिक नीति उपकरण:

भारत में मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए विभिन्न प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इन उपकरणों का संक्षेप में विवरण निम्नलिखित है:

1. रेपो दर

यह वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई, तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत प्रतिभागियों को सरकारी और अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों के विरुद्ध तरलता प्रदान करता है।

2. स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ)

यह वह दर है जिस पर आरबीआई, एलएएफ प्रतिभागियों से बिना प्रतिभूति के जमा स्वीकार करता है। यह दर पॉलिसी रेपो दर से 25 आधार अंक नीचे रखी जाती है (अगस्त 2024 के अनुसार)। अप्रैल 2022 में एसडीएफ की शुरुआत के साथ, इसने निश्चित रिवर्स रेपो दर को एलएएफ कॉरिडोर के निचले सीमा के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया।

3. मार्जिनल स्टैंडिंग सुविधा (एमएसएफ)

यह एक दंडात्मक दर है जिस पर बैंक अपनी वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) पोर्टफोलियो में से पूर्व-निर्धारित सीमा (अभी 2% तक, अगस्त 2024 के अनुसार) तक तरलता प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रणाली को अप्रत्याशित तरलता झटकों से बचाने के लिए एक सुरक्षा उपाय है। एमएसएफ दर पॉलिसी रेपो दर से 25 आधार अंक ऊपर रखी जाती है।

4. रिवर्स रेपो दर

यह वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बैंकों से पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के विरुद्ध तरलता अवशोषित करता है।

5. तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ)

एलएएफ के तहत, आरबीआई बैंकिंग प्रणाली में तरलता डालने/अवशोषित करने के लिए संचालन करता है। इसमें ओवरनाइट और टर्म रेपो/रिवर्स रेपो (स्थिर और परिवर्तनशील दर), एसडीएफ और एमएसएफ शामिल हैं।

6. एलएएफ कॉरिडोर

यह कॉरिडोर, एमएसएफ दर (ऊपरी सीमा) और एसडीएफ दर (निचली सीमा) के बीच होता है, जिसमें पॉलिसी रेपो दर बीच में होती है।

7. बैंक दर

यह वह दर है जिस पर आरबीआई एक्सचेंज बिलों या अन्य वाणिज्यिक दस्तावेजों को पुनर्खरीद या पुनः छूट देने को तैयार रहता है। यह दंडात्मक दर भी है, जिसका उपयोग बैंकों द्वारा आरक्षित आवश्यकताओं (सीआरआर और एसएलआर) को पूरा करने में विफलता के लिए किया जाता है। बैंक दर को एमएसएफ दर के साथ जोड़ा गया है और पॉलिसी रेपो दर में बदलाव के साथ यह स्वचालित रूप से बदलती है।

8. कैश रिज़र्व अनुपात (सीआरआर)

बैंक को रिज़र्व बैंक के पास अपनी कुल शुद्ध माँग और समय देनदारियों (एनडीटीएल) के निर्दिष्ट अनुपात (प्रतिशत) के रूप में एक निश्चित राशि रखना आवश्यक है, जो एक शनिवार से शुरू होकर अगले रिपोर्टिंग शुक्रवार तक के पखवाड़े के लिए होता है। यह आवश्यक अनुपात रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है। पखवाड़े के दौरान CRR बैलेंस का रखरखाव औसत दैनिक आधार पर किया जाता है, जिसमें रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित न्यूनतम दैनिक रखरखाव का पालन करना अनिवार्य होता है।

9. वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर)

भारत में प्रत्येक बैंक अपनी परिसंपत्तियों का रखरखाव करता है, जिनका मूल्य उसके भारत में कुल माँग और समय देनदारियों के ऐसे प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए, जो दूसरे पिछले पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार के आधार पर हो, जैसा कि रिज़र्व बैंक समय-समय पर सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकता है (अगस्त 2024 तक 18 प्रतिशत)। इन परिसंपत्तियों को अधिसूचना में निर्दिष्ट अनुसार बनाए रखा जाना चाहिए (आमतौर पर मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों, नकद और सोने में)।

10. ओपन मार्केट ऑपरेशन्स (ओएमओ)

इनमें पुनर्खरीद (रेपो या रिवर्स रेपो) परिचालन और सरकारी प्रतिभूतियों की प्रत्यक्ष खरीद और बिक्री दोनों शामिल हैं, जो क्रमशः तरलता के प्रवाह और अवशोषण के लिए होती हैं।

11. बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस)

मौद्रिक प्रबंधन के लिए इस उपकरण की शुरुआत 2004 में की गई थी। बड़े पैमाने पर पूंजी प्रवाह से उत्पन्न दीर्घकालिक अधिशेष तरलता को कम अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों की बिक्री के माध्यम से अवशोषित किया जाता

है। अधिशेष तरलता की प्रकृति (दीर्घकालिक/ अल्पकालिक) के आधार पर एमएसएस के तहत प्रतिभूतियां (दीर्घकालिक डेटेड प्रतिभूतियां/ अल्पकालिक सीएमबी) जारी की जाती हैं। इस प्रक्रिया में जुटाई गई नकदी को रिज़र्व बैंक के पास एक अलग सरकारी खाते में रखा जाता है।⁵

12. विदेशी मुद्रा स्वेप

यह प्रणालीगत तरलता को स्थायी आधार पर प्रबंधित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। स्वेप, रिज़र्व बैंक द्वारा एक साधारण बेचने/खरीदने वाले विदेशी मुद्रा स्वेप के रूप में होते हैं। एक बैंक रिज़र्व बैंक से अमेरिकी डॉलर बेचता/खरीदता है और स्वेप अवधि के अंत में समान मात्रा में अमेरिकी डॉलर खरीदने/बेचने पर सहमति करता है। रिज़र्व बैंक उपयुक्त खरीद/बिक्री स्वेप का संचालन करके प्रणालीगत तरलता की मात्रा को नियंत्रित कर सकता है।

अपरंपरागत मौद्रिक नीति उपकरण (यूएमपीटी)

वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को वास्तविक जीडीपी में तीव्र और स्थायी गिरावट का सामना करना पड़ा। इन अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंक पारंपरिक मौद्रिक नीति (जैसे नीति दरों में कटौती) पर पूरी तरह निर्भर नहीं रह सके क्योंकि नीति दर पर शून्य-निम्न सीमा (ज़ेडएलबी) का प्रतिबंध था। इस स्थिति ने उन्हें अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए अपरंपरागत मौद्रिक नीतियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। **अपरंपरागत मौद्रिक नीतियां मुख्य रूप से दो उपायों पर आधारित थीं - मात्रात्मक सहजता (क्यूई) और आगे की मार्गदर्शन।** मात्रात्मक सहजता केंद्रीय बैंकों द्वारा परिसंपत्ति खरीद कार्यक्रमों को संदर्भित करता है। इन उपायों ने केंद्रीय बैंकों की कुल परिसंपत्तियों में भारी वृद्धि की और उनकी परिसंपत्ति संरचना को बदल दिया। इसके विपरीत, पारंपरिक मौद्रिक नीतियों का केंद्रीय बैंकों की बैलेंस शीट पर नगण्य प्रभाव पड़ता है। **आगे की मार्गदर्शन** केंद्रीय बैंकों द्वारा संचार का उपयोग है, जिसमें भविष्य की नीतियों की दिशा के बारे में अपेक्षाओं को प्रबंधित किया जाता है। इसका उद्देश्य घरों और फर्मों के वित्तीय निर्णयों को प्रभावित करना है।

भारत में उपयोग किए गए अपरंपरागत मौद्रिक नीति उपकरण

कोविड-19 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक ने कई पारंपरिक और अपरंपरागत उपाय किए। इन उपायों में शामिल थे (i) उधार या दीर्घकालिक वित्तपोषण संचालन का विस्तार, जिसमें पुनर्वित्त के माध्यम से तरलता समर्थन शामिल था; (ii) परिसंपत्ति खरीद कार्यक्रम, जिसमें ऑपरेशन ट्विस्ट (ओटी) शामिल थे; और (iii) अग्रिम मार्गदर्शन, जिसके व्यापक रूपरेखा नीचे चर्चा की गई है।

(i) लिक्विडिटी सपोर्ट ऑपरेशंस

(क) **विस्तारित ऋण/दीर्घकालिक वित्तपोषण:** भारतीय रिज़र्व बैंक ने मौद्रिक नीति के संचरण को सुविधाजनक बनाने और ऋण वितरण का समर्थन करने के लिए फरवरी 2020 में दीर्घकालिक रेपो परिचालन (एलटीआरओ) शुरू किया। इस योजना के तहत, रिज़र्व बैंक ने बैंकों को पूर्ववर्ती नीति रेपो दर (5.15 प्रतिशत) पर दीर्घकालिक तरलता प्रदान की –

⁵ योजना की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं, अन्य बातों के अलावा: (i) इस योजना के तहत, सरकार प्रणाली से तरलता को अवशोषित करने के लिए, सामान्य उधारी आवश्यकताओं के अतिरिक्त, ट्रेजरी बिल और/या दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करती है; (ii) एमएसएस के तहत जारी ट्रेजरी बिल/दिनांकित प्रतिभूतियों में नियमित ट्रेजरी बिल और दिनांकित प्रतिभूतियों के सभी गुण होते हैं। ये प्रतिभूतियां सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर), रेपो और तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) के लिए पात्र होती हैं; (iii) एमएसएस के तहत जुटाई गई राशि को एक अलग पहचान योग्य नकद खाते, जिसे बाजार स्थिरीकरण योजना खाता (एमएसएस खाता) कहा जाता है, में रखा जाता है और इसका रखरखाव तथा संचालन रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है; (iv) एमएसएस खाते में जमा की गई राशि का उपयोग केवल एमएसएस के तहत जारी ट्रेजरी बिलों और/या दिनांकित प्रतिभूतियों के पुनर्खरीद और/या पुनर्खरीद (बाय बैक) के उद्देश्य से किया जा सकता है।

यह दर मौजूदा बाजार दरों और बैंकों की अपनी जमा लागत से कम थी – ताकि उनकी निधियों की लागत को कम किया जा सके। फरवरी-मार्च 2020 के दौरान, पांच एलटीआरओ नीलामियां आयोजित की गईं (प्रत्येक ₹25,000 करोड़ की, जिनमें से एक 1-वर्षीय और चार 3-वर्षीय अवधि की थीं), जिनसे प्रणाली की तरलता में ₹1,25,117 करोड़ की वृद्धि हुई। हालांकि, सितंबर 2020 में, बैंकों ने परिपक्वता से पहले प्रीपेमेंट विकल्प का उपयोग करते हुए ₹1,23,572 करोड़ (लगभग 98.8 प्रतिशत ऋण राशि) चुका दिया ताकि अपनी निधियों की लागत को कम किया जा सके। घटना अध्ययन विश्लेषण ने यह संकेत दिया कि घोषणा के दिनों के आसपास एलटीआरओ का कुछ अवधि के जी-सेक यील्ड्स पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा (दास एट आल., 2020; आरबीआई, 2020a)।

कोविड-19 महामारी के प्रकोप ने वित्तीय बाजारों में बिकवाली का दबाव बढ़ा दिया, क्योंकि बड़े वैश्विक प्रभावों ने सुरक्षा की ओर रुख करने के लिए मजबूर कर दिया। परिणामस्वरूप, वित्तीय परिस्थितियां सख्त हो गईं, क्योंकि कॉर्पोरेट बॉन्ड, सीपी (कमर्शियल पेपर) और डिबेंचर्स पर जोखिम प्रीमियम में तेज वृद्धि के कारण व्यापारिक गतिविधियां ठप हो गईं और बाजार में तरलता की कमी हो गई। इस समस्या के समाधान के लिए, लक्षित दीर्घकालिक रेपो संचालन (टीएलटीआरओ) शुरू किए गए, ताकि उन विशिष्ट क्षेत्रों और संस्थानों को तरलता प्रदान की जा सके जो तरलता संकट का सामना कर रहे थे। मार्च-अप्रैल 2020 के दौरान (टीएलटीआरओ नीलामियां आयोजित की गईं, जिसके तहत बैंकों को निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड, सीपी और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर्स में धन लगाने के लिए पैसा दिया गया। बैंकों को अपनी अतिरिक्त होल्डिंग्स का पचास प्रतिशत तक पात्र उपकरणों को प्राथमिक बाजार से और शेष को द्वितीयक बाजार से खरीदने की आवश्यकता थी, जिसमें म्यूचुअल फंड (एमएफ) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से अधिग्रहण भी शामिल था।

चूंकि टीएलटीआरओ फंड का उपयोग मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं और बड़े कॉर्पोरेट्स के प्राथमिक निर्गम तक सीमित था, इसलिए छोटे और मध्यम आकार के कॉर्पोरेट्स, जिसमें गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और सूक्ष्म वित्त संस्थान शामिल हैं, को राहत प्रदान करने के लिए टीएलटीआरओ 2.0 शुरू किया गया। बैंकों को यह निर्देश दिया गया कि वे एनबीएफसी के निवेश ग्रेड बॉन्ड, कमर्शियल पेपर (सीपी) और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर्स में निवेश करें, जिसमें कुल प्राप्त राशि का कम से कम 50 प्रतिशत छोटे और मध्यम आकार के एनबीएफसी और एमएफआई को जाना चाहिए।

तरलता उपायों को ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित किया गया जो विकास पर गुणक प्रभाव डालते हैं। इसी उद्देश्य से, अक्टूबर 2020 में 'ऑन टैप टीएलटीआरओ' शुरू किया गया, जिसमें तीन साल तक की अवधि के लिए नीति रेपो दर से जुड़े फ्लोटिंग रेट पर धन उपलब्ध कराया गया। प्राप्त धनराशि को पांच विशिष्ट क्षेत्रों की संस्थाओं द्वारा जारी कॉर्पोरेट बॉन्ड, कमर्शियल पेपर और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर्स में निवेश करने के लिए उपयोग किया जाना था। इसके अतिरिक्त, इन क्षेत्रों को बैंक ऋण और अग्रिम देने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता था। इसके बाद, दिसंबर 2020 में कामथ समिति (2020) द्वारा पहचाने गए 26 तनावग्रस्त क्षेत्रों को इस योजना के दायरे में शामिल किया गया। फरवरी 2021 में इसे और विस्तारित करते हुए एनबीएफसी को दिए जाने वाले बैंक ऋण को भी इसमें शामिल किया गया।

(ख) **क्षेत्र-विशिष्ट पुनर्वित्त:** सख्त होती वित्तीय परिस्थितियों को देखते हुए, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई) को संसाधन जुटाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उनकी तरलता संबंधी चुनौतियों को कम करने और क्षेत्रीय ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, 2020 में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक (नाबार्ड), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), और राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) को नीति रेपो दर पर विशेष पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान की गईं।

इसके अलावा, विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एग्जिम बैंक को 90 दिनों की अवधि (अधिकतम एक वर्ष तक रोलओवर की अनुमति के साथ) के लिए एक डॉलर स्वेप सुविधा के तहत एक ऋण सीमा प्रदान की गई। मार्च 31, 2022 तक कुछ संपर्क-गहन क्षेत्रों, जैसे होटल और रेस्तरां; पर्यटन - ट्रेवल एजेंट, टूर ऑपरेटर और एडवेंचर/हेरिटेज सुविधाएं; विमानन सहायक सेवाएं - ग्राउंड हैंडलिंग और आपूर्ति श्रृंखला; और अन्य सेवाएं जैसे निजी बस ऑपरेटर, कार मरम्मत सेवाएं, किराए पर कार सेवा प्रदाता, इवेंट/कॉन्फ्रेंस आयोजक, स्पा क्लिनिक और ब्यूटी पार्लर/सैलून के लिए ₹15,000 करोड़ की तरलता खिड़की तीन साल तक की अवधि और रेपो दर पर खोली गई। प्रोत्साहन के रूप में, बैंकों को इस योजना के तहत बनाई गई ऋण पुस्तिका के आकार तक अपनी अतिरिक्त तरलता को रिवर्स रेपो विंडो के माध्यम से रिजर्व बैंक के पास रेपो दर से 25 आधार अंकों कम दर पर, या अन्य शब्दों में, रिवर्स रेपो दर से 40 आधार अंकों अधिक दर पर पार्क करने की अनुमति दी गई। इस योजना को बाद में 30 जून, 2022 तक बढ़ा दिया गया।

(ग) **म्यूचुअल फंड्स के लिए तरलता सुविधा:** म्यूचुअल फंड्स (एमएफ) पर रिडेम्पशन (निवेश की वापसी) के दबाव को कम करने और कुछ डेट म्यूचुअल फंड्स के बंद होने से उत्पन्न संभावित संक्रमण प्रभावों को न्यूनतम करने के लिए, अप्रैल में म्यूचुअल फंड्स के लिए एक विशेष तरलता सुविधा (एसएलएफ- एमएफ) शुरू की गई। इससे पहले, रिजर्व बैंक ने 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के दौरान और बाद में 2013 में टेपर टैट्रम के बाद म्यूचुअल फंड्स को ऐसी ही एक सुविधा प्रदान की थी।

कोविड19 के दौरान भारत के अपरंपरागत ऋण संचालन

Lending Operations	Announced Amount (₹ crore)			
	2019-20	2020-21	2021-22	Total
1	2	3	4	5
I. LTRO/TLTROs/SLTROs ⁴	2,25,000	2,25,000	10,000	4,60,000
II. Lending to Mutual Funds/ NBFCs	-	80,000	-	80,000
III. Lending to Emergency Health Services/ Contact-intensive Sectors	-	-	65,000	65,000
IV. Refinancing to AIFIs	-	75,000	66,000	1,41,000
Total	2,25,200	3,80,000	1,41,000	7,46,200

Source: RBI.

(ii) **एसेट परचेज प्रोग्राम (एपीपी):** कई केंद्रीय बैंकों के विपरीत, रिजर्व बैंक की खरीदारी केवल द्वितीयक बाजार में और केवल सरकारी प्रतिभूतियों (गवर्नमेंट सिक्क्योरिटीज) तक सीमित रही है। एक नवाचार के रूप में, 2020-21 के लिए विशेष मामले के रूप में, अक्टूबर 2020 में राज्य सरकार की प्रतिभूतियों को शामिल किया गया।

अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ऑपरेशन ट्विस्ट्स (ओटी) के अनुभव की पृष्ठभूमि में, रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2019 में विशेष ओएमओ (ओटी) की घोषणा की, जिसमें लंबी अवधि की प्रतिभूतियों की खरीद और छोटी अवधि की प्रतिभूतियों की बिक्री को एक साथ शामिल किया गया। यह कदम भारत में कोविड-19 के प्रकोप से पहले का है। इन संचालन का उद्देश्य टर्म प्रीमियम को कम करना और यील्ड कर्व की तीव्र ढलान को घटाना था। लंबी अवधि की जोखिम-मुक्त (जी-सेक) दरों में कमी अन्य वित्तीय बाजार उपकरणों में भी परिलक्षित होती है, जो जी-सेक दर पर आधारित होते हैं, जिससे मौद्रिक संचरण में सुधार होता है। ओटी की सफलता, सीधे ओएमओ के माध्यम से तरलता प्रवाह के साथ, यील्ड को स्थिर करने और सरकार के लिए उधारी की लागत को कम करने में सहायक रही।

मौद्रिक नीति के संचरण को बेहतर बनाने और यील्ड कर्व के स्थिर और व्यवस्थित विकास को सक्षम करने के उद्देश्य से, रिजर्व बैंक ने अप्रैल-सितंबर 2021 में सेकेंडरी मार्केट जी-सेक अधिग्रहण कार्यक्रम (जी- सैप) लागू किया। जी- सैप के तहत, रिजर्व बैंक ने जी-सेक खरीद की राशि पर पहले से प्रतिबद्धता जताई। इस कदम ने बाजार की चिंताओं को दूर किया और यह दर्शाया कि बाजार उधारी कार्यक्रम के बढ़ने के बावजूद, रिजर्व बैंक बाजार का समर्थन जारी रखेगा। नियमित ओएमओ की तरह, जी-सैप भी द्वितीयक बाजार से सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद तक सीमित रहा।

(iii) फॉरवर्ड गाइडेंस (एफजी): महामारी के बाद, फॉरवर्ड गाइडेंस ने मौद्रिक नीति समिति के उदार रुख का समर्थन करने के लिए रिजर्व बैंक की संचार रणनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एमपीसी द्वारा यह दोहराया जाना कि मौद्रिक नीति का रुख तब तक उदार बना रहेगा जब तक कि वृद्धि का पुनरुद्धार न हो जाए, समय-आधारित और स्थिति-आधारित एफजी का उदाहरण है। उदाहरण के लिए, अक्टूबर 2020 में एमपीसी ने कहा: "... निर्णय लिया गया है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष और अगले वित्तीय वर्ष के दौरान, आवश्यकतानुसार लंबे समय तक उदार रुख जारी रखा जाएगा, ताकि विकास को स्थायी रूप से पुनर्जीवित किया जा सके और अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम किया जा सके, जबकि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहे" (आरबीआई, 2020b)।

इसके अलावा, गवर्नर ने वित्तीय बाजारों को आश्वासन दिया कि रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति के रुख के अनुरूप तरलता की अनुकूल स्थिति बनाए रखेगा और वित्तीय बाजार स्थिरता और यील्ड कर्व के व्यवस्थित विकास को *सार्वजनिक वस्तुओं* के रूप में रेखांकित करते हुए सहकारी समाधान की आवश्यकता पर बल दिया (आरबीआई, 2020c)। पुनरुद्धार को बनाए रखने के लिए अनुकूल वित्तीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता ने तरलता संकट की आशंकाओं को दूर किया और बाजार की भावना को मजबूत किया। इस रुख के समर्थन में रिजर्व बैंक के तरलता प्रबंधन संचालन ने बाजार सहभागियों को सामूहिक और सहयोगात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित किया, जो मौद्रिक नीति संचार में एफजी की प्रभावशीलता को दर्शाता है। इस प्रकार, एफजी ने कोविड के बाद के माहौल में अन्य अपरंपरागत मौद्रिक नीति उपायों (युएमपीटी) को प्रभावी रूप से पूरक किया।

III. मौद्रिक नीति संचरण

मौद्रिक संचरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक केंद्रीय बैंक द्वारा नीति दर में किए गए बदलाव पूरे ब्याज दरों के स्पेक्ट्रम तक पहुंचाए जाते हैं, जैसे मनी मार्केट दरें, बॉन्ड यील्ड, बैंक जमा और ऋण दरें, और संपत्ति की कीमतें जैसे स्टॉक और मकानों की कीमतें। विभिन्न आर्थिक एजेंट, जैसे परिवार, फर्म और सरकार, इन ब्याज दर परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया करते हुए अपने खर्च के व्यवहार में बदलाव करते हैं। यह प्रक्रिया परिवारों और फर्मों की समग्र मांग को बदलती है और इसे समग्र आपूर्ति की स्थितियों के अनुरूप बनाती है। इसके परिणामस्वरूप, व्यापक आर्थिक नीति के उद्देश्य, जैसे मूल्य स्थिरता और अर्थव्यवस्था का सतत विकास, प्राप्त किए जाते हैं। यह पूरी प्रक्रिया महीनों, और कभी-कभी एक वर्ष से अधिक का समय ले सकती है।

भारत के लिए अनुभवजन्य साक्ष्य यह संकेत करते हैं कि मौद्रिक नीति क्रियाएँ उत्पादन पर 2-3 तिमाही के अंतराल के साथ प्रभाव डालती हैं और महंगाई पर 3-4 तिमाही के अंतराल के साथ प्रभाव डालती हैं, और इसका प्रभाव 8-12 तिमाही तक बना रहता है। प्रसारण विभिन्न 'चैनल' के माध्यम से होता है, अर्थात् (i) ब्याज दर चैनल, (ii) क्रेडिट चैनल, (iii) विनिमय दर चैनल, (iv) संपत्ति मूल्य चैनल, और (v) अपेक्षाएँ चैनल, जो कि एक बाजार-आधारित मौद्रिक नीति ढांचे जैसे एफआईटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई अध्ययनों के अनुसार, ब्याज दर चैनल को भारत में सबसे मजबूत पाया गया है। मौद्रिक नीति की

प्रभावशीलता इस पर निर्भर करती है कि नीति दर परिवर्तनों का आर्थिक नीति के अंतिम उद्देश्यों, अर्थात् वृद्धि और महंगाई पर कितना और कितनी तेजी से प्रभाव पड़ता है। एक बैंक-प्रधान प्रणाली में जैसे कि भारत में, बैंकों की उधारी दरों तक प्रसारण मौद्रिक नीति की सफल कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए, रिजर्व बैंक का प्रयास रहा है कि बैंकिंग प्रणाली की उधारी ब्याज दरों के डिज़ाइन पर ध्यान केंद्रित कर मौद्रिक प्रसारण को मजबूत किया जाए। हालांकि, नीति दर से बैंकों की उधारी दरों तक के प्रसारण का मुद्दा हमेशा चिंता का विषय रहा है। बैंकों की उधारी दरों तक प्रसारण विभिन्न कारकों द्वारा बाधित हुआ है, और इस प्रकार, नीति परिवर्तन का आर्थिक गतिविधि और महंगाई पर प्रभाव मंद पड़ा है (मित्रा और चट्टोपाध्याय, 2020)।

इस चिंता को संबोधित करने के लिए, रिजर्व बैंक ने समय-समय पर बैंकों की ब्याज दर निर्धारण पद्धति को परिष्कृत किया है। 1 अक्टूबर, 2019 से प्रभावी, आंतरिक अध्ययन समूह (आरबीआई, 2017) की सिफारिशों के अनुसरण में, रिजर्व बैंक ने यह अनिवार्य किया कि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) नई फ्लोटिंग रेट व्यक्तिगत या खुदरा ऋणों और माइक्रो एवं स्मॉल एंटरप्राइजेज (एमएसई) के फ्लोटिंग रेट ऋणों को नीति रेपो दर, 3-महीने की टी-बिल दर, 6-महीने की टी-बिल दर या फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा प्रकाशित किसी अन्य बेंचमार्क बाजार ब्याज दर से जोड़ें। मौद्रिक प्रसारण को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया कि वे मध्यम उद्यमों के लिए ऋण मूल्य निर्धारण को भी 1 अप्रैल, 2020 से एक बाहरी बेंचमार्क से जोड़ें। इस बेंचमार्किंग प्रणाली के तहत, बैंकों को बेंचमार्क दर पर स्प्रेड चुनने की स्वतंत्रता है, बशर्ते कि क्रेडिट जोखिम प्रीमियम केवल तभी बदले जब उधारकर्ता की क्रेडिट आकलन में ऋण अनुबंध में सहमति के अनुसार महत्वपूर्ण बदलाव हो। बाहरी बेंचमार्क पारदर्शी होते हैं क्योंकि वे सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध होते हैं और इस प्रकार उधारकर्ताओं के लिए आसानी से सुलभ होते हैं। बाहरी बेंचमार्क प्रणाली की शुरुआत के बाद, उन क्षेत्रों में मौद्रिक प्रसारण में सुधार हुआ है, जहां नए फ्लोटिंग रेट ऋण बाहरी बेंचमार्क से जोड़े गए हैं।

अध्याय 4: बाजार परिचालन

यह अध्याय भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के बाजार परिचालनों के उद्देश्य, ढांचे और कार्यान्वयन पर चर्चा करता है। यह दो खंडों में विभाजित है। पहला खंड मौद्रिक नीति परिचालनों पर केंद्रित है, और दूसरा खंड आरबीआई के विदेशी मुद्रा परिचालनों पर केंद्रित है।

1. मौद्रिक नीति परिचालन

मौद्रिक नीति परिचालनों का उद्देश्य मौद्रिक नीति को वित्तीय प्रणाली में प्रभावी ढंग से लागू करना है। मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीतिगत ब्याज दर और नीति रुख तय करती है। मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य वेटेड एवरेज कॉल रेट (डब्ल्यूसीआर) है, जो कॉल मनी बाजार (पैसा बाजार का बिना गारंटी वाला खंड) में किए गए रातोंरात लेनदेन की वॉल्यूम वेटेड दर है। आरबीआई अपने द्वारा तैयार किए गए चलनिधि प्रबंधन ढांचे के अनुसार बाजार परिचालन करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डब्ल्यूसीआर दैनिक आधार पर नीति दर के साथ संरेखित हो।

चलनिधि एक अच्छी तरह से काम करने वाली और सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। केंद्रीय बैंक चलनिधि से आशय बैंकिंग प्रणाली को केंद्रीय बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए भंडार से है। यह मौद्रिक नीति के कार्यान्वयन का मुख्य साधन है, और चलनिधि प्रबंधन परिचालनों का ध्यान बैंकिंग प्रणाली की चलनिधि पर केंद्रित है। बैंकों को अपने केंद्रीय बैंक खातों में एक अनिवार्य स्तर का संतुलन बनाए रखना होता है, जिसे आवश्यक भंडार कहा जाता है। अगर बैंक अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए इंटर-बैंक बाजार से फंड जुटाने में असमर्थ होते हैं, तो वे केंद्रीय बैंक से उधार लेते हैं। इसके विपरीत, अगर उनके पास आवश्यकता से अधिक भंडार होता है, तो वे इसे केंद्रीय बैंक में जमा कर सकते हैं।

आरबीआई का चलनिधि प्रबंधन ढांचा अस्थायी चलनिधि (जैसे, चलनिधि अधिशेष या अल्पता) के प्रबंधन के लिए चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) का उपयोग करता है।

प्रणाली चलनिधि

चलनिधि प्रबंधन परिचालनों का मुख्य बिंदु बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि है, जिसे प्रणाली चलनिधि कहा जाता है। किसी दिए गए दिन, यदि बैंकिंग प्रणाली आरबीआई से शुद्ध उधारकर्ता है, तो प्रणाली की चलनिधि को घाटे में माना जाता है (अर्थात्, प्रणाली की उधार ली गई रिज़र्व की मांग सकारात्मक है) और यदि बैंकिंग प्रणाली आरबीआई को शुद्ध ऋणदाता है, तो प्रणाली की चलनिधि को अधिशेष में माना जाता है (अर्थात्, प्रणाली की उधार ली गई रिज़र्व की मांग नकारात्मक है)। व्यवहार में, बैंक अपनी अपेक्षित आरक्षित राशि से थोड़ा सकारात्मक अंतर (अधिशेष आरक्षित) बनाए रखते हैं, ताकि अप्रत्याशित निपटान दायित्वों (या आरक्षित की एहतियाती मांग) को पूरा किया जा सके। इसे ध्यान में रखते हुए उस दिन बैंकिंग प्रणाली में उपलब्ध चलनिधि की मात्रा का आकलन किया जाता है। इस प्रकार, बैंकिंग प्रणाली की चलनिधि को निम्न प्रकार से संक्षेपित किया जा सकता है:

प्रणाली चलनिधि = आरबीआई से कुल उधार – बैंकों द्वारा बनाए गए अधिशेष भंडार.... (1)

आरबीआई से शुद्ध उधार = सभी रेपो/एमएसएफ/एसएलएफ उधार की कुल राशि – सभी रिवर्स-रेपो जमा की कुल राशि

अधिशेष भंडार = बैंकों द्वारा बनाए गए वास्तविक भंडार - आवश्यक भंडार

नोट: एक सकारात्मक मूल्य प्रणाली चलनिधि में कमी को दर्शाता है, जबकि नकारात्मक मूल्य अधिशेष को दर्शाता है।

अस्थायी और स्थायी चलनिधि

प्रणाली की चलनिधि या आरक्षित निधि की मांग को उनके स्रोत की प्रकृति के आधार पर अस्थायी/घर्षणशील या स्थायी में विभाजित किया जा सकता है। अस्थायी/घर्षणशील चलनिधि उस स्थिति को दर्शाती है जो रातोंरात या अल्पकाल में पलट सकती है। सरकार के नकद शेष, जो आरबीआई के पास रखे जाते हैं, अस्थायी/घर्षणशील आरक्षित निधि मांग का प्रमुख स्रोत हैं।

स्थायी चलनिधि या आरक्षित निधि की स्थायी मांग आरबीआई की देनदारियों में स्थायी या दीर्घकालिक परिवर्तनों से उत्पन्न होती है, जैसे: प्रचलन में मुद्रा (सीआईसी) का विस्तार/संकुचन और बिना स्टेरलाइज़ किए गए विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप से बैंकिंग प्रणाली के आरक्षित निधि का घटाव/वृद्धि। स्थायी चलनिधि को अधिक सरलता से समझने के लिए, इसे प्रणाली की चलनिधि से भारत सरकार (भारत सरकार) के शेष को समायोजित करके निकाला जा सकता है। इस प्रकार, यदि बैंकिंग प्रणाली द्वारा आरबीआई से शुद्ध उधार भारत सरकार के शेष से अधिक है, तो यह इंगित करता है कि स्थायी चलनिधि घाटे में है और इसके विपरीत।

आरबीआई का चलनिधि प्रबंधन ढांचा

चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) आरबीआई द्वारा चलनिधि प्रबंधन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख उपकरणों में से एक है। इसका उपयोग अस्थायी चलनिधि (जो अल्पकालिक प्रकृति की होती है और अधिशेष या घाटे के रूप में होती है) को बैंकिंग प्रणाली में प्रवाहित करने या सोखने के लिए किया जाता है। इसमें रातोंरात और अवधि रेपो/रिवर्स रेपो (निश्चित और परिवर्तनीय दरें), स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ), और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) शामिल हैं। स्थायी/दृढ़ चलनिधि प्रबंधन के लिए, दीर्घकालिक रेपो/रिवर्स रेपो संचालन (एलटीआरओ/एलटीआरआरओ), खुले बाजार संचालन (ओएमओ) द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की सीधी खरीद और बिक्री, आवश्यक नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में परिवर्तन, बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस), और यूएसडी/आईएनआर स्वैप नीलामी (विदेशी मुद्रा स्वैप नीलामी) जैसे उपकरणों का उपयोग किया जाता है।

सीआरआर एक प्रत्यक्ष उपकरण है जो प्रणाली की चलनिधि को तुरंत प्रभावित करता है। यदि सीआरआर में वृद्धि होती है, तो बैंकों को आरबीआई के साथ अपने चालू खाते में उच्च शेष बनाए रखना होता है, जिससे बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि घट जाती है। इसी प्रकार, सीआरआर में कमी का तुरंत प्रभाव बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि बढ़ाने के रूप में होता है। चलनिधि प्रबंधन के अन्य उपकरणों का विवरण आगामी पैराग्राफ में दिया गया है।

आरबीआई के एक आंतरिक कार्य समूह ने सितंबर 2019 में चलनिधि प्रबंधन ढांचे की समीक्षा की और अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। समूह ने कॉल मनी दर को नीति दर के करीब और संगत बनाए रखने के मौजूदा उद्देश्यों को जारी रखा, साथ ही अंतर-बैंक मनी मार्केट में मूल्य खोज को बाधित न करने की नीति अपनाई। समूह ने कॉल मनी दर को लक्षित दर के रूप में रखने के साथ एक गलियारा प्रणाली को बनाए रखने की सिफारिश की, लेकिन बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि अधिशेष या घाटे के उचित स्तर के निर्णय के लिए वित्तीय स्थितियों के आधार पर अधिक लचीलापन अपनाने का सुझाव दिया। अन्य सिफारिशों में शामिल थे:

1. संचालन की संख्या को कम करके अधिक दक्षता प्राप्त करना।

2. एनडीटीएल के 1% तक आश्वासित चलनिधि की व्यवस्था को समाप्त करना।
3. स्थायी चलनिधि प्रबंधन के लिए मौजूदा उपकरणों के अतिरिक्त दीर्घकालिक रेपो संचालन को शामिल करना।
4. चलनिधि प्रबंधन पर अधिक जानकारी का प्रसार।

समूह की सिफारिशों के आधार पर, आरबीआई ने अपने चलनिधि प्रबंधन ढांचे को अद्यतन किया है, जिसे नीचे सारणीबद्ध किया गया है।

क्रमांक	साधन	मात्रा	समय-सीमा / समयानुकूलता
A. एलएएफ ढांचे के तहत अल्पकालिक/क्षणिक चलनिधि प्रबंधन हेतु साधन			
1.	14-दिन का परिवर्तनीय दर रेपो/रिवर्स रेपो नीलामी (मुख्य परिचालन)	नीलामी राशि आरबीआई द्वारा तय की जाती है और एकल नीलामी (रेपो या रिवर्स रेपो) आरबीआई द्वारा चलनिधि स्थिति के आकलन के आधार पर की जाती है।	रिपोर्टिंग शुक्रवार को (यदि रिपोर्टिंग शुक्रवार अवकाश हो, तो यह नीलामी मुंबई में पिछले कार्यदिवस पर आयोजित की जाती है)।
2.	परिवर्तनीय दर अवधि रेपो/रिवर्स रेपो नीलामी (अवधि: एक रात और 13 दिनों तक) (सूक्ष्म-संतुलन परिचालन)	नीलामी राशि आरबीआई द्वारा चलनिधि स्थिति के आकलन के आधार पर तय की जाती है।	विवेकाधीन
3.	स्टैंडिंग डिपॉजिट सुविधा (एसडीएफ) (अवधि: एक रात; हालांकि, आरबीआई आवश्यकता पड़ने पर उचित मूल्य निर्धारण के साथ एसडीएफ के तहत लंबे समय तक चलनिधि को अवशोषित करने का लचीलापन रखता है।)	राशि पर कोई प्रतिबंध नहीं।	प्रतिदिन 05:30 बजे से 11:59 बजे के बीच।
4.	मार्जिनल स्टैंडिंग सुविधा (एमएसएफ)	व्यक्तिगत बैंक अतिरिक्त एसएलआर + एसएलआर से 2 प्रतिशत नीचे तक धन जुटा सकते हैं।	
5.	एफएक्स स्वैप	राशि आरबीआई द्वारा चलनिधि स्थिति के आकलन के आधार पर तय की जाती है।	विवेकाधीन
6.	स्थिर दर रिवर्स रेपो	समय-समय पर निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए आरबीआई के विवेक पर।	

क्रमांक	साधन	मात्रा	समय-सीमा / समयानुकूलता
B. दीर्घकालिक चलनिधि प्रबंधन के साधन			
7.	दीर्घकालिक परिवर्तनीय दर रेपो परिचालन (एलटीआरओ) 14 दिनों से अधिक	नीलामी राशि आरबीआई द्वारा चलनिधि स्थिति के आकलन के आधार पर तय की जाती है।	विवेकाधीन
8.	दीर्घकालिक परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो परिचालन (एलटीआरआरओ) 14 दिनों से अधिक		
9.	विदेशी मुद्रा स्वैप नीलामी (एफएक्स स्वैप)	नीलामी राशि आरबीआई द्वारा चलनिधि स्थिति के आकलन के आधार पर तय की जाती है।	विवेकाधीन
10.	खुला बाजार परिचालन (ओएमओ)	राशि आरबीआई द्वारा चलनिधि स्थिति के आकलन के आधार पर तय की जाएगी।	विवेकाधीन

एसडीएफ को अप्रैल 2022 में शुरू किया गया। 30 दिसंबर, 2023 से प्रभावी, आरबीआई ने बैंकों को उनके फंड प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए वीकेंड और छुट्टियों के दौरान भी एसडीएफ और एमएसएफ के तहत चलनिधि सुविधाओं को रिवर्स करने की अनुमति दी है।

एलएएफ के तहत रेपो/रिवर्स रेपो/एमएसएफ की मुख्य विशेषताएं:

आरबीआई का विवेकाधिकार:

संशोधित चलनिधि ढांचे के तहत मुख्य संचालन 14-दिन की वेरिबल रेट रेपो या रिवर्स रेपो (मौजूदा चलनिधि परिस्थितियों पर निर्भर) होता है, लेकिन आरबीआई को बाजार की स्थिति और अन्य कारकों के आधार पर रातोंरात/लंबी अवधि के रेपो/रिवर्स रेपो नीलामी करने का अधिकार है। आरबीआई उपलब्ध डेटा और चलनिधि के पूर्वानुमान के आधार पर चलनिधि की स्थिति का आकलन करता है और इस विवेक का उपयोग करता है। इस तंत्र का विवरण अध्याय के अगले भाग में दिया गया है।

ब्याज दर:

रेपो के लिए लागू ब्याज दर एमपीसी द्वारा समय-समय पर तय की गई पॉलिसी रेट होती है। रिवर्स रेपो और एमएसएफ दरें पॉलिसी रेट से जुड़ी होती हैं और आरबीआई द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाती हैं। वेरिबल रेट रेपो और रिवर्स रेपो नीलामी के लिए, लागू ब्याज दर आरबीआई द्वारा प्राप्त बोली/प्रस्तावों के आधार पर तय की गई कट-ऑफ दर होती है।

संपार्श्विक के रूप में पात्र प्रतिभूतियां:

एसएलआर-योग्य और अनअंकित भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां (तेल बांड सहित)/ट्रेजरी बिल और राज्य सरकार की प्रतिभूतियां (रेटेड और अनरेटेड) रेपो/एमएसएफ और रिवर्स रेपो संचालन के लिए पात्र मानी जाती हैं।

रेपो/एमएसएफ/रिवर्स रेपो संचालन के लिए संपार्श्विक आवश्यकता की गणना करने के लिए ऑपरेशन के दिन की बाजार मूल्यांकन (एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित) का उपयोग किया जाता है। आरबीआई के पास यह विकल्प भी है कि वह गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों का पुनर्मूल्यांकन पूर्व-निर्धारित अंतरालों पर करे, जैसा कि वर्तमान में एलटीआरओ और टीएलटीआरओ

के लिए किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऋण पर्याप्त रूप से गिरवी से सुरक्षित रहे।

मार्जिन आवश्यकता:

पात्र प्रतिभूतियों के संदर्भ में एक मार्जिन लागू किया जाता है, जो यह प्रभावी रूप से सुनिश्चित करता है कि रेपो या एमएसएफ विंडो का उपयोग करके रुपये की निधि उधार लेने वाला उधारकर्ता अतिरिक्त संपार्श्विक प्रदान करे। उदाहरण के लिए, यदि मार्जिन 5% है और बाजार प्रतिभागी रेपो विंडो से ₹100 करोड़ उधार ले रहा है, तो उसे ₹105 करोड़ मूल्य की पात्र प्रतिभूतियां प्रदान करनी होंगी। रिवर्स रेपो संचालन के तहत आरबीआई द्वारा प्रदान किए गए संपार्श्विक के लिए कोई मार्जिन आवश्यकता नहीं होती है।

संचालन की प्रक्रिया:

- बोली/प्रस्ताव इलेक्ट्रॉनिक रूप से आरबीआई के कोर बैंकिंग प्रणाली (ई-कुबेर) में निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत की जाती है। एमएसएफ/एसडीएफ लेन-देन का निपटान स्वचालित और तत्काल होता है।
- पात्र एलएएफ प्रतिभागियों को उनके दिन के अंत में सीआरआर शेष प्रबंधन में अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए, आरबीआई अपने ई-कुबेर प्रणाली में एक वैकल्पिक स्वचालित स्वीप-इन और स्वीप-आउट (एसआईएसओ) सुविधा प्रदान करता है। इसके तहत, बैंक दिन के अंत में आरक्षित बैंक के साथ अपने चालू खातों में रखी जाने वाली राशि (विशिष्ट या सीमा) को पहले से निर्धारित कर सकते हैं। इस पूर्व निर्धारित राशि के अनुसार, दिन के अंत में बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के एमएसएफ और एसडीएफ बोली स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। यह सुविधा वैकल्पिक है और ई-कुबेर पोर्टल के माध्यम से एसडीएफ और एमएसएफ विंडो में मैनुअल बोली लगाने की मौजूदा प्रक्रिया के अतिरिक्त है।
- परिवर्तनीय दर संचालन के लिए, निपटान नीलामी के परिणामों की घोषणा के बाद किया जाता है। संचालन के परिणाम आरबीआई की वेबसाइट पर प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से घोषित किए जाते हैं।

परिवर्तनीय-दर नीलामी के कट-ऑफ के संबंध में निर्णय:

- **परिवर्तनीय-दर रेपो:** बैंकों के लिए बोली की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। बैंक अधिसूचित राशि तक बोली लगा सकते हैं। बोली लगाने का समय समाप्त होने के बाद, सभी बोलियों को उद्धृत दरों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, और नीलामी की अधिसूचित राशि के अनुसार कट-ऑफ दर तय की जाती है। सफल बोलीदाता वे हैं जिन्होंने अपनी बोलियां कट-ऑफ दर पर या उससे अधिक पर लगाई हैं। यदि कट-ऑफ दर पर एक से अधिक सफल बोलियां हों, तो आनुपातिक आवंटन किया जाता है। मौजूदा रेपो दर पर या उससे नीचे की कोई भी बोली स्वीकार नहीं की जाती।
- **परिवर्तनीय-दर रिवर्स रेपो:** परिवर्तनीय-दर रिवर्स रेपो नीलामी का संचालन रेपो नीलामी के संचालन के विपरीत होता है। इस मामले में, मौजूदा रेपो दर पर या उससे ऊपर की कोई भी पेशकश स्वीकार नहीं की जाती।

एलएएफ गलियारा कैसे काम करता है?

यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारित औसत कॉल दर (डब्ल्यूसीआर) नीति रेपो दर से अधिक विचलन न करे, रिजर्व बैंक एक गलियारा प्रणाली बनाए रखता है। इसमें स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर को तल और सीमांत स्थायी सुविधा

(एमएसएफ) दर को छत के रूप में रखा जाता है। एमएसएफ विंडो के माध्यम से बैंक रिजर्व बैंक से रुपये उधार ले सकते हैं, जिसमें स्वीकृत प्रतिभूतियों को गिरवी रखना होता है। एसडीएफ विंडो के माध्यम से बैंक रुपये रिजर्व बैंक में जमा कर सकते हैं, जिसमें आरबीआई को कोई संपार्श्विक रखने की आवश्यकता नहीं होती। महत्वपूर्ण बात यह है कि एमएसएफ और एसडीएफ दोनों दरें नीति रेपो दर से जुड़ी होती हैं, जिसे मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) तय करती है। आरबीआई गलियारे की चौड़ाई तय करने का अधिकार रखता है।

- एमएसएफ दर: गलियारे की ऊपरी सीमा।
- एसडीएफ दर: गलियारे की निचली सीमा।

बैंक अन्य बाजार सहभागियों से धन उधार लेने और देने के लिए धन बाजार (मनी मार्केट) का भी उपयोग करते हैं। आरबीआई सुविधा का उपयोग करने से पहले, बैंक धन बाजार के अन्य क्षेत्रों जैसे कॉल मनी, ट्राई-पार्टी रेपो⁶, बाजार रेपो, आदि में उधार और ऋण के लिए उपलब्ध विकल्पों पर विचार करते हैं। मुख्य निर्णय कारक ब्याज दर होती है, लेकिन बैंक अन्य पहलुओं जैसे गिरवी प्रतिभूतियों की आवश्यकता, संचालन में सुविधा, उपलब्धता, अवधि, आदि पर भी विचार करते हैं। ब्याज दर का स्तर डब्ल्यूएसीआर को नीति रेपो दर के साथ समक्रमण करने में मदद करता है।

आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यदि XYZ बैंक को अपना अधिशेष धन उधार देना हो तो बैंक धन बाजार में अन्य प्रतिभागियों को उधार देने की कोशिश करेगा। प्रणाली में अधिशेष चलनिधि (ज्यादा उधारदाता और कम उधारकर्ता) की स्थिति में, बाजार दरें गिर सकती हैं। चूंकि बैंक के पास अपनी अधिशेष निधि को एसडीएफ में जमा करने का विकल्प होता है, एसडीएफ दर धन बाजार की दरों के लिए तल निर्धारित करती है। बैंक एसडीएफ दर से कम पर उधार नहीं देगा।

यदि XYZ बैंक को रातभर के लिए रुपये उधार लेने की आवश्यकता हो तो बैंक धन बाजार के अन्य प्रतिभागियों से उधार लेने की कोशिश करेगा। प्रणाली में चलनिधि घाटे (ज्यादा उधारकर्ता और कम उधारदाता) की स्थिति में, बाजार दरें बढ़ सकती हैं। चूंकि बैंक एमएसएफ विंडो से उधार ले सकता है, एमएसएफ दर छत निर्धारित करती है। बैंक आमतौर पर एमएसएफ दर से अधिक दर पर उधार नहीं लेगा। हालांकि, एमएसएफ विंडो से उधार लेने की राशि बैंक के पास उपलब्ध मुफ्त गिरवी प्रतिभूतियों की मात्रा से सीमित होती है। इसका अर्थ है कि पात्र प्रतिभूतियां, जो सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) आवश्यकताओं से अधिक हों, और इसके साथ ही वह छूट, जो बैंकों को उनकी एसएलआर होल्डिंग को आरबीआई द्वारा अनुमत सीमा तक वैधानिक आवश्यकता से कम रखने की अनुमति देती है। इसलिए, यदि प्रणाली स्तर पर चलनिधि का भारी घाटा हो, तो यह संभव है कि धन बाजार की दरें छत पार कर जाएं और एमएसएफ दर से अधिक हो जाएं। हालांकि, ऐसी स्थिति केवल असाधारण परिस्थितियों में ही अपेक्षित है।

संकरा गलियारा धन बाजार की दरों को नीति रेपो दर के पास बनाए रखने में मदद करता है। चौड़ा गलियारा दरों में उतार-चढ़ाव की अधिक संभावना देता है और बाजार विकास को प्रोत्साहित करता है।

डब्ल्यूएसीआर को नीति रेपो दर के अनुरूप कैसे लाया जाता है?

भारी अधिशेष चलनिधि के समय, कॉल दरें एलएएफ गलियारे की निचली सीमा, यानी एसडीएफ दर, की ओर झुकाव दिखाती

⁶ ट्राई-पार्टी रेपो एक मनी मार्केट उपकरण है जिसे सीसीआईएल द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें बाजार सहभागियों को पात्र सुरक्षा संपत्तियों के खिलाफ शॉर्ट-टर्म रुपए के फंड उधार लेने और देने की सुविधा मिलती है। मनी मार्केट का सीबीएल सेगमेंट 5 नवम्बर 2018 से समाप्त कर दिया गया है और इसे ट्राई-पार्टी रेपो से बदल दिया गया है।

हैं। इसी प्रकार, भारी चलनिधि घाटे के समय, कॉल दरें गलियारे की ऊपरी सीमा, यानी एमएसएफ दर, की ओर झुकाव दिखाती हैं। डब्ल्यूसीआर को रेपो दर के करीब बनाए रखने के लिए, 14-दिन की मुख्य नीलामी के अलावा, रिजर्व बैंक फाइन-ट्यूनिंग ऑपरेशंस का उपयोग करता है। इसमें विवेकाधीन परिवर्तनशील दर वाले रेपो और रिवर्स रेपो नीलामियां शामिल हैं। इनके लिए राशि और समय का निर्धारण रिजर्व बैंक द्वारा चलनिधि की स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। रिजर्व बैंक बाजार के समय के दौरान धन बाजार की दरों की लगातार निगरानी करता है और आवश्यकता पड़ने पर फाइन-ट्यूनिंग ऑपरेशंस करता है ताकि डब्ल्यूसीआर को नीति दर के करीब बनाए रखा जा सके। उदाहरण के लिए, यदि डब्ल्यूसीआर एसडीएफ दर के करीब है, तो इसका मतलब है कि प्रणाली में चलनिधि अधिशेष है। मान लें कि चलनिधि के आकलन और बाजार सहभागियों से प्राप्त फीडबैक से पता चलता है कि अप्रत्याशित सरकारी व्यय के कारण प्रणाली में ₹50,000 करोड़ आ गए हैं। ऐसी स्थिति में, पर्याप्त राशि के लिए अतिरिक्त परिवर्तनशील दर रिवर्स रेपो नीलामी की घोषणा बाजार दरों को सहारा देने और उन्हें ऊपर की ओर धकेलने में मदद करेगी, जिससे यह नीति रेपो दर के करीब आ जाएगी। इसी प्रकार, भारी चलनिधि घाटे की स्थिति में, जब डब्ल्यूसीआर एमएसएफ दर की ओर झुकाव दिखा रहा हो, पर्याप्त राशि के लिए अतिरिक्त परिवर्तनशील दर रेपो नीलामी की घोषणा डब्ल्यूसीआर को नीचे खींचेगी और इसे रेपो दर के साथ संरेखित करेगी। ऑपरेशंस की राशि, अवधि और समय का निर्धारण करने के लिए, प्रणाली स्तर की चलनिधि का सतत आकलन अत्यंत महत्वपूर्ण है।

रिजर्व बैंक द्वारा प्रणाली स्तर की चलनिधि का आकलन कैसे किया जाता है?

प्रणाली स्तर की चलनिधि के आकलन के लिए विचार किए गए महत्वपूर्ण कारकों को ज्ञात और अज्ञात कारकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रतिदिन के आधार पर, ज्ञात कारकों की मात्रा और प्रभाव की जानकारी निश्चित रूप से उपलब्ध रहती है। ज्ञात कारकों के कुछ उदाहरण हैं एलएएफ के तहत रिजर्व बैंक के शेष ऑपरेशंस का रिवर्सल, ओएमओ का निपटान, रिजर्व बैंक के फॉरेक्स ऑपरेशंस का निपटान, सरकारी बांडों का परिपक्व होना, कूपन भुगतान, प्राथमिक नीलामियां, आदि। अज्ञात कारकों की मात्रा और प्रभाव की जानकारी तुरंत उपलब्ध नहीं रहती है और इसे आंका या पूर्वानुमानित करना पड़ता है। अज्ञात कारकों के कुछ उदाहरण हैं किसी भी दिन बैंकों द्वारा आरक्षित निधियों का रखरखाव, प्रचलन में मुद्रा में परिवर्तन, केंद्रीय सरकार के खातों से प्रवाह/प्रवाह की सटीक मात्रा, आदि। पूर्वानुमान के लिए पिछले डेटा और सरकार/बैंकों के साथ अनौपचारिक संवाद से प्राप्त जानकारी पर निर्भर किया जाता है। प्रणाली की चलनिधि पर शुद्ध प्रभाव निर्धारित करने के लिए, ज्ञात और अज्ञात दोनों कारकों पर विचार करना आवश्यक होता है।

भारत में चलनिधि प्रबंधन ढांचा दो व्यापक, परस्पर सुदृढ़ स्तंभों पर आधारित है, जो अग्रिम आकलन पर केंद्रित हैं⁷:

- स्तंभ-1 निकट-अवधि (4-6 सप्ताह) के लिए प्रणाली स्तर की चलनिधि मांग का आकलन करता है। स्तंभ-1 का मुख्य उद्देश्य चलनिधि के स्वायत्त कारकों की निकट-अवधि की परियोजनाओं के आधार पर प्रणाली स्तर की चलनिधि मांग का आकलन करना है। इसका मुख्य घटक मुद्रा की मांग (यह परिवारों के व्यवहार को दर्शाता है), अतिरिक्त आरक्षित निधि की मांग (यह बैंकिंग प्रणाली के व्यवहार को दर्शाता है), केंद्र सरकार के रिजर्व बैंक के पास शेष धनराशि: यह

⁷ डॉ. उर्जित आर. पटेल। (2014)। मौद्रिक नीति ढांचे को संशोधित और सुदृढ़ करने के लिए विशेषज्ञ समिति। मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक।

सरकार के नकदी प्रवाह पर निर्भर करती है। विदेशी मुद्रा बाजार हस्तक्षेप को भी चलनिधि का स्वायत्त कारक माना जाता है। हालांकि, निकट-अवधि के पूर्वानुमान के अभाव में इसे सूचना उपलब्ध होने पर ही आकलन में शामिल किया जाता है। अग्रिम जानकारी और समय-श्रृंखला विश्लेषण का संयोजन करते हुए, चलनिधि के निर्धारकों का आकलन नियमित रूप से किया जाता है। यह रिजर्व बैंक के विवेकाधीन चलनिधि प्रबंधन निर्णयों को सूचित करने का कार्य करता है।

- स्तंभ-II अपेक्षाकृत लंबी समयावधि में प्रणाली स्तर की चलनिधि का आकलन है, जो व्यापक मुद्रा, बैंक ऋण और जमाओं में संभावित वृद्धि, आधार मुद्रा विस्तार के क्रम पर केंद्रित है। इस आकलन को स्तंभ-I के अंतर्गत प्राप्त चलनिधि के स्वायत्त और विवेकाधीन कारकों के विश्लेषण के साथ जोड़ा जाता है। इस प्रकार, स्तंभ-II एक व्यापक सूचना सेट बन जाता है, जिसके भीतर विवेकाधीन चलनिधि प्रबंधन उपायों से संबंधित निर्णय स्तंभ-I के आकलन के आधार पर लिए जाते हैं।

आरबीआई के विवेकाधीन चलनिधि प्रबंधन संचालन कैसे तय होते हैं?

आरबीआई का चलनिधि प्रबंधन संचालन (मुख्यतः वेरिएबल-रेट रेपो/रिवर्स रेपो और ओएमओ) मौद्रिक नीति समिति की स्थिति, चलनिधि अधिशेष/घाटे की स्थिति और घाटे/अधिशेष की प्रकृति (क्षणिक या स्थायी) पर आधारित होते हैं। क्षणिक चलनिधि के लिए **एलएएफ संचालन** का उपयोग किया जाता है। स्थायी चलनिधि के लिए **एलटीआरओ, ओएमओ, एमएसएस और सीआरआर** जैसे उपकरणों का उपयोग किया जाता है। एमएसएस का उपयोग उन परिस्थितियों में किया जाता है जब ओएमओ का उपयोग वांछनीय नहीं होता है और/या प्रणाली में अधिशेष चलनिधि को अवशोषित करने के लिए रिजर्व बैंक के पास अपनी प्रतिभूतियों का पर्याप्त पोर्टफोलियो नहीं होता। एमएसएस की प्रक्रिया को बाद के पैराग्राफ में एमएसएस उपखंड में समझाया गया है।

चलनिधि की स्थिति स्थायी है या नहीं, यह कैसे निर्धारित करें?

लगातार उच्च स्तर के रिजर्व बैंक रेपो या रिवर्स रेपो यह संकेत देते हैं कि घाटा/अधिशेष स्थायी प्रकृति का है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, स्थायी चलनिधि या आरक्षित निधि की स्थायी मांग रिजर्व बैंक की देनदारियों में स्थायी या दीर्घकालिक परिवर्तनों से उत्पन्न होती है, जैसे कि परिसंचरण में मुद्रा का विस्तार/संकुचन, अस्टरलाइज़्ड विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप संचालन, और बैंकिंग प्रणाली की शुद्ध मांग और समय देनदारियों (एनडीटीएल) में परिवर्तनों के कारण आरक्षित निधियों में कमी/वृद्धि। हालांकि, आरक्षित निधि की मांग/आपूर्ति में अस्थायी परिवर्तन, जो घर्षणकारी कारकों जैसे कर निकासी या सरकारी व्यय से उत्पन्न होते हैं, बैंकिंग प्रणाली की चलनिधि में अस्थायी असंतुलन उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि सरकारी संतुलन ₹10,000 करोड़ के सकारात्मक संतुलन से घटकर लगभग शून्य हो जाता है, तो यह बैंकिंग प्रणाली के अधिशेष को उतनी राशि से बढ़ा देगा जब तक कि यह राशि कर संग्रह और अन्य राजस्व के रूप में सरकारी खाते में वापस नहीं आ जाती। इसी प्रकार का प्रभाव घाटे के लिए भी देखा जा सकता है। सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, रिजर्व बैंक चलनिधि अधिशेष या घाटे की प्रकृति का निर्णय करता है और उसी के अनुसार उपयुक्त साधनों का उपयोग किया जाता है।

स्थायी चलनिधि का प्रबंधन कैसे करें?

पारंपरिक रूप से, स्थायी चलनिधि से निपटने के लिए ओएमओ और एमएसएस संचालन का उपयोग किया जाता है। इन

संचालन की प्रक्रिया निम्नलिखित अनुच्छेदों में दी गई है। हालांकि, हाल ही में, रिज़र्व बैंक ने प्रणाली की स्थायी चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी चलनिधि प्रबंधन उपकरण किट को लंबी अवधि के विदेशी मुद्रा खरीद/बिक्री यूएसडी-आईएनआर स्वेप नीलामी और लंबी अवधि के रेपो संचालन (एलटीआरओ)/लक्षित लंबी अवधि के रेपो संचालन (टीएलटीआरओ) को शामिल करके विस्तारित किया है। पहली ऐसी खरीद/बिक्री स्वेप नीलामी 26 मार्च, 2019 को 3 वर्षों की अवधि के लिए 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए आयोजित की गई थी।

एलटीआरओ को फरवरी 2020 में चलनिधि प्रबंधन उपकरण किट को मजबूत करने के लिए पेश किया गया था। एलटीआरओ की प्रक्रिया रेपो के समान है, लेकिन वे एक से तीन वर्षों की लंबी अवधि के होते हैं।

ओएमओ संचालन की प्रक्रिया

रिज़र्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की ओएमओ बिक्री का प्रभाव प्रणाली की चलनिधि को कम करने का होता है। इसके विपरीत, सरकारी प्रतिभूतियों की ओएमओ खरीद का प्रभाव प्रणाली की चलनिधि को बढ़ाने का होता है। ओएमओ का संचालन रिज़र्व बैंक द्वारा नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से या सीधे द्वितीयक बाजार में लेनदेन करके किया जाता है। ऐसे प्रत्यक्ष द्वितीयक बाजार लेनदेन एनडीएस-ओएम (नेगोशिएटेड डीलिंग प्रणाली – ऑर्डर मैचिंग) प्लेटफ़ॉर्म पर किए जाते हैं, जो सरकारी प्रतिभूतियों के लिए एक गुमनाम ऑर्डर मैचिंग प्लेटफ़ॉर्म है। रिज़र्व बैंक द्वारा द्वितीयक बाजार में ओएमओ खरीद या बिक्री लेनदेन की कुल राशि पर डेटा साप्ताहिक रूप से प्रकाशित किया जाता है, हालांकि, एक सप्ताह की देरी के साथ। नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से ओएमओ संचालन के लिए, रिज़र्व बैंक प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से नीलामी की राशि, दिनांक, समय और प्रतिभूतियों के चयन का विवरण प्रदान करता है। नीलामी के दिन, बोली लगाने की अंतिम समय सीमा के बाद, बोलियों को संसाधित किया जाता है और रिज़र्व बैंक की ओएमओ नीलामी समिति कट-ऑफ़ यील्ड पर निर्णय लेती है। यह निर्णय प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से घोषित किया जाता है। नीलामी की आवृत्ति आमतौर पर पूर्व-निर्धारित या पूर्व-घोषित नहीं होती है, जैसा कि सरकार के बाजार उधारी कार्यक्रम के तहत आयोजित प्राथमिक नीलामी में होता है। यह विकसित हो रही चलनिधि स्थितियों पर निर्भर करता है।

ओएमओ संचालन से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा जी-सेक यील्ड पर इसका प्रभाव है। ओएमओ बिक्री की घोषणा प्रणाली में प्रतिभूतियों की अधिक आपूर्ति के कारण यील्ड को बढ़ा सकती है। ओएमओ नीलामी के लिए प्रतिभूतियों का चयन नीलामी की सफलता में एक महत्वपूर्ण कारक होता है। ओएमओ नीलामियों की कट-ऑफ़ यील्ड को बाजारों द्वारा गहन रूप से देखा जाता है, क्योंकि यह यील्ड्स के प्रति रिज़र्व बैंक के आराम स्तर को इंगित कर सकता है।

हाल ही में, रिज़र्व बैंक ने विशेष ओएमओ संचालित किए हैं, जिसमें सरकारी प्रतिभूतियों की एक साथ बिक्री और खरीद शामिल है, जिसे 'ऑपरेशन ट्विस्ट' भी कहा जाता है। ये संचालन प्रारंभ में चलनिधि के दृष्टिकोण से तटस्थ होते हैं और चलनिधि की स्थिति को बदले बिना दीर्घकालिक और अल्पकालिक ब्याज दरों पर वांछित प्रभाव डालने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं।

एमएसएस संचालन की प्रक्रिया

मार्केट स्टेबिलाइजेशन स्कीम (एमएसएस) रिज़र्व बैंक द्वारा प्रणाली में अधिशेष चलनिधि का प्रबंधन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक और उपकरण है। एमएसएस का उपयोग उन समयों में किया गया था जब बड़े पूंजी प्रवाह ने विदेशी मुद्रा बाजार में अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए रिज़र्व बैंक के हस्तक्षेप की आवश्यकता पैदा की थी। बड़ी मात्रा में डॉलर

की खरीद और परिणामस्वरूप चलनिधि में वृद्धि को सीमित करने के लिए, अत्यधिक पूंजी प्रवाह के मुद्रास्फीति संबंधी प्रभावों को रोकने के लिए स्टरलाइजेशन ऑपरेशंस आवश्यक हो गए। इसके अलावा, विमुद्रीकरण के बाद, जनता द्वारा बैंकों में जमा राशि में वृद्धि के कारण हुई बड़ी अधिशेष चलनिधि की स्थिति से निपटने के लिए एमएसएस का उपयोग किया गया। ओएमओ बिक्री और रिवर्स रेपो संचालन के लिए रिज़र्व बैंक को पर्याप्त सरकारी प्रतिभूतियों की आवश्यकता होती है। चूंकि ओएमओ बिक्री और रिवर्स रेपो केवल रिज़र्व बैंक के पास उपलब्ध सरकारी प्रतिभूतियों की सीमा तक ही संचालित किए जा सकते हैं⁸, इसलिए एमएसएस उन स्थितियों में उपयोगी साबित होता है जहां ओएमओ बिक्री वांछनीय नहीं है या प्रणाली में चलनिधि अधिशेष को प्रबंधित करने के लिए रिज़र्व बैंक के पास सरकारी प्रतिभूतियों की मात्रा अपर्याप्त है।

एमएसएस के तहत, सरकारी प्रतिभूतियों (जिनमें नकदी प्रबंधन बिल (सीएमबी), टी-बिल और परिपक्वता प्रतिभूतियां शामिल हैं) की नीलामी की जाती है। सामान्य सरकारी उधारी के विपरीत, एमएसएस के तहत जुटाई गई राशि को एक पृथक खाते में रखा जाता है और सरकार के लिए व्यय हेतु उपलब्ध नहीं होती है। यह आवश्यक है क्योंकि सरकार का व्यय रुपये की चलनिधि को फिर से बैंकिंग प्रणाली में स्थानांतरित कर देता, जिससे उस उद्देश्य को विफल कर दिया जाता जिसके लिए इस उपकरण का उपयोग किया गया था।

रिज़र्व बैंक के परामर्श से, सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए एमएसएस की सीमा और दहलीज सीमा तय करती है। सरकार से पुष्टि प्राप्त करने के बाद, रिज़र्व बैंक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सकल जारी राशि की सीमा और दहलीज राशि के बारे में जानकारी देता है।

एक बार जब एमएसएस के तहत सकल जारी राशि दहलीज सीमा तक पहुंच जाती है, या अतिरिक्त आवश्यकता होती है, तो रिज़र्व बैंक सरकार को इसके बारे में सूचित करता है। सरकार इस पर पुनर्विचार करती है और संशोधित सीमा और दहलीज सीमा की सलाह देती है।

एमएसएस के तहत प्रतिभूतियों का चयन, अन्य कारकों के साथ, अधिशेष चलनिधि स्थितियों की प्रकृति के अनुमान पर निर्भर करता है। यदि अधिशेष को लंबे समय तक बने रहने का पूर्वानुमान है, तो लंबी परिपक्वता वाली सरकारी प्रतिभूतियां जारी की जाएंगी। वहीं, यदि अधिशेष को अल्पकालिक माना जाता है, तो टी-बिल या सीएमबी जारी किए जाएंगे। नीलामी आयोजित करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है। नीलामी की खिड़की के दौरान, बाजार भागीदार आरबीआई के कोर बैंकिंग प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी बोलियां लगा सकते हैं। अन्य सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी की तरह, एक आंतरिक नीलामी समिति कट-ऑफ तय करती है और इसे प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है।

रिज़र्व बैंक के धन बाजार संचालन की प्रभावशीलता का नियमित रूप से विश्लेषण किया जाता है और इसे द्विवार्षिक मौद्रिक नीति रिपोर्ट (एमपीआर), एमपीसी वक्तव्यों और वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाता है। संचालन ढांचे और उसके घटकों को वित्तीय बाजारों, मौद्रिक स्थितियों का समर्थन करने और आधुनिक अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिष्कृत और संशोधित किया गया है, जबकि मौद्रिक नीति रुख के साथ सुसंगतता सुनिश्चित की गई है। प्रभावी चलनिधि प्रबंधन के लिए बेहतर बाजार खुफिया जानकारी के माध्यम से पूर्वानुमान की सटीकता में सुधार के लिए भी नियमित प्रयास किए गए हैं।

⁸ 2014 में उर्जित पटेल समिति ने एक स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) की सिफारिश की थी, जिससे रिवर्स रेपो संचालन में आरबीआई को संपार्श्विक प्रतिभूतियां प्रदान करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती। इससे ऐसी स्थितियों में चलनिधि प्रबंधन में प्रतिभूतियों के संतुलन की बाधा नहीं होती। इसके बाद, एसडीएफ की शुरुआत के लिए आरबीआई अधिनियम में संशोधन किया गया है।

विशेष संचालन

धन बाजार में विशेष संचालन का संचालन वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने और रिज़र्व बैंक की अंतिम ऋणदाता की भूमिका के दृष्टिगत आवश्यक हो जाता है। नीचे कुछ प्रमुख विशेष संचालन का विवरण दिया गया है:

- अक्टूबर 2008 से अक्टूबर 2009 तक, रिज़र्व बैंक ने विशेष रेपो नीलामी आयोजित की, ताकि बैंकों को म्यूचुअल फंड (एमएफ), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) की चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके।

अप्रैल 2020 में, म्यूचुअल फंड्स (एमएफ) पर पड़े रिडेम्प्शन दबाव और कोविड-19 संबंधित व्यवधानों के कारण कुछ कर्ज एमएफ के बंद होने से उत्पन्न संभावित संक्रमणीय प्रभावों के चलते चलनिधि संकट से निपटने के लिए, रिज़र्व बैंक ने म्यूचुअल फंड्स के लिए ₹50,000 करोड़ की विशेष चलनिधि सुविधा (एसएलएफ-एमएफ) की घोषणा की। इस योजना के तहत, रिज़र्व बैंक ने 90 दिनों की अवधि के रेपो संचालन निश्चित रेपो दर पर किए। एसएलएफ-एमएफ ऑन-टैप और ओपन-एंडेड थी। इस योजना के तहत प्राप्त निधि का उपयोग बैंकों को विशेष रूप से म्यूचुअल फंड्स की चलनिधि आवश्यकताओं को ऋण प्रदान करके, और म्यूचुअल फंड्स द्वारा धारित इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, वाणिज्यिक पत्र (सीपी), डिबेंचर और जमा प्रमाणपत्रों (सीडी) को संपार्श्विक के रूप में खरीदने और/या रेपो संचालन के माध्यम से पूरा करने के लिए करना था।

- टीएलटीआरओ (टार्गेटेड एलटीआरओ), जो एलटीआरओ का एक रूपांतर है, मार्च 2020 में विशिष्ट क्षेत्रों/उपकरणों को लंबी अवधि की धनराशि उपलब्ध कराने के लिए पेश किए गए। बैंकों द्वारा टीएलटीआरओ के तहत प्राप्त चलनिधि का उपयोग इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, वाणिज्यिक पत्र, और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर्स में प्राथमिक और द्वितीयक बाजारों में निवेश के लिए करना था। अप्रैल 2020 में, रिज़र्व बैंक ने टार्गेटेड लॉन्ग-टर्म रेपो ऑपरेशन 2.0 (टीएलटीआरओ 2.0) की घोषणा की, ताकि कोविड-19 व्यवधानों से प्रभावित छोटे और मध्यम आकार के कॉर्पोरेट्स, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों (एमएफआई) को चलनिधि पहुंचाई जा सके। टीएलटीआरओ 2.0 के तहत प्राप्त निधियों का उपयोग इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स, वाणिज्यिक पत्र, और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर्स में करना था। प्राप्त निधियों का कम से कम 50% निम्नानुसार आवंटित किया जाना था:

- i. 10% माइक्रो फाइनेंस संस्थानों (एमएफआई) द्वारा जारी प्रतिभूतियों/उपकरणों में।
- ii. 15% उन एनबीएफसी द्वारा जारी प्रतिभूतियों/उपकरणों में जिनकी परिसंपत्ति का आकार ₹500 करोड़ से कम है।
- iii. 25% उन NBFCs द्वारा जारी प्रतिभूतियों/उपकरणों में जिनकी परिसंपत्ति का आकार ₹500 करोड़ से ₹5,000 करोड़ के बीच है।

- 2021 में, महामारी से प्रभावित क्षेत्रों को और चलनिधि समर्थन प्रदान करने के लिए, पहला, मई 2021 में ₹50,000 करोड़ की ऑन-टैप चलनिधि विंडो खोली गई—जो प्रारंभ में मार्च 2022 के अंत तक उपलब्ध थी लेकिन बाद में जून 2022 के अंत तक बढ़ाई गई। यह तीन वर्षों तक की अवधि के लिए रेपो दर पर उपलब्ध कराई गई ताकि देश में कोविड-19 संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं और अवसंरचना को तेजी से बढ़ाने के लिए तत्काल चलनिधि उपलब्ध कराई जा सके। दूसरा, मई 2021 में, छोटे वित्तीय बैंकों (एसएफबी) को ₹10,000 करोड़ की तीन वर्ष की विशेष दीर्घकालिक रेपो

संचालन (एसएलटीआरओ) सुविधा रेपो दर पर प्रदान की गई ताकि छोटे व्यवसायिक इकाइयों, लघु और सूक्ष्म उद्योगों, और अन्य असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं को समर्थन दिया जा सके। तीसरा, जून 2021 में ₹15,000 करोड़ की एक चलनिधि विंडो खोली गई (जो प्रारंभ में मार्च 2022 के अंत तक उपलब्ध थी लेकिन बाद में जून 2022 के अंत तक बढ़ाई गई)। यह तीन वर्षों तक की अवधि के लिए रेपो दर पर उपलब्ध कराई गई, ताकि संपर्क-प्रधान क्षेत्रों में तनाव को कम किया जा सके। अंत में, वास्तविक अर्थव्यवस्था को ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने अप्रैल और जून 2021 के दौरान चयनित एआईएफआई के लिए ताजा ऋण देने हेतु ₹66,000 करोड़ का अतिरिक्त चलनिधि समर्थन घोषित किया।

संचार और प्रकटीकरण

चलनिधि प्रबंधन संचालन की जानकारी के बेहतर प्रसार के लिए, रिज़र्व बैंक ने एक दैनिक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें मुद्रा बाजार संचालन (एमएमओ) का विवरण दिया गया, ताकि रिज़र्व बैंक के चलनिधि संचालन के दैनिक प्रवाह और स्टॉक प्रभाव दोनों को प्रदर्शित किया जा सके। इसके अलावा, बैंकिंग प्रणाली की स्थायी चलनिधि स्थितियों का एक मात्रात्मक आकलन एक पखवाड़े के अंतराल के साथ प्रकाशित किया गया।

II. भारत की विदेशी मुद्रा संचालन

उद्देश्य⁹

रुपये की विनिमय दर बाजार की मांग और आपूर्ति की ताकतों द्वारा निर्धारित होती है। विनिमय दर प्रबंधन का उद्देश्य और प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि रुपये के बाहरी मूल्य में आर्थिक मौलिकताएं परिलक्षित हों। इस सामान्य उद्देश्य के अधीन, विनिमय दर नीति का संचालन तीन प्रमुख उद्देश्यों द्वारा निर्देशित होता है:

1. विनिमय दरों में अत्यधिक अस्थिरता को कम करना, जबकि यह सुनिश्चित करना कि बाजार व्यवस्थित रूप से कार्य करे।
2. विदेशी मुद्रा भंडार का पर्याप्त स्तर बनाए रखने में सहायता करना।

व्यवस्थित स्थितियां सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक घरेलू और विदेशी वित्तीय बाजारों में हो रहे विकास पर करीबी निगरानी रखता है।

भारत की पूंजी प्रवाह पर महत्वपूर्ण निर्भरता के कारण, जो अक्सर बड़े और अनियमित हो सकते हैं और अचानक रुकावटों और उलटफेरों के अधीन रहते हैं, तेल आयात की थोक मांग और सरकारी भुगतानों के समूह में आने के कारण विदेशी मुद्रा बाजार अस्थिरता की अवस्थाओं के प्रति संवेदनशील हो जाता है। हाल के दिनों में, व्यापार युद्ध की आशंकाओं, मध्य-पूर्व में तनाव और गंभीर बाह्य झटकों (जैसे 2020 में कोविड-19 के कारण बाजारों में अस्थिरता) जैसे महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक घटनाओं ने वैश्विक और घरेलू विदेशी मुद्रा बाजारों में बाधाएं उत्पन्न की हैं। हाल के वर्षों में रुपये के एनडीएफ (गैर-वितरणीय फॉरवर्ड) बाजार में ऑफशोर व्यापार मात्रा में तेज वृद्धि देखी गई है, जो संभवतः ऑनशोर बाजारों की मात्रा को भी पार कर गई है और ऑनशोर बाजार में मूल्य की खोज में योगदान बढ़ा रही है।

⁹ भारत का विदेशी मुद्रा भंडार: नीति, स्थिति और मुद्दे (डॉ. वाई.वी. रेड्डी का भाषण, 10 मई, 2002 को राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली में)

भारत में अस्थिरता के विभिन्न चरणों के प्रति नीति प्रतिक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू बाजार हस्तक्षेप रहा है, जिसे अत्यधिक अस्थिरता से जुड़ी चिंताओं को संबोधित करने के लिए मौद्रिक और प्रशासनिक उपायों के साथ जोड़ा गया है। इसके साथ-साथ, भाषणों और प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से संवाद स्थापित कर पूरक या समानांतर कदम उठाए गए हैं। विदेशी मुद्रा बाजार की तैयारी और परिपक्वता तथा बाह्य मोर्चे पर भारत की स्थिति (जैसे भंडार, ऋण, चालू खाता घाटा आदि) के आधार पर, मौजूदा और पूंजी खाता लेनदेन के लिए एक उदार विनिमय प्रणाली स्थापित करने के उद्देश्य से सुधारात्मक कदम प्रगतिशील रूप से उठाए गए हैं, जिससे विदेशी मुद्रा बाजार का और अधिक विकास हो सके।

जबकि नियामक उपाय वांछित परिणाम प्राप्त करने में समय ले सकते हैं, आरबीआई का विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप बाजार में विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति पर तुरंत प्रभाव डालता है। विनिमय दर में अस्थिरता को नियंत्रित करने के उद्देश्य से, आरबीआई विदेशी मुद्रा बाजार में विदेशी मुद्रा की बिक्री या खरीद करता है, ताकि अत्यधिक अस्थिरता को रोका जा सके और/या बड़े पैमाने पर होने वाले प्रवाह/निकासी को सुचारू किया जा सके। ये बिक्री और खरीद विनिमय दर के आसपास किसी पूर्वनिर्धारित लक्ष्य या सीमा द्वारा शासित नहीं होती हैं।

आरबीआई के हस्तक्षेप का प्रभाव

आरबीआई का हस्तक्षेप यूएसडी/आईएनआर मुद्रा जोड़ी में अत्यधिक अस्थिरता को नियंत्रित करने में सहायक होता है। उदाहरण के लिए, एक ऐसे परिदृश्य पर विचार करें, जहां भारी पूंजी प्रवाह के कारण डॉलर-रुपये की चाल में अस्थिरता बढ़ जाती है और रुपये पर डॉलर की तुलना में तीव्र सराहना का दबाव बनता है। ऐसे प्रवाह विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर की आपूर्ति बढ़ाते हैं, क्योंकि विदेशी निवेशक रुपये के बांड और इक्विटी शेयरों में निवेश करने के लिए डॉलर बेचते हैं। हालांकि, अधिकतर मामलों में, मूल्य समायोजन सुचारू नहीं होता है और यह ऊपर-नीचे होता रहता है। ऐसे परिदृश्य में, आरबीआई का हस्तक्षेप डॉलर की खरीद के माध्यम से डॉलर की अस्थायी अति-आपूर्ति के प्रभाव को निष्प्रभावी कर देता है। लेकिन, आरबीआई द्वारा खरीदे गए डॉलर और डॉलर की अति-आपूर्ति के बीच सीधा अनुपात नहीं होता है। आरबीआई के हस्तक्षेप का संकेत भर ही बाजार की भावनाओं को प्रभावित करता है, बाजार की गतिशीलता को बदलता है और मूल्य कार्रवाई को सुचारू बनाने में मदद करता है।

उदाहरण के लिए, यदि रुपया डॉलर के मुकाबले तेजी से सराहना कर रहा है, तो वे प्रतिभागी (जैसे आयातक) जो सबसे अनुकूल मूल्य पर डॉलर खरीदने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, रुपये के और अधिक मजबूत होने की उम्मीद में खरीदने से रुक सकते हैं। लेकिन यदि आयातक को रुपये की सराहना में उलटफेर होने की संभावना दिखती है, तो वह मौजूदा मूल्य पर तुरंत बाजार से डॉलर खरीदना चाहेगा। इसी तरह, अनुमोदित सीमा के भीतर अधिकृत डीलर (एडी)¹⁰ स्वामित्व वाले पद ले सकते हैं। एडी बैंक भी डॉलर खरीदने और बेचने के द्वारा मूल्य चाल से लाभ प्राप्त करने के लिए स्थिति लेते हैं। चूंकि एडी बैंकों के पास विदेशी मुद्रा बाजार में मांग और आपूर्ति की बेहतर जानकारी होती है, वे विदेशी मुद्रा में डॉलर की अति-खरीदी से अति-बिक्री की स्थिति और इसके विपरीत, जल्दी से अपनी स्थिति बदल सकते हैं। इस प्रकार, आरबीआई का हस्तक्षेप बाजार प्रतिभागियों के व्यवहार को प्रभावित करता है, जिससे घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर की अल्पकालिक मांग और आपूर्ति प्रभावित होती है और बाजार में स्थिरता आती है।

¹⁰ अधिकृत डीलर वे बैंक हैं जिन्हें विदेशी मुद्रा लेनदेन करने के लिए आरबीआई द्वारा लाइसेंस और अनुमति प्रदान की गई है।

इसी प्रकार, बड़े पूंजी प्रवाह के दौरान रुपये पर मूल्यहास के दबाव के साथ बढ़ी हुई अस्थिरता का सामना करने के लिए, आरबीआई बाजार में डॉलर बेचता है। इससे डॉलर की आपूर्ति बढ़ती है, जिससे रुपये के डॉलर के मुकाबले अवमूल्यन को रोका जा सकता है। बाजार की भावनाओं और प्रतिभागियों के व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है, जिससे अंततः बाजार में स्थिरता आती है।

विदेशी मुद्रा बाजार में आरबीआई के हस्तक्षेप का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका रुपये की चलनिधि की स्थिति पर एक साथ और समानुपातिक प्रभाव पड़ता है। यदि आरबीआई विदेशी मुद्रा बेचता है, तो उसे बाजार प्रतिभागियों से रुपये प्राप्त होते हैं, जिससे बैंकिंग प्रणाली की चलनिधि उसी अनुपात में घट जाती है। इसी प्रकार, जब आरबीआई विदेशी मुद्रा खरीदता है, तो बैंकिंग प्रणाली में रुपये की चलनिधि बढ़ जाती है। विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप के चलते रुपये की चलनिधि पर पड़ने वाले इस प्रभाव को कम करने के लिए, आरबीआई अपनी चलनिधि प्रबंधन उपकरणों के माध्यम से संतुलनकारी लेनदेन करता है। इस प्रक्रिया को 'स्टरलाइजेशन' कहा जाता है और इस प्रकार के विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप को कभी-कभी 'स्टरलाइज्ड हस्तक्षेप' कहा जाता है। हालांकि, इन दोनों के बीच हमेशा एक-से-एक संबंध होना आवश्यक नहीं है।

आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप के लिए उपयोग किए जाने वाले साधन

आरबीआई स्पोट, फॉरवर्ड्स, स्वैप और फ्यूचर्स बाजारों में हस्तक्षेप करता है। रुपये की विनिमय दर का निर्धारण स्पोट बाजार (T+2 सेटलमेंट) में लेनदेन से होता है। फॉरवर्ड्स (स्पोट के अलावा) के लिए विदेशी मुद्रा दरें स्पोट और स्वैप लेनदेन के संयोजन से प्राप्त होती हैं। फॉरवर्ड लेनदेन का प्रभाव स्पोट रेट और फॉरवर्ड प्रीमियम दोनों पर पड़ता है, जबकि स्वैप केवल फॉरवर्ड प्रीमियम को प्रभावित करते हैं। स्पोट, फॉरवर्ड्स और स्वैप ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) बाजार में ट्रेड किए जाते हैं। फॉरवर्ड बाजार में संचालन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह आरबीआई को घरेलू रुपये की चलनिधि की स्थिति को मौद्रिक नीति के रुख के अनुरूप नियंत्रित करने का लचीलापन प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, जब आरबीआई विदेशी मुद्रा बाजार से विदेशी मुद्रा खरीदता है और अपनी विदेशी मुद्रा गतिविधि के कारण रुपये की चलनिधि के प्रवाह को स्थगित करना चाहता है, तो वह एक सेल/बाय स्वैप कर सकता है। इस स्वैप से विदेशी मुद्रा की डिलीवरी को भविष्य की तिथि तक टाल दिया जाता है, जिससे रुपये की चलनिधि पर प्रभाव को भविष्य की तिथि तक स्थानांतरित किया जा सकता है।

मुद्रा वायदा अधिकृत एक्सचेंजों जैसे एनएसई, बीएसई आदि पर ट्रेड किए जाते हैं और विदेशी मुद्रा बाजार के एक्सचेंज-ट्रेडेड सेगमेंट का हिस्सा हैं। भारत में, ओटीसी और एक्सचेंज-ट्रेडेड सेगमेंट के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि जहां ओटीसी सेगमेंट में लेनदेन डिलीवरी आधारित होते हैं (दोनों रुपये और डॉलर के लेन-देन नियत तिथियों पर सेटल होते हैं), वहीं एक्सचेंज-ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव (ईटीसीडी) सेगमेंट में लेनदेन केवल रुपये के आधार पर नकद सेटल होते हैं, और केवल लाभ या हानि को रुपये के रूप में सेटल किया जाता है। ईटीसीडी बाजार का एक और महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह विदेशी मुद्रा भंडार के स्तर को प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि इसमें केवल शुद्ध राशि रुपये में सेटल की जाती है और डॉलर की डिलीवरी या प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है।

बाजार संचालन या तो सीधे या चयनित एजेंसी बैंकों के माध्यम से किया जा सकता है, हालांकि सामान्य रूप से प्राथमिकता चयनित बैंकों के माध्यम से अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप को दी जाती है। दोनों दृष्टिकोणों के अपने-अपने फायदे और नुकसान हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण का लाभ यह है कि यह हस्तक्षेप संचालन की गोपनीयता बनाए रखता है, जिससे उनकी प्रभावशीलता बढ़ती

है¹¹। आरबीआई के विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप संचालन से संबंधित डेटा कुछ अंतराल के साथ आरबीआई मासिक बुलेटिन और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के विशेष डेटा प्रसार मानकों में प्रकाशित किया जाता है (जो आरबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं)।

विदेशी मुद्रा बाजार में अत्यधिक अस्थिरता क्यों खराब है?

विनिमय दर की अस्थिरता समय के साथ विनिमय दर में बदलाव को दर्शाती है। इसका परिवर्तन जितना अधिक होगा, या जितनी जल्दी यह समय के साथ बदलता है, यह उतनी ही अधिक अस्थिर होगी। अस्थिरता को मापने के लिए मानक विचलन एक लोकप्रिय मापदंड है। ऐतिहासिक मानक विचलन एक पिछड़ा-दिखने वाला माप है, जबकि निहित अस्थिरता डेरिवेटिव बाजार में ट्रेड किए गए विकल्पों से प्राप्त की जा सकती है। बाजार प्रतिभागी अस्थिरता का पूर्वानुमान लगाने के लिए कई अन्य मॉडल का उपयोग करते हैं, जैसे कि ऑटो रेग्रेसिव कंडीशनल हेटेरोस्केडैस्टिसिटी (एआरसीच) और जेनरलाइज्ड ऑटो रेग्रेसिव कंडीशनल हेटेरोस्केडैस्टिसिटी (गार्च)। अस्थिर विनिमय दरें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश निर्णयों को अधिक कठिन बना देती हैं क्योंकि इससे जोखिम बढ़ता है। विनिमय दर जोखिम उस संभावना को दर्शाता है जिसमें विनिमय दर में परिवर्तन के कारण पैसा गंवाने की संभावना होती है।

कुछ उदाहरण जो यह दिखाते हैं कि कैसे व्यापारियों और निवेशकों को विनिमय दर में तीव्र परिवर्तन के कारण नुकसान हो सकता है, निम्नलिखित हैं:

उदाहरण 1: मान लीजिए कि एक भारतीय परिधान निर्माता को अमेरिका के एक रिटेलर से एक विशेष प्रकार के परिधान के 1000 टुकड़े निर्यात करने का आदेश प्राप्त हुआ है, जिसकी कीमत प्रति आइटम 10 डॉलर तय हुई है। परिधान निर्माता के लिए प्रत्येक आइटम की लागत ₹800 थी, और उस समय डॉलर-रुपया विनिमय दर ₹85 प्रति डॉलर थी। इस प्रकार, परिधान निर्माता को प्रत्येक आइटम पर ₹50 का लाभ होने की उम्मीद थी। मान लीजिए कि शिपमेंट तीन महीने के बाद किया जाना है और शिपमेंट का भुगतान भी उसी समय किया जाएगा। तीन महीने बीत जाने के बाद, शिपमेंट के बदले 10,000 डॉलर प्राप्त होते हैं। अब, तीन महीने के अंत में, यदि रुपया गिरकर ₹80 प्रति डॉलर हो जाता है, तो इस दर पर रूपांतरण करने पर प्रत्येक आइटम का मूल्य केवल ₹800 आता है। यह राशि मूल रूप से अपेक्षित ₹850 प्रति आइटम से कम है। इसलिए, विनिमय दर में बदलाव के कारण प्रत्येक आइटम पर ₹50 का अपेक्षित लाभ खो गया। यह एक उदाहरण है कि एक निर्यातक को मुद्रा मूल्य में परिवर्तन के कारण किस प्रकार का जोखिम उठाना पड़ता है।

उदाहरण 2: मान लीजिए कि एक अन्य उदाहरण में, एक भारतीय कंपनी ने पिछले वर्ष अमेरिका के एक विदेशी बैंक से एक साल की अवधि के लिए 1 मिलियन डॉलर का ऋण लिया था ताकि वहां की कम ब्याज दर का लाभ उठाया जा सके। उस समय डॉलर-रुपया विनिमय दर ₹85 प्रति डॉलर थी। मान लें कि उस उधारकर्ता के लिए अमेरिका में एक वर्ष का उधारी खर्च 3% था, जबकि भारत में उधारी दर 10% थी। भारतीय कंपनी ने डॉलर की राशि ₹85,000,000 में परिवर्तित कर अपने व्यवसाय में इसका उपयोग किया। इस निवेशक ने मुद्रा जोखिम का बचाव नहीं किया। डॉलर ने अप्रत्याशित रूप से रुपये के मुकाबले मजबूती दिखाई, और जब ऋण चुकाने का समय आया, तो यह ₹90 प्रति डॉलर पर व्यापार कर रहा था। इस प्रकार, उधार ली

¹¹ बीआईएस पेपर संख्या 73, "विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप: भारतीय रिजर्व बैंक का दृष्टिकोण", जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के श्री राकेश त्रिपाठी ने श्री जी. महालिंगम और श्री हरुण आर. खान के मार्गदर्शन में तैयार किया। यह पेपर 21 और 22 फरवरी 2013 को बेसल में बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स द्वारा आयोजित उभरते बाजारों के डिप्टी गवर्नर्स की बैठक में प्रस्तुत किया गया।

गई राशि को ब्याज के साथ चुकाने के लिए, भारतीय कंपनी को 1.03 मिलियन डॉलर खरीदने के लिए ₹92,700,000 खर्च करने पड़े। इसका अर्थ है कि कुल उधारी लागत भारत में उधार लेने की दर से भी अधिक हो गई।

दूसरी ओर, ऊपर दिए गए दोनों उदाहरणों में अनुकूल मुद्रा परिवर्तनों से लाभ हो सकता था। पहले उदाहरण में, यदि रुपये की विनिमय दर ₹90 हो जाती, तो शिपमेंट का मूल्य रुपये में बढ़ जाता, जिससे प्रति आइटम ₹100 का लाभ होता। इसी प्रकार, दूसरे उदाहरण में, यदि विनिमय दर ₹80 पर आ जाती, तो उधार लेने की लागत और भी कम हो जाती। इस प्रकार, अस्थिर विनिमय दर अप्रत्याशित हानि या लाभ का कारण बन सकती है।

इस प्रकार के विनिमय दर परिवर्तनों (जिसे मुद्रा जोखिम भी कहते हैं) से बचने और अपने आपको सुरक्षित रखने के लिए कई तरीके हैं। कुछ महत्वपूर्ण व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) साधन हैं: फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, और ऑप्शन्स आदि। हालांकि, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव या तो हानि के जोखिम को बढ़ाते हैं या उन जोखिमों से बचाव के लिए अतिरिक्त लागत का कारण बनते हैं।

विदेशी मुद्रा भंडार की पर्याप्तता

विदेशी मुद्रा बाजार हस्तक्षेप संचालन के माध्यम से आरबीआई द्वारा डॉलर की खरीद से विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होती है, जबकि डॉलर की बिक्री से विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आती है। विदेशी मुद्रा भंडार की पर्याप्तता का आकलन कई मानकों के आधार पर किया जाता है, जिसमें आयात कवर, पूंजी प्रवाह के विभिन्न प्रकारों की मात्रा, संरचना और जोखिम प्रोफ़ाइल, और अर्थव्यवस्था की बाहरी झटकों के प्रति संवेदनशीलता को ध्यान में रखा जाता है। कई अन्य देशों के विपरीत, भारत ने अपना भंडार चालू खाता अधिशेष के माध्यम से अर्जित नहीं किया है, बल्कि बड़े पैमाने पर पूंजी प्रवाह के माध्यम से एकत्र किया है। इसलिए, यह तर्क दिया जा सकता है कि भारत द्वारा रखे गए भंडार वास्तव में "कमाए गए" नहीं हैं, बल्कि "उधार लिए गए" प्रकृति के हैं, और उन्हें "वापस करना" पड़ सकता है यदि पूंजी प्रवाह उलट हो जाए, जैसा कि 2008-09 के दौरान हुआ था। विदेशी मुद्रा भंडार में लागत भी शामिल है, क्योंकि निवेश पर कम रिटर्न होता है, जबकि रुपये के निवेश पर अपेक्षाकृत उच्च रिटर्न मिलता है।

आरबीआई हस्तक्षेप डेटा

आरबीआई के हस्तक्षेप से संबंधित डेटा एक महीने के अंतराल के साथ व्यापार निपटान आधार पर आरबीआई मासिक बुलेटिन में प्रकाशित किया जाता है। ओटीसी बाजार में हस्तक्षेप के लिए खरीद, बिक्री और फॉरवर्ड बकाया का डेटा उपलब्ध कराया जाता है। ईटीसीडी बाजार में हस्तक्षेप पर एक अलग तालिका भी प्रदान की जाती है। इसके अलावा, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों पर शुद्ध ड्रेन संबंधित डेटा अंतराल के साथ आईएमएफ के *स्पेशल डेटा डिसेमिनेशन स्टैंडर्ड्स टेम्पलेट ऑन इंटरनेशनल रिज़र्व्स/फॉरेन करेंसी लिक्विडिटी* में प्रकाशित किया जाता है।

विदेशी मुद्रा बाजार में विशेष संचालन

स्थिर परिस्थितियों को बनाए रखने और चलनिधि तनाव की अवधि के दौरान विश्वास बहाल करने के उद्देश्य से, आरबीआई ने रुपये और विदेशी मुद्रा चलनिधि को बढ़ाने के लिए अतीत में विशेष उपाय किए हैं। कुछ महत्वपूर्ण विशेष संचालन निम्नलिखित हैं:

- 2008 में लेहमन ब्रदर्स के पतन के बाद, वैश्विक संकट के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर चलनिधि की कमी हो गई थी। भारतीय बैंकों, जिनकी विदेशी शाखाएँ या सहायक कंपनियाँ थीं, को उनके अल्पकालिक विदेशी फंडिंग

आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता देने के लिए, नवंबर 2008 में एक रुपये-डॉलर अस्थायी स्वैप सुविधा शुरू की गई। इस सुविधा के तहत, बैंकों को अधिकतम तीन महीने की अवधि के लिए अपने रुपये को डॉलर में स्वैप करने की अनुमति दी गई। इसके अलावा, इन स्वैप्स के लिए फंडिंग के लिए, बैंकों को लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी (एलएएफ) के तहत संबंधित अवधि के लिए प्रचलित रेपो दर पर उधार लेने की अनुमति दी गई। यह सुविधा बाद में एक्ज़िम बैंक तक बढ़ा दी गई, ताकि वे अपनी पहले से प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों के तहत भुगतान कर सकें। इस सुविधा का समग्र प्रभाव यह था कि पात्र इकाइयों को एलएएफ-योग्य प्रतिभूतियों के संपार्श्विक पर अस्थायी अवधि के लिए डॉलर उधार दिया गया।

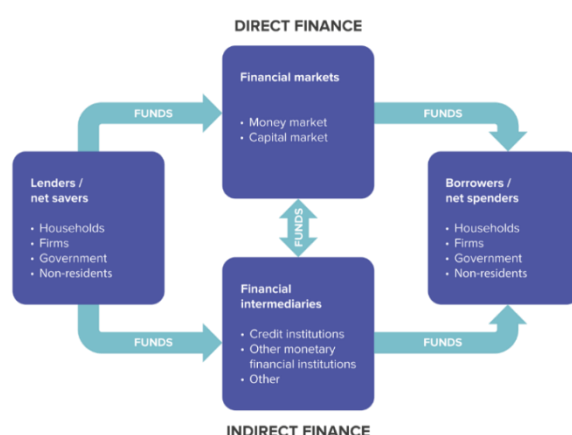
- 6 सितंबर, 2013 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) के लिए एफसीएनआर (बी) डॉलर निधियों को आकर्षित करने के लिए एक स्वैप विंडो की घोषणा की गई। यह सुविधा 30 नवंबर, 2013 तक खुली रही। इसके तहत, एफसीएनआर (बी) जमाओं के लिए स्वीकृत मुद्राओं में 3 से 5 वर्षों की अवधि के लिए एक अमेरिकी डॉलर-रुपया स्वैप विंडो प्रदान की गई। यह स्वैप सुविधा केवल अमेरिकी डॉलर में उपलब्ध थी और इसे प्रति वर्ष 3.5 प्रतिशत की निश्चित दर पर किया गया। लेन-देन के पहले चरण में, बैंक ने आरबीआई को अमेरिकी डॉलर आरबीआई संदर्भ दर पर बेचे। स्वैप लेन-देन के रिवर्स चरण में, रुपये की धनराशि को स्वैप प्रीमियम सहित आरबीआई को लौटाया गया, ताकि अमेरिकी डॉलर पुनः प्राप्त किए जा सकें। इस सुविधा का प्रभाव स्वैप अवधि के लिए आरबीआई के पास डॉलर की उपलब्धता बढ़ाने में हुआ। अधिकांश स्वैप तीन साल की अवधि के लिए किए गए, जो 2016 में समाप्त हुए।
- मार्च 2019 में, आरबीआई ने अपनी चलनिधि प्रबंधन रणनीति में फॉरेक्स स्वैप नीलामियों (रुपया-डॉलर के खरीद-बिक्री या बिक्री-खरीद स्वैप) को शामिल किया। पहली ऐसी खरीद/बिक्री नीलामी (जिसमें रुपये की चलनिधि इंजेक्ट की गई) 26 मार्च, 2019 को 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए 3 साल की अवधि हेतु आयोजित की गई। इस नीलामी के माध्यम से जुटाई गई अमेरिकी डॉलर राशि आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में स्वैप अवधि के लिए परिलक्षित हुई, जबकि यह आरबीआई की अग्रिम देनदारियों में भी दिखाई दी। 2020 में, आरबीआई ने फॉरेक्स स्वैप नीलामियों का उपयोग बाजार को अमेरिकी डॉलर की चलनिधि प्रदान करने के लिए किया (एक बिक्री/खरीद स्वैप के माध्यम से)। यह एक बहुमुखी उपकरण है, जिसका उपयोग लंबी या छोटी अवधि के लिए अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपये की चलनिधि को इंजेक्ट/अवशोषित करने के लिए किया जा सकता है।

अध्याय 5: वित्तीय स्थिरता

एक अच्छी तरह से काम करने वाली वित्तीय प्रणाली - जिसमें वित्तीय बाजार, वित्तीय मध्यस्थ (जैसे, बैंक, बीमा कंपनियां, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां, आदि) और वित्तीय अवसंरचना (भुगतान, समाशोधन और निपटान के लिए जिम्मेदार) शामिल हैं - आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उधारदाताओं से उधारकर्ताओं तक संसाधनों का कुशल अंतरण सुनिश्चित करता है। यदि किसी को केवल अपनी मेहनत की बचत के साथ या अपने माता-पिता, रिश्तेदारों या दोस्तों की सहायता से कारोबार शुरू करना पड़े तो कई शानदार आइडिया कभी साकार ही नहीं हो पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ, निवेश के अवसरों के अभाव में बचत व्यर्थ या निरर्थक हो जाएगी। इसी तरह, यदि आप किसी कंपनी में निवेश करते हैं और आप अपने शेयर या बॉन्ड बेचने या कहीं और निवेश करने में सक्षम नहीं हैं, तो आप एक ही कंपनी में हमेशा के लिए निवेशित रहते हैं और संभावनाओं से भरे उद्यमों के लिए पूंजी जुटाना और कारोबार को बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस प्रकार, एक स्थिर वित्तीय प्रणाली, समाज की संचित बचत को बाज़ार में उपलब्ध सर्वाधिक उत्पादक उपयोग के लिए आवंटित करके, न केवल वित्त तक पहुंच प्रदान करती है, जो आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि जोखिम प्रबंधन और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

वित्त दो चैनलों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है: सीधे प्रतिभूतियों (शेयरों या बॉन्ड) को जारी करके या अप्रत्यक्ष रूप से बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों जैसे वित्तीय मध्यस्थों के माध्यम से। इसे नीचे चार्ट -1 में दर्शाया गया है:

चार्ट -1 वित्तीय प्रणालियों के कार्य



दोनों चैनल आम तौर पर एक-दूसरे के पूरक होते हैं। तथापि, किसी देश में वित्तीय प्रणालियों के विकास की प्रकृति के आधार पर, एक चैनल चैनल की तुलना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में जहां वित्तीय बाजार अधिक विकसित हैं, प्रत्यक्ष या बाजार-आधारित वित्त अधिक लोकप्रिय है। दूसरी ओर, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में, अर्थव्यवस्था के वित्तपोषण में बैंक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। भारत में, बैंक न केवल परिवारों और

कॉर्पोरेट्स के लिए वित्तपोषण का मुख्य स्रोत हैं, बल्कि बचत के लिए मुख्य माध्यम भी हैं। एक स्वस्थ वित्तीय प्रणाली की अनुपस्थिति में, मध्यस्थता प्रक्रिया नहीं होगी, और आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा।

वित्तीय प्रणाली, ज्यादातर समय, अपनी भूमिका कुशलतापूर्वक निभाती है। हालांकि, जब वे ऐसा नहीं कर पाती हैं, तब वित्तीय अस्थिरता और वित्तीय संकट की घटनाएं सामने आती हैं। भले ही वित्तीय संकट चिंता का एक कारण है, लेकिन यह केवल तभी विनाशकारी हो जाता है जब वास्तविक अर्थव्यवस्था में फैल जाता है। यदि वित्तीय प्रणाली आघातों को सहन कर सकती है और इस तरह वास्तविक अर्थव्यवस्था को बिखरने से बचाए रख सकती है, तो इसे आघातसहनीय और अच्छी

तरह से काम करने वाला कहा जाता है। हालाँकि, आधुनिक अर्थव्यवस्था में वित्तीय संकट के कई प्रकरण हुए हैं, जब वित्तीय प्रणाली में आघात वास्तविक अर्थव्यवस्था में फैल गए जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और मंदी आई, और कभी-कभी, वास्तविक अर्थव्यवस्था से शुरू हुआ संकट पूरी वित्तीय प्रणाली में फैल जाता है जैसा कि कोविड संकट (2020) में हुआ था। विशेष रूप से, बैंक अपनी बैलेंस शीट में घाटे के कारण या कम पूंजी के कारण ऋण देना बंद कर सकते हैं या अवधिपूर्ण ऋणों को आगे की अवधि के लिए बढ़ाना बंद कर सकते हैं। यह अचानक चलनिधि की कमी के कारण भी हो सकता है क्योंकि बैंक की बैलेंस शीट में परिसंपत्ति आमतौर पर दीर्घकालिक और अतरल होती है। बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में, ऋणदाता उधारकर्ता की चुकाने की क्षमता को लेकर अपना भरोसा खो सकते हैं और उनकी प्रतिभूतियों में निवेश करने या कोई अल्पकालिक वित्त देने के लिए तैयार नहीं होंगे। परिणामस्वरूप, वित्त पोषण में गिरावट आती है जिससे उपभोग और निवेश तथा अंततः आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वित्तीय साहित्य इस तरह की घटना को प्रणालीगत जोखिम के रूप में वर्गीकृत करता है - वह जोखिम जिसमें *"वित्तीय प्रणाली द्वारा आवश्यक वित्तीय उत्पादों और सेवाओं का प्रावधान इस हद तक बाधित हो जाएगा कि आर्थिक विकास और कल्याण भौतिक रूप से प्रभावित हो सकते हैं"*¹²। प्रणालीगत जोखिम का निर्माण वित्तीय अस्थिरता की स्थिति बनाता है। इसलिए, वित्तीय स्थिरता एक ऐसी स्थिति है जिससे प्रणालीगत जोखिम की स्थिति बनने को रोका जाता है।

2007-09 का वित्तीय संकट प्रणालीगत जोखिम का प्रत्यक्षीकरण है क्योंकि आवास बुलबुले के फटने और बड़े वित्तीय संस्थाओं की विफलता के बाद कई अर्थव्यवस्थाएं मंदी में चली गईं। इस संकट ने कई नए जोखिमों को सामने लाया जिनका समाधान प्रणालीगत जोखिम को रोकने के लिए किया जाना आवश्यक था। इनमें लीवरेज का निर्माण, नए वित्तीय लिखतों की जटिलता, बाजारों की अस्पष्टता और संस्थाओं के बीच परस्पर संबंध शामिल हैं, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। विनियामक परिधि के बाहर वित्तीय मध्यस्थता, तथाकथित छाया बैंकिंग, और विनियमित बैंकिंग प्रणाली के साथ उसका संबंध भी वित्तीय संकट के लिए एक प्रमुख उत्प्रेरक था।

प्रणालीगत जोखिम के निर्माण की पहचान दो पहलुओं, अर्थात्, समय और क्रॉस-सेक्शनल आयाम के साथ की गई है। इसलिए, वित्तीय स्थिरता का उद्देश्य प्रणालीगत जोखिम को बनने से रोकना और साथ ही ऐसे प्रणालीगत जोखिम उत्पन्न होने के परिणामों के फैलाव को सीमित करना भी होना चाहिए। जोखिमों का फैलाव वित्तीय क्षेत्रों के विभिन्न खंडों के परस्पर संबंध से उत्पन्न होता है। जोखिम के फैलाव को सीमित करने का एक तरीका विभिन्न क्षेत्रों के बीच परस्पर संबंध को प्रतिबंधित करना हो सकता है। हालाँकि, इससे बाजार की दक्षता में कमी आएगी और मध्यस्थता की लागत में काफी वृद्धि होगी, साथ ही बाजार की संस्थाओं और वित्तीय सेवाओं के अंतिम उपभोक्ताओं को उच्च स्तर की असुविधा का सामना करना पड़ेगा। इसलिए, वित्तीय स्थिरता का उद्देश्य वित्तीय प्रणाली में प्रणालीगत जोखिमों की पहचान करना, उनकी निगरानी करना और उन्हें न्यूनतम करना तथा सबसे कुशल और प्रभावी तरीके से उनके प्रभाव-विस्तार को कम करना होना चाहिए। इसमें अधिकतम बाजार दक्षता, उच्चतम उपभोक्ता संरक्षण और न्यूनतम प्रणालीगत जोखिमों के उद्देश्यों के बीच एक अच्छा सामंजस्य शामिल है।

वित्तीय स्थिरता के उद्देश्यों को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों के अंतर्गत विभाजित एक ढांचे की स्थापना करके प्राप्त किया जा सकता है, जैसे, (1) वित्तीय स्थिरता के लिए एक संस्थागत और अधिशासन संरचना की स्थापना करना (2) प्रणालीगत जोखिम

¹² यूरोपीय सेंट्रल बैंक

को मापना और निगरानी करना; और (3) पहचाने गए प्रणालीगत जोखिमों को कम करने के लिए समष्टि विवेकपूर्ण नीतियों को लागू करना।

वित्तीय स्थिरता के लिए संस्थागत और अधिशासन संरचना

वर्ष 2007-09 के वित्तीय संकट के बाद कई केंद्रीय बैंकों ने सुस्पष्ट नीतिगत उद्देश्य के रूप में वित्तीय स्थिरता को आगे बढ़ाने की आवश्यकता को स्वीकार किया है। हालांकि, यह देखते हुए कि वित्तीय प्रणाली में कई वित्तीय मध्यस्थ और बाजार खंड शामिल हैं, वित्तीय स्थिरता के लिए जिम्मेदारी अधिकांश देशों में सरकार के पास होती है, जिसमें केंद्रीय बैंक एक महत्वपूर्ण सहायक भूमिका निभाते हैं।

प्रणालीगत जोखिम को मापना और निगरानी करना

अधिकांश केंद्रीय बैंकों और वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के लिए निरंतर आधार पर प्रणालीगत जोखिमों की निगरानी करना अनिवार्य हो गया है। यह निगरानी विभिन्न उपकरणों की सहायता से की जाती है जैसे सूक्ष्म और समष्टि स्तर पर दबाव परीक्षण, विभिन्न वित्तीय बाजार संस्थाओं और क्षेत्रों के बीच परस्पर संबंध का विश्लेषण, बैंकिंग स्थिरता संकेतक, प्रणालीगत चलनिधि संकेतक, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के साथ-साथ विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के लिए ऋण-सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि प्रवृत्तियों जैसे विभिन्न संकेतकों का उपयोग। अधिकांश अधिकार क्षेत्रों में, इन संकेतकों और उपकरणों को वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट या वित्तीय स्थिरता समीक्षा नामक आवधिक रिपोर्टों में प्रकाशित किया जाता है।

पहचाने गए प्रणालीगत जोखिमों को कम करने के लिए नीतियों को लागू करना

एक बार प्रणालीगत जोखिमों की पहचान हो जाने के बाद, अगला कार्य ऐसे जोखिमों को कम करने के लिए नीतियों को लागू करना है। कई आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में, वित्तीय संस्थाओं के विनियमन और पर्यवेक्षण के कार्यों को कई एजेंसियों के बीच वितरित किया जाता है। इससे इन संस्थानों की गतिविधियों के पर्यवेक्षण का समन्वय करना और ऐसी जानकारी साझा करना मुश्किल हो जाता है जो प्रणाली के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकती है। इसलिए, भले ही वित्तीय स्थिरता केंद्रीय बैंकिंग के प्रमुख उद्देश्यों में से एक रही है, लेकिन केंद्रीय बैंक की भूमिका चलनिधि के प्रावधान तक सीमित थी, अर्थात्, अंतिम ऋणदाता। वित्तीय संकट ने वित्तीय स्थिरता से निपटने के लिए नीतियों और उपकरणों को मान्यता दी।

वैश्विक वित्तीय संकट से पहले भारत में वित्तीय स्थिरता का प्रबंधन

संकट से पहले भी वित्तीय स्थिरता बनाए रखना रिज़र्व बैंक के मुख्य उद्देश्यों में से एक रहा है। रिज़र्व बैंक विगत कई वर्षों से प्रणालीगत जोखिम से निपटने के लिए, उन्हें स्पष्ट रूप से लेबल किए बिना, समष्टि विवेकपूर्ण नीतियों का पालन कर रहा है। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड और भुगतान और निपटान प्रणाली बोर्ड, केंद्रीय निदेशक मंडल की दोनों समितियों का गठन वित्तीय प्रणाली से संबंधित सूचनाओं को समग्र रूप से एकत्रित करने और व्यक्तिगत संस्था तथा प्रणाली दोनों ही स्तर पर अस्थिरता के किसी भी संकेत से निपटने के लिए संसूचित निर्णय लेने के लिए किया गया था। रिज़र्व बैंक के पास वाणिज्यिक और आवासीय अचल संपत्ति खंड में ऋण वृद्धि को कम करने के लिए अलग-अलग एलटीवी अनुपात का उपयोग करने का रिकॉर्ड रहा है। इसके अतिरिक्त, इक्विटी बाजार में भागीदारी पर सख्त ऋणजोखिम सीमा लागू करके, प्रतिपक्षकारों के असुरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर का पता लगाने के साथ-साथ बैंकों को रियल एस्टेट पर समग्र ऋणजोखिम सीमा रखने

का निदेश देकर वित्तीय बाजारों के क्रॉस-सेक्शनल स्पिलओवर को नियंत्रित किया गया है। इसी प्रकार, विदेशी मुद्रा दबाव के समय भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों की ओपन पोजीशन की सख्त सीमाएं लागू की हैं और पूंजी बाजार विनियामक के समन्वय से एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स पर उच्च मार्जिन मानदंड के साथ-साथ पोजीशन सीमाएं भी लागू की हैं। अंतिम ऋणदाता सुविधा के साथ-साथ मूल्य और विनिमय दर स्थिरता सुनिश्चित करने में केंद्रीय बैंक का अनुभव, वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में केंद्रीय बैंक की भूमिका को और भी महत्वपूर्ण बनाता है।

वैश्विक वित्तीय संकट के बाद भारत में वित्तीय स्थिरता का प्रबंधन:

सरकार ने वित्तीय स्थिरता बनाए रखने, अंतर-विनियामक समन्वय बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए तंत्र को सुदृढ़ और संस्थागत बनाने के लिए शीर्ष स्तरीय मंच के रूप में दिसंबर 2010 में वित्तीय स्थिरता विकास परिषद (एफएसडीसी) की स्थापना की। इस परिषद के अध्यक्ष वित्त मंत्री हैं, और इसके सदस्यों में वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों के प्रमुख शामिल हैं, जैसे, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), वित्त सचिव और/या सचिव, आर्थिक कार्य विभाग (डीईए), सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, और मुख्य आर्थिक सलाहकार। बाद में, मई 2018 में एफएसडीसी का पुनर्गठन किया गया ताकि आर्थिक कार्य विभाग के लिए जिम्मेदार राज्य मंत्री, डिजिटल लेनदेन और डेटा गोपनीयता के महत्व को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव, वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) आरंभ के बाद राजस्व सचिव और भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के अध्यक्ष जैसे अतिरिक्त सदस्यों को शामिल किया जा सके। इसके अलावा, अगस्त 2020 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) के अध्यक्ष को एफएसडीसी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। यदि आवश्यक हो तो परिषद अपनी बैठक में विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकती है। विनियामकों की स्वायत्तता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद अर्थव्यवस्था की व्यापक विवेकपूर्ण निगरानी करती है, जिसमें बड़े वित्तीय समूहों का कामकाज भी शामिल है और अंतर-विनियामक समन्वय और वित्तीय क्षेत्र विकास से जुड़ी समस्याओं को दूर करती है। यह वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन पर भी ध्यान केंद्रित करती है।

वित्तीय स्थिरता विकास परिषद की सहायता के लिए वित्तीय स्थिरता विकास परिषद की एक उप-समिति का गठन किया गया था, जिसने वित्तीय बाजारों पर पिछली उच्च-स्तरीय समन्वय समिति का स्थान लिया। उप-समिति की अध्यक्षता भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर करते हैं और इसमें एफएसडीसी के सभी सदस्यों (वित्त मंत्री और राज्य मंत्री (वित्त) को छोड़कर) का प्रतिनिधित्व होता है। इसके अलावा, चार उप गवर्नर भी सदस्य हैं, और भारतीय रिज़र्व बैंक के एक कार्यपालक निदेशक (वित्तीय स्थिरता के प्रभारी) उप-समिति के सदस्य सचिव हैं। देश में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और समष्टि विवेकपूर्ण विनियमन की निगरानी करने के लिए समष्टि अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों में विकास की समीक्षा करने के लिए उप-समिति नियमित रूप से बैठकें करती है। इसके अतिरिक्त, विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उप समिति द्वारा पांच तकनीकी समूह गठित किए गए हैं। ये हैं:

- १) **अंतर-विनियामक तकनीकी समूह (आईआरटीजी)** – इसे देश के वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों के बीच सहयोग बढ़ाने और सूचना साझा करने के लिए गठित किया गया। इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय

बोर्ड (सेबी), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) सहित प्रमुख वित्तीय विनियामक निकायों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

- 2) **वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता पर तकनीकी समूह (टीजीएफआईएफएल)** – इसे देश भर में वित्तीय साक्षरता और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक पहल के रूप में गठित किया गया है जिसका उद्देश्य आबादी के विभिन्न वर्गों, विशेष रूप से हाशिए पर पड़े और वंचित समुदायों के बीच वित्तीय ज्ञान और पहुंच में अंतराल को दूर करना है।
- 3) **अंतर-विनियामक फोरम (आईआरएफ)** – यह विभिन्न वित्तीय विनियामकों के बीच बेहतर समन्वय और संचार की सुविधा के लिए स्थापित एक सहयोगी मंच है। इस फोरम का उद्देश्य वित्तीय प्रणाली के कई खंडों को प्रभावित करने वाली साझा चुनौतियों और उभरती समस्याओं पर संवाद को बढ़ावा देकर वित्तीय क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले विनियामक ढांचे में सुधार लाना है।
- 4) **प्रारंभिक चेतावनी समूह (ईडब्ल्यूजी)** – यह वित्तीय स्थिरता के लिए संभावित जोखिमों को प्रारंभिक चरण में ही आकलन और निगरानी करने के लिए स्थापित एक विशेष समिति है।
- 5) **अंतर-विनियामक तकनीकी समूह-फिनटेक (आईआरटीजी-फिनटेक)** - भारत में एक सहयोगात्मक पहल जिसका उद्देश्य वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) नवाचारों के विकास और विनियमन के संबंध में विभिन्न वित्तीय विनियामकों के बीच संवाद और समन्वय को बढ़ावा देना है।

2007-09 के वित्तीय संकट ने व्यापक आर्थिक स्थिरता के लिए वित्तीय स्थिरता के महत्व को मजबूत किया और मौजूदा संरचना को मजबूत करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने अगस्त 2009 में स्वतंत्र रूप से परिचालन करने वाली वित्तीय स्थिरता इकाई (एफएसयू) की स्थापना की, जो 2023 में वित्तीय स्थिरता विभाग (एफएसडी) बन गई। एफएसडी छमाही वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट तैयार करता है, जो भारत की वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिमों पर एफएसडीसी की उप-समिति के सामूहिक मूल्यांकन को दर्शाता है। एफएसडी के अन्य प्रमुख कार्यों में वित्तीय प्रणाली की निरंतर आधार पर समष्टि विवेकपूर्ण निगरानी करना, बैंकिंग प्रणाली की आघातसहनीयता का आकलन करने के लिए आवधिक प्रणालीगत तनाव परीक्षण करना और वित्तीय स्थिरता की समस्याओं का आकलन करने के लिए मॉडल विकसित करना शामिल है, लेकिन यह इन तक ही सीमित नहीं है। अलग-अलग संस्थाओं की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य वाली सूक्ष्म विवेकपूर्ण नीतियों पर ध्यान केंद्रित करना अपर्याप्त पाया गया और वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा करने तथा प्रणालीगत जोखिम उत्पन्न होने को रोकने के उद्देश्य वाली समष्टि विवेकपूर्ण नीतियों को प्रमुखता मिली।

समष्टि विवेकपूर्ण नीतियों के उद्देश्य दोहरे हैं:

- प्रचक्रियता को कम करना, यानी, ऋण और लीवरेज के माध्यम से जोखिम के अत्यधिक निर्माण को रोकना, जो तेजी और मंदी के चक्रों (समय आयाम) को बढ़ाता है
- वित्तीय प्रणाली की आघातसहनीयता यानी, वास्तविक अर्थव्यवस्था में संक्रामक (क्रॉस-सेक्शनल आयाम) को सीमित करके और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं (उदाहरण के लिए उच्च पूंजी स्तर) को लक्षित करके बड़े व्यवधानों के बिना आघात को अवशोषित करने की क्षमता में सुधार करना

उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, कई उपकरणों की पहचान की गई है। ये उपकरण कभी-कभी स्टैंडअलोन समष्टि-विवेकपूर्ण उपकरण होते हैं या वे मौजूदा सूक्ष्म विवेकपूर्ण लिखतों पर एक ओवरले हो सकते हैं। पहले उद्देश्य को प्राप्त

करने के लिए, अर्थात्, प्रचक्रियता को कम करने के लिए, लीवरेज अनुपात (लीवरेज को कम करने और इस तरह बैंकों के ऋण देने पर अंकुश लगाने के लिए), ऋण-से-मूल्य अनुपात को सीमित करना (उदाहरण के लिए घर खरीदारों को अपने पैसे का अधिक हिस्सा लाना चाहिए), गतिशील प्रावधान, बैंक ऋणों पर उच्च जोखिम-भार, आदि, का उपयोग किया जाता है। इसी तरह, दीर्घकालिक संस्थागत निवेशकों को कुछ क्षेत्रों में निवेश करने से रोका जा सकता है या एक निश्चित क्रेडिट रेटिंग से नीचे के उपकरणों में निवेश नहीं करने का निर्देश दिया जा सकता है। प्रणाली स्तर पर, विनियामक सभी सेक्टरों में कुछ उपाय सुझा सकते हैं जैसे कि प्रतिचक्रिय पूंजी बफर, जब एक पूर्व-निर्धारित सीमा, जैसे कि जीडीपी अंतर के लिए ऋण, का उल्लंघन होता है। वित्तीय प्रणाली की आघातसहनीयता को बढ़ाने के लिए, पूंजी बफर (आर्थिक उन्नति के दौरान आर्थिक मंदी में उनका उपयोग करने के लिए एहतियाती भंडार के रूप में पूंजी का संचय), चलनिधि बफर (बैलेंस शीट में महत्वपूर्ण उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि परिसंपत्तियों की उपस्थिति), प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण संस्थाओं के लिए उच्च पूंजी आवश्यकताएं, बैलेंस शीट की ताकत का आकलन करने के लिए तनाव परीक्षण आदि का उपयोग किया जाता है।

कोविड-19 महामारी के दौरान और उसके बाद भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय संकट का प्रबंधन

जब कोविड-19 महामारी आई, तो भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो महीने (मार्च-मई 2020) की अवधि में नीतिगत दर में 115 आधार अंकों की बड़ी कटौती की; हालांकि, रिज़र्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर को 4 प्रतिशत के मुद्रास्फीति लक्ष्य से नीचे नहीं घटाकर अति-उदार होने से परहेज किया। अग्रानुक्रम में, 17.2 लाख करोड़ रुपये (2021-22 के सकल घरेलू उत्पाद के 8.7 प्रतिशत के बराबर) की चलनिधि बढ़ाने के उपायों के माध्यम से वित्तीय स्थितियों को काफी हद तक आसान बनाया गया। अच्छे संपार्श्विक के विरुद्ध, बैंकों के साथ प्रतिपक्षकारों के रूप में और अधिमानतः सावधि विधि-खंडों के साथ, भविष्य में उत्पन्न होने वाली मूल्य और वित्तीय स्थिरता चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ये सभी उपाय सूक्ष्म थे। 2021 के दौरान, अधिशेष तरलता को धीरे-धीरे अल्पावधि से दीर्घावधि में स्थानांतरित किया गया, जिसने अल्पावधि दरों को अति-निम्न स्तरों से ऊपर उठाया, जिससे वित्तीय स्थिरता की चुनौतियों का समाधान हुआ। महामारी के उपायों ने उदाहरण प्रस्तुत किया कि कैसे रिज़र्व बैंक विभिन्न उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से संतुलित कर सकता है – एफआईटी ढांचे द्वारा प्रदान किए गए लचीलेपन के भीतर मूल्य स्थिरता बनाए रखने के साथ-साथ वित्तीय स्थिरता पर भी विचार किया जाएगा। कोविड-19 महामारी के दौरान भी जब रिज़र्व बैंक ने नीतिगत दरों में उल्लेखनीय कमी की थी और उसके बाद मुद्रास्फीति में उछाल के दौरान जब पॉलिसी को तेजी से सख्त कर दिया गया था, तब बैंकों को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी के अंतर्गत रखी जा सकने वाली प्रतिभूतियों के अनुपात को समायोजित करके अधिक लचीला बना दिया गया था, ताकि मार्च 2023 के बैंकिंग संकट को ट्रिगर करने वाले मार्क टू मार्केट (एमटीएम) घाटे से बचा जा सके। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक ने विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया और एकीकृत एवं सुमेलीकृत संरचना विकसित करके बैंकों, एनबीएफसी तथा अन्य वित्तीय निकायों के विनियमन एवं पर्यवेक्षण में सुधार करने के लिए अनेक पहलें की हैं। परिणामस्वरूप, भारत की बैंकिंग प्रणाली लचीली और स्वस्थ बनी हुई है, जैसा कि बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता, पर्याप्त पूंजी और चलनिधि बफर और मजबूत आय वृद्धि द्वारा समर्थित बैंक ऋण में निरंतर वृद्धि में परिलक्षित होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय स्थिरता उपायों के माध्यम से बाजार के कामकाज को सुदृढ़ किया, सुचारू नीति संचरण सुनिश्चित करके मूल्य स्थिरता को सुगम बनाया।

वित्तीय स्थिरता से संबंधित हाल के घटनाक्रम वैश्विक स्तर पर कई प्रमुख प्रवृत्तियों और चुनौतियों को प्रकट करते हैं, जो आर्थिक बदलाव, विनियामक परिवर्तन और तकनीकी प्रगति से प्रेरित हैं।

1. समष्टि आर्थिक स्थितियां

- **बढ़ती ब्याज दरें और बैंकिंग क्षेत्र पर दबाव:** केंद्रीय बैंक उच्च मुद्रास्फीति से निपट रहे हैं और तदनुसार मौद्रिक नीतियों को समायोजित कर रहे हैं। मौद्रिक नीति संचरण में देरी को देखते हुए, उच्च नीति दरों से ब्याज दर जोखिम वित्तपोषण लागतों में कई तिमाहियों में साकार होते हैं। उच्च ब्याज दरों की लंबी अवधि भी बैंकिंग क्षेत्र के आघातसहनीयता की परीक्षा लेगी। उदाहरण के लिए, नवंबर 2023 में प्रकाशित यूरोपीय सेंट्रल बैंक की वित्तीय स्थिरता समीक्षा में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि बढ़ती ब्याज दरों के कारण उच्च ऋण-हानि प्रावधान अधिक हो गए हैं और बैंक की लाभप्रदता में गिरावट आई है। ऋण की मांग कमजोर हुई है, और ऋण मानक सख्त हो गए हैं, जिससे ऋण वृद्धि में कमी आई है।
- **वैश्विक अवस्फीति और भेद्यता:** अप्रैल 2024 में प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि यद्यपि निकट अवधि में वैश्विक वित्तीय स्थिरता जोखिम कम हो गए हैं, तथापि मध्यम अवधि की भेद्यता बनी हुई है। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि एक लंबी अवस्फीति यात्रा निवेशकों को आश्चर्यचकित कर सकती है, जिससे परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन हो सकता है और वित्तीय बाजार की अस्थिरता फिर से बढ़ सकती है। इसके अलावा, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में ऋण का संचय करने से ऋण असुरक्षाएं उत्पन्न हो सकती हैं।

2. प्रौद्योगिकीय प्रगति और जोखिम

- **वित्त में कृत्रिम मेधा:** वित्तीय स्थिरता बोर्ड वित्तीय सेवाओं में कृत्रिम मेधा (एआई) के एकीकरण की जांच कर रहा है। कृत्रिम मेधा का उपयोग कार्यों को स्वचालित करने, अनुपालन में सहायता करने और नए वित्तीय उत्पादों को विकसित करने के लिए किया जा रहा है। हालाँकि, कृत्रिम मेधा के कार्यान्वयन से मॉडल जोखिम, डेटा गुणवत्ता सुजुड़ी समस्याओं और अधिशासन की चुनौतियों सामने आती हैं। एआई मॉडल पर अत्यधिक निर्भरता की संभावना, जैसे अतीत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों पर निर्भरता, अच्छी तरह प्रबंधित नहीं होने पर महत्वपूर्ण जोखिम उत्पन्न करती है।
- **साइबर जोखिम-** पिछले 5 वर्षों में साइबर हमलों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है और वित्तीय क्षेत्र साइबर जोखिमों के अत्यधिक संवेदनशील बना हुआ है। आईएमएफ ने चेतावनी दी है कि "प्रमुख वित्तीय संस्थाओं में गंभीर घटनाओं से भरोसे में कमी, महत्वपूर्ण सेवाओं के व्यवधान और तकनीकी और वित्तीय अंतर्संबंध के कारण समष्टि वित्तीय स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है"।

3. विनियामक और पर्यवेक्षी प्रतिक्रियाएँ:

- **दबाव परीक्षण और विनियामक मानकों में वृद्धि:** भेद्यताओं को दूर करने के लिए, विशेष रूप से उच्च-ब्याज-दर वाले वातावरण में, प्राधिकारी दबाव परीक्षण बढ़ा रहे हैं और विनियामक मानकों को सख्त कर रहे हैं। इसमें गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थों (एनबीएफआई) की निगरानी में सुधार और दबाव की अवधि के दौरान पर्याप्त चलनिधि प्रावधान सुनिश्चित करना शामिल है।

भारत में वित्तीय स्थिरता से संबंधित नवीनतम घटनाक्रम, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक की हालिया रिपोर्टों और अपडेट में उल्लिखित है, कई प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है:

- **मजबूत समष्टि-आर्थिक आधार:** भारतीय अर्थव्यवस्था अपने मजबूत समष्टि-आर्थिक आधार के कारण आघातसहनीय वृद्धि को बनाए रखने के लिए तैयार है, जैसा कि मुद्रास्फीति को कम करने, मजबूत बाहरी स्थिति और चल रहे राजकोषीय समेकन में परिलक्षित होता है।
- **वित्तीय क्षेत्र का आघातसहनीयता:** भारतीय रिज़र्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की मजबूती पर प्रकाश डालती है। यह जोर देता है कि भारतीय बैंकों ने मजबूत पूंजी स्थिति और स्वस्थ परिसंपत्ति गुणवत्ता बनाए रखी है, जो वित्तीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- **गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए):** एनपीए के प्रबंधन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। बैंकों के लिए सकल एनपीए अनुपात में गिरावट आई है, जो बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता और तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए प्रभावी समाधान तंत्र को दर्शाता है।
- **वैश्विक जोखिम:** भारतीय रिज़र्व बैंक वैश्विक वित्तीय स्थितियों पर बारीकी से नज़र रख रहा है, विशेष रूप से भू-राजनीतिक तनाव और प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा नीतिगत सख्ती को ध्यान में रखते हुए। इन वैश्विक कारकों का भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों पर प्रभाव पड़ सकता है।
- **साइबर सुरक्षा:** वित्तीय सेवाओं के बढ़ते डिजिटलीकरण के साथ रिज़र्व बैंक ने साइबर सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के महत्व को रेखांकित किया है। इसमें साइबर खतरों के खिलाफ वित्तीय संस्थाओं की आघातसहनीयता बढ़ाना और मजबूत आईटी गवर्नेंस फ्रेमवर्क को सुनिश्चित करना शामिल है।
- **जलवायु जोखिम:** भारतीय रिज़र्व बैंक अपने विनियामक और पर्यवेक्षी ढाँचे में जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों को एकीकृत करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसमें वित्तीय स्थिरता पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करना और स्थायी वित्त प्रथाओं को प्रोत्साहित करना शामिल है।

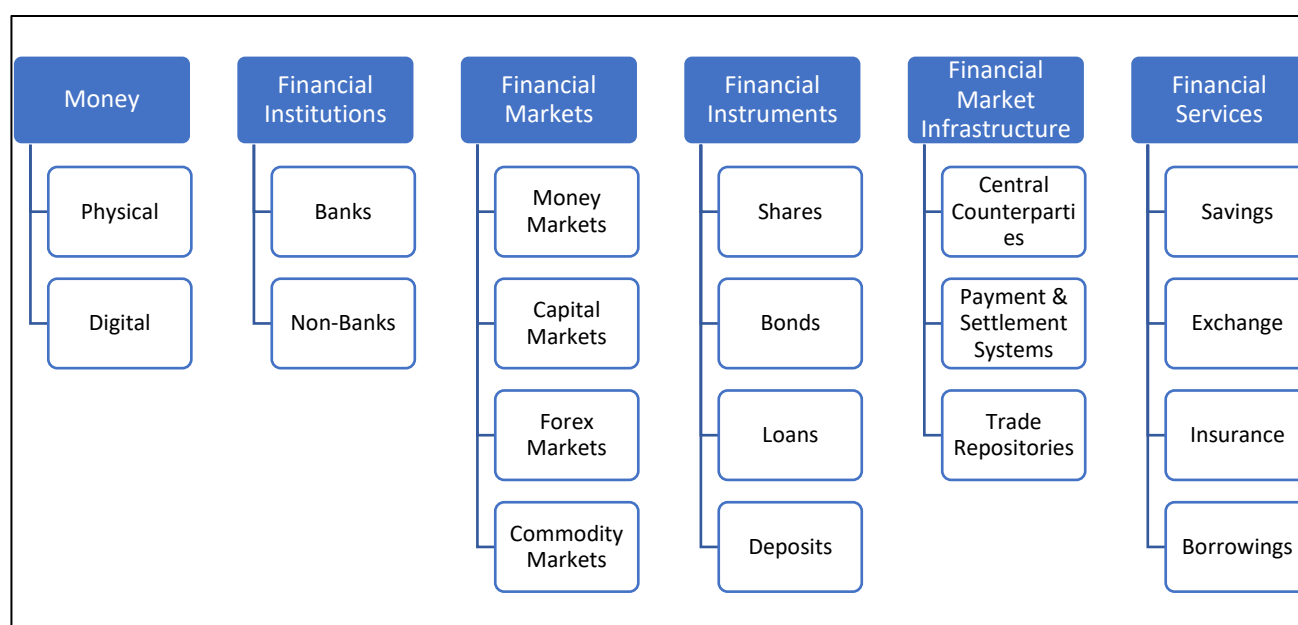
ये घटनाक्रम उभरती वैश्विक और घरेलू चुनौतियों के बीच भारत में एक स्थिर और आघात सहनीय वित्तीय प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।

कुल मिलाकर, यद्यपि वैश्विक वित्तीय प्रणाली वर्तमान में स्थिर है, तथापि तकनीकी एकीकरण और बदलती आर्थिक स्थितियों से उभरते जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए निरंतर सतर्कता की आवश्यकता है। नीति निर्माताओं और वित्तीय संस्थाओं को मजबूत अधिशासन ढांचे को सुनिश्चित करने और संभावित प्रणालीगत आघातों के प्रति आघातसहनीयता बनाए रखने के लिए सहयोग करना चाहिए।

अध्याय 6: भारतीय वित्तीय प्रणाली का अवलोकन

भारतीय वित्तीय प्रणाली में मोटे तौर पर मुद्रा (भौतिक और डिजिटल मुद्रा), वित्तीय संस्थाएं (बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड आदि), वित्तीय बाजार (मुद्रा बाजार, सरकारी प्रतिभूति बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार आदि), वित्तीय लिखत, वित्तीय बाजार अवसंरचना और वित्तीय सेवाएं (चित्र 1 देखें) शामिल हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक को भारत में विभिन्न बैंकों को विनियमित और उनका पर्यवेक्षण करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम और बैंककारी विनियमन अधिनियम के अंतर्गत व्यापक शक्तियां प्राप्त होती हैं। उपर्युक्त के अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक को विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत वित्तीय प्रणाली के विभिन्न घटकों को विनियमित और उनका पर्यवेक्षण करने की शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। इनमें से कुछ सबसे अधिक प्रासंगिक अधिनियम हैं,- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999, दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007, आदि।

चित्र 1 - वित्तीय प्रणाली का अवलोकन



वित्तीय विनियमन के लिए औचित्य

वित्तीय प्रणाली कई महत्वपूर्ण कार्य करती है: बचतकर्ताओं और निवेशकों के बीच मध्यस्थता करना, भुगतान को सुगम बनाना, जोखिम साझा करना, चलनिधि प्रदान करना, उधारकर्ताओं और उधारदाताओं के बीच सूचना विषमता को कम करना आदि। एक सुव्यवस्थित वित्तीय प्रणाली आर्थिक कल्याण में योगदान देती है, जबकि एक असंगठित या अस्थिर वित्तीय प्रणाली आर्थिक कठिनाई उत्पन्न करती है। विनियमन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय प्रणाली वास्तविक अर्थव्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन महत्वपूर्ण कार्यों को भली-भांति निष्पादित करती है।

वेकपूर्ण विनियमन का पारंपरिक दृष्टिकोण व्यक्तिगत संस्थाओं की स्थिरता की रक्षा करना रहा है। विवेकपूर्ण विनियमन के अलावा, उपभोक्ता संरक्षण के उद्देश्य से भी विनियम मौजूद हैं। ऐसे विनियम, जो इस बात की पड़ताल करते हैं कि व्यक्तिगत संस्थान किस प्रकार बाह्य आघातों का सामना करते हैं और उनकी सुदृढ़ता सुनिश्चित करते हैं, उन्हें सूक्ष्म विवेकपूर्ण विनियम

कहा जाता है। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद विनियमन के केन्द्रबिन्दु ने एक समष्टि विवेकपूर्ण चरित्र ले लिया है, क्योंकि इससे पता चला है कि मौजूदा विनियामक संरचना प्रणालीगत जोखिम को उत्पन्न होने से रोकने के लिए अपर्याप्त थी, जहां वित्तीय प्रणाली समग्र रूप से दुर्बल थी और मध्यस्थता करने की स्थिति में नहीं थी। अतएव, वित्तीय प्रणाली को आघातसहनीय बनाने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए सूक्ष्म विवेकपूर्ण और समष्टि विवेकपूर्ण, दोनों ही तरह के विनियमनों के संयोजन का उपयोग करने का दृष्टिकोण था। हाल के दिनों में, भारतीय रिज़र्व बैंक सिद्धांत आधारित विनियमन को अपनाने का प्रयास कर रहा है, जिसका अर्थ है कि विनियामक व्यापक सिद्धांतों को स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिससे विनियमित संस्थाओं द्वारा जोखिम प्रबंधन के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की अनुमति मिलेगी। यह विनियामक उद्देश्यों को प्राप्त करने के साथ लचीलेपन को संतुलित करने में सहायता करता है।

भारत में विनियामक और पर्यवेक्षी संरचना

भारत में वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण अलग-अलग विनियामक और पर्यवेक्षी प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक की विनियामक भूमिका के दायरे में वाणिज्य बैंकों, सहकारी बैंकों और इसके साथ पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की कुछ श्रेणियां शामिल हैं। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) अपने साथ पंजीकृत अन्य वित्तीय कंपनियों को विनियमित करता है। इसके अलावा, वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 (2019 का 23) ने राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 में संशोधन किया है, जिसके अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के विनियमन के लिए कुछ शक्तियां प्रदान करता है। सहकारी क्षेत्र के संबंध में, दोहरे विनियमन की प्रणाली मौजूद है, जिसमें एकल राज्य सहकारी बैंकों के मामले में संबंधित राज्यों के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) तथा बहु-राज्यीय सहकारी बैंकों के मामले में सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार (सीआरसीएस) संयुक्त रूप से इन कंपनियों को रिज़र्व बैंक के साथ विनियमित करते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक का सरोकार सहकारी बैंकों के बैंकिंग कार्य-कलापों तक ही है, जबकि इनके प्रबंधन पर आरसीएस / सीआरसीएस का नियंत्रण होता है। ऐसे दोहरे नियंत्रण से सहकारी बैंकों का विनियमन और पर्यवेक्षण, दोनों ही प्रभावित होता है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) बीमा क्षेत्र का विनियमन करता है और पूंजी बाजार, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों आदि को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा विनियमित किया जाता है।

देश में विभेदित बैंकों की अवधारणा वर्ष 2013 में डॉ. नचिकेत मोर की अध्यक्षता में गठित एक समिति की सिफारिशों के आधार पर शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य छोटे कारोबारों और कम आय वाले परिवारों को व्यापक वित्तीय सेवाएं प्रदान करना था। 'भुगतान बैंक' की अवधारणा पर पहली बार समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में चर्चा की गई थी, जिसने भारत में विभेदित बैंकिंग पर औपचारिक विमर्श शुरू किया। इसके बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवंबर 2014 में लघु वित्त बैंक (एसएफबी) और भुगतान बैंक (पीबी) स्थापित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए।

भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी भूमिका में वाणिज्य बैंक (लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक सहित), शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी), कुछ वित्तीय संस्थाएं (एफआई) और इसके साथ पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) शामिल हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) का पर्यवेक्षण राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा किया जाता है, जबकि आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) का पर्यवेक्षण राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) द्वारा किया जाता है।

वित्तीय संस्थाओं के विनियमन और पर्यवेक्षण के अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक वित्तीय बाजारों और वित्तीय बाजार अवसंरचना के कुछ हिस्सों का भी विनियमन और पर्यवेक्षण करता है जिनकी चर्चा आगे के अध्यायों में की जाएगी। भारतीय वित्तीय प्रणाली एक सक्रिय और विकासोन्मुख नेटवर्क है जो देश की आर्थिक वृद्धि और विकास को समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संस्थाओं, बाजारों और विनियामक निकायों के अपने विविधतापूर्ण संयोजन के साथ, यह प्रणाली चुनौतियों का सामना करने और तेजी से बदलते आर्थिक परिदृश्य के अवसरों का लाभ उठाने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। निरंतर सुधार, तकनीकी प्रगति और वित्तीय समावेशन पर ध्यान केंद्रित करना भारतीय वित्तीय प्रणाली की दीर्घकालिक स्थिरता और आघात सहनीयता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

अध्याय 7: वाणिज्यिक बैंकों का विनियमन

बैंक विनियमन के लिए मुख्य तर्क का पता उस विशेष भूमिका से लगाया जा सकता है जो बैंक अर्थव्यवस्था में निभाते हैं। बैंकिंग का मुख्य कार्य - मांग पर वापस ली जाने वाली जमाओं को स्वीकार करना और उधार देने और निवेश के लिए ऐसे धन का उपयोग करना - बचत को जुटाकर और निवेश और उपभोग को प्रोत्साहित करके आर्थिक विकास में मदद करता है। वित्तीय मध्यस्थों की अपनी भूमिका के निर्वहन में, बैंक आकार, जोखिम, तरलता और परिपक्वता के परिवर्तन कार्य करते हैं, जो उन्हें महत्वपूर्ण जोखिमों के लिए उजागर करते हैं। तरलता और परिपक्वता ट्रांसफार्मर के रूप में, बैंक मांग जमा जैसे अल्पकालिक और तरल उपकरणों का उपयोग करके दीर्घकालिक अनकदी परिसंपत्तियों (बंधक, उदाहरण के लिए) को निधि देते हैं। परिणामी परिसंपत्ति-देयता बेमेल, बैंकिंग व्यवसाय के लिए केंद्रीय होने के बावजूद, बैंकों को डिजाइन से नाजुक बनाता है। मांग पर जमा राशि को वापस करने में असमर्थता या यहां तक कि कथित अक्षमता से जनता के विश्वास का क्षरण हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप 'आहरण होड़' हो सकता है, जो किसी भी बैंक को नीचे ला सकता है। बैंकिंग प्रणाली में जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए स्थापित तंत्र - जमाकर्ता बीमा और केंद्रीय बैंक द्वारा तरलता समर्थन का प्रावधान - स्वयं नैतिक जोखिम जैसी अन्य नियामक चिंताओं को जन्म दे सकता है। बैंकों द्वारा सामना किए जा रहे इन जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा और अच्छी तरह से कार्य करना सुनिश्चित करने के लिए एक सुविचारित विनियामक ढांचा अनिवार्य शर्त है।

बैंक अत्यधिक लीवरेज संस्थान हैं क्योंकि वे अपनी इक्विटी पूंजी की अपेक्षाकृत बहुत कम मात्रा के खिलाफ भारी मात्रा में जमा और उधार जुटाते हैं। चूंकि बैंक जमाकर्ताओं के धन का उपयोग करके भारी लाभ उठाते हैं, इसलिए जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा बैंक विनियमन के केंद्रीय कारणों में से एक बन जाती है। बैंकों के अपरिष्कृत जमाकर्ता असममित सूचना उपलब्धता के कारण बैंकों की प्रभावी निगरानी करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। असममित जानकारी की उपलब्धता का ऐसा परिदृश्य तब उत्पन्न होता है जब आर्थिक लेनदेन के लिए एक पक्ष के पास दूसरे पक्ष की तुलना में अधिक भौतिक जानकारी होती है। यहां तक कि अगर कोई जमाकर्ता बैंक की देनदारियों की तुलना में उसकी परिसंपत्तियों के वर्तमान मूल्य का आकलन कर सकता है, तो स्थिति बदल सकती है क्योंकि बैंकिंग व्यवसाय गतिशील है क्योंकि बैंक लगातार अपनी परिसंपत्ति होल्डिंग में बदलाव कर रहे हैं और नए जमाकर्ताओं और लेनदारों को ले रहे हैं। भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए, जमाकर्ताओं के बीच नकारात्मक जोखिम के लिए बहुत कम सहिष्णुता है, जिनमें से कई बैंकों के साथ अपनी जीवन बचत रखते हैं। इसलिए, नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक और मानवीय दृष्टिकोण से, यह जरूरी है कि बैंकिंग प्रणाली अच्छी तरह से विनियमित हो।

भुगतान और निपटान सेवाओं की सुविधा में और मौद्रिक नीति के प्रसारण में वित्तीय प्रणाली में केंद्रीय भूमिका वाले बैंक भी बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता को नियामकों का एक अडिग उद्देश्य बनाते हैं। बैंकिंग संकट भुगतान और निपटान प्रणाली को बाधित करके और मौद्रिक नीति संचरण को कम प्रभावी बनाकर अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन हानि और बेरोजगारी के संदर्भ में भारी सामाजिक क्षति होती है।

उपरोक्त सभी कारणों से एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए बैंकिंग विनियमन की आवश्यकता होती है।

विनियमन क्या पूरा करने का इरादा नहीं रखता है?

जबकि जमाकर्ता संरक्षण, प्रणालीगत स्थिरता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, आदि विनियमन के लक्ष्य हैं, ऐसे कई पहलू हैं जो बैंकिंग विनियमन का उद्देश्य उसे पूरा करना नहीं है।¹³ सबसे पहले, अलग-अलग बैंकों की विफलता को रोकना बैंकिंग विनियमन का प्राथमिक केंद्र-बिन्दु नहीं है, इस शर्त के अधीन कि जमाकर्ता सुरक्षित हैं, वित्तीय स्थिरता प्रभावित नहीं होती है, और पर्याप्त बैंकिंग सेवाएं बनाए रखी जाती हैं। दूसरे, बैंकिंग विनियमन को अपने संचालन के बारे में बैंकर के वाणिज्यिक निर्णयों को प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए। अंत में, बैंकिंग विनियमन को दूसरों से अधिक कतिपय समूहों का पक्ष नहीं लेना चाहिए। बैंकों को अन्य संस्थानों से प्रतिस्पर्धा से भी बचाया नहीं जाना चाहिए।

बैंकिंग विनियमन के लिए कानूनी ढांचा

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अधिनियमन से पहले, बैंकिंग कंपनियों से संबंधित कानून के प्रावधान भारतीय कंपनी अधिनियम में निहित थे। कंपनी कानून भारत में 1850 के कंपनी अधिनियम 43 के साथ लाया गया था, जो अंग्रेजी कंपनी अधिनियम, 1844 पर आधारित था। जब भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 लागू हुआ, तो रिज़र्व बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य बैंकों के नकदी भंडार की अभिरक्षा को रखना, उन्हें विवेकाधीन तरीके से निभाव की मंजूरी देना और क्रेडिट नियंत्रण के साधनों के माध्यम से अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुसार उनके संचालन को विनियमित करना था। देश की बैंकिंग प्रणाली के संबंध में, रिज़र्व बैंक की प्राथमिक भूमिका की कल्पना बैंकों की अल्पकालिक आस्तियों की तरलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंतिम ऋणदाता के रूप में की गई थी। बैंकिंग विनियमन (बीआर) अधिनियम 17 फरवरी, 1949 को पारित किया गया था, जो व्यापक रूप से कई परिचालन मुद्दों के अलावा बैंक की स्थापना से लेकर समामेलन तक के कई पहलुओं से संबंधित है।

इसके अतिरिक्त, बैंकों का कामकाज भी उनकी श्रेणी के आधार पर विभिन्न संविधियों के अंतर्गत कवर किया जाता है, उदाहरणार्थ भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, बैंककारी कंपनी (एटीयू) अधिनियम 1970 और 1980, आरआरबी अधिनियम 1976। इसके अलावा, 1965 में, सहकारी बैंकों के कामकाज को विनियमित करने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम में धारा 56 डाली गई थी।

भारत में बैंकिंग विनियमन का विकास

जैसे-जैसे रिज़र्व बैंक के कार्य वर्षों में विकसित हुए, विनियामक और पर्यवेक्षी दृष्टिकोणों को आवश्यकतानुसार संशोधित किया गया। सामान्य रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से बैंकिंग प्रणाली में समय-समय पर हुए विकास के अनुरूप, बैंकिंग प्रणाली की सुदृढ़ता और स्थिरता को बनाए रखने के मूल उद्देश्य को बनाए रखते हुए विनियमन और पर्यवेक्षण के उद्देश्यों और दृष्टिकोणों में भी बदलाव आया है। एक नियामक और पर्यवेक्षक के रूप में रिज़र्व बैंक की भूमिका का ध्यान धीरे-धीरे नियम आधारित और इकाई-आधारित विनियमन से गतिविधि आधारित और पैमाना-आधारित विनियमन में स्थानांतरित हो गया है। विनियामक और पर्यवेक्षक के रूप में रिज़र्व बैंक की भूमिका का ध्यान धीरे-धीरे बैंकों के दिन-प्रतिदिन के कार्यकलापों के

¹³ अध्याय X के पैरा 10.11 के तहत मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट (अध्याय X), भारतीय रिज़र्व बैंक 4 सितंबर, 2008 / बैंकिंग में विनियामक और पर्यवेक्षी चुनौतियाँ।

सूक्ष्म विनियमन से स्थानांतरित हो गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विनियमों का अनुपालन ऐसे वातावरण में किया जाता है जहां बैंकों के प्रबंधन को अपने विवेक के आधार पर वाणिज्यिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी जाती है। चूंकि भारतीय बैंकिंग प्रणाली ने हाल के वर्षों में धीरे-धीरे वैश्विक चरित्र प्राप्त करना शुरू कर दिया है, विनियमन और पर्यवेक्षण ने प्रणालीगत अस्थिरता को रोकने, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और बाजार प्रथाओं में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया है। जबकि विनियमन और पर्यवेक्षण का मूल उद्देश्य "वित्तीय प्रणाली की सुदृढ़ता और स्थिरता को बनाए रखना" जारी रहा, विनियमन और पर्यवेक्षण ने एक साथ अन्य उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित किया है जैसे कि बैलेंस शीट की पारदर्शिता, जमाकर्ता के हितों की सुरक्षा, सामाजिक जरूरतों को पूरा करना और दक्षता में सुधार, सूचना विषमताओं को कम करना और धन-शोधन गतिविधियों को रोकना। संक्षेप में, घरेलू और बाह्य वित्तीय माहौल में निरंतर परिवर्तनों के साथ, रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर उपयुक्त रूप से और सक्रिय तरीके से, स्थिति विकसित होने पर अपने विनियामक और पर्यवेक्षी कार्यों के फोकस को ठीक करके प्रतिक्रिया दी।

भारतीय बैंकिंग प्रणाली

वाणिज्यिक बैंक

भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र काफी विविध है। स्वामित्व पैटर्न के आधार पर, बैंकों को मोटे तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जबकि भारतीय स्टेट बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) संसद के संबंधित अधिनियमों के अंतर्गत गठित किए गए हैं, गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में यथा परिभाषित बैंकिंग कंपनियां माना जाता है। 2015 तक, केवल सार्वभौमिक बैंकिंग लाइसेंस जारी किए जा रहे थे। हालांकि, 2015 के बाद से, विभेदित बैंकों (आला बैंकों - भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक) के लिए लाइसेंस भी सार्वभौमिक बैंकों के लाइसेंस के साथ जारी किए जा रहे हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

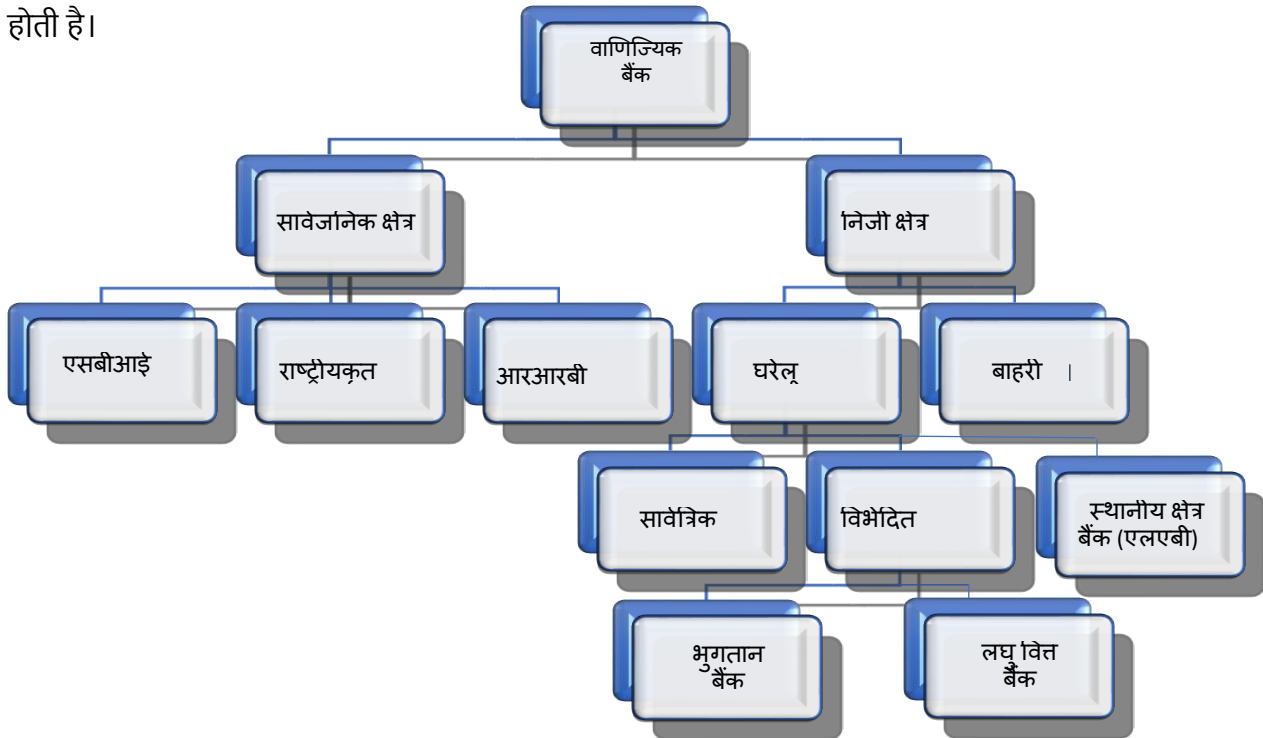
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की स्थापना विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी। स्थानीय स्तर की संस्थाएं होने के नाते, वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों के साथ आरआरबी को कृषि और ग्रामीण ऋण के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की इक्विटी का अंशदान केन्द्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक द्वारा 50:15:35 के अनुपात में किया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में वित्तीय विनियमन का कार्य रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है और पर्यवेक्षी शक्तियां नाबार्ड में निहित की गई हैं।

स्थानीय क्षेत्र के बैंक

स्थानीय क्षेत्र बैंकों (एलएबी) की कल्पना कम लागत वाली संरचनाओं के रूप में और ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में परिचालन के अपने क्षेत्रों में कुशल और प्रतिस्पर्धी वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई थी। इस योजना में आईएनआर 5 करोड़ की न्यूनतम पूंजी के साथ एक स्थानीय क्षेत्र बैंक और तीन सन्निहित जिलों को शामिल करते हुए संचालन के क्षेत्र की परिकल्पना की गई थी। इसके अलावा, एलएबी को विकसित होने का अवसर प्रदान करने के लिए, दिसंबर 2012 में, उन्हें दो और जिलों में अपने संचालन के क्षेत्र का विस्तार करने की अनुमति दी गई थी।

विदेशी बैंक

विदेशी बैंकों को भारत में शाखाओं या पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों (डब्ल्यूओएस) के रूप में काम करने की अनुमति है। भारत में विदेशी बैंकों द्वारा शाखाएं खोलने की अनुमति डब्ल्यूटीओ के प्रति भारत की वचनबद्धता द्वारा निर्देशित होती है।



बैंकिंग विनियम

बैंकों द्वारा सामना किए जा रहे विशेष जोखिमों और साथ ही, उनकी विफलता का अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को देखते हुए, यह अनिवार्य है कि बैंकिंग विनियमन व्यापक और सुदृढ़ हो। बैंकिंग विनियमन बैंक के कार्यों के संपूर्ण विस्तार को विनियमित करना चाहता है, जो उनकी स्थापना से शुरू होकर समापन तक होता है। मोटे तौर पर बैंकिंग विनियमन रणनीतियां प्रत्याशित कार्यनीतियों जैसे प्रवेश विनियम, कार्यकलाप विनियम, विवेकपूर्ण विनियम, अभिशासन विनियम, आचरण विनियम एवं सूचना विनियम तथा समाधान नीतियां जैसे पश्चात विनियम से संबंधित हैं।

बैंक लाइसेंसिंग

भारत में बैंकिंग परिचालन शुरू करने के लिए, चाहे वह भारतीय या विदेशी बैंक द्वारा हो, रिज़र्व बैंक से लाइसेंस की आवश्यकता होती है। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में प्रावधान है कि बैंकिंग कारोबार करने की इच्छुक कंपनी को विशिष्ट अधिनियमितियों के तहत स्थापित बैंकों (सरकारी क्षेत्र के बैंक और आरआरबी) को छोड़कर आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त करना होगा। आरबीआई 'प्रवेश के परीक्षण' पूरे होने के बाद ही लाइसेंस जारी करता है।

भारत में नए बैंकों की स्थापना के लिए न्यूनतम सांविधिक आवश्यकताएं बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में निर्धारित हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों में स्वामित्व को यह सुनिश्चित करने के आशय से विनियमित किया जाता है कि बैंकों का अंतिम स्वामित्व और नियंत्रण भली-भांति विविधीकृत हो और बैंकों के प्रमुख शेयरधारक सतत आधार पर उपयुक्त एवं उचित हों। बैंकों में विविधीकृत स्वामित्व प्राप्त करने के लिए सीमा का अनुपालन करने के लिए शेयरधारिता सीमा और कम

करने की अनुसूची निर्धारित की गई है।

अतीत में, यूनिवर्सल बैंक (यूबी) की स्थापना के लिए बैंक लाइसेंस 'स्टॉप एंड गो' आधार पर दिए गए थे। तदनुसार, 1993 में जारी किए गए गैर-सरकारी क्षेत्र के नए बैंकों के प्रवेश संबंधी दिशानिर्देशों के आधार पर दस लाइसेंस जारी किए गए थे और 2001 और 2013 में जारी लाइसेंसिंग दिशानिर्देशों के आधार पर प्रत्येक में दो लाइसेंस जारी किए गए थे। लाइसेंसिंग नीति की समीक्षा की गई और प्रतिस्पर्धा के स्तर को बढ़ाने और सिस्टम में नए विचारों को लाने के उद्देश्य से इसे 2016 में 'निरंतर प्राधिकरण'/ऑन टैप लाइसेंसिंग नीति के साथ बदल दिया गया है। तदनुसार, 'ऑन टैप' लाइसेंसिंग के लिए एक ढांचा स्थापित किया गया था।

भुगतान, जमा और क्रेडिट के कार्यात्मक बिलिंग ब्लॉकों का उपयोग करके वित्तीय समावेशन के कारण को आगे बढ़ाने के लिए, लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) और भुगतान बैंकों (पीबी) को लाइसेंस देने के लिए दिशानिर्देश 2014 में जारी किए गए थे। भुगतान बैंकों की स्थापना का उद्देश्य निम्नलिखित (i) लघु बचत खाते और (ii) प्रवासी श्रमिक कार्यबल, कम आय वाले परिवारों, छोटे व्यवसायों, असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं और अन्य उपयोगकर्ताओं को भुगतान/विप्रेषण सेवाएं प्रदान करके वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाना है। लघु वित्त बैंकों की स्थापना का उद्देश्य निम्नलिखित द्वारा वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाना है (i) बचत साधनों का प्रावधान, और (ii) उच्च प्रौद्योगिकी-कम लागत वाले संचालन के माध्यम से लघु व्यवसाय इकाइयों; छोटे और सीमांत किसान; सूक्ष्म और लघु उद्योग; और अन्य असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं को ऋण की आपूर्ति। तदनुसार, लघु वित्त बैंकों को दस लाइसेंस जारी किए गए जिनमें से एक लघु वित्त बैंक का दूसरे लघु वित्त बैंक के साथ समामेलित कर दिया गया। भुगतान बैंकों को सात लाइसेंस जारी किए गए थे जिनमें से एक बैंक ने स्वेच्छा से अपना कारोबार बंद कर दिया है। मौजूदा लघु वित्त बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा के बाद और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए, इन बैंकों का लाइसेंस 2019 में 'ऑन-टैप' किया गया था और वर्तमान में दो (2) एसएफबी को इन दिशानिर्देशों के तहत लाइसेंस दिया गया है। इसके अलावा, बेहतर स्पष्टता लाने के उद्देश्य से, एसएफबी के लिए यूनिवर्सल बैंक में ट्रांज़िशन के लिए पात्रता मानदंड अप्रैल 2024 में जारी किए गए थे।

शाखा विस्तार - व्यवसाय के नए स्थान (बैंकिंग आउटलेट) खोलना

बैंकों के कारोबार के नए स्थानों को खोलना और मौजूदा कारोबार स्थलों का स्थानांतरण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों द्वारा शासित होता है। इन प्रावधानों के अनुसार, बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के पूर्वानुमोदन के बिना, भारत में अथवा विदेश में कारोबार का नया स्थान नहीं खोल सकते अथवा उसी शहर, कस्बे अथवा गांव के भीतर मौजूदा कारोबार स्थल के स्थान में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तथापि, बड़ी संख्या में अल्पसुविधा प्राप्त और बैंक रहित जनसंख्या की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने शाखा लाइसेंसिंग मानदंडों को उदार बनाया है जिसमें सभी घरेलू वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर) को प्रत्येक मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमति लेने की आवश्यकता के बिना टीयर 1 से टीयर 6 केन्द्रों में बैंकिंग आउटलेट¹⁴

¹⁴ बैंकिंग आउटलेट एक निश्चित बिंदु सेवा सुपुर्दगी इकाई होती है, जिसका संचालन बैंक के कर्मचारियों या उसके कारोबार प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है, जहां जमा राशियां स्वीकार करने, चेकों के नकदीकरण/नकद आहरण या धन उधार देने की सेवाएं सप्ताह में कम से कम पांच दिन प्रति दिन न्यूनतम 4 घंटे के लिए प्रदान की जाती हैं। अधिक जानकारी के लिए

<https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/NOTI3062319C9C94C33494794C2B5271CF92878.PDF> देखें।

खोलने की अनुमति दी गई है, जब तक कि अन्यथा विशिष्ट रूप से प्रतिबंधित न हो। घरेलू वाणिज्यिक बैंकों को सलाह दी गई है कि वे बैंक रहित ग्रामीण केन्द्रों में कम से कम 25% ऐसे आउटलेट खोलें। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने अप्रैल 2022 में डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (DBU) की अवधारणा को त्वरित 'डिजिटल वित्तीय समावेशन' और 'डिजिटल बैंकिंग बुनियादी ढांचे की उपलब्धता' के दोहरे उद्देश्यों के साथ बैंकों के लिए डिजिटल रूप से विभेदित व्यवसाय मॉडल/रणनीति के रूप में लाया है। डीबीयू की परिकल्पना डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं की पहुंच और जागरूकता में तेजी लाने और डिजिटल रूप से वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने के लिए ग्राहकों के बीच झिझक को कम करने के लिए की गई है।

सांविधिक आरक्षित निधि का रखरखाव

वाणिज्यिक बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का एक निश्चित भाग रिज़र्व बैंक के पास नकदी के रूप में रखें, जिसे आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) कहा जाता है। आरक्षित नकदी निधि के अलावा, भारत में प्रत्येक बैंक आस्तियां भी रखेगा, जिसका मूल्य भारमुक्त अनुमोदित प्रतिभूतियों, नकदी, सोना और आरबीआई द्वारा अधिसूचित किसी अन्य लिखत में निवेश के रूप में अपने एनडीटीएल के निर्धारित प्रतिशत से कम नहीं होगा। इसे सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) कहा जाता है।

विवेकपूर्ण मानदंड

विवेकपूर्ण मानदंड बैंकों की सुरक्षा और मजबूती सुनिश्चित करने के लिए बैंकिंग नियामक द्वारा जारी दिशानिर्देश हैं। प्रमुख विवेकपूर्ण मानदंड आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण, पूंजी पर्याप्तता, एक्सपोजर आदि से संबंधित हैं।

- **आय निर्धारण और परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण (IRACP) मानदंड- परिसंपत्ति गुणवत्ता:** अपने व्यवसाय के दौरान, बैंक परिसंपत्तियों के विभिन्न वर्गों में उधार देते हैं और निवेश करते हैं, जिनमें से कुछ या तो आर्थिक मंदी या उधारकर्ता के लिए विशिष्ट कारकों जैसे प्रणालीगत कारकों के कारण गैर-निष्पादित हो सकते हैं। बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे वस्तुपरक रूप से ऐसी दबावग्रस्त आस्तियों की पहचान करें और सुधारात्मक कार्रवाई करें। इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप, रिज़र्व बैंक ने बैंकों के वित्तीय विवरणों में अधिक स्थिरता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश जारी किए। इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुरूप, भारतीय बैंकों को बैंक के लिए आय उत्पन्न करना बंद करने के बाद परिसंपत्तियों को गैर-निष्पादित के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, यदि सावधि ऋण के ब्याज और/या मूलधन की किस्त 90 दिनों की अवधि के लिए अतिदेय रहती है, तो बैंकों को उन्हें गैर-निष्पादित ऋण के रूप में वर्गीकृत करना आवश्यक है। बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रोद्भव आधार पर ऐसी आस्तियों से होने वाली आय का निर्धारण करें और गैर-निष्पादित आस्तियों के संबंध में प्रावधान भी करें। गैर-निष्पादित आस्तियों का वर्गीकरण गैर-निष्पादित आस्तियों की आयु के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाता है और प्रावधान परिसंपत्ति की आयु बढ़ने, प्रतिभूति की उपलब्धता तथा एनपीए के उच्च ग्रेडों के लिए उच्चतर प्रावधानीकरण अपेक्षाओं के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।
- **पूंजी और तरलता पर बासेल दिशानिर्देश:** बैंक की पूंजी (सामान्य इक्विटी और पूंजी के अन्य अनुमत वर्ग) बैंक द्वारा अप्रत्याशित नुकसान की स्थिति में जमाकर्ताओं की रक्षा करने वाले नुकसान को अवशोषित करने वाले बफर के रूप में कार्य करती है। इसके अलावा, पूंजी का स्तर बैंक के उत्तोलन को भी निर्धारित करता है, इसकी सुरक्षा सुनिश्चित

करता है। बासेल पूंजी पर्याप्तता ढांचे के तहत, बैंकों की पूंजी आवश्यकताओं को उनके परिसंपत्ति वर्गों के जोखिम प्रोफाइल से जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त, जिन बैंकों को घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उनसे अतिरिक्त पूंजीगत बफर रखने की अपेक्षा की जाती है। बासेल फ्रेमवर्क 1988 में बासेल I फ्रेमवर्क की शुरुआत के बाद से एक अवधि में विकसित हुआ, जिसके लिए बैंकों को अपने क्रेडिट जोखिम एक्सपोजर के प्रतिशत के रूप में पूंजी रखने की आवश्यकता थी। धीरे-धीरे, बैंकों की बैलेंस शीट पर अन्य जोखिमों जैसे बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम को शामिल करने के लिए ढांचे का विस्तार किया गया था। 2006 में जारी किए गए व्यापक बासेल II दिशानिर्देशों ने बैंकों को मानकीकृत मॉडल के अलावा अपने आंतरिक मॉडल का उपयोग करके जोखिमों का आकलन करने के लिए लचीलापन प्रदान किया।

वैश्विक वित्तीय संकट जिसने अच्छी तरह से पूंजीकृत बैंकों की विफलता देखी, ने पूंजी ढांचे के ओवरहाल को गति दी और बेसल III की शुरुआत की। यह पूर्व-संकट नियामक ढांचे की कमियों को दूर करता है और एक लचीली बैंकिंग प्रणाली के लिए एक नियामक आधार प्रदान करता है जो वास्तविक अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है। यह पूंजी की मात्रा और गुणवत्ता को बढ़ाने, जोखिम कवरेज को बढ़ाने और उत्तोलन अनुपात, पूंजी संरक्षण बफर, प्रतिचक्रीय पूंजी बफर और तरलता अनुपात (तरलता कवरेज अनुपात और निवल स्थिर वित्त पोषण अनुपात) जैसे मैक्रो-विवेकपूर्ण तत्वों को पेश करने का प्रयास करता है। चलनिधि अनुपात विशेष रूप से उन कमियों को दूर करने की कोशिश करता है जो संकट के दौरान चलनिधि जोखिम प्रबंधन में देखी गई थीं जैसे कि अपर्याप्त तरलता जोखिम प्रबंधन शासन, धन सांद्रता का समाधान करने में विफलता, तरलता की स्थिति का आकलन करने के लिए सार्थक नकदी प्रवाह अनुमानों की कमी, उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियों की अपर्याप्त होल्डिंग, तनाव परीक्षण में अंतराल और तनाव परीक्षणों के साथ आकस्मिक योजनाओं का अनुचित संयोजन, आदि। एलसीआर और एनएसएफआर दोनों पर दिशानिर्देश क्रमशः 9 जून, 2014 और 01 अक्टूबर, 2021 से लागू हुए हैं। रिज़र्व बैंक ने संशोधित बेसल मानकों के साथ अधिक अभिसरण को सुरक्षित करने के लिए परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं का निर्धारण करने के लिए पहले के सभी दृष्टिकोणों को प्रतिस्थापित करते हुए नया मानकीकृत दृष्टिकोण निर्धारित किया। नए मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत, बैंकों को अपने परिचालन जोखिम नियामक पूंजी गणना में हानि डेटा-आधारित आंतरिक हानि गुणक (आईएलएम) [बड़े बैंकों के लिए] के साथ एक वित्तीय विवरण-आधारित कारोबार संकेतक घटक (बीआईसी) पर विचार करने की आवश्यकता है।

- *एक्सपोजर मानदंड*: किसी बैंक के अपने प्रतिपक्षों के प्रति एक्सपोजर के परिणामस्वरूप उसकी आस्तियां एकल प्रतिपक्ष या संबद्ध प्रतिपक्षों के समूह के पास संकेंद्रण कर सकती हैं। बेहतर जोखिम प्रबंधन और ऋण जोखिमों के संकेंद्रण से बचने के उद्देश्य से विवेकपूर्ण उपाय के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने वृहत् एक्सपोजर मानदंड ढांचा लागू किया है जिसमें एकल प्रतिपक्ष और संबद्ध प्रतिपक्षों के समूह के प्रति बैंक के एक्सपोजरों पर नियत सीमाएं शामिल हैं। एक्सपोजरों को एकल अथवा प्रतिपक्षकारों के समूह तक सीमित करने के अलावा, बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि वे विशिष्ट उद्योग अथवा क्षेत्रों के प्रति समग्र वचनबद्धताओं के लिए आंतरिक सीमाएं निर्धारित करने पर विचार करें, ताकि एक्सपोजर विभिन्न क्षेत्रों में समान रूप से फैले रहें। इसके अतिरिक्त, बैंकों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे कंपनियों में शेयरधारिता पर कतिपय सांविधिक सीमाओं तथा पूंजी बाजार एक्सपोजर और अंतरा-समूह एक्सपोजर के संबंध में अन्य विनियामक एक्सपोजर सीमाओं का पालन करें। दिशा-निर्देशों में भारत

सरकार, राज्य सरकारों और भारतीय रिज़र्व बैंक/नाबार्ड जैसे विनियामक निकायों को कतिपय एक्सपोजरों के लिए छूट का भी प्रावधान है।

निवेश दिशानिर्देश: बैंक विभिन्न प्रकार के लिखतों जैसे सरकारी प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, शेयरों, डिबेंचर और बॉन्ड, सहायक / संयुक्त उद्यम और वाणिज्यिक पत्रों और म्यूचुअल फंड इकाइयों में निवेश कर सकते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक वित्तीय बाजारों में हो रही गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए तथा विकसित हो रही अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के लिए दिशानिर्देश जारी करता है।

निवेशों के वर्गीकरण, माप और मूल्यांकन पर वैश्विक मानकों, पूंजी पर्याप्तता ढांचे के साथ संबंधों के साथ-साथ घरेलू वित्तीय बाजारों में प्रगति में समय के साथ हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए, बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा और अद्यतन करने की आवश्यकता महसूस की गई, जो दो दशकों से अधिक समय से काफी हद तक अपरिवर्तित रहे हैं। संशोधित दिशानिर्देशों के अंतर्गत, बैंकों के संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो को तीन श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए, यथा परिपक्वता तक धारित (एचटीएम), बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) और लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल)। ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी) एफवीटीपीएल के भीतर एक अलग निवेश उप-श्रेणी होगी। मुख्य विशेषताओं में निवेश पोर्टफोलियो का सिद्धांत आधारित वर्गीकरण, परिपक्वता तक धारित(एचटीएम) श्रेणी में/से अंतरण और एचटीएम से बिक्री के आसपास विनियमों को कड़ा बनाना, कुछ शर्तों को पूरा करने के अध्वधीन एचटीएम में गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों को शामिल करना, एचटीएम पर अधिकतम सीमा को हटाना, उचित मूल्य लाभ और हानि का सममित उपचार, ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी) के तहत स्पष्ट रूप से अभिज्ञेय ट्रेडिंग बुक, एचएफटी के तहत होल्टिंग अवधि पर 90-दिवसीय सीमा को हटाना, और निवेश पोर्टफोलियो पर अधिक विस्तृत खुलासे शामिल है।

जबकि संशोधित दिशानिर्देश बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के लिए लेखांकन मानदंडों को वैश्विक वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के अनुरूप बनाते हैं, निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफआर), गैर-एसएलआर निवेशों के संबंध में उचित सावधानी/सीमाएं, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, समीक्षाएं और रिपोर्टिंग आदि जैसे महत्वपूर्ण विवेकपूर्ण सुरक्षा उपायों को बनाए रखा गया है और मूल्यांकन की विश्वसनीयता पर विवेकपूर्ण चिंताओं को दूर किया गया है।

- तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान: बैंक बैलेंस शीट को डिक्लोग करने और पूंजी के कुशल पुनर्निर्वाह के लिये तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का तेज़, समयबद्ध समाधान महत्वपूर्ण है। बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2017, और बाद में भारत सरकार द्वारा दिए गए प्राधिकरण ने रिज़र्व बैंक को तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए बैंकों को निर्देश जारी करने का अधिकार दिया, जिसमें परिसंपत्तियों को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 (आईबीसी) में संदर्भित करना शामिल है। उक्त प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा की गई कार्रवाई और 7 जून 2019 को दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण फ्रेमवर्क जारी करना भारत में दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विनियामक दृष्टिकोण में एक आमूलचूल बदलाव को दर्शाता है। इस ढांचे का उद्देश्य दबावग्रस्त आस्तियों का सामूहिक कार्रवाई खंडों के साथ पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है ताकि दबावग्रस्त आस्तियों के संभावित चिंताजनक मूल्य को मान्यता देते हुए ऋणदाताओं द्वारा अधिकतम मूल्य प्राप्त किया जा सके। पुनर्गठन के लिए पिछली योजनाओं के विपरीत, बैंकों को पूर्ण विवेकाधिकार और लचीलापन दिया गया है कि वे उन उधारकर्ताओं से निपटने के लिए अपने स्वयं के जमीनी नियम तैयार करें, जिनके पास कई बैंकों

के साथ एक्सपोजर है। ऋणदाता समाधान योजनाओं को लागू कर सकते हैं जो उनकी आंतरिक नीतियों और जोखिम उठाने की प्रवृत्ति के अनुरूप हैं।

- **क्रेडिट जोखिम बाजार:** भारत में क्रेडिट जोखिम बाजार की गहराई वित्तीय प्रणाली को परिष्कार के अगले स्तर तक ले जाने के लिए एक आवश्यक शर्त है। आरबीआई हाल के वर्षों में इस दिशा में कई कदम उठा रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने कारपोरेट ऋणों के लिए द्वितीयक बाजार के विकास हेतु एक स्व-विनियामक संगठन के रूप में द्वितीयक ऋण बाजार संघ की स्थापना को सुकर बनाया। ऋण जोखिम बाजार के विकास के लिए जारी किए गए निदेशों पर संक्षेप में नीचे चर्चा की गई है:
 - **ऋण एक्सपोजर का हस्तांतरण:** ऋण में एक मजबूत द्वितीयक बाजार ऋण संस्थानों द्वारा क्रेडिट एक्सपोजर के प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र हो सकता है। यह तरलता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त रास्ते भी बनाता है। 24 सितंबर, 2021 को जारी किए गए ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण पर मास्टर निर्देश बैंकों, एनबीएफसी और एआईएफआई द्वारा ऋण एक्सपोजर के हस्तांतरण के लिए व्यापक नियामक ढांचा तैयार करते हैं। विशेष रूप से, दबावग्रस्त ऋण एक्सपोजर को बाजार भागीदारों के व्यापक समूह को विनिदष्ट शर्तों के अधधीन अंतरित करने के लिए एक समर्थकारी ढांचा स्थापित किया गया है।
 - **प्रतिभूतिकरण:** पारंपरिक प्रतिभूतिकरण संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए 24 सितंबर, 2021 को जारी 'मानक परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण' पर निर्देशों ने नियामक ढाँचे को तर्कसंगत बनाया है। न्यूनतम धारण अवधि और न्यूनतम प्रतिधारण आवश्यकता पर आवश्यकताओं को काफी सरल बनाया गया है, जबकि प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर के लिए पूंजी आवश्यकताओं को सरल, पारदर्शी और तुलनीय (एसटीसी) प्रतिभूतिकरण के मामले में रियायती पूंजी व्यवस्था सहित बासेल III आवश्यकताओं के साथ अभिसरित किया गया है। इन दिशा-निर्देशों में प्रतिभूतिकरण के लिए एक मजबूत समर्थन पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए विभिन्न सुविधा प्रदाताओं के लिए आवश्यकताओं को भी निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए 25 जनवरी, 2023 को तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के ढाँचे के प्रतिभूतिकरण पर एक चर्चा पत्र जारी किया गया था। जनता की टिप्पणियों और आंतरिक विचार-विमर्श के आधार पर, अंतिम दिशानिर्देश शीघ्र ही जारी किए जाएंगे।

जोखिम प्रबंधन

वित्तीय मध्यस्थता की प्रक्रिया में बैंकों को विभिन्न प्रकार के वित्तीय और गैर-वित्तीय जोखिमों का सामना करना पड़ता है, जैसे ऋण, ब्याज दर, विदेशी विनिमय दर, तरलता, इक्विटी मूल्य, वस्तु मूल्य, कानूनी, नियामक, प्रतिष्ठा, परिचालन, आदि। ये जोखिम अत्यधिक अन्योन्याश्रित हैं और जोखिम के एक क्षेत्र को प्रभावित करने वाली घटनाओं में अन्य जोखिम श्रेणियों की एक श्रृंखला के लिए प्रभाव पड़ सकता है। रिज़र्व बैंक बैंकों को समय-समय पर दिशानिर्देश जारी करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंकों का प्रबंधन किए गए जोखिमों के समग्र स्तर की पहचान, माप, निगरानी और नियंत्रण करने की क्षमता में सुधार करने को पर्याप्त महत्व देता है। ये दिशानिर्देश बैंकों की जोखिम प्रबंधन संरचना, विभिन्न जोखिमों का आकलन और प्रबंधन करने के लिए तंत्र, जोखिम एकत्रीकरण और पूंजी आवंटन जैसे पहलुओं से संबंधित हैं।

इसके अतिरिक्त, बैंकों से यह भी अपेक्षित है कि वे औपचारिक दबाव परीक्षण ढाँचे को प्रचालनात्मक रूप दें ताकि उन्हें

एक सुदृढ़ एवं भविष्योन्मुखी जोखिम प्रबंधन ढांचा तैयार करने में सहायता मिल सके। बैंकों को विनियामक द्वारा दर्शाए गए सभी स्तरों की गंभीरता के आघातों का सामना करने के लिए अपने लचीलेपन का मूल्यांकन करना अपेक्षित है और कम से कम आधारभूत आघातों से बचने में सक्षम होना चाहिए।

जलवायु संबंधी जोखिम

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अधिक स्पष्ट होने के साथ, विनियमित संस्थाओं के साथ-साथ समग्र रूप से वित्तीय प्रणाली के लिए जलवायु संबंधी जोखिमों का आकलन करना अनिवार्य हो गया है। इस संबंध में, आरबीआई ने सतत वित्त समूह (एसएफजी) के रूप में जाना जाने वाला एक नया प्रभाग बनाकर विनियमित संस्थाओं के लिए जलवायु संबंधी जोखिमों का विनियामक और जोखिम मूल्यांकन शुरू कर दिया है।

अपने अधिदेश के हिस्से के रूप में वित्तीय स्थिरता के साथ एक पूर्ण-सेवा केंद्रीय बैंक होने के नाते, रिज़र्व बैंक मानता है कि जलवायु परिवर्तन विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए जलवायु से संबंधित वित्तीय जोखिमों में तब्दील हो सकता है जिनके व्यापक वित्तीय स्थिरता निहितार्थ हो सकते हैं। इसलिए, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर एक रणनीति तैयार करने के लिए, जलवायु जोखिम और सतत वित्त पर एक चर्चा पत्र (डीपी) को सार्वजनिक टिप्पणियों और प्रतिक्रिया के लिए 27 जुलाई, 2022 को आरबीआई की वेबसाइट पर रखा गया था। इस संबंध में प्राप्त फीडबैक के विश्लेषण के आधार पर, आरई के लिए जलवायु जोखिम संबंधी दिशानिर्देश जारी करने का निर्णय लिया गया:

- अ) ग्रीन डिपॉजिट की स्वीकृति के लिए व्यापक ढांचा;
 - आ) जलवायु से संबंधित वित्तीय जोखिमों पर प्रकटीकरण ढांचा, और;
 - इ) जलवायु परिदृश्य विश्लेषण और तनाव परीक्षण पर मार्गदर्शन।
- ग्रीन डिपॉजिट स्वीकार करने के दिशानिर्देश 11 अप्रैल, 2023 को जारी किए गए हैं जबकि अन्य दो दिशानिर्देश जल्द ही जारी किए जाने वाले हैं।

ब्याज दरों का विनियमन

- अ) बैंकों को संसाधन जुटाने में अधिक लचीलापन प्रदान करते हुए जमाराशियों पर ब्याज दरों को उत्तरोत्तर अविनियमित किया गया है। तथापि, ग्राहक सेवा को ध्यान में रखते हुए, जमाराशि दरें सभी शाखाओं में और सभी ग्राहकों के लिए एक समान होनी अपेक्षित हैं और बैंकों द्वारा अपने किसी भी कार्यालय में एक ही तारीख को स्वीकार की गई एक जमा राशि और समान राशि और अवधि की दूसरी जमा राशि और अवधि के बीच जमा राशि पर भुगतान किए गए ब्याज के मामले में किसी प्रकार के भेदभाव की अनुमति नहीं है। बैंक वरिष्ठ नागरिकों की जमाराशियों के संबंध में अधिक ब्याज की अनुमति दे सकते हैं, और सेवानिवृत्त कर्मचारियों (शर्तों के अधीन) और कर्मचारियों के संघों (सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संघों को छोड़कर) सहित बैंक के अपने कर्मचारियों और अधिकारियों की जमाराशियों के संबंध में अतिरिक्त ब्याज की अनुमति दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित ब्याज दरें यथोचित, सुसंगत, पारदर्शी तथा जब कभी अपेक्षित हो, पर्यवेक्षी समीक्षा/संवीक्षा के लिए उपलब्ध होनी अपेक्षित होती हैं।

आ) अग्रिमों पर ब्याज दरों के संबंध में, जबकि बैंकों को नियत अथवा अस्थिर ब्याज दरों पर सभी श्रेणियों के अग्रिमों का प्रस्ताव करने की छूट प्रदान की गई है, विनियमों के अनुसार यह अपेक्षित है कि ऐसी दरें उचित एवं पारदर्शी हों और इनका निर्धारण आंतरिक अथवा बाह्य बेंचमार्क दर के आधार पर किया जाए। बैंकों को एमएसएमई को दिए गए सभी नए फ्लोटिंग रेट व्यक्तिगत या खुदरा ऋण और फ्लोटिंग रेट ऋणों को बाहरी बेंचमार्क जैसे रेपो रेट, भारत सरकार के 3-महीने और 6-महीने के ट्रेजरी बिल यील्ड को फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा प्रकाशित या एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित किसी अन्य बेंचमार्क बाजार ब्याज दर से जोड़ना अनिवार्य किया गया है। बैंक ऐसे बाहरी बेंचमार्क लिंक्ड लोन को अन्य प्रकार के उधारकर्ताओं को भी दे सकते हैं। बाहरी बेंचमार्क, सार्वजनिक रूप से ज्ञात होने के कारण, ब्याज दरों के निर्धारण में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं। मौद्रिक नीति के प्रसारण में विलंब को रोकने के लिए, बैंकों को सलाह दी गई है कि वे तीन माह में कम से कम एक बार बाह्य बेंचमार्क प्रणाली के अंतर्गत ब्याज दरों का पुनर्निर्धारण करें। पारदर्शिता, मानकीकरण और उधारकर्ताओं द्वारा ऋण उत्पादों की समझ में आसानी सुनिश्चित करने के लिए, बैंकों को ऋण श्रेणी के भीतर एक समान बाहरी बेंचमार्क अपनाने की सलाह दी गई है; दूसरे शब्दों में, एक ही बैंक द्वारा एक ऋण श्रेणी के भीतर कई बेंचमार्क अपनाने की अनुमति नहीं है।

अपने ग्राहक मानदंडों को जानें

बैंकों की सुरक्षा और सुदृढ़ता तथा देश में बैंकिंग प्रणाली की अखंडता के लिए ठोस 'अपने ग्राहक को जानिए' (केवाईसी) नीतियां और प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण हैं। बैंकिंग प्रणाली के जरिये धन-शोधन रोकने के लिये रिज़र्व बैंक ने अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी), धन-शोधन रोधी (एएमएल) और आतंकवाद वित्तपोषण से निपटने (सीएफटी) संबंधी दिशानिर्देश जारी किये हैं। ये अनुदेश धन शोधन निवारण (पीएमएल) अधिनियम, 2002 और धन शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियमावली, 2005 के उपबंधों पर आधारित हैं और वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की सिफारिशों के अनुरूप हैं। केवाईसी पर रिज़र्व बैंक का विनियामक रुख बैंकों को धन-शोधन गतिविधियों के लिए आपराधिक तत्वों द्वारा उपयोग किए जाने से बचाने और ग्राहकों, उत्पादों और सेवाओं, वितरण चैनलों द्वारा उत्पन्न जोखिम को समझने में सक्षम बनाने और विवेकपूर्ण तरीके से उनके जोखिमों का आकलन और प्रबंधन करने में मदद करने के उद्देश्य से है। बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपने सभी ग्राहकों के लिए केवाईसी प्रक्रिया अपनाएं ताकि वे अपनी पहचान स्थापित कर सकें और संदिग्ध लेन-देनों की सूचना वित्तीय आसूचना इकाई को दे सकें।

कॉर्पोरेट अभिशासन

कॉर्पोरेट अभिशासन सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करने की कुंजी है और अच्छे कॉर्पोरेट अभिशासन की आवश्यकता वर्षों से अधिक जोर दे रही है। भारत में बैंकिंग विनियमन 1990 के दशक में निर्देशात्मक पद्धति से विवेकपूर्ण पद्धति में स्थानांतरित हो गया, जिसने विनियमन से दूर और कॉर्पोरेट प्रशासन की ओर संतुलन में बदलाव को निहित किया। बैंकों को अपने तुलनात्मक लाभ के अनुरूप अपनी स्वयं की कारोबार योजनाएं और कार्यान्वयन रणनीतियां तैयार करने के लिए अधिक स्वतंत्रता और लचीलापन प्रदान किया जाता है। इस स्वतंत्रता के लिए सख्त शासन मानकों की आवश्यकता थी जिसमें बैंक बोर्डों को प्राथमिक जिम्मेदारी संभालने और निदेशकों को अधिक जानकारी होने और विभिन्न रणनीतियों और

नीति विकल्पों पर सूचित निर्णय लेने की आवश्यकता थी। कॉरपोरेट अभिशासन को सुदृढ़ करने की दृष्टि से, समय के साथ-साथ बोर्ड द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका, सामान्य रूप से बैंकों के निदेशकों के लिए और विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के निर्वाचित निदेशकों के लिए उपयुक्त और उचित मानदंड, बोर्ड द्वारा की जाने वाली समीक्षाओं की सूची, बैंकिंग और प्रौद्योगिकी में नवाचारों की पृष्ठभूमि में निदेशकों के लिए विशेषज्ञता के क्षेत्रों का विस्तार करना, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के पद के विभाजन आदि से संबंधित मामलों में विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इसके अलावा, पिछले कुछ वर्षों में विकसित अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ मुआवजा नीति को बेहतर ढंग से संरेखित करने के उद्देश्य से, और बैंकों द्वारा अपने पूर्णकालिक निदेशकों के लिए मांगे गए पारिश्रमिक के वस्तुनिष्ठ आकलन के लिए, मुआवजे से संबंधित दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है।

वाणिज्यिक बैंकों में अभिशासन के ढांचे की समीक्षा के लिए जून 2020 में 'भारत में वाणिज्यिक बैंकों में अभिशासन' पर एक चर्चा पत्र जारी किया गया था। प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर कुछ ऑपरेटिव पहलुओं को संबोधित करने के लिए, अप्रैल 2021 में बोर्ड के अध्यक्ष और बैठकों, बोर्ड की कुछ समितियों की संरचना, निदेशकों की आयु, कार्यकाल और पारिश्रमिक, और पूर्णकालिक निदेशकों (WTDs) की नियुक्ति के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे। निर्देशों में एक स्वतंत्र अंशकालिक अध्यक्ष को अनिवार्य किया गया था, जिसमें महत्वपूर्ण बोर्ड समितियों की संरचना निर्दिष्ट की गई थी जैसे बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी), बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) और नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी), साथ ही गैर-कार्यकारी निदेशकों (एनईडी) की अवधि, आयु सीमा और पारिश्रमिक और एमडी और सीईओ के कार्यकाल को भी निर्दिष्ट किया गया था। इसके अलावा, बैंक बोर्डों और इसकी विभिन्न समितियों के कुशल कामकाज में एनईडी की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए और बैंकों को अपने बोर्डों में योग्य सक्षम व्यक्तियों को पर्याप्त रूप से आकर्षित करने में सक्षम बनाने के लिए, फरवरी 2024 में एनईडी के निश्चित पारिश्रमिक के संबंध में सीमा बढ़ाकर 30 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दी गई थी।

बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि वे प्रभावी उत्तराधिकार योजना की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से एमडी और सीईओ पदों के लिए कार्यकाल और ऊपरी आयु सीमा के नियामक अनुबंध के मद्देनजर और बैंकिंग क्षेत्र की बढ़ती जटिलता को ध्यान में रखते हुए एमडी और सीईओ सहित बोर्ड में कम से कम दो डब्ल्यूटीडी की उपस्थिति सुनिश्चित करें।

प्रकटीकरण मानदंड

प्रासंगिक जानकारी का सार्वजनिक प्रकटीकरण बाजार अनुशासन को लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसलिए, पिछले कुछ वर्षों में, रिज़र्व बैंक ने बैंकों के लिए प्रकटीकरण मानदंडों को मजबूत किया है। बैंकों को अब अपनी वार्षिक रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ पूंजी पर्याप्तता, परिसंपत्ति गुणवत्ता, तरलता, आय और नियामक द्वारा उन पर लगाए गए जुर्माने आदि के बारे में खुलासा करना आवश्यक है।

जमा बीमा

जमा बीमा जमाकर्ताओं को उनकी जमा राशि के नुकसान से बचाता है यदि कोई जमा संस्थान बीमित जमाकर्ताओं के प्रति अपने दायित्व को पूरा करने में सक्षम नहीं है। भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की शाखाओं सहित सभी वाणिज्यिक बैंक,

स्थानीय क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जमा बीमा योजना के अंतर्गत आते हैं।

इस योजना के अंतर्गत बैंक की सभी शाखाओं में एक साथ समान क्षमता और समान अधिकार में धारित जमा राशियों के लिए बीमा कवर प्रति जमाकर्ता ₹ 5,00,000/- तक सीमित है। बीमाकृत बैंकों द्वारा डीआईसीजीसी को भुगतान किए गए प्रीमियम का वहन बैंकों द्वारा स्वयं किया जाना अपेक्षित है और इसे जमाकर्ताओं पर नहीं डाला जाना अपेक्षित है।

बैंकों का संकल्प

जिन बैंकिंग कंपनियों के वित्तीय मानदंड अनिश्चित होते हैं, उन पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाती है। आरबीआई की कार्रवाइयों का उद्देश्य कमजोर बैंकों को जल्दी से स्वास्थ्य में वापस लाना है, और यदि ऐसे प्रयासों से वांछित परिणाम नहीं मिलते हैं, तो उन्हें यथासंभव गैर-विघटनकारी तरीके से हल किया जा सकता है। दबावग्रस्त बैंकों को एक विश्वसनीय पूंजी और पुनरुद्धार योजना तैयार करने के लिए पर्याप्त समय और छूट प्रदान किया जाता है। तथापि, यदि जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैंकिंग कंपनी के लिए पूंजी निवेश अथवा पुनरुद्धार के लिए कोई विलय प्रस्ताव नहीं है, तो भारतीय रिज़र्व बैंक किसी बैंकिंग कंपनी के अनिवार्य सम्मेलन अथवा पुनर्गठन की प्रक्रिया आरंभ कर सकता है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 के अंतर्गत अनिवार्य सम्मेलन/पुनर्गठन के लिए केन्द्र सरकार पर लागू होता है। वर्ष 2020 में बीआर अधिनियम, 1949 की धारा 45 (4) में संशोधन के बाद, सम्मेलन का निर्णय स्थगन की अवधि के दौरान या किसी अन्य समय में किया जा सकता है। पुनर्निर्माण/अनिवार्य सम्मेलन संबंधी प्रारूप स्कीम को पुनर्निर्माण/अनिवार्य सम्मेलन के लिए पणधारियों की टिप्पणियों/आपत्तियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर डाला गया है। इन टिप्पणियों/सुझावों को, जहां कहीं उपयुक्त पाया जाता है, प्रारूप योजना में शामिल किया जाता है। इसके बाद प्रारूप योजना को अनुमोदन के लिए भारत सरकार को भेजा जाता है और भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है।

तथापि, ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें भारतीय रिज़र्व बैंक, जनहित में संतुष्ट हो या यदि बैंकिंग कंपनी भारत में बैंकिंग कारोबार करना बंद कर देती है या यदि बैंकिंग कंपनी बीआर अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (1) या (3) या (3क) के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान करने के लिए उस पर अधिरोपित किसी भी शर्त का अनुपालन करने में विफल रहती है, बीआर अधिनियम की धारा 22 (4) के प्रावधानों के तहत एक बैंकिंग कंपनी का लाइसेंस रद्द कर सकता है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 22(4) के अंतर्गत बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्णय से असंतुष्ट बैंकिंग कंपनी उस तारीख से तीस दिनों के भीतर, जिस तारीख को इस प्रकार का निर्णय उसे सूचित किया जाता है, केन्द्र सरकार को अपील कर सकती है।

पैरा बैंकिंग गतिविधियां

बैंकिंग क्षेत्र के विनियमन और वित्तीय क्षेत्र के विकास ने कई बैंकों को गैर-पारंपरिक बैंकिंग गतिविधियों को शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिन्हें पैरा-बैंकिंग भी कहा जाता है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 6 (1) उन व्यवसायों को सूचीबद्ध करती है जो एक बैंकिंग कंपनी अधिनियम की धारा 5 (बी) के तहत परिभाषित बैंकिंग व्यवसाय के अतिरिक्त कर सकती है। इसके अलावा, पैरा-बैंकिंग गतिविधियों के लिए विस्तृत विवेकपूर्ण मानदंडों को बैंकों द्वारा 26 मई 2016 को प्रदान की गई वित्तीय सेवाओं पर मास्टर निदेश में समेकित किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को म्यूचुअल फंड

कारोबार, बीमा व्यवसाय, मर्चेट बैंकिंग कार्यकलाप, फैक्टरिंग सेवाएं, कार्ड व्यवसाय, पेंशन निधि प्रबंधन, निवेश परामर्शी सेवाएं, एजेंसी व्यवसाय, सेबी अनुमोदित स्टॉक एक्सचेंजों की सदस्यता आदि जैसे विविध कार्यकलाप करने की अनुमति दी है। जबकि कुछ कार्यकलापों को विभागीय रूप से किए जाने की अनुमति है, कतिपय कार्यकलाप निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुरूप इक्विटी भागीदारी के माध्यम से केवल सहायक/संयुक्त उद्यम मार्ग के माध्यम से ही किए जाने हैं। बैंकों को पूर्वोक्त मास्टर निदेश में यथा निर्धारित बैंकों के निवेशों के लिए विवेकपूर्ण विनियम के अनुसार वित्तीय/गैर-वित्तीय कंपनियों की इक्विटी/इकाई पूंजी, वैकल्पिक निवेश निधियों और स्थावर संपदा निवेश न्यास/अवसंरचना निवेश न्यास में निवेश करने की भी अनुमति है।

अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों का विनियमन

अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई) भारतीय वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि वे पुनर्वित्त और प्रत्यक्ष ऋण के माध्यम से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मध्यम से दीर्घकालिक वित्त प्रदान करते हैं। इन संस्थानों की स्थापना निर्यात, ग्रामीण और कृषि क्षेत्र, आवास एवं लघु उद्योगों, अवसंरचना जैसे विशेष वर्गों की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए की गई है और ये इन क्षेत्रों को ऋण देने तथा उनके समक्ष आने वाली चुनौतियों/मुद्दों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

पांच एआईएफआई अर्थात् भारतीय निर्यात-आयात (एक्जिम) बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (एनएबीएफआईडी), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) रिज़र्व बैंक के विनियमन और पर्यवेक्षण के अधीन हैं। इन अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं का गठन उनकी अपनी संविधियों के अंतर्गत किया गया है जो भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के उपबंधों के साथ उनके विनियमन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं। वाणिज्यिक बैंकों की तरह, आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण, एक्सपोजर, निवेश, पूंजी पर्याप्तता और प्रकटीकरण से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड एआईएफआई पर भी लागू होते हैं। एआईएफआई ऑन-साइट निरीक्षण और ऑफ-साइट निगरानी के अधीन भी हैं।

क्रेडिट सूचना कंपनियां

क्रेडिट रिपोर्टिंग क्रेडिट बाजारों की एक मूलभूत समस्या, उधारकर्ताओं और उधारदाताओं के बीच असममित जानकारी, जिससे प्रतिकूल चयन, क्रेडिट राशनिंग और नैतिक खतरे की समस्याएं हो सकती हैं, को दूर करती है। क्रेडिट रिपोर्टिंग सिस्टम में संस्थान, व्यक्ति, विधियों, प्रक्रियाओं, मानकों और प्रौद्योगिकी शामिल हैं जो क्रेडिट और ऋण समझौतों से संबंधित निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक सूचना प्रवाह को सक्षम करते हैं।

भारत में ऋण रिपोर्टिंग प्रणाली में वर्तमान में चार क्रेडिट सूचना कंपनियां (सीआईसी), ट्रांसयूनियन सिबिल लिमिटेड, एक्सपेरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इक्विफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और सीआरआईएफ हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और क्रेडिट संस्थान - बैंक, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, राज्य वित्तीय निगम, क्रेडिट कार्ड कंपनियां आदि शामिल हैं जो भारतीय ऋण सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005, ऋण सूचना कंपनी नियमावली, 2006 और ऋण सूचना कंपनी विनियम, 2006 के उपबंधों द्वारा अभिशासित होते हैं।

उधारकर्ताओं की क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) सीआईसी से सीआईसी विनियमों के तहत सूचीबद्ध विशिष्ट उपयोगकर्ताओं द्वारा प्राप्त की जा सकती है जिनमें क्रेडिट संस्थान, दूरसंचार कंपनियां, अन्य नियामक, बीमा कंपनियां, स्टॉक ब्रोकर, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां, समाधान पेशेवर आदि शामिल हैं।

ऋण संस्थानों को सलाह दी गई है कि वे ऋण मूल्यांकन के लिए कम से कम एक सीआईसी से सीआईआर को एक इनपुट के रूप में शामिल करें। हालांकि, पहली बार उधारकर्ताओं के ऋण आवेदनों को केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उनका कोई क्रेडिट इतिहास नहीं है। सीआईसी क्रेडिट स्कोर जैसे मूल्य वर्धित उत्पाद भी प्रदान करते हैं। व्यक्तिगत उधारकर्ता भी सीआईसी से क्रेडिट रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। आरबीआई ने सीआईसी को निः शुल्क पूर्ण क्रेडिट रिपोर्ट (FFCR) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है जिसमें कैलेंडर वर्ष में एक बार व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को क्रेडिट स्कोर शामिल है।

नियामक उपायों के लिए सहभागी और परामर्शी दृष्टिकोण

रिज़र्व बैंक सामान्यतः नए/प्रमुख विनियामक उपायों, वर्तमान दिशानिर्देशों में वृद्धिशील विनियामक परिवर्तनों और मौजूदा दिशानिर्देशों/विनियमों की व्यापक समीक्षा पर पणधारकों/जनता से टिप्पणियां/प्रतिक्रिया मांगता है। नए/प्रमुख विनियामक उपायों के मामले में, रिज़र्व बैंक द्वारा अंतिम विनियामक दिशानिर्देश जारी करने से पहले संगत कार्यदल की रिपोर्टें, चर्चा पत्रों और प्रारूप परिपत्रों/दिशानिर्देशों को अपनी वेबसाइट पर डालकर सार्वजनिक परामर्श अनिवार्य रूप से किया जाता है। नीतिगत प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए स्टेकहोल्डरों की तैयारी और स्वीकार्यता का आकलन करने के लिए उनके साथ आंतरिक परामर्श भी किए जाते हैं।

वर्तमान विनियम की व्यापक समीक्षा करते समय सामान्यतः सभी स्टेकहोल्डरों के साथ व्यापक परामर्श किया जाता है। कतिपय मामलों में, प्रस्तावित उपायों/विनियमों के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श और परामर्श के लिए सलाहकार समितियां गठित की जाती हैं। विभिन्न प्रश्नों के उत्तर और विनियामक उपायों पर स्टेकहोल्डरों के साथ चल रहे सहभागिता के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) जारी करने का एक तंत्र भी मौजूद है, इसके अलावा वर्तमान विनियामक दिशानिर्देशों पर जनता/स्टेकहोल्डरों से निरंतर फीडबैक सुनिश्चित किया जाता है।

हाल के दिशानिर्देश

वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) में निवेश

कथित सदाबहारीकरण के कुछ उदाहरण सामने आए थे जिनके द्वारा एआईएफ योजनाओं में आरई द्वारा निवेश को संबंधित आरई के तनावग्रस्त उधारकर्ताओं द्वारा उनके ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए विनियोजित किया गया था। सदाबहारीकरण सहित ऐसे किसी भी विवेकपूर्ण उल्लंघन को रोकने के लिए, निम्नलिखित उपाय शुरू किए गए थे: (क) आरई को एआईएफ योजनाओं में से किसी में निवेश करने से प्रतिबंधित किया गया था, जिसमें संबंधित आरई की किसी भी देनदार कंपनी में डाउनस्ट्रीम निवेश है; (ख) आरई को 30 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर एआईएफ में अपने मौजूदा निवेशों को समाप्त करने के लिए अनिवार्य किया गया था, यदि एआईएफ योजना ने आरई की देनदार कंपनी में निवेश किया था या बाद में निवेश किया था, जिसमें विफल होने पर आरई उस विशेष योजना में अपने निवेश के लिए पूर्ण प्रावधान करेंगे; और (ग) आरई को अनिवार्य किया गया था कि जूनियर किश्त में किसी भी निवेश को उनके नियामक पूंजी निधि से पूर्ण रूप से घटा

दिया जाएगा। कार्यान्वयन में निरंतरता सुनिश्चित करने और कुछ प्रमुख मुद्दों पर और अधिक विनियामक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए, आगे स्पष्टीकरण जारी किए गए थे जिसमें सलाह दी गई थी कि: (i) डाउनस्ट्रीम निवेश इक्विटी शेयरों को छोड़कर लेकिन अन्य लिखतों को शामिल करते हैं; (ii) प्रावधानीकरण केवल एआईएफ योजना में आरई के निवेश की सीमा (आनुपातिक आधार) पर लागू होता है, न कि संपूर्ण निवेश पर; (iii) पूंजी से प्रस्तावित कटौतियां टियर-1 और टियर-2 पूंजी दोनों को प्रभावित करती हैं, जिसमें प्रायोजक इकाइयों सहित सभी प्रकार के अधीनस्थ एक्सपोजर शामिल हैं और (iv) फंड ऑफ फंड्स या म्यूचुअल फंड जैसे मध्यवर्तियों के माध्यम से एआईएफ में निवेश इन दिशानिर्देशों के दायरे से बाहर हैं।

उचित उधार प्रथा - ऋण खातों में दंड शुल्क

दंडात्मक ब्याज/प्रभार लगाने के संबंध में संशोधित प्राक्कलनों के बीच भिन्न-भिन्न प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए, संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए थे जिनमें आरई को दंडात्मक प्रभारों पर बोर्ड अनुमोदित नीति तैयार करने और उधारकर्ताओं को दंडात्मक प्रभार लगाने की मात्रा और कारण पारदर्शी रूप से प्रकट करने का अधिदेश दिया गया है। इसके अलावा, यदि उधारकर्ता द्वारा ऋण संविदा के महत्वपूर्ण निबंधनों एवं शर्तों का अनुपालन न करने के लिए आरई द्वारा जुर्माना लगाया जाता है तो वह दंड प्रभारों के रूप में होगा और दंडात्मक ब्याज के रूप में नहीं लगाया जाएगा। आरई को दंडात्मक प्रभारों को पूंजीकृत करने से भी प्रतिबंधित किया गया है, अर्थात् ऐसे प्रभारों पर आगे कोई ब्याज संगणित नहीं किया जाएगा।

समान मासिक किस्त (ईएमआई) आधारित व्यक्तिगत ऋणों पर फ्लोटिंग ब्याज दर का पुनर्निर्धारण

ईएमआई आधारित फ्लोटिंग दर वाले व्यक्तिगत ऋणों के संबंध में, बढ़ती ब्याज दरों के मद्देनजर, उधारकर्ताओं के साथ उचित संचार और/या सहमति के बिना ऋण अवधि बढ़ाने और/या ईएमआई राशि में वृद्धि से संबंधित कई उपभोक्ता शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इस मुद्दे के समाधान के लिए आरई को विनियम जारी किए गए हैं, जिनमें आरई से यह अपेक्षा की गई है कि वे मंजूरी के समय ही यह आकलन करें कि क्या बढ़ती ब्याज दरों के प्रभाव को वहन करने के लिए पर्याप्त गुंजाइश है। इसके अतिरिक्त, जब कभी किसी उत्पाद श्रेणी में अस्थिर ब्याज दर का पुनर्निर्धारण किया जाता है, आरई को सलाह दी गई है कि वे उधारकर्ताओं को अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार नियत दर पर स्विच करने का विकल्प प्रदान करें। उधारकर्ताओं को निम्नलिखित विकल्प चुनने का विकल्प भी दिया जाएगा (i) ईएमआई में वृद्धि या अवधि में वृद्धि या दोनों विकल्पों के संयोजन के लिए; और, (ii) ऋण की अवधि के दौरान किसी भी समय आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से प्री-पे करना। आरई यह सुनिश्चित करेंगे कि फ्लोटिंग दर वाले ऋण के मामले में अवधि के विस्तार के परिणामस्वरूप नकारात्मक परिशोधन न हो। विनियमों में इन विकल्पों के प्रयोग से संबंधित विभिन्न प्रभारों का पारदर्शी प्रकटन और उधारकर्ताओं को महत्वपूर्ण सूचना का उचित संचार भी निर्धारित किया गया है।

जिम्मेदार उधार आचरण - व्यक्तिगत ऋणों के पुनर्भुगतान/निपटान पर चल / अचल संपत्ति दस्तावेजों को वापस करना

ऋण खाता बंद होने के बाद चल/अचल संपत्ति दस्तावेजों को वापस करने में आरई द्वारा अपनाई गई अलग-अलग पद्धतियों को दूर करने के लिए, जिसके परिणामस्वरूप ग्राहक शिकायतें और विवाद होते हैं, विनियम जारी किए गए थे जिनमें आरई को यह अधिदेशित किया गया था कि वे ऋण खाते के पूर्ण पुनर्भुगतान/निपटान के बाद 30 दिनों के भीतर किसी भी रजिस्ट्री

के साथ पंजीकृत प्रभारों को हटाने सहित सभी मूल चल/अचल संपत्ति दस्तावेजों को वापस करें। इन विनियमों में, *अन्य बातों के साथ-साथ*, आरई द्वारा दस्तावेजों को लौटाने में विलंब के लिए क्षतिपूर्ति निर्धारित की गई है और खोने/क्षति के मामले में दस्तावेजों की डुप्लीकेट/प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने की जिम्मेदारी आरई पर डाली गई है।

सीआईसी (क्रेडिट सूचना कंपनियों) और क्रेडिट संस्थानों (सीआई) द्वारा प्रदान की गई ग्राहक सेवा का सुदृढीकरण

सीआईसी और सीआई द्वारा प्रदान की गई ग्राहक सेवा को सुदृढ करने के लिए, उनके द्वारा क्रेडिट सूचना के अद्यतन/सुधार के लिए समय-सीमा (30 दिन) का पालन न करने के लिए एक क्षतिपूर्ति ढांचा निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, सीआईसी को सलाह दी गई है कि वे ग्राहकों को उनकी क्रेडिट सूचना रिपोर्ट तक पहुंच के संबंध में लघु संदेश सेवा (एसएमएस) या ई-मेल के माध्यम से सूचित करें। ऋण सूचना रिपोर्टिंग प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए, सीआई को सलाह दी गई है कि वे मौजूदा ऋण सुविधाओं में चूक अथवा पिछले दिनों के संबंध में सीआईसी को सूचना प्रस्तुत करते समय अपने उधारकर्ताओं को एसएमएस अथवा ई-मेल के माध्यम से सूचित करें। इसके अलावा, सीआई के पास सीआईसी द्वारा उठाए गए ग्राहकों की शिकायतों को संबोधित करने के लिए एक समर्पित नोडल बिंदु होगा, छमाही आधार पर ग्राहक शिकायतों का मूल कारण विश्लेषण (आरसीए) करेगा और ग्राहकों को उनके डेटा सुधार अनुरोध की अस्वीकृति के कारणों को सूचित करेगा। सीआईसी को सलाह दी गई है कि वे सीआई से प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर क्रेडिट सूचना डेटा को अपने डेटाबेस में शामिल करें (1 जनवरी, 2025 से प्रभावी पांच दिनों में संशोधित), अपनी वेबसाइट पर प्राप्त शिकायतों के डेटा का खुलासा करें, अपने 'सर्व एंड मैच' लॉजिक एल्गोरिदम की आवधिक समीक्षा करें और अपनी वेबसाइट पर मुफ्त पूर्ण क्रेडिट रिपोर्ट तक पहुंचने के लिए लिंक को प्रमुखता से प्रदर्शित करें।

डिजिटल उधार पर दिशानिर्देश

डिजिटल उधार पर कार्य समूह द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, रिज़र्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और आवास वित्त कंपनियों (सामूहिक रूप से आरई के रूप में संदर्भित) सहित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लागू डिजिटल ऋण पर दिशानिर्देश जारी किए। इन दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों के लिए पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने का प्रयास किया गया है (क) उधारदाताओं और उधारकर्ताओं के बीच निधियों के प्रवाह को केवल उनके बैंक खातों के माध्यम से अनिवार्य करना, जिसमें किसी तीसरे पक्ष का पास-थ्रू खाता/पूल खाता नहीं है; (ख) यह सुनिश्चित करना कि ऋण सेवा प्रदाता ग्राहक से सीधे कोई शुल्क/प्रभार वसूल न करें; (ग) उधारकर्ता के लिए सर्व-समावेशी लागत सहित उधार व्यवस्था के मुख्य तथ्यों का पारदर्शी प्रकटीकरण; (घ) स्पष्ट ग्राहक सहमति द्वारा समर्थित लेखापरीक्षा परीक्षणों के साथ आंकड़ों का आवश्यकता आधारित संग्रहण सुनिश्चित करना; और, (e) ग्राहक डेटा के संबंध में एक उपयुक्त गोपनीयता नीति बनाना। इसके अलावा, यह दोहराया गया है कि ऋण सेवा प्रदाता (एलएसपी)/डिजिटल लेंडिंग ऐप (डीएलए) के साथ आरई द्वारा दर्ज की गई आउटसोर्सिंग व्यवस्था आरई के दायित्वों को कम नहीं करती है और वे आउटसोर्सिंग पर मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुरूप बने रहेंगे। आरई यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा लगाए गए एलएसपी और डीएलए (या तो आरई या उनके द्वारा लगाए गए एलएसपी) दिशानिर्देशों का पालन करते हैं।

डिजिटल उधार में डिफॉल्ट लॉस गारंटी (DLG) पर दिशानिर्देश

आरई की कुछ व्यावसायिक प्रथाएं नए जोखिम पैदा कर सकती हैं, क्योंकि डिजिटल लेंडिंग ऐप (डीएलए)/फिनटेक कंपनियों के साथ कुछ आरई द्वारा किए गए डीएलजी समझौतों के तहत, आरई को प्रदान की गई फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी (एफएलडीजी) के कारण आरई द्वारा 100 प्रतिशत तक क्रेडिट जोखिम वहन किया गया था। ऐसी व्यवस्थाओं के तहत, डीएलए ने आरई के लाइसेंस का उपयोग करके उधारकर्ताओं को प्रभावी ढंग से अपने स्वयं के धन उधार दिए, जिन्होंने कोई जोखिम साझा नहीं किया लेकिन बदले में गारंटीकृत प्रतिफल प्राप्त कर रहे थे। ऐसे मामलों के प्रसार से अनियमित उधार से जुड़े जोखिम बढ़ सकते हैं और साथ ही विशिष्ट क्षेत्रों/पोर्टफोलियो में दबाव की पहचान करने की प्रक्रिया में विलंब हो सकता है।

विवेक और नवाचार के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर विचार करते हुए, रिज़र्व बैंक ने उपयुक्त नियामक सुरक्षा के साथ डीएलजी व्यवस्था की अनुमति देते हुए अनुदेश जारी किए। डीएलजी व्यवस्था में एलएसपी शामिल होते हैं जो पोर्टफोलियो के पूर्व-निर्धारित प्रतिशत तक ऋण पोर्टफोलियो पर डिफॉल्ट नुकसान वहन करने की पेशकश करते हैं जहां आरई का ऐसे एलएसपी के साथ आउटसोर्सिंग समझौता होता है। आरई यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे किसी भी पोर्टफोलियो पर डीएलजी कवर की कुल राशि उस ऋण पोर्टफोलियो की राशि के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगी और इसे केवल नकद, सावधि जमा या बैंक गारंटी के रूप में पेश किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, आरई किसी भी डीएलजी व्यवस्था में प्रवेश करने से पहले बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति लागू करेंगे। कोई भी डीएलजी व्यवस्था क्रेडिट मूल्यांकन आवश्यकताओं के विकल्प के रूप में कार्य नहीं करेगी। इसके अलावा, पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए, आरई को एलएसपी की वेबसाइट पर डीएलजी का प्रकटीकरण सुनिश्चित करना आवश्यक है।

समझौता निपटानों और तकनीकी राइट-ऑफ के लिए रूपरेखा

वर्तमान विनियमों के अनुसार, ऋणदात्री संस्थाओं के ऋण संबंधी वसूली मामले अधिकांशतः अविनियमित हैं। ऐसे वसूली उपाय या तो उधारकर्ताओं के खातों में दबाव के समाधान के माध्यम से विभिन्न सांविधिक अथवा न्यायालय से बाहर तंत्रों के माध्यम से हो सकते हैं अथवा ये समझौता निपटानों के माध्यम से हो सकते हैं। जबकि समझौता निपटान/राइट-ऑफ करने के संबंध में वाणिज्यिक बैंकों और एनबीएफसी को कतिपय विनियम जारी किए गए थे, इस मामले में कोई स्व-निहित विनियामक ढांचा नहीं था। सहकारी बैंकों के मामले में, समझौता निपटानों पर कोई समर्थकारी विनियामक ढांचा नहीं था, जबकि संबंधित राज्य संविधियों के अनुसार सहकारी बैंकों को देय किसी ऋण/देयता को माफ करने के लिए सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) की अनुमति अपेक्षित है। इसलिए, समझौता निपटान और सभी विनियमित संस्थाओं को कवर करने वाले ऋणों के तकनीकी राइट-ऑफ को नियंत्रित करने वाला एक व्यापक नियामक ढांचा 08 जून, 2023 को जारी किया गया था। इस ढांचे में अन्य बातों के साथ-साथ त्याग/माफी पर विचार करने से पूर्व ध्यान में रखे जाने वाले कारक, अनुमत त्याग/माफी के लिए मानदंड, शक्तियों का प्रत्यायोजन, विवेकपूर्ण व्यवहार, रिपोर्टिंग तंत्र, बोर्ड द्वारा निरीक्षण, कूलिंग अवधि, धोखाधड़ी और इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत खातों के साथ व्यवहार शामिल होगा।

एनबीएफसी को उपभोक्ता ऋण और बैंक ऋण के लिए विनियामक उपाय

कोविड के बाद, उपभोक्ता ऋण खंड, विशेष रूप से असुरक्षित पोर्टफोलियो की ओर क्रेडिट-ऑफटेक काफी महत्वपूर्ण रहा है। इसके अलावा बैंक उधारी पर एनबीएफसी की बढ़ती निर्भरता नियामकीय चिंताओं को बढ़ा रही है। हालांकि व्यापक

पोर्टफोलियो स्तर पर परिसंपत्ति गुणवत्ता तनाव के किसी भी प्रमुख संकेत को प्रदर्शित नहीं कर रही थी, फिर भी उपरोक्त खंडों में रिपोर्ट की गई लगातार उच्च क्रेडिट वृद्धि से विवेकपूर्ण हस्तक्षेप की आवश्यकता महसूस हुई। तदनुसार, 16 नवंबर, 2023 को एक परिपत्र जारी किया गया, जिसमें विभिन्न मात्रात्मक और गुणात्मक उपाय किए गए।

ग्रीन डिपॉजिट स्वीकार करने की रूपरेखा

ग्रीन डिपॉजिट ब्याज वाली जमा हैं, जो विनियमित इकाई (आरई) द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए प्राप्त की जाती हैं, जिसकी आय ग्रीन फाइनेंस के आवंटन के लिए निर्दिष्ट की जाती है। आरई को ग्राहकों को ग्रीन डिपॉजिट की पेशकश करने, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने, ग्रीनवाशिंग जोखिमों को दूर करने और हरित गतिविधियों/परियोजनाओं के लिए ऋण के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, अप्रैल 2023 में ग्रीन डिपॉजिट की स्वीकृति के लिए फ्रेमवर्क जारी किया गया था। इस ढांचे में आरई को ग्रीन डिपॉजिट के प्रभावी आवंटन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क स्थापित करने के लिए अधिदेशित किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, पात्र हरित कार्यकलाप/परियोजनाएं, जिन्हें ग्रीन डिपॉजिट के माध्यम से जुटाई गई आय से वित्तपोषित किया जा सकता है, परियोजना मूल्यांकन और आरई द्वारा चयन की प्रक्रिया, ग्रीन डिपॉजिट की आय का आवंटन और इसकी रिपोर्टिंग, आय के आवंटन और प्रभाव मूल्यांकन का तृतीय-पक्ष सत्यापन/आश्वासन, और अस्थायी आवंटन का विवरण शामिल हैं। आरई भारत सरकार के 'सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के लिए फ्रेमवर्क' से अपनाए गए नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ परिवहन, टिकाऊ जल और अपशिष्ट प्रबंधन, ग्रीन बिल्डिंग आदि जैसे क्षेत्रों में ग्रीन डिपॉजिट से जुटाई गई धनराशि का आवंटन करेंगे। इसके अतिरिक्त, आरई वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन माह के भीतर अपने निदेशक मंडल के समक्ष समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान ग्रीन डिपॉजिट के अंतर्गत जुटाई गई राशि, उन हरित कार्यकलापों/परियोजनाओं की सूची, जिन्हें आय आबंटित की गई है, पात्र हरित कार्यकलापों/परियोजनाओं को आबंटित राशि और तृतीय पक्ष सत्यापन/आश्वासन रिपोर्ट तथा प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट की एक प्रति शामिल होगी।

बड़े इरादतन चूककर्ताओं और चूककर्ताओं का ट्रीटमेंट

रिजर्व बैंक ने इरादतन चूककर्ताओं से निपटने के लिए एक योजना शुरू की थी, जो 1 अप्रैल, 1999 से प्रभावी थी। इरादतन चूककर्ताओं के संबंध में अनुदेशों को वर्तमान अनुदेशों की समीक्षा करने और माननीय उच्चतम न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालयों के विभिन्न निर्णयों/आदेशों के साथ-साथ बैंकों एवं अन्य पणधारियों से प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद संशोधित किया गया है। नवीनतम दिशा-निर्देशों के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त इरादतन चूककर्ताओं के ढांचे की प्रयोज्यता का विस्तार टियर 3 और 4 गैर-अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों, मध्यम और उससे ऊपर के स्तरों में एनबीएफसी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र के बैंकों तक किया गया है। इरादतन चूक की परिभाषा को व्यापक बनाया गया है ताकि इसमें उन उधारकर्ताओं को शामिल किया जा सके जो पूंजी लगाने के लिए प्रतिबद्ध थे लेकिन ऐसा करने में विफल रहे। इरादतन चूक का शीघ्र पता लगाने के लिए, सभी एनपीए खातों की समीक्षा इरादतन चूक की पहचान के लिए उनके एनपीए के रूप में वर्गीकरण के छह (6) महीने के भीतर निर्धारित की गई है।

इरादतन चूककर्ताओं और उनकी संबद्ध कंपनियों पर लागू दंडात्मक उपायों में संस्थागत वित्त पर रोक, अतिरिक्त ऋण

सुविधाओं के लिए इरादतन चूककर्ताओं की सूची से हटाए जाने के बाद एक वर्ष की कूलिंग अवधि, नए उद्यम शुरू करने के लिए ऋण सुविधाओं पर पांच वर्ष (इरादतन चूककर्ता सूची से नाम हटाने के बाद) प्रतिबंध और ऋण सुविधा की पुनर्संरचना के लिए अपात्र होना शामिल है।

एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, एक दो-स्तरीय संरचना निर्धारित की गई है जिसमें एक पहचान समिति और एक समीक्षा समिति शामिल है। पहचान और समीक्षा समिति की संरचना को विभिन्न प्रकार के उधारदाताओं के लिए विस्तृत किया गया है, जिसमें उनकी अनूठी संगठनात्मक संरचनाओं को ध्यान में रखा गया है। इरादतन चूककर्ताओं के वर्गीकरण की प्रक्रिया को परिष्कृत किया गया है, जिसमें उन सभी सामग्रियों और सूचनाओं का प्रकटीकरण शुरू किया गया है जिन पर कारण बताओ नोटिस आधारित है, समीक्षा समिति को पहचान समिति के आदेश के विरुद्ध लिखित अभ्यावेदन का प्रावधान और समीक्षा समिति द्वारा उधारकर्ता के लिए व्यक्तिगत सुनवाई का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा, अद्यतन निर्देश दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) प्रक्रिया के तहत समाधान के बाद या ऋण असाइनमेंट पर इरादतन चूक खातों के उपचार पर स्पष्टता प्रदान करते हैं। इरादतन चूककर्ताओं के विरुद्ध विशिष्ट उपायों का प्रावधान किया गया है जिनमें *अन्य बातों के साथ-साथ* आपराधिक कार्यवाहियां शुरू करना, फोटोग्राफ प्रकाशित करना और दंडात्मक उपाय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, ऋणदाताओं को मासिक आधार पर क्रेडिट सूचना कंपनियों को इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं (₹ 1 करोड़ और उससे अधिक की बकाया राशि वाले चूककर्ताओं और संदिग्ध या हानि या मुकदमा दायर के रूप में वर्गीकृत चूककर्ताओं) का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

क्रेडिट संस्थानों द्वारा सीआईसी को क्रेडिट जानकारी की रिपोर्टिंग की आवृत्ति

ऋण संस्थाओं (सीआई) से यह अपेक्षा की गई थी कि वे अपने उधारकर्ताओं की ऋण सूचना मासिक आधार पर अथवा सीआई और सीआईसी के बीच परस्पर सहमत कम अंतरालों पर ऋण सूचना कंपनियों (सीआईसी) को सूचित करें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सीआईसी द्वारा प्रदान की गई क्रेडिट सूचना रिपोर्ट अधिक हाल की जानकारी को दर्शाती है, सीआई द्वारा सीआईसी को क्रेडिट जानकारी की रिपोर्टिंग की आवृत्ति मासिक से पाक्षिक अंतराल तक या सीआई और सीआईसी के बीच पारस्परिक रूप से सहमत ऐसे छोटे अंतराल पर 1 जनवरी, 2025 से बढ़ा दी गई है। सीआई को यह भी सलाह दी गई थी कि वे संगत रिपोर्टिंग पखवाड़े के सात कैलेण्डर दिवसों के भीतर सीआईसी को पाक्षिक रूप से ऋण सूचना प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

कार्ड संचालन के आचरण पहलुओं को बढ़ावा देना – क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पर मास्टर निदेश – जारी करना और आचरण निर्देश, 2022

मास्टर निदेश 21 अप्रैल, 2022 को जारी किया गया था और बाद में 07 मार्च, 2024 को अपडेट किया गया था। ये निर्देश कार्ड बाजार में नवीनतम घटनाओं से जुड़े हुए हैं और कार्डधारकों के हित में सुरक्षा उपायों को पेश किया गया है। ग्राहक की सहमति को मास्टर निदेश का केन्द्र बिन्दु माना गया है। निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं जो मौजूदा निर्देशों में किए गए हैं:

- (अ) ग्राहक अधिग्रहण - आवेदन के दौरान मुख्य तथ्य पत्रक प्रदान करना, टेलीमार्केटिंग के लिए ग्राहकों को कॉल करने के लिए समय खिड़की (10:00 बजे से 19:00 बजे), हस्ताक्षरित समझौते की प्रति प्रदान करना, क्रेडिट कार्ड आवेदन के लिए डिजिटल सहमति को सक्षम करना।
- (आ) हामीदारी मानक - ईएमआई रूपांतरण में पारदर्शिता, धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने के लिए स्वीकृत क्रेडिट सीमा से परे कोई उपयोग नहीं।
- (इ) ब्याज दरें - क्रेडिट कार्ड पर प्रभारित ब्याज उस लागत और वापसी की सीमा को ध्यान में रखते हुए न्यायोचित होगा जिसकी कार्ड जारीकर्ता द्वारा यथोचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति में निर्धारित ब्याज दरें और इसके लिए तर्क लेखा परीक्षा योग्य होंगे।
- (ई) क्रेडिट कार्ड बंद करना – किसी भी देरी के लिए सात कार्य दिवसों की समयावधि और ₹ 500 प्रति कैलेंडर दिन का जुर्माना, सूचना के साथ अप्रयुक्त क्रेडिट कार्ड खाते (एक वर्ष से अधिक) को बंद करने की शुरुआत।
- (उ) बिलिंग - कार्डधारक द्वारा बिलिंग चक्र को बदलने का विकल्प, क्रेडिट लेनदेन (क्रेडिट सीमा का 1% या ₹5000, जो भी कम हो) को क्रेडिट सीमा में समायोजित करने के लिए स्पष्ट सहमति, देय भुगतान के लिए क्रेडिट लेनदेन का स्वचालित समायोजन, क्रेडिट कार्ड बकाया के लिए भुगतान स्वीकार करने के लिए कार्ड-जारीकर्ताओं द्वारा अधिकृत मोड प्रदर्शित करना।
- (ऊ) ग्राहक आचरण – कार्डधारक को प्रदान किए जाने वाले वसूली एजेंटों का विवरण, ओटीपी आधारित सहमति के माध्यम से क्रेडिट कार्ड को सक्रिय करना यदि कार्ड जारी करने की तारीख से 30 दिनों से अधिक समय तक निष्क्रिय रहता है, शिकायतों के आधार पर कर्मचारी या बिक्री एजेंट के खिलाफ कार्रवाई, क्रेडिट कार्ड सक्रिय होने पर ही सीआईसी को क्रेडिट जानकारी की रिपोर्टिंग, आदि।

ऋण और अग्रिम पर मुख्य तथ्य विवरण

विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा लगाए गए ब्याज या प्रभारों/शुल्कों की अपारदर्शिता से संबंधित चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस) पर एक परिपत्र जारी किया है जो सभी आरई द्वारा स्वीकृत खुदरा और एमएसएमई मीयादी ऋण उत्पादों पर लागू है। उधारकर्ताओं को एक विवरण प्रदान किया जाना आवश्यक है जिसमें ऋण समझौते के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी सरल और समझने में आसान प्रारूप में हो, जिसमें ऋण की सभी लागत शामिल हो, । केएफएस में वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) की एक गणना पत्रक, और ऋण अवधि में ऋण का परिशोधन अनुसूची भी शामिल होगी। एपीआर में वे सभी शुल्क शामिल होंगे जो आरई द्वारा लगाए जाएंगे और वास्तविक आधार पर तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाताओं की ओर से आरई द्वारा उधारकर्ताओं से वसूले जाने वाले शुल्क शामिल होंगे। आरई के पास 30 सितंबर, 2024 तक पर्याप्त सिस्टम और प्रक्रियाएं हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 1 अक्टूबर, 2024 को या उसके बाद स्वीकृत सभी नए खुदरा और एमएसएमई मीयादी ऋण, जिसमें मौजूदा ग्राहकों को नए ऋण शामिल हैं, दिशानिर्देशों के अनुपालन में हैं।

कुछ संविधियों में संशोधन

बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 और बहु-राज्य सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2023 के माध्यम से

बीआर अधिनियम, 1949 और एमएससीएस अधिनियम, 2002 में संशोधनों किए गए। बीआर अधिनियम में संशोधन का उद्देश्य सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए प्रबंधन, पूंजी, लेखा परीक्षा और परिसमापन के संदर्भ में सहकारी बैंकों पर आरबीआई की नियामक निगरानी को बढ़ाना था। एमएससीएस अधिनियम, 2022 में 2023 का संशोधन संविधान के भाग IXबी के तहत प्रदान किए गए प्रावधानों के साथ इसके प्रावधानों को संरेखित करने और सहकारी समितियों के कामकाज और शासन के साथ कुछ चिंताओं को दूर करने के लिये अधिनियम में संशोधन करना चाहता है।

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) बैंकों की पूंजी और ब्याज दरों में प्रतिकूल गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली आय के लिए वर्तमान या संभावित जोखिम को संदर्भित करता है जो उनकी बैंकिंग बही स्थितियों को प्रभावित करता है। जब ब्याज दरें बदलती हैं, तो भविष्य के नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य और समय बदल जाता है। बदले में ये परिवर्तन बैंकों की दर-संवेदनशील परिसंपत्तियों, देनदारियों और ऑफ-बैलेंस शीट वस्तुओं के अंतर्निहित मूल्य को प्रभावित करते हैं और इसलिए, उनके आर्थिक मूल्य (ईवी) प्रभावित होते हैं। ब्याज दरों में बदलाव ब्याज दर के प्रति संवेदनशील आय और व्यय में बदलाव करके बैंकों की आय को भी प्रभावित करता है, जिससे उनकी शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) प्रभावित होती है। अत्यधिक आईआरआरबीबी बैंकों के वर्तमान पूंजी आधार और/या भविष्य की आय के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम पैदा कर सकता है यदि उचित रूप से प्रबंधित नहीं किया जाता है। तदनुसार, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) द्वारा जारी संशोधित ढांचे के अनुरूप, बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम के अभिशासन, माप और प्रबंधन पर अंतिम दिशानिर्देश 17 फरवरी, 2023 को जारी किए गए थे। यद्यपि, कार्यान्वयन की अंतिम तारीख अभी सूचित की जानी है, बैंकों को सलाह दी गई है कि वे नए ढांचे के अंतर्गत ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करने के लिए तैयार रहें।

अध्याय 8: वाणिज्यिक बैंकों का पर्यवेक्षण

वाणिज्यिक बैंकिंग पर्यवेक्षण - अवधारणाएं और विकास

पर्यवेक्षण, सरल शब्दों में, नियमों और विनियमों का प्रवर्तन है जो नियामक द्वारा विनियमित संस्थाओं के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए तैयार किए जाते हैं और साथ ही खामियों या ग्रे क्षेत्रों को स्पॉट करते हैं जहां नियामक सुदृढीकरण देय हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के विभिन्न उपबंधों के अंतर्गत भारत में स्थित वाणिज्यिक बैंकों के साथ-साथ भारत से बाहर स्थित भारतीय बैंकों की शाखाओं का पर्यवेक्षण करता है। पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) सभी आरबीआई विनियमित संस्थाओं, जैसे, वाणिज्यिक बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों, शहरी सहकारी बैंकों, लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) और क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) के पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है।

उठने वाले मूलभूत प्रश्नों में से एक यह है कि पर्यवेक्षण, विनियमन से कैसे भिन्न है। आम बोलचाल में वे अक्सर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं क्योंकि वे एक ही उद्देश्य की सेवा करते हैं - जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और वित्तीय स्थिरता को संरक्षित करना। हालांकि, दोनों कार्यों के बीच अंतर है। 'विनियमन' सभी बाजार खिलाड़ियों द्वारा व्यापार करने के लिए नियमों और मानदंडों को निर्धारित करने का पर्याय है और इसलिए, सभी बाजार सहभागियों के लिए समान रूप से लागू है। दूसरी ओर, 'पर्यवेक्षण' वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्तिगत इकाई स्तर पर नियमों और मानदंडों को लागू किया जाता है। इस प्रकार, जबकि विनियमन समग्र रूप से प्रणाली पर लागू होता है, पर्यवेक्षण इकाई-विशिष्ट है, पर्यवेक्षण की तीव्रता कथित जोखिम स्तरों के समानुपाती होती है¹⁵।

बैंकों के पर्यवेक्षण का औचित्य इन संस्थाओं के विनियमन के समान है। एक लचीली बैंकिंग प्रणाली को बढ़ावा देकर वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने का व्यापक उद्देश्य प्रभावी पर्यवेक्षण की नींव है। विशेष रूप से, बैंक वित्तीय प्रणाली में एक पूर्व-प्रतिष्ठित स्थान रखते हैं और परिपक्वता और तरलता परिवर्तन शुरू करके और महत्वपूर्ण भुगतान प्रणालियों का समर्थन करके आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देते हैं। हालांकि, बैंकिंग के व्यवसाय में कई विशेषताएं हैं (लीवरेज, परिसंपत्ति-देयता बेमेल, आदि), जो अस्थिरता उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। इसके अतिरिक्त, बैंकों को नकदी सहायता और जमाकर्ता गारंटी के रूप में सरकार/विनियामक से भी समर्थन प्राप्त है। यह बदले में संभावित रूप से नैतिक खतरे के मुद्दों को जन्म दे सकता है, जैसे कि अत्यधिक जोखिम लेना और बैलेंस शीट की परिणामी हानि। प्रणालीगत दृष्टिकोण से, बैंकों की विफलता वास्तविक अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा सकती है क्योंकि एक बिगड़ा हुआ बैंकिंग प्रणाली बचतकर्ताओं और उधारकर्ताओं के बीच वित्तीय मध्यस्थता का आवश्यक कार्य नहीं कर सकती है। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए बैंकों का प्रभावी पर्यवेक्षण आवश्यक है कि बैंक नियमों और विनियमों का अक्षरशः और भावना से पालन करें और साथ ही साथ उनकी जोखिम संस्कृति और जोखिम शासन इसकी शोधन क्षमता के लिए खतरा पैदा न करें।

1990 के दशक की शुरुआत तक, पर्यवेक्षण कार्य मौजूदा नियामक ढांचे के लिए एक सहायक के रूप में कार्य कर रहा था

¹⁵ जोखिम आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से बैंकिंग पर्यवेक्षण को सुदृढ बनाना: स्टेपिंग द स्टेप्स, डॉ. के. सी. चक्रवर्ती, डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, मई, 2013

जो मुख्य रूप से लाइसेंसिंग, जमा के साथ-साथ ऋण, भंडार और तरल संपत्ति आवश्यकताओं पर ब्याज दरों के प्रशासन सहित सेवाओं के मूल्य निर्धारण पर केंद्रित था। 1988 में बेसल समझौते का विकास और 1991 के भुगतान संकट के संतुलन के बाद आर्थिक उदारीकरण, जिसके परिणामस्वरूप बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हुए, पर्यवेक्षी दृष्टिकोण में बदलाव आया। पर्यवेक्षण हस्तक्षेपकारी सूक्ष्म-स्तरीय हस्तक्षेप से अधिक व्यापक-आधारित दृष्टिकोण में स्थानांतरित हो गया, जो विनियमन की विवेकपूर्ण प्रकृति, ब्याज दरों के विनियमन और बैंकों के निजी स्वामित्व को दर्शाता है। बेसल मानकों को अपनाने से पर्यवेक्षी और नियामक प्रथाओं को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ फिर से संगठित किया गया। हालांकि, यह भारतीय वित्तीय प्रणाली के विकास के चरण और समग्र आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से किया गया था। वर्षों से, पर्यवेक्षी दृष्टिकोण में सुधार के लिए प्रक्रियाओं और प्रथाओं की समीक्षा करने के लिए कई विशेषज्ञ समूहों का गठन किया गया था। महत्वपूर्ण बैंकों में बैंकों के ऑन-साइट पर्यवेक्षण की प्रणाली की समीक्षा करने के लिए कार्य समूह (अध्यक्ष: एस पद्मनाभन, 1995), समेकित पर्यवेक्षण की सुविधा के लिए समेकित लेखांकन और अन्य मात्रात्मक तरीकों पर कार्य समूह (अध्यक्ष: विपिन मलिक, 2001), व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय मध्यस्थों (वित्तीय समूह) की निगरानी पर कार्य समूह (संयोजक: श्रीमती श्यामला गोपीनाथ, 2004), वाणिज्यिक बैंकों के लिए पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय संचालन समिति (अध्यक्ष: केसी चक्रवर्ती, 2012), फिनटेक और डिजिटल बैंकिंग पर अंतर-नियामक कार्य समूह (अध्यक्ष: श्री सुदर्शन सेन, 2018) और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण देने सहित डिजिटल ऋण पर कार्य समूह (अध्यक्ष: श्री जयंत कुमार दाश, कार्यकारी निदेशक, 2021)।

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (बीसीबीएस) ने प्रभावी बैंकिंग पर्यवेक्षण के लिए कोर सिद्धांतों की पहचान की है जो मूल रूप से सितंबर 1997 में प्रकाशित हुई थी। इसका उपयोग भारत सहित कई देशों द्वारा अपनी पर्यवेक्षी प्रणालियों की गुणवत्ता का आकलन करने और भविष्य में किए जाने वाले कार्यों की पहचान करने के लिए एक बेंचमार्क के रूप में किया गया है। 1997 के बाद से, हालांकि, बैंकिंग विनियमन और पर्यवेक्षण में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, इन सिद्धांतों की समीक्षा की आवश्यकता है। इस तरह का नवीनतम संशोधन सितंबर 2012 में किया गया था और वर्तमान में 29 प्रमुख सिद्धांत हैं जो पर्यवेक्षी शक्तियां और जिम्मेदारियां, बैंकों की पर्यवेक्षी अपेक्षाएं, अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन और जोखिम प्रबंधन के महत्व पर जोर देते हैं, साथ ही पर्यवेक्षी मानकों के अनुपालन पर जोर देते हैं।

अच्छी निगरानी के गुण क्या हैं? आईएमएफ स्टाफ पोजिशन नोट जिसका शीर्षक है "द मेकिंग ऑफ गुड सुपरविजन: लर्निंग टू से 'नो'", कुछ अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह पांच प्रमुख विशेषताओं की पहचान करता है जो एक अच्छे पर्यवेक्षी ढांचे के लिए आवश्यक हैं। सबसे पहले, अच्छा पर्यवेक्षण घुसपैठ है, अर्थात्, पर्यवेक्षक को पर्यवेक्षित इकाई के व्यवसाय मॉडल, इसकी जोखिम संस्कृति और शासन संरचना की पूरी समझ होनी चाहिए। जब बैंक पर्यवेक्षण की बात आती है तो हैंड्स-ऑफ दृष्टिकोण उचित नहीं है। दूसरा, अच्छा पर्यवेक्षण संदेहपूर्ण लेकिन सक्रिय है। पर्यवेक्षकों को चीजें हल्के में नहीं लेनी चाहिए और अच्छे समय में भी बैंक के कार्यों पर सवाल उठाना चाहिए। तीसरा, अच्छा पर्यवेक्षण व्यापक है। पर्यवेक्षण केवल बैंक और उसकी मुख्य गतिविधियों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। इसमें सहायक कंपनियां, ऑफ-बैलेंस शीट वाहन या संरचनाएं आदि शामिल होनी चाहिए। अक्सर जोखिम कोर के बजाय परिधि से निकल सकता है और पर्यवेक्षक को सतर्क रहना चाहिए। चौथा, अच्छा पर्यवेक्षण अनुकूल है। वित्तीय उद्योग में नवाचार के उच्च स्तर को देखते हुए, पर्यवेक्षकों को उभरते जोखिमों की पहचान करने के लिए संपर्क में रहने के लिए अपने कौशल को लगातार उन्नत करना चाहिए। अंत में, अच्छा पर्यवेक्षण निर्णायक है। पर्यवेक्षकों को इसका पालन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पर्यवेक्षी

निष्कर्षों को तार्किक निष्कर्ष पर ले जाया जाए। आईएमएफ नोट के अनुसार, अच्छी निगरानी लाने के लिए, दो सहायक स्तंभ आवश्यक हैं: कार्य करने की क्षमता और कार्य करने की इच्छा। कार्य करने की क्षमता कानूनी प्राधिकरण, आवश्यक संसाधनों, स्पष्ट रणनीति, एक मजबूत आंतरिक सेटअप और अन्य नियामकों और पर्यवेक्षकों के साथ प्रभावी कार्य संबंधों पर निर्भर है। कार्य करने की इच्छा को एक स्पष्ट जनादेश, परिचालन स्वतंत्रता, जवाबदेही, कुशल कर्मचारी, उद्योग के साथ स्वस्थ संबंध और निदेशक मंडल के साथ एक प्रभावी साझेदारी के संदर्भ में आंका जाता है।

आरबीआई में कानूनी और संस्थागत संरचना

आरबीआई को बैंकिंग विनियमन अधिनियम (बीआर अधिनियम), 1949 और आरबीआई अधिनियम, 1934 के विभिन्न प्रावधानों के तहत भारतीय बैंकिंग प्रणाली की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विशेष रूप से, बीआर अधिनियम की धारा 35 के तहत बैंकों का निरीक्षण बैंक लाइसेंसिंग विनियमन और अधिनियम की धारा 22 में निर्धारित उद्देश्यों के अनुवर्ती के रूप में किया जाता है। सांविधिक निरीक्षणों का मूल उद्देश्य यह सत्यापित करना है कि क्या वे शर्तें, जिनके अधीन बैंक को बैंकिंग कारोबार करने के लिए लाइसेंस जारी किया गया है [उपधारा 3 के अनुसार, और विदेशी बैंकों के लिए भी धारा 22 का 3क] उनके द्वारा पूरी की जाती हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी ऋण संस्थाओं अर्थात् बैंकों, विकास वित्तीय संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के समर्पित और एकीकृत पर्यवेक्षण के उद्देश्य से नवम्बर, 1994 में भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड की एक उप-समिति वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) की स्थापना की थी। बीएफएस आरबीआई (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और शहरी सहकारी बैंक, वित्तीय संस्थान और गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों) के अधिकार क्षेत्र के तहत वित्तीय क्षेत्र के समेकित पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है। गवर्नर, आरबीआई बीएफएस के अध्यक्ष हैं, और बैंकिंग पर्यवेक्षण के प्रभारी डिप्टी गवर्नर को उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया जाता है। रिजर्व बैंक के अन्य डिप्टी गवर्नर पदेन सदस्य होते हैं और आरबीआई के केन्द्रीय बोर्ड के चार गैर-आधिकारिक निदेशकों को दो साल की अवधि के लिए सदस्यों के रूप में सहयोजित किया जाता है। डॉस बीएफएस के सचिवालय के रूप में कार्य करता है, जो आम तौर पर विभिन्न पर्यवेक्षी मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और बैंकों की रेटिंग को मंजूरी देने के लिए हर महीने एक बार मिलता है।

1993 से पहले, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग (डीबीओडी) वाणिज्यिक बैंकों के पर्यवेक्षण और विनियमन के लिए जिम्मेदार था। दिसंबर 1993 में, पर्यवेक्षण विभाग (डॉस) को डीबीओडी से अलग किया गया था, जिसका उद्देश्य आरबीआई के नियामक कार्यों से पर्यवेक्षी भूमिका को अलग करना था। जैसे-जैसे वित्तीय प्रणाली विकसित हुई और जटिलता बढ़ी, यह महसूस किया गया कि विभिन्न वित्तीय संस्थाओं का समर्पित और केंद्रित पर्यवेक्षण समय की आवश्यकता थी। तदनुसार, डीओएस को बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस), गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस) और सहकारी बैंक पर्यवेक्षण विभाग (डीसीबीएस) में विभाजित किया गया था। बाद के दो गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों और शहरी सहकारी बैंकों की देखरेख के लिए बनाए गए थे।

नवंबर 2019 में, विनियमित संस्थाओं के पर्यवेक्षण और विनियमन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण रखने की दृष्टि से ताकि बढ़ती जटिलताओं, आकार और अंतर-संबद्धता को संबोधित किया जा सके और संभावित प्रणालीगत जोखिम से अधिक प्रभावी ढंग से निपटा जा सके जो संभावित पर्यवेक्षी मध्यस्थता और सूचना विषमता के कारण उत्पन्न हो सकता है, पर्यवेक्षण कार्य को पर्यवेक्षण के एकीकृत विभाग (डीओएस) में एकीकृत करने का निर्णय लिया गया। इस पुनर्गठन का उद्देश्य आरबीआई

पर्यवेक्षित सभी संस्थाओं को उनके आकार और जटिलता से जोड़ने के लिए एक श्रेणीबद्ध पर्यवेक्षी दृष्टिकोण अपनाना है; भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी वाली संस्थाओं के बीच वित्तीय समूहों के अधिक प्रभावी समेकित पर्यवेक्षण की सुविधा प्रदान करना; और अनुभवी और कुशल मानव संसाधन बनाने में मदद करने के लिए जिसके परिणामस्वरूप इसका कुशल आवंटन भी होता है। इसके अलावा, पर्यवेक्षी विभागों में कर्मियों के कौशल को प्रशिक्षित करने, विकसित करने और सुधारने के लिए, एक 'कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स' की स्थापना की गई थी। 'पर्यवेक्षकों का कॉलेज' सभी विनियमित संस्थाओं के पर्यवेक्षण से संबंधित विषयों और कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला पर अधिकारियों को व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

पर्यवेक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले दृष्टिकोण /

यह सर्वविदित है कि बैंकों के पर्यवेक्षण के लिए कोई एकल इष्टतम संरचना या प्रक्रिया नहीं है। तदनुसार, किसी देश द्वारा अपनाया गया पर्यवेक्षी दृष्टिकोण उसकी वित्तीय प्रणाली के विकास के चरण और बैंकिंग प्रणाली के आकार और जटिलता का कार्य है। पर्यवेक्षी दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाले कुछ अन्य कारकों में बैंकों के व्यवसाय मॉडल और पर्यवेक्षण के संचालन के लिए तकनीकी और मानव संसाधनों की उपलब्धता शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। प्रभावी बैंकिंग पर्यवेक्षण के लिए बैंकिंग पर्यवेक्षण संबंधी बेसल समिति (बीसीबीएस) द्वारा जारी किए गए मूल सिद्धांत पर्यवेक्षण के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करते हैं। सिद्धांत 8 में कहा गया है कि " बैंकिंग पर्यवेक्षण की एक प्रभावी प्रणाली के लिए पर्यवेक्षकों को व्यक्तिगत बैंकों और बैंकिंग समूहों के जोखिम प्रोफाइल का दूरदंशी मूल्यांकन विकसित करने और बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जो उनके प्रणालीगत महत्व के अनुपात में होता है; बैंकों और समग्र बैंकिंग प्रणाली से उत्पन्न जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और समाधान करना; प्रारंभिक हस्तक्षेप के लिए एक रूपरेखा है; और अन्य संबंधित प्राधिकरणों के साथ साझेदारी में, बैंकों के गैर-व्यवहार्य होने पर व्यवस्थित तरीके से समाधान करने के लिए कार्रवाई करने की योजना है। वैश्विक वित्तीय संकट से पहले, अधिकांश न्यायालयों में, एक नियम-आधारित या अनुपालन-आधारित पर्यवेक्षी दृष्टिकोण लागू था। बैंकों की निगरानी कैमिल्स (पूँजी पर्याप्तता, परिसंपत्ति गुणवत्ता, प्रबंधन, आय, तरलता और बाजार जोखिम के प्रति संवेदनशीलता) मॉडल के तहत की जाती है। भारतीय संदर्भ में, कैमिल्स परिवर्णी शब्द एस सिस्टम एंड कंट्रोल के लिए था। यह दृष्टिकोण बैंकों की वित्तीय स्थिति की निगरानी और परीक्षा और नियमों और विनियमों के अनुपालन पर केंद्रित था। इस मॉडल के तहत, ऑनसाइट परीक्षा ऑफसाइट निगरानी द्वारा समर्थित वार्षिक आधार पर की जाती है। कैमिल्स दृष्टिकोण बैंकों की शोधन क्षमता और तरलता पर केंद्रित था और मुख्य रूप से जमाकर्ताओं को नुकसान के जोखिम को सीमित करने के उद्देश्य से था। इस दृष्टिकोण में 'सिंगल-साइज़ फिट' दृष्टिकोण होने का दोष था और जब वित्तीय क्षेत्र में नवाचार के साथ तालमेल रखने की बात आती है तो यह वक्र के पीछे पाया जाता है।

वैश्विक वित्तीय संकट से पता चला कि हालांकि कई देशों में समान वित्तीय प्रणालियां थीं और समान नियमों (बेसल मानकों) के तहत संचालित होती थीं, उनमें से कुछ कम प्रभावित थे। इस अपशॉट के लिए जिम्मेदार कारणों में से एक "बेहतर पर्यवेक्षण" है। कैमिल्स मॉडल में निहित कमजोरियों को देखते हुए, जिसने संकट से पहले अस्तित्व में ढीले पर्यवेक्षण में योगदान दिया हो सकता है, कई देशों में पर्यवेक्षण के लिए जोखिम-आधारित या जोखिम-केंद्रित दृष्टिकोण की ओर एक कदम ने गति प्राप्त की। जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण की ओर इस बदलाव के मुख्य रूप से दो कारण थे। सबसे पहले, एक बढ़ती मान्यता है कि उधार देने के उद्देश्य से जमा स्वीकार करने के पारंपरिक अर्थों में बैंकिंग अब प्रचलन में नहीं है और बैंक और बैंकिंग जटिल होते जा रहे हैं। दूसरा और समान रूप से महत्वपूर्ण यह अहसास है कि पर्यवेक्षी संसाधन दुर्लभ हैं

और पर्यवेक्षी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इष्टतम रूप से तैनात करने की आवश्यकता है।

इस प्रकार, एक मजबूत पर्यवेक्षी ढांचे की आवश्यकता थी, जो सक्रिय रूप से प्रारंभिक जोखिमों की पहचान करता है और उन्हें संबोधित करने के लिए उपाय करता है। इसे स्वीकार करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों के लिए पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं की समीक्षा करने के लिए अगस्त 2011 में पूर्व डिप्टी गवर्नर, श्री के सी चक्रवर्ती की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय संचालन समिति का गठन किया। समिति में विनियामक, उद्योग और शिक्षाविदों का प्रतिनिधित्व था। समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ मौजूदा अनुपालन आधारित दृष्टिकोण के स्थान पर पर्यवेक्षण के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाने की सिफारिश की है। समिति की सिफारिशों के आधार पर, पर्यवेक्षण के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण 2013 से चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया था। भारत में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अब जोखिम आधारित पर्यवेक्षी (आरबीएस) ढांचे के तहत हैं और पूर्ववर्ती कैमल्स ढांचा अब प्रचलन में नहीं है।

जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण (RBS)

आरबीएस को "एक सतत प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें बैंक के जोखिमों का आकलन किया जाता है और पर्यवेक्षक द्वारा डिजाइन और कार्यान्वित की गई उपयुक्त पर्यवेक्षी योजनाएं होती हैं"। इस प्रकार आरबीएस को एक संरचित प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है, जो उन भौतिक और महत्वपूर्ण जोखिमों की पहचान करता है जिनका बैंक संभावित रूप से सामना कर सकता है, और एक केंद्रित पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से, प्रतिकूल परिणामों के लिए अपनी वित्तीय भेद्यता के साथ-साथ संभावित जोखिमों का प्रबंधन करने की बैंक की क्षमता का आकलन करता है। पर्यवेक्षण के मूल उद्देश्य, जोखिम-आधारित या अन्यथा, दो गुना हैं:

- अलग-अलग बैंकों की सुरक्षा और सुदृढ़ता सुनिश्चित करना और इस तरह जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना; और
- वित्तीय प्रणाली की स्थिरता की रक्षा करना

पर्यवेक्षण के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण का उद्देश्य बैंकों द्वारा सामना किए जा रहे प्रमुख जोखिमों के व्यापक और संरचित मूल्यांकन की पर्यवेक्षी प्रक्रिया के माध्यम से उपर्युक्त सर्वसमावेशी उद्देश्यों को प्राप्त करना है। जोखिम-आधारित दृष्टिकोण पहले मुख्य रूप से अनुपालन-आधारित कैमल/सीएलसीएस पद्धति से काफी बदलाव को चिह्नित करता है¹⁶, लेकिन इसमें अनुपालन संस्कृति और परिचर जोखिमों का आकलन करने के उद्देश्य से बैंकों में अनुपालन के स्तर का आकलन करना शामिल है।

व्यापक स्तर पर, जोखिम-आधारित और अनुपालन-आधारित दृष्टिकोणों में बहुत कुछ समान है। वे दोनों ऑन-साइट परीक्षा और ऑफ-साइट डेटा विश्लेषण का संयोजन शामिल करते हैं। महत्वपूर्ण अंतर यह है कि जोखिम-आधारित दृष्टिकोण के तहत एक बैंक की उन गतिविधियों की पहचान करने और मात्रा निर्धारित करने के लिए एक अधिक संगठित संरचना होती है जो अधिक जोखिम उठाते हैं और जोखिम को कम करने के लिए जोखिम प्रबंधन प्रथाओं और नियंत्रणों का भी आकलन करते हैं। जोखिम-आधारित पर्यवेक्षी दृष्टिकोण का उद्देश्य एक पर्यवेक्षी प्रणाली है जो बैंकों की सुरक्षा और सुदृढ़ता का

¹⁶ CALCS (पूँजी पर्याप्तता, परिसंपत्ति गुणवत्ता, तरलता, अनुपालन, Sys और नियंत्रण) विदेशी बैंकों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पर्यवेक्षी रेटिंग मॉडल था

आकलन करती है। यह बैंक के जोखिमों का सटीक मूल्यांकन प्राप्त करने का प्रयास करता है ताकि बैंक के जोखिमों के स्तर के अनुरूप पूंजी की सीमा का पता लगाया जा सके। ऐसा करने में, जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण उभरते जोखिमों की प्रारंभिक पहचान और समय पर प्रतिक्रिया को लक्षित करता है। इससे पर्यवेक्षक पहचान किए गए जोखिमों से निपटने के लिए दुर्लभ पर्यवेक्षी संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने में सक्षम होगा। इसके अलावा, अनुपालन-आधारित कैमल्स मॉडल के विपरीत, जहां व्यक्तिगत जोखिमों की अलगाव में जांच की जाती है, जोखिम-आधारित ढांचे में, जोखिमों के बीच बातचीत की जांच की जाती है। इस प्रकार, पर्यवेक्षी संसाधनों के इष्टतम उपयोग के माध्यम से पर्यवेक्षण की आनुपातिकता और आर्थिक दक्षता में सुधार और विशेष विशेषज्ञता विकसित करना आरबीएस की आधारशिला है।

आरबीआई द्वारा अपनाए गए आरबीएस ढांचे को एसपीएआरसी (जोखिम और पूंजी के आकलन के लिए पर्यवेक्षी कार्यक्रम) कहा जाता है। जबकि कैमल्स के तहत पर्यवेक्षी दृष्टिकोण प्रदर्शन आधारित, प्रतिक्रियाशील है और एक बिंदु-इन-टाइम मूल्यांकन है, एसपीएआरसी प्रारंभिक जोखिमों की पहचान करने और शीघ्र प्रतिक्रिया को प्रेरित करने में जोखिम-आधारित, दूरदर्शी, सक्रिय और गतिशील है। एसपीएआरसी के तीन मुख्य उद्देश्य हैं: (i) बैंक के जोखिम प्रोफाइल के आधार पर विभेदित पर्यवेक्षण लागू करना। यानी, विभिन्न बैंकों को पर्यवेक्षण की अलग-अलग डिग्री के अधीन किया जाएगा; (ii) बैंक के लिए उच्चतर जोखिम समझे जाने वाले क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करना। यानी, एक बैंक के भीतर उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जिन्हें महत्वपूर्ण भौतिक जोखिमों के लिए पहचाना जाता है; और (iii) बैंकों को उनकी जोखिम प्रबंधन प्रणालियों, निरीक्षण और नियंत्रण में सुधार करने में मदद करना। एसपीएआरसी का ध्यान अप्रत्याशित नुकसान (जैसे, बकाया के विपरीत एक्सपोजर) पर है, जिसके लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता हो सकती है।

एक जोखिम-आधारित पर्यवेक्षी ढांचे के दो आयाम हैं: पहला, विफलता का जोखिम, जो अंतर्निहित जोखिमों के आकलन पर आधारित है, इकाई स्तर पर नियंत्रण, बैंक में शासन और निरीक्षण और उपलब्ध पूंजी; दूसरा, विफलता का प्रभाव, जो समग्र वित्तीय प्रणाली में इकाई या समूह के सापेक्ष महत्व को ध्यान में रखता है। विफलता का जोखिम समग्र पर्यवेक्षी रेटिंग निर्धारित करता है।

विफलता के जोखिम का आकलन करने के लिए, ऑनसाइट और ऑफसाइट दोनों की जोखिम खोज की जाती है। ऑफसाइट जोखिम खोज प्रक्रिया में डेटा, दस्तावेज आदि का संग्रह शामिल है, साथ ही बैंकों के प्रबंधन कर्मियों के साथ चर्चा भी शामिल है। ऑफसाइट जोखिम खोज प्रक्रिया एक बैंक से संबंधित प्रमुख जोखिम क्षेत्रों (जोखिम उपायों के ब्रह्मांड में शामिल हैं, क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम, तरलता जोखिम, आदि) के बारे में जानकारी प्रदान करती है। ऑफसाइट जोखिम खोज प्रक्रिया उन क्षेत्रों को निर्धारित करेगी, जिन्हें और अधिक स्पष्टता की आवश्यकता है और ऑनसाइट यात्रा, ऑन-साइट यात्रा की अवधि और इस तरह की यात्रा के संचालन के लिए आवश्यक पर्यवेक्षी संसाधनों की आवश्यकता है। ऑफसाइट निगरानी पर्यवेक्षी ढांचे का एक प्रमुख घटक है, आरबीएस में और भी अधिक। स्थलेतर निगरानी भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों की स्थिति की निरंतर निगरानी करने में समर्थ बनाती है, जो उपचारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, के लिए इनपुट के रूप में कार्य करते हैं। चूंकि दुर्लभ पर्यवेक्षी संसाधनों का इष्टतम उपयोग आरबीएस के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है, इसलिए ऑफसाइट निगरानी अधिक महत्व रखती है क्योंकि ऑनसाइट परीक्षा लक्षित फैशन में की जाती है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर पर्यवेक्षी ध्यान दिया जाता है।

ऑनसाइट जोखिम खोज प्रक्रिया में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने सहित पहचाने गए जोखिम क्षेत्रों में आगे की जांच शामिल है। इस चरण में, पर्यवेक्षकों की एक समर्पित टीम बैंकिंग संस्था के परिसर में पहचाने गए क्षेत्रों/पहलुओं का

ऑनसाइट निरीक्षण करती है। जोखिम की गंभीरता और व्यवसाय की मात्रा साइट पर परीक्षा की आवधिकता, लंबाई और घुसपैठ निर्धारित करती है। ऑन-साइट जांच के एक प्रमुख भाग में शामिल हैं: (i) प्रक्रियाओं, उत्पादों, नीतियों, प्रक्रियाओं आदि के संबंध में बैंक के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ चर्चा, (ii) नियामक रिपोर्टिंग के हिस्से के रूप में बैंक द्वारा प्रस्तुत जानकारी की सटीकता का सत्यापन, जिसमें कोई अतिरिक्त डेटा/जानकारी प्राप्त हुई है, (iii) बैंक के सामने आने वाले भौतिक जोखिमों से निपटने के लिए नियंत्रण की प्रभावशीलता की समीक्षा, (iv) समग्र बोर्ड और प्रबंधन निरीक्षण और बैंक में जोखिम प्रबंधन और आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य द्वारा निभाई गई भूमिका की समीक्षा, और (v) विनियामक दिशानिर्देशों और लेखांकन मानकों के अनुपालन की समीक्षा, जिसमें पूर्व-निर्धारित नमूना आकार के आधार पर लेनदेन का परीक्षण शामिल है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे दिशानिर्देशों के अनुपालन में हैं या नहीं। इस प्रकार, आरबीएस ढांचे में प्रमुख संकेतकों के दोनों तत्व शामिल हैं जो जोखिम की खोज और पूंजी और अनुपालन समीक्षा जैसे संकेतकों को पीछे छोड़ने के उद्देश्य से हैं।

भले ही विभिन्न पर्यवेक्षकों द्वारा लागू जोखिम-आधारित दृष्टिकोण मोटे तौर पर समान हैं, वे पर्यवेक्षी एजेंसियों के जनादेश सहित कई कारकों के आधार पर भिन्न होते हैं। एक महत्वपूर्ण आयाम जिसे कई पर्यवेक्षी एजेंसियों ने अपनी जोखिम-आधारित प्रणाली में शामिल किया है, प्रत्येक फर्म के प्रणालीगत महत्व का निर्धारण कर रहा है। व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण फर्म, अन्य सभी चीजें समान हैं, गैर-व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण फर्मों की तुलना में अधिक पर्यवेक्षी ध्यान (और संसाधन) आकर्षित करती हैं।

एक वरिष्ठ पर्यवेक्षी प्रबंधक (एसएसएम) का निर्माण एसपीएआरसी की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। एसएसएम का सृजन मुख्य रूप से आरबीआई के भीतर बैंकों के लिए पर्यवेक्षी संपर्क का एकल बिंदु रखने के उद्देश्य से है। इससे पर्यवेक्षण विभाग के भीतर और अधिक व्यापक रूप से भारतीय रिजर्व बैंक के भीतर बैंकों के लिए संपर्क के कई बिंदुओं को हटाकर पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं की दक्षता और प्रभावशीलता में सुधार होने की उम्मीद है, जो कभी-कभी एक प्रभावी और सतत पर्यवेक्षण को कमजोर कर सकता है। एक बैंक के लिए एसएसएम अधिकारियों की एक समर्पित टीम द्वारा समर्थित है। एसएसएम से ऑफ-साइट और ऑन-साइट परीक्षा और निरंतर निगरानी के माध्यम से बैंक और इसके संचालन की एक मजबूत समझ विकसित करने की उम्मीद है।

संक्षेप में, पर्यवेक्षण के लिए जोखिम-आधारित ढांचे के प्रमुख लाभ हैं: (i) दुर्लभ पर्यवेक्षी संसाधनों का इष्टतम उपयोग, जिसके परिणामस्वरूप संगठन के संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है (ii) विनियमित संस्थाओं द्वारा सामना किए जाने वाले जोखिमों का गतिशील और चल रहा मूल्यांकन; (iii) उभरते जोखिमों की शीघ्र पहचान और पहचान; (iv) अंतर्निहित जोखिमों और जोखिम प्रबंधन नियंत्रणों दोनों के अलग-अलग मूल्यांकन के आधार पर जोखिमों के मूल्यांकन के लिए एक ढांचा। यह बैंकिंग क्षेत्र के जोखिमों के सिस्टम-वाइड मूल्यांकन में भी सक्षम बनाता है क्योंकि सभी संस्थाओं का मूल्यांकन कम व्यक्तिपरकता के साथ एक ही मॉडल के तहत किया जाता है; और (v) बैंक के व्यवसाय, प्रणालियों, प्रक्रियाओं, मानव संसाधन, आदि की बेहतर समझ।

पर्यवेक्षी दृष्टिकोण की टाइपोलॉजी

पर्यवेक्षण के लिए विभेदित दृष्टिकोण और आनुपातिकता प्रतिमान को ध्यान में रखते हुए, कुछ बेंचमार्क के आधार पर नियमित बैंकों के लिए मुख्य मॉडल और छोटे या आला बैंकों के लिए अन्य मॉडल के अलावा भिन्न आरबीएस मॉडल

विकसित किए जाते हैं। ऑनसाइट और ऑफ-साइट पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं के बीच सही संतुलन प्राप्त करने के लिए, बैंकों की विभिन्न श्रेणियों के पर्यवेक्षण में निम्नलिखित वर्गीकरण अपनाया जाता है।

- (अ) **पूर्ण कार्यक्षेत्र पर्यवेक्षण (एफएस):** इसमें बैंक के सभी भौतिक जोखिमों को कवर करते हुए, ऑन-साइट और ऑफ-साइट दोनों में सबसे विस्तृत और दखल देने वाला पर्यवेक्षी दृष्टिकोण शामिल है
- (आ) **स्कोप पर्यवेक्षण (एसएस) का चयन करें:** ऑफ-साइट पर्यवेक्षण इस दृष्टिकोण में प्रमुख भूमिका निभाता है, ऑन-साइट परीक्षा ऑफ-साइट विश्लेषण से उभरने वाली चिंताओं का एक कार्य है। इसके अलावा, ऑन-साइट जांच उन परिचालनों के आसपास केंद्रित होगी जो बैंक के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि निजी बैंकों के संबंध में आईटी / साइबर जोखिम, लघु वित्त बैंकों के मामले में अनुपालन, आदि।
- (इ) **विषयगत मूल्यांकन (टीए):** इस दृष्टिकोण का उद्देश्य सामयिक विषयों का आकलन करना है, जैसे कि परिसंपत्ति की गुणवत्ता, साइबर जोखिम, आदि, मूल्यांकन के साथ बैंकों या सभी बैंकों के एक समूह को कवर करना।
- (ई) **लक्षित संवीक्षा (टीएस):** इस दृष्टिकोण के तहत, पर्यवेक्षी या बाजार खुफिया इनपुट के आधार पर बैंक के विशिष्ट पहलुओं की जांच करने के लिए जांच की जाती है।
- (उ) **केवाईसी/एएमएल जोखिम (एसएकेएआर) ढांचे का पर्यवेक्षी मूल्यांकन** - पर्यवेक्षित संस्थाओं में केवाईसी/एएमएल जोखिमों का केंद्रित पर्यवेक्षण - एसई में केवाईसी/एएमएल जोखिमों पर विशेष पर्यवेक्षी ध्यान देने और केवाईसी/एएमएल जोखिमों की अलग-अलग डिग्री का आकलन करने के लिए, एससीबी के केवाईसी/एएमएल पर्यवेक्षण के लिए एक जोखिम-आधारित दृष्टिकोण (आरबीए) को पर्यवेक्षी चक्र 2020-21 में डिजाइन और कार्यान्वित किया गया था। आरबीए में अन्य बातों के साथ-साथ केवाईसी/एएमएल विशिष्ट पर्यवेक्षी डेटा टेम्पलेट्स डिजाइन करना शामिल था, एक विश्लेषणात्मक मॉडल जिसमें विभिन्न जोखिम संकेतक/ड्राइवर शामिल हैं जो बैंकों की उपयुक्त जोखिम रूपरेखा में सहायता करेंगे और उभरते केवाईसी/एएमएल जोखिमों के बारे में उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे। केवाईसी/एएमएल पर्यवेक्षण के लिए आरबीए के दायरे को बढ़ाने की दृष्टि से, इसे चुनिंदा यूसीबी और चुनिंदा एनबीएफसी तक भी विस्तारित किया गया है, जो आगे चलकर अपने पर्यवेक्षी मूल्यांकन में विशेष इनपुट प्रदान करने की उम्मीद करते हैं।
- आरबीए ने उन बैंकों की पहचान करने में मदद की है जो अपने कारोबार मॉडल, ग्राहक आधार, लेनदेनों की मात्रा और मूल्य के कारण उच्च केवाईसी/एएमएल जोखिमों के संपर्क में हैं और ऐसे बैंकों को केवाईसी/एएमएल क्षेत्र में नियंत्रणों और प्रक्रियाओं में अंतरालों की पहचान के लिए स्थल पर संकेन्द्रित मूल्यांकन के अध्वधीन रखा गया है। केवाईसी/एएमएल पर्यवेक्षण के लिए आरबीए ने एसई को उनके केवाईसी/एएमएल जोखिमों पर अधिक केंद्रित तरीके से संवेदनशील बनाने और ऐसे जोखिमों को संबोधित करने के लिए उचित शमन/नियंत्रण उपायों को लागू करने में सहायता की है।
- बैंकों में केवाईसी/एएमएल जोखिमों के लिए नियंत्रण अंतराल मूल्यांकन की शुरुआत के साथ जोखिम मूल्यांकन को और सुदृढ़ किया गया है। इसके साथ, एसई पर केवाईसी/एएमएल जोखिमों का एक समग्र दृष्टिकोण सुविधाजनक होगा, क्योंकि डेटा-संचालित विश्लेषणात्मक मॉडल के माध्यम से अंतर्निहित जोखिम मूल्यांकन को इकाई स्तर पर नियंत्रण/जोखिम कम करने वाले ढांचे के केंद्रित पर्यवेक्षी मूल्यांकन द्वारा पूरक किया जाएगा।
- (ऊ) **माइक्रो डेटा विश्लेषण (एमडीए):** कोर बैंकिंग और अन्य कोर सिस्टम के डेटा डंप, जिसमें ग्राहक स्तर, खाता स्तर

और लेनदेन स्तर डेटा शामिल हैं, बैंकों से उनके कामकाज के विभिन्न डोमेन के संबंध में प्राप्त होते हैं। इन आंकड़ों का विश्लेषण पर्यवेक्षी चिंताओं के लिए किया जाता है, जिनमें आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन, बैंकिंग नैतिकता को बनाए रखने और अनुशासित सर्वोत्तम प्रथाओं के कार्यान्वयन आदि शामिल हैं। इन विश्लेषणों के परिणामों को आगे की जांच और जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट (आरएआर) में शामिल करने के लिए ऑन-साइट एसएसएम टीमों के साथ साझा किया जाता है, यदि फिट माना जाता है।

(ऊ) उन्नत पर्यवेक्षी विश्लेषिकी समूह (एसएजी): कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) सहित उन्नत सुपरटेक उपकरण और तकनीकों का उपयोग जोखिम मूल्यांकन और प्रक्रिया सुधार जैसे पर्यवेक्षी कार्यों में चिंताओं का विश्लेषण करने के लिये किया जाता है। विश्लेषण का फोकस भविष्योन्मुखी आकलन/इनपुट (नैदानिक /वर्णनात्मक मूल्यांकन की तुलना में) उत्पन्न करने, सभी प्रकार के जोखिमों के लिए जोखिम मूल्यांकन प्रक्रियाओं को मानकीकृत करने और मानव निर्णय के ओवरले के साथ मानव केंद्रित/निर्भर से मशीन केंद्रित होने के लिए संक्रमण और डेटा संग्रह और विश्लेषणात्मक कार्यों को प्रभावी ढंग से स्केल/एकीकृत करने पर रहता है। उन्नत विश्लेषिकी परिनियोजन के कुछ उदाहरण हैं डेटा फ्रेमवर्क को मान्य करना, आचरण जोखिम का आकलन करने के लिए बैंकिंग और वित्त श्रेयों के असाधारण मूल्य आंदोलन के आसपास सोशल मीडिया अंतर्दृष्टि प्राप्त करना, बोर्ड की निगरानी की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए पर्यवेक्षित संस्थाओं के बोर्ड/उप-समितियों से संबंधित एजेंडा/नोट्स/मिनटों का अध्ययन, बैठक के विचार-विमर्श/गतिविधियों में संतुलन और रुझानों को समझना और इस तरह प्रबंधन उद्देश्यों को समझना, आरएमपी पर विचार-विमर्श का वैधीकरण, धोखाधड़ी भेद्यता सूचकांक का निर्माण करके धोखाधड़ी भेद्यता आकलन। अन्य फोकस क्षेत्रों में जोखिम विषय शामिल हैं जिनमें बाजार जोखिम, बाजार निगरानी, कदाचार विश्लेषण के माध्यम से जोखिम का आचरण, सूक्ष्म और स्थूल विवेकपूर्ण जोखिम, एकाग्रता जोखिम, आउटसोसग जोखिम सहित प्रचालनात्मक जोखिम आदि शामिल हैं।

विभेदित पर्यवेक्षी दृष्टिकोण के लिए बैंकों का समूहन

आनुपातिकता प्रतिमान पर्यवेक्षण के लिए विभेदित दृष्टिकोण की मांग करता है। तदनुसार, बैंकों को उपयुक्त पर्यवेक्षी दृष्टिकोण का निर्णय लेने के लिए समूहों/उपसमूहों में वर्गीकृत किया गया है। बैंकों को वर्गीकृत करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सिद्धांत मानदंड उनकी रिपोर्ट की गई परिसंपत्तियों का बाजार हिस्सा है। पर्यवेक्षी घुसपैठ सामान्य परिस्थितियों में बैंक की श्रेणी से जुड़ी होती है, हालांकि किसी इकाई के मामले में उत्पन्न जोखिमों के आधार पर इसकी समीक्षा की जा सकती है।

पर्यवेक्षण के विभिन्न उपकरण

विनियमित संस्थाओं के सार्थक पर्यवेक्षण का संचालन करने के लिए, ऑफ-साइट निगरानी और ऑनसाइट परीक्षा दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। आरबीआई बैंकों के 'करीबी और निरंतर' पर्यवेक्षण का संचालन करने के लिए ऑफ-साइट और ऑन-साइट टूल के विवेकपूर्ण मिश्रण का उपयोग करता है।

ऑफ-साइट पर्यवेक्षण

ऑफ-साइट पर्यवेक्षण एक प्रमुख पर्यवेक्षी उपकरण है जिसका उपयोग अधिकारियों द्वारा गतिशील आधार पर बैंक की प्रोफाइल, संस्कृति, जोखिम सहिष्णुता, संचालन और पर्यावरण का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। यह विशिष्ट इनपुट प्रदान करता है जो साइट पर परीक्षा को आकार देता है। ऑफ-साइट पर्यवेक्षण का उद्देश्य बैंक का प्रारंभिक जोखिम मूल्यांकन करना और प्रमुख जोखिम क्षेत्रों की खोज करना है। इसमें उनकी कारोबार योजना/रणनीतियों, समूह संरचना, वित्तीय विवरणों, अनुपालन और आंतरिक लेखा परीक्षा/योजनाओं और रिपोर्टों, बाह्य लेखापरीक्षकों के टिप्पणियों आदि का मूल्यांकन शामिल है। इसके साथ-साथ वृहत आर्थिक कारकों और बाजार आसूचना इनपुट के मूल्यांकन से ऑनसाइट जांच के लिए अपेक्षित कार्यक्षेत्र, फोकस, संसाधन और समय निर्धारित करने में सहायता मिलती है।

इस संदर्भ में, ऑन-साइट निरीक्षण के पूरक उपकरण के रूप में एक ऑफ-साइट निगरानी और निगरानी (ऑस्मोस) प्रणाली स्थापित की गई थी, जिसे जून 2023 में केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) से बदल दिया गया है। सीआईएमएस मुख्य रूप से विभिन्न रिटर्न के संग्रह के लिए केंद्रीकृत पोर्टल है जो विभिन्न अवधियों, जैसे साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, छमाही और वार्षिक में एकत्र किए जाते हैं।

बड़े ऋणों पर सूचना का केंद्रीय भंडार (Central Repository of Information on Large Credits- CRILC) को 2014 में अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनरुद्धार के लिए फ्रेमवर्क के हिस्से के रूप में पेश किया गया है। इस प्रणाली के अंतर्गत बड़े उधारकर्ताओं के संबंध में ऋण सूचना¹⁷ जून, 2014 को समाप्त तिमाही से बैंकों से एकत्र की जाती है। ऑफसाइट पर्यवेक्षी रिटर्न (सीआरआईएलसी के साथ) के माध्यम से एकत्र की गई जानकारी में बैलेंस शीट, आय, व्यय और लाभप्रदता, पूंजी, संपत्ति की गुणवत्ता, स्वामित्व, ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर, तरलता और महत्वपूर्ण विवरण के साथ कई अन्य क्षेत्र शामिल हैं। सभी संबंधित प्रयोक्ता सीआईएमएस-भारतीय अर्थव्यवस्था पर डाटाबेस (डीबीआईई) स्थल के माध्यम से स्थलेतर आंकड़ों तक पहुंचते हैं¹⁸।

सीआरआईएलसी प्रणाली में रिपोर्ट की गई उधारकर्ता स्तर की ऋण जानकारी और बैंकों के बीच प्रासंगिक जानकारी साझा करने से सूचना विषमता समाप्त हो गई है और बहुत आवश्यक पारदर्शिता आई है। इससे बैंकों में ऋण मूल्यांकन तंत्र में वृद्धि होने की आशा है, जिससे उधारकर्ता के बारे में अब तक अपेक्षित सूचना नहीं मिली हो। इस प्रकार, सीआरआईएलसी को बैंकों, एसएसएम के साथ-साथ नीति निर्माण के लिए बहुत उपयोगी पाया गया है। डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स ग्रुप मुख्य रूप से निम्नलिखित के लिए प्रयास करता है (i) बैंकों से डेटा का समय पर संग्रह, (ii) डेटा गुणवत्ता की उचित डिग्री बनाए रखने के लिए और (iii) सीआईएमएस-डीबीआईई में उपयोगी और सार्थक आसानी से उपलब्ध मानक रिपोर्ट प्रदान करके डेटा की समझ बनाने की सुविधा के अलावा आवश्यकता-आधारित विश्लेषण और विशाल डेटा की आपूर्ति।

ऑनसाइट परीक्षा

ऑनसाइट परीक्षा ऑफ-साइट निगरानी के तहत एकत्र किए गए डेटा के सत्यापन जांच करने, पूंजी मूल्यांकन सहित पहचाने गए जोखिम क्षेत्रों का आकलन करने और पिछले आकलन से पहचाने गए मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने पर ध्यान केंद्रित

¹⁷ CALCS (पूंजी पर्याप्तता, परिसंपत्ति गुणवत्ता, तरलता, अनुपालन, Sys और नियंत्रण) विदेशी बैंकों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पर्यवेक्षी रेटिंग मॉडल था

¹⁸ डीबीआईई को www.rbi.org.in से एक्सेस किया जा सकता है

करके ऑफ-साइट निगरानी का पूरक है। ऑनसाइट परीक्षा में न केवल उच्च स्तर के तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है, बल्कि जोखिम को समझने और उसका आकलन करने के साथ-साथ ऐसी जानकारी भी प्राप्त करने के लिए पारस्परिक कौशल की आवश्यकता होती है जो बैंक की चिंता के रूप में जारी रखने की क्षमता के लिए सामग्री हो सकती है।

पैरा-पर्यवेक्षी गतिविधियाँ

केंद्रीय धोखाधड़ी रजिस्ट्री

जैसा कि फ्रेडरिक विलियम रॉबर्टसन ने स्पष्ट रूप से कहा, "दुनिया में तीन चीजें हैं जो दया के लायक नहीं हैं - पाखंड, धोखाधड़ी और अत्याचार। धोखाधड़ी - इसका कोई सार्वभौमिक अर्थ नहीं है - एक सामान्य शब्द है जिसका उपयोग मानव सरलता का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो सत्य के दमन या झूठ को बढ़ावा देने के माध्यम से अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से बेईमान गतिविधियों में संलग्न होता है। बैंकिंग में धोखाधड़ी एक गंभीर मामला है क्योंकि बैंक वित्तीय मध्यस्थों के रूप में अपनी भूमिका में बड़ी मात्रा में सार्वजनिक धन से निपटते हैं। जबकि धोखाधड़ी के कई कारण हो सकते हैं, नुकसान को रोकने और उनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रारंभिक चरण में उनका पता लगाना महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, 20 जनवरी 2016 से एक केंद्रीय धोखाधड़ी रजिस्ट्री (सीएफआर) शुरू की गई है। सीएफआर 'बैंकों द्वारा उपयोग के लिए एक खोज योग्य केंद्रीकृत डेटाबेस' प्रदान करता है, जो धोखाधड़ी के जोखिम की समय पर पहचान करने में उन्हें सचेत कर सकता है। बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ लागू करें कि सीएफआर में उपलब्ध सूचना का उपयोग ऋण जोखिम और धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन के लिए प्रभावी रूप से किया जाता है।

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने धोखाधड़ी की पहचान करने की प्रक्रिया के दौरान नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों के अनुपालन पहलू को ध्यान में रखते हुए विनियमित निकायों में धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन संबंधी दिशानिर्देशों को संशोधित किया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और खातों पर लाल निशान (आरएफए) से संबंधित दिशा-निर्देशों को भी सुदृढ़ बनाया गया है ताकि इन्हें सुदृढ़, प्रभावी और प्रौद्योगिकी प्रेरित बनाया जा सके।

साइबर सुरक्षा ढांचा

सूचना प्रौद्योगिकी बैंक के परिचालन पहलुओं का एक अभिन्न अंग बन गई है और हाल के दिनों में प्रौद्योगिकी का उपयोग तेजी से बढ़ा है। जबकि प्रौद्योगिकी के उपयोग के कई फायदे हैं, यह बैंकों को साइबर और आईटी जोखिमों के लिए भी उजागर करता है। बैंकों में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर बढ़ती चिंताओं के मद्देनजर, बीएफएस ने निर्देश दिया कि आरबीआई को बैंकों की आईटी प्रणालियों में पूरी तरह से पर्यवेक्षी अंतर्दृष्टि होनी चाहिए। तदनुसार, साइबर सुरक्षा और आईटी परीक्षा पर एक विशेषज्ञ पैनल का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष के रूप में बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के कार्यकारी निदेशक प्रभारी थे। भारतीय रिज़र्व बैंक के भीतर जून 2015 में एक समर्पित साइबर सुरक्षा और आईटी परीक्षा सेल (CSITE सेल) भी स्थापित किया गया था।

विशेषज्ञ पैनल के तत्वावधान में, साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं को कवर करते हुए एक व्यापक परिपत्र बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचा जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त, डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रणों,

आईटी सेवाओं की आउटसोर्सिंग और आईटी गवर्नेंस सहित आईटी और साइबर सुरक्षा के विभिन्न डोमेन पर परिपत्र जारी किए गए हैं ताकि आईटी और साइबर सुरक्षा जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन के लिए विनियमित संस्थाओं को पर्याप्त मार्गदर्शन सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, खतरे की आसूचना संबंधी जानकारीयों और विनियमित संस्थाओं द्वारा सूचित घटनाओं के आधार पर उन्हें खतरे के बारे में सुग्राही बनाने और उन्हें त्वरित निवारक/सुधारात्मक कार्रवाई करने में सक्षम बनाने के लिए परामर्शी, चेतावनियां जारी की जाती हैं।

ऑनसाइट पर्यवेक्षी तंत्र:

आईटी/साइबर जोखिमों पर वर्तमान अनुदेशों के अनुपालन का मूल्यांकन संशोधित अनुमान की प्रकृति और जोखिम के आधार पर आवधिक रूप से बैंकों की आईटी जांच के माध्यम से किया जाता है। आईटी परीक्षा के दौरान फोकस में कुछ पहलुओं में शामिल हैं:

- आईटी गवर्नेंस में सुधार
- तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाताओं की निगरानी
- मजबूत आईटी आश्वासन तंत्र
- आईटी निवेश की गति
- फिनटेक भागीदारों के साथ तकनीकी चपलता बनाए रखना
- किसी भी उभरते मुद्दों की पहचान करने के लिए नवीनतम तकनीकों और स्वचालित उपकरणों का उपयोग
- छोटी संस्थाओं के लिए बुनियादी साइबर स्वच्छता सुनिश्चित करना

ऑफसाइट पर्यवेक्षी तंत्र

पर्यवेक्षित संस्थाओं की साइबर सुरक्षा स्थिति की निगरानी आवधिक और तदर्थ आधार पर विभिन्न आंकड़ों/सूचनाओं के संग्रहण और विश्लेषण के माध्यम से की जाती है। साइबर सुरक्षा की स्थिति मात्रात्मक संकेतकों के एक सेट के माध्यम से प्राप्त की जाती है जिसे तिमाही आधार पर एकत्र किया जाता है। एकत्र किए जाने वाले अन्य आवधिक आंकड़ों में पब्लिक फेसिंग एप्लिकेशन और उनके डेटाबेस, डिजिटल बैंकिंग चैनलों के डाउनटाइम पर डेटा, साइबर घटना सारांश, डीआर परीक्षण आदि शामिल हैं। वर्तमान परामर्शी, परिपत्रों/मास्टर निदेशों के अनुपालन का मूल्यांकन ऑफसाइट मॉनीटरिंग के माध्यम से भी किया जाता है जिन्हें ऑनसाइट आईटी जांच में आगे वैधीकृत किया जाता है। ऑफसाइट पर्यवेक्षी इनपुट संभावित खतरों और कमजोरियों की पहचान करके साइबर सुरक्षा और आईटी जोखिम निगरानी में ऑनसाइट पर्यवेक्षण का पूरक और समर्थन करते हैं और विशिष्ट साइबर जोखिमों को संबोधित करने में ऑनसाइट निरीक्षण को अधिक लक्षित और प्रभावी बनाने में सक्षम बनाते हैं।

दक्ष

रिज़र्व बैंक की उन्नत पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली (DAKSH) 6 अक्टूबर, 2022 को आरबीआई के गवर्नर द्वारा शुरू की गई थी। यह एक वेब-आधारित एंड-टू-एंड वर्कफ़्लो एप्लिकेशन है जिसके माध्यम से आरबीआई आरई जैसे बैंकों, एनबीएफसी आदि में अनुपालन संस्कृति में और सुधार करने के उद्देश्य से अधिक केंद्रित तरीके से पर्यवेक्षी अनुपालन की निगरानी करता

है। एप्लिकेशन एक वेब प्लेटफॉर्म के माध्यम से निर्बाध संचार, निरीक्षण योजना और निष्पादन, साइबर घटना रिपोर्टिंग और विश्लेषण, विभिन्न एमआईएस रिपोर्ट आदि के प्रावधान को सक्षम करेगा जो किसी भी समय-कहीं भी सुरक्षित पहुंच को सक्षम बनाता है।

पूर्व चेतावनी प्रणाली और कार्रवाई

बैंकिंग प्रणाली में कमजोरियों के निर्माण का पता लगाने के लिए प्रारंभिक चेतावनी संकेतक महत्वपूर्ण हैं। वृहद स्तर पर, इसमें प्रणालीगत जोखिम की पहचान करने के लिए ऋण-से-जीडीपी अनुपात, अर्थव्यवस्था-व्यापी ऋण सेवा अनुपात (डीएसआर) आदि जैसे समग्र संकेतकों को देखना शामिल है। सूक्ष्म स्तर पर, बैंक तनाव परीक्षण, पूंजी नियोजन, परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा, तरलता निगरानी आदि के अधीन हैं। इनका उद्देश्य बैंक प्रबंधन और पर्यवेक्षी प्राधिकारियों को संभावित प्रतिकूल झटकों के बारे में सचेत करना है जो जोखिमों की एक विस्तृत श्रृंखला से उत्पन्न हो सकते हैं और साथ ही बैंकों और पर्यवेक्षी प्राधिकरणों को वित्तीय संसाधनों के बारे में एक अनुमान प्रदान करना है जो जोखिमों के उत्पन्न होने पर हानियों को अवशोषित करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

2022-23 में, एक नया ईडब्ल्यूआई ढांचा विकसित और बैंक-टेस्ट किया गया है जो एससीबी के वित्तीय प्रदर्शन का व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह ईडब्ल्यूआई ढांचा 18 महत्वपूर्ण अनुपातों के सेट में महत्वपूर्ण थ्रेसहोल्ड के उल्लंघनों के संदर्भ में एक प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करता है। एमएजी आइएमएफ द्वारा प्रकाशित अक्टूबर 2023 के लिये वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (Global Financial Stability Report- GFSR) के आधार पर EWI ढाँचे में सुधार करने की प्रक्रिया में है। दृष्टिकोण में एकरूपता लाने के अलावा मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) पर अपेक्षाओं को सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित करने के लिए, बैंकों में अनुपालन कार्य पर दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया था। इस परिपत्र से सीसीओ के कामकाज में स्वतंत्रता, अधिकार, पारदर्शिता और जिम्मेदारी बढ़ने की उम्मीद है, जिसमें बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुपालन नीति की आवश्यकता, न्यूनतम कार्यकाल निर्धारित करके सीसीओ की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने, स्थानांतरण, हटाने, पात्रता मानदंड के साथ-साथ चयन प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश शामिल हैं।

शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए)

1997 में बेसल समिति द्वारा तैयार किए गए "प्रभावी बैंकिंग पर्यवेक्षण के लिए मुख्य सिद्धांत", जो पर्यवेक्षी अधिकारियों को उनकी वर्तमान पर्यवेक्षी व्यवस्था को मजबूत करने में मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से न्यूनतम आवश्यकताओं की प्रकृति में थे, पर्यवेक्षकों के पास पर्याप्त पर्यवेक्षी उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया गया, कानूनी प्रतिबंधों द्वारा समर्थित, समय पर सुधारात्मक कार्रवाई लाने के लिए जब बैंक विवेकपूर्ण आवश्यकताओं (जैसे न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात) को पूरा करने में विफल रहते हैं, जब नियामकीय उल्लंघन होते हैं या जमाकर्ताओं के हितों को किसी अन्य तरीके से खतरा पैदा होता है। तदनुसार, मौजूदा पर्यवेक्षी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए दिसम्बर, 2002 में पूर्व निर्धारित नियम आधारित ढांचागत प्रारंभिक हस्तक्षेप के आधार पर त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) प्रणाली लागू की गई थी। पीसीए की मूल योजना के अनुसार आरबीआई उन बैंकों पर कुछ संरचित कार्रवाइयां शुरू करेगा, जैसे लाभांश भुगतान पर प्रतिबंध, व्यापार की नई लाइनों में प्रवेश, नई जमा राशि की स्वीकृति, आदि, जो पूंजी पर्याप्तता, परिसंपत्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता के मामले में ट्रिगर बिंदुओं को हिट कर चुके हैं।

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC-SC) की उप-समिति के निर्देशों के अनुसार, आरबीआई ने बैंकों के लिए मौजूदा पीसीए ढांचे की समीक्षा और उन्नयन करने का निर्णय लिया। संशोधित पीसीए ढांचे को अप्रैल 2017 में अधिसूचित किया गया था, जिसे 2021 में फिर से संशोधित किया गया और 01 जनवरी, 2022 से प्रभावी किया गया। यह शाखाओं अथवा सहायक कंपनियों के माध्यम से परिचालित विदेशी बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होता है, लेकिन इसमें लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल नहीं हैं, जो पहचान किए गए संकेतकों की जोखिम सीमा के उल्लंघन पर आधारित है। संशोधित ढांचे के तहत बैंकों की निगरानी के लिए प्रमुख क्षेत्र पूंजी, परिसंपत्ति गुणवत्ता और उत्तोलन हैं। पूंजी, परिसंपत्ति गुणवत्ता और उत्तोलन के लिए ट्रैक किए गए संकेतक क्रमशः सीआरएआर/सामान्य इक्विटी टियर 1 अनुपात, शुद्ध एनपीए अनुपात और नियामक न्यूनतम टियर 1 उत्तोलन अनुपात हैं। जोखिम सीमा के तीन स्तरों को परिभाषित किया गया है, जिसके उल्लंघन के परिणामस्वरूप पीसीए का आह्वान किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप कुछ अनिवार्य और विवेकाधीन कार्रवाइयां होती हैं। अनिवार्य कार्रवाइयों में लाभांश वितरण, शाखा विस्तार, उच्चतर प्रावधान आदि पर प्रतिबंध शामिल हैं। विवेकाधीन कार्रवाइयों के चयन के लिए एक सामान्य मैनू है जैसे विशेष पर्यवेक्षी बातचीत (उदाहरण के लिए, बैंक की विशेष लेखा परीक्षा), रणनीति संबंधी कार्रवाइयां (बैंक को व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्रचना करने का निर्देश देना), शासन संबंधी कार्रवाइयां (विभिन्न पहलुओं पर बैंक के बोर्ड के साथ सक्रिय रूप से संलग्न होना), पूंजी संबंधी (पूंजी संरक्षण के लिए उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में जोखिम में कमी), ऋण जोखिम संबंधी (ऋण समीक्षा तंत्र को सुदृढ़ बनाना), बाजार जोखिम संबंधी (व्युत्पन्न क्रियाकलापों पर प्रतिबंध), मानव संसाधन संबंधी (मौजूदा कर्मचारियों की विशिष्ट प्रशिक्षण आवश्यकताओं की समीक्षा), लाभप्रदता संबंधी (पूंजीगत व्यय के कुछ रूपों पर प्रतिबंध) और प्रचालन संबंधी (शाखा विस्तार योजनाओं पर प्रतिबंध)। इसके अतिरिक्त, पीसीए ढांचा आरबीआई को फेरमवर्क में निर्धारित सुधारात्मक कार्रवाइयों के अतिरिक्त कोई अन्य कार्रवाई करने से नहीं रोकता है जो वह उचित समझे।

लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों और आरबीआई द्वारा किए गए चल रहे पर्यवेक्षी मूल्यांकन के आधार पर बैंक को पीसीए ढांचे के तहत रखा जाता है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक वर्ष के दौरान किसी भी बैंक पर पीसीए लागू कर सकता है (जिसमें एक सीमा से दूसरी सीमा में माइग्रेशन शामिल है), यदि परिस्थितियां ऐसी हों।

तनाव परीक्षण

2007-09 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से तनाव परीक्षण की भूमिका तेजी से विकसित हुई है और महत्व में बढ़ी है। कई न्यायालय 'पर्यवेक्षी पूंजी' के उचित स्तर को तय करने के लिए तनाव परीक्षण का उपयोग कर रहे हैं। दिसंबर 2013 में, आरबीआई ने तनाव परीक्षण पर दिशानिर्देश जारी किए और सभी बैंकों के लिए यह अनिवार्य कर दिया कि वे दिशानिर्देशों में निर्धारित झटकों को शामिल करते हुए कम से कम ट्रेस टेस्ट करें। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि बैंकों को कम से कम आधारभूत झटकों से बचने में सक्षम होना चाहिए और दबाव परीक्षण कार्यक्रमों को अपनाना चाहिए जो परिष्कार की डिग्री के अनुरूप हो। एमएजी एससीबी का पर्यवेक्षी तनाव परीक्षण करता है, और परिणाम एससीबी के एसएसएम के साथ-साथ बैंक के शीर्ष प्रबंधन के साथ साझा किए जाते हैं। हाल ही में, एससीबी के लिए एमएजी द्वारा उपयोग किए जा रहे एकल-कारक तनाव परीक्षण मॉडल को तनाव परीक्षण के एक बहु-कारक मॉडल द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जिसमें मुद्रास्फीति, जीडीपी वृद्धि, विनिमय दर और बेरोजगारी दर जैसे व्यापक आर्थिक कारक शामिल हैं, जो एससीबी विशिष्ट विशिष्टताओं द्वारा पूरक हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आस्ति गुणवत्ता और पूंजी जोखिम-भारित संपत्ति अनुपात

(सीआरएआर) की स्थिति व्यापक आर्थिक कारकों के साथ-साथ संस्था विशिष्ट विशेषताओं के साथ तालमेल बिठाती है।

पर्यवेक्षी परिणाम प्रस्तुत करना

प्राप्त अनुभव के साथ और व्यापक पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं के घटकों के लिए एक मॉड्यूलर दृष्टिकोण रखने के लिए, पर्यवेक्षी परिणामों को विभाजित किया जाता है (i) बैंकों के अप्रत्याशित नुकसान का ख्याल रखते हुए जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट (आरएआर); (ii) निरीक्षण रिपोर्ट (आईआर) जिसमें (क) विनियामक प्रचालनों का आकलन अर्थात् अनुपालन समीक्षा और (ख) पूंजी समीक्षा जिसमें उपलब्ध पूंजी का मूल्यांकन शामिल है, के माध्यम से बैंकों की प्रत्याशित हानियों को कवर करना; और (iii) बैंक के ग्राहक और बाजार आचरण से संबंधित मुद्दों को कवर करने वाले व्यवसाय के संचालन का आकलन।

क्रॉस-नेशनल संदर्भ में पर्यवेक्षण

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय बैंक उस क्षेत्राधिकार के लिए जोखिम का स्रोत हो सकते हैं जिसमें यह संचालित होता है और साथ ही गृह देश के लिए जहां इसके प्रमुख संचालन किए जाते हैं। इसलिए, देशों के लिए इन संस्थाओं की निगरानी में सहयोग करना महत्वपूर्ण है। चूंकि बैंकों का विनियमन और पर्यवेक्षण ज्यादातर सुपरनैशनल स्तर के बजाय राष्ट्रीय स्तर पर होता है, इसलिए अधिकारियों के बीच इस तरह का सहयोग सीमाओं के पार वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। भारतीय रिज़र्व बैंक आवधिक रूप से विदेशों में स्थित भारतीय बैंक शाखाओं की ऑनसाइट जांच आयोजित करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे घरेलू और मेजबान देश दोनों विनियमों का पालन करते हैं और साथ ही बैंक तुलन पत्र में शाखा तुलन-पत्रों द्वारा उत्पन्न जोखिमों को समझते हैं।

सीमा पार पर्यवेक्षी सहयोग पर बीसीबीएस सिद्धांतों के अनुरूप, रिज़र्व बैंक ने विदेशी समकक्ष पर्यवेक्षकों के साथ जुड़ाव जारी रखा। रिज़र्व बैंक ने मुंबई में एशिया-प्रशांत अर्थव्यवस्थाओं के पर्यवेक्षण के निदेशकों के 25वें दक्षिणपूर्व एशियाई केंद्रीय बैंक-वित्तीय स्थिरता संस्थान (SEACEN-FSI) सम्मेलन और एसईएसीईएन SEACEN सदस्यों के पर्यवेक्षण निदेशकों की 36वीं बैठक की मेजबानी की। रिज़र्व बैंक ने मुंबई में जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण पर अध्ययन यात्रा सह कार्यशाला के लिए बांग्लादेश बैंक के एक प्रतिनिधिमंडल की भी मेजबानी की।

पर्यवेक्षी कॉलेज

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशों में भारतीय बैंकों के सीमापार परिचालनों के पर्यवेक्षण के भाग के रूप में छह प्रमुख बैंकों (भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड और पंजाब नेशनल बैंक) के लिए पर्यवेक्षी कॉलेज स्थापित किए हैं, जिनकी महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति है। पर्यवेक्षी कॉलेज का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग समूह के जोखिम प्रोफाइल की समझ में सुधार के लिए पर्यवेक्षकों के बीच सूचना विनिमय और सहयोग को बढ़ाना है। इससे अंतराष्ट्रीय रूप से सक्रिय बैंकों का और अधिक प्रभावी पर्यवेक्षण करने में सुविधा होगी। इसके अलावा, अंतरिक्ष विभाग ने पर्यवेक्षी सहयोग और आदान-प्रदान के मामले में बड़ी संख्या में वैश्विक संस्थानों (44 समझौता ज्ञापन, दो पत्रों का आदान-प्रदान – ईओएल और सहयोग का एक विवरण (एसओसी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

वर्ष 2023-24 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने चुनिंदा बैंकों की पर्यवेक्षी कॉलेज बैठकें आयोजित कीं और पर्यवेक्षी चिंताओं, कार्यप्रणाली और सर्वोत्तम प्रथाओं पर जानकारी के आदान-प्रदान के लिए विदेशी पर्यवेक्षकों के साथ सात बैठकें कीं। इसके

बदले में, रिज़र्व बैंक ने मेजबान प्राधिकारी के रूप में विदेशी पर्यवेक्षकों द्वारा चुनिंदा बैंकों के लिए आयोजित सात पर्यवेक्षी कॉलेजों की बैठकों में भाग लिया। रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधियों ने यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) और हांगकांग मौद्रिक प्राधिकरण (एचकेएमए) द्वारा 'पर्यवेक्षी दृष्टिकोण, कार्यप्रणाली और व्यवहार' पर संबंधित कार्यशालाओं में भाग लिया।

पीएसबी और पीवीबी में शासन प्रथाएँ

एक मजबूत शासन संरचना बैंक की स्थिरता के साथ-साथ स्थायी वित्तीय प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तदनुसार, हाल के वर्षों में फोकस क्षेत्रों में से एक एसई के भीतर शासन प्रथाओं को मजबूत करना रहा है। इस पहलू की न केवल ऑनसाइट पर्यवेक्षी प्रक्रिया के दौरान जांच की जाती है, बल्कि बोर्ड/वरिष्ठ प्रबंधन के साथ सम्मेलनों और बैठकों के रूप में एसई के साथ निरंतर जुड़ाव और ऑफसाइट सिस्टम स्तर के आकलन के माध्यम से भी जोर दिया जाता है। बैंक, क्रेडिट के सबसे महत्वपूर्ण प्रदाताओं के रूप में, अन्य संस्थाओं से भिन्न होते हैं क्योंकि उनके पतन का जमाकर्ताओं, संस्थानों और वित्तीय प्रणाली के लिए व्यापक प्रभाव पड़ता है। इससे बैंकों को विशिष्ट नियमों और करीबी निगरानी के अधीन करना अनिवार्य हो जाता है। बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे उचित नीतियां और उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण रखें ताकि शासन संरचना को अच्छी तरह से लागू किया जा सके क्योंकि बैंक वित्तीय संरचना और अर्थव्यवस्था के लिए आधार के रूप में कार्य करते हैं।

यह अत्यावश्यक है कि बैंकों के पास सुदृढ़ अभिशासन नीतियां और प्रक्रियाएं हों जिनमें बैंक के जोखिम प्रोफाइल और प्रणालीगत महत्व के अनुरूप कार्यनीतिक दिशा, समूह और संगठनात्मक संरचना, नियंत्रण वातावरण, बोर्डों और वरिष्ठ प्रबंधन के उत्तरदायित्व शामिल हों। बोर्ड के पास बैंक की रणनीतिक योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी देने और देखरेख करने की जिम्मेदारी है- जोखिम की भूख और संबंधित नीतियां; कॉर्पोरेट संस्कृति और मूल्यों की स्थापना और संचार; और हितों के टकराव और एक मजबूत नियंत्रण वातावरण से संबंधित नीति तैयार करना।

पर्यवेक्षी मूल्यांकन के दौरान, नीतियों के उपरोक्त पहलुओं और कार्यान्वयन की जांच की जाती है। इनमें उपयुक्त कौशल और विशेषज्ञता के साथ बोर्ड के सदस्यों की पर्याप्त संख्या की उपलब्धता और अन्य पहलुओं के साथ-साथ निर्धारित नीतियों के अनुसार बोर्ड बैठकों का प्रभावी संचालन शामिल है। पीएसबी और पीवीबी में मजबूत शासन प्रथाएं विभिन्न पणधारकों, विशेष रूप से जमाकर्ताओं को विश्वास प्रदान करने में मदद करती हैं, जिनके पास बैंकों के व्यावसायिक निर्णयों में कोई बात नहीं होती है। इसके लिए रणनीतिक मुद्दों और जोखिम निगरानी में बैंकों के बोर्डों की गहन भागीदारी की आवश्यकता है।

एसई में शासन ढांचे का निरंतर मूल्यांकन

चूंकि शासन व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है और पर्यवेक्षी चिंताओं का मूल कारण भी यही है, इसलिए रिज़र्व बैंक ने एस.ई. के प्रबंधन और निदेशकों के साथ अपने संबंधों को पुनः स्थापित किया है। वर्ष के दौरान, पीएसबी और पीवीबी के बोर्डों के निदेशकों के लिए 'बैंकों में शासन - सतत विकास और स्थिरता को बढ़ावा देना' विषय के साथ सम्मेलन आयोजित किए गए, जिनमें रिज़र्व बैंक के गवर्नर और शीर्ष प्रबंधन ने भाग लिया। भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों और पीवीबी के प्रबंध निदेशकों (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) के साथ भी बैठकें कीं। इन बैठकों में, एसई को जोखिमों की शीघ्र पहचान और शमन को सक्षम करने के लिए शासन संरचना को और मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित

किया गया था। रिज़र्व बैंक नामिती निदेशकों (एनडी) और अपर निदेशकों (एडी) के लिए आवधिक सम्मेलन भी आयोजित किए जाते हैं।

घरेलू वित्तीय नियामकों के साथ अंतर-नियामक सहयोग

'अग्रणी नियामक' सिद्धांत की तर्ज पर अंतर-नियामक फोरम फॉर मॉनिटरिंग फाइनेंशियल कंग्लोमरेट्स (आईआरएफ) का गठन अगस्त 2012 में वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की उप-समिति के तत्वावधान में किया गया था। भारतीय रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण विभाग के प्रभारी डिप्टी गवर्नर की अध्यक्षता में आईआरएफ में पूर्णकालिक सदस्य स्तर पर अन्य विनियामकों/पर्यवेक्षकों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। 2019 से राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) को स्थायी आमंत्रित के रूप में शामिल करने के साथ, फोरम में अब RBI, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण और एनएचबी शामिल हैं।

आईआरएफ वित्तीय समूह (एफसी) के पर्यवेक्षण को मजबूत करने और एफसी की गतिविधियों से उत्पन्न प्रणालीगत स्थिरता के जोखिमों का आकलन करने के लिए घरेलू वित्तीय क्षेत्र नियामकों/पर्यवेक्षकों के एक कॉलेज के रूप में कार्य करता है। इससे प्रणालीगत स्पिलओवर और अंतर-नियामक आयामों वाले किसी भी मुद्दे पर चिंताओं/सूचनाओं को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करने की उम्मीद है। इसके समन्वित निरीक्षण में वित्त आयुक्तों के साथ आवधिक बैठकें आयोजित करना, उभरते जोखिमों की पहचान करने के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक सूचना का मिलान करना, स्थलेतर विश्लेषण से उभरने वाली प्रमुख पर्यवेक्षी चिंताओं की समीक्षा करना और घरेलू विनियामकों/पर्यवेक्षकों के बीच सूचना के संरचित आदान-प्रदान को सुकर बनाना शामिल है। आईआरएफ के दायरे में एफसी से संबंधित विभिन्न मामलों पर नीतियां तैयार करना भी शामिल है, जैसे एफसी और सामग्री समूह संस्थाओं की पहचान के लिए मानदंडों को परिभाषित करना।

एसई के साथ पर्यवेक्षी जुड़ाव की रूपरेखा बदलना

एसई के साथ पर्यवेक्षी जुड़ाव प्रासंगिकता, पारदर्शिता, स्पष्टता, व्यापकता और समयबद्धता के व्यापक सिद्धांतों का पालन करता है। इन वर्षों में, एसई के साथ जुड़ाव का क्षेत्र बातचीत स्तर और आवृत्ति दोनों के संदर्भ में काफी बढ़ गया है। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में बदलती वास्तविकताओं को अपनाने के लिए रिज़र्व बैंक का पर्यवेक्षी दृष्टिकोण लगातार विकसित हो रहा है। नतीजतन, एसई के साथ पर्यवेक्षी जुड़ाव की रूपरेखा लगातार विकसित हो रही है, पारंपरिक दृष्टिकोणों से आगे बढ़ रही है जैसा कि नीचे दिया गया है:

आउटलायर एसई के साथ बैठकें

बैंकों और गैर-बैंकों के बीच प्रारंभिक और उभरती कमजोरियों और क्षेत्रीय तनाव की घटनाओं की पहचान करने के लिए ऑफसाइट मूल्यांकन में विश्लेषण के दायरे को बढ़ाया गया था। इस उद्देश्य के लिए, डेटा-संचालित निर्णयों को सुविधाजनक बनाने, जोखिमों की पहचान करने और वित्तीय स्थिरता की सुरक्षा के लिए समय पर कार्रवाई करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी और डेटा एनालिटिक्स का लाभ उठाया जा रहा है। इसके अलावा, एसई के व्यापार मॉडल की गहन जांच और उल्लिखित जोखिम क्षमता के साथ इसके संरेखण के बारे में सावधानीपूर्वक मूल्यांकन भी किया जा रहा है।

रिज़र्व बैंक का शीर्ष प्रबंधन उपर्युक्त मूल्यांकनों में आउटलायर्स के रूप में पहचाने गए एसई के साथ बैठकें आयोजित करता है। इसके अलावा, जैसा कि अपेक्षित था, बैंकों के निदेशक मंडल और आश्वासन कार्यों के प्रमुखों के लिए सम्मेलन आयोजित किए गए हैं।

आश्वासन कार्यकर्ता

चूंकि एसई के आश्वासन कार्य रिज़र्व बैंक की विस्तारित पर्यवेक्षी शाखाओं के रूप में कार्य करते हैं, आंतरिक आश्वासन कार्यों को मजबूत करना हाल के वर्षों में एक पर्यवेक्षी प्राथमिकता रही है। वर्ष के दौरान, पर्यवेक्षी अपेक्षाओं को व्यक्त करने के लिए बैंकों के आश्वासन पदाधिकारियों के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। रिज़र्व बैंक के प्रशिक्षण प्रतिष्ठान भी नियमित रूप से एसई के आश्वासन कार्यकर्ताओं के लिए कार्यक्रम आयोजित करते हैं।

कैलिब्रेटेड निरंतर पर्यवेक्षण

इसके अलावा, पर्यवेक्षी टीमों ऑनसाइट निरीक्षण के दौरान कई स्तरों पर एसई के साथ लगातार जुड़ती हैं। जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण ढांचे के तहत, संरचित वार्षिक पर्यवेक्षी चक्र के अलावा, पर्यवेक्षक भी विकसित स्थितियों के आधार पर एसई के साथ सक्रिय रूप से संलग्न होते हैं।

संक्षेप में, विभिन्न स्तरों पर एसई के साथ जुड़ाव प्रारंभिक और प्रभावी हस्तक्षेप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन व्यस्तताओं से प्राप्त अंतर्दृष्टि संभावित पर्यवेक्षी चिंताओं को कम करने में मदद करती है और/या एसई को वांछनीय पर्यवेक्षी उद्देश्यों की ओर धकेलने के लिए अधिक बढ़े हुए पर्यवेक्षी हस्तक्षेपों पर जोर देती है। साथ ही, महत्वपूर्ण हितधारकों से समर्थन प्राप्त करने से स्वीकृति भी बढ़ती है, लागत कम हो जाती है और इसलिए, पर्यवेक्षी हस्तक्षेप को अधिक प्रभावी बनाता है।

भारत का एफएटीएफ पारस्परिक मूल्यांकन

भारत को एफएटीएफ द्वारा 'पारस्परिक मूल्यांकन' (एमई) प्रक्रिया के अधीन किया गया था। एमई प्रक्रिया में, अन्य बातों के साथ-साथ, एफएटीएफ सिफारिशों (तकनीकी अनुपालन) के अनुपालन के साथ-साथ धन शोधन/आतंकवादी वित्तपोषण/प्रसार वित्तपोषण प्रयोजनों [प्रभावशीलता मूल्यांकन (ईए)] के लिए वित्तीय क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने में क्षेत्राधिकार द्वारा स्थापित एएमएल/सीएफटी/सीपीएफ ढांचे की प्रभावकारिता पर मूल्यांकन शामिल है। रिज़र्व बैंक ने क्षेत्रवार विनियामक के रूप में एएमएल/टीएफ जोखिमों से निपटने के लिए स्थापित प्रणालियों के मानकों और प्रभावकारिता के अनुपालन को प्रदर्शित करने में मूल्यांकन के दौरान अन्य हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से योगदान दिया।

अध्याय 9: सहकारी बैंकों का विनियमन और पर्यवेक्षण

*"सहकारी संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को साबित करते हैं कि
आर्थिक व्यवहार्यता और सामाजिक जिम्मेदारी दोनों को आगे बढ़ाना संभव है" -
संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव - बान की मून*

परिचय

महात्मा गांधी ने एक बार कहा था: "मान लीजिए कि मेरे पास उचित मात्रा में संपत्ति है - या तो विरासत के माध्यम से, या व्यापार और उद्योग के माध्यम से - मुझे पता होना चाहिए कि वह सारी संपत्ति मेरी नहीं है; सम्मानजनक आजीविका का अधिकार मेरा है, जो लाखों अन्य लोगों द्वारा प्राप्त आजीविका से बेहतर नहीं है। मेरी शेष संपत्ति समुदाय की है और इसका उपयोग समुदाय के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए।" यह सहकारी आंदोलन का सार है, जो सामुदायिक सौहार्द, आपसी सहायता, लोकतांत्रिक निर्णय लेने और खुली सदस्यता आदि के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसे आमतौर पर "सहकारी सिद्धांत" के रूप में जाना जाता है।

सहकारी आंदोलन का इतिहास

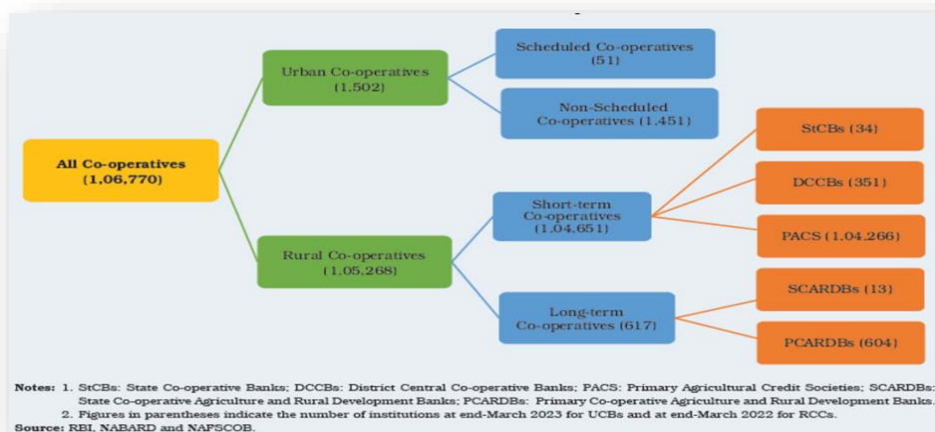
भारत में सहकारी आंदोलन एक शताब्दी से भी अधिक पुराना है। भारत में सहकारी संस्थानों का संगठन 19^{वीं} शताब्दी का है, जब 05 फरवरी 1889 को बड़ौदा, गुजरात में पहली पारस्परिक सहायता संस्था 'अन्योन्य सहकारी मंडली' का गठन किया गया था। 1904 में सहकारी समिति अधिनियम के पारित होने से इन संस्थानों को पहली बड़ी प्रोत्साहन प्रदान की गई और तमिलनाडु में स्थित कांचीपुरम सहकारी क्रेडिट सोसाइटी इस अधिनियम के तहत पंजीकृत पहली क्रेडिट सोसाइटी बन गई। बाद में 1919 में, सहकारिता का विषय केंद्र सरकार से प्रांतीय राज्यों में अंतरित कर दिया गया।

सहकारी ऋण संस्थान बैंकिंग/वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग हैं, क्योंकि वे जमाराशियां जुटाने और छोटे साधनों के लोगों को ऋण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे वित्तीय समावेशन के लिए एक महत्वपूर्ण वाहन होते हैं और लेनदेन की सुविधा प्रदान करते हैं। परंपरागत रूप से, भारत में सहकारी संस्थागत संरचना को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, अर्थात् 'ग्रामीण' और 'शहरी' जिसमें ग्रामीण सहकारी समितियों का संघीय ढांचा है। वर्तमान संरचना का रेखांकन नीचे दर्शाया गया है।

सहकारी संस्थाओं की विशेषताएँ

- उनके परिचालन क्षेत्र ध्यान केंद्रित है।
- निदेशक मंडल का चुनाव शेयरधारकों द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से किया जाता है।
- इन संस्थानों से उधार केवल इसके सदस्यों तक ही सीमित है, कुछ अपवादों को छोड़कर यथा नाममात्र के सदस्यों को उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं ऋण, गैर-सदस्यों (वेतनभोगी शहरी सहकारी बैंक) की सावधि जमाराशियों पर ऋण, सहकारी आवास समितियों को आवास ऋण।

- उधार लेने के लिए शेयर लिंकिंग है, अर्थात्, उधारकर्ता सदस्य को सहकारी बैंक में शेयर पूंजी रखने की आवश्यकता है, जिसकी राशि बैंक से उधार ली गई राशि के एक निश्चित निर्दिष्ट प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।
- सदस्य केवल एक वोट डाल सकते हैं, चाहे उनके पास जितने भी शेयर हो।
- इन संस्थानों के शेयरों को सूचीबद्ध और कारोबार नहीं किया जा सकता है।



सहकारी ऋण समितियों और सहकारी बैंकों में अंतर

'सहकारी समितियां' राज्य सूची में प्रविष्टि 32 पर आती हैं, जबकि 'बैंकिंग' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत संघ सूची में प्रविष्टि 45 पर दिखाई देती है। इसलिए, भारत में सहकारी समितियां राज्य का विषय है, और वे आरबीआई के नियामक दायरे में नहीं आती हैं। सहकारी ऋण समितियां मुख्य रूप से अपने सदस्यों से जमाराशियां जुटाकर अपने सदस्यों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।

सहकारी ऋण समितियां, जिन्हें बैंकिंग गतिविधियां करने के लिए लाइसेंस जारी हैं, वे सहकारी बैंक के रूप में कार्य करती हैं और वे आम जनता से जमाराशियां स्वीकार करने के लिए पात्र हैं। शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) मुख्यतः या तो संबंधित राज्य के राज्य सहकारी समिति अधिनियम अथवा बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के उपबंधों के अंतर्गत सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत होते हैं, यदि बैंक का परिचालन क्षेत्र एक राज्य की सीमाओं से परे फैला हो।

सहकारी बैंकों को विनियमित करने के लिए विधिक ढांचा

बैंकिंग विनियमन अधिनियम (जिसे तब बैंकिंग कंपनी अधिनियम कहा जाता था) 1949 में लागू हुआ, हालांकि, बैंकिंग कानून केवल मार्च 1966 में अधिनियम में संशोधन के माध्यम से सहकारी समितियों पर लागू किए गए थे (और बैंकिंग विनियमन अधिनियम के रूप में नाम दिया गया था) अधिनियम की धारा 56 (भाग V) को शामिल करके, जिसे आमतौर पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) - (सहकारी समितियों के लिए लागू) के रूप में जाना जाता है।

इसके साथ, सहकारी बैंक संबंधित राज्य सरकारों / केंद्र सरकार और रिज़र्व बैंक के दोहरे नियंत्रण में आ गए, जो इन संस्थानों को वाणिज्यिक बैंकों से अलग बनाते हैं। जबकि पंजीकरण, भर्ती और परिसमापन जैसे प्रशासनिक पहलुओं को राज्य/केंद्र सरकारों द्वारा विनियमित किया जाता है, बैंकिंग से संबंधित मामलों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है। कुछ ऐसे पहलू भी हैं जहां सरकारों और आरबीआई के पास समवर्ती शक्तियां हैं।

हाल ही में, बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 और बहु-राज्य सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2023

द्वारा क्रमशः बैंकिंग विनियमन अधिनियम (BR), 1949 और महाराष्ट्र राज्य सहकारी समिति (MSCS) अधिनियम, 2002 में संशोधन किए गए हैं। MSCS अधिनियम, 2002 में 2023 का संशोधन संविधान के भाग IXB के तहत प्रदान किए गए प्रावधानों के साथ इसके प्रावधानों को संरक्षित करने और सहकारी समितियों के कामकाज और शासन के साथ कुछ चिंताओं को दूर करने के लिए अधिनियम में संशोधन करना चाहता है।

बीआर अधिनियम में संशोधन का उद्देश्य सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए प्रबंधन, पूंजी, लेखापरीक्षा और परिसमापन के संदर्भ में सहकारी बैंकों पर आरबीआई की नियामक निगरानी को बढ़ाना था। संशोधित अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ आरबीआई के अनुमोदन एवं आरबीआई द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन सार्वजनिक निर्गम या निजी नियोजन के माध्यम से शेयरों, डिबेंचरों और अन्य समान प्रतिभूतियां जारी करने का प्रावधान किया गया है। संशोधित अधिनियम में मूल अधिनियम के कई अन्य प्रावधान भी हैं, जैसे कि सहकारी बैंकों के प्रबंधन, लेखापरीक्षा, समामेलन आदि से संबंधित।

संशोधित अधिनियम आरबीआई को सहकारी बैंकों के निदेशक मंडल से किसी एक निदेशक को हटाने और अतिरिक्त निदेशक नियुक्त करने का अधिकार देता है। इसमें आगे कहा गया है कि किसी राज्य की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत सहकारी बैंकों के मामले में, आरबीआई संबंधित राज्य सरकार के परामर्श के बाद और उसके द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर निदेशक मंडल का अतिक्रमण कर सकता है। इसके अतिरिक्त, आरबीआई किसी सहकारी बैंक अथवा सहकारी बैंकों के किसी वर्ग को अधिसूचना के माध्यम से अधिनियम के कतिपय उपबंधों से ऐसे समय के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन जो इसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, छूट दे सकता है।

वर्षों से, रिज़र्व बैंक सहकारी बैंकिंग संरचना को मजबूत करने के लिए सुधारों की शुरुआत करता रहा है। इसकी दोतरफा रणनीति में सांविधिक सुधार और नियामक समर्थन शामिल हैं। रिज़र्व बैंक ने 19 जुलाई 2022 को यूसीबी को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे को संशोधित किया। ढांचे का मार्गदर्शन करने वाला दृष्टिकोण ग्राहक आधार में विविधता को पूरा करके अनुकूल पड़ोस बैंकों के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करना है, जबकि मजबूत यूसीबी को क्रेडिट मध्यस्थता में उनके योगदान को बढ़ाने के लिए अधिक परिचालनात्मक लचीलापन प्रदान करना है।

जबकि शहरी सहकारी बैंक आरबीआई द्वारा विनियमित और पर्यवेक्षण किए जाते हैं, ग्रामीण सहकारी बैंक अर्थात् राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) आरबीआई द्वारा विनियमित होते हैं लेकिन राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा पर्यवेक्षण किया जाता है। दीर्घावधिक ग्रामीण सहकारी समितियां अर्थात् राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी) और प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी) भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियामक अथवा पर्यवेक्षी कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं।

सहकारी बैंक की परिभाषा

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसएस) की धारा 5 (सीसीवी) में यूसीबी को प्राथमिक कृषि ऋण समिति से इतर सहकारी समिति के रूप में परिभाषित किया गया है और जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है:

- जिसका प्राथमिक उद्देश्य या प्रमुख व्यवसाय बैंकिंग व्यवसाय का लेन-देन है
- जिसकी प्रदत्त शेयर पूंजी और आरक्षित निधि एक लाख रुपये से कम न हो; और
- जिसके उपनियम किसी अन्य सहकारी समिति को सदस्य के रूप में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते।

विकास और समेकन

जब 1966 में इन शहरी सहकारी बैंकों पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबंध लागू किए गए थे, जिससे बैंकिंग कारोबार करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य हो गया था, तब लगभग 1100 शहरी सहकारी बैंक जिनकी जमाराशियां और अग्रिम राशि क्रमशः 167 करोड़ रुपये और 153 करोड़ रुपये युक्त थे। इसके बाद, रिज़र्व बैंक ने विशेष रूप से मराठे समिति की सिफारिशों के अनुसरण में एक उदार लाइसेंसिंग नीति अपनाई। तदनुसार, वर्ष 1993 में रही 1311 यूसीबी से यह संख्या 2003 तक बढ़कर 2104 हो गई। तथापि, नए लाइसेंस प्राप्त शहरी सहकारी बैंकों में से लगभग एक-तिहाई अल्प अवधि के भीतर वित्तीय रूप से अस्वस्थ हो गए। अनुभव और यूसीबी क्षेत्र की मौजूदा वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2004-05 में यह निर्णय लिया गया था कि रिज़र्व बैंक नए लाइसेंस जारी करने पर तभी विचार करेगा जब इस क्षेत्र के लिए उपयुक्त कानूनी और विनियामक ढांचे सहित व्यापक नीति लागू कर दी जाएगी। तब से नए यूसीबी स्थापित करने के लिए कोई नए लाइसेंस जारी नहीं किए गए हैं। विलय/समामेलन, क्रेडिट सोसाइटियों के रूप में रूपांतरण और वर्षों में यूसीबी के लाइसेंस रद्द करने के कारण, देश में यूसीबी की संख्या 31 मार्च 2024 तक घटकर 1472 हो गई है।

इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए आरबीआई द्वारा की गई पहल

यूसीबी क्षेत्र की वित्तीय सुदृढ़ता में सुधार करने के लिए, सह-नियामकों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2005 से सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित किए। समझौता ज्ञापन के तहत की गई व्यवस्थाओं के हिस्से के रूप में, रिज़र्व बैंक ने प्रत्येक राज्य में, यूसीबी हेतु सहकारी शहरी बैंकों (टीएफसीयूबी) के लिए एक राज्य-स्तरीय टास्क फोर्स (टैफकब) का गठन किया। बहु-राज्य यूसीबी के लिए एक केंद्रीय टैफकब का गठन किया गया था। ऐसे टैफकब, राज्यों में संभावित रूप से अर्थक्षम और गैर-अर्थक्षम यूसीबी जो वित्तीय रूप से कमजोर की पहचान करते हैं और अर्थक्षम यूसीबी के लिए पुनरुद्धार मार्ग तथा गैर-अर्थक्षम शहरी सहकारी बैंकों के लिए गैर-विघटनकारी विकास मार्ग का सुझाव देते हैं। गैर-अर्थक्षम बैंकों का बाहर निकलना मजबूत बैंकों के साथ विलय/समामेलन, सोसाइटियों के रूप में रूपांतरण या अंतिम विकल्प के रूप में परिसमापन के माध्यम से हो सकता है। कमजोर बैंकों (अनिश्चित वित्तीय स्थिति वाले बैंकों) के लिए समाधान प्रक्रियाओं को दिशा और प्रोत्साहन देने के लिए, रिज़र्व बैंक ने विभिन्न वित्तीय लिखतों सहित कमजोर बैंकों के पुनरुद्धार में सहायता के लिए वित्तीय पुनर्गठन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनका उपयोग इस उद्देश्य और निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) की सहायता के साथ और इसके बिना यूसीबी के अन्य यूसीबी के साथ विलय पर, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा शहरी सहकारी बैंकों का अधिग्रहण आदि के लिए किया जा सकता है।

यूसीबी के लघु वित्त बैंक (SFB) के रूप में स्वैच्छिक परिवर्तन के लिए दिशानिर्देश 2018 में कुछ शर्तों के अधीन लाए गए थे और वर्ष 2019 में यूसीबी के शासन और बैंकिंग कार्यों में सुधार लाने के लिए निदेशक मंडल (BoD) के अलावा प्रबंधन मंडल (BOM) के गठन के लिए दिशानिर्देश जारी किये गए थे।

इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन में यूसीबी की भूमिका को मजबूत करने के लिए यूसीबी के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) लक्ष्य को 40% से बढ़ाकर 75% (श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण में) कर दिया। लक्ष्य प्राप्त न करने वालों को हतोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) / राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) / भारतीय

लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) / सूक्ष्म इकाई विकास और पुनर्वित्त एजेंसी लि (मुद्रा) तथा इसी प्रकार की अन्य निधियों के लिए पात्र निधियों के प्रति अंशदान निर्धारित किया गया है। पीएसएल लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले शहरी सहकारी बैंकों को उच्चतर सीमा के बुलेट पुनर्भुगतान ऋणों के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक ने कुल पूंजी के बजाय मजबूत टियर-1 पूंजी के अनुपात को जोड़ते हुए एक्सपोजर मानदंडों को सख्त कर दिया है और शहरी सहकारी बैंकों के पास अपने कुल ऋणों और अग्रिमों का कम से कम 50 प्रतिशत (चरणबद्ध तरीके से प्राप्त किया जाना) होना अनिवार्य कर दिया है जिसमें लघु मूल्य के ऋण शामिल हैं। फिर भी, वे भारतीय रिज़र्व बैंक की अग्रणी बैंक योजना से बाहर बने हुए हैं और राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) के विभिन्न मंचों में इनका प्रतिनिधित्व नहीं है।

यूसीबी की साइबर सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए, आधारभूत साइबर सुरक्षा नियंत्रण एक श्रेणीबद्ध तरीके से निर्धारित किए गए हैं। श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण, यूसीबी को उनकी साइबर सुरक्षा तैयारियों को बढ़ाने में मदद करना था और यह भी सुनिश्चित करना था कि यूसीबी विविध भुगतान सेवाओं और उच्चतर सेवा प्रदान करते हैं। साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने में सूचना प्रौद्योगिकी की पैठ वाणिज्यिक बैंकों के बराबर लाई गई है।

उभरती आईटी और साइबर खतरे के माहौल के प्रति यूसीबी के साइबर लचीलेपन को मजबूत करने के उद्देश्य से, सितंबर 2020 में रिज़र्व बैंक ने विभिन्न हितधारकों के इनपुट के आधार पर यूसीबी हेतु 'साइबर सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी विज्ञान: 2020-2023' जारी किया। इसमें पांच-स्तंभों वाले रणनीतिक दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है जिसमें (i) शासन निरीक्षण; (ii) उपयोगी प्रौद्योगिकी निवेश; (iii) उपयुक्त विनियमन और पर्यवेक्षण; (iv) मजबूत सहयोग; और (v) आवश्यक आईटी और साइबर सुरक्षा कौशल सेट विकसित करना।

यूसीबी को उनकी साइबर सुरक्षा तैयारी में सुधार करने में सहायता प्रदान करने के लिए, साइबर सुरक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी परीक्षा (सीएसआईटीई) समूह द्वारा कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे के सहयोग से यूसीबी के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का एक व्यापक सेट डिजाइन किया गया था। यह पहल अगस्त 2021 के महीने में लागू की गई थी।

यूसीबी का विनियमन

भारतीय रिज़र्व बैंक मुख्य रूप से बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (AACS) और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 से यूसीबी को विनियमित करने की अपनी शक्तियाँ प्राप्त करता है। इन विनियमों में शाखा लाइसेंस जारी करना, उनके परिचालन क्षेत्र का विस्तार करने के लिए प्राधिकार, सीआरआर और एसएलआर अपेक्षाओं को निर्धारित करना और पूंजी पर्याप्तता के लिए विवेकपूर्ण मानदंड, आय मान्यता, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंड, एक्सपोजर मानदंड, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए लक्ष्य, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शहरी सहकारी बैंकों को शामिल करना, शासन संबंधी दिशानिर्देश आदि शामिल हैं।

सहकारी बैंकों के विनियमन के लिए दृष्टिकोण

शहरी सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों के समान बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाने की दृष्टि से, आरबीआई ने उन्हें विशेषकृत शाखाएं, मुद्रा तिजोरियां, ऑन-साइट/ऑफ-साइट/मोबाइल एनी टाइम मनी (एटीएम) खोलने, सरकारी प्रतिभूतियों में इंटर-डे शॉर्ट सेलिंग करने और कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में तैयार वायदा संविदाएं, केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली / रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) / नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) / नेगोशिएटेड डीलिंग

सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग (एनडीएस-ओएम) की एक्सेस की अनुमति दी है। भारतीय रिज़र्व बैंक के पास चालू खाता और एसजीएल खाते खोलने, बीमा उत्पाद/म्यूचुअल फंड यूनिट बेचने, पैन सेवा एजेंट के रूप में कार्य करने, पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के लिए प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस सेवाएं लेने, कारोबार संवाददाताओं / व्यवसाय सुविधादाताओं को नियुक्त करने, डीमैट खाताधारकों को मोबाइल बैंकिंग / इंटरनेट बैंकिंग सुविधा और ट्रेडिंग सुविधाएं प्रदान करने, प्रीपेड लिखत जारी करने की अनुमति प्रदान की गई। अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) और सीमांत स्थाई सुविधा (एमएसएफ) की एक्सेस की अनुमति दी गई है। इस प्रकार, ये सहकारी समितियां एक प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र में सार्वभौमिक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती हैं, जबकि वाणिज्यिक बैंकों को पूरे भारत में विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए अनिवार्य किया जाता है।

यूसीबी के लिए संशोधित नियामक ढांचा

विनियामक उद्देश्यों के लिए शहरी सहकारी बैंकों को निम्नलिखित चार स्तरों में वर्गीकृत किया गया है:

- टियर 1 - सभी यूनिट यूसीबी और वेतनभोगी यूसीबी (विभिन्न जमा आकार के बावजूद), और अन्य सभी यूसीबी जिनकी जमा राशियां ₹ 100 करोड़ तक हैं।
- टियर 2 - ₹100 करोड़ से अधिक और ₹1000 करोड़ तक जमा राशियां वाले यूसीबी।
- टियर 3 - ₹1000 करोड़ से अधिक और ₹10,000 करोड़ तक जमा राशियां वाले यूसीबी।
- टियर 4 - ₹10,000 करोड़ से अधिक जमा राशियां वाले यूसीबी।

ऊपर उल्लिखित जमाराशियों की गणना तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार की जाएगी। यदि कोई शहरी सहकारी बैंक किसी वर्ष जमाराशियों में वृद्धि के कारण उच्च स्तर पर जाता है तो उसे पारित उच्चतर स्तर की उच्च विनियामक अपेक्षाओं, यदि कोई हो, का अनुपालन करने के लिए अधिकतम तीन वर्षों तक का ग्लाइड पाथ प्रदान किया जा सकता है।

शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए संशोधित नियामक ढांचा – निवल मूल्य और पूंजी पर्याप्तता

यूसीबी का न्यूनतम निवल मूल्य निम्नानुसार होगा:

- एक ही जिले में संचालित टियर 1 यूसीबी का न्यूनतम निवल मालियत ₹ 2 करोड़ होगा।
- अन्य सभी यूसीबी (सभी स्तरों के) का न्यूनतम निवल मालियत ₹ 5 करोड़ होगा।
- यूसीबी जो वर्तमान में न्यूनतम निवल मालियत की आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं, जैसा कि ऊपर दिया गया है, चरणबद्ध तरीके से न्यूनतम 2 करोड़ रुपये या 5 करोड़ रुपये (जैसा लागू हो) प्राप्त करेंगे। ऐसे शहरी सहकारी बैंकों को 31 मार्च 2026 को या उससे पहले लागू न्यूनतम निवल मालियत का कम से कम 50 प्रतिशत और 31 मार्च 2028 को या उससे पहले संपूर्ण निर्धारित न्यूनतम निवल मालियत प्राप्त करना होगा।

शहरी सहकारी बैंक जोखिम प्रतीक्षित अनुपात (सीआरएआर) की तुलना में न्यूनतम पूंजी निम्नानुसार बनाए रखेंगे:

- टियर 1 यूसीबी, पहले की तरह, निरंतर आधार पर जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) का न्यूनतम 9 प्रतिशत सीआरएआर बनाए रखेंगे।
- टियर 2 से 4 यूसीबी निरंतर आधार पर आरडब्ल्यूए का न्यूनतम सीआरएआर 12 प्रतिशत बनाए रखेंगे।

- टियर 2 से 4 में यूसीबी, जो वर्तमान में आरडब्ल्यूए के 12 प्रतिशत के संशोधित सीआरएआर को पूरा नहीं करते हैं, चरणबद्ध तरीके से इसे प्राप्त करेंगे। ऐसे शहरी सहकारी बैंकों को 31 मार्च 2024 तक कम से कम 10 प्रतिशत, 31 मार्च 2025 तक 11 प्रतिशत और 31 मार्च 2026 तक 12 प्रतिशत का सीआरएआर प्राप्त करना होगा।

उधार मानदंडों के साथ शेयर लिंकिंग

मौजूदा मानदंडों के अधीन, यूसीबी जो निरंतर आधार पर 12 प्रतिशत का सीआरएआर बनाए रखते हैं, उन्हें अनिवार्य शेयर लिंकिंग मानदंडों से छूट दी गई है। इसकी समीक्षा करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि उधार मानदंडों से शेयर-लिंकिंग उन शहरी सहकारी बैंकों के विवेकानुसार होगी जो सांविधिक निरीक्षण के दौरान आरबीआई द्वारा किए गए आकलन के अनुसार नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और अंतिम सीआरएआर के अनुसार 9 प्रतिशत के न्यूनतम विनियामक सीआरएआर मानदंड और 5.5 प्रतिशत के टियर 1 सीआरएआर मानदंडों को पूरा करते हैं।

राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड (NUCFDC) - यूसीबी के लिए छत्र संगठन

भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ टाइप-II एनबीएफसी-एनडी के रूप में पंजीकृत एनयूसीएफडीसी को यूसीबी के लिए एक छत्र संगठन के साथ-साथ शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र (आगे बढ़ते हुए) के लिए स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) के रूप में कार्य करने के लिए आरबीआई द्वारा जमाएं स्वीकार न करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है। यह दोहरी भूमिका एनयूसीएफडीसी को वित्तीय सहायता प्रदान करने और इस क्षेत्र के लिए कुछ विनियम स्थापित करने के लिए सशक्त बनाएगी, जिससे सकारात्मक बदलाव आएगा। एनयूसीएफडीसी का मिशन आपसी समर्थन को बढ़ावा देना और यूसीबी को उनके विकास, शासन में संरक्षित करना, उनकी आईटी क्षमताओं को बढ़ाना और प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों का सामना करने और राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान करने की क्षमता पैदा करना है।

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में मुख्य जोखिम अधिकारी की नियुक्ति

सहकारी क्षेत्र में बढ़ती जटिलताओं और उनके आकार और व्यवसाय के दायरे में वृद्धि के साथ, यूसीबी अपने परिचालन में विविध और अत्यधिक जोखिम का सामना करते हैं। तदनुसार, ₹5,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक की संपत्ति वाले यूसीबी को जून 2021 में एक मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त करने के लिए सूचित किया गया है। उन्हें निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति गठित करने के लिए भी सूचित किया गया ताकि जोखिम प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर अपेक्षित स्तर का ध्यान दिया जा सके।

यूसीबी का पर्यवेक्षण

यह सुनिश्चित करने के लिए कि शहरी सहकारी बैंक ठोस लाइनों पर कार्य करते हैं और उनके परिचालन के तरीके सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप हैं और जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक नहीं हैं, वे (i) ऑन-साइट निरीक्षण और (ii) ऑफ-साइट निगरानी दोनों के अधीन हैं।

- 1) **ऑन-साइट निरीक्षण:** बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 के तहत किए गए सांविधिक निरीक्षण में यूसीबी की पूंजी पर्याप्तता (सी), आस्ति गुणवत्ता (ए), प्रबंधन (एम), आय (ई), चलनिधि (एल)

और सिस्टम और नियंत्रण (एस) का आकलन करने के लिए कैमल्स पैटर्न का अनुसरण करते हैं। ये निरीक्षण मूल रूप से एक मुख्य मूल्यांकन करते हैं और निम्नलिखित की विशिष्ट समीक्षा करते हैं:

- अ. वित्तीय स्थिति और कार्यनिष्पादन,
 - आ. निदेशक मंडल और प्रबंधन का शासन और निरीक्षण, प्रणालियों और नियंत्रणों और नियामक और अन्य दिशानिर्देशों का अनुपालन।
 - इ. जोखिम मूल्यांकन जो बैंकों के व्यापार मॉडल, प्रबंधन, ऋण, चलनिधि, बाज़ार, परिचालनात्मक और प्रणालियों और नियंत्रणों में निहित है।
- २) **ऑफ-साइट निगरानी:** यूसीबी पर निरंतर पर्यवेक्षण करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने आवधिक विवेकपूर्ण विवरणियों के एक सेट के माध्यम से ऑफ-साइट निगरानी (ओएसएस) के साथ आवधिक ऑन-साइट निरीक्षण की प्रणाली की व्यवस्था की है जिसे यूसीबी द्वारा आरबीआई को प्रस्तुत किया जाएगा। इन विवरणियों का विश्लेषण भारतीय रिज़र्व बैंक में प्रारंभिक संकेतकों की पहचान करने के लिए किया जाता है जो बैंकों के स्वास्थ्य में गिरावट ला सकते हैं। कभी-कभी, विश्लेषण निर्धारित होने से पहले निरीक्षण के लिए यूसीबी लेने के लिए एक ट्रिगर के रूप में भी कार्य कर सकता है।

त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) ढांचा

प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के लिए मौजूदा पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे (एसएएफ) की समीक्षा यूसीबी के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचे (पीसीए) पर डीओएस, केंद्रीय कार्यालय परिपत्र दिनांक 26 जुलाई 2024 के माध्यम से की गई है। पीसीए ढांचा सभी समावेशी निदेशों के तहत होने वाले यूसीबी को छोड़कर टियर 2, टियर 3 और टियर 4 श्रेणियों के तहत होने वाले सभी यूसीबी पर लागू होगा। टियर-1 यूसीबी, हालांकि अभी पीसीए फ्रेमवर्क के तहत कवर नहीं किए गए हैं, वर्तमान पर्यवेक्षी ढांचे के तहत बड़ी हुई निगरानी के अधीन होंगे। पीसीए ढांचे से टियर 1 यूसीबी की छूट की यथासमय समीक्षा की जाएगी।

पीसीए ढांचे का उद्देश्य उचित समय पर पर्यवेक्षी हस्तक्षेप को सक्षम करना है और यूसीबी से समय पर ढंग से उपचारात्मक उपायों को शुरू करने और कार्यान्वित करने की अपेक्षा करना है, ताकि उनकी वित्तीय स्थिति बहाल हो सके। पीसीए ढांचा भारतीय रिज़र्व बैंक को ढांचे में निर्धारित सुधारात्मक कार्रवाइयों के अलावा किसी भी समय उचित समझे जाने वाले किसी अन्य कार्रवाई करने से नहीं रोकता है। पीसीए ढांचा के प्रावधान 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगे। संशोधित पीसीए ढांचे में निगरानी के लिए पूंजी, परिसंपत्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता प्रमुख क्षेत्र होंगे। पूंजी, आस्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता के लिए ट्रैक किए जाने वाले संकेतक क्रमशः सीआरएआर, निवल एनपीए अनुपात (निवल अग्रिमों के प्रति निवल एनपीए का प्रतिशत) और निवल लाभ होंगे। किसी भी जोखिम सीमा (जैसा कि नीचे विस्तृत है) के उल्लंघन के परिणामस्वरूप पीसीए का आह्वान किया जा सकता है।

PCA matrix – Parameters, Indicators and Risk Thresholds				
Parameter	Indicator	Risk Threshold 1	Risk Threshold 2	Risk Threshold 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Capital (Breach of CRAR)²	CRAR – Minimum Regulatory Requirement, as applicable*	Up to 250 bps below the Indicator prescribed at column (2)	More than 250 bps but not exceeding 400 bps below the Indicator prescribed at column (2)	In excess of 400 bps below the Indicator prescribed at column (2)
Asset Quality	Net Performing Advances (NPA) Ratio	>=6.0% but <9.0%	>=9.0% but <12.0%	>=12.0%
Profitability	Net profit	Incurred losses during two consecutive years	--	--
* For Tier 2 to 4 UCBs as per the glide path provided for achieving the regulatory minimum CRAR of 12% by March 31, 2026.				

किसी बैंक को सामान्यतः रिपोर्ट की गई / लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय परिणामों और/अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए चालू पर्यवेक्षी मूल्यांकन के आधार पर पीसीए ढांचे के अंतर्गत रखा जाएगा। तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक वर्ष के दौरान कभी भी (एक सीमा से दूसरी सीमा में श्रेणी अंतरण सहित) यदि परिस्थितियां ऐसी हों, किसी भी बैंक पर पीसीए लगा सकता है। हालांकि की गई पर्यवेक्षी कार्रवाई मुख्य रूप से पीसीए ढांचे के तहत निर्दिष्ट मानदंडों पर आधारित होगी, फिर भी अन्य महत्वपूर्ण सूचकों / मापदंडों में दबाव या गंभीर शासन मुद्दों के मामले में रिज़र्व बैंक को उचित पर्यवेक्षी कार्रवाई करने से नहीं रोका जाएगा। साथ ही, रिज़र्व बैंक को प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर इस परिपत्र में दर्शाए गए कार्यों के अलावा कोई पर्यवेक्षी कार्रवाई करने से नहीं रोका जाएगा।

पीसीए से बाहर निकलना और पीसीए के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को वापस लेना - एक बार जब किसी बैंक को पीसीए के तहत रखा जाता है, तो बैंक को पीसीए ढांचे से बाहर निकालने और/या पीसीए ढांचे के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को वापस लेने पर तब विचार किया जाएगा: जब ए) यदि चार निरंतर तिमाही वित्तीय विवरणों के अनुसार किसी भी पैरामीटर में जोखिम सीमा में कोई उल्लंघन नहीं देखा जाता है, जिनमें से एक लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण होना चाहिए (आरबीआई द्वारा मूल्यांकन के अधीन); और बी) आरबीआई के पर्यवेक्षी सुविधा के आधार पर, जिसमें बैंक के प्रमुख वित्तीय पत्रकों में सतत सुधार पर एक आकलन शामिल है।

समझौता निपटान और तकनीकी बट्टे खाते डालने के लिए रूपरेखा

वर्तमान विनियमों के अनुसार, ऋणदात्री संस्थाओं के ऋण संबंधी वसूली मामले अधिकांशतः अविनियमित हैं। ऐसे वसूली उपाय या तो उधारकर्ताओं के खातों में दबाव के समाधान के माध्यम से विभिन्न सांविधिक अथवा न्यायालय से बाहर तंत्रों के माध्यम से हो सकते हैं अथवा ये समझौते निपटान के माध्यम से हो सकते हैं। जबकि समझौता निपटान करने/बट्टे खाते डालने के संबंध में वाणिज्यिक बैंकों और एनबीएफसी को कतिपय विनियम जारी किए गए थे, सहकारी बैंकों के मामले में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने समझौता निपटान के संबंध में दिशानिर्देश जारी नहीं किए थे, क्योंकि संबंधित राज्य संविधियों में सहकारी बैंकों को देय किसी ऋण/देयता को माफ करने के लिए सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (आरसीएस) की अनुमति अपेक्षित है।

इसलिए, समझौता निपटान और सभी विनियमित संस्थाओं (यूसीबी, राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों सहित) को कवर करने वाले ऋणों के तकनीकी बट्टे खाते डालने को नियंत्रित करने वाला एक व्यापक नियामक ढांचा 08 जून 2023

को जारी किया गया था। इस ढांचे में अन्य बातों के साथ-साथ त्याग/माफी पर विचार करने से पूर्व विचार किए जाने वाले कारक, अनुमत त्याग/माफी के मानदंड, शक्तियों का प्रत्यायोजन, विवेकपूर्ण व्यवहार, रिपोर्टिंग तंत्र, बोर्ड द्वारा निगरानी, कूलिंग अवधि, धोखाधड़ी और इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत खातों का उपचार शामिल है।

मानक आस्तियों के लिए प्रावधान

24 अप्रैल 2023 को रिज़र्व बैंक ने यूसीबी की सभी श्रेणियों पर लागू 'मानक' आस्तियों के लिए प्रावधान मानदंडों को सुसंगत बनाया, चाहे संशोधित ढांचे में उनका स्तर कुछ भी हो। कृषि तथा लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई) क्षेत्रों को प्रत्यक्ष अग्रिम के लिए 0.25 प्रतिशत की एक समान प्रावधानीकरण आवश्यकता होती है, जबकि वाणिज्यिक स्थावर संपदा (सीआरई) क्षेत्र, वाणिज्यिक रियल एस्टेट -आवासीय हाउसिंग (सीआरई-आरएच) और अन्य सभी मानक अग्रिमों के लिए प्रावधानीकरण की आवश्यकता क्रमशः 1.00 प्रतिशत, 0.75 प्रतिशत और 0.40 प्रतिशत है। टियर 1 यूसीबी, जो "अन्य सभी मानक अग्रिमों" पर 0.25 प्रतिशत प्रावधान बनाए हुए थे, को 31 मार्च 2025 तक सांतरित तरीके से 0.40 प्रतिशत की आवश्यकता को प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी।

यूसीबी में साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए नियामक उपाय

अक्टूबर 2018 में यूसीबी के लिए आधारभूत साइबर सुरक्षा नियंत्रण का एक सेट निर्धारित किया गया था। इसके बाद, यूसीबी के सूचना प्रौद्योगिकी परिपक्वता स्तर के विभिन्न स्तरों पर विचार करते हुए, एक साइबर सुरक्षा ढांचे को निर्धारित करने की आवश्यकता महसूस की गई जो यूसीबी द्वारा डिजिटल उत्पाद पेशकशों की प्रकृति, विविधता और पैमाने के आधार पर उत्तरोत्तर मजबूत सुरक्षा और आईटी / साइबर शासन उपायों के कार्यान्वयन को अधिदेशित करेगा। यूसीबी को अपनी साइबर सुरक्षा तैयारियों को बढ़ाने में मदद करने के लिए श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण अपनाने की मांग की गई थी और यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि साइबर सुरक्षा खतरों को दूर करने में भुगतान सेवाओं और उच्च सूचना प्रौद्योगिकी पैठ की एक श्रृंखला की पेशकश करने वाले यूसीबी वाणिज्यिक बैंकों के बराबर लाए जाते हैं।

तदनुसार, 31 दिसंबर 2019 को एक व्यापक साइबर सुरक्षा ढांचा जारी किया गया था। ढांचे ने यूसीबी को उनकी डिजिटल गहराई और भुगतान प्रणाली परिदृश्य के परस्पर संबंध के आधार पर चार स्तरों में वर्गीकृत किया। इसके अलावा, यूसीबी और प्रायोजक बैंकों के बीच भुगतान पारिस्थितिकी, साइबर सुरक्षा पर निदेशक मंडल की निगरानी, बैंक विशिष्ट ईमेल डोमेन में अंतरण, रैसमवेयर खतरों को कम करने आदि को कवर करने वाले यूसीबी के लिए कई नियंत्रण निर्धारित किए गए हैं।

साइबर सुरक्षा के लिए आरबीआई की पर्यवेक्षी रणनीति

ऑफसाइट समीक्षा के भाग के रूप में, एक घटना रिपोर्टिंग तंत्र स्थापित किया गया है, जिसमें यूसीबी और अन्य पर्यवेक्षित संस्थाओं (एसई) को आरबीआई को असामान्य साइबर घटनाओं की रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। यदि रिपोर्ट की गई घटनाओं को प्रणालीगत निहितार्थ माना जाता है, तो उनका विश्लेषण किया जाता है, और कार्यप्रणाली को सलाह और अलर्ट के माध्यम से अन्य एसई को सूचित किया जाता है, जिससे उन्हें समय पर निवारक या सुधारात्मक उपाय करने में सक्षम बनाया जाता है।

यूसीबी की ऑनसाइट परीक्षा के भाग के रूप में, चयनित यूसीबी ऑनसाइट आईटी परीक्षा (आईटीई) से गुजरते हैं, जो मुख्य

रूप से यूसीबी के लिए आरबीआई द्वारा स्थापित साइबर सुरक्षा ढांचे के अनुपालन को सत्यापित करने पर केंद्रित है।

ग्रामीण सहकारी समितियां

ग्रामीण ऋण सहकारी समितियां अनिवार्य रूप से किसानों को सस्ती लागत पर ऋण प्रदान करने और ग्रामीण ऋणग्रस्तता और गरीबी के दोहरे मुद्दों को हल करने के लिए एक संस्थागत तंत्र के रूप में अस्तित्व में आईं। आउटरीच और कारोबार की मात्रा में अपनी अभूतपूर्व वृद्धि के साथ, ग्रामीण ऋण वितरण प्रणाली में ग्रामीण ऋण सहकारी समितियों की एक अद्वितीय स्थिति है। अल्पकालिक और दीर्घकालिक संरचनाओं के माध्यम से, वे उत्पादकता बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा प्रदान करने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने और गरीबों और कमजोर लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए ऋण के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहते हैं।

- **दीर्घावधि सहकारी ऋण ढांचे** में शीर्ष स्तर पर राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीबी) और जिला अथवा ब्लॉक स्तर पर प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी) होते हैं। इन संस्थाओं की संकल्पना कृषि में दीर्घावधिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से की गई थी और ये भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियामक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं।
- देश की **अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना** (एसटीसीसीएस) मुख्य रूप से किसानों और ग्रामीण कारीगरों की फसल और कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करती है। एसटीसीसीएस का पिरामिड मुख्य रूप से 3-स्तरीय है और एक राज्य के भीतर प्रकृति में संघीय है।

शीर्ष स्तर पर राज्य सहकारी बैंक (StCB) है, जिला स्तर पर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCB) हैं और ग्राम स्तर पर, प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS) हैं। पूरे भारत में, 95000 से अधिक पैक्स हैं। वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमन के अधीन नहीं हैं, क्योंकि वे 1949 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम के दायरे से बाहर हैं। उनका विनियमन और निगरानी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। जबकि राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) का विनियमन रिज़र्व बैंक में निहित है, उनका पर्यवेक्षण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35(6) के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा किया जाता है। राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के विनियमन के भाग के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक पूंजी पर्याप्तता, आय पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंड, एक्सपोज़र मानदंड आदि पर विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित करने के अलावा सीआरआर और एसएलआर अपेक्षा निर्धारित करता है।

ग्रामीण सहकारी समितियों का विनियमन

बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 39) को राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 23 दिसंबर 2020 की अधिसूचना के माध्यम से 1 अप्रैल 2021 से अधिसूचित किया गया है। अधिसूचना जारी होने के साथ, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44-ए के प्रावधानों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सहकारी बैंकों के साथ डीसीसीबी के सम्मेलन को मंजूरी दी जानी है। इस अधिसूचना के अनुसरण में, जिला सहकारी बैंकों को बीआर अधिनियम, 1949 की

धारा 56 के साथ पठित धारा 23 के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही कारोबार के नए स्थान खोलने/एटीएम स्थापित करने या ऐसे कार्यालयों के स्थान को स्थानांतरित करने की अनुमति है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आरसीबी को मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग सुविधा जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान करने, बीमा उत्पादों का वितरण करने, पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के लिए प्वाइंट ऑफ प्रेज़न्स सेवाएं देने, प्रीपेड लिखत और प्वाइंट ऑफ सर्विस (पीओएस) टर्मिनल (कार्ड के लिए) जारी करने और क्रेडिट कार्डों आदि के लिए सह-ब्रांडिंग भागीदार के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है।

निष्कर्ष

सहकारी बैंक अपनी विशिष्ट संरचना, ग्राहक और क्रेडिट वितरण के दृष्टिकोण के कारण आरबीआई के पर्यवेक्षी-परिधि के बाहर हैं। वे भारत की बैंकिंग प्रणाली में मूलभूत संस्थानों के रूप में कार्य करते हैं, जो शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में मध्यम और निम्न-आय वाले समूहों को आवश्यक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान उनके लचीलेपन और स्थिरता ने विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं दोनों की वित्तीय प्रणालियों के भीतर अपने महत्व को उजागर किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत और एकीकृत करने के लिए विभिन्न नीतिगत पहलों को लागू किया है और भविष्य में इन प्रयासों को बनाए रखेगा।

अध्याय 10 - भारत में एनबीएफसी का विनियमन और पर्यवेक्षण

भारत में ऐसी वित्तीय संस्थाएँ हैं, जो बैंक नहीं हैं, लेकिन बैंक जैसे कार्य करती हैं, खास तौर पर धन जुटाने और ऋण देने की वित्तीय मध्यस्थता में। ये गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी) हैं और वे अंतिम मील क्रेडिट मध्यस्थता प्रदान करके वित्तीय प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जबकि बैंकों बैंकों द्वारा सेवा न दिए जाने वाले क्षेत्रों की ज़रूरतों को पूरा करके जोखिमों को अवशोषित और विविधता प्रदान करती हैं और अभिनव वित्तीय उत्पादों का लाने में अग्रणी भूमिका निभाती हैं। इन संस्थाओं को विनियमित करने की चुनौती इस क्षेत्र की नवीनता और गतिशीलता को बनाए रखने के साथ-साथ इसके लचीलेपन को बढ़ावा देने के बीच एक अच्छा संतुलन बनाए रखना है। उनकी बड़ी संख्या (9,000 से अधिक) और विविधता के कारण उनका पर्यवेक्षण एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन जाता है जिसमें ऑनसाइट पर्यवेक्षण को ऑफसाइट निगरानी, बाजार आसूचना, वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और हितधारक के साथ बातचीत के द्वारा सुदृढ़ करने की आवश्यकता होती है। यह अध्याय एनबीएफसी की परिभाषा पर गहनता से विचार करके, क्षेत्र की विविधता को स्पष्ट करके तथा विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचे का अवलोकन देकर एनबीएफसी क्षेत्र के बारे में जानकारी देने का प्रयास करता है।

एनबीएफसी की परिभाषा

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 ('आरबीआई अधिनियम') की धारा आई (एफ) के तहत एनबीएफसी को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

- एक वित्तीय संस्थान, जो एक कंपनी है;
- एक गैर-बैंकिंग संस्थान जो एक कंपनी है, और जिसका मुख्य कारोबार किसी भी योजना या व्यवस्था के तहत या किसी अन्य तरीके से जमा प्राप्त करना या किसी भी तरीके से ऋण प्रदान करना है;
- ऐसी अन्य गैर-बैंकिंग संस्था या ऐसी संस्थाओं की श्रेणी, जो बैंक केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से और सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।

इस प्रकार, मोटे तौर पर एक 'वित्तीय संस्थान' जो एक कंपनी है, एक एनबीएफसी है। संक्षेप में, वित्तीय संस्थान का अर्थ है कोई भी गैर-बैंकिंग संस्थान जो अपने कारोबार (या अपने कारोबार के हिस्से) के रूप में निम्नलिखित में से कोई भी गतिविधि ('वित्तीय गतिविधियाँ') करता है:

- अपनी गतिविधियों के अलावा अन्य गतिविधियों के लिए ऋण देना या वित्तपोषण करना
- सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए शेयर/स्टॉक/बॉन्ड/डिबेंचर/प्रतिभूतियों या इसी तरह की प्रकृति की अन्य विपणन योग्य प्रतिभूतियों का अधिग्रहण।
- पट्टे पर देना या किराया-खरीद
- बीमा कारोबार
- चिट का कारोबार
- धन संग्रह

लेकिन इसमें कोई भी संस्था शामिल नहीं है, जो इनमें अपना प्रमुख कारोबार करती है

- कृषि परिचालन
- औद्योगिक गतिविधि
- किसी भी सामान की खरीद या बिक्री (प्रतिभूतियों के अलावा)
- कोई भी सेवा प्रदान करना और
- अचल संपत्ति की बिक्री/खरीद/निर्माण

कभी-कभी, गैर-बैंकिंग संस्थान जो वित्तीय संस्थान की गतिविधियों को संचालित नहीं करते हैं, उन्हें अभी भी एनबीएफसी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। उन्हें राजपत्र में एक अधिसूचना के माध्यम से एनबीएफसी के रूप में नामित किया गया है, जैसा कि एनबीएफसी-अकाउंट एग्रीगेटर्स और एनबीएफसी-पीयर-टू-पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म के मामले में¹⁹ है, जैसा कि बाद में स्पष्ट किया गया है। एक अन्य पहलू यह है कि एनबीएफसी के रूप में वर्गीकृत होने के लिए कंपनी को वित्तीय गतिविधियों में पूरी तरह से शामिल होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसे इस उद्देश्य के लिए प्रमुख कारोबारी मानदंडों को पूरा करना होगा। इसके अलावा, गैर-बैंकिंग संस्थान जो अपने प्रमुख व्यवसाय के रूप में गैर-वित्तीय गतिविधियों जैसे कृषि, औद्योगिक गतिविधि, वस्तुओं का व्यापार आदि करता है, उसे वित्तीय संस्थान के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। मुद्रा यह है कि कोई प्रमुख कारोबार को कैसे परिभाषित करता है।

प्रमुख कारोबारी मानदंड (पीबीसी)

जैसा कि ऊपर बताया गया है, केवल वह कंपनी जो एक वित्तीय संस्थान ('वित्तीय गतिविधि') का कारोबार अपने प्रमुख कारोबार के रूप में करती है, उसे एनबीएफसी कहा जा सकता है। दूसरी ओर, यदि कोई कंपनी कृषि, विनिर्माण, वस्तुओं का व्यापार आदि अपनी प्रमुख गतिविधि के रूप में करती है, तो इसे एनबीएफसी नहीं कहा जा सकता है, भले ही वह कुछ वित्तीय गतिविधि करती हो। "प्रमुख कारोबार" शब्द को आरबीआई अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। इसलिए, 'प्रमुख कारोबार' शब्द की व्याख्या को स्पष्टता और स्थिरता देने के लिए, बैंक ने 8 अप्रैल 1999 की अपनी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से इस शब्द की व्याख्या की। इस प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कंपनी को एनबीएफसी के रूप में पहचान स्थापित करने के लिए, बैंक उसे प्रमुख कारोबार को तय करने लेने के लिए कंपनी की अंतिम लेखा परीक्षित की गई तुलन पत्र में प्रमाणित परिसंपत्तियों और आय के पैटर्न दोनों पर विचार करेगा। एक कंपनी को एनबीएफसी के रूप में तब माना जाता है, अगर उसकी वित्तीय परिसंपत्तियाँ²⁰ उसकी कुल परिसंपत्तियों (अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा नेटऑफ) के 50 प्रतिशत (सावधि जमा को छोड़कर) से अधिक हैं और वित्तीय परिसंपत्तियों से आय सकल आय के 50 प्रतिशत से अधिक है। किसी कंपनी के प्रमुख कारोबार के लिए निर्धारक कारक के रूप में इन दोनों शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। यदि कोई कंपनी प्रमुख कारोबारी मानदंड को पूरा करती है, तो वह एक एनबीएफसी है और उसके लिए आरबीआई के साथ पंजीकृत होना

¹⁹ आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-1 (f) (iii) के तहत केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ आरबीआई द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित

²⁰ 15 मार्च, 2012 के परिपत्र के अनुसार, यह स्पष्ट किया गया था कि सावधि जमा में निवेश को वित्तीय परिसंपत्ति नहीं माना जाएगा और बैंकों के पास सावधि जमा पर ब्याज आय को वित्तीय परिसंपत्तियों से आय नहीं माना जाएगा क्योंकि ये आरबीआई अधिनियम की धारा 45-आई (सी) में "वित्तीय संस्थान" की परिभाषा में उल्लिखित गतिविधियों के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसके अलावा, बैंक जमा निकट मुद्रा है और इसका प्रयोग केवल निष्क्रिय निधियों की अस्थायी पार्किंग के लिए किया जा सकता है, और/या उन मामलों में जहां एनबीएफआई व्यवसाय शुरू होने तक एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शुरू में सावधि जमा के रूप में निधियों को रखा जाता है।

आवश्यक है जब तक कि विशेष रूप से ऐसा करने से छूट न दी गई हो।

क्या एनबीएफसी शैडो बैंक हैं?

नवंबर 2010 में शैडो बैंकिंग की निगरानी और विनियमन को मजबूत करने के लिए समूह 20 (जी 20) के नेताओं के अनुरोध के जवाब में, वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) ने²¹ शैडो बैंकिंग को "नियमित बैंकिंग प्रणाली के बाहर संस्थाओं और गतिविधियों (पूरी तरह या आंशिक रूप से) को शामिल करने वाली क्रेडिट मध्यस्थता" के रूप में परिभाषित किया और शैडो बैंकिंग से वित्तीय स्थिरता जोखिमों को दूर करने के लिए दो-आयामी रणनीति अपनाई, जिसमें एक प्रणाली-व्यापी निरीक्षण ढांचा और ऐसे जोखिमों को दूर करने के लिए नीतियों का समन्वय और विकास शामिल है। हालांकि, 22 अक्टूबर, 2018 को, एफएसबी ने भविष्य के संप्रेषणों में "गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता" (एनबीएफआई) शब्द के साथ "शैडो बैंकिंग" शब्द को बदलने के अपने फैसले की घोषणा की। शब्दावली में इस बदलाव का उद्देश्य गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता के लचीलेपन को बढ़ाने और तकनीकी शब्दों के उपयोग को स्पष्ट करने के लिए एफएसबी के काम के दूरगामी पहलू पर जोर देना है। हर साल एफएसबी गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता पर एक वैश्विक निगरानी रिपोर्ट प्रकाशित करता है। 18 दिसंबर, 2023 की रिपोर्ट में निम्नलिखित निगरानी ऐग्रेगिट्स का उपयोग किया गया है:

- (1) एनबीएफआई (गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता सभी गैर-बैंक वित्तीय संस्थाओं का एक व्यापक उपाय है, जो सभी वित्तीय संस्थानों से बना है जो केंद्रीय बैंक, बैंक या सार्वजनिक वित्तीय संस्थान नहीं हैं।
- (2) ओएफआई (अन्य वित्तीय मध्यस्थ) एनबीएफआई क्षेत्र का एक सबसेट है, जो उन सभी वित्तीय संस्थानों से बना है जो केंद्रीय बैंक, बैंक, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान, बीमा निगम (आईसी), पेंशन फंड (पीएफ), या वित्तीय सहायक नहीं हैं।
- (3) गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता (या "संकीर्ण उपाय") का संकीर्ण माप एनबीएफआई संस्थाओं से बना है जिन्हें अधिकारियों ने क्रेडिट मध्यस्थता गतिविधियों में शामिल होने के रूप में मूल्यांकन किया है जो बैंक की तरह वित्तीय स्थिरता जोखिम (यानी, क्रेडिट मध्यस्थता जिसमें परिपक्वता / तरलता परिवर्तन, उत्तोलन या अपूर्ण क्रेडिट जोखिम हस्तांतरण शामिल है) और/या विनियामक मध्यस्थता उत्पन्न कर सकते हैं जो कि एफएसबी के वार्षिक एनबीएफआई निगरानी अभ्यास में उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली और वर्गीकरण मार्गदर्शन के अनुसार है।

²¹ वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB) एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है जो वैश्विक वित्तीय प्रणाली की निगरानी करता है और उसके बारे में सिफारिशें करता है। इसकी स्थापना वित्तीय स्थिरता फोरम (एफएसएफ) के उत्तराधिकारी के रूप में अप्रैल 2009 में 2009 जी20 लंदन शिखर सम्मेलन के बाद की गई थी। बोर्ड में भारत, एफएसएफ सदस्य और यूरोपीय आयोग सहित सभी जी20 की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ शामिल हैं। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के बेसल में है।

भारतीय रिजर्व बैंक विनियमन से छूट

जैसा कि आरबीआई अधिनियम में एनबीएफसी की परिभाषा से देखा जा सकता है, यहां तक कि बीमा कंपनियां और स्टॉक ब्रोकिंग कंपनियां जैसी संस्थाएं भी एनबीएफसी हैं। तथापि, इन संस्थाओं को उनके सांविधिक कार्य के भाग के रूप में अन्य विनियामकों द्वारा विनियमित किया जाता है। इसलिए, दोहरे विनियमन से बचने के लिए, आरबीआई ने एनबीएफसी की विभिन्न श्रेणियों को छूट दी है जो पंजीकरण और / या अन्य आवश्यकताओं से अन्य नियामकों / सरकार द्वारा विनियमित हैं। नीचे दी गई तालिका विभिन्न छूट प्राप्त श्रेणियों और उनके विनियामकों को सूचीबद्ध करती है।

एनबीएफसी के प्रकार / गतिविधियाँ	द्वारा विनियमित
वैकल्पिक निवेश कोष कंपनियां, मर्चेन्ट बैंकिंग कंपनियां, स्टॉक ब्रोकिंग या सब-ब्रोकिंग कंपनियां, स्टॉक एक्सचेंज	भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी)
बीमा कंपनियां	बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए)
म्यूचुअल बेनिफिट कंपनियां, निधि कंपनियां	कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय (एमसीए)
चिट कंपनियां	राज्य सरकारें

एनबीएफसी के प्रकार

मोटे तौर पर, एनबीएफसी को निम्नलिखित तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है:

- सार्वजनिक निधियों की स्वीकृति और ग्राहक इंटरफेस के आधार पर
- जमा राशियों की स्वीकृति, आकार और अन्य कारकों के आधार पर
- गतिविधि के आधार पर इसका विनियामक ढांचा

सार्वजनिक निधियों की स्वीकृति और ग्राहक इंटरफेस के आधार पर

निधियों को जमाराशि के तौर पर स्वीकार करने वाले एनबीएफसी (एनबीएफसी-डी) के पंजीकरण के लिए आवेदनों पर 1997 से विचार नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा, जून 2016 में, आरबीआई ने नए एनबीएफसी के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल और तर्कसंगत बनाने के लिए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। निधियों को जमाराशि के तौर पर स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी) के संबंध में, निधियों के स्रोतों और ग्राहक इंटरफेस के आधार पर दो प्रकार के आवेदन हैं।

- **टाइप I** - एनबीएफसी-एनडी सार्वजनिक निधियों को जमाराशि के तौर पर स्वीकार नहीं करते हैं। भविष्य में सार्वजनिक निधियों को जमाराशि के तौर पर स्वीकार करने और ग्राहक इंटरफेस रखने का इरादा नहीं रखते हैं। "सार्वजनिक निधि" शब्द में सार्वजनिक जमाराशियां, वाणिज्यिक पत्र, डिबेंचर, अंतर-कॉर्पोरेट जमाराशियां और बैंक

वित्त के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुटाई गई निधियां शामिल होंगी, लेकिन इसमें जारी होने की तारीख से 10 वर्ष से अनधिक अवधि के भीतर अनिवार्य रूप से इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय लिखतों के निर्गम द्वारा जुटाई गई निधियां शामिल नहीं हैं। टाइपा-एनबीएफसी-एनडी आवेदकों के लिए मामलों की प्रोसेसिंग कम गहन जांच और सम्यक जांच के अधीन है। हालांकि, अगर ये कंपनियां भविष्य में सार्वजनिक निधियों या ग्राहक संपर्क का लाभ उठाने का इरादा रखती हैं तो उन्हें विनियमन विभाग (डीओआर) से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

- **टाइप II** - एनबीएफसी-एनडी सार्वजनिक निधियों को जमाराशियों के तौर पर स्वीकार करने वाली /भविष्य में सार्वजनिक निधियों को जमाराशियों के तौर पर स्वीकार करने का इरादा रखने वाली और/या ग्राहक इंटरफेस/भविष्य में ग्राहक इंटरफेस रखने का इरादा रखना वाली।

यहां तक कि विनियामक ढांचा उन कंपनियों के लिए कुछ छूट प्रदान करता है जो सार्वजनिक निधियों को जमाराशियों के तौर पर स्वीकार नहीं करते हैं और / या ग्राहक इंटरफेस रखते हैं।

जमा राशियों को स्वीकार करने, आकार और अन्य कारकों के आधार पर

निधियों को जमाराशियों के तौर पर न लेने वाली एनबीएफसी को बेस लेयर एनबीएफसी (एनबीएफसी-बीएल) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यदि उनकी संपत्ति का आकार ₹1000 करोड़ से कम है। जमाराशियों को स्वीकार न करने वाले ₹ 1000 करोड़ और उससे अधिक की परिसंपत्ति आकार वाले वाली एनबीएफसी को मिडिल लेयर एनबीएफसी (एनबीएफसी-ML) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके बावजूद, गतिविधि के आधार पर, एनबीएफसी को बेस या मिडिल लेयर में हो सकते हैं, भले ही उनकी परिसंपत्ति का आकार कुछ भी हो। सार्वजनिक जमाराशियों के प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए, जमाराशियों को स्वीकार करने वाली एनबीएफसी (यानी, एनबीएफसी-डी) को उनके आकार पर ध्यान दिए बिना कम से कम मध्य स्तर में वर्गीकृत किया जाता है। दरअसल, एनबीएफसी-डी के लिए कुछ नियम जमाराशियों को स्वीकार न करने वाले एनबीएफसी की तुलना में कड़े हैं। शीर्ष दस पात्र एनबीएफसी को उनके परिसंपत्ति आकार के संदर्भ में अपर लेयर एनबीएफसी (एनबीएफसी-यूएल) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। अपर लेयर में वे पात्र एनबीएफसी भी शामिल होंगे जिन्हें विशेष रूप से बैंक द्वारा मापदंडों और स्कोरिंग पद्धति के एक सेट के आधार पर चिह्नित किया गया है। अगली श्रेणी अर्थात्, टॉप लेयर (एनबीएफसी-टीएल) आदर्श रूप से शून्य होने की उम्मीद है और इसमें बढ़ोतरी हो सकती है यदि बैंक की राय बनती है कि विशिष्ट एनबीएफसी-यूएल से संभावित प्रणालीगत जोखिम में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

गतिविधि के आधार पर

एनबीएफसी की गतिविधियों में विषमताएं हैं। जबकि कुछ मुख्य रूप से सूक्ष्म वित्त में संलग्न हैं और समाज के वंचित वर्गों से कारोबार करते हैं, अन्य दीर्घकालिक परियोजना और बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण में विशेषज्ञ हैं। नतीजतन, 'सभी के लिए उपयुक्त एक जैसा' विनियामक ढांचा बनाना मुश्किल है और एनबीएफसी को उनकी प्रमुख गतिविधियों के आधार पर वर्गीकृत करने की आवश्यकता है। यह विनियामक ढांचे को जटिल बनाता है और विनियमों को सुसंगत बनाने और श्रेणियों की संख्या को कम करने के प्रयास किए गए हैं। आज संख्या के हिसाब से 96 प्रतिशत से अधिक एनबीएफसी एनबीएफसी-निवेश और क्रेडिट श्रेणी (एनबीएफसी-आईसीसी) के अंतर्गत आते हैं, जिसे नीचे समझाया गया है।

क्र. स.	एनबीएफसी का प्रकार	गतिविधि की प्रकृति	प्रमुख योग्यता मानदंड
1.	एनबीएफसी-निवेश और क्रेडिट कंपनी (एनबीएफसी-आईसीसी)	(1) ऋण देना (पूर्ववर्ती ऋण कंपनियां) (2) ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर और जनरेटर (पूर्ववर्ती परिसंपत्ति वित्त कंपनियों) सहित भौतिक परिसंपत्तियों का वित्तपोषण (3) प्रतिभूतियों का अधिग्रहण (पूर्व में निवेश कंपनियां) इसमें गोल्ड लोन कंपनियां शामिल हैं जो एनबीएफसी मुख्य रूप से सोने के आभूषणों के बदले उधार देने में लगी हुई हैं (यानी, वित्तीय परिसंपत्तियों का 50 प्रतिशत या अधिक)	किसी अन्य श्रेणी में होने के योग्य नहीं है (या पंजीकृत नहीं किया गया है)
2.	एनबीएफसी-इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (एनबीएफसी-आईएफसी)	बुनियादी ढांचे के विकास के लिए दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना	बुनियादी ढांचा ऋण कुल संपत्ति का कम से कम 75 प्रतिशत होना चाहिए।
3.	कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी)	समूह कंपनियों में निवेश/ऋण देना	(1) समूह की कंपनियों को निवेश और ऋण के लिए शुद्ध परिसंपत्तियों का कम से कम 90 प्रतिशत और शुद्ध परिसंपत्तियों का 60 प्रतिशत इक्विटी और समूह कंपनियों के समान निवेश में होना चाहिए। (2) ब्लॉक बिक्री के माध्यम से विलयन /विनिवेश के सिवाय समूह कंपनियों के शेयरों, बांडों, डिबेंचरों, ऋण/ऋणों में अपने निवेश में ट्रेड नहीं करता है, (3) निर्दिष्ट के सिवाय कोई वित्तीय गतिविधि नहीं करता है।
4.	इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड – एनबीएफसी (आईडीएफ-एनबीएफसी)	पूर्ण ढांचागत परियोजनाओं के मौजूदा ऋण का पुनर्वित्त	(i) प्रचालन प्रारंभ होने के बाद (सीओडी) ढांचागत परियोजनाएं जिन्होंने संतोषजनक वाणिज्यिक प्रचालन का कम से कम एक वर्ष पूरा कर लिया है (ii) प्रत्यक्ष ऋणदाता के रूप में वित्त पथकर प्रचालन अंतरण (टीओटी) परियोजनाएं

5.	एनबीएफसी- माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (एनबीएफसी- एमएफआई)	छोटे उधारकर्ताओं को संपार्श्विक मुक्त ऋण	माइक्रोफाइनेंस ऋण के रूप में कुल परिसंपत्ति का कम से कम 75 प्रतिशत प्रदान करता है
6.	एनबीएफसी – कारक	फैक्टरिंग कारोबार यानी प्राप्तियों का वित्तपोषण। फैक्टरिंग अधिनियम की धारा 3 के तहत पंजीकृत	फैक्टरिंग कारोबार में वित्तीय परिसंपत्ति कुल परिसंपत्ति का कम से कम 50 प्रतिशत और वहां प्राप्त आय कुल आय का 50 प्रतिशत से कम नहीं होना।
7.	बंधक गारंटी कंपनियां (एमजीसी)	आवास ऋण के लिए बंधक गारंटी प्रदान करना	कारोबारी टर्नओवर का बंधक गारंटी कारोबार से कम से कम 90 प्रतिशत कारोबार या बंधक गारंटी कारोबार से सकल आय का कम से कम 90 प्रतिशत
8.	नॉन-ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी)	अपने प्रवर्तक/प्रवर्तक समूहों के माध्यम से निजी क्षेत्र में नए बैंक स्थापित करने के लिए	पहले आरबीआई से एक वाणिज्यिक बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करना।
9.	एनबीएफसी- अकाउंट एग्रीगेटर (एनबीएफसी-एए)	अनुबंध के तहत अपने ग्राहक की वित्तीय जानकारी (स्पष्ट सहमति के साथ) को रिट्रीव, समेकित, सुव्यवस्थित और प्रस्तुत करने की सेवा प्रदान करना	केवल खाता एग्रीगेटर सेवाएं प्रदान करना। वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों के विनियामक दायरे में आने वाली वित्तीय परिसंपत्तियों को एग्रीगेटर कर सकता है। ये एग्रीगेटर ग्राहकों के लेनदेन का समर्थित नहीं कर सकते हैं और खाता एग्रीगेशन के कारोबार को करने के लिए तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाताओं की सेवाएं नहीं ले सकते हैं।
10	एनबीएफसी- पीयर-टू-पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म (एनबीएफसी- पी2पी) [धारा 45I(f)(iii) के तहत अधिसूचित]	पी2पी लेंडिंग प्लेटफॉर्म का कारोबार करता है यानी प्लेटफॉर्म पर प्रतिभागियों को ऋण सुविधा सेवाएं प्रदान करता है।	केवल मंच प्रदान कर सकते हैं। अपनी बहियों से कोई उधार नहीं।
11	हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (HFC) [धारा 45I(f)(iii) के तहत अधिसूचित]	आवास और आवास परियोजनाओं के लिए वित्त प्रदान करने का कारोबार करना।	(i) आवास के लिए वित्त प्रदान करने के कारोबार में वित्तीय परिसंपत्तियाँ अपनी कुल परिसंपत्तियों का कम से कम 60% (अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा निवर्तित) होंगी।

			(ii) कुल आस्तियों (अमूर्त आस्तियों द्वारा निविहित) में से कम से कम 50% व्यक्तियों के लिए आवास वित्त होगा।
12.	स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलर (एसपीडी)	प्राथमिक डीलरों से प्राथमिक नीलामियों में भाग लेने, सरकारी प्रतिभूतियों में बाजार निर्माण, न्यूनतम द्वितीयक बाजार कारोबार अनुपात प्राप्त करने आदि जैसे विभिन्न दायित्वों के माध्यम से अपने प्राथमिक और द्वितीयक बाजार खंडों दोनों में सरकारी प्रतिभूतियों में सक्रिय भूमिका निभाने की आशा की जाती है।	किसी भी समय सरकारी प्रतिभूतियों में कुल वित्तीय निवेश (दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों) का कम से कम 50 प्रतिशत।

उपर्युक्त श्रेणियों के अतिरिक्त, एनबीएफसी का एक वर्ग है जिसे अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियां (आरएनबीसी) कहा जाता है। ऐसी कंपनियों का प्रमुख कारोबार किसी भी योजना या व्यवस्था के तहत या किसी अन्य तरीके से जमा प्राप्त करना रहा है और उन्हें निर्दिष्ट तरीके से निवेश करना रहा है। हालांकि, इस श्रेणी के लिए कोई नया पंजीकरण जारी नहीं किया जा रहा है क्योंकि वर्तमान में बैंक के साथ कोई आरएनबीसी पंजीकृत नहीं है। विविध गैर-बैंकिंग कंपनियां (एमएनबीसी) एनबीएफसी हैं जो चिट फंड कारोबार का प्रबंधन करती हैं²²। चिट फंड मुख्य रूप से राज्य सरकारों द्वारा विनियमित किए जाते हैं और चिट फंड कारोबार करने वाली एनबीएफसी को पंजीकरण आवश्यकता से छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त, एमएनबीसी को दिनांक 28 अगस्त, 2009 के परिपत्र के तहत नई जमाराशियां स्वीकार करने से रोक दिया गया है और भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान विनियामक ढांचा ऐसी कंपनियों के मौजूदा जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा से संबंधित है। उपर्युक्त के अलावा, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (एआरसी) भी हैं जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा बेची गई वित्तीय आस्तियों के अर्जन और निपटान के लिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (एसएआरएफईईएसआई) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत और विनियमित हैं। एआरसी गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एआरसी को आरबीआई अधिनियम के तहत पंजीकरण से आरबीआई द्वारा छूट दी गई है और इसके बजाय आरबीआई द्वारा सरफेसी अधिनियम की धारा 3 के तहत पंजीकृत किया जाता है।²³ इन कंपनियों के लिए निर्धारित न्यूनतम एनओएफ को अप्रैल 2017 में ₹2 करोड़ से बढ़ाकर ₹100 करोड़ कर दिया

²² चिटफंड एक चक्रीय बचत एवं ऋण योजना है। आम तौर पर, व्यक्तियों का एक समूह एक चिट फंड में कई महीनों तक मासिक रूप से एक निश्चित राशि (सदस्यों की संख्या के बराबर) का योगदान करने के लिए एक साथ आता है। इस फंड का प्रबंधन एक फोरमैन द्वारा किया जाता है। हर महीने चिट फंड के लिए नीलामी आयोजित की जाती है और सबसे कम राशि की बोली लगाने वाला सदस्य नीलामी जीत जाता है। मूल रूप से, विजेता को एक बॉक्स से चिट निकालकर चुना जाता था (इसलिए "चिट फंड" शब्द) और यह प्रथा नीलामी के बजाय कुछ चिट फंडों में जारी है। फोरमैन के कमीशन को समायोजित करने के बाद शेष राशि को बाकी सदस्यों के बीच वितरित किया जाता है। नीलामी जीतने वाले सदस्य को भविष्य की नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं है, लेकिन उसे मासिक सदस्यता का योगदान जारी रखना होगा।

²³ निवल स्वाधिकृत निधि = स्वाधिकृत निधि (-) एनबीएफसी के अपने समूह की कंपनियों और सहायक कंपनियों और अन्य एनबीएफसी

गया था, जिसे अक्टूबर 2022 में बढ़ाकर ₹300 करोड़ कर दिया गया है जिसे 31 मार्च, 2026 तक प्राप्त करना होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इन कंपनियों के लिए भी पूंजी पर्याप्तता बनाए रखने, निधियों के नियोजन, आस्ति पुनर्रचना, आस्ति वर्गीकरण मानदंड, प्रकटन मानदंड आदि पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं।

एनबीएफसी को अलग करने का एक और तरीका स्वामित्व यानी सरकारी स्वामित्व और अन्य पर आधारित है। विनियामक ढांचे ने चरणबद्ध तरीके से सरकार के स्वामित्व वाली एनबीएफसी पर विवेकपूर्ण ढांचा लागू करके इस अंतर को दूर करने का प्रयास किया है। तथापि, सांविधिक ढांचे में अंतर है क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक के पास सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के निदेशकों को हटाने अथवा निदेशक मंडल का अधिक्रमण करने की शक्तियां नहीं हैं।

एनबीएफसी का विनियमन - उत्पत्ति और कानूनी ढांचा

आरबीआई ने 1963 में आरबीआई अधिनियम में अध्याय III-बी के सम्मिलन के साथ एनबीएफसी पर विनियामक और पर्यवेक्षी शक्तियां हासिल कीं। बैंककारी विधि (प्रकीर्ण उपबंध) विधेयक, 1963 के उद्देश्यों और कारणों के कथन का एक अंश, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम में अध्याय III ख अंतस्थापित किया गया है जो नीचे दिया गया है।

"बैंकों से संबंधित मौजूदा अधिनियमों में उन कंपनियों या संस्थानों पर किसी भी नियंत्रण का प्रावधान नहीं है, जिन्हें हालांकि बैंक के रूप में नहीं माना जाता है, लेकिन आम जनता से जमा स्वीकार करते हैं या अन्य कारोबार करते हैं जो बैंकिंग से संबद्ध हैं। रिज़र्व बैंक द्वारा मौद्रिक और ऋण प्रणाली के अधिक प्रभावी पर्यवेक्षण और प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए, यह वांछनीय है कि रिज़र्व बैंक को उन शर्तों को विनियमित करने में सक्षम बनाया जाए जिन पर इन गैर-बैंकिंग कंपनियों या संस्थानों द्वारा जमाराशियां स्वीकार की जा सकती हैं। रिज़र्व बैंक को उन मामलों के संबंध में किसी वित्तीय संस्था या संस्थाओं को निर्देश देने का भी अधिकार होना चाहिए, जिनमें देश की केंद्रीय बैंकिंग संस्था के रूप में रिज़र्व बैंक की रुचि क्रेडिट नीति पर नियंत्रण की दृष्टि से हो सकती है।"

जबकि आरबीआई द्वारा एनबीएफसी का विनियमन 1963 में एनबीएफसी की जमाराशियां स्वीकार करने की गतिविधि को विनियमित करने की आवश्यकता की संसद की मान्यता के साथ शुरू हुआ, 1996 ने एनबीएफसी के लिए एक बड़े एनबीएफसी (सीआरबी कैपिटल) की विफलता के साथ एक ऐतिहासिक वर्ष के तौर पर चिह्नित किया। शाह समिति (1992), जिसने एनबीएफसी के विनियामक और पर्यवेक्षी फोकस का विस्तार करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला था, की सिफारिशों के आधार पर, आरबीआई अधिनियम के अध्याय IIIबी में संशोधन के साथ आरबीआई की विनियामक और पर्यवेक्षी शक्तियों को मजबूत किया गया था। 1997 में किए गए कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों में शामिल हैं:

- आरबीआई के साथ अनिवार्य पंजीकरण और 'प्रमुख कारोबारी' मानदंडों को पूरा करने वाली कंपनियों के लिए न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) को रखना (धारा 45आईए)
- सार्वजनिक जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी द्वारा तरल परिसंपत्तियों को रखना (धारा 45आईबी)
- सभी एनबीएफसी द्वारा प्रत्येक वर्ष अपने निवल लाभ का 20 प्रतिशत अंतरित करके आरक्षित निधि का सृजन करना (धारा 45आईसी)

में निवेश और अन्य एक्सपोजर, स्वाधिकृत निधि के 10% की सीमा तक हो। स्वाधिकृत निधि = पूंजी + रिज़र्व - संचित घाटा और आस्थगित राजस्व व्यय - अन्य अमूर्त परिसंपत्ति।

- नीति निर्धारित करने और एनबीएफसी को निर्देश जारी करने के लिए आरबीआई को शक्तियां (धारा 45जेए)
 - एनबीएफसी के खातों की विशेष लेखापरीक्षा करना, यदि आवश्यक हो (धारा 45एमए)
 - जमाराशियों की स्वीकृति और परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर रोक लगाने की भारतीय रिज़र्व बैंक की शक्ति (धारा 45एमबी)
 - कंपनी अधिनियम, 1956 (धारा 45एमसी) के तहत समापन याचिका दायर करने की भारतीय रिज़र्व बैंक की शक्ति
 - एनबीएफसी के जमाकर्ताओं के लिए नामांकन सुविधा की शुरुआत (धारा 45क्यूबी)
 - वित्तीय कारोबार में संलग्न अनिगमित निकायों द्वारा जमाराशियों को स्वीकार करने का निषेध (धारा 45एस)
 - दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए एनबीएफसी पर जुर्माना लगाने की भारतीय रिज़र्व बैंक की शक्ति (धारा 58जी)
- रिज़र्व बैंक ने पंजीकरण संबंधी कठोर आवश्यकताओं, बढ़ी हुई रिपोर्टिंग और पर्यवेक्षण के साथ एनबीएफसी पर विनियामक संरचना को कड़ा कर दिया। बैंक ने नई सार्वजनिक जमाराशियों को स्वीकार न करने के लिए भी नीतिगत रुख अपनाया और मौजूदा को जमाराशि स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी में परिवर्तित होने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अलावा, 1999 में, नए पंजीकरण के लिए एनओएफ आवश्यकता को ₹ 25 लाख से बढ़ाकर ₹ 2 करोड़ कर दिया गया था।

एनबीएफसी द्वारा अपने आकार, वित्तीय सेवाओं और उत्पादों के नए क्षेत्रों में प्रवेश, नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने आदि के संदर्भ में परिचालन की प्रकृति के संदर्भ में तेजी से की गई प्रगति को देखते हुए, 2014 में इस क्षेत्र के लिए विनियामक ढांचे की फिर से समीक्षा की गई²⁴। समीक्षा इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि यह क्षेत्र तेजी से दूसरों के साथ जुड़ रहा था। संशोधित विनियामक ढांचे में प्रमुख परिवर्तन इस प्रकार थे:

- विरासत वाली एनबीएफसी के लिए ₹ 2 करोड़ की न्यूनतम एनओएफ की आवश्यकता।
- सभी श्रेणियों में जमा स्वीकार करने की आवश्यकताओं का सामंजस्य और परिसंपत्ति वित्त कंपनियों के लिए जमा स्वीकार करने की न्यूनतम निवेश ग्रेड रेटिंग आवश्यकता की शुरुआत।
- प्रणालीगत महत्व की सीमा में ₹100 करोड़ से ₹ 500 करोड़ तक का संशोधन और प्रणालीगत महत्व सीमा की गणना के लिए एक ही समूह के भीतर कई एनबीएफसी को शामिल करना
- ग्राहक इंटरफेस और धन के स्रोत के आधार पर विभेदित विनियामक दृष्टिकोण। स्पेक्ट्रम के एक तरफ, 500 करोड़ रुपये से कम संपत्ति आकार वाली और बिना ग्राहक इंटरफेस के सार्वजनिक निधियों को स्वीकार नहीं करने संस्थाओं को विवेकपूर्ण और कारोबारी आचरण नियमों से छूट दी गई थी। दूसरी ओर, ग्राहक इंटरफेस के साथ सार्वजनिक निधियों को स्वीकार करने वाली संस्थाओं को नियमों के पूर्ण अनुपालन के अधीन किया गया।
- बैंकों के साथ एनबीएफसी-डी और एनबीएफसी-एनडी-एसआई के लिए परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंडों का सामंजस्य।
- एनबीएफसी-डी और एनबीएफसी-एनडी-एसआई के लिए लागू बोर्ड समितियों (लेखापरीक्षा समिति, नामांकन समिति और जोखिम प्रबंधन समिति) के गठन और लेखा परीक्षा भागीदारों के रोटेशन के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन और

²⁴ दिनांक 10 नवंबर 2014 के डीएनबीआर (पीडी) सीसी.नं.002/03.10.001/2014-15 के माध्यम से जारी एनबीएफसी के लिए संशोधित विनियामक ढांचा देखें

प्रकटीकरण मानदंडों की समीक्षा।

वर्ष 2019 में आरबीआई अधिनियम के अध्याय III-बी में नीचे दिए गए कुछ संशोधन फिर से किए गए, जिसने *अन्य बातों के साथ-साथ* RBI की पर्यवेक्षी शक्तियों को मज़बूत किया है।

- रिज़र्व बैंक ₹.25 लाख और ₹.100 करोड़ (धारा 45आईए) के बीच न्यूनतम एनओएफ के साथ एनबीएफसी की विभिन्न श्रेणियों को एनओएफ की अलग-अलग राशि अधिसूचित कर सकता है
 - आरबीआई एनबीएफसी के निदेशकों (सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी के अलावा) को हटा सकता है – (धारा 45आईडी)
 - आरबीआई एनबीएफसी (सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी के अलावा) के निदेशक मंडल को अधिक्रमित कर सकता है – (धारा 45 आईई)
 - आरबीआई एनबीएफसी के लेखा परीक्षक को एक बार में अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए हटा या प्रतिबंधित कर सकता है (धारा 45एमएए)
 - समामेलन, पुनर्निर्माण, विभिन्न गतिविधियों में विभाजन आदि के माध्यम से एनबीएफसी का समाधान (धारा 45एमबीए)
 - समूह कंपनियों की जानकारी मांगने और समूह कंपनियों का निरीक्षण करने की शक्ति (धारा 45एनएए)
- इसके अलावा, वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2019 (2019 का 23) ने राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 में संशोधन किया है और एचएफसी के पंजीकरण और विनियमन को आरबीआई को हस्तांतरित कर दिया है। भारत सरकार द्वारा दिवाला और दिवालियापन (वित्तीय सेवा प्रदाताओं की दिवाला और परिसमापन कार्यवाही और निर्णय प्राधिकरण के लिए आवेदन) नियम, 2019 की अधिसूचना के साथ, बैंक को नवंबर 2019 से दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के तहत एनबीएफसी (एचएफसी सहित) की दिवाला समाधान प्रक्रिया भी सौंपी गई है।

विनियामक ढांचे का अवलोकन

एनबीएफसी वित्तीय सेवा मध्यस्थ होने के नाते प्रतिपक्ष विफलताओं, फंडिंग और परिसंपत्ति एकाग्रता, ब्याज दर में उतार-चढ़ाव और तरलता और शोधन क्षमता से संबंधित जोखिमों से उत्पन्न जोखिमों से अवगत हैं। इसके अलावा, वित्तीय बाजारों में अन्य भागीदारों के साथ एनबीएफसी का परस्पर संबंध समय के साथ एनसीडी, सीपी, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उधार के माध्यम से सार्वजनिक निधियों तक अधिक पहुंच के साथ बढ़ा है। नतीजतन, एनबीएफसी क्षेत्र के जोखिमों को आसानी से बाकी वित्तीय प्रणाली या विलोमतः संचारित कर सकता है। जबकि एनबीएफसी के लिए विनियम बैंकों की तुलना में सरल और कम हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर मूल्यांकन किया जाता है कि एनबीएफसी विनियम एनबीएफसी के प्रणालीगत प्रभावों के अनुरूप हैं जो एनबीएफसी उत्पन्न कर सकते हैं, और कुछ वित्तीय बाजार गतिविधियां विनियामक परिधि से बाहर नहीं हैं।

मोटे तौर पर विनियामक उद्देश्य दोहरे हैं अर्थात (i) वित्तीय प्रणाली स्थिरता को बढ़ावा देना और (ii) उपभोक्ता संरक्षण। इन उद्देश्यों के आधार पर, एनबीएफसी पर लागू विनियमों को विवेकपूर्ण (यानी, वित्तीय प्रणाली स्थिरता को बढ़ावा देने वाले)

और कारोबार संचालन (यानी, जो उपभोक्ता संरक्षण प्रदान करते हैं) के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। जबकि विवेकपूर्ण विनियमों में पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं, एकल/समूह उधारकर्ता जोखिम मानदंड, आय मान्यता, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंड, ऋण-मूल्य (एलटीवी) अनुपात, लेवरेज अनुपात²⁵, सार्वजनिक जमाराशियों को स्वीकार करने संबंधी शासित करने वाले विनियम आदि निर्धारित करना शामिल है, कारोबार संचालन विनियम मुख्य रूप से उधारदाताओं द्वारा अनुपालन की जाने वाली उचित व्यवहार संहिता (एफपीसी) और एनबीएफसी द्वारा अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों के अनुपालन से संबंधित हैं। विनियामक ढांचा इस बात का भी संज्ञान लेता है कि क्या एनबीएफसी ने सार्वजनिक निधियों तक अपनी पहुंच बनाई है या उसका ग्राहक इंटरफेस है। बेस लेयर एनबीएफसी जो सार्वजनिक निधियों को स्वीकार नहीं करते हैं, उन्हें विवेकपूर्ण नियमों से छूट दी गई है, जबकि वे सभी एनबीएफसी जिनके पास ग्राहक इंटरफेस नहीं है, उन्हें कारोबारी आचरण नियमों से छूट दी गई है।

बैंकों की तुलना में एनबीएफसी के लिए विनियामक ढांचे के प्रमुख बिंदुओं की तुलना नीचे दी गई तालिका में संक्षेप में दी गई है:

	बेस लेयर एनबीएफसी	मिडिल लेयर और अपर लेयर एनबीएफसी-	बैंकों
कानूनी आधार	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम का अध्याय IIIबी		बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949
पूंजी पर्याप्तता	कोई सीआरएआर नहीं। 7 गुना का लीवरेज अनुपात	एनबीएफसी-एमएल और सभी एमएफआई- न्यूनतम सीआरएआर 15 प्रतिशत (बेसल I के समान, समान जोखिम भार और बाजार या परिचालन जोखिमों के लिए कोई पूंजी प्रभार नहीं) एनबीएफसी-यूएल को 9 प्रतिशत की कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल (सीईटी 1) बनाए रखने की भी आवश्यकता है।	9 प्रतिशत का न्यूनतम सीआरएआर + पूंजी संरक्षण बफर + काउंटर चक्रीय बफर (बेसल III आधारित)
ऋण संकेद्रण	कोई विशिष्ट सीमा नहीं, केवल आंतरिक बोर्ड अनुमोदित नीति	टियर I पूंजी के प्रतिशत के रूप में गणना की गई सीमाएं एनबीएफसी-एमएल- एकल प्रतिपक्ष सीमा: 25 प्रतिशत प्रतिपक्षों का समूह सीमा: 40 प्रतिशत एनबीएफसी-यूएल - एकल प्रतिपक्ष सीमा: बोर्ड के अनुमोदन के साथ 20 प्रतिशत + 5 प्रतिशत	बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क - टियर I पूंजी के प्रतिशत के रूप में गणना की गई सीमा एकल प्रतिपक्ष: 20 प्रतिशत जुड़े प्रतिपक्षों के समूह: 25 प्रतिशत

²⁵ एनबीएफसी के लिए लीवरेज अनुपात को कुल बाहरी देनदारियों/स्वामित्व वाली निधियों के रूप में परिभाषित किया गया है। मौजूदा विनियमों के अनुसार, बेस लेयर एनबीएफसी (एनबीएफसी-एमएफआई को छोड़कर) के लिए लीवरेज अनुपात 7 से अधिक नहीं होना चाहिए।

		जुड़े प्रतिपक्षों का समूह सीमा: 25 प्रतिशत निर्दिष्ट वितरण के लिए उपलब्ध हैं (i) ढांचागत एक्सपोजर के लिए एनबीएफसी-एमएल और एनबीएफसी-यूएल और (ii) एनबीएफसी-आईएफसी	
लिक्विडिटी कवरेज अनुपात (एलसीआर)	चलनिधि जोखिम प्रबंधन ढांचा ₹100 करोड़ और उससे अधिक की परिसंपत्ति के आकार वाले सभी एनबीएफसी-डी और जमा स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी के लिए लागू है। एलसीआर उन सभी एनबीएफसी-डी और जमाराशि स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी पर लागू होता है, जिनकी परिसंपत्ति का आकार 5,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक है।		सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए लागू (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों को छोड़कर)
निवल स्थिर वित्त पोषण अनुपात	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रभावी होने पर जारी किए गए दिशा-निर्देश सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) पर लागू होंगे।
केवाईसी/ए एमएल- सीएफटी	बैंकों और एनबीएफसी पर समान मानदंड समान रूप से लागू		
लेखांकन मानदंड	मुख्य रूप से कंपनी अधिनियम, 2013 पर आधारित है। ₹ 250 करोड़ या उससे अधिक की निवल परिसंपत्ति वाले सूचीबद्ध एनबीएफसी और अन्य एनबीएफसी को आईएफआरएस अभिसरित भारतीय लेखा मानकों (इंडस्ट्रीज़ एएस) के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की आवश्यकता है		वैधानिक आवश्यकताओं, लेखा मानकों, आरबीआई के निर्देशों और स्व-विनियामक संगठनों द्वारा जारी मार्गदर्शन नोटों का मिश्रण।

इंड एस के कार्यान्वयन पर विनियामक मार्गदर्शन

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए आईएफआरएस अभिसरित भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) में परिवर्तन के रोडमैप के अनुसार, 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक की निवल संपत्ति वाली एनबीएफसी पहले ही 1 अप्रैल, 2018 से इंड एस में परिवर्तित हो चुकी हैं, इसके बाद 250 करोड़ रुपये या उससे अधिक की निवल संपत्ति वाली एनबीएफसी और अन्य सूचीबद्ध एनबीएफसी 1 अप्रैल, 2019 से परिवर्तन कर रही हैं।

भारतीय लेखा मानक (इंड एस) अन्य बातों के साथ-साथ अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) ढांचे, अन्य व्यापक आय, सममित उचित मूल्य लेखांकन आदि की अवधारणाओं को पेश करके लेखांकन में प्रतिमान बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जो विनियामक पूंजी गणना के साथ लेखांकन ढांचे की पारस्परिक प्रभाव को भी प्रभावित करता है। "नियम आधारित" के बजाय "सिद्धांत आधारित" होने के कारण, भारतीय लेखा मानक व्यक्तिपरकता और प्रबंधन विवेक में भी महत्वपूर्ण वृद्धि लाता है, जिसके परिणामस्वरूप तुलनात्मकता का नुकसान होता है। उच्च गुणवत्ता और निरंतर कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के साथ-

साथ तुलनात्मकता और बेहतर पर्यवेक्षण की सुविधा के लिए, आरबीआई ने 13 मार्च, 2020 के परिपत्र के माध्यम से, इंड एस को लागू करने वाली एनबीएफसी को विनियामक मार्गदर्शन जारी किया। प्रस्तावित मार्गदर्शन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- बोर्ड द्वारा अनुमोदित कारोबारी मॉडल उद्देश्यों, ईसीएल मॉडल, चूक की परिभाषा आदि के दस्तावेजीकरण के माध्यम से भारतीय लेखा मानक में निहित महत्वपूर्ण मान्यताओं और प्रबंधन निर्णय के लिए एक शासन ढांचा निर्धारित किया गया है। बोर्ड पर जिम्मेदारी डालते हुए, यह लेखा परीक्षकों और पर्यवेक्षकों द्वारा सत्यापन की सुविधा भी प्रदान करेगा।
- भारतीय लेखा मानक 109 में स्पष्ट रूप से चूक को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन संस्थाओं को आंतरिक ऋण जोखिम प्रबंधन के लिए उपयोग किए जाने वाले तरीके से चूक को परिभाषित करने की आवश्यकता है। परिपत्र में सिफारिश की गई है कि लेखांकन उद्देश्यों के लिए अपनाई गई चूक की परिभाषा विनियामक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली परिभाषा द्वारा निर्देशित होनी चाहिए। इसके अलावा, इसमें एसीबी को उन खातों के वर्गीकरण को मंजूरी देने की आवश्यकता है जो 90 दिनों से अधिक समय से बकाया हैं, लेकिन उन्हें हासित के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। ऐसे खातों में बकाया राशि और कुल राशि का भी खुलासा किया जाना चाहिए।
- इंड एस के तहत, जब क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि का आकलन किया जाता है, तो ईसीएल भत्ते 12 महीने से आजीवन ईसीएल में बदल जाते हैं। इंडस्ट्रीज़ एस एक खंडन योग्य अनुमान प्रदान करता है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से वित्तीय परिसंपत्ति पर क्रेडिट जोखिम में काफी वृद्धि हुई है जब संविदात्मक भुगतान 30 दिनों से अधिक समय से देय है। सीमित परिस्थितियों में जहां एनबीएफसी/एआरसी इस अनुमान का खंडन करते हैं, उन्हें एसीबी के समक्ष औचित्य रखना चाहिए। इसके अलावा, क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि की मान्यता को उन खातों के लिए स्थगित नहीं किया जाना चाहिए जो 60 दिनों से अधिक समय से बकाया हैं।
- इंड एस के अंतर्गत अपर्याप्त प्रावधान से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए वर्तमान मानदंडों (आईआरएसीपी) पर आधारित एक विवेकपूर्ण फ्लोर निर्धारित किया गया है। यदि भारतीय लेखा मानक के तहत प्रावधान आईआरएसीपी मानदंडों से कम है, तो अंतर लाभांश के भुगतान के लिए उपलब्ध नहीं होगा और इसके बजाय इसे 'क्षति रिजर्व' में स्थानांतरित करने की आवश्यकता होगी। विनियामक पूंजी के लिए क्षति रिजर्व की गणना नहीं की जाएगी। इस रिजर्व से कोई भी निकासी आरबीआई से मंजूरी के अधीन होगी। इसके अलावा, हितधारकों के लिए तुलना के लिए एक बेंचमार्क प्रदान करने के लिए, भारतीय लेखा मानक और आईआरएसीपी वर्गीकरण और प्रावधान की तुलना करने वाला एक प्रकटीकरण टेम्पलेट निर्धारित किया गया है।
- विनियामक पूंजी संगणना में कठिनाई को कम करने के लिए, दिशा-निर्देशों में निवल अप्राप्त उचित मूल्य लाभों की अनदेखी करने का प्रावधान है, जबकि निवल अप्राप्त उचित मूल्य हानियों का प्रावधान है। वे 12 महीने के ईसीएल (सामान्य प्रावधानों के समान ही), अचल परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन पर छूट, नकदी प्रवाह हेज रिजर्व और स्वयं के क्रेडिट जोखिम के कारण अप्राप्त लाभ और हानि की मान्यता और समूह संस्थाओं के उचित मूल्यांकन के कारण शुद्ध स्वामित्व वाले धन में समायोजन के लिए व्यवस्था भी निर्धारित करते हैं। यह भी स्पष्ट किया गया है कि विनियामक पूंजी की आवश्यकता उन वित्तीय साधनों पर होगी जो मान्यता रद्द करने के लिए योग्य नहीं हैं। आगे विनियामक अनुपात, सीमाएँ और प्रकटीकरण भारतीय लेखा मानक के आंकड़ों पर आधारित होंगे।

एनबीएफसी क्षेत्र में फिनटेक विकास

भारत में, बैंक और एनबीएफसी वित्तीय नवाचार को अपनाने के लिए प्रौद्योगिकी का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। वित्तीय क्षेत्र के विनियामक के रूप में, भारतीय रिजर्व बैंक नए वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के विकास के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने में सबसे आगे रहा है। वास्तव में, गैर-बैंकिंग और भुगतान और प्रणाली के क्षेत्र में, बैंक समकालीन से आगे रहा है और नए उत्पादों और सेवाओं के लिए तब विनियमों के लाया जब उद्योग स्वयं नवजात अवस्था में था। एनबीएफसी-पी2पी और एनबीएफसी-ए ऐसे मामले हैं जहां विनियमन ने उद्योग को व्यवस्थित और मजबूत तरीके से बढ़ने में मदद की है।

एनबीएफसी-P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म- एक मध्यस्थ जो उधारकर्ताओं और उधारदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर लाता है। प्लेटफॉर्म स्वयं कोई क्रेडिट जोखिम नहीं लेता है, क्रेडिट सूचना कंपनियों पर लेनदेन की सूचना दी जाती है और प्लेटफॉर्म पर उधारकर्ताओं और उधारदाताओं पर विवेकपूर्ण सीमाएं रखी गई हैं। 31 मार्च, 2024 तक बैंक के साथ 26 एनबीएफसी-पी2पी प्लेटफॉर्म पंजीकृत हैं।

एनबीएफसी-खाता एग्रीगेटर - ग्राहक की वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित जानकारी को इसके धारकों से पुनः प्राप्त या एकत्र करता है और ग्राहकों द्वारा निर्दिष्ट ग्राहकों या उपयोगकर्ताओं को प्रस्तुत करने से पहले इसे एकत्र करता है। एनबीएफसी-ए का बड़ा लक्ष्य भारत जैसी उभरती बाजार अर्थव्यवस्था में डेटा सशक्तिकरण या डेटा लोकतंत्रीकरण है, जहां वित्तीय सेवाओं (गुणात्मक और मात्रात्मक) तक पहुंच अभी भी काफी हद तक सीमित है।

एनबीएफसी-ए के लिए तकनीकी विनिर्देश- एनबीएफसी-ए इकोसिस्टम में, डेटा को विभिन्न वित्तीय क्षेत्र विनियमित संस्थाओं में एक मानकीकृत और एन्क्रिप्टेड प्रारूप में स्थानांतरित होना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक सुरक्षित और संरक्षित वातावरण में सिस्टम में डेटा की आवाजाही निर्बाध है, एनबीएफसी-ए के लिए तकनीकी विनिर्देश निर्धारित किए गए हैं। ये डेटा के संचलन के लिए तैयार किए गए एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस (एपीआई) आधारित विनिर्देश हैं और मूल में सहमति संरचना है जो एनबीएफसी-ए परितंत्र को अपनी पूरी क्षमता में कार्य करने में बहुत अधिक मददगार साबित होगा।

इन विनियमों की मुख्य बात यह है कि इनसे न केवल नए, तीव्रतर और कुशल प्रौद्योगिकी/ कारोबारी मॉडलों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है बल्कि फिनटेक आधारित वित्तीय सेवाओं को अपनाने से उत्पन्न होने वाली चिंताएं भी कम होती हैं। विशेष रूप से, विनियामक विशेषताएं जैसे, आंकड़ा साझाकरण के लिए स्पष्ट सहमति, सर्वरों के लिए देश में अवस्थान, इलेक्ट्रॉनिक सहमति आर्टिफैक्ट, ऑडिट ट्रेल्स, सीआईएसए ऑडिट, डेटा ब्लाइंड एनबीएफसी-ए प्लेटफॉर्म आदि प्रकृति में अग्रणी और प्रगतिशील हैं।

एनबीएफसी का पर्यवेक्षण

आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए एक मजबूत और व्यापक पर्यवेक्षी प्रणाली स्थापित किया है। आरबीआई का ध्यान विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण पर है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एनबीएफसी मजबूत और स्वस्थ स्थिति में काम करें और अत्यधिक जोखिम लेने से बचें। आरबीआई ने निम्नलिखित के आधार पर पांच-आयामी पर्यवेक्षी ढांचा तैयार किया है:

ऑन-साइट निरीक्षण: 1997 के दौरान स्थापित ऑन-साइट परीक्षा की प्रणाली कैमल्स (CAMELS) (पूंजी, संपत्ति, प्रबंधन,

आय, तरलता, और प्रणाली और नियंत्रण) दृष्टिकोण के आधार पर संरचित है। रिज़र्व बैंक आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45N के तहत एनबीएफसी का निरीक्षण करने और वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, (सरफेसी अधिनियम) 2002 की धारा 12बी के तहत एआरसी के मामले में, किसी भी बयान या जानकारी की शुद्धता या पूर्णता को सत्यापित करने के उद्देश्य से या किसी भी जानकारी या विवरण प्राप्त करने के लिए निरीक्षण करना यदि बैंक को लगता है कि ऐसा करना जरूरी है। एनबीएफसी की बहियों का निरीक्षण करने की शक्तियां आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (4) के तहत बैंक के पास निहित हैं, मुख्य रूप से यह सत्यापित करने के लिए कि क्या वित्तीय कंपनी पंजीकरण प्रमाण पत्र (सीओआर) प्रदान करने के लिए निर्धारित शर्तों का अनुपालन करती है। एनबीएफसी के ऑन-साइट निरीक्षण के समग्र उद्देश्य हैं: -

- पूंजी और आय की संभावनाओं की पर्याप्तता का आकलन करें और कैमल्स के आधार पर पर्यवेक्षी रेटिंग प्रदान करें।
- वित्तीय कंपनी की शोधन क्षमता का मूल्यांकन।
- भारतीय रिज़र्व बैंक/सरफेसी अधिनियमों के प्रावधानों और समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों/अधिसूचनाओं और किसी भी अन्य दिशानिर्देशों/विनियमों के अनुपालन की स्थिति का मूल्यांकन करना जो बैंक द्वारा वर्तमान अधिनियम के तहत निर्धारित किए जा सकते हैं।
- उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां कंपनी को मजबूत करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है।

पर्यवेक्षी ढांचे में सांविधिक सुझावों, निदेशों और विवेकपूर्ण विनियमों को ध्यान में रखा जाता है। इस ढांचे के भीतर, कंपनियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कारोबार से उत्पन्न जोखिमों का विवेकपूर्ण तरीके से स्वयं ही प्रबंधन करें और यह सुनिश्चित करें कि वे अपने दायित्वों, विशेष रूप से (सार्वजनिक) जमाशायियों की देनदारियों और अन्य लेनदारों को पूरा करने की स्थिति में हैं और यह भी सुनिश्चित करें कि वे अपने जमाकर्ताओं या समग्र वित्तीय प्रणाली के हितों के प्रति नुकसानदेह तरीके से कार्य न करें। ऐसे निरीक्षणों की आवधिकता एनबीएफसी की श्रेणी और परिसंपत्ति-आकार पर आधारित होगी।

ऑफ-साइट निगरानी: ऑन-साइट निरीक्षणों से एकत्र की गई जानकारी के पूरक के लिए, ऑफ-साइट निगरानी प्रणाली के हिस्से के रूप में एनबीएफसी के लिए कई विवरणी निर्धारित किए गए हैं। प्रदान की गई जानकारी का विश्लेषण संभावित पर्यवेक्षी चिंताओं की पहचान करने के लिए किया जाता है और कुछ मामलों में ऑन-साइट निरीक्षण के लिए ट्रिगर के रूप में कार्य करता है। एनबीएफसी द्वारा प्रस्तुत की जा रही विवरणियों की सूचना के दायरे को व्यापक बनाने के लिए कई अंतराल पर इसकी समीक्षा और जांच की जाती है, ताकि पर्यवेक्षी उद्देश्यों के लिए आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके या इन कंपनियों के कामकाज के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विभिन्न हित समूहों को इसे प्रस्तुत किया जा सके।

बाजार आसूचना: बाजार आसूचना वित्तीय क्षेत्र की निगरानी का एक महत्वपूर्ण घटक है। जबकि ऑफ-साइट निगरानी प्रणाली और ऑन-साइट निरीक्षण वित्तीय स्थिति और पंजीकृत कंपनियों के समग्र विनियामक अनुपालन का आकलन करने में प्रभावी उपकरण हैं, सक्रिय बाजार आसूचना किसी विशेष एनबीएफसी के स्वास्थ्य के बारे में प्रारंभिक चेतावनी संकेतों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने/प्रणालीगत जोखिमों से बचने के लिए पर्यवेक्षी कार्रवाई आरंभ किया जा सकता है। हाल ही में, उन कंपनियों के कार्यकलापों में तेजी आई है जो विनियामकों के निर्देशों का उल्लंघन करके विभिन्न तरीकों से निधियों को स्वीकार करती हैं और अपनी योजना की संरचना इस प्रकार करती

हैं कि 'जमाराशियों' की स्पष्ट परिभाषा और विनियामकों के ध्यान से बच जाएं। बेईमान कंपनियों द्वारा जमाराशियां अनधिकृत रूप से स्वीकार करने की घटनाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सभी राज्यों में राज्य स्तरीय समन्वय समितियों (एसएलसीसी) का मई 2014 में पुनर्गठन किया गया था ताकि विनियामकों यथा आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, एनएचबी, पीएफआरडीए, कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) आदि और राज्यों की प्रवर्तन एजेंसियों अर्थात् गृह विभाग, वित्त विभाग, विधि विभाग, आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) आदि के बीच सूचनाओं को शेयर किया जा सके ताकि अनधिकृत संस्थाओं की अवैध गतिविधियों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा सके। पिछले कुछ वर्षों में, विनियामकों और प्रवर्तन प्राधिकरणों के बीच नियमित विचार-विमर्श में वृद्धि हुई है ऐसे मामलों के प्रभावी संचालन के लिए जागरूकता और समन्वय और मानक संचालन प्रक्रियाएं विकसित की जा रही हैं।

सचेत पोर्टल: रिज़र्व बैंक ने 4 अगस्त 2016 को जनता के साथ-साथ विनियामकों की मदद करने के लिए एक मोबाइल फ्रेंडली पोर्टल सचेत (sachet.rbi.org.in) लॉन्च किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल विनियमित संस्थाएं ही जनता से जमाराशियां स्वीकार करें। पोर्टल का उपयोग जनता द्वारा जानकारी साझा करने के लिए किया जा सकता है, जिसमें वे विज्ञापनों/प्रचार सामग्री की तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं, किसी भी धन उगाहने/निवेश योजनाओं पर प्रश्न उठा सकते हैं और शिकायत दर्ज कर सकते हैं। पोर्टल में सभी विनियामकों के लिंक हैं और जनता आसानी से विनियमित संस्थाओं की सूचियों पर जानकारी प्राप्त कर सकती है। पोर्टल में क्लोस्ड उपयोगकर्ता समूह के लिए एक सेक्शन भी है – अनधिकृत जमा संग्रह और वित्तीय गतिविधियों पर समन्वित कार्रवाई के लिए सूचना के आदान-प्रदान के लिए एसएलसीसी अंतर-विनियामक मंच। यह विनियामकों और राज्य सरकार की एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने में मदद करता है, जो अनधिकृत रूप से जमाराशियों को स्वीकार करने के बारे में शीघ्रता से पता लगाने और अंकुश लगाने के लिए सूचना के उपयोगी स्रोत के रूप में कार्य करता है। 24 अक्टूबर, 2019 को सचेत पोर्टल को आम जनता में अपनी पैठ को आगे बढ़ाने के लिए हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 11 और प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया गया था।

सांविधिक लेखा परीक्षकों की अपवाद रिपोर्ट: उपरोक्त सभी प्रकार के पर्यवेक्षण के अलावा, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के साथ-साथ आरबीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेदारी भी एनबीएफसी के सांविधिक लेखा परीक्षकों को सौंपी गई है। सांविधिक लेखा परीक्षकों से अपेक्षित है कि वे सार्वजनिक जमाराशियों को स्वीकार करने, क्रेडिट रेटिंग, विवेकपूर्ण मानदंड और एक्सपोजर सीमा, पूंजी पर्याप्तता, तरल आस्तियों के अनुरक्षण और कंपनियों द्वारा धारित अतिरिक्त जमाओं के नियमितीकरण से संबंधित विनियमों की किसी भी अनियमितता या उल्लंघन के बारे में रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करें।

हितधारकों के साथ बातचीत: क्षेत्र में उभरते जोखिमों और गतिविधियों की बारीकी से समझ विकसित करने तथा त्वरित कार्रवाई को सुविधाजनक बनाने के लिए, विभाग एनबीएफसी, सांविधिक लेखा परीक्षकों, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों, क्रेडिट सूचना कंपनियों, म्यूचुअल फंड आदि के प्रबंधन जैसे विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत करता है। उपर्युक्त के अलावा, निवेशकों के परिप्रेक्ष्य से पर्यवेक्षित इकाई की स्थिति को समझने के लिए बाजार विभाग के साथ बाजार विभाग के साथ बाजार में पर्यवेक्षित इकाई की कार्रवाइयों और एनबीएफसी के बॉन्ड/सीपी में निवेशकों के दृष्टिकोण पर चर्चा की जाती है।

स्केल आधारित विनियमन: एनबीएफसी के लिए एक संशोधित विनियामक ढांचा

अक्टूबर 2021 में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने एक 'स्केल-आधारित विनियमन' (एसबीआर) ढांचा जारी किया था जिसमें एनबीएफसी के विनियमन के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया था – जिसमें पूंजी आवश्यकताएँ, शासन मानक, विवेकपूर्ण विनियमन आदि शामिल थे। ये दिशानिर्देश 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी हैं। एनबीएफसी के लिए विनियामक संरचना में उनके आकार, गतिविधि और कथित जोखिम के आधार पर चार परतें शामिल होंगी। सबसे निचली परत में एनबीएफसी को एनबीएफसी - बेस लेयर (एनबीएफसी-बीएल) के रूप में जाना जाएगा। मिडिल लेयर और अपर लेयर में एनबीएफसी को क्रमशः एनबीएफसी - मिडिल लेयर (एनबीएफसी-एमएल) और एनबीएफसी - अपर लेयर (एनबीएफसी-यूएल) के रूप में जाना जाएगा। टॉप लेयर की आदर्श स्थिति में शून्य होने की उम्मीद है और इसे एनबीएफसी - टॉप लेयर (एनबीएफसी-टीएल) के रूप में जाना जाएगा।

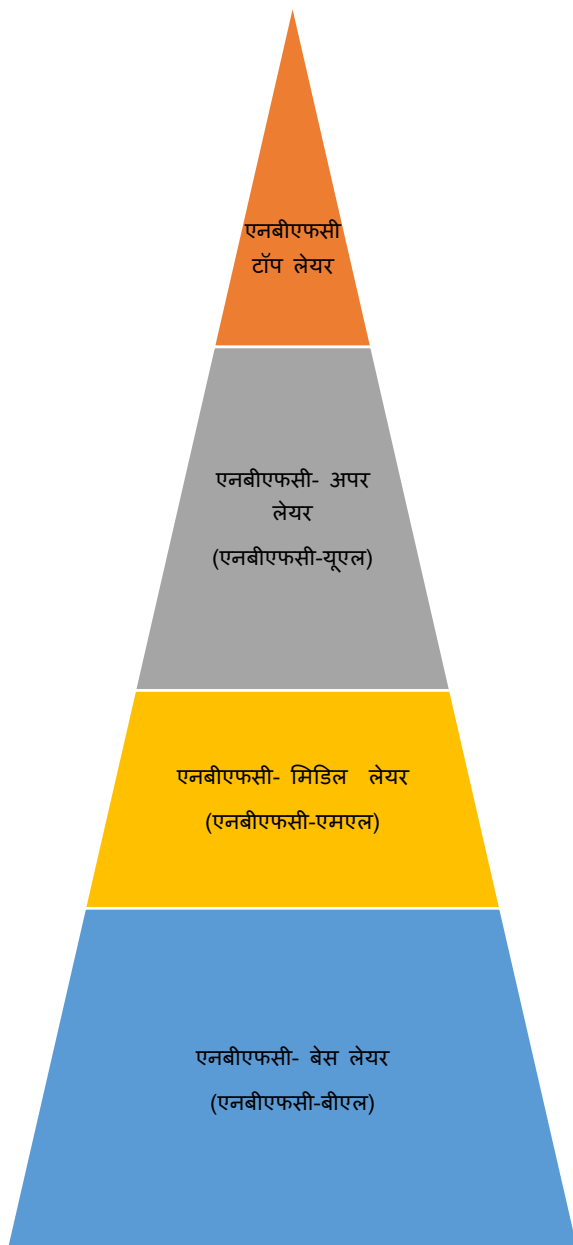
इसके अलावा, आरबीआई ने 11 अप्रैल 2022 के परिपत्र के माध्यम से, एनबीएफसी- अपर लेयर और एनबीएफसी- मिडिल लेयर में अनुपालन संबंधी कार्य और मुख्य अनुपालन अधिकारी की भूमिका के लिए एक रूपरेखा जारी की।

इसके बाद, 19 अप्रैल 2022 को, आरबीआई ने एनबीएफसी – अपर लेयर के लिए एनबीएफसी के लिए बड़े एक्सपोज़र फ्रेमवर्क, एनबीएफसी – अपर लेयर की पूंजी आवश्यकताएँ, एनबीएफसी के ऋण और अग्रिम पर विनियामक प्रतिबंध और वित्तीय विवरणों के खातों के नोटों में प्रकटीकरण पर परिपत्र जारी किया। 29 अप्रैल 2022 को, आरबीआई ने 'बेस लेयर' और सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी के तहत वर्गीकृत लोगों को छोड़कर, एसबीआर ढांचे के तहत सभी एनबीएफसी के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों की अर्थोपचार नीति पर दिशानिर्देश जारी किए, जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी है। जून 6, 2022 को, आरबीआई ने मानक परिसंपत्तियों के प्रावधानीकरण पर दिशानिर्देश जारी किए, जो एनबीएफसी – अपर लेयर के लिए लागू हैं।

एनबीएफसी के लिए विनियामक संरचना में नीचे दिए गए पिरामिड में परिभाषित चार लेयर शामिल होंगी:

टॉप लेयर में संख्या को तभी बढ़ाया जब आरबीआई की राय हो कि अपर लेयर में विशिष्ट एनबीएफसी से संभावित प्रणालीगत जोखिम में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इन एनबीएफसी के साथ बढ़ी हुई और गहन पर्यवेक्षी संवाद को बढ़ाया जाएगा।

एनबीएफसी को आरबीआई द्वारा कुछ मात्रात्मक और गुणात्मक मानदंडों के पैरामीट्रिक विश्लेषण के माध्यम से विशेष रूप से पहचाना जाएगा। अपनी परिसंपत्ति के आकार के संदर्भ में शीर्ष 10 पात्र एनबीएफसी हमेशा अपर लेयर में रहेंगी, चाहे कोई भी अन्य कारक हो।



सभी जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-डीएस), रुपये 1000 करोड़ या उससे अधिक की परिसंपत्ति वाली जमा न स्वीकार करने वाली एनबीएफसी, स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स (एसपीडी), इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड-एनबीएफसी (आईडीएफ-एनबीएफसी), कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी), आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी), इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियां (एनबीएफसी-आईएफसी) और कुछ सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी।

रुपये 1000 करोड़ से कम परिसंपत्ति वाली जमाराशि स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी, एनबीएफसी-पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म (एनबीएफसी-पी2पी), एनबीएफसी-अकाउंट एग्रीगेटर (एनबीएफसी-एए), नॉन-ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी), सार्वजनिक निधि का लाभ न उठाने वाली और ग्राहकों से संपर्क न रखने वाली एनबीएफसी तथा कुछ सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी।

स्केल आधारित विनियमन (एसबीआर) के तहत विनियामक परिवर्तन

विनियामक ढांचे में सभी लेयर के लिए एसबीआर के तहत विनियामक परिवर्तन

- निवल स्वाधिकृत निधि – एनबीएफसी-आईसीसी, एनबीएफसी-एमएफआई और एनबीएफसी-कैक्टर्स के लिए विनियामक न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) को बढ़ाकर ₹10 करोड़ किया जाएगा। मौजूदा एनबीएफसी को ₹10 करोड़ का एनओएफ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित ग्लाइड पाथ प्रदान किया गया है:

एनबीएफसी	वर्तमान एनओएफ	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2027 तक
एनबीएफसी-आईसीसी	₹2 करोड़	₹5 करोड़	₹10 करोड़

एनबीएफसी- एमएफआई	₹5 करोड़ (एनईआर में ₹2 करोड़*)	₹7 करोड़ (एनईआर में ₹5 करोड़)	₹10 करोड़
एनबीएफसी- फैक्टर्स	₹5 करोड़	₹7 करोड़	₹10 करोड़

*- एनईआर – पूर्वोत्तर-पूर्वी क्षेत्र

हालांकि, एनबीएफसी-पी2पी, एनबीएफसी-एए और एनबीएफसी के लिए जिनके पास कोई सार्वजनिक निधि नहीं है और कोई ग्राहक इंटरफ़ेस नहीं है, एनओएफ ₹2 करोड़ बरबरा रहेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि एनबीएफसी - आईडीएफ, आईएफसी, एमजीसी, एचएफसी और एसपीडी के लिए मौजूदा विनियामक न्यूनतम एनओएफ में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

- एनपीए वर्गीकरण - एनबीएफसी की सभी श्रेणियों के लिए मौजूदा एनपीए वर्गीकरण मानदंड 90 दिनों से अधिक की अतिदेय अवधि में बदल गया है। एनबीएफसी को बेस लेयर में निम्नानुसार 90 दिनों के एनपीए मानदंड का पालन करने के लिए एक ग्लाइड पाथ प्रदान किया जाता है

एनपीए मानदंड	समयसीमा
150 दिन अतिदेय	मार्च 31, 2024 तक
120 दिन अतिदेय	31 मार्च 2025 तक
90 दिन	31 मार्च 2026 तक

स्पष्टीकरण: ग्लाइड पथ एनबीएफसी पर लागू नहीं होगा जिन्हें पहले से ही 90-दिवसीय एनपीए मानदंड का पालन करना आवश्यक है।

- बोर्ड का अनुभव - एनबीएफसी के मामलों के प्रबंधन में पेशेवर अनुभव की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, कम से कम एक निदेशक को बैंक/एनबीएफसी में काम करने का प्रासंगिक अनुभव होना चाहिए।
- आईपीओ फंडिंग पर सीलिंग - प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के सब्सक्रिप्शन के वित्तपोषण के लिए प्रति उधारकर्ता ₹ 1 करोड़ की सीमा होगी²⁶। एनबीएफसी अधिक सतर्कतावादी सीमाएं तय कर सकते हैं।

विनियामक ढांचे में विभिन्न लेयर के लिए एसबीआर के तहत विनियामक परिवर्तन

पूँजीगत दिशानिर्देश - एनबीएफसी-एमएल और एनबीएफसी-यूएल के लिए लागू

- **आंतरिक पूँजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आईसीएएपी)** - एनबीएफसी के लिए अपने कारोबार में जोखिमों के अनुरूप पूँजी की आवश्यकता का गहन आंतरिक मूल्यांकन करना आवश्यक है। यह आंतरिक मूल्यांकन उसी तर्ज पर होगा जैसा कि आईसीएएपी ने टियर 2 के तहत वाणिज्यिक बैंकों के लिए निर्धारित किया है। जबकि पिलर 2 पूँजी पर जोर नहीं दिया जाएगा, एनबीएफसी को जोखिमों का यथार्थवादी मूल्यांकन करना होगा। आंतरिक पूँजी मूल्यांकन में आंतरिक रूप से निर्धारित की जाने वाली पद्धति के अनुसार ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन

²⁶ यह विनियमन 01 अप्रैल, 2022 से प्रभावी हो गया है।

जोखिम और अन्य सभी अवशिष्ट जोखिमों को शामिल किया जाएगा। आईसीएएपी का उद्देश्य कारोबार के सभी जोखिमों के प्रति पर्याप्त पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है और एनबीएफसी को अपने जोखिमों की निगरानी और प्रबंधन के लिए बेहतर आंतरिक जोखिम प्रबंधन तकनीकों को विकसित करने और उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

- **एनबीएफसी-यूएल पर लागू एसबीआर के तहत अतिरिक्त विनियामक परिवर्तन**

सामान्य इक्विटी टियर 1 – विनियामक पूंजी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, एनबीएफसी-यूएल जोखिम भारित परिसंपत्तियों के कम से कम 9 प्रतिशत की सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी बनाए रखेगा।

लिवरेज - सीआरएआर के अलावा, एनबीएफसी-यूएल को भी **लिवरेज** आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी संवृद्धि अन्य कारकों के साथ पर्याप्त पूंजी द्वारा समर्थित है। जब भी आवश्यक होगा, इन कंपनियों के लिए बाद में लिवरेज के लिए एक उपयुक्त सीमा निर्धारित की जाएगी।

विभेदक मानक परिसंपत्ति प्रावधान- एनबीएफसी-यूएल को मानक परिसंपत्तियों के विभिन्न वर्गों के लिए विभेदक प्रावधान रखने की आवश्यकता होगी।

एनबीएफसी के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों (केएमपी) और वरिष्ठ प्रबंधन के पारिश्रमिक के निर्धारण के लिए दिशानिर्देश

एनबीएफसी के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों (केएमपी) और वरिष्ठ प्रबंधन के पारिश्रमिक को तय करने के लिए सिद्धांतों का एक सेट जारी किया गया था। दिशानिर्देशों के अनुसार, एनबीएफसी को एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) का गठन करना आवश्यक है, जो पारिश्रमिक नीति तैयार करने, समीक्षा करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार होगी। दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया है कि नियत और परिवर्तनीय वेतन वाले पारिश्रमिक पैकेज को सभी प्रकार के जोखिमों के प्रति समायोजित किया जाएगा। परिवर्तनीय वेतन के एक निश्चित हिस्से में एक आस्थगित व्यवस्था हो सकती है और आस्थगित वेतन को मैलस/क्लॉ बैक व्यवस्था के अधीन किया जा सकता है।

सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी

31 मई, 2018 के 'सरकारी स्वामित्व वाली एनबीएफसी को दी गई छूट की वापसी' पर रिज़र्व बैंक के परिपत्र के अनुसार, सरकार के स्वामित्व वाली एनबीएफसी अभी भी न्यूनतम सीआरएआर प्राप्त करने के लिए संक्रमण अवधि में हैं। इसलिए, यह निर्णय लिया गया है कि इस समय इन एनबीएफसी को अपर लेयर को विनियामक ढांचे के अधीन नहीं किया जाए। निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाली पात्र सरकारी एनबीएफसी को अपर लेयर में शामिल करने का निर्णय बाद के चरण में लिया जाएगा और उस समय तक एनबीएफसी-बीएल या एनबीएफसी-एमएल के लिए यथा लागू दिशानिर्देश लागू होंगे।

एनबीएफसी के लिए पीसीए फ्रेमवर्क

एनबीएफसी आकार में बढ़ रहे हैं और वित्तीय प्रणाली के अन्य क्षेत्रों के साथ पर्याप्त अंतर-संबंध हैं। तदनुसार, एनबीएफसी के लिए लागू पर्यवेक्षी साधनों को और सुदृढ़ करने के लिए एनबीएफसी के लिए पीसीए ढांचा तैयार किया गया है। यह इनपर

लागू होगा:

- जमाराशि स्वीकार करने वाली सभी एनबीएफसी [सरकारी कंपनियों को छोड़कर],
- जमाराशि स्वीकार न करने वाली सभी मिडिल, अपर और टॉप लेयर एनबीएफसी [(i) एनबीएफसी सार्वजनिक निधि को स्वीकार नहीं करने वाली/स्वीकार न करने का इरादा रखने वाली; (ii) सरकारी कंपनियां, (iii) प्राथमिक डीलर और (iv) आवास वित्त कंपनियां के अलावा]
- एनबीएफसी के लिए पीसीए फ्रेमवर्क 31 मार्च, 2022 को या उसके बाद एनबीएफसी की वित्तीय स्थिति के आधार पर 1 अक्टूबर, 2022 से लागू होगा।
- एनबीएफसी-डी और एनबीएफसी-एनडी के लिए, पूंजी और परिसंपत्ति गुणवत्ता पीसीए ढांचे में निगरानी के लिए प्रमुख क्षेत्र होंगे।
- सीआईसी के लिए, पूंजी, लिवरेज और परिसंपत्ति गुणवत्ता पीसीए फ्रेमवर्क में निगरानी के लिए प्रमुख क्षेत्र होंगे
- एनबीएफसी-डी और एनबीएफसी-एनडी के लिए, ट्रैक किए जाने वाले संकेतक जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर), टियर I पूंजी अनुपात और निवल एनपीए अनुपात (एनएनपीए) होंगे। सीआईसी के लिए, ट्रैक किए जाने वाले संकेतकों में समायोजित निवल मूल्य/सकल जोखिम भारित परिसंपत्तियां, लिवरेज अनुपात और एनएनपीए होंगे।
- एनबीएफसी को आमतौर पर लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय परिणामों और/या आरबीआई द्वारा किए गए पर्यवेक्षी मूल्यांकन के आधार पर पीसीए ढांचे के तहत रखा जाएगा। हालांकि, यदि परिस्थितियां ऐसी हों तो आरबीआई किसी भी एनबीएफसी पर वर्ष (एक सीमा से दूसरी सीमा में माइग्रेशन सहित) के दौरान पीसीए लगा सकता है।

अध्याय 11: भारतीय रिज़र्व बैंक में प्रवर्तन

भारतीय रिज़र्व बैंक के पास विभिन्न कानूनों के तहत बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाने की शक्तियां हैं, जिसमें मौद्रिक दंड भी शामिल है। ये कानून हैं: बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949; भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934; राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987; भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007; वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002; फ़ैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011; क्रेडिट सूचना कंपनियां (विनियमन) अधिनियम, 2005; इत्यादि। यद्यपि रिज़र्व बैंक इन कानूनों के तहत मौद्रिक दंड लगाने के रूप में दंडात्मक कार्रवाई कर रहा था, यह प्रक्रिया विभिन्न नियामकीय/पर्यवेक्षी विभागों में विभाजित थी, जो पर्यवेक्षी प्रक्रिया से प्रवर्तन कार्रवाई को अलग करने के अंतरराष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं के अनुरूप नहीं था।

विनियमन, पर्यवेक्षण और प्रवर्तन वित्तीय क्षेत्र की निगरानी प्रणाली के तीन महत्वपूर्ण आयाम हैं। विनियम वह ढांचा निर्धारित करते हैं जिसके भीतर वित्तीय संस्थाएं कार्य करती हैं, ताकि एक ओर विवेकशीलता, पारदर्शिता और तुलनात्मकता सुनिश्चित हो सके और दूसरी ओर ग्राहकों के हितों की रक्षा की जा सके। पर्यवेक्षण (जिसमें ऑफ-साइट निगरानी भी शामिल है) वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विनियमों के अनुपालन की निगरानी की जाती है। प्रवर्तन उन मामलों से संबंधित है जहां पर्यवेक्षी प्रक्रिया या अन्य तरीकों से विनियमों के अनुपालन में चूक पाई जाती है।

एक प्रभावी बैंकिंग पर्यवेक्षण प्रणाली, अन्य बातों के साथ-साथ, नियामकीय निर्देशों के सशक्त प्रवर्तन पर निर्भर करती है, जिसके लिए एक एकीकृत और स्पष्ट प्रवर्तन नीति और संस्थागत ढांचे की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप, 5 अप्रैल 2016 को वर्ष 2016-17 की प्रथम द्विमासिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के क्रम में, वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (BFS/ बीएफएस) ने अनुपालन न करने वाले विनियमित संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई हेतु एक पर्यवेक्षी प्रवर्तन ढांचा स्वीकृत किया, जिसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के साथ-साथ पारदर्शिता, संगति, कठोरता और समयबद्धता का पालन सुनिश्चित किया गया। हालाँकि यह ढांचा मूल रूप से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई करने के लिए बनाया गया था, वर्ष 2016-17 की छठी द्विमासिक नीति वक्तव्य में 8 फरवरी 2017 को की गई घोषणा के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक में 3 अप्रैल 2017 को एक पृथक प्रवर्तन विभाग (EFD) की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किए गए उल्लंघनों की पहचान और प्रक्रिया को एक संरचित, नियम-आधारित दृष्टिकोण के साथ लागू करना था। इसके बाद, प्रवर्तन विभाग को शहरी सहकारी बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, आवास वित्त कंपनियों, क्रेडिट सूचना कंपनियों और भुगतान प्रणाली संचालकों के खिलाफ भी प्रवर्तन कार्रवाई करने और इसे विनियमित संस्थानों में समान रूप से लागू करने का दायित्व सौंपा गया। नीचे दिए गए बॉक्स में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ में प्रचलित प्रवर्तन ढांचों की तुलना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थानों के प्रवर्तन ढांचे से की गई है।

अंतरराष्ट्रीय अनुभव

संयुक्त राज्य अमेरिका में, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस (FDI) अधिनियम और फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (FDIC) के नियम और विनियम, वित्तीय संस्थानों के सुधार, पुनर्प्राप्ति और प्रवर्तन अधिनियम (FIRREA), 1989 और अमेरिकी नागरिक संहिता कुछ ऐसे कानून हैं जो वित्तीय क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं। पर्यवेक्षी और प्रवर्तन शक्तियां संघीय और राज्य स्तर पर विभिन्न एजेंसियों के अलावा चार प्रमुख एजेंसियों के बीच विभाजित हैं, अर्थात् फेडरल रिज़र्व सिस्टम (Federal Reserve) के गवर्नर्स बोर्ड, एफडीआईसी (FDIC), नियंत्रक कार्यालय (OCC) और उपभोक्ता वित्तीय सुरक्षा ब्यूरो (CFPB)। इसके अतिरिक्त, न्याय विभाग (DoJ) आपराधिक अपराधों और प्रतिस्पर्धा विरोधी कृत्यों से संबंधित दुराचार को प्रवर्तित करता है। उल्लंघनों को उनके गंभीरता के आधार पर तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: श्रेणी 1, श्रेणी 2 और श्रेणी 3, और प्रवर्तन कार्रवाई में सार्वजनिक बयानों, निषेध आदेशों, प्राधिकरण की वापसी, प्रबंधन पर अस्थायी प्रतिबंध, मौद्रिक दंड और आपराधिक दंड जैसी गैर-मौद्रिक कार्रवाइयां शामिल हैं।

यूरोपीय संघ (EU/ ईयू) में बैंकिंग पर्यवेक्षण एकल पर्यवेक्षी तंत्र (सिंगल सुपरवाइजरी मेकानिज़्म) द्वारा किया जाता है, जो यूरोपीय संघ के बैंकिंग यूनियन के दो स्तंभों में से एक है, दूसरा एकल समाधान तंत्र (सिंगल रेजोल्यूशन मेकानिज़्म) है। यह तंत्र यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB/ ईसीबी) और भाग लेने वाले सदस्य देशों के राष्ट्रीय सक्षम प्राधिकरणों (NCA/ एनसीए) से मिलकर बना है। ईसीबी और एनसीए का पर्यवेक्षी क्षेत्र संस्था के वर्गीकरण के आधार पर निर्धारित होता है, जैसे कि प्रमुख संस्थाओं की निगरानी ईसीबी द्वारा की जाती है और कम महत्वपूर्ण संस्थाओं की एनसीए द्वारा। उल्लंघन की प्रकृति (ईयू कानून, ईसीबी विनियम और निर्णय या राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन) के आधार पर मौद्रिक दंड ईसीबी या एनसीए द्वारा लगाया जा सकता है। यह दंड उल्लंघन के कारण अर्जित लाभ या बचाई गई हानि की राशि का दो गुना तक, या पिछले व्यापार वर्ष में प्रमुख संस्थान के कुल वार्षिक कारोबार का 10 प्रतिशत तक हो सकता है। यह दंड प्रभावशीलता, अनुपातिकता और विघटनशीलता के सिद्धांतों पर आधारित होता है, जिसमें उल्लंघन की गंभीरता और उग्र और शमनकारी परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता है। नियमावली में यह भी प्रावधान है कि उल्लंघन की तिथि से कितने समय के भीतर दंड लगाने का निर्णय लिया जाना चाहिए और कितने समय के भीतर दंड वसूला जाना चाहिए।

प्रवर्तन विभाग का प्रमुख कार्य और अधिदेश

प्रवर्तन विभाग का मुख्य कार्य विनियमों को सभी विनियमित संस्थाओं के लिए समान रूप से लागू करना है, ताकि इन संस्थाओं द्वारा उच्च स्तर का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। यह कार्य वित्तीय स्थिरता, सार्वजनिक हित, और उपभोक्ता संरक्षण की व्यापक सिद्धांतों के तहत किया जाता है। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) द्वारा अनुमोदित प्रवर्तन नीति ढांचे में प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान निष्पक्षता, स्थिरता और गैर-पक्षपाती रवैया अपनाने पर जोर दिया गया है।

प्रारंभ में, वाणिज्यिक बैंकों के प्रणालीगत महत्व को ध्यान में रखते हुए, प्रवर्तन विभाग को बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 47ए के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किए गए उल्लंघनों पर मौद्रिक दंड लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई

थी। इसके साथ ही धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत उन उल्लंघनों पर भी कार्रवाई की जाती है, जिन पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम के तहत निर्देश जारी किए हैं।

तत्पश्चात, 3 अक्टूबर 2018 से सहकारी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC/एनबीएफसी) से संबंधित प्रवर्तन कार्यों को भी प्रवर्तन विभाग के अधिकार क्षेत्र में लाया गया। इसके उपरांत, वित्त (संख्या 2) अधिनियम 2019 के तहत 9 अगस्त 2019 से राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 में संशोधन किया गया, और इसके साथ ही आवास वित्त कंपनियों (HFC/एचएफसी) के विनियमन और उन पर प्रवर्तन कार्य भी भारतीय रिज़र्व बैंक को हस्तांतरित कर दिया गया।

दिनांक 28 जून 2022 से क्रेडिट सूचना कंपनियों (CIC/सीआईसी) के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई को भी प्रवर्तन विभाग के अधिदेश में शामिल कर लिया गया। इसके अलावा, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के तहत मौद्रिक दंड और संकलन संबंधी प्रवर्तन कार्यों को 1 अप्रैल 2023 से प्रवर्तन विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया।

सहकारी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) सहित बड़ी संख्या में संस्थाओं के विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाई करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, परिचालन कुशलता और केंद्रित प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए मई 2019 में भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, नागपुर और नई दिल्ली में प्रवर्तन विभाग क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गए। तदनुसार, कुछ विनियमित संस्थाओं के विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाई करने के अधिकार प्रवर्तन विभाग क्षेत्रीय कार्यालयों को भी सौंपे गए हैं। हालांकि, यह महत्वपूर्ण है कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 और सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 के तहत उल्लंघनों पर मौद्रिक दंड लगाने से संबंधित प्रवर्तन कार्रवाई, साथ ही उल्लंघनों को संकलित करने जैसी अन्य विनियामक या पर्यवेक्षी कार्रवाइयां अभी भी संबंधित विनियामक/पर्यवेक्षी विभागों द्वारा ही की जाती हैं।

प्रवर्तन नीति और उद्देश्य

प्रवर्तन विभाग के लिए प्राथमिक भूमिका एक व्यापक प्रवर्तन नीति विकसित करना था। तदनुसार, 9 अक्टूबर 2017 को 'प्रवर्तन नीति रूपरेखा' का प्रालेख तैयार किया गया और वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसके बाद, सहकारी बैंकों और एनबीएफसी को शामिल करने के लिए प्रवर्तन विभाग के अधिकार क्षेत्र का विस्तार और अन्य अधिनियमों को शामिल करने के लिए इसके दायरे में वृद्धि के साथ, उपरोक्त नीति को उपयुक्त रूप से संशोधित और अद्यतन किया गया। इस संशोधित नीति को 25 सितंबर 2019 को बीएफएस द्वारा अनुमोदित किया गया और बाद में 13 दिसंबर 2019 को केंद्रीय बोर्ड के समक्ष जानकारी के लिए प्रस्तुत किया गया।

इस नीति का उद्देश्य विभिन्न क़ानूनों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी नियमों/निर्देशों के अनुपालन को और अधिक सुनिश्चित करना है। नीति के अंतर्गत प्रवर्तन कार्रवाई का प्रारंभ पर्यवेक्षी विभागों द्वारा भेजी गई निरीक्षण रिपोर्टों और जांच रिपोर्टों, अन्य विभागों से प्राप्त बाजार खुफिया रिपोर्टों, और भारतीय रिज़र्व बैंक के शीर्ष प्रबंधन के संदर्भों के आधार पर किया जाना है। प्रवर्तन कार्रवाई भली-भांति परिभाषित सिद्धांतों जैसे महत्वपूर्णता, अनुपातिकता और उद्देश्य के आधार पर की जाती है, जिन्हें सभी संस्थाओं पर समान रूप से लागू किया जाता है, जिससे मनमानी और विवेकाधिकार को कम किया जा सके (उद्देश्यपूर्ण, स्थिर और पूर्वानुमेय)। जिन उल्लंघनों की आवृत्ति अधिक होती है और जिनका प्रणालीगत प्रभाव अधिक होता है, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाती है (उत्तरदायी, जोखिम-केंद्रित और अनुपातिक)।

प्रवर्तन का दायरा

यद्यपि विभिन्न क़ानून भारतीय रिज़र्व बैंक को मौद्रिक और गैर-मौद्रिक प्रतिबंध लगाने का अधिकार देते हैं, प्रवर्तन नीति उन उल्लंघनों को संबोधित करती है जिन पर मौद्रिक दंड लगाया जा सकता है। ऐसे उल्लंघन, जिन पर मौद्रिक दंड या दंडात्मक ब्याज से इतर कार्रवाई की आवश्यकता होती है, उनका प्रवर्तन संबंधित नियामक और पर्यवेक्षी विभागों द्वारा किया जाएगा। प्रवर्तन नीति का उद्देश्य न तो व्यक्तिगत उपभोक्ता शिकायतों से निपटना है और न ही यह शिकायत निवारण की कोई प्रणाली है। इसके अलावा, प्रवर्तन कार्रवाई पर्यवेक्षी अनुपालन प्रक्रिया का विकल्प भी नहीं है।

प्रवर्तन का आधार

निरीक्षण रिपोर्टों, जांच रिपोर्टों और संदर्भों में देखे गए उल्लंघनों को कार्रवाई योग्य और गैर-कार्रवाई योग्य उल्लंघनों में विभाजित किया जाता है। कार्रवाई योग्य उल्लंघनों का निर्धारण निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है: (i) उल्लंघन का तथ्य, और (ii) उल्लंघन की महत्वपूर्णता।

उल्लंघन का तथ्य उस उल्लंघन की पहचान पर आधारित होता है, जिसमें विधिक प्रावधानों और उसके तहत जारी निर्देशों/दिशा-निर्देशों का उल्लंघन शामिल होता है। उल्लंघन की महत्वपूर्णता निम्नलिखित आधारों पर निर्धारित की जाती है:

- i. परिमाण (यानी नियामक सीमा को किस हद तक या किस प्रतिशत तक पार किया गया है; या भले ही यह छोटा प्रतिशत/परिमाण हो, उल्लंघन कितने व्यापक (भौगोलिक) स्तर पर हुआ है, आदि),
- ii. आवृत्ति (एक ही उल्लंघन के कई उदाहरणों की उपस्थिति), और
- iii. उल्लंघन की गंभीरता।

उल्लंघन की गंभीरता का निर्धारण उल्लंघन में शामिल राशि, चाहे वह पूर्णांक हो या व्यावसायिक आकार के अनुपात में, के आधार पर किया जाता है। शमनकारी कारकों के अलावा, उग्र कारक जैसे बार-बार या लगातार होने वाले उल्लंघन, अनुपालन रिपोर्ट, यदि कोई हो, में दिया गया झूठा अनुपालन, इत्यादि को भी महत्वपूर्णता निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखा जाता है।

प्रवर्तन प्रक्रिया

प्रवर्तन प्रक्रिया एक अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया है। इसलिए, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करने के लिए, यह विनियमित संस्थाओं को कारण बताओ नोटिस जारी करने और उसे लिखित रूप से तथा अनुरोध करने पर मौखिक रूप से सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने का प्रावधान करता है। एक न्यायनिर्णय समिति, जो केंद्रीय कार्यालय में तीन कार्यपालक निदेशकों (जिसमें केंद्रीय कार्यालय में प्रवर्तन विभाग के प्रभारी कार्यपालक निदेशक भी शामिल होते हैं) और क्षेत्रीय कार्यालय में क्षेत्रीय निदेशक एवं दो वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर बनी होती है, इस मामले का निर्णय करती है। यह समिति विनियमित संस्था को प्रवर्तन कार्रवाई और उसके कारणों का उल्लेख करते हुए, अच्छी तरह से व्याख्यायित आदेश जारी करती है।

हालांकि उल्लंघन के लिए लगाए जा सकने वाले अधिकतम दंड की राशि संबंधित कानूनों में निर्धारित की गई है, प्रत्येक

मामले में लगाए जाने वाले दंड की राशि सीमा के भीतर गुण-दोष के आधार पर, अनुपात, मंशा, और शमनकारी कारकों, यदि कोई हों, के अनुसार तय की जाती है। लगाया गया दंड विनियमित संस्थाओं द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर चुकाना होता है जैसा कि संबंधित कानूनों में प्रावधान किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के पास न्यायनिर्णय समिति के आदेश के खिलाफ कोई अपील सुनने या आदेश की समीक्षा करने का अधिकार नहीं है, सिवाय उन मामलों के जहां सारफेसी अधिनियम के तहत मौद्रिक दंड लगाया गया हो। प्रवर्तन कार्रवाई के विवरण प्रेस विज्ञप्तियों और भारतीय रिज़र्व बैंक की विभिन्न प्रकाशनों के माध्यम से सार्वजनिक किए जाते हैं।

निष्कर्ष

एक प्रभावी, सुसंगत और पूर्वानुमेय प्रवर्तन ढांचा एक विश्वसनीय बैंकिंग/वित्तीय नियामक और पर्यवेक्षी प्रणाली के लिए अनिवार्य है। प्रवर्तन कार्रवाई का विनियमित संस्थाओं के लिए आर्थिक और प्रतिष्ठागत रूप से निवारक प्रभाव होता है, और इसका अन्य विनियमित संस्थाओं पर भी अनुकरणीय प्रभाव पड़ता है। विभिन्न अध्ययन यह सुझाव देते हैं कि प्रवर्तन कार्रवाई केवल दंडित संस्थाओं के व्यवहार में सुधार लाने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह उन संस्थाओं पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है जिन्हें दंडित नहीं किया गया है।²⁷

वर्तमान में, भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रवर्तन कार्रवाई के तहत केवल विनियमित संस्थाओं पर मौद्रिक दंड लगाने का अधिकार प्राप्त है, उन व्यक्तियों पर नहीं जो इन संस्थाओं के प्रभारी होते हैं या उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार होते हैं। प्रवर्तन औपचारिक हो सकता है, जो पर्यवेक्षी प्रक्रिया का हिस्सा होते हुए अनुपालन सुनिश्चित करने या संस्थाओं/व्यक्तियों पर दंड लगाने के रूप में होता है; या यह अनौपचारिक हो सकता है, जो नियामक द्वारा जारी स्पष्टीकरण/सावधान परामर्श के रूप में होता है। प्रवर्तन के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण में दोनों तत्व शामिल होते हैं, जहां निरंतर/दोहराए जाने वाले उल्लंघनों पर अनुकरणीय कार्रवाई की जाती है।

²⁷ मंथोस डी. डेलिस, पनागियोटिस के. स्टाइकौरस, क्रिस त्सौमास (2016) औपचारिक प्रवर्तन क्रियाएँ और बैंक व्यवहार। प्रबंधन विज्ञान 63(4):959-987।

अध्याय 12: वित्तीय बाजारों का विकास और विनियमन

वित्तीय बाजार, बाजार-उन्मुख नीतिगत वातावरण में केंद्रीय बैंक द्वारा मौद्रिक नीति संकेतों को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में वित्तीय बाजार, जो मुख्य रूप से मुद्रा बाजार, सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार और इक्विटी बाजार से मिलकर बनते हैं, मुख्यतः बैंक-केंद्रित वित्तीय प्रणाली की रूपरेखा के भीतर विकसित हुए हैं। 1990 के दशक की शुरुआत में वित्तीय क्षेत्र में सुधार शुरू होने के बाद, और बैंकिंग विनियमों को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाए जाने के बाद, विभिन्न बाजार घटकों को व्यापक बाजार विकास एजेंडा के तहत धीरे-धीरे पेश किया गया। इस एजेंडा का मुख्य ध्यान आवश्यक बाजार सूक्ष्मसंरचना (माइक्रोस्ट्रक्चर) विकसित करने पर था, जिसमें संस्थान, प्रौद्योगिकी, बाजार सहभागी और उपयुक्त विनियम शामिल थे।

जबकि इक्विटी बाजार मुख्य रूप से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा विनियमित है, भारतीय रिज़र्व बैंक मुद्रा बाजार, सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार और संबंधित डेरिवेटिव बाजारों (जिसमें क्रेडिट डेरिवेटिव शामिल हैं) को आरबीआई अधिनियम, 1934 के अध्याय III डी के प्रावधानों के तहत विनियमित करता है। ये बाजार मुख्य रूप से ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) प्रकृति के होते हैं।

जहां तक एक्सचेंज-ट्रेडेड उपकरणों का संबंध है, जो बाजार की पारदर्शिता बढ़ाने, मूल्य खोज प्रक्रिया में सुधार करने और व्यापक खुदरा भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ओटीसी उत्पादों का पूरक होते हैं, आरबीआई ऐसे उपकरणों की शुरुआत के लिए नियामक ढांचा जारी करता है। इसके बाद सेबी एक्सचेंज पर ट्रेड के निष्पादन और निपटान की प्रक्रिया से संबंधित परिचालन निर्देश जारी करता है, जो आरबीआई अधिनियम की धारा 45 डबल्यू के प्रावधानों के अनुसार होता है।

इन बाजारों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक विकासात्मक और नियामक दोनों भूमिकाएं निभा रहा है। विकासात्मक भूमिका बाजारों के व्यवस्थित विकास को सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है, जबकि नियामक भूमिका बाजार की अखंडता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त सतर्कता और आचरण संबंधी विनियम तैयार करने पर केंद्रित है।

पिछले वर्षों में वित्तीय बाजारों को विकसित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रयासों ने एक अधिक आत्मविश्वासी और आकांक्षी अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया है। सुधार प्रयासों ने (i) पूंजी जुटाने को अधिक कुशल बनाया है; (ii) ऑनशोर और ऑफशोर बाजारों के बीच विभाजन को समाप्त किया है; (iii) बाजारों तक पहुंच को आसान बनाकर भागीदारी का आधार विस्तारित किया है; (iv) उत्पादों की एक बड़ी श्रृंखला के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा दिया है; (v) बाजार और बाजार अवसंरचना की अखंडता और लचीलेपन को सुनिश्चित किया है; और (vi) बाजार सहभागियों द्वारा निष्पक्ष आचरण सुनिश्चित किया है।

इन नियामक पहलों के कारण, वित्तीय बाजारों में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। इसके परिणामस्वरूप बाजार सहभागियों की व्यापक श्रेणी और व्यापारिक मात्रा (तरलता) में वृद्धि हुई है। बढ़ती भागीदारी के साथ, यह सुनिश्चित करने के लिए बेहतर बाजार निगरानी की आवश्यकता है कि सहभागी निष्पक्ष आचरण के सिद्धांतों का पालन करें। पिछले कुछ वर्षों से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बाजार प्रतिनिधि निकायों, जैसे कि फिक्स्ड इनकम, मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए), फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स' एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफईडीआई) और प्राइमरी डीलर्स' एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पीडीआई) को अधिक ज़िम्मेदारियां सौंपी हैं। इन निकायों को विभिन्न बाजार खंडों के विकास और स्व-विनियामक तंत्र स्थापित करने, जिसमें आचरण संहिताएं, दलालों की निगरानी और व्यापारिक विवादों के निपटान के लिए मध्यस्थता शामिल हैं, का कार्य सौंपा गया है। बैंक ने एक स्वतंत्र बेंचमार्क प्रशासक, फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) की स्थापना को भी सुविधाजनक बनाया है, जिसे एफआईएमएमडीए, एफईडीआई और इंडियन बैंक्स' एसोसिएशन (आईबीए) द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया। एफबीआईएल को मनी, जी-सेक, विदेशी मुद्रा बाजार और संबंधित डेरिवेटिव बाजारों से जुड़े प्रमुख वित्तीय बेंचमार्क का नियंत्रण करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।

पिछले कई वर्षों में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने मजबूत वित्तीय बाजार अवसंरचनाओं की स्थापना के लिए कई कदम उठाए हैं। एक प्रमुख मील का पत्थर जो 2001 में स्थापित हुआ, वह है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) की स्थापना, जिसने फरवरी 2002 में अपना संचालन शुरू किया। सीसीआईएल को जी-सेक, मनी मार्केट और विदेशी मुद्रा लेन-देन की क्लियरिंग और निपटान के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया था। अपनी शुरुआत से ही, सीसीआईएल ने अपनी गतिविधियों का विस्तार करके कई कैश बाजार और डेरिवेटिव उत्पादों में केंद्रीय काउंटर पार्टी (सीसीपी) आधारित निपटान को शामिल किया है और इसके साथ ही सभी ओटीसी विदेशी मुद्रा, ब्याज दर और क्रेडिट डेरिवेटिव्स के लिए एक ट्रेड रिपोजिटरी भी स्थापित की है।

बाजार विकास और विनियमन के प्रति अधिक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए, वित्तीय बाजार विनियमन विभाग (एफएमआरडी) नामक एक नया विभाग, जिसे अन्य विभागों के कार्य-संचालनों को अलग करते हुए स्थापित किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय बाजारों से संबंधित मुख्य विकासात्मक और विनियामक कार्यों का विवरण नीचे दिया गया है:

मुद्रा बाजार

मनी मार्केट, अल्पावधि वित्तीय संपत्तियों का बाजार है, जो धन का निकटतम विकल्प माना जाता है। मनी मार्केट, निधियों की अल्पावधि मांग और आपूर्ति को संतुलित करने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करता है, जिससे मौद्रिक नीति के संचालन में सहायता मिलती है। एक स्वतंत्र रूप से संचालित मनी मार्केट, वित्तीय बाजारों की वर्तमान और विकसित हो रही स्थितियों का एक संवेदनशील बैरोमीटर होता है और उधारदाताओं द्वारा लघु अवधि के अधिशेष निधियों का प्रबंधन और उधारकर्ताओं द्वारा लघु अवधि की वित्तीय कमी का प्रबंधन करने में सहायता करता है।

भारत में, मनी मार्केट और इसकी संरचना को मजबूत करना, वित्तीय क्षेत्र सुधार के समग्र अविनियमन प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा रहा। मनी मार्केट में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण विकासात्मक और नियामक भूमिकाएँ निम्नलिखित हैं:

विकासात्मक भूमिका

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विभिन्न सुधारों और नवाचारों के माध्यम से भारतीय मनी मार्केट के विकास को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा दिया। 1989 में इसने अंतर-बैंक कॉल/नोटिस मनी पर ब्याज दर की सीमा को हटाया और 1986 से 1992 के बीच नए उपकरणों जैसे ट्रेजरी बिल (टी-बिल), सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (सीडी), कमर्शियल पेपर (सीपी), और रिपचेज एग्रीमेंट (रेपो) को पेश किया। आरबीआई ने बाजार में भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रवेश की बाधाओं को कम किया, 1988 में डिस्काउंट एण्ड फाइनेंस ऑफ इंडिया (डीएफएचआई) जैसी संस्थाओं की स्थापना की, और प्रमुख एवं साटिलाइट डीलरों को पेश किया।

बाजार-निर्धारित दरों को प्रोत्साहित करने के लिए, आरबीआई ने कैश क्रेडिट से लोन-आधारित प्रणाली में संक्रमण किया और फिक्स्ड-रेट ट्रेजरी बिल्स को समाप्त किया। इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने 1993 में बाजार-आधारित विनिमय दर प्रणाली अपनाने के बाद मनी मार्केट और विदेशी मुद्रा बाजार के बीच संबंध को मजबूत किया। डीएफएचआई ने इन सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि इसने बाजार में सक्रिय भागीदारी की। कुछ

उल्लेखनीय समितियाँ जिनकी सिफारशों ने भारत में वित्तीय बाजारों के विकास को आकार दिया, उनमें चक्रवर्ती समिति (1985), वाघुल समिति (1987) और नरसिंहम्हम समितियाँ (1991 और 1998) शामिल हैं।

मुद्रा बाजार लेन देनों के व्यापार, रिपोर्टिंग, समाशोधन और मुद्रा निपटान को बाजार के विकास के साथ गति बनाए रखने के लिए बाजार अवसंरचना को मजबूत किया। उच्चतम तकनीकी इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्रणालियाँ जैसे नेगोसिएटेड डीलिंग सिस्टम-कॉल (एनडीएस-कॉल), क्लियरकॉर्प रेपो ऑर्डर मैचिंग सिस्टम (सीआरओएमएस), ट्रिपार्टी रेपो डीलिंग सिस्टम (टीआरडीपीएस), लेनदेन की स्ट्रेट-थ्रू-प्रोसेसिंग (एसटीपी), रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस), और सीसीआईएल का निर्माण जो सुनिश्चित निपटान के लिए था, ये सभी कदम समय के साथ उठाए गए थे। वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, प्राइमरी डीलर्स (पीडी), बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंड्स, नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (एनबीएफसी) जैसी वित्तीय संस्थाओं के अलावा, आरबीआई ने कंपनियों को मुद्रा बाजार के संपार्श्विक क्षेत्रों में भाग लेने की अनुमति दी।

अन्य महत्वपूर्ण विकासात्मक उपायों में शामिल हैं: (i) री-रेपो और ट्राइ-पार्टी रेपो की शुरुआत; (ii) मुंबई इंटर-बैंक आउट-राइट रेट (एमआईबीओआर) के निर्धारण प्रक्रिया को मजबूत करना; और (iii) कॉल/नोटिस/टर्म मनी मार्केट में नए प्रवेशकों जैसे भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को उधारकर्ता और उधारदाता दोनों के रूप में भाग लेने की अनुमति देना।

विनियामक भूमिका

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विभिन्न मनी मार्केट उपकरणों जैसे कॉल/नोटिस/टर्म मनी, रेपो, वाणिज्यिक पत्र (सीपी), जमा प्रमाणपत्र (सीडी), मूल या प्रारंभिक परिपक्वता अवधि एक वर्ष तक की गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर्स (एनसीडी), और मनी मार्केट ब्याज दर/बेंचमार्क से जुड़े व्युत्पन्न उत्पादों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित किए हैं।

कॉल, नोटिस और टर्म मनी

कॉल, नोटिस, और टर्म मनी का तात्पर्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), लघु वित्त बैंकों (एसएफबी), भुगतान बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), सहकारी बैंकों, और प्राथमिक डीलरों (पीडी) के बीच बिना संपार्श्विक के धन उधार लेने और देने से है। ये लेनदेन इन संस्थाओं के लिए एक प्रमुख तरलता प्रबंधन उपकरण के रूप में कार्य करते हैं।

कॉल मनी, एक दिन के लिए उधार/ऋण लेनदेन के लिए है, नोटिस मनी, दो से चौदह दिनों की अवधि के लिए है और टर्म मनी, पंद्रह दिनों से लेकर एक वर्ष तक की अवधि के लिए होता है।

ये लेनदेन ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) और सीसीआईएल द्वारा प्रबंधित इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम, एनडीएस-कॉल पर किए जाते हैं। ओटीसी लेनदेन को निष्पादन के बाद एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर एनडीएस-काल प्लेटफ़ॉर्म पर रिपोर्ट करना अनिवार्य है। प्रतिभागियों को कॉल, नोटिस और टर्म मनी मार्केट में बकाया ऋण लेनदेन के लिए अपने स्वयं के बोर्ड की मंजूरी और आरबीआई के नियामक ढांचे के भीतर अपनी सीमाएं तय करने की अनुमति है। उधारी के लिए, एससीबी (छोटे वित्त और भुगतान बैंकों को छोड़कर) अपनी आंतरिक बोर्ड-अनुमोदित दिशानिर्देशों के साथ, इंटर-बैंक देनदारियों के लिए प्रूडेंशियल सीमाओं के अनुरूप अपनी सीमाएं तय कर सकते हैं। आरबीआई ने एसएफबी, भुगतान बैंकों, आरआरबी, सहकारी बैंकों, और पीडी के लिए बकाया उधारी लेनदेन की विशिष्ट विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित की हैं।

पुनर्खरीद समझौता (रेपो) बाजार

रेपो एक ऐसा साधन है जिसमें फंड उधार (लेंडिंग) देने के लिए प्रतिभूतियों (सिक्योरिटीज) को बेचकर (खरीदकर) भविष्य की एक सहमत तारीख पर सहमत मूल्य पर फिर से खरीदने (बेचने) का समझौता किया जाता है, जिसमें उधार लिए (दिए) गए फंड पर ब्याज शामिल होता है। मूल रूप में, रेपो प्रतिभूतियों के खिलाफ अल्पकालिक संपार्श्विक उधार है। यह लेनदेन उधारकर्ता (सिक्योरिटी का विक्रेता) के दृष्टिकोण से रेपो कहलाता है और फंड के प्रदाता (सिक्योरिटी का खरीदार) के दृष्टिकोण से रिवर्स रेपो कहलाता है।

जो रेपो भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ किए जाते हैं, उन्हें 'लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी (एलएएफ)-रेपो' कहा जाता है, जबकि जो बाजार के प्रतिभागियों के बीच किए जाते हैं, वे 'मार्केट रेपो' के नाम से जाने जाते हैं। वर्तमान में, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी सरकारी प्रतिभूतियां, ट्रेजरी बिल्स, वाणिज्यिक पत्र (कॉमर्शियल पेपर्स), जमा प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट), डेट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) की यूनिट्स, और

सूचीबद्ध कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और डिबेंचर्स को मार्केट रेपो के लिए पात्र प्रतिभूतियों के रूप में अनुमति दी गई है। मार्केट रेपो में भाग लेने वाले प्रतिभागियों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक , प्राइमरी डीलर्स (पीडी), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी), हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां (एचएफसी), अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (एआईएफआई), बीमा कंपनियां, सूचीबद्ध और असूचीबद्ध कंपनियां आदि शामिल हैं, जो कुछ शर्तों के अधीन होती हैं।

रेपो लेनदेन को किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ईटीपी) या ओवर-द-काउंटर बाजार में किया जा सकता है। वर्तमान में सरकारी प्रतिभूतियों पर रेपो लेनदेन आमतौर पर सीसीआईएल के गुमनाम क्रामस पर, टीआरईपीएस या ओटीसी के माध्यम से होते हैं। सरकारी प्रतिभूतियों पर ओटीसी रेपो लेनदेनों को निष्पादन के बाद निर्धारित समय सीमा के भीतर क्रोमस पर रिपोर्ट करना आवश्यक है। रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियों को अनुबंध की अवधि के दौरान नहीं बेचा जा सकता, सिवाय उन संस्थाओं के जिन्हें शॉर्ट सेलिंग की अनुमति है। रिवर्स रेपो के तहत प्राप्त प्रतिभूतियों में पुनः रेपो की अनुमति है।

ट्राई-पार्टी रेपो एक ऐसा रेपो अनुबंध है जहां उधारकर्ता और उधारदाता के अलावा तीसरा पक्ष (जिसे ट्राई-पार्टी एजेंट कहा जाता है) लेनदेन को सरल बनाने के लिए एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। ट्राई-पार्टी एजेंट संपार्श्विक चयन, भुगतान और निपटान, कस्टडी और लेनदेन की अवधि के दौरान प्रबंधन जैसी सेवाएं प्रदान करता है। ट्राई-पार्टी रेपो के मामले में, आरबीआई ने उत्पाद के विभिन्न पहलुओं, पात्रता मानदंड और ट्राई-पार्टी एजेंट की भूमिकाओं और दायित्वों को निर्दिष्ट किया है।

जुलाई 2018 में, सरकारी प्रतिभूतियों और कॉर्पोरेट ऋण पर रेपो के लिए व्यापक निर्देश जारी किए गए थे ताकि विभिन्न प्रकार के संपार्श्विक के लिए विनियमों को सरल और सामंजस्यपूर्ण बनाया जा सके और विशेष रूप से कॉर्पोरेट ऋण रेपो में व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके। कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों के एक सक्रिय बाजार को विकसित करने के उद्देश्य से, आरबीआई ने एएमसी रेपो क्लियरिंग लिमिटेड को ट्राई-पार्टी रेपो एजेंट के रूप में कार्य करने और कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में ट्राई-पार्टी रेपो उपलब्ध कराने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता के सीपी और एनसीडी

वाणिज्यिक पत्र (सीपी) एक असुरक्षित मुद्रा बाजार उपकरण है जिसे एक प्रतिज्ञा पत्र के रूप में जारी किया जाता है, जबकि गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) एक सुरक्षित मुद्रा बाजार उपकरण है, जिसकी मूल या प्रारंभिक परिपक्वता एक वर्ष तक की होती है। ये उपकरण उच्च श्रेणीबद्ध कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं को अपने अल्पकालिक उधार स्रोतों में विविधता लाने और निवेशकों को अतिरिक्त साधन प्रदान करने की अनुमति देते हैं। निम्नलिखित संस्थाएं सीपी और एनसीडी जारी कर सकती हैं, बशर्ते कि उन्होंने बैंकों/ एआईएफआई/ एनबीएफसी से जो भी फंड-आधारित सुविधाएं ली हों, वे जारी करने के समय "स्टैंडर्ड" के रूप में वर्गीकृत हों:

- (a) कंपनियां
- (b) एनबीएफसी, जिसमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां (HFCs) शामिल हैं
- (c) इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स
- (d) ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस
- (e) कोई अन्य निकाय कॉर्पोरेट जिसकी न्यूनतम नेट-वर्थ ₹100 करोड़ हो, बशर्ते वह निकाय भारत में ऋण लेने या ऋण उपकरण जारी करने के लिए वैधानिक रूप से अनुमत हो
- (f) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेष रूप से अनुमत कोई अन्य इकाई
- (g) सहकारी समितियां और सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी।) जिनकी न्यूनतम नेट-वर्थ ₹100 करोड़ हो, सीपी। जारी कर सकती हैं, बशर्ते कि उन्होंने बैंकों/ एआइएफआइ/ एनबीएफसी से जो भी फंड-आधारित सुविधाएं ली हों, वे जारी करने के समय "स्टैंडर्ड" के रूप में वर्गीकृत हों।

सीपी/एन सी डी जारी करते समय, उपयोग की जाने वाली निधि का उद्देश्य प्रस्ताव दस्तावेज़ में स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। सीपी और एनसीडी के जारी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग, सेबी द्वारा निर्धारित रेटिंग प्रतीक और परिभाषा के अनुसार, 'ए3' होनी चाहिए। सीपी और एन सी डी के सभी प्राथमिक जारीकरण और इन उपकरणों के ओटीसी।व्यापार को सीसीआइएल के फाइनेंशियल मार्केट ट्रेड रिपोर्टिंग एंड कन्फर्मेशन प्लेटफॉर्म ("एफ-टीआरएसी।") पर निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर रिपोर्ट करना आवश्यक है। जारीकर्ता, जारी और भुगतान एजेंट (आईपीए), डिबेंचर ट्रस्टी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (सीआरए) के कर्तव्य और उत्तरदायित्व आरबीआई के दिशा-निर्देशों में उल्लिखित हैं।

जमा प्रमाणपत्र (सीडी):

सीडी एक परक्राम्य, असुरक्षित मुद्रा बाजार उपकरण है, जिसे एक बैंक/एआइएफआइ द्वारा उस बैंक या एआइएफआइ में निर्दिष्ट समय अवधि के लिए जमा धन के खिलाफ एक उपयोग प्रॉमिसरी नोट के रूप में जारी किया जाता है। सीडी निम्नलिखित द्वारा जारी किए जा सकते हैं:

- a. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी और एसएफबी सहित)
- b. एआइएफआइ जिन्हें आरबीआई द्वारा निर्धारित छत्र सीमा के भीतर अल्पकालिक संसाधन जुटाने की अनुमति दी गई है।

बैंकों द्वारा जारी सीडी की परिपक्वता अवधि 7 दिन से कम और 1 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि एआइएफआइ द्वारा सीडी की परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से कम और 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। सीडी के खिलाफ ऋण प्रदान करना बैंकों/एआइएफआइ के लिए तब तक प्रतिबंधित है, जब तक कि आरबीआई द्वारा विशेष रूप से अनुमति न दी गई हो। सीडी के सभी प्राथमिक जारीकरण और ओटीसी व्यापार को सीसीआइएल के एफ-टीआरएसी प्लेटफॉर्म पर निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर रिपोर्ट करना आवश्यक है।

सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) का बाजार:

जी-सेक बाजार किसी भी वित्तीय प्रणाली का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण खंड है। जी-सेक बाजार अन्य वित्तीय बाजारों से एक बुनियादी तरीके से भिन्न है – यह वह बाजार है, जिसमें जोखिम-मुक्त ब्याज दर, एक प्रमुख मैक्रोइकोनॉमिक वेरिएबल, निर्धारित होती है। जी-सेक यील्ड्स अधिकांश वित्तीय संपत्तियों की कीमत निर्धारण के लिए बेंचमार्क के रूप में कार्य करती हैं। यह वह बाजार है, जहां सरकार द्वारा जारी किए गए ऋण उपकरण, जैसे ट्रेजरी बिल, सरकारी बॉन्ड और अन्य प्रतिभूतियों का व्यापार होता है।

इन प्रतिभूतियों को सरकार द्वारा अपने खर्चों, जैसे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, सामाजिक कार्यक्रमों और अन्य सार्वजनिक सेवाओं के वित्तपोषण के लिए धन जुटाने के लिए जारी किया जाता है। इस बाजार के प्राथमिक खंड का विकास सार्वजनिक ऋण प्रबंधकों को जोखिमों के उपयुक्त विचार के साथ, बाजार से लागत प्रभावी तरीके से धन जुटाने की अनुमति देता है। जी-सेक बाजार का एक मजबूत द्वितीयक बाजार मौद्रिक नीति के प्रभावी कार्यान्वयन में मदद करता है, जैसे कि खुले बाजार परिचालन (ओएमओ) के माध्यम से, जो कि पैसे की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है। जी-सेक बाजार को निश्चित आय प्रतिभूति बाजारों की नींव माना जाता है, क्योंकि यह बेंचमार्क यील्ड कर्व प्रदान करता है और अन्य वित्तीय बाजारों में तरलता बढ़ाता है। एक कुशल सरकारी प्रतिभूति बाजार की उपस्थिति को कॉर्पोरेट ऋण बाजार के विकास के लिए एक आवश्यक पूर्व शर्त माना जाता है।

जी-सेक बाजार की कुछ अन्य विशिष्ट विशेषताएँ भी हैं। पहला, वैश्विक रूप से जी-सेक बाजार मुख्य रूप से एक संस्थागत बाजार है, जिसमें प्रमुख भागीदार बैंक और दीर्घकालिक निवेशक होते हैं, जैसे निवेश फंड, बीमा फंड, और पेंशन फंड। दूसरा, विभिन्न जी-सेक उपकरण काफी हद तक एक-दूसरे के स्थानापन्न होते हैं, और इनका मुख्य भिन्नता कारक केवल उनके उपकरणों की परिपक्वता अवधि (टेन्योर) होता है। यही एक कारण है कि G-Sec यील्ड कर्व को सार्वजनिक संपत्ति के रूप में देखा जा सकता है। तीसरा, जी-सेक भुगतान और निपटान प्रणालियों, तरलता प्रबंधन कार्यों और अन्य वित्तीय क्षेत्र के लेन-देन के लिए उच्च गुणवत्ता वाले संपार्श्विक (कोलेटरल) के रूप में सबसे अधिक उपयोग किए जाते हैं। चौथा, लगभग सभी मौद्रिक संचालन जी-सेक बाजार में ही किए जाते हैं। किसी भी बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में प्रभावी मौद्रिक नीति संचरण एक कुशल G-Sec बाजार से मौलिक रूप से जुड़ा होता है। जी-सेक को केंद्रीय सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों दोनों द्वारा जारी किया जा सकता है। भारत में, केंद्रीय सरकार ट्रेजरी बिल और बॉन्ड (या डेटेड सिक्योरिटीज) दोनों जारी करती है, जबकि राज्य सरकारें केवल बॉन्ड (या डेटेड सिक्योरिटीज) जारी करती हैं, जिन्हें राज्य सरकार सिक्योरिटीज (एसजीसी) कहा जाता है। दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां दीर्घकालिक सिक्योरिटीज होती हैं (जिनकी मूल परिपक्वता 1 वर्ष से अधिक होती है) और ये एक निश्चित या परिवर्तनीय कूपन (ब्याज दर) रखती हैं, जो इनके फेस वैल्यू पर आधारित होती है और निश्चित समयावधि (आमतौर पर छमाही) में भुगतान की जाती है। डेटेड सिक्योरिटीज की अवधि लंबी हो सकती है (वर्तमान

में, भारत में 50 वर्षों तक)।

आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूति बाजार में निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण विकासात्मक और विनियामक भूमिकाएँ निम्नलिखित हैं:

विकासात्मक भूमिका

भारत में जी-सेक (सरकारी प्रतिभूति) बाजार पहले संकीर्ण था, जिसका मुख्य कारण कम कूपन दरें थीं। इसके अलावा, यह बाजार संस्थागत निवेशकों द्वारा नियंत्रित था, जिन्हें वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करने के लिए सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में अनिवार्य रूप से निवेश करना पड़ता था। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने यह महसूस किया कि एक मजबूत और गतिशील सरकारी प्रतिभूति बाजार ऋण प्रबंधन, नियमन और प्रभावी मौद्रिक और सार्वजनिक ऋण प्रबंधन के लिए अनिवार्य है। वित्तीय क्षेत्र में सुधार की शुरुआत के बाद, आरबीआई ने जी-सेक बाजार के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। सरकारी ऋण के स्वतः मुद्रीकरण की समाप्ति, प्राथमिक जारी करने के लिए नीलामी प्रक्रिया की शुरुआत, और वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 (FRBM) का अधिनियम, इस विकास में सहायक रहे। अप्रैल 2002 से जी-सेक नीलामियों के लिए जारी कैलेंडर की शुरुआत ने आपूर्ति में पारदर्शिता बढ़ाई। नीलामियां इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जाती हैं, जिससे पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित होती है।

2006 में जी-सेक में "व्हेन इश्यूड" (डब्ल्यू आइ।) ट्रेडिंग की अनुमति दी गई, जिससे बड़ी मात्रा के जी-सेक को बाजार में व्यवस्थित रूप से अवशोषित करने का समय मिला और मूल्य खोज प्रक्रिया में सुधार हुआ। फरवरी 2006 में सरकारी प्रतिभूतियों में शॉर्ट सेलिंग की शुरुआत की गई और समय के साथ इसमें बाजार की मांगों के अनुसार सुधार किया गया।

विभिन्न उत्पादों की विविधता सुनिश्चित करने के लिए फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, कैपिटल इंडेक्स्ड बॉन्ड्स, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स, और स्ट्रिप्स (सेपरेट ट्रेडिंग ऑफ रेजिस्टर्ड इन्ट्रेस्ट ऐंड प्रिन्सिपल) सेक्युरिटीज़ जैसे नए उपकरण पेश किए गए। खुदरा निवेशकों के लिए विशेष उत्पादों में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड (सोने में अंकित एक सरकारी प्रतिभूति) और सेविंग्स बॉन्ड शामिल हैं। जी-सेक के रेपो बाजार में तरलता बढ़ाने के लिए आरबीआई ने ईटीपी (इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लैटफॉर्म), अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लेखा-निर्देशों का संशोधन, और री-रेपो की शुरुआत जैसे उपाय किए। साथ ही, बाजार की पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए 2018 में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लैटफॉर्म (ईटीपी) दिशानिर्देश, 2019 में मार्केट एब्यूज की रोकथाम के लिए दिशानिर्देश, और वित्तीय बेंचमार्क प्रशासक दिशानिर्देश जारी किए गए। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, जी-सेक बाजार के लिए कानूनी और नियामक ढांचा विकसित हुआ है, जिससे सार्वजनिक ऋण प्रबंधन और द्वितीयक बाजारों के विकास को गति प्रदान हुई।

एक सुदृढ़, मजबूत और सुरक्षित बाजार संरचना सरकारी प्रतिभूति बाजार को बाहरी झटकों के खिलाफ लचीलापन

बढ़ाती है और मूल्य निर्धारण में योगदान करती है। व्यापार और पोस्ट-ट्रेड सेवाओं के लिए बाजार संरचना, जिसमें क्लियरिंग, सेटलमेंट, रिपोर्टिंग और व्यापारित जानकारी का समय पर प्रसार शामिल है, दोनों आउट-राइट और रेपो बाजारों में, बाजार के विकास के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से विकसित और सुदृढ़ की गई है। इलेक्ट्रॉनिक बोलियां और स्ट्रेट-थ्रू-प्रोसेसिंग क्षमताओं के साथ उन्नत प्राथमिक निर्गमन प्रक्रिया, आरबीआई में पूरी तरह से डिमैटरियलाइज्ड डिपॉजिटरी प्रणाली, डिलीवरी-वरसस-पेमेंट (डीवीपी) मोड के सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम - ऑर्डर मैचिंग) (एनडीएस-ओएम) और सरकारी प्रतिभूतियों के लेन-देन के लिए गारंटी सेटलमेंट हेतु सीसीआईएल में अलग से सीसीपीकी स्थापना, वे सभी पहले हैं जो वर्षों से बैंक द्वारा उठाई गई हैं।

एनडीएस-ओएम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एक गुमनाम स्क्रीन-आधारित आदेश मिलान प्लेटफॉर्म है जो आरबीआई के स्वामित्व में है और सीसीआईएल द्वारा संचालित किया जाता है। यह प्रणाली सभी प्रकार के केंद्रीय सरकारी प्रतिभूतियों, एसजीएस, विशेष प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों में द्वितीयक बाजार व्यापार को सक्षम करती है। अनुमत प्रतिभागी प्रणाली में लॉग इन कर सकते हैं और अपनी बोली/प्रस्ताव दे सकते हैं या पहले से उपलब्ध आदेश पुस्तिका में मौजूदा कोटों को स्वीकार कर सकते हैं। निपटान एसटीपी आधार पर होता है, और सौदे की जानकारी सीधे सीसीआईएल को भेजी जाती है ताकि गारंटीकृत निपटान हो सके। एनडीएस-ओएम प्रणाली तक सीधी पहुँच फिलहाल केवल चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं जैसे वाणिज्यिक बैंकों, प्राथमिक डीलरों, बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंड्स, एनबीएफसी आदि को उपलब्ध है। अन्य प्रतिभागी इस प्रणाली तक अपनी कस्टोडियनों के माध्यम से पहुँच सकते हैं, यानी, जिनके साथ वे गिल्ट खाता रखते हैं। यह प्रणाली प्रतिभागियों के बीच पूर्ण गुमनामी सुनिश्चित करती है, क्योंकि काउंटरपार्टी जानकारी न तो किसी प्रणाली प्रतिभागी के पास व्यापार से पूर्व होती है और न ही व्यापार के बाद, इस प्रकार निष्पक्ष मूल्य निर्धारण में बाधा डाले बिना सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करती है।

यह प्रणाली जो गुमनामी प्रदान करती है, बड़ी टिकट के निष्पादन को सक्षम बनाती है बिना बाजार की भावना और/या मूल्य संतुलन को विकृत किए, जो सामान्यतः द्विपक्षीय बाजार में पाया जाता है। एनडीएस-ओएम वेब आधारित प्रणाली एक इंटरनेट एक्सेस-आधारित उपयोगिता है जिसे विभिन्न गिल्ट खाता धारकों (जीएच) द्वारा एनडीएस-ओएम तक सीधी पहुँच के लिए उपयोग किया जाता है। यहां तक कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को भी इस वेब मॉड्यूल के माध्यम से एनडीएस-ओएम तक सीधी पहुँच दी गई है। जबकि जएएच एनडीएस-ओएम तक पहुँच और व्यापार कर सकते हैं, ऐसी गतिविधियाँ उनके कस्टोडियनों (प्राथमिक सदस्यों) की अनुमति सीमा के भीतर होंगी। यह मार्जिनल खिलाड़ियों को एनडीएस-ओएम पर सीधे व्यापार करने के लिए अधिक परिचालन स्वतंत्रता प्रदान करता है। जिन व्यक्तिगत निवेशकों के पास डिपॉजिटरी के साथ डिमैट खाते हैं, उन्हें भी एनडीएस-ओएम पर सीधे व्यापार करने की अनुमति दी गई है। बाँड टर्नओवर अनुपात, जो बाँड बाजार की तरलता का एक माप है और यह दर्शाता है कि द्वितीयक बाजार में व्यापारित राशि बांडों के कुल बाकी

अवशेषों के मुकाबले कितनी है, कई विकसित देशों के साथ अच्छी तुलना करता है। ऑन-द-रन प्रतिभूतियों का बिड-आस्क स्प्रेड संकरा रहता है, जिससे इन प्रतिभूतियों में बढ़ी हुई तरलता होती है। सरकारी यील्ड कर्व अब 50 वर्षों तक कुछ अच्छी तरह से विकसित बेंचमार्क बिंदुओं के साथ फैला हुआ है।

गवर्नमेंट सिक्योरिटीज (सी-सेक) बाजार के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, भारतीय रिज़र्व बैंक-रिटेल डायरेक्ट (आरबीआई-आरडी) योजना का शुभारंभ, जो सामान्य व्यक्ति के लिए से-सेक में निवेश की प्रक्रिया को सरल बनाकर इसे आसानी से उपलब्ध कराता है। इस योजना के तहत रिटेल निवेशकों के लिए जी-सेक में निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए एक एकीकृत समाधान प्रदान किया गया है। योजना की शुरुआत के बाद, रिटेल डायरेक्ट योजना का समर्थन करने के लिए पीडी (प्रोफेशनल डीलर्स) के लिए एक मार्केट मेकिंग योजना की घोषणा की गई थी। मई 2024 में, रिटेल डायरेक्ट ऐप्लिकेशन लॉन्च किया गया, जिससे रिटेल निवेशकों के लिए रिटेल डायरेक्ट प्लेटफ़ॉर्म तक निर्बाध और सुविधाजनक पहुंच सुनिश्चित की गई।

विनियामक भूमिका

सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार का नियमन समय के साथ विकसित हुआ है, जो प्रणालीगत आवश्यकताओं और संस्थागत विवेक को केंद्र में रखते हुए। बड़े सरकारी उधारी नीतियों के कारण उपज वक्र पर प्रभाव डालते हैं, जिससे अपेक्षाएँ उत्पन्न होती हैं। वित्तीय क्षेत्र पर सीधे असर के अलावा, ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव का सरकार के बैलेंस शीट पर महत्वपूर्ण असर पड़ता है, जो बाद में वित्तीय क्षेत्र के बैलेंस शीट पर प्रभाव डाल सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि विभिन्न बाजार प्रतिभागियों की गतिविधियों के कारण ब्याज दरों में अस्थिरता पर निगरानी रखी जाए। G-Sec बाजार में व्यवस्थित स्थिति बनाए रखने के लिए आरबीआई ने बाजार के विभिन्न पहलुओं पर नियम बनाए हैं। कुछ प्रमुख पहलू निम्नलिखित हैं:

- **शॉर्ट सेलिंग:** शॉर्ट सेलिंग प्रतिभागियों को ब्याज दरों पर दो-तरफ़ा दृष्टिकोण व्यक्त करने का एक उपकरण प्रदान करता है, जिससे मूल्य निर्धारण में सुधार होता है। शॉर्ट सेलिंग पर नियमन पात्र प्रतिभागियों, शॉर्ट सेल के लिए सीमा, शॉर्ट सेल पोज़ीशन को रखने के लिए अधिकतम समय अवधि आदि पर प्रकाश डालता है। शॉर्ट सेल लेन-देन के सुगम निपटान के लिए, जो बाजार के व्यवस्थित संचालन के लिए आवश्यक है, आरबीआई ने 2017 में यह तय किया था कि (i) शॉर्ट सेलर को 'नोटिओनल शॉर्ट सेल' के लिए प्रतिभूतियों को उधार लेने की आवश्यकता नहीं है और वह अपनी होल्ड-फॉर-ट्रेडिंग/एवलेबल-फॉर-सेल/होल्ड-टू-मैच्योरिटी पोर्टफोलियो में रखी हुई प्रतिभूतियों को प्रदान कर सकता है; 2018 में, प्रतिभागियों के आधार को उदार बनाया गया और G-Sec तथा रेपो बाजार को और विकसित और गहरा करने के लिए शॉर्ट सेलिंग के लिए सुरक्षा श्रेणी और संस्था-आधारित सीमाएँ शिथिल की गईं।
- **एफपीआई द्वारा निवेश:** एफपीआई (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों) को सी-सेक बाजार में अधिक पहुंच प्रदान की गई है। 2015 में, रुपये के ऋण प्रतिभूतियों में FPI निवेश की सीमा के लिए मीडियम-टर्म फ्रेमवर्क

(एमटीएफ) की घोषणा की गई थी, ताकि एक अधिक पूर्वानुमानित व्यवस्था प्रदान की जा सके। FPI निवेश के लिए पूर्वानुमानित व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, एमटीएफ के तहत एफपीआई निवेश की सीमा को प्रत्येक छह महीने में संशोधित किया जाता है। एमटीएफ के तहत, केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों के लिए FPI निवेश की सीमा 6 प्रतिशत और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए 2 प्रतिशत निर्धारित की गई है। सीमा को भारतीय रुपये में निर्दिष्ट किया गया है (अमेरिकी डॉलर के बजाय), जिससे विनिमय दर में उतार-चढ़ाव से उत्पन्न जटिलताएँ समाप्त हो जाती हैं। जी-सेक में एफपीआई निवेश विभिन्न मैक्रो-प्रूडेंशियल और अन्य नियामक प्रावधानों के अधीन होता है, जो आरबीआई द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाते हैं।

2018 में एफपीआई (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) द्वारा किए गए ऋण निवेशों के लिए नियामक व्यवस्था की समीक्षा की गई थी, ताकि एफपीआई को उनके पोर्टफोलियो को प्रबंधित करने में अधिक लचीलापन मिल सके, जैसे कि निवेश की सीमाओं में वृद्धि, पात्र उपकरण, अवधि और काल प्रबंधन आदि। किसी भी केंद्रीय सरकार के सुरक्षा में एफपीआई के कुल निवेश पर जो सीमा थी, उसे 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया था। सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए तीन साल की न्यूनतम शेष परिपक्वता की आवश्यकता को हटा दिया गया, कुछ शर्तों के साथ। अन्य मैक्रो-प्रूडेंशियल उपायों में प्रत्येक ऋण श्रेणी में एफपीआई निवेश के लिए कुल निवेश सीमा के प्रतिशत के रूप में एकाग्रता सीमाएँ, शॉर्ट-टर्म निवेश सीमा और कॉर्पोरेट बांड में एकल तथा समूह निवेशक-वार सीमा शामिल हैं। इसके बाद इस व्यवस्था में समय-समय पर कुछ परिवर्तनीय बदलाव किए गए। एफपीआई द्वारा निवेश की संचालनात्मक सुविधा को सरल बनाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं, जिनमें बैंकों को G-सेक्योरिटीज में उनके लेन-देन के लिए मार्जिन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एफपीआई को उधार देने की अनुमति देना और ऑनशोर बाजार घंटों के बंद होने के बाद व्यापारों की रिपोर्टिंग के लिए विस्तारित विंडो प्रदान करना शामिल है। साथ ही, गैर-निवासी निवेशकों, जिनमें एफपीआई भी शामिल हैं, को घरेलू डेरिवेटिव बाजारों में निवेश की अनुमति दी गई है/आसान किया गया है, ताकि इन संस्थाओं द्वारा ब्याज दर, विदेशी मुद्रा और क्रेडिट जोखिमों के हेजिंग में मदद मिल सके। केंद्रीय बजट 2021-22 की घोषणा के अनुसार, एफपीआई को इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (InvITs) और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स (REITs) द्वारा जारी किए गए ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति दी गई।

2019 में एक अलग चैनल, जिसे 'स्वैच्छिक रोकन सीमा मार्ग' (वीआरआर) कहा गया, पेश किया गया था, जो परिचालन लचीलापन के साथ-साथ उपकरण विकल्पों और नियामक सीमाओं से छूट प्रदान करता है, ताकि एफपीआई को भारत में दीर्घकालिक ऋण निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। मार्च 2020 में, एक अलग चैनल, जिसे 'पूर्ण रूप से सुलभ मार्ग' (एफएआर) कहा गया, आरबीआई द्वारा गैर-निवेशकों के लिए भारतीय सरकार के विशेष सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की अनुमति देने के लिए पेश किया गया। पात्र निवेशक इस मार्ग के तहत विशिष्ट सरकारी प्रतिभूतियों में बिना किसी मैक्रो-प्रूडेंशियल सीमा और

निवेश की छत के निवेश कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए 5-, 7- और 10-वर्षीय प्रतिभूतियां और संप्रभु ग्रीन बांड इस मार्ग के तहत आते हैं। यह योजना दो मौजूदा मार्गों, यानी एमटीएफ और वीआरआर के साथ काम करती है। FAR 2020 में और संबंधित बाजार सुधारों के बाद, भारतीय सरकारी बांड (आईजीबी) को प्रमुख वैश्विक बांड सूचियों में शामिल किए जाने पर विचार किया गया है। सितंबर 2023 में, एक सूचकांक प्रदाता ने अपनी उभरती बाजार सूचियों में आईजीबी को जून 2024 से शामिल किए जाने की घोषणा की, जिसमें FAR के तहत जारी किए गए सरकारी बांड कुछ समावेशन मानदंडों के अधीन शामिल होने के योग्य होंगे। मार्च 2024 में, एक अन्य सूचकांक प्रदाता ने अपनी उभरती बाजार सूचियों में भारत एफएआर बांड को शामिल करने की घोषणा की।

जब इश्यू (WI) ट्रेडिंग: WI मार्केट उस बाजार को कहा जाता है जहाँ सरकारी प्रतिभूतियाँ जो घोषित की जा चुकी हैं, लेकिन अभी जारी नहीं हुई हैं, उनका व्यापार किया जाता है। इस बाजार में निवेशक इन प्रतिभूतियों को उस समय के दौरान खरीद और बेच सकते हैं जब तक इनका वास्तविक जारी होने की तिथि नहीं आ जाती। WI मार्केट ने जी-सेक के वितरण प्रक्रिया को बेहतर बनाया है क्योंकि यह हर निर्गम के लिए वितरण अवधि को बढ़ाता है, जिससे बाजार को बड़े निर्गम को बिना किसी व्यवधान के अवशोषित करने के लिए अधिक समय मिलता है। यह मूल्य खोज प्रक्रिया को भी सुविधाजनक बनाता है क्योंकि यह नीलामी के आसपास की अनिश्चितताओं को कम करता है। शुरुआत में, WI मार्केट केवल एनडीएस पर ट्रेडिंग तक सीमित था। हालांकि, समय के साथ, WI दिशानिर्देशों का अनुप्रयोग गैर-एनडीएस ट्रेड्स तक बढ़ा दिया गया और पात्र भागीदारों का दायरा बढ़ाया गया, साथ ही विभिन्न भागीदार श्रेणियों के लिए शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशनों पर सीमा भी बढ़ाई गई ताकि इस खंड में अधिक ट्रेडिंग को बढ़ावा मिल सके।

पंजीकृत ब्याज और मूलधन के अलग-अलग व्यापार (STRIPS): STRIPS एक प्रकार का वित्तीय उपकरण है जो सरकारी प्रतिभूति के ब्याज भुगतान (कूपन) और मूलधन भुगतान को अलग-अलग घटकों में विभाजित करके बनता है, जिन्हें फिर अलग-अलग व्यापार किया जा सकता है। रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2010 में सरकारी प्रतिभूतियों में स्ट्रिपस (STRIPS) को पेश किया था। स्ट्रिपिंग/पुनःसंयोजन के लिए योग्य प्रतिभूतियाँ, स्ट्रिपिंग/पुनःसंयोजन के लिए न्यूनतम राशि, स्ट्रिपस के मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले छूट दर आदि को आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट किया गया था। कुछ शुरुआती रुचि के बाद, उत्पाद को बाजार में ज्यादा प्रशंसा नहीं मिली। स्ट्रिपस में व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए और इसे बाजार की आवश्यकताओं के साथ अधिक अनुरूप बनाने के उद्देश्य से, 2018 में संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए थे, जिसके अनुसार सभी निश्चित कूपन सरकारी प्रतिभूतियाँ, चाहे उनकी परिपक्वता वर्ष कोई भी हो, स्ट्रिपिंग/पुनःसंयोजन के लिए योग्य हैं, यदि वे ऐसी प्रतिभूतियाँ हैं जो संविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के लिए योग्य हैं और हस्तांतरणीय हैं।

सरकारी प्रतिभूतियों में प्रतिभूतियों की उधारी और उधार की शुरुआत: जी-सेक बाजार में तरलता को गहरा और

बेहतर बनाने, कुशल मूल्य खोज की सुविधा प्रदान करने, 'विशेष रिवर्स रेपो' बाजार को बढ़ावा देने और निवेशकों को बेहतर पोर्टफोलियो रिटर्न के लिए अपनी निष्क्रिय प्रतिभूतियों का उपयोग करने का एक तरीका प्रदान करने के लिए, 2023 में सरकारी प्रतिभूतियों में प्रतिभूतियों की उधारी और उधार लेने की अनुमति दी गई। इस तंत्र के तहत, सभी संस्थाएँ जो जी-सेक में रिवर्स रेपो लेन-देन करने के लिए अधिकृत हैं, वे उधार देने के योग्य हैं, जबकि वे संस्थाएँ जो जी-सेक में शॉर्ट सेल लेन-देन करने के लिए अधिकृत हैं, वे उधार लेने के योग्य हैं। उधारी/उधार की अवधि एक दिन से लेकर आरबीआई द्वारा निर्धारित अधिकतम अवधि तक हो सकती है, ताकि जी-सेक में शॉर्ट सेल को कवर किया जा सके।

कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार

एक सक्रिय और विकसित कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार उधारकर्ताओं को बैंक वित्तपोषण का विकल्प प्रदान करता है, जिससे दीर्घकालिक फंडिंग की लागत कम करने में मदद मिलती है। चूंकि बैंकों को उनके अल्पकालिक दायित्वों के कारण दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने में सीमाएं होती हैं, इसलिए कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार कंपनियों के लिए दीर्घकालिक पूंजी का अधिक कुशल और किफायती स्रोत प्रदान कर सकता है। यह बीमा कंपनियों, भविष्य निधि और पेंशन फंड जैसे संस्थागत निवेशकों को दीर्घकालिक वित्तीय परिसंपत्तियां प्रदान करता है, जिससे उनकी परिसंपत्तियों और दायित्वों का बेहतर मिलान संभव होता है।

मैक्रो-वित्तीय दृष्टिकोण से, एक विकसित कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार जोखिम को बैंकिंग प्रणाली से दूर वितरित करने में मदद करता है, जो वित्तीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। व्यापक निवेशकों के बीच जोखिम को फैलाकर, कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार समग्र वित्तीय स्थिरता का समर्थन करता है। यह बाजार कॉर्पोरेट वित्तपोषण और व्यापक वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

हाल के वर्षों में प्राथमिक और द्वितीयक कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजारों में पर्याप्त वृद्धि हुई है, हालांकि यह अभी भी वैश्विक स्तर पर अपने समकक्षों से पीछे है। कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार का प्रमुख नियामक, सेबी (SEBI), वर्षों से कॉर्पोरेट बॉन्ड के बाजार संरचना में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। आरबीआई ने भी कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार को विकसित करने के लिए कई उपाय किए हैं - बैंकों को आंशिक क्रेडिट संवर्धन (Partial Credit Enhancement - PCE) प्रदान करने की अनुमति देना ताकि बड़े निवेशकों को आकर्षित किया जा सके; बड़े उधारकर्ताओं को अपने वृद्धिशील उधारों का एक हिस्सा (लगभग 50%) बाजार साधनों के माध्यम से जुटाने की आवश्यकता रखना; विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) को बढ़ावा देना, निवेश सीमा बढ़ाना और वोलंटरी रिटेंशन रूट (Voluntary Retention Route) की शुरुआत करना आदि।

आरबीआई केवल कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार के कुछ पहलुओं को नियंत्रित करता है, जैसे कि बैंकों और अन्य आरबीआई-नियंत्रित संस्थाओं की कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में भागीदारी, कॉर्पोरेट बॉन्ड में FPI निवेश, कॉर्पोरेट बॉन्ड में रेपो और कॉर्पोरेट बॉन्ड पर क्रेडिट डेरिवेटिव्स। एक संस्था नियामक के रूप में, आरबीआई ने अपनी नियंत्रित

संस्थाओं को कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया है। कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार के संबंध में आरबीआई द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण विकासात्मक और नियामक भूमिकाएं नीचे दी गई हैं:

विकासात्मक भूमिका

भागीदारी बढ़ाना:

आरबीआई ने बैंकों को दीर्घकालिक परियोजनाओं और किफायती आवास के लिए ऋण को वित्तपोषित करने के लिए न्यूनतम सात साल की परिपक्वता वाले दीर्घकालिक बॉन्ड जारी करने की अनुमति दी है। इसके अलावा, इन बॉन्ड्स के माध्यम से जुटाए गए धन को CRR/SLR आवश्यकताओं से छूट दी गई है। बैंकों और प्राथमिक डीलरों (पीडी) को कॉर्पोरेट बॉन्ड में व्यापार करने के लिए स्टॉक एक्सचेंजों का सदस्य बनने की अनुमति दी गई है। निवेश मानदंडों में ढील देकर इस तरह के निवेशों को प्रोत्साहित किया गया है। एफपीआई को द्वितीयक बाजार में अधिक पहुंच प्रदान की गई है, जिसमें निवेश सीमाओं में वृद्धि और एक सरल सीमा आवंटन पद्धति शामिल है।

बाजार तरलता बढ़ाना:

संस्थागत खरीदारों को उनके दीर्घकालिक स्थानों के लिए धन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कॉर्पोरेट बॉन्ड में रेपो की शुरुआत की गई है। बड़े उधारकर्ताओं के लिए बॉन्ड बाजार के माध्यम से क्रेडिट आपूर्ति को बढ़ाने के लिए आरबीआई के दिशानिर्देश बाजार तरलता को बढ़ाने के लिए जारी किए हैं।

बाजार अवसंरचना:

डिलिवरी वर्सेस पेमेंट (डीवीपी) मोड का परिचय ओटीसी कॉर्पोरेट बॉन्ड ट्रेड्स के लिए 2009 में किया गया, जिससे निपटान जोखिम को समाप्त किया जा सके। 2007 में, आरबीआई ने बैंकों, प्राइमरी डीलर्स और अन्य नियामक संस्थाओं को कॉर्पोरेट बॉन्ड ट्रेड्स को नामित रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करने का निर्देश दिया, ताकि बाजार की पारदर्शिता में सुधार हो।

जोखिम प्रबंधन:

क्रेडिट डिफॉल्ट स्वेप्स (सीडीएस) का परिचय दिसंबर 2011 में दिया गया था, जिसे 2022 में संशोधित किया गया, ताकि कॉर्पोरेट बॉन्ड धारकों को क्रेडिट जोखिम को हेज करने की सुविधा दी जा सके। बैंकों को कुछ सीमाओं के अधीन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पर आंशिक क्रेडिट एन्हांसमेंट प्रदान करने की अनुमति दी गई।

नियामकीय भूमिका:

1. कॉर्पोरेट बॉन्ड में रेपो:

आरबीआई ने रेपो लेन-देन के लिए पात्र प्रतिभूतियों, हेयरकट और मूल्यांकन विधियों आदि के दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं।

2. क्रेडिट डेरिवेटिव्स:

- सीडीएस की अनुमति मनी मार्केट डेट इंस्ट्रूमेंट्स, रेटेड भारतीय रुपया कॉर्पोरेट बॉन्ड और डिबेंचर, बिना

रेटेड भारतीय रुपया कॉरपोरेट बॉन्ड और डिबेंचर (जो इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनियों द्वारा स्थापित विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) द्वारा जारी किए गए हैं), कॉल/पुट विकल्प वाले बॉन्ड पर दी गई है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (कुछ अपवादों के साथ), स्टैंड-अलोन प्राइमरी डीलर्स, ₹500 करोड़ की न्यूनतम शुद्ध स्वामित्व निधि वाले NBFCs (आरबीआई के विशिष्ट अनुमोदन के अधीन), और EXIM बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी जैसे संस्थान बाजार निर्माताओं के रूप में कार्य करने के पात्र हैं। दिशा-निर्देश गैर-खुदरा उपयोगकर्ताओं जैसे विनियमित वित्तीय संस्थाओं और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को प्रोटेक्शन बेचने की अनुमति देते हैं। गैर-खुदरा उपयोगकर्ता हेजिंग या क्रेडिट जोखिम पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए प्रोटेक्शन खरीद सकते हैं, जबकि खुदरा उपयोगकर्ता केवल अंतर्निहित जोखिम को हेज करने के लिए प्रोटेक्शन खरीद सकते हैं।

3. बैंकों द्वारा ऋण सीमा में वृद्धि/ क्रेडिट एन्हांसमेंट:

- बैंकों को प्रोजेक्ट्स के लिए एक गैर-वित्त पोषित अधीनस्थ सुविधा के रूप में पीसीई (पीसीई) प्रदान करने की अनुमति दी गई है, जिसे बॉन्ड की सेवा के लिए नकदी प्रवाह में कमी होने की स्थिति में उपयोग किया जाएगा। पीसीई बॉन्ड की क्रेडिट रेटिंग को सुधारता है। आरबीआई ने व्यक्तिगत बैंकों और किसी विशेष बॉन्ड इश्यू के लिए सभी बैंकों द्वारा प्रदान किए जा सकने वाले कुल पीसीई के लिए सीमा निर्धारित की है।

4. एफपीआई निवेश:

आरबीआई कॉरपोरेट बॉन्ड में एफपीआई निवेश के लिए सीमा निर्धारित करता है। एमटीएफ और वीआरआर के तहत एफपीआई निवेश की सीमा को सभी प्रकार के कॉरपोरेट बॉन्ड के लिए एकल सीमा के रूप में निर्धारित किया गया है। एफपीआई निवेश सीमा को कॉरपोरेट ऋण में बकाया स्टॉक का 15% तक सीमित किया गया है और इसे अर्धवार्षिक आधार पर संशोधित किया जाता है।

विनियामक भूमिका

कॉर्पोरेट बॉन्ड में रेपो: भारतीय रिजर्व बैंक ने कॉरपोरेट बांडों में रेपो लेनदेन के लिए पात्र प्रतिभूतियों, हेयर-कट और मूल्यांकन विधियों आदि पर दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं।

क्रेडिट डेरिवेटिव: सीडीएस की अनुमति मुद्रा बाजार ऋण उपकरणों, रेटेड आईएनआर कॉर्पोरेट बॉन्ड और डिबेंचर, अनरेटेड आईएनआर कॉर्पोरेट बॉन्ड और बुनियादी ढांचा कंपनियों द्वारा स्थापित विशेष प्रयोजन वाहनों द्वारा जारी किए गए डिबेंचर, संदर्भ दायित्वों के रूप में कॉल / पुट विकल्पों के साथ बांड पर दी जाती है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कुछ अपवादों को छोड़कर, 500 करोड़ रुपये की न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधियों वाले एकल एकल पीडीएस, एनबीएफसी और विनियमन विभाग, रिजर्व बैंक तथा रिजर्व बैंक, एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी द्वारा विशेष रूप से अनुमत किसी अन्य संस्था के विशिष्ट अनुमोदन के अध्यक्षीन सीडीएस में बाजार निर्माताओं के रूप में कार्य करने के पात्र हैं। दिशानिर्देश गैर-खुदरा उपयोगकर्ताओं जैसे विनियमित वित्तीय संस्थाओं और एफपीआई

को सुरक्षा बेचने की अनुमति देते हैं। वे गैर-खुदरा उपयोगकर्ताओं को हेजिंग के लिए सुरक्षा खरीदने या क्रेडिट जोखिम पर अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति देते हैं जबकि खुदरा उपयोगकर्ताओं को केवल अंतर्निहित जोखिम की हेजिंग के लिए सुरक्षा खरीदने की अनुमति है।

बैंकों द्वारा ऋण वृद्धि: बैंकों को गैर-वित्तपोषित अधीनस्थ सुविधा के रूप में एक परियोजना को पीसीई प्रदान करने की अनुमति दी गई है, जो एक अपरिवर्तनीय आकस्मिक ऋण रेखा के रूप में है जिसे बांड की सर्विसिंग के लिए नकदी प्रवाह में कमी के मामले में तैयार किया जाएगा। पीसीई बॉन्ड इश्यू की क्रेडिट रेटिंग में सुधार करता है। आरबीआई ने अलग-अलग बैंकों द्वारा पीसीई के लिए सीमाएं निर्धारित की हैं और साथ ही कुल पीसीई जो किसी विशेष बॉन्ड इश्यू के लिए सभी बैंकों द्वारा प्रदान किया जा सकता है।

एफपीआई निवेश: आरबीआई कॉर्पोरेट बॉन्ड में एफपीआई निवेश की सीमा निर्धारित करता है। रुपया ऋण प्रतिभूतियों में एफपीआई निवेश के लिए एमटीएफ और वीआरआर, जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, कॉर्पोरेट बॉन्ड में एफपीआई निवेश सीमा को भी शामिल करता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश को इसकी विभिन्न उप-श्रेणियों को बंद करके और सभी प्रकार के कॉर्पोरेट बॉन्ड में एफपीआई निवेश के लिए एक सीमा निर्धारित करके सुव्यवस्थित किया गया है। कॉर्पोरेट ऋण में एफपीआई निवेश की सीमा एमटीएफ के तहत बकाया स्टॉक के 15 प्रतिशत से जुड़ी है और इसे छमाही आधार पर संशोधित किया गया है।

ब्याज दर डेरिवेटिव (आईआरडी)

ब्याज दर स्वेप (आईआरएस)/ वायदा दर करार (एफआरए) को 1999 में मनी मार्केट को और गहराई देने और बाजार सहभागियों को उनके ब्याज दर जोखिमों से बचाव करने में सक्षम बनाने के लिए शुरू किया गया था। एफआरए और आईआरएस को जुलाई 1999 में ब्याज दरों के उदारीकरण के बाद बैंकों और प्राइमरी डीलरों (पीडी) को ब्याज दर जोखिम का बेहतर प्रबंधन करने में मदद के लिए पेश किया गया। मार्च 2011 में, आरबीआई ने 91-दिन के टी-बिल पर फ्यूचर्स की अनुमति दी। बाद में, दिसंबर 2016 में, आरबीआई ने अन्य मनी मार्केट उपकरणों या मनी मार्केट ब्याज दरों पर आधारित फ्यूचर्स की भी अनुमति दी। इसी वर्ष, रुपया ब्याज दर विकल्प (आईआरओ) पेश किए गए, जिनकी शुरुआत साधारण "प्लेन वनीला" आईआरओ तक सीमित रही। हालांकि, 2018 में, आरबीआई ने रुपया आईआरओ पर निर्देशों की समीक्षा की और इसके परिणामस्वरूप रुपया ब्याज दर स्वेप्स की शुरुआत हुई। ओटीसी आईआरडी बाजार में, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आईआरडी अनुबंधों के व्यापार के लिए उपलब्ध हैं और सीसीआईएल आईआरएस अनुबंधों के लिए गारंटीकृत निपटान प्रदान करता है।

जून 2019 में, आरबीआई ने "रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2019" जारी किए, ताकि व्यक्तिगत उत्पादों पर विनियमों को एकीकृत किया जा सके और एक्सचेंजों और बाजार निर्माताओं को उत्पादों की डिजाइन और नवाचार में लचीलापन प्रदान किया जा सके। यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि इन डेरिवेटिव बाजारों में कम अनुभवी प्रतिभागियों की पर्याप्त सुरक्षा हो। वर्तमान में, भारत में स्वीकृत आईआरडी में एफआरए, आईआरएस, और यूरोपीय आईआरओ (जिसमें कैप, फ्लोर, कॉलर और रिवर्स कॉलर शामिल हैं), स्वेप्स और संरचित डेरिवेटिव उत्पाद (लीवरेज्ड डेरिवेटिव्स को छोड़कर) शामिल हैं।

दोनों निवासी और अनिवासी आईआरडी लेनदेन कर सकते हैं। भारतीय या अनिवासी होल्डिंग कंपनियां, समूह कंपनियां, या केंद्रीकृत ट्रेजरीज़ अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों या समूह कंपनियों की ओर से आईआरडी लेनदेन कर सकती हैं। लेनदेन हेजिंग और अन्य उद्देश्यों दोनों के लिए, कुछ शर्तों के अधीन, की अनुमति है। आईआरडी लेनदेन ओटीसी बाजारों (जिसमें ETP पर लेनदेन शामिल हैं) और मान्यता प्राप्त एक्सचेंजों पर किए जा सकते हैं। एक्सचेंजों को किसी भी मानकीकृत आईआरडी उत्पाद की पेशकश करने की अनुमति दी गई है, जिसमें उत्पाद की डिजाइन, पात्र प्रतिभागी और अन्य विवरण एक्सचेंजों द्वारा तय किए जाते हैं। हालांकि, किसी नए आईआरडी उत्पाद को पेश करने या किसी मौजूदा उत्पाद में संशोधन करने से पहले आरबीआई से पूर्व अनुमोदन आवश्यक है।

2022 में, भारत में आईआरडी को और गहराई देने, ऑनशोर और ऑफशोर बाजारों के बीच विभाजन को समाप्त करने और मूल्य खोज की दक्षता में सुधार करने के लिए, आरबीआई ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के तहत अधिकृत डीलर श्रेणी-I (एडी कैट-I) लाइसेंस और स्वतंत्र प्राइमरी डीलरों को ऑफशोर फॉरेन करेंसी सेटल्ल ओवरनाइट इंडेक्स्ड स्वेप (एफसीएस-ओआईएस) बाजार में अनिवासियों और अन्य बाजार निर्माताओं के साथ उनके भारत स्थित शाखाओं, विदेशी शाखाओं या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) बैंकिंग इकाइयों (आईबीयू) के माध्यम से लेनदेन करने की अनुमति दी।

ओटीसी बाजार में आईआरडी में उपयोग की जाने वाली कोई भी फ्लोटिंग ब्याज दर, मूल्य, या सूचकांक एक वित्तीय बेंचमार्क प्रशासक (एफबीए) द्वारा प्रकाशित या फिम्डा द्वारा अनुमोदित बेंचमार्क होना चाहिए। फिम्डा को यह सुनिश्चित करना होगा कि अनुमोदित फ्लोटिंग दर को पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ और बाहरी लेनदेन के माध्यम से निर्धारित किया गया हो। आईआरडी लेनदेन का निपटान द्विपक्षीय रूप से या आरबीआई द्वारा अनुमोदित किसी भी क्लियरिंग व्यवस्था के माध्यम से किया जा सकता है। ओटीसी बाजारों में बाजार निर्माताओं को आरबीआई द्वारा निर्धारित 'उपयुक्तता और अनुकूलता' आवश्यकताओं का पालन करना होगा। सभी ओटीसी लेनदेन, जिनमें ग्राहक लेनदेन शामिल हैं, को बाजार निर्माताओं द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर सीसीआईएल के ट्रेड रिपॉजिटरी में रिपोर्ट करना होगा, जिसमें यह स्पष्ट रूप से संकेत दिया जाएगा कि व्यापार हेजिंग के लिए है या अन्य उद्देश्यों के लिए।

विदेशी मुद्रा बाजार

भारत के विदेशी मुद्रा बाजार का विकास पिछले कुछ दशकों में भारत की विनिमय दर नीतियों में हुए परिवर्तनों के अनुरूप देखा जा सकता है, जिसमें पार मूल्य प्रणाली से बास्केट पेग और आगे प्रबंधित फ्लोट विनिमय दर प्रणाली तक का विकास शामिल है।

भारत में विदेशी मुद्रा बाजार की शुरुआत 1978 में हुई, जब बैंकों को इंटर-डे ट्रेडिंग की अनुमति दी गई। इस अवधि के दौरान, आरबीआई ने भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों की मुद्राओं की भारत बास्केट का उपयोग करके रुपये की विनिमय दर निर्धारित की और अधिकृत डीलरों (एडी) को दैनिक खरीद और बिक्री दरें घोषित की। यह बाजार इन दरों के बीच 0.5% के अंतराल में संचालित होता था।

1990 के दशक में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, विशेष रूप से जुलाई 1991 में दो-चरणीय विनिमय दर समायोजन के साथ, जिसने पेग्ड विनिमय दर व्यवस्था को समाप्त कर दिया। 1990-91 के खाड़ी संकट के बाद, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पर उच्च स्तरीय समिति, जिसकी अध्यक्षता डॉ. सी. रंगराजन ने की थी, ने बाजार-निर्धारित विनिमय दर की सिफारिश की। इसके परिणामस्वरूप

मार्च 1992 में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली (एलईआरएमएस) की शुरुआत हुई, जिसमें 60% आय बाजार दर पर और 40% आरबीआई की आधिकारिक दर पर विनिमय की जाती थी। मार्च 1993 तक, एलईआरएमएस एकीकृत, बाजार-निर्धारित विनिमय दर व्यवस्था में परिवर्तित हो गया, जिससे अगस्त 1994 में चालू खाता परिवर्तनीयता का मार्ग प्रशस्त हुआ। आगे के विकास में भारत में विदेशी मुद्रा बाजारों पर विशेषज्ञ समूह की स्थापना शामिल थी, जिसकी अध्यक्षता श्री ओ.पी. सोधानी ने की। इस समूह ने बाजार को गहराई देने के लिए सिफारिशें दीं। जनवरी 1996 से विदेशी मुद्रा व्यापार की मात्रा बढ़ने के साथ व्यापक सुधार लागू किए गए। तब से, आरबीआई ने कई नियामकीय पहलें की हैं, जैसे कि फॉरवर्ड अनुबंधों को रद्द करने और पुनः बुक करने की स्वतंत्रता, एडी (आधिकारिक डीलरों) को अपने ग्राहकों के वस्तु मूल्य जोखिम को हेज करने की अनुमति देने की शक्तियां आदि, जिसने भारतीय विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास में मदद की है।

परिणामस्वरूप, पिछले दो दशकों में भारतीय विदेशी मुद्रा बाजार ने असाधारण वृद्धि देखी है, जहां औसत दैनिक टर्नओवर 2001 में लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2022 में 53 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया (बीआईएस त्रैवार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार)।

ऑफशोर भारतीय रुपये (आईएनआर) डेरिवेटिव बाजार ने समय के साथ तेजी से विकास किया है। इस बाजार का प्रमुख खंड गैर-डिलीवरेबल फॉरवर्ड (एनडीएफ) बाजार है, जहां विदेशी मुद्रा फॉरवर्ड अनुबंध ओटीसी बाजार में ऑफशोर स्थानों जैसे सिंगापुर, हांगकांग, लंदन, दुबई और न्यूयॉर्क के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों (आईएफसी) में व्यापारित होते हैं। इसके अलावा, शिकागो, सिंगापुर और दुबई में रुपये के फ्यूचर्स और ऑप्शन्स का व्यापार करने वाले कुछ एक्सचेंज-ट्रेडेड ऑफशोर रुपये बाजार भी हैं। इन बाजारों में मात्रा आमतौर पर ऑफशोर एनडीएफ ओटीसी बाजार की तुलना में काफी कम रही है। भारतीय रुपये में ऑफशोर रुचि को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2019 में एक कार्य बल (जिसकी अध्यक्षता श्रीमती उषा थोराट, पूर्व डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक ने की) का गठन किया, ताकि ऑफशोर रुपये बाजारों से संबंधित मुद्दों की गहन जांच की जा सके और उचित नीतिगत उपायों की सिफारिश की जा सके। कार्य बल की कुछ सिफारिशों, जैसे ऑनशोर बाजार घंटों का विस्तार और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) में विदेशी मुद्रा में निपटान किए गए रुपये डेरिवेटिव्स को व्यापार करने में सक्षम बनाना, ने विदेशी मुद्रा बाजार के धीरे-धीरे खोलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है।

विकासात्मक भूमिका

संस्थागत ढांचा: 1973 के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) को 1999 में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) से बदलने के साथ, आरबीआई ने अधिकृत डीलरों (एडी) को विभिन्न उद्देश्यों के लिए विदेशी मुद्रा जारी करने की शक्तियां सौंपी। बैंक ने बाजार सहभागियों द्वारा नैतिक आचरण सुनिश्चित करने और विदेशी मुद्रा बाजार के विभिन्न खंडों के विकास के लिए स्व-नियामक तंत्र स्थापित करने हेतु फेडआई को अधिक अधिकार और जिम्मेदारियां सौंपी हैं।

उपकरणों के समूह का विस्तार: भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न आर्थिक एजेंटों द्वारा मुद्रा जोखिमों के प्रभावी हेजिंग की सुविधा के लिए वर्षों में कई नए उपकरणों की शुरुआत को सक्षम किया है। विदेशी मुद्रा-रुपया ऑप्शंस, क्रॉस करेंसी ऑप्शंस, विदेशी मुद्रा-रुपया स्वैप्स, क्रॉस करेंसी स्वैप्स, ब्याज दर स्वैप्स और विदेशी मुद्रा में ऑप्शंस को समय-समय पर पेश किया गया। ओटीसी टोकरे को 2008 से चरणबद्ध तरीके से एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर्स और ऑप्शंस की शुरुआत के साथ पूरक किया गया। वर्तमान में, भारतीय विदेशी मुद्रा बाजार में निम्नलिखित उपकरण उपलब्ध हैं:

- स्पॉट, कैश और टॉम

- फॉरवर्ड्स
- एफएक्स स्वेप्स
- करेंसी स्वेप्स
- एफएक्स ऑप्शंस (जिसमें लागत कम करने वाले स्ट्रक्चर और कवर कॉल्स व पुट्स शामिल हैं)
- एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर्स और ऑप्शंस

बाजार बुनियादी ढांचा: सीसीआईएल ने 2002 से इंटर-बैंक यूएसडी-आईएनआर स्पॉट और फॉरवर्ड ट्रेड्स और 2004 से इंटर-बैंक यूएसडी-आईएनआर कैश और टॉम ट्रेड्स के लिए विदेशी मुद्रा संचालन के निपटान की शुरुआत की। सीसीआईएल विदेशी मुद्रा व्यापारों के निपटान को एक बहुपक्षीय नेटिंग आधार पर नवेशन प्रक्रिया के माध्यम से संचालित करता है। सभी स्पॉट, कैश, टॉम (यूएसडी-आईएनआर) और फॉरवर्ड्स लेनदेन (शेष परिपक्वता 13 महीने तक के यूएसडी-आईएनआर फॉरवर्ड्स) के निपटान की गारंटी दी जाती है।

खुदरा प्रतिभागियों के लिए विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म: खुदरा उपयोगकर्ताओं (व्यक्तिगत और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों) के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में पारदर्शी और निष्पक्ष मूल्य निर्धारण के मुद्दे से निपटने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2019 में सीसीआईएल द्वारा एफएक्स-रिटेल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की सुविधा प्रदान की। एफएक्स-रिटेल प्लेटफॉर्म बैंकों के ग्राहकों के लिए यूएसडी/आईएनआर मुद्रा जोड़ी में गुमनाम और ऑर्डर-चालित सौदों की सुविधा प्रदान करता है। यह तंत्र पारदर्शिता प्रदान करता है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है, और खुदरा ग्राहकों के लिए बेहतर मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करता है। बैंक अपने खुदरा ग्राहकों से प्रशासनिक खर्चों के लिए एक पूर्व सहमति फ्लैट शुल्क ले सकते हैं, जिसे सार्वजनिक रूप से घोषित करना आवश्यक है। कुल मिलाकर, यह उम्मीद की जाती है कि विदेशी मुद्रा बाजार में खुदरा ग्राहकों द्वारा वहन की जाने वाली कुल लागत में कमी आएगी। खुदरा ग्राहकों को सीधे बाजार में पहुंच प्रदान करना, बजाय इसके कि उनके बैंक मूल्य निर्धारण करें, न केवल ग्राहकों के लिए लाभकारी है, बल्कि बैंकों द्वारा लेनदेन को संभालने में आने वाले जोखिम को भी कम करता है।

नियामकीय भूमिकाएं

ओटीसी डेरिवेटिव बाजार तक पहुंच: आरबीआई ने यह अनिवार्य किया है कि आईएनआर से संबंधित ओटीसी विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव तक पहुंच वैध अंतर्निहित जोखिम के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान करने पर निर्भर करती है। इस विनियमन का मुख्य उद्देश्य कॉर्पोरेट ग्राहकों द्वारा विनिमय दर जोखिमों को हेज करने के लिए ओटीसी विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव के उपयोग को सीमित करना है, न कि सट्टा व्यापार के लिए। चूंकि विनिमय दर एक महत्वपूर्ण व्यापक आर्थिक चर है, इसलिए इसमें सट्टा व्यापार से व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

माल व्यापार और सेवाओं में लेनदेन के संबंध में पिछले प्रदर्शन के आधार पर संभावित जोखिमों को हेज करने की सुविधा ने बिना अंतर्निहित दस्तावेजों के हेजिंग में लचीलापन प्रदान किया है। बैंक ने विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव्स तक आसान पहुंच के लिए प्रलेखन आवश्यकताओं को सरल बनाने के लिए कई उपाय किए हैं।

2020 में, विदेशी मुद्रा जोखिम हेजिंग के लिए आरबीआई द्वारा निर्देश जारी किए गए, जिसके तहत निवासियों और गैर-निवासियों के लिए सुविधाओं को एकलीकृत कर सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक संयुक्त सुविधा के रूप में पेश किया गया। इन निर्देशों के तहत अनुबंधित और प्रत्याशित जोखिम दोनों को हेज करने की अनुमति दी गई और अनुबंधों को स्वतंत्र रूप से

रद्द करने और पुनः बुक करने की सुविधा दी गई। उपयोगकर्ताओं को किसी भी अनुमत उपकरण का उपयोग करके अपने वैध जोखिमों को हेज करने की अनुमति है। अधिकृत डीलरों के लिए विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव्स की पेशकश के लिए सरल प्रक्रियाएं शुरू की गईं। आरबीआई ने उपयोगकर्ताओं को ओटीसी बाजार में 100 मिलियन यूएसडी तक की मुद्रा डेरिवेटिव लेनदेन करने की अनुमति दी, जिसके लिए अंतर्निहित जोखिम के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बैंकों को असाधारण परिस्थितियों में यह विवेक प्रदान किया गया है कि वे प्रत्याशित जोखिमों पर बुक किए गए हेज लेनदेन से उत्पन्न शुद्ध लाभ, यदि कोई हो, को स्थानांतरित कर सकते हैं, जहां अंतर्निहित नकदी प्रवाह साकार नहीं हुआ है। इसके अलावा, जटिल डेरिवेटिव्स को केवल उन उपयोगकर्ताओं को बेचने की अनुमति दी गई है, जो जोखिम प्रबंधन की क्षमता रखते हैं, जिसके लिए 2020 में एक उपयोगकर्ता वर्गीकरण ढांचे की शुरुआत की गई। खुदरा प्रतिभागियों के लिए मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, अधिकृत डीलरों को खुदरा उपयोगकर्ताओं को मध्य-बाजार अंकन का खुलासा करने की आवश्यकता है। विदेशी मुद्रा जोखिमों के हेजिंग के लिए नियामकीय ढांचे की समीक्षा की गई और 2024 में संशोधित निर्देश जारी किए गए। इन निर्देशों ने ओटीसी और एक्सचेंज-ट्रेडेड दोनों प्रकार के लेनदेन के संबंध में पूर्व नियमों और अधिसूचनाओं को एकल मास्टर निर्देश के तहत समेकित किया, अनुमत विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव उत्पादों के दायरे का विस्तार किया और उपयोगकर्ता वर्गीकरण ढांचे को परिष्कृत किया ताकि आवश्यक जोखिम प्रबंधन क्षमताओं वाले अधिक उपयोगकर्ताओं को अपने जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की अनुमति मिल सके।

एक्सचेंज-ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स (ईटीसीडी): मुद्रा वायदा बाजार में विभिन्न प्रकार के प्रतिभागियों के लिए स्थिति सीमा (पोजीशन लिमिट) सेबी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट की गई है। आरबीआई ने एडी श्रेणी-1 बैंकों को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के मुद्रा डेरिवेटिव बाजार में, अपने खातों के साथ-साथ अपने ग्राहकों की ओर से व्यापार और निपटान सदस्य के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है, बशर्ते वे विवेकपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करें। ईटीसीडी में ट्रेडिंग, सेबी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट विभिन्न मार्जिनों को बनाए रखने के अधीन है। फरवरी 2018 में, भारत में निवासियों और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) को, सभी एक्सचेंजों में संयुक्त रूप से और भारतीय रुपये (आईएनआर) से जुड़े सभी मुद्रा जोड़ों में, बिना अंतर्निहित जोखिम के अस्तित्व को स्थापित किए, 100 मिलियन यूएसडी के समकक्ष की सीमा तक स्थिति (लॉन्ग या शॉर्ट) लेने की अनुमति दी गई।

भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्तियों की पहुंच: आरबीआई ने धीरे-धीरे प्रतिबंधों में ढील दी है और गैर-निवासियों को भारतीय विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपये से जुड़े उनके मुद्रा जोखिमों को हेज करने के लिए अधिक पहुंच प्रदान की है। मार्केट मेकिंग/ट्रेडिंग: पात्र अधिकृत व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा बाजार में मार्केट मेकर के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई है। उन्हें विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) की धारा 10(1) के तहत आरबीआई द्वारा लाइसेंस प्रदान किया गया है। एडी बैंकों के निदेशक मंडल को विदेशी मुद्रा बाजार में परिचालन के लिए शुद्ध रातभर ओपन एक्सचेंज पोजीशन लिमिट (एनओओपीएल) और समग्र अंतराल सीमा (एजीएल) तय करनी होती है। ये सीमाएं नियामकीय सीमा के भीतर निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए।

ऑनशोर बाजार के समय से परे ग्राहक और इंटर-बैंक लेनदेन: ऑफशोर रुपये बाजार पर टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर, आरबीआई ने 2020 में एडी श्रेणी-1 बैंकों को भारत में निवास करने वाले और भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्तियों के साथ ग्राहक और इंटर-बैंक लेनदेन, ऑनशोर बाजार के समय से परे, स्वैच्छिक रूप से करने की अनुमति दी।

भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्तियों के साथ लेनदेन उनके विदेशी शाखाओं और सहायक कंपनियों के माध्यम से भी ऑनशोर बाजार समय से परे किया जा सकता है।

कमोडिटी हेजिंग: भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों, जो आयात और निर्यात व्यापार में शामिल हैं या समय-समय पर आरबीआई द्वारा अनुमोदित हैं, को अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी एक्सचेंजों/बाजारों में अनुमत वस्तुओं की मूल्य जोखिम को हेज करने की अनुमति है। एडी बैंकों की भूमिका मुख्य रूप से मार्जिन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विदेशी मुद्रा राशि भेजने की सुविधा प्रदान करने की होती है, जो लागू दिशा-निर्देशों के अनुपालन में होनी चाहिए। इन संस्थाओं को अपने सोने के जोखिम की मूल्य जोखिम को अधिक कुशलता से हेज करने के लिए, 2022 से निवासी संस्थाओं को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससी) द्वारा मान्यता प्राप्त आईएफएससी में मान्यता प्राप्त एक्सचेंजों पर अपने सोने की मूल्य जोखिम को हेज करने की अनुमति दी गई है। 2024 से, निवासियों को आईएफएससी में ओटीसी डेरिवेटिव्स का उपयोग करके अपने सोने की मूल्य जोखिम को हेज करने की अनुमति दी गई है।

आईएफएससी में रुपये डेरिवेटिव्स: 2020 में, आरबीआई ने भारत में कार्यरत एडी श्रेणी-1 बैंकों को, जो आईबीयू संचालित करते हैं, गैर-डिलीवरबल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स (एनडीडीसी) की पेशकश करने की अनुमति दी, जिसमें रुपये से संबंधित लेनदेन गैर-निवासियों के लिए शामिल हैं। बैंक इन लेनदेन को भारत में अपनी शाखाओं, आईबीयू या विदेशी शाखाओं (भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों के मामले में, मूल बैंक की किसी भी शाखा)/विदेश स्थित पूर्ण स्वामित्व वाली बैंकिंग सहायक कंपनियों/बैंकिंग संयुक्त उपक्रमों के माध्यम से कर सकते हैं। इस अधिसूचना से पहले, भारतीय बैंकों को रुपये से संबंधित एनडीडीसी उत्पाद पेश करने की अनुमति नहीं थी। 2023 में, आईबीयू संचालित करने वाले एडी श्रेणी-1 बैंकों को निवासी गैर-रिटेल उपयोगकर्ताओं को हेजिंग के उद्देश्य से रुपये एनडीडीसी की पेशकश करने की अनुमति दी गई। जनवरी 2024 में, आईबीयू संचालित करने वाले एडी श्रेणी-1 बैंकों को सभी निवासियों को हेजिंग के उद्देश्य से रुपये एनडीडीसी की पेशकश करने की अनुमति दी गई।

इसका उद्देश्य गैर-डिलीवरबल रुपये डेरिवेटिव्स के लिए ऑनशोर बाजार को विकसित करना और उपयोगकर्ताओं को अपने हेजिंग कार्यक्रमों को कुशलतापूर्वक डिज़ाइन करने के लिए लचीलापन प्रदान करना है।

अनधिकृत फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने वाली इकाइयों की चेतावनी सूची: वर्तमान वैधानिक और नियामक ढांचे के अनुसार, भारत में निवास करने वाले व्यक्ति केवल अनुमत चालू और पूंजी खाता लेनदेन के लिए और केवल अधिकृत व्यक्तियों (जिसमें मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज शामिल हैं) से/के लिए फॉरेक्स खरीद/विक्रय कर सकते हैं। जबकि अनुमत फॉरेक्स लेनदेन इलेक्ट्रॉनिक रूप से निष्पादित किए जा सकते हैं, इन्हें केवल आरबीआई द्वारा स्वीकृत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर या मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर आरबीआई द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार ही किया जाना चाहिए।

हाल के वर्षों में, देश में अनधिकृत ईटीपी की वृद्धि हुई है, जो निवासियों को फॉरेक्स ट्रेडिंग सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म समाचार प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया (जैसे सर्च इंजन, ओवर-द-टॉप प्लेटफॉर्म और गेमिंग ऐप्स) पर बड़े पैमाने पर विज्ञापित किए जाते हैं। इनके भ्रामक विज्ञापन अक्सर भोले-भाले ग्राहकों को असामान्य/अत्यधिक रिटर्न, शुरुआती निवेश पर बोनस और सुनिश्चित इनाम के वादों के माध्यम से लक्षित करते हैं।

इस बाजार विकास और इन प्लेटफॉर्म द्वारा लोगों के पैसे गंवाने और धोखाधड़ी की बढ़ती शिकायतों को ध्यान में रखते हुए,

2022 से आरबीआई द्वारा नियमित रूप से सतर्कता परामर्श जारी किए गए हैं। जनता को सलाह दी गई है कि वे अनधिकृत ईटीपी पर फॉरेक्स लेनदेन न करें और ऐसे अनधिकृत लेनदेन के लिए पैसा प्रेषित/जमा न करें। यह स्पष्ट किया गया है कि निवासी व्यक्ति, जो फॉरेक्स लेनदेन एफईएमए के तहत अनुमत उद्देश्यों के अलावा करते हैं या ऐसे ईटीपी पर लेनदेन करते हैं जो आरबीआई द्वारा अधिकृत नहीं हैं, खुद को एफईएमए के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बना लेंगे।

जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से, एक 'अलर्ट सूची' जारी की गई है, जिसमें उन इकाइयों के नाम शामिल हैं जो न तो फेमा के तहत फॉरेक्स डीलिंग के लिए अधिकृत हैं और न ही फॉरेक्स लेनदेन के लिए ईटीपी संचालित करने के लिए अधिकृत हैं। यह सूची नियमित अंतराल पर अपडेट की जाती है। 'अलर्ट सूची' में उन इकाइयों/प्लेटफॉर्म/वेबसाइटों के नाम भी शामिल हैं जो अनधिकृत इकाइयों/ईटीपी को बढ़ावा देते प्रतीत होते हैं, जैसे कि इनके विज्ञापन या प्रशिक्षण/सलाहकार सेवाएं प्रदान करने का दावा करते हुए। यह स्पष्ट किया गया है कि 'अलर्ट सूची' संपूर्ण नहीं है और इसे प्रकाशित करते समय आरबीआई के पास उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। किसी इकाई का नाम सूची में न होना इसे आरबीआई द्वारा अधिकृत मानने का आधार नहीं है।

इसके साथ ही, फॉरेक्स लेनदेन के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) भी प्रकाशित किए गए, जिसमें अधिकृत ईटीपी की सूची शामिल है। जोखिमों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 'आरबीआई कहता है' कार्यक्रम के तहत एक जागरूकता अभियान भी शुरू किया गया है, जिसमें अनधिकृत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर लेनदेन के जोखिमों को उजागर किया गया है। इसके अतिरिक्त, 2024 में, एडी श्रेणी-1 बैंकों को अधिक सतर्क रहने और अनधिकृत विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग को सुविधाजनक बनाने में बैंकिंग चैनलों के दुरुपयोग को रोकने के लिए अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी गई।

अन्य वित्तीय बाजार विनियम

- बाजार दुरुपयोग विनियम: यह विनियमन, जो 2019 में लागू किया गया था, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप था और इसका उद्देश्य एक निष्पक्ष, खुला और पारदर्शी बाजार स्थापित करना था, जो उच्च नैतिक मानकों पर आधारित हो। इस विनियमन के दायरे में बाजार में हेरफेर, बेंचमार्क में हेरफेर, जानकारी का दुरुपयोग या इसी प्रकार की अन्य गतिविधियाँ शामिल हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ईटीपी) का प्राधिकरण: 2018 में, आरबीआई ने वित्तीय बाजार के उपकरणों के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ईटीपी) के प्राधिकरण हेतु एक ढांचा स्थापित करने के लिए "ईटीपी दिशानिर्देश" पेश किए। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य पारदर्शिता में सुधार करना, लेन-देन के समय और लागत को कम करना, प्रभावी ऑडिट ट्रेल्स को सुविधाजनक बनाना, जोखिम नियंत्रण को बढ़ाना और बाजार निगरानी को मजबूत बनाना था। इस ढांचे में विस्तृत पात्रता मानदंड, तकनीकी आवश्यकताएँ और रिपोर्टिंग मानक शामिल हैं। इसके तहत, मौजूदा और नए ईटीपी दोनों के लिए आरबीआई से प्राधिकरण प्राप्त करना अनिवार्य है।
- लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर (एलईआई): वैश्विक वित्तीय संकट के बाद वित्तीय डेटा प्रणालियों की गुणवत्ता और सटीकता में सुधार के लिए बेहतर जोखिम प्रबंधन हेतु "लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर" (एलईआई) को एक प्रमुख उपाय के रूप में विकसित किया गया। एलईआई एक 20-अक्षरों का अद्वितीय अल्फ़ा-न्यूमेरिक कोड है, जिसका उपयोग वित्तीय लेन-देन में शामिल पक्षों की वैश्विक पहचान के लिए किया जाता है। जून 2017 में, इसे रुपये के ब्याज दर डेरिवेटिव्स, विदेशी

मुद्रा डेरिवेटिव्स और क्रेडिट डेरिवेटिव्स के ओटीसी बाजारों में गैर-व्यक्तिगत प्रतिभागियों के लिए लागू किया गया। 2018 में, इस प्रणाली का विस्तार गैर-व्यक्तिगत इकाइयों, जिनमें अनिवासी संस्थाएँ शामिल हैं, द्वारा मनी, गवर्नमेंट सिक्क्योरिटी (जी-सेक) और विदेशी मुद्रा बाजारों में किए गए वित्तीय बाजार लेन-देन तक किया गया। एलईआई प्रणाली को लागू करने के लिए एक चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाया गया और 2020 में इसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया।

- मास्टर डायरेक्शन – भारतीय रिजर्व बैंक (ओटीसी डेरिवेटिव्स में मार्केट-मेकर्स) डायरेक्शन: 2021: 2021 में, भारतीय रिजर्व बैंक ने इन डायरेक्शन्स को जारी किया, जिनका उद्देश्य (i) सिद्धांत-आधारित विनियामक ढांचा तैयार करना; (ii) डेरिवेटिव्स पर व्यापक दिशा-निर्देश (सीजीडी) और अन्य डायरेक्शन्स के बीच ओवरलैप को संबोधित करना; और (iii) अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप डेरिवेटिव बाजारों की बढ़ती परिष्कृत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए प्रावधानों को शामिल करना था। इन डायरेक्शन्स में ओटीसी डेरिवेटिव व्यवसाय के लिए शासन व्यवस्था, जोखिम प्रबंधन, ग्राहक उपयुक्तता और उपयुक्तता सुनिश्चित करने हेतु विनियामक आवश्यकताओं को निर्धारित किया गया है।
- गैर-केंद्रीय रूप से समायोजित डेरिवेटिव्स के लिए मार्जिन का आदान-प्रदान: ओटीसी डेरिवेटिव बाजारों की स्थिरता को मजबूत करने और क्रेडिट जोखिम को कम करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-केंद्रीय रूप से समायोजित ओटीसी डेरिवेटिव लेन-देन के पक्षों के बीच प्रारंभिक और परिवर्तनशील मार्जिन का आदान-प्रदान अनिवार्य कर दिया है। इन दिशा-निर्देशों का दायरा ब्याज दर, विदेशी मुद्रा और क्रेडिट डेरिवेटिव लेन-देन तक फैला है और यह वित्तीय और गैर-वित्तीय संस्थाओं पर लागू होगा, जो ओटीसी डेरिवेटिव बाजारों में अपनी लंबित लेन-देन के आधार पर होंगे।
- वित्तीय बेंचमार्क प्रशासन: 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय बेंचमार्क समिति की सिफारिशों के आधार पर, जो भारत में प्रमुख वित्तीय बेंचमार्क्स को नियंत्रित करने वाली प्रणालियों की समीक्षा करने के लिए बनाई गई थी, फिमिडा और फेडाई को भारतीय रूपये ब्याज दर बेंचमार्क्स और विदेशी मुद्रा बेंचमार्क्स के लिए बेंचमार्क प्रशासनकर्ता के रूप में पहचाना गया था और शासन ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए उपाय किए गए थे। बाद में, 2015 में फिमिडा, फेडाई और आईबीए द्वारा संयुक्त रूप से वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) की स्थापना की गई और इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक स्वतंत्र बेंचमार्क प्रशासनकर्ता के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। 2019 में, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय बेंचमार्क प्रशासनकर्ता (आरबीआई) दिशा-निर्देश, 2019 जारी किए, जो बेंचमार्क प्रक्रियाओं के प्रशासन को बेहतर बनाने, बेंचमार्क प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और बेंचमार्क के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक नियामक ढांचा प्रदान करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित बेंचमार्क्स को वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा प्रशासित 'महत्वपूर्ण बेंचमार्क्स' के रूप में अधिसूचित किया है:

- ओवरनाइट मुंबई इंटरबैंक आउट-राइट रेट (माइबोर)
- यूएसडी/आईएनआर संदर्भ दर
- ट्रेजरी बिल दरें
- सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन
- राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन
- संशोधित मुंबई इंटरबैंक फॉरवर्ड आउट-राइट रेट (एममाइफोर)

2023 के दिसंबर में एक व्यापक जोखिम-आधारित नियामक ढांचा लागू किया गया, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित वित्तीय

बाजारों से संबंधित सभी बेंचमार्क्स के प्रशासन को कवर करता है। इस ढांचे के अंतर्गत, वित्तीय बेंचमार्क प्रशासनकर्ताओं को शासन और पर्यवेक्षण व्यवस्थाओं, नियंत्रणों और पारदर्शिता का पालन करने, और हितों के टकराव से बचने की आवश्यकता होती है ताकि बेंचमार्क्स की सटीकता और अखंडता की सुनिश्चितता की जा सके।

अध्याय 13: भुगतान और निपटान प्रणाली

केंद्रीय बैंक हमेशा भुगतान और निपटान प्रणाली से निकटता से जुड़े रहे हैं। दुनिया भर में केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य मजबूत अर्थव्यवस्था और स्थिर वित्तीय बाजार बनाए रखना है। ये लक्ष्य काफी हद तक सुदृढ़ भुगतान प्रणालियों पर निर्भर हैं। भुगतान प्रणाली, विशेष रूप से खुदरा प्रणाली, दुनिया भर में तेजी से विकसित हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान मानक बनता जा रहा है। नई प्रौद्योगिकियाँ, नए प्रतिभागी और नई बाजार संरचनाएं लगातार उत्पन्न होती रहती हैं।

केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति की जिम्मेदारी लेने से बहुत पहले, बैंकनोट जारी करने के लिए नामित बैंक थे जिसे विधिमान्य मुद्रा के रूप में संरक्षित भुगतान के साधन का मान्यता प्राप्त था। केंद्रीय बैंकिंग की उत्पत्ति भुगतान प्रौद्योगिकी की इस क्रांति को प्रदर्शित करती है, जिसमें धातु से कागज तक, आंतरिक मूल्य के साथ कमोडिटी मनी से लेकर कागजी मुद्रा (फिडुशियारी मनी) तक का अर्थ निहित है। लैटिन मूल "फिडुशिया" से कागजी मुद्रा (फिडुशियारी मनी) उत्पन्न हुआ है, जिसमें पैसे का मूल्य उस विश्वास में निहित है जो इसे उत्पन्न करता है। हालांकि, विश्वास कुछ ऐसी वस्तु नहीं है जिसे उत्पन्न करने के लिए किसी अदृश्य के हाथ इसे छोड़ दिया जा सकता है। विश्वास बनाए रखने के लिए संस्थानों की आवश्यकता है। एक संस्था के रूप में केंद्रीय बैंकों की स्थापना मुद्रा में विश्वास बनाए रखने के लिए की गई है।

भुगतान, भुगतानकर्ता से आदाता को धन का हस्तांतरण है। अधिकतर मामलों में, भुगतान एक आर्थिक एजेंट द्वारा निभाए गए दायित्वों का निर्वहन है, जब भी वह वास्तविक या वित्तीय संसाधनों का अधिग्रहण करता है। केंद्रीय बैंक भुगतान और निपटान प्रणाली में तीन मुख्य भूमिका निभाते हैं, यथा प्रणाली प्रदाता, विनियामक और उपयोगकर्ता।

प्रणाली प्रदाता

- प्रचालक स्वामित्व: केंद्रीय बैंकों ने पारंपरिक रूप से अधिकांश देशों में भुगतान प्रणाली शुरू करने की विकासात्मक भूमिका निभाई है। जहां केंद्रीय बैंक स्वयं प्रणाली नहीं चलाते हैं, वहाँ भुगतान प्रणालियों को विकसित करने के लिए विभिन्न सेवाएं प्रदान की हैं और अभी भी अधिकांश देशों में बड़े मूल्य भुगतान प्रणाली (एलवीपीएस) केंद्रीय बैंकों द्वारा चलाए जाते हैं।
- निपटान प्रणाली: अधिकांश केंद्रीय बैंक केंद्रीय बैंक खाते में एलवीपीएस के निपटान की अनुमति देते हैं। यहां तक कि जब भुगतान प्रणाली निजी ऑपरेटरों द्वारा चलाई जाती है, तो निपटान अंततः केंद्रीय बैंक के खातों में होता है। एक अकाद्य तर्क यह है कि क्यों केंद्रीय बैंक के पैसे में निपटान के जरिए अंतिम निपटान सबसे बेहतर ढंग से हासिल किया जाता है, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण तर्क है कि केंद्रीय बैंक के पास वह क्षमता है कि वह प्रणाली के सुचारू कामकाज को सक्षम करने के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में संपार्श्विक के एवज में तरलता प्रदान करे।

विनियामक

- पर्यवेक्षक: केंद्रीय बैंक पर्यवेक्षण एक प्रमुख केंद्रीय बैंक गतिविधि है। केंद्रीय बैंक नियमों को निर्धारित करके भुगतान प्रणालियों की निगरानी और देखरेख करते हैं (आमतौर पर एक कानूनी ढांचे द्वारा समर्थित)।

- उत्प्रेरक और सुविधाकर्ता: भुगतान प्रणाली को वैश्विक परिप्रेक्ष्य के साथ विकसित किया जाता है, जो सुरक्षित और कुशल वित्तीय लेनदेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। एक कुशल भुगतान प्रणाली की उपलब्धता न केवल कुशल आर्थिक संचरण को बढ़ावा देता है बल्कि मौद्रिक नीति के निर्बाध संचरण और प्रणालीगत जोखिम को कम करने की सुविधा भी प्रदान करती है।

उपयोगकर्ता

बैंकों और सरकार के बैंकर के रूप में, केंद्रीय बैंक भुगतान और निपटान प्रणाली के एक भाग के रूप में एक अनूठी भूमिका में काम करते हैं। यह भूमिका केंद्रीय बैंकों को निरीक्षक की भूमिका निभाने और व्यवधानों के मामले में संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्य करने में सक्षम बनाती है।

भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली

भारत में भुगतान साधनों और प्रक्रियाओं का बहुत लंबा इतिहास रहा है। भारत में उपयोग किए जाने वाले सबसे पहले भुगतान उपकरण सिक्के थे, जिसमें या तो छेद होते थे या चांदी और तांबे में ढाले जाते थे। जबकि सिक्के एक भौतिक समकक्ष का प्रतिनिधित्व करते थे, विनिमय बिलों से जुड़े क्रेडिट सिस्टम ने अंतर-स्थानिक हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की। मौर्य काल में, "*आदेश*" नामक एक उपकरण उपयोग में था, जो किसी बैंकर पर एक आदेश था कि वह किसी तीसरे व्यक्ति को पैसे का भुगतान करे, जो आज के संदर्भ में विनिमय बिल की परिभाषा से मेल खाता है। भारत में विकसित होने वाले ऋण लिखत का सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी *हुंडी कहलाता था*। उनका उपयोग बारहवीं शताब्दी में सबसे अधिक और व्यापक था और आज तक जारी है। एक अर्थ में, वे ऋण लिखत के सबसे पुराने जीवित रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। हुंडियों का उपयोग क्रेडिट उपकरणों (पैसे उधार लेने) और व्यापार लेनदेन (विनिमय बिल के रूप में) के रूप में धन प्रेषण उपकरणों (एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन हस्तांतरित करने के लिए) के रूप में किया जाता था।

आधुनिक अर्थों में, कागजी मुद्रा की उत्पत्ति 18 वीं शताब्दी के अंत में निजी बैंकों के साथ-साथ अर्ध-सरकारी बैंकों द्वारा नोट जारी करने के साथ हुई है। सबसे पहले बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जेनरल बैंक इन बंगाल एण्ड बेहार, और द बंगाल बैंक ने कागजी मुद्रा जारी की। बाद में, तीन प्रेसीडेंसी बैंकों की स्थापना के साथ, नोट जारी करने का काम उनके द्वारा किया गया। प्रत्येक प्रेसीडेंसी बैंक को निश्चित सीमाओं के भीतर नोट जारी करने का अधिकार था। 1861 के द पेपर करेंसी एक्ट ने भारत सरकार को नोट जारी करने का एकाधिकार प्रदान किया, जिससे निजी और प्रेसीडेंसी बैंकों द्वारा नोट जारी करना समाप्त कर दिया गया।

निजी बैंकों और प्रेसीडेंसी बैंकों ने भारतीय मुद्रा बाजार में अन्य भुगतान लिखतों की शुरुआत की। बैंक ऑफ हिंदुस्तान द्वारा चेक जारी किए गए थे, जो 1770 में स्थापित पहला जॉइंट स्टॉक बैंक था। 1833 में, बैंक ऑफ बंगाल के क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स में कैश क्रेडिट खातों को जोड़ा गया था। विनिमय बिलों को खरीदना और बेचना 1839 से बैंक ऑफ बंगाल द्वारा संचालित किए जाने वाला एक कारोबार बन गया।

1881 में, परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई अधिनियम) अधिनियमित किया गया, जिसमें चेक, विनिमय बिल और वचन पत्र जैसे उपकरणों के उपयोग और विशेषताओं को औपचारिक रूप दिया गया। एनआई अधिनियम ने भारत में गैर-नकद कागज भुगतान उपकरणों के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान किया। बैंकिंग प्रणाली के विकास और चेक की संख्या में बढ़ोतरी

के कारण बैंकों के बीच एक संगठित चेक समाशोधन प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ी। 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना के साथ, उस बैंक पर आहरित चेक के जरिए निपटान किया गया। आरबीआई अधिनियम 1935 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना के बाद, प्रेसीडेंसी शहरों में स्थित क्लियरिंग हाउस भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ले लिए गए।

भुगतान प्रणालियों का विकास और आरबीआई की भूमिका

आरबीआई ने हमेशा हमारे देश में भुगतान और निपटान प्रणाली के विकास और पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भुगतान और निपटान अधिनियम, 2007 की धारा 3 के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत भुगतान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए नामित प्राधिकरण है। पीएसएस अधिनियम, 2007 भारत में भुगतान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए अधिकार प्रदान करता है और भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) को उस उद्देश्य और सभी संबंधित मामलों के लिए प्राधिकरण के रूप में नामित करता है। रिज़र्व बैंक इस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत है कि वह भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड (बीपीएसएस) के नाम से जानी जाने वाली अपने केंद्रीय बोर्ड की एक समिति गठित करे ताकि वह इस संविधि के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कार्यों का निष्पादन कर सके और अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। अधिनियम "निवल (नेटिंग)" और "निपटान अंतिमता" के लिए कानूनी आधार भी प्रदान करता है (आमतौर पर इसे धन के हस्तांतरण या/और प्रतिभूतियों के हस्तांतरण द्वारा दायित्व के निर्वहन के रूप में परिभाषित किया जाता है जो अपरिवर्तनीय और बिना शर्त के हैं)। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में, तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली के अलावा अन्य सभी भुगतान प्रणालियां शुद्ध निपटान के आधार पर कार्य करती हैं। भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग बोर्ड को अपने कार्य करने में सहायता प्रदान करता है।

वर्ष 1998 से रिज़र्व बैंक कार्यान्वयन की रूपरेखा को सूचीबद्ध करते हुए प्रत्येक तीन वर्ष के लिए निरंतर भुगतान प्रणाली विजन दस्तावेज़ प्रकाशित करता आ रहा है। समाशोधन परिचालनों का कम्प्यूटरीकरण भुगतान प्रणाली के आधुनिकीकरण की दिशा में पहला बड़ा कदम था। अस्सी के दशक में चेक की मात्रा में तेजी से वृद्धि ने मैनुअल सॉर्टिंग और लिस्टिंग के कार्य को बहुत मुश्किल काम बना दिया। बैंक चेक की भारी मात्रा का सामना करने में असमर्थ थे, जिन्हें क्लियरिंग हाउस में उनकी प्रस्तुति से पहले भौतिक रूप से रखना पड़ता था।

इसके समाधान के रूप में मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन (एमआईसीआर) आधारित मशीनीकृत चेक प्रोसेसिंग तकनीक की शुरुआत की गई। मौजूदा चेकों को एक एमआईसीआर कोड लाइन शामिल करते हुए फिर से डिजाइन किया गया जिसे रीडर-सॉर्टर्स नामक दस्तावेज़ प्रसंस्करण मशीनों द्वारा पढ़ा जा सकता था। इन्हें मुंबई (1986) में स्थापित किया गया, इसके बाद चेन्नै, नई दिल्ली (1987) और कलकत्ता (1989) में स्थापित किया गया। इसके तुरंत बाद मुख्य महानगरों और अन्य प्रमुख केंद्रों में अन्य एमआईसीआर प्रसंस्करण केंद्र शुरू किए गए। ये एमआईसीआर केंद्र बैंकों द्वारा चलाए जा रहे थे। एमआईसीआर समाशोधन के लगभग बीस वर्षों के बाद, चेक ट्रैकेशन प्रणाली (सीटीएस) को पहली बार 2008 में नई दिल्ली में शुरू किया गया और सभी एमआईसीआर केंद्रों को नई दिल्ली, चेन्नै और मुंबई में तीन ग्रीड-सीटीएस प्रणालियों में मिला दिया गया है। सभी तीनों ग्रीडों को अब चेन्नै में सीटीएस के लिए एकल ग्रीड राष्ट्रीय ग्रीड में एकीकृत किया गया है। इसके अलावा, चेक विशेषताओं, जिसमें धोखाधड़ी निवारण उपाय शामिल हैं, के साथ मानकीकरण भी सीटीएस-2010 चेक मानकों के रूप में लाया गया है।

इस बीच, 90 के दशक की शुरुआत में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली तेजी से विकसित हुई। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस

(ईसीएस) को 1990 के दशक की शुरुआत में आरम्भ किया गया, ईसीएस क्रेडिट लाभांश, वेतन, ब्याज भुगतान आदि जैसे कई भुगतानों की सुविधा के लिए तथा ईसीएस डेबिट उपयोगिता भुगतान जैसे कई भुगतान की सुविधा के लिए इस्तेमाल किए गए। ईसीएस ने अपने आप में एक स्थानीय प्रणाली से एक क्षेत्रीय प्रणाली और फिर एक राष्ट्रीय स्तर की प्रणाली में कई बदलाव किए हैं। बैंकों में सीबीएस को अपनाने से इन परिवर्तनों को लागू करने में सुविधा हुई है जिसने भुगतानों के सीधे-थ्रू-प्रोसेसिंग को सक्षम किया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) के प्रचालन से इस क्षेत्र में और अधिक दक्षता लाई गई है। 90 के दशक में शुरू की गई पहले की ईएफटी प्रणाली भी अत्याधुनिक एनईएफटी के रूप में विकसित हुई है। वर्ष 2004 में, देश में पहली बार आरटीजीएस लागू किया गया जिसे 2013 में राष्ट्र को समर्पित एक नई प्रणाली में अपग्रेड किया गया है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणाली और रियल टाइम ग्राँस सेटलमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली का प्रबंधन क्रमशः खुदरा और थोक भुगतानों के निपटान के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा किया जा रहा है। इन प्रणालियों की यात्रा में एनईएफटी और आरटीजीएस ने क्रमशः 16 दिसंबर, 2019 और 14 दिसंबर, 2020 से 24x7x365 आधार पर काम करने का एक महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल किया है।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई)

2008 में, भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक छत्र संगठन, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) को भारत में एक मजबूत भुगतान और निपटान प्रणाली बनाने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और भारतीय बैंक संघ (IBA) की एक पहल के रूप में स्थापित किया गया। एनपीसीआई को कंपनी अधिनियम 1956 (अब कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8) की धारा 25 के प्रावधानों के तहत "लाभ के लिए नहीं" कंपनी के रूप में शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और निपटान प्रणाली के लिए भारत में संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को बुनियादी ढांचा प्रदान करना है। एनपीसीआई परिचालन में अधिक दक्षता प्राप्त करने और भुगतान प्रणालियों की पहुंच को व्यापक बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से खुदरा भुगतान प्रणालियों में नवाचार लाने पर केंद्रित है।

भुगतान प्रणालियों का वर्गीकरण

जबकि सभी भुगतान और निपटान प्रणालियां देश के वित्तीय बुनियादी ढांचे के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, इन प्रणालियों की निगरानी को व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण प्रणालियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जो मूल्य के संदर्भ में बड़े हैं और वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई) और अन्य प्रणालियों को सामूहिक रूप से खुदरा भुगतान प्रणाली के रूप में जाना जाता है।

वित्तीय बाजार अवसंरचना

फाइनेंशियल मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर (FMI) को इसमें भाग लेने वाले संस्थानों के बीच एक बहुपक्षीय प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें सिस्टम के ऑपरेटर शामिल हैं, जिसका उपयोग भुगतान, प्रतिभूतियों, डेरिवेटिव या अन्य वित्तीय लेनदेन को समाशोधन करने, निपटाने या रिकॉर्ड करने के उद्देश्यों के लिए किया जाता है। एफएमआई शब्द आम तौर पर प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण भुगतान प्रणालियों, केंद्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार (सीएसडी), प्रतिभूति निपटान प्रणाली

(एसएसएस), केंद्रीय काउंटर पार्टियों (सीसीपी), और व्यापार रिपॉजिटरी (TRS) को संदर्भित करता है जो वित्तीय लेनदेन के समाशोधन, निपटान और रिकॉर्डिंग की सुविधा प्रदान करते हैं। एफएमआई वित्तीय प्रणाली और व्यापक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वित्तीय स्थिरता और आर्थिक विकास को बनाए रखने और बढ़ावा देने में योगदान करते हैं। साथ ही, एफएमआई भी जोखिम को केंद्रित करते हैं और यदि ठीक से प्रबंधित नहीं किया जाता है, तो एफएमआई वित्तीय झटके या एक प्रमुख स्रोत हो सकते हैं जिसके माध्यम से इन झटकों को वित्तीय बाजारों में प्रसारित किया जाता है। इन जोखिमों से निपटने के लिए, भुगतान और निपटान प्रणाली समिति (सीपीएसएस) और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (आईओएससीओ) ने अप्रैल 2012 में प्रकाशित "वित्तीय बाजार अवसंरचना के लिए सिद्धांत" (पीएफएमआई) शीर्षक से 24 सिद्धांतों का एक व्यापक सेट जारी किया है। इन सिद्धांतों ने मौजूदा मानकों को मजबूत किया है, नए मानकों को लागू किया है और प्राधिकारियों की जिम्मेदारियों को बढ़ाया है।

आरबीआई द्वारा अधिकृत भुगतान प्रणाली को फाइनेंशियल मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर (एफएमआई) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यदि इसमें प्रणालीगत व्यवधानों को ट्रिगर या प्रसारित करने की क्षमता होती है या यदि यह प्रणालीगत या सिस्टम-व्यापी महत्व प्राप्त करती है। आरबीआई कई मापदंडों के आधार पर इसका आकलन करता है, जिसमें संसाधित लेनदेन की मात्रा और मूल्य, बाजार हिस्सेदारी, बाजार जिसमें यह संचालित होता है, प्रतिभागियों की संख्या और प्रकार, परस्पर जुड़ाव की मात्रा और केंद्रित भुगतान गतिविधियां शामिल हैं। इन मानदंडों के आधार पर, आरबीआई ने एफएमआई के रूप में भुगतान और निपटान अवसंरचना से संबंधित निम्नलिखित संस्थाओं की पहचान और विनियमन किया है:

- तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) –** आरटीजीएस सिस्टम मार्च 2004 में लागू किया गया। आरटीजीएस प्रणाली का स्वामित्व और संचालन आरबीआई द्वारा किया जाता है। यह एक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली (SIPS) है जहां अंतर-बैंक भुगतान आरबीआई के खातों में 'वास्तविक' समय और सकल आधार पर निपटाते हैं। आरटीजीएस प्रणाली क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रचालित प्रणालियों सहित अन्य सहायक भुगतान प्रणालियों से जारी होने वाली बहुपक्षीय नेट सेटलमेंट बैच (एमएनएसबी) फाइलों का भी निपटान करती है। आरबीआई ने 2013 में अगली पीढ़ी आरटीजीएस (NG-RTGS) लागू किया, जो अग्रिम तरलता प्रबंधन कार्यों, अगली तारीख पर कार्य करने क्षमता, मात्रा बढ़ाने की क्षमता आदि के साथ ISO20022 मानकों पर बनाया गया है। आरटीजीएस प्रणाली को 15 मार्च, 2023 से विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) कोड लागू करने, आरटीजीएस के विभिन्न नोड्स के बीच बेहतर और कुशल स्वचालित संदेश प्रवाह जैसी नई कार्यक्षमता के साथ अद्यतन और उन्नत किया गया है। इनके अलावा, बेहतर उपयोगकर्ता प्रबंधन नियंत्रण और प्रमाणन प्राधिकरण, अर्थात् बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास और अनुसंधान संस्थान (आईडीआरबीटी) द्वारा जारी नवीनतम डिजिटल प्रमाणपत्रों के साथ संगतता के संदर्भ में प्रणाली की सुरक्षा विशेषताओं को उन्नत किया गया है। आरटीजीएस ने 14 दिसंबर, 2020 से 24x7x365 काम करना शुरू किया।
- प्रतिभूति निपटान प्रणाली (SSS) –** आरबीआई, मुंबई का सार्वजनिक ऋण कार्यालय (पीडीओ) द्वितीयक बाजार में किए गए एकमुश्त और रेपो लेनदेन दोनों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों के लिए प्रतिभूति निपटान प्रणाली का प्रबंधन और संचालन करता है। सरकारी प्रतिभूतियों (एकमुश्त सीधे) को टी+1 आधार पर डीवीपी मॉडल 3 तंत्र का उपयोग करके निपटाया जाता है। रेपो टी + 0 या टी + 1 आधार पर निपटाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, पीडीओ प्रणाली

डिमटेरियालाइज्ड सरकारी प्रतिभूतियों के लिए डिपॉजिटरी के रूप में भी कार्य करती है। भारतीय रिज़र्व बैंक में कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) के कार्यान्वयन से प्रतिभूति निपटान प्रणाली को सीबीएस प्लेटफॉर्म में अंतरित कर दिया गया है।

- **भारतीय समाशोधन निगम लि. (सीसीआईएल) प्रणाली** – सीसीआईएल एक केंद्रीय प्रतिपक्ष (काउंटर पार्टी) (सीसीपी) है जिसे अप्रैल 2001 में देश में सरकारी प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा और मुद्रा बाजारों में लेनदेन के लिए समाशोधन और निपटान प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। सीसीआईएल, आरबीआई द्वारा विनियमित वित्तीय बाजारों के विभिन्न खंडों में एक केंद्रीय प्रतिपक्ष के रूप में कार्य करता है, जैसे सरकारी प्रतिभूति खंड, यूएसडी-आईएनआर और विदेशी मुद्रा फॉरवर्ड सेगमेंट। इसके अलावा, सीसीआईएल ब्याज दर स्वैप/वायदा दर करार बाजार जैसे रुपया मूल्यवर्ग समर्थित ब्याज दर डेरिवेटिव में गैर-गारंटीकृत निपटान प्रदान करता है। यह सीएलएस बैंक निपटान सदस्य के तीसरे पक्ष के सदस्य के रूप में कार्य करते हुए निरंतर लिंकड सेटलमेंट (सीएलएस) बैंक के माध्यम से भारत में बैंकों को क्रॉस करेंसी ट्रेडों के गैर-गारंटीकृत निपटान भी प्रदान करता है। सीसीआईएल, ओटीसी ब्याज दर और विदेशी डेरिवेटिव लेनदेन के लिए ट्रेड रिपोजिटरी (टीआर) के रूप में भी कार्य करता है।

अन्य भुगतान प्रणाली

खुदरा भुगतान प्रणाली

खुदरा भुगतान प्रणालियों को मोटे तौर पर लेनदेन के माध्यम के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात्, कागज आधारित प्रणाली, कार्ड-आधारित प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली और मोबाइल आधारित प्रणाली, हालांकि नवाचार के कारण इसमें समस्याएं आ रही हैं।

○ कागज आधारित सिस्टम

एनपीसीआई द्वारा चेक ट्रेंडेशन सिस्टम (सीटीएस) के माध्यम से बड़े पैमाने पर चेक, डिमांड ड्राफ्ट और भुगतान आदेश जैसी कागज आधारित प्रणालियों का निपटान किया जाता है। छोटे केंद्रों में, एक्सप्रेस चेक क्लियरिंग सिस्टम (ईसीसीएस) नामक एक चुंबकीय मीडिया-आधारित चेक क्लियरिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। हालांकि, सितंबर 2020 से, सभी गैर-सीटीएस क्लियरिंग हाउस (ईसीसीएस केंद्र) को सीटीएस में स्थानांतरित कर दिया गया है।

○ कार्ड आधारित सिस्टम

कार्ड को कार्ड धारक द्वारा जारी करने, उपयोग और भुगतान के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। कार्ड तीन प्रकार के होते हैं (ए) डेबिट, (बी) क्रेडिट, और (सी) प्रीपेड। बिक्री केंद्र टर्मिनल पर कार्ड को अंदर डाला जा सकता है (चिप आधारित कार्ड), टैप किया जा सकता है (संपर्क रहित नियर फील्ड कम्युनिकेशन {NFC} कार्ड) या स्वाइप (मैग्नेटिक-स्ट्राइप कार्ड) किया जा सकता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कार्ड प्रदाताओं को अपने ग्राहकों को कार्ड टोकनाइजेशन सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी है। टोकनाइजेशन सुरक्षित लेनदेन के लिए संवेदनशील कार्ड विवरण को एक विशिष्ट पहचानकर्ता या टोकन से बदल देता है। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देश विभिन्न उपकरणों के लिए टोकनाइजेशन की अनुमति

देते हैं। इसके लिए ग्राहकों की स्पष्ट सहमति की आवश्यकता होती है और सुरक्षा मानकों के अनुपालन को अनिवार्य बनाया गया है। व्यापारियों को वास्तविक कार्ड विवरण संग्रहीत करने से प्रतिबंधित किया जाता है। इन उपायों का उद्देश्य सुरक्षा बढ़ाना, धोखाधड़ी को कम करना और उपभोक्ता डेटा की सुरक्षा करना है। भारत में जारी कार्ड पर कार्ड प्रेजेंट (सीपी) और कार्ड नॉट प्रेजेंट (सीएनपी) के सभी लेनदेन अतिरिक्त कारक प्रमाणीकरण (एएफए) के साथ सुरक्षित हैं। यह एएफए किसी भी रूप में हो सकता है और कुछ मामलों पर इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्म पिन, डायनेमिक वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी), स्टैटिक कोड आदि हैं। इसके अतिरिक्त, सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से, चेक ब्योरों जैसे राशि, तारीख और भुगतान से पूर्व आदाता का सत्यापन करके धोखाधड़ी को कम करने के उद्देश्य से सकारात्मक भुगतान प्रणाली शुरू की गई है जिसमें यह अधिदेश दिया गया है कि बैंक उच्च मूल्य वाले चेकों (50,000 रुपये और उससे अधिक) के मुख्य ब्योरों का समाशोधन करने से पूर्व जारीकर्ता से पुनः पुष्टि करें।

○ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम

उपयोगिता भुगतानों के संग्रहण, लाभांश के भुगतान आदि जैसे थोक और दोहराव वाले भुगतानों के लिए, आरबीआई इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (ईसीएस) चला रहा था। एनपीसीआई द्वारा राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) के प्रचालन के साथ इस क्षेत्र में और अधिक दक्षता लाई गई है। यह थोक और दोहराव वाले भुगतानों को संसाधित करने के लिए एक अखिल भारतीय प्रणाली है और ईसीएस को धीरे-धीरे एनएसीएच में शामिल कर लिया गया है। एनएसीएच प्रणाली प्रतिभागियों को लेनदेन और फाइल-आधारित लेनदेन प्रसंस्करण क्षमताओं दोनों के साथ एक मजबूत, सुरक्षित और स्केलेबल प्लेटफॉर्म प्रदान करती है, जो 1 अगस्त, 2021 से सप्ताह के सभी दिनों के लिए उपलब्ध है। इसमें देश भर के सभी प्रतिभागियों के लिए बेहतरीन बहु-स्तरीय डेटा सत्यापन सुविधा के साथ श्रेणी सुरक्षा सुविधाएं, लागत दक्षता और भुगतान प्रदर्शन (एसटीपी) है।

आरबीआई द्वारा संचालित **राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी)** प्रणाली प्रमुख खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों में से एक है। एनईएफटी एक राष्ट्रव्यापी भुगतान प्रणाली है जो वन-टू-वन फंड ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करती है। इस योजना के तहत, व्यक्ति, फर्म और कॉर्पोरेट इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी भी बैंक शाखा / मोबाइल बैंकिंग / इंटरनेट बैंकिंग से किसी भी व्यक्ति, फर्म या कॉर्पोरेट को धन हस्तांतरित कर सकते हैं, जिसका देश में किसी अन्य बैंक शाखा के साथ खाता है। बैंक शाखा में खाता रखने वाले व्यक्ति, फर्म या कॉर्पोरेट्स एनईएफटी का उपयोग करके फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। यहां तक कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास बैंक खाता नहीं है (वॉक-इन ग्राहक) एनईएफटी का उपयोग करके धन हस्तांतरित करने के निर्देशों के साथ एनईएफटी सक्षम शाखाओं में अनुमत सीमा तक नकद जमा कर सकते हैं। हालांकि, इस तरह के नकद प्रेषण एक सीमा के अधीन हैं। सिस्टम वर्तमान में 24x7 चलता है, जिसमें हर आधे घंटे में बैचों में सेटलमेंट किया जाता है।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के पास भुगतान उत्पादों का एक समूह है। **राष्ट्रीय वित्तीय स्विच (एनएफएस)** जिसे एनपीसीआई ने 2009 में आईडीआरबीटी से लिया था, कार्ड लेनदेन के लिए पूरे देश में सभी एटीएम को जोड़ता है। निर्बाध स्विचिंग की अनुमति देने के अलावा, एनएफएस नेटवर्क उप-सदस्यता मॉडल की अनुमति देता है

जो आरआरबी और स्थानीय सहकारी बैंकों सहित छोटे, क्षेत्रीय बैंकों को एटीएम नेटवर्क में भाग लेने में सक्षम बनाता है। एनपीसीआई ने डिस्कवर फाइनेंशियल सर्विस (डीएफएस), जापान क्रेडिट ब्यूरो (जेसीबी) और चाइना यूनियनपे इंटरनेशनल (सीयूपीआई) जैसी अंतरराष्ट्रीय कार्ड योजनाओं के साथ भी करार किया है जो उनके कार्डधारकों को एनएफएस नेटवर्क से जुड़े एटीएम का उपयोग करने की अनुमति देता है। इन नेटवर्कों के साथ रुपये कोब्रांडेड कार्ड 200 से अधिक देशों में स्वीकार किए जाते हैं।

एनएफएस और इसके आईएमपीएस प्लेटफॉर्म पर आधारित, एनपीसीआई कई नवीन इलेक्ट्रॉनिक खुदरा भुगतान प्रणालियों के साथ आया है। इनमें से कुछ नवोपेक्षी और नई भुगतान प्रणालियां नीचे दी गई हैं:

तत्काल भुगतान प्रणाली (आईएमपीएस) – एनपीसीआई द्वारा संचालित तत्काल भुगतान प्रणाली (आईएमपीएस) छोटे प्रेषण के लिए 24x7 सुविधा प्रदान करती है। आईएमपीएस त्वरित और वास्तविक समय फंड ट्रांसफर प्रदान करता है जो एक त्वरित, 24x7, इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सेवा प्रदान करता है जिसे मोबाइल, इंटरनेट, एटीएम, एसएमएस, शाखा जैसे कई चैनलों पर एक्सेस किया जा सकता है। आईएमपीएस एक सशक्त सेवा है जो सुरक्षित और किफायती तरीके से पूरे भारत में बैंकों के भीतर तुरंत धन हस्तांतरित करने की अनुमति देती है। आईएमपीएस प्लेटफॉर्म के स्थिरीकरण ने एनपीसीआई को अन्य नवाचारों के साथ आने की अनुमति दी है।

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) - यूपीआई एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लिकेशन (किसी भी भाग लेने वाले बैंक के) में विभिन्न बैंकिंग सुविधाओं, निर्बाध फंड रूटिंग और मर्चेन्ट भुगतान को एक ही छत में विलय करने का अधिकार देती है। यह "पीयर टू पीयर" संग्रह अनुरोध को भी पूरा करता है जिसे आवश्यकता और सुविधा के अनुसार शेड्यूल और भुगतान किया जा सकता है। डिजिटल भुगतान प्रणाली होने के नाते, यह 24x7 और सार्वजनिक छुट्टियों के दौरान उपलब्ध है। पारंपरिक मोबाइल वॉलेट के विपरीत, जो ग्राहक के पैसे को अपने वॉलेट में अनुमत सीमा तक रखते हैं, यूपीआई लेनदेन का अनुरोध किए जाने पर सीधे बैंक खाते से धन निकलाता है और जमा करता है। यह वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (बैंक द्वारा प्रदान की गई एक विशिष्ट आईडी), आईएफएससी कोड के साथ खाता संख्या, एमएमआईडी (मोबाइल मनी आइडेंटिफायर) के साथ मोबाइल नंबर, आधार नंबर या एक बार उपयोग की जाने वाली वर्चुअल आईडी का उपयोग करता है। प्रत्येक भुगतान की पुष्टि के लिए एक एमपीआईएन (मोबाइल बैंकिंग व्यक्तिगत पहचान संख्या) आवश्यक है। कई बैंकों ने यूपीआई के आधार पर ऐप्स बनाए हैं। एनपीसीआई ने **भारत इंटरफेस फॉर मनी (भीम) नामक अपना यूपीआई आधारित ऐप लॉन्च किया है।** वर्तमान में, बचत खाता, ओवरड्राफ्ट खाता, प्रीपेड वॉलेट, रुपये क्रेडिट कार्ड और बैंकों में पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइन को यूपीआई से जोड़ा जा सकता है।

नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (एनईटीसी) – एनपीसीआई ने भारतीय बाजार की इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (एनईटीसी) प्रोग्राम विकसित किया है। यह निपटान और विवाद प्रबंधन के लिए क्लियरिंग हाउस सेवाओं सहित एक इंटरऑपरेबल राष्ट्रव्यापी टोल भुगतान समाधान प्रदान करता है। इंटरऑपरेबिलिटी, जैसा कि यह राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (एनईटीसी) प्रणाली पर लागू होता है, प्रक्रियाओं, व्यावसायिक नियमों और तकनीकी विशिष्टताओं का एक सामान्य समूह शामिल करता है जो ग्राहक को किसी

भी टोल प्लाजा पर भुगतान मोड के रूप में अपने फास्ट टैग का उपयोग करने में सक्षम बनाता है, भले ही टोल प्लाजा का अधिग्रहण किसने किया हो।

फास्ट टैग (FASTag) एक ऐसा उपकरण है जो चलते हुए वाहनों के लिए सीधे टोल भुगतान करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) तकनीक को नियोजित करता है। फास्ट टैग (RFID टैग) वाहन की विंडस्क्रीन पर चिपका दिया जाता है और ग्राहक को फास्ट टैग से जुड़े खाते से सीधे टोल भुगतान करने में सक्षम बनाता है। फास्ट टैग मुनाफे के साथ-साथ कैशलेस भुगतान की सुविधा प्रदान करता है, जैसे - ईंधन और समय की बचत क्योंकि ग्राहक को टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ता है।

भारत क्यूआर कोड – आरबीआई के आदेश पर, प्रमुख कार्ड नेटवर्क, मास्टरकार्ड, वीज़ा और एनपीसीआई ने इंटरऑपरेबल, भारत क्यूआर कोड विकसित किया है। क्यूआर कोड या क्लिक रिस्पॉन्स कोड एक द्वि-आयामी मशीन-पठनीय कोड है, जो काले और सफेद चौकोर से बना होता है और इसका उपयोग यूआरएल या अन्य जानकारी संग्रहीत करने के लिए किया जाता है। इन्हें स्मार्टफोन के कैमरे से आसानी से पढ़ा जा सकता है। व्यापारियों को अपने परिसर में क्यूआर कोड प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। उपयोगकर्ता बीक्यूआर सक्षम मोबाइल बैंकिंग ऐप के माध्यम से इन क्यूआर को स्कैन कर सकते हैं और कार्ड लिंकड अकाउंट / वीपीए / आईएफएससी + अकाउंट / आधार का उपयोग करके भुगतान कर सकते हैं।

आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) – एईपीएस, बैंक समर्थित वाला मॉडल है जो आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके किसी भी बैंक के बिजनेस कॉर्रेस्पॉन्डेंट के माध्यम से माइक्रो एटीएम पर ऑनलाइन इंटरऑपरेबल वित्तीय समावेशन लेनदेन (नकद जमा, नकद निकासी, इंटरबैंक या इंटरबैंक फंड ट्रांसफर, बैलेंस पूछताछ और एक मिनी स्टेटमेंट प्राप्त करने) की अनुमति देता है।

यूएसएसडी (*99#) - जबकि बैंक ऐप आधारित मॉडल न केवल भुगतान के लिए बल्कि मोबाइल बैंकिंग के सभी रूपों के लिए व्यापक रूप से प्रचलित हैं, एनपीसीआई ने सभी गैर-स्मार्ट फोन उपयोगकर्ताओं को बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करके मोबाइल बैंकिंग को अधिक सुलभ बनाने के लिए राष्ट्रीय एकीकृत यूएसएसडी प्लेटफॉर्म (एनयूयूपी) लॉन्च किया है। देश भर में हर आम आदमी तक बैंकिंग सेवाओं को ले जाने के लिए *99# सेवा शुरू की गई है। बैंकिंग ग्राहक अपने मोबाइल फोन पर सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के लिए एक "सामान्य नंबर" *99# डायल करके और मोबाइल स्क्रीन पर प्रदर्शित एक इंटरैक्टिव मेनू के माध्यम से लेनदेन करके इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। *99# सेवा के तहत दी जाने वाली प्रमुख सेवाओं में खाते में धन भेजने और प्राप्त करने, बैलेंस पूछताछ, यूपीआई पिन सेट करने / बदलने के अलावा अन्य सेवाओं की प्राप्ति करना शामिल है। *99# सेवा उपभोक्ता सेवा के लिए एक अद्वितीय इंटरऑपरेबल डायरेक्ट है जो बैंकों और टीएसपी (दूरसंचार सेवा प्रदाता) जैसे विविध पारिस्थितिकी तंत्र भागीदारों को एक साथ लाती है। आम आदमी के लिए स्थानीय भाषा में बातचीत की सुविधा के लिए यह कई क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध है।

आधार भुगतान पुल (एपीबी) - एनपीसीआई द्वारा विकसित एनएसीएच की एपीबी प्रणाली प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना को सफल बनाने में सरकार और सरकारी एजेंसियों की मदद कर रही है। एपीबी प्रणाली आधार संख्याओं का उपयोग

करके इच्छित लाभार्थियों को सरकारी सब्सिडी और लाभ सफलतापूर्वक प्रसारित कर रही है। एपीबी प्रणाली एक तरफ सरकारी विभागों और उनके प्रायोजक बैंकों को लाभार्थी बैंकों के साथ तथा दूसरी तरफ लाभार्थी के साथ जोड़ती है।

रुपे कार्ड नेटवर्क – भारतीय बैंक मास्टरकार्ड, वीज़ा और अमेरिकन एक्सप्रेस सहित सभी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय कार्ड नेटवर्क के विभिन्न प्रकार के कार्ड जारी करते हैं। एनपीसीआई ने रुपे नामक अपना स्वदेशी कार्ड नेटवर्क लॉन्च किया है। एनपीसीआई द्वारा शुरू की गई रुपे कार्ड भुगतान योजना की कल्पना एक घरेलू ओपन-लूप, बहुपक्षीय प्रणाली लागू करने के लिए की गई है जो भारत में सभी भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान में भाग लेने की अनुमति देगी। नेशनल फाइनेंशियल स्विच के तहत रुपे कार्ड पूरे भारत में सभी स्वचालित टेलर मशीनों (एटीएम) पर स्वीकार किए जाते हैं, और डीएफएस के साथ एनपीसीआई के समझौते के तहत, रुपे कार्ड अंतरराष्ट्रीय डिस्कवर नेटवर्क पर स्वीकार किए जाते हैं। बैंक रुपे के प्रीपेड, डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं और तीनों में से सबसे ज्यादा डेबिट कार्ड जारी किए जाते हैं। कार्ड के टोकनाइजेशन की अनुमति देने वाले हालिया उदारीकरण से कार्ड को उपयोगकर्ता के डिवाइस से सुरक्षित रूप से उपयोग करने की अनुमति देंगे, जहां उन्हें सुरक्षित तरीके से टोकन किया जा सकता है और नियर फील्ड कम्युनिकेशन (एनएफसी) तकनीक के माध्यम से लेनदेन के लिए सक्षम किया जा सकता है। कार्ड का उपयोग ऑनलाइन लेनदेन, एटीएम और पॉइंट ऑफ़ सेल टर्मिनलों में बड़े पैमाने पर किया जाता है।

नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) – नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC), भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा परिकल्पित एक इंटर-ऑपरेबल ट्रांसपोर्ट कार्ड है। इसे 4 मार्च 2019 को लॉन्च किया गया है। ट्रांसपोर्ट कार्ड उपयोगकर्ता को यात्रा, टोल शुल्क (टोल टैक्स), खुदरा खरीदारी और पैसे निकालने के लिए भुगतान करने में सक्षम बनाता है। यह रुपे कार्ड प्रणाली के माध्यम से सक्षम है। एनसीएमसी कार्ड, जो क्यूस्पार्क (रुपे चिप के भुगतान अनुप्रयोग के लिए त्वरित विशिष्टता) विनिर्देश द्वारा संचालित है, भागीदार बैंकों द्वारा प्रीपेड, डेबिट या क्रेडिट रुपे कार्ड से जुड़े खाते के कॉम्बो के रूप में जारी किया जा सकता है, जिसका उपयोग नियमित ऑनलाइन भुगतान के लिए किया जा सकता है, जिसमें कार्ड बैलेंस वाला एक अन्य प्रीपेड घटक होता है जिसका उपयोग पारगमन में छोटे मूल्य के ऑफ़लाइन भुगतानों के लिए किया जा सकता है। qSPARC एक दोहरी इंटरफ़ेस ओपन लूप भुगतान विनिर्देश है, जिसमें एक ही कार्ड पर कई भुगतान एप्लिकेशन लोड करने का विकल्प है।

एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) को 3 अप्रैल, 2020 को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया (NPCI) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया। एनपीसीआई की अंतरराष्ट्रीय शाखा के रूप में, एनआईपीएल एनपीसीआई की स्वदेशी, सफल रीयल-टाइम भुगतान प्रणाली – यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (यूपीआई) और कार्ड योजना – रुपे को भारत के बाहर तैनात करने के लिए समर्पित है।

अन्य खुदरा भुगतान और निपटान पहल

व्हाइट लेवल एटीएम (WLA) - गैर-बैंकों द्वारा स्थापित, स्वामित्व और संचालित एटीएम को डब्ल्यूए कहा जाता है। गैर-बैंक कंपनियों को डब्ल्यूएलए स्थापित करने की अनुमति देने का औचित्य विशेष रूप से अर्ध-शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक/विस्तारित ग्राहक सेवा के लिए एटीएम के भौगोलिक दायरे को बढ़ाना रहा है।

प्री-पेड इंस्ट्रूमेंट्स (पीपीआई) – पीपीआई भुगतान उत्पादों की एक विशिष्ट श्रेणी है, जिन्होंने हाल के दिनों में प्रमुखता प्राप्त की है, खासकर मोबाइल वॉलेट के उपयोग के कारण। पीपीआई बंद, अर्ध-बंद और खुले सिस्टम में जारी किए जा सकते हैं। आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त करने के बाद पीपीआई बैंकों और गैर-बैंकों दोनों द्वारा जारी किए जाते हैं। खुले पीपीआई जो नकद निकासी की अनुमति देते हैं, केवल बैंकों द्वारा जारी किए जा सकते हैं। पीपीआई दिशानिर्देश दो प्रकार के पीपीआई की अनुमति देते हैं, एक न्यूनतम केवाईसी के साथ और दूसरा अलग-अलग सीमाओं के साथ पूर्ण केवाईसी के साथ। पीपीआई जारीकर्ता के लिए पूर्ण-केवाईसी पीपीआई (केवाईसी -अनुपालन पीपीआई) धारकों को अधिकृत कार्ड नेटवर्क (कार्ड के रूप में पीपीआई के लिए) और यूपीआई (पीपीआई के लिए वॉलेट के रूप में) के माध्यम से इंटरऑपरेबिलिटी देना अनिवार्य होगा।

भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) - भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) एक एकीकृत बिल भुगतान प्लेटफार्म है जो विभिन्न भुगतान मोड (यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, कार्ड, नकद, प्रीपेड भुगतान उपकरण, आदि) का उपयोग करके कई चैनलों (मोबाइल ऐप, मोबाइल बैंकिंग, भौतिक एजेंटों, बैंक शाखाओं आदि) के माध्यम से बिलों के भुगतान / संग्रह को सक्षम बनाता है। सिस्टम कई भुगतान मोड और भुगतान की तत्काल पुष्टि प्रदान करता है। बीबीपीएस एकल भारत बिल भुगतान केंद्रीय इकाई (बीबीपीसीयू) और कई भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयों (बीबीपीओयू) के साथ एक स्तरीय संरचना के रूप में काम करता है – यानी, बिलर ऑपरेटिंग यूनिट या ग्राहक परिचालन इकाइयां या दोनों के साथ काम करता है। एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड (NBBL), एनपीसीआई की सहायक कंपनी बीबीपीसीयू अधिकृत है। यह प्रणाली सभी बिलों के लिए वन-स्टॉप भुगतान मंच है, जो लेनदेन की निश्चितता, विश्वसनीयता और सुरक्षा के साथ पूरे भारत में सभी ग्राहकों को एक इंटरऑपरेबल और सुलभ "कभी भी , कहीं भी" बिल भुगतान सेवा प्रदान करती है। एनबीबीएल ने डिजिटल भुगतान के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान (ODR) प्रणाली पर आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुपालन में केंद्रीकृत एंड-टू-एंड शिकायत प्रबंधन के लिए एक विवाद समाधान ढांचा रखा है।

व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (TReDS) व्यापार प्राप्तियों के वित्तपोषण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। टीआरडीएस का उद्देश्य छूट के माध्यम से कॉर्पोरेट खरीदारों पर तैयार किए गए एमएसएमई के चालान/बिलों के वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करना है। बिलों को "फैक्टरिंग इकाइयों" में परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें बाद में TReDS प्लेटफॉर्म पर कारोबार किया जाता है जहां फाइनेंसर बोली लगा सकते हैं, और विक्रेता सबसे अच्छी बोली का चयन कर सकता है। TReDS के तहत संसाधित लेनदेन एमएसएमई के लिए "आश्रय रहित" हैं। क्रेताओं की क्रेडिट रेटिंग पर ध्यान दिए बिना उनके भुगतानों के वित्तपोषण/छूट को प्रोत्साहित करने के लिए, TReDS पर बीमा सुविधा की अनुमति है और तदनुसार, बीमा कंपनियों को एमएसएमई विक्रेताओं, खरीदारों और फाइनेंसरों के अलावा, TReDS पर "चौथे भागीदार" के रूप में भाग लेने की अनुमति है। फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम के तहत फैक्टरिंग व्यवसाय करने के लिए पात्र सभी संस्थाओं/ संस्थानों को टीआरडीएस में फाइनेंसरों के रूप में भाग लेने की अनुमति है। फाइनेंसरों को अपने मौजूदा पोर्टफोलियो को अन्य फाइनेंसरों को ऑफलोड करने की अनुमति देने के लिए, TReDS प्लेटफार्मों को उसी प्लेटफॉर्म में द्वितीयक बाजार को सक्षम करने की अनुमति दी गई है।

भुगतान एग्रीगेटर (पीए) ऐसी संस्थाएं हैं जो ई-कॉमर्स साइटों और व्यापारियों को अपने भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए ग्राहकों से विभिन्न भुगतान साधनों को स्वीकार करने की सुविधा प्रदान करती हैं जिसमें व्यापारियों को अपने स्वयं के लिए एक अलग भुगतान एकीकरण प्रणाली बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भुगतान एग्रीगेटर व्यापारियों को अधिग्रहणकर्ताओं से जुड़ने की सुविधा प्रदान करते हैं। इस प्रक्रिया में, वे ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करते हैं, इकट्ठा करते हैं और एक समय अवधि के बाद उन्हें व्यापारियों को हस्तांतरित करते हैं। पेमेंट एग्रीगेटर-क्रॉस बॉर्डर (पीए-सीबी) ऐसी संस्थाएं हैं जो ऑनलाइन मोड में अनुमत वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात के लिए सीमा पार भुगतान लेनदेन की सुविधा प्रदान करती हैं।

पेमेंट गेटवे (पीजी) ऐसी इकाइयां हैं जो धन की आवाजाही में किसी भी भागीदारी के बिना ऑनलाइन भुगतान लेनदेन के मार्ग और प्रसंस्करण की सुविधा के लिए प्रौद्योगिकी अवसंरचना प्रदान करती हैं।

व्यापार निरंतरता और ग्राहक संरक्षण पहल

ए) बिक्री केंद्र (PSO) को जारी किए गए प्राधिकरण प्रमाणपत्र (CoA) की स्थायी वैधता - भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने लाइसेंसिंग अनिश्चितताओं को कम करने और उन्हें अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाने के लिये भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) को स्थायी वैधता प्रदान की है। यह कुछ शर्तों के अधीन है, जिनमें निम्न शामिल हैं:

- अनुपालन: पीएसओ को अपने प्राधिकरण के नियमों और शर्तों का पूरी तरह से पालन करना होगा।
- प्रवेश मानदंड: पीएसओ को पूंजी और निवल मूल्य के लिए प्रवेश मानदंडों को पूरा करना होगा।
- नियामक चिंताएँ: पीएसओ के संचालन के बारे में कोई बड़ी नियामक या पर्यवेक्षी चिंताएँ नहीं होनी चाहिये।
- ग्राहक शिकायत निवारण: पीएसओ के पास एक प्रभावी ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए।
- प्रतिकूल रिपोर्ट: आरबीआई या अन्य नियामकों या वैधानिक निकायों के अन्य विभागों से कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए।

इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक ने पीएसओ को किसी भी अधिग्रहण, नियंत्रण के अधिग्रहण, या भुगतान प्रणाली गतिविधियों की बिक्री के लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अनिवार्य किया है, खासकर जब इन गतिविधियों को अनधिकृत संस्थाओं को हस्तांतरित किया गया हो।

बी) गैर-बैंकों के लिये केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों तक पहुँच - आरबीआई द्वारा संचालित केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली (सीपीएस) – आरटीजीएस और एनईएफटी की सदस्यता बैंकों, कुछ अपवादों के साथ, जैसे कि समाशोधन निगम और चुनिंदा विकास वित्तीय संस्थान जैसी विशेष संस्थाएँ तक सीमित थी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 28 जुलाई 2021 से कुछ शर्तों के अधीन गैर-बैंकिंग संस्थाओं को सीपीएस तक सीधी पहुँच अनुमति दी है क्योंकि भुगतान क्षेत्र में गैर-बैंकिंग संस्थाओं की भूमिका (जैसे, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) जारीकर्ता, कार्ड नेटवर्क, व्हाइट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) ऑपरेटर, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरडीएस) प्लेटफॉर्म) के महत्व और मात्रा में वृद्धि हुई है और उन्होंने प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर उपयोगकर्ताओं को अनुकूलित समाधान प्रदान करके नवाचार किया है। गैर-बैंकों के लिये सीपीएस तक

सीधी पहुँच भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में समग्र जोखिम को कम करती है। यह गैर-बैंकों के लिए लाभ भी लाता है जैसे भुगतान की लागत में कमी, बैंकों पर निर्भरता को कम करना, भुगतान पूरा करने में लगने वाले समय को कम करना, भुगतानों की अंतिमता में अनिश्चितता को समाप्त करना क्योंकि निपटान केंद्रीय बैंक के धन में किया जाता है, आदि। निधि अंतरण के निष्पादन में विफलता या देरी के जोखिम से भी बचा जा सकता है जब लेनदेन सीधे गैर-बैंक संस्थाओं द्वारा शुरू और संसाधित किए जाते हैं।

सी) गैर-बैंक बिक्री केंद्र (पीएसओ) के लिए साइबर लचीलापन और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण

साइबर लचीलापन एक अवधारणा है जो व्यापार निरंतरता, सूचना प्रणाली सुरक्षा और संगठनात्मक लचीलापन को एक साथ लाती है। यह अवधारणा चुनौतीपूर्ण साइबर घटनाओं, जैसे साइबर हमले, प्राकृतिक आपदाओं या आर्थिक मंदी का सामना करने के बावजूद इच्छित परिणाम देने की क्षमता की जानकारी देती है। कुशल सूचना सुरक्षा और लचीलापन बताता है कि कोई संगठन बिना किसी डाउनटाइम के व्यवसाय संचालन को कितनी अच्छी तरह जारी रख सकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस संबंध में गैर-बैंक भुगतान प्रणाली प्रचालकों को निदेश जारी किए हैं जिनमें पदनामित मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) और नियमित जोखिम मूल्यांकन के साथ एक व्यापक अभिशासन ढांचा को अनिवार्य किया गया है। भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों को एन्क्रिप्शन, सुरक्षित कोडिंग और बहु-कारक प्रमाणीकरण सहित मजबूत साइबर सुरक्षा नियंत्रण लागू करना होगा। एक अच्छी तरह से परिभाषित घटना प्रतिक्रिया योजना के साथ-साथ निरंतर निगरानी और घटना रिपोर्टिंग तंत्र की आवश्यकता होती है। इसके लिए तृतीय-पक्ष विक्रेताओं को सुरक्षा मानकों का पालन करना चाहिए और कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आवश्यक हैं। डिजिटल भुगतान प्रणालियों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई के निर्देशों का अनुपालन और सुरक्षा नियंत्रणों का आकलन करने के लिए नियमित जांच अनिवार्य है।

डी) सीमित देयता - अनधिकृत लेनदेन के मामलों में, यदि कोई ग्राहक तुरंत अनधिकृत लेनदेन की रिपोर्ट करता है, तो उसकी देयता एक पूर्वनिर्धारित राशि तक और घटना की रिपोर्ट करने में लगने वाला समय तक सीमित होती है। सीमित देयता नियम केवल तभी लागू होते हैं जब नुकसान ग्राहक की लापरवाही के कारण नहीं हुआ था। तीन दिनों के भीतर रिपोर्ट किए गए लेनदेन के लिए, ग्राहक की अधिकतम देयता शून्य पर निर्धारित किया जाता है। यदि चार से सात दिनों के बीच रिपोर्ट की जाती है, तो देयता बढ़ जाती है लेकिन सीमित रहती है। सात दिनों से परे, देयता जारीकर्ता की बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के आधार पर निर्धारित की जाती है। इन उपायों का उद्देश्य ग्राहकों को अनधिकृत लेनदेन के कारण महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान से बचाना है, जबकि डिजिटल भुगतान प्रणालियों में सुरक्षा और विश्वास बढ़ाने के लिए ऐसी घटनाओं की समय पर रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करना है।

ई) टोकनाइजेशन वास्तविक कार्ड विवरण को अद्वितीय टोकन के साथ बदलकर कार्ड लेनदेन की सुरक्षा को बढ़ाता है। कार्ड जारी करने वाले बैंकों को टोकनाइजेशन सेवाएं लागू करने की आवश्यकता होती है, जिससे व्यापारियों को कार्ड विवरण के बजाय टोकन स्टोर करने की अनुमति मिलती है, इस प्रकार डेटा उल्लंघनों का जोखिम कम होता है। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि पारदर्शिता और नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए कार्ड विवरण को टोकन में बदलने से पहले ग्राहक की सहमति

प्राप्त की जाए। टोकन का उपयोग केवल उस व्यापारी के लेनदेन के लिए किया जा सकता है जिसने टोकन का अनुरोध किया है, जिससे सुरक्षा बढ़ जाती है। डेटा सुरक्षा मानकों के साथ इसे कड़ाई से अनुपालन निर्धारित किया गया है और नियमित ऑडिट को अनिवार्य किया गया है। बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे प्रगामी ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र बनाएं और ग्राहकों को टोकनाइजेशन के लाभों और प्रक्रिया के बारे में शिक्षित करें। इस पहल का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधा बनाए रखते हुए डिजिटल लेनदेन में विश्वास और सुरक्षा को बढ़ावा देना है।

एफ) आवर्ती ऑनलाइन लेनदेन के लिये ई-अधिदेश - आवर्ती लेनदेन के लिये ई-अधिदेश के प्रसंस्करण की रूपरेखा अगस्त 2019 में ग्राहक सुविधा के साथ डिजिटल लेनदेन की सुरक्षा और संरक्षा को संतुलित करने के लिए शुरू किया गया था। एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन (AFA) के बिना ई-मैडेट के निष्पादन की सीमा 12 दिसंबर, 2023 से निम्नलिखित श्रेणियों (ए) म्यूचुअल फंड की सब्सक्रिप्शन, (बी) इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान, और (सी) क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान, के लिए ₹1,00,000/- प्रति लेनदेन के रूप में निर्धारित की गई है। :

जी) आरबीआई - डिजिटल भुगतान सूचकांक - भारतीय रिज़र्व बैंक ने देश भर में भुगतानों के डिजिटलीकरण की मात्रा को जानने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक (डीपीआई) का निर्माण किया है। आरबीआई- डीपीआई में पांच व्यापक पैरामीटर शामिल हैं जो विभिन्न समय अवधि में देश में डिजिटल भुगतान की गहराई और पैठ को मापने में सक्षम बनाते हैं। ये पैरामीटर हैं – (i) भुगतान सक्षम (भार 25%), (ii) भुगतान अवसंरचना- मांग-पक्ष कारक (10%), (iii) भुगतान अवसंरचना – आपूर्ति-पक्ष कारक (15%), (iv) भुगतान प्रदर्शन (45%) और (v) उपभोक्ता केंद्रितता (5%)। इनमें से प्रत्येक पैरामीटर में उप-पैरामीटर होते हैं, जो विभिन्न मापने योग्य संकेतकों से मिलकर बनते हैं। आरबीआई-डीपीआई का निर्माण मार्च 2018 को आधार अवधि के रूप में किया गया है, अर्थात्, मार्च 2018 के लिए डीपीआई स्कोर 100 पर निर्धारित किया गया है। आरबीआई-डीपीआई को छमाही आधार पर बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जा रहा है।

एच) पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (PIDF) योजना – जनवरी 2021 में शुरू की गई योजना (और अंतिम बार 31 दिसंबर, 2025 तक बढ़ाई गई) है जो भारत में भुगतान स्वीकृति उपकरणों की संख्या बढ़ाने के लिए बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। योजना के उद्देश्यों में निम्न शामिल हैं:

- छोटे क्षेत्रों में भुगतान बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना
- भुगतान स्वीकृति बुनियादी ढांचे स्थापित करने को प्रोत्साहित करना
- टियर-3 से टियर-6 केंद्रों में भुगतान स्वीकृति तकनीक की स्थापना
- वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना

यह योजना पॉइंट-ऑफ-सेल टर्मिनल, अन्य भुगतान स्वीकृति बुनियादी ढांचे, साउंडबॉक्स डिवाइस और आधार-सक्षम बायोमेट्रिक डिवाइस के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सब्सिडी राशि 60% से 90% तक होती है।

आई) जियो-टैगिंग - डिजिटल भुगतान को प्रसारित करने और पूरे भारत में समावेशी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कई पहलुओं के साथ एक मजबूत भुगतान स्वीकृति बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है। जियो-टैगिंग, जो भुगतान बिंदुओं के भौगोलिक निर्देशांक को कैप्चर करती है, क्षेत्रीय डिजिटल भुगतान पैठ और बुनियादी ढांचे के घनत्व की बेहतर निगरानी

को सक्षम बनाती है। यह डेटा लक्षित नीति हस्तक्षेपों और डिजिटल साक्षरता पहलों का समर्थन करता है, जिससे भुगतान प्रणाली परिनियोजन को अनुकूलित करने में मदद मिलती है।

जे) डिजिटल भुगतान के लिये ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) प्रणाली – अगस्त 2020 में, रिज़र्व बैंक ने डिजिटल लेनदेन में उपभोक्ता शिकायतों के समाधान को कारगर बनाने के लिये भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) प्रणाली पर दिशानिर्देश लागू किए हैं। इन दिशानिर्देशों में कहा गया है कि पीएसओ 01 जनवरी, 2021 से ऐसे ओडीआर तंत्र को लागू करें जो शून्य या न्यूनतम मैनुअल हस्तक्षेप के साथ ग्राहक विवादों और शिकायतों को हल करने के लिए पारदर्शी, नियम-आधारित, प्रणाली-संचालित, उपयोगकर्ता के अनुकूल और निष्पक्ष हो। आरबीआई का ध्यान डिजिटल भुगतान से संबंधित विवादों को संबोधित करने में पारदर्शिता, समय पर निवारण और दक्षता सुनिश्चित करके ग्राहक अनुभव को बढ़ाने पर है। ये दिशानिर्देश विफल लेनदेन से जुड़े विवादों को प्राथमिकता देते हैं और चरणबद्ध तरीके से अन्य शिकायतों में ओडीआर कवरेज का विस्तार करना चाहते हैं। यह पहल डिजिटल भुगतान में विश्वास और स्थायिता को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं के लिए एक सहज और सुरक्षित अनुभव सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई के व्यापक लक्ष्य का एक हिस्सा है।

भविष्य के लिए विज़न

भारत में भुगतान प्रणालियों की यात्रा पिछले आठ वर्षों में अभूतपूर्व रही है। भुगतान विज़न दस्तावेज देश में भुगतान प्रणालियों को और उन्नत करने के लिए तैयार किए जाते हैं। विज़न 2025 उपयोगकर्ताओं को बेहतर सुविधा के साथ किसी भी समय और कहीं भी सुलभ, किफायती भुगतान विकल्प प्रदान करने का वादा करता है। यूपीआई की क्षमता को दुनिया भर में कई प्राधिकरणों द्वारा मान्यता दी गई है। रिज़र्व बैंक संबंधित हितधारकों के साथ मिलकर घरेलू भुगतान प्रणालियों को विस्तार करने के लिए वैश्विक आउटरीच पहलों का सक्रिय रूप से समर्थन करता है।

अध्याय 14: मुद्रा प्रबंधन

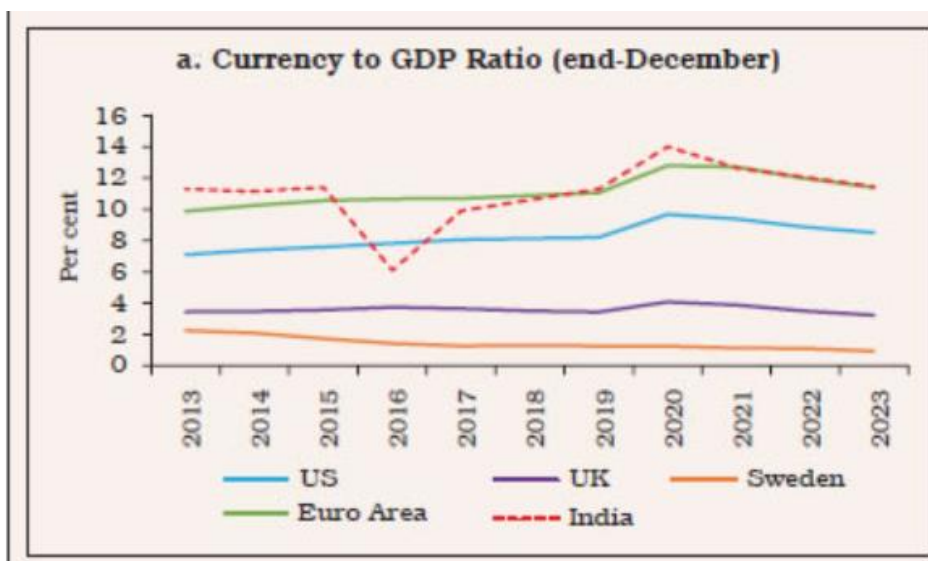
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की प्रस्तावना में केंद्रीय बैंक को प्रदत्त सांविधिक जिम्मेदारी के आधार पर मुद्रा प्रबंधन, आरबीआई के मुख्य कार्यों में से एक है, जिसके अनुसार, *भारत में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने की दृष्टि से बैंक नोटों के निर्गम को विनियमित करना तथा प्रारक्षित निधि को बनाए रखना और सामान्य रूप से देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली संचालित करना, अत्यधिक जटिल अर्थव्यवस्था की चुनौती से निपटने के लिए आधुनिक मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क रखना, वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना*।

आरबीआई अधिनियम की धारा 22, 'बैंक नोट जारी करने का अधिकार', के अंतर्गत एक रुपये के नोटों, जिन्हें भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है, को छोड़कर अन्य विभिन्न मूल्यवर्ग के बैंक नोट जारी करने का अधिकार आरबीआई के पास है। सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 के अनुसार सिक्कों के उत्पादन / ढलाई का अनन्य अधिकार भारत सरकार के पास है। हालांकि सिक्कों की ढलाई का दायित्व भारत सरकार में निहित है, फिर भी आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 38 और धारा 39 के उपबंधों के अनुसार, जारी किए गए सिक्कों का संचलन केवल भारतीय रिज़र्व बैंक के माध्यम से किया जाता है।

करेंसी के अंतर्गत रु.2 से रु.10000 (आरबीआई अधिनियम की धारा 24) के दायरे में समय-समय पर आरबीआई द्वारा जारी किए जाने वाले विभिन्न मूल्यवर्गों के बैंक नोट और आरबीआई के माध्यम से भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले 1 (रु.1 के नोट भी शामिल हैं), 2, 5, 10 और 20 के रुपया सिक्के शामिल हैं। वर्तमान में 50 पैसे के सिक्के ही भारत सरकार द्वारा संचलन में रखे जाने वाले छोटे मूल्यवर्ग के हैं, वहीं 20 दिसंबर 2010 की राजपत्र अधिसूचना एस.ओ.2978 के माध्यम से 25 पैसे और उससे कम मूल्यवर्ग के सिक्कों का संचलन 30 जून 2011 से बंद किया गया।

यद्यपि, तेजी, सुविधा व प्रतिस्पर्धा की वजह से विभिन्न लेनदेनों के निपटान के लिए डिजिटल भुगतान प्रणालियों के उपयोग में काफी बढ़ोतरी हुई है, फिर भी कागजी करेंसी दैनिक लेनदेनों के

"बेंचमार्किंग इंडियाज पेमेंट सिस्टम्स, 2022" पर रिपोर्ट के अनुसार प्रचलन में मुद्रा (CIC), जीडीपी के प्रतिशत के रूप में

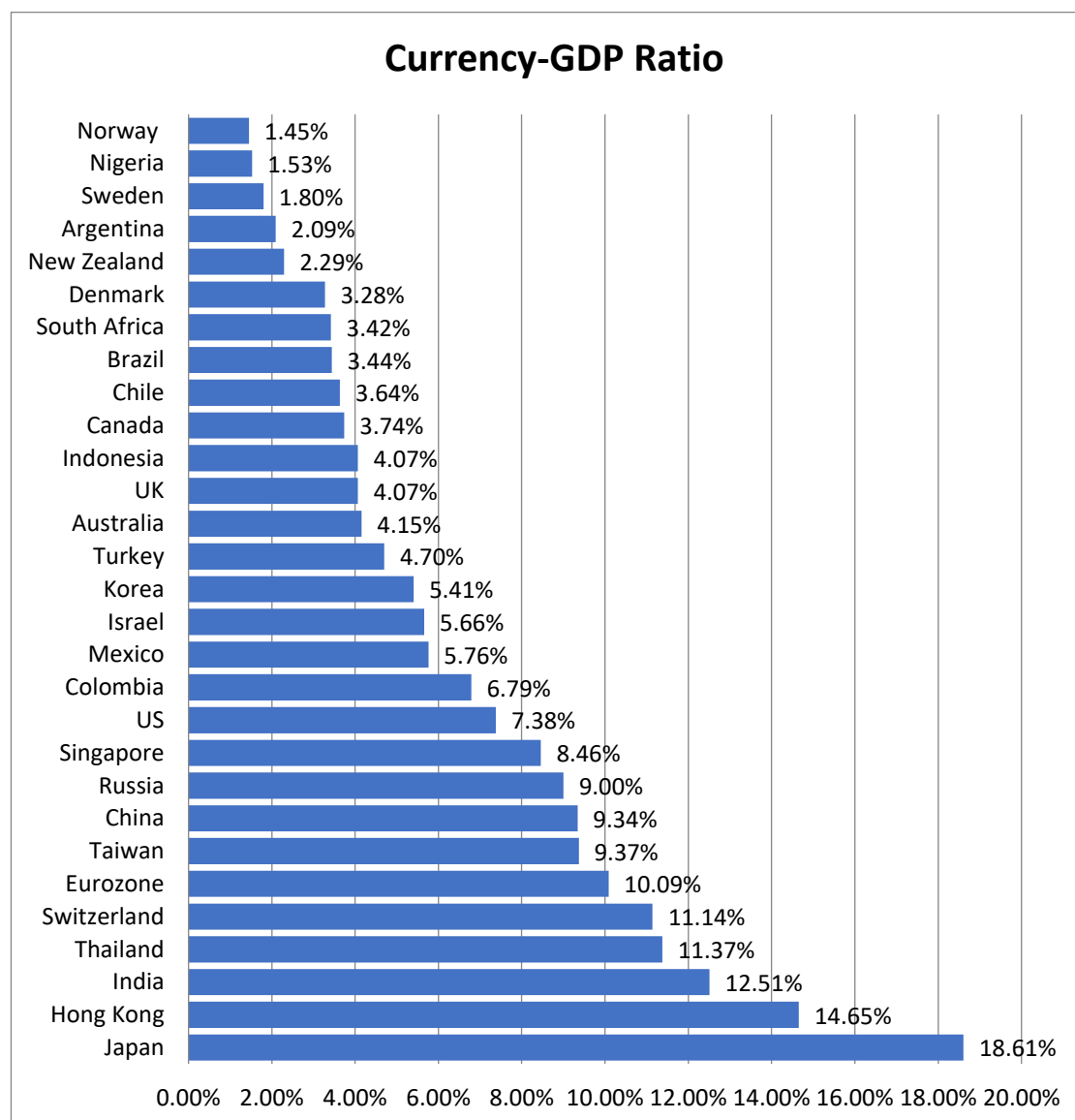


बेंचमार्किंग एक्सरसाइज में शामिल देशों में से भारत, तीसरे स्थान पर देखा गया है। भारत में सीआईसी वर्ष 2017 में सकल घरेलू उत्पाद के 10.7% से बढ़कर वर्ष 2020 में सकल घरेलू उत्पाद का 14.4% हो गया, जो सभी न्यायालयों में देखी गई प्रवृत्ति के अनुरूप है। हालांकि, तब से, जीडीपी के लिए

सीआईसी में गिरावट आ रही है (जैसा कि नीचे दिए गए चार्ट में भी देखा जा सकता है) और वर्तमान में लगभग 12.0% है।

'नकदी की प्रासंगिकता बनी हुई है'।

भारत और जी20 देशों के जीडीपी अनुपात में नकद भी नकदी के महत्व को दर्शाता है जो नीचे दिए गए चार्ट में प्रदर्शित किया गया है:



मूलभूत शब्दावली

- संचलन में करेंसी: संचलन में करेंसी के अंतर्गत संचलन में नोट, रुपया सिक्के और छोटे सिक्के शामिल हैं। आरबीआई के तुलन-पत्र में रुपया सिक्कों और छोटे सिक्कों के अंतर्गत अक्टूबर 1969 से जारी किए गए दस रुपये के सिक्के, नवंबर 1982 से जारी किए गए दो रुपये के सिक्के और नवंबर 1985 से जारी किए गए पांच रुपये के हैं।) सिक्के शामिल हैं।
- संचलन में नोट: संचलन में नोटों के अंतर्गत 1935 तक भारत सरकार द्वारा और उसके बाद से आरबीआई द्वारा जारी किए गए नोट शामिल हैं, अर्थात् आरबीआई के बाहर जनसाधारण, बैंक ट्रेज़रियों आदि द्वारा रखे जा रहे नोट, वहीं इसमें बैंकिंग विभाग द्वारा धारित नोट शामिल नहीं हैं। जुलाई 1940 से जारी भारत सरकार के एक रुपये के नोटों

को रुपया सिक्का माना जाता है और इस वजह से उन्हें इस शीर्ष के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। बैंक नोट जारी करने का एक मात्र प्राधिकरण होने के नाते आरबीआई के लिए अनिवार्य है कि वह हमेशा बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्रणाली में पर्याप्त रूप से और समय से स्वच्छ नोटों की आपूर्ति सुनिश्चित करे। देश में कागजी मुद्रा का विकास भारत में, प्राचीन काल से विभिन्न आकार-प्रकार की चीजों और धातुओं का प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाता रहा है। कागजी मुद्रा पहली बार 18वीं शताब्दी में देखी गई, जब रॉयल ट्रेजरियों / बैंकों द्वारा इन्हें वचन-पत्र के रूप में जारी किया गया। इस प्रकार की कागजी मुद्रा / नोट बैंक ऑफ हिंदुस्तान (1770-1832), जनरल बैंक ऑफ बंगाल और बिहार (1773-75), दि बंगाल बैंक (1784-91) तथा कॉमर्शियल बैंक आदि द्वारा जारी किए गए थे। (1819-1828), बैंक नोट जारी करने की जो जिम्मेदारी निजी बैंकों और प्रेसीडेंसी बैंकों को दी गई थी, वह पेपर करेंसी अधिनियम, 1861 के अंतर्गत पूरी तरह भारत सरकार को अंतरित कर दी गई। तब से लेकर अब तक बैंक नोट जारी करने का एकाधिकार भारत सरकार के पास बना रहा। सरकार के मुद्रा विभाग के नोट निर्गम के कार्य के समेकन के बाद, देश के समस्त भौगोलिक क्षेत्र की मुद्रा सबधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई मुद्रा सर्कल बनाए गए। निर्गम और मोचन के लिए प्रेसीडेंसी बैंकों को एजेंट नियुक्त किया गया। सरकार के मुद्रा विभाग के स्थान पर 1913 में मुद्रा नियंत्रक कार्यालय बनाया गया। भारिबैं अधिनियम, 1934 लागू होने के बाद नोट जारी करने का कार्य मुद्रा नियंत्रक कार्यालय से 1935 में भारिबैं के पास आ गया। तब से लेकर अब तक बैंक नोट जारी करने का एकाधिकार भारिबैं के पास है और वह देश के मुद्रा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। (Sec 22 of RBI Act 1954)

शुरु में नोट मुद्रण इंग्लैंड में होता था, लेकिन 1928 में महाराष्ट्र के नासिक में मुद्रा प्रिंटिंग प्रेस स्थापित होने के साथ नोटों का मुद्रण भारत में होने लगा। बाद में 1974 में सरकार ने मध्यप्रदेश के देवास में एक और मुद्रा प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। इस बीच, 1968 में मध्यप्रदेश के होशंगाबाद में 1500 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाली सुरक्षा कागज मिल स्थापित की गई। बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण मुद्रा की बढ़ती मांग को पूरा करने और मांग-पूर्ति के बीच के अंतर को समाप्त करने के लिए भारिबैं ने 1995 में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल) की स्थापना की। 1996 में बीआरबीएनएमपीएल ने दो मुद्रण प्रेस एक कर्नाटक के मैसूर में और दूसरी प. बंगाल के सालबनी में स्थापित की ताकि देश के बैंक नोट उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके। वर्तमान में आरबीआई को प्राप्त होने वाले बैंक नोटों में इन दो प्रेसों का लगभग दो-तिहाई का हिस्सा है। उक्त दो प्रेसों की पूरी क्षमता के उपयोग से देश मुद्रा नोट मुद्रण के मामले में आत्म-निर्भर हो गया है। बीआरबीएनएमपीएल ने महात्मा गांधी (नए) श्रृंखला के बैंकनोटों की डिजाइनिंग अपने देश में करके तथा व्यापक ऑटोमेशन व एंटरप्राइज रिसोर्स प्लैनिंग को जारी रखते हुए मुद्रा प्रबंधन क्षेत्र में से कार्यनीतिपरक उद्देश्यों को हासिल करने में काफी योगदान किया है। संयुक्त रुप एसपीएमसीआईएल के साथ बीआरबीएनएमपीएल ने बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बीएनपीएमआईपीएल) की स्थापना की है, जो संस्था बैंकनोट उत्पादन के लिए अपेक्षित सिलेंडर वॉटरमार्क्स बैंक नोट (सीडब्ल्यूबीएन) पेपर का उत्पादन करती है।) इसी प्रकार, बीआरबीएनएमपीएल ने भी 1,500 मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाले एक स्याही कारखाने की भी स्थापना की है, जिसने अपना वाणिज्यिक उत्पादन अगस्त 2018 में शुरू किया है। इसके परिणामस्वरूप मैसूर स्याही कारखाने में बैंक नोटों के मुद्रण में उपयोग की जाने वाली ड्राईऑफसेट, इंटाग्लियो, नब्रिंग और कलर शिफ्टिंग स्याहियों का विनिर्माण किया

जा रहा है। बीएनपीएमआईपील और बीआरबीएनएमपीएल स्याही कारखाना 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम और नए बैंक नोटों के उत्पादन में देशीकरण की दिशा में किए गए प्रयासों में हासिल किए गए महत्वपूर्ण मील के पथर हैं।

मुद्रा प्रबंधन की संरचना

मुद्रा (करेंसी) प्रबंधन, नोटों के जीवन-चक्र के प्रबंधन की प्रक्रिया का नाम है, जिसमें विभिन्न मूल्यवर्ग के नोटों की जरूरतों का आकलन, नोट प्रिंटिंग प्रेस को नोट छापने का आदेश देना, देश भर में पर्याप्त संख्या में नोटों की आपूर्ति और संवितरण के साथ-साथ स्वच्छ नोटों की सतत आपूर्ति के जरिए और कटे-फटे गंदे नोटों को समय पर संचलन से बाहर करते हुए संचलन में रहने वाले बैंक नोटों की गुणवत्ता बनाए रखना, शामिल है। भारिवै अधिनियम, 1934 की धारा 23 में यह निर्दिष्ट किया गया है कि बैंक नोट जारी करने के काम के लिए भारिवै में निर्गम विभाग नाम से एक अलग विभाग खोला जाएगा। अतः समग्र मुद्रा प्रबंधन कार्य भारिवै के मुंबई स्थित केंद्रीय कार्यालय के मुद्रा प्रबंध विभाग द्वारा देखा जाता है, लेकिन मुद्रा प्रबंधन के परिचालन कार्य के लिए भारिवै के क्षेत्रीय कार्यालयों में अलग से निर्गम विभाग कार्यरत हैं। उन्नीस (19) निर्गम कार्यालयों (अहमदाबाद, बंगलूर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नै, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुअनंतपुरम) के अलावा, भारिवै के इस कार्य को सुगम बनाने के लिए देश भर की बैंक शाखाओं और एटीएम में मुद्रा तिजोरीयों और छोटे सिक्कों के डिपो का नेटवर्क फैला हुआ है।

मुद्रा तिजोरी और छोटे सिक्कों के डिपो, अधिकांशतः वाणिज्य बैंकों की शाखाओं में बैंक नोटों, रुपया सिक्कों। छोटे सिक्कों के भंडारगृह का काम करते हैं। इसके अलावा, कुछ मुद्रा तिजोरी राज्य सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्यों के ट्रेजरी कार्यालयों और यहां तक कि भारि के कोच्चि कार्यालय में भी स्थापित किए गए हैं। मुद्रा तिजोरी और छोटे सिक्कों के डिपो भारि की विस्तारित शाखाएं हैं, जो प्रणाली में मुद्रा डालने और उससे बाहर निकालने में भारिवै की सहायता करने के साथ-साथ अपने संबंधित क्षेत्र की मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने का दायित्व भी निभाती है।

नोटों की डिजाइनिंग

बैंक नोटों के डिजाइन, आकार-प्रकार और प्रयुक्त सामग्री का निर्णय, भारिवै अधिनियम, 1934 की धारा 25 के अनुसार भारिवै के केंद्रीय बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर, भारत सरकार द्वारा लिया जाता है। नोटों के आकार, रंग तथा डिजाइन के चयन के बारे में विशेष सावधानी रखी जाती है, ताकि जनता द्वारा विभिन्न मूल्यवर्ग के नोटों की पहचान उन पर दृष्टि डालते ही की जा सके। साथ ही, नोटों में सुरक्षा संबंधी अधिकाधिक विशेषताएं शामिल करने का भी ध्यान रखा जाता है ताकि आसानी से उनकी जालसाजी न की जा सके। वर्तमान में, महात्मा गांधी श्रृंखला में विभिन्न मूल्यवर्ग के नए नोट जारी किए गए हैं।)

महात्मा गांधी (नए) श्रृंखला के बैंक नोट

बैंक नोटों के डिजाइन व सुरक्षागत विशेषताओं की सामयिक समीक्षा और उन्नयन संबंधी अंतरराष्ट्रीय प्रथा के अनुरूप 2016-17 में देश की सांस्कृतिक धरोहर और वैज्ञानिक उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए नए डिजाइन, परिमाणों व मूल्यवर्गों में बैंक नोटों की नई श्रृंखला (महात्मा गांधी नई श्रृंखला) की शुरुआत की गई। उसके बाद रु.10, रु.20, रु.50, रु.100, रु.200, रु.500 और रु.2000 के मूल्यवर्गों के बैंक नोट जारी किए गए।

देवनागरी में अंक और स्वच्छ भारत के लोगो जैसे कतिपय अन्य तत्व इन नोटों में जोड़े गए। इन नए नोटों में डिजाइन संबंधी अन्य कई तत्व और जटिल रूप व आकार विद्यमान हैं। बैंक नोटों की वर्तमान श्रृंखला में सुरक्षागत विशेषताएं जारी हैं, वहीं, नए डिजाइन नोटों में सापेक्षिक विन्यास में बदलाव हुआ है।

मूल्यवर्ग	रंग	आकार	मोटिफ	पहचान चिह्न	ब्लिड लाइन्स
2000	मैजंटा	166 मिमी x 66 मिमी	मंगलयान	समतल आयत	सातकोणीय लाइनें
500	स्टोन्ग्रे	150 मिमी x 66 मिमी	भारतीय जके साथलाल किला	वृत्त	पांचकोणीय लाइनें
200	प्रफुल्ल पीला	146 मिमी x 66 मिमी	संचिस्तूप	H	चारकोणीय लाइनें बीचमें दो वृत्त
100	लैवेंडर	142 मिमी x 66 मिमी	रानीकीवाव	त्रिकोण	चारकोणीय लाइनें
50	चमकीलसा नीला	135 मिमी x 66 मिमी	हमके साथ रथ	-	-
20	हलकहरा पीला	129 x 63 मिमी	एलोरकी गुफाएं	-	-
10	काले ब्राउन	123 मिमी x 63 मिमी	यूनिवर्सल कोणार्क	-	-

वार्षिक अपेक्षा की आयोजना

मुद्रण हेतु अपेक्षित नोटों की मात्रा आरबीआई द्वारा भारत सरकार के साथ परामर्श करके निर्धारित की जाती है। वास्तविक जीडीपी संवृद्धि, मुद्रास्फीति, व्याज दर, डिजिटल भुगतान आदि के रूप में निरूपित आर्थिक गतिविधि करेंसी मांग का प्रमुख चालक होती है। बैंकनोटों और सिक्कों का पूर्वानुमान लगाकर वार्षिक इंडेंट को अंतिम रूप दिया जाता है। जहां तक बैंकनोटों का संबंध है कुल मांग की गणना दो घटकों, यथा- वृद्धिशील मांग (संव्यवहारात्मक मांग) और प्रतिस्थापन मांगी, का समेकन कर की जाती है। वृद्धिशील का आकलन विभिन्न अर्थमितीय मॉडलों को जोड़कर किया जाता है, यथा- समय परिवर्ती मापदंड-स्वप्रतिगामी वितरित लैंग (टीवीपी-एआरडीएल) मॉडल, प्रतीयमानतः असंबंधित प्रतिगामी समीकरण (एसयूआरई) मॉडल और बहिर्जात चरों को कल्पित करने वाले स्वप्रतिगामी एकीकृत चल औसत (एआरआईएमए) मॉडल, जैसे- वास्तविक जीडीपी संवृद्धि, सीपीआई मुद्रास्फीति दर, मांग दर, डिजिटल / वैकल्पिक भुगतान की वृद्धि दर आदि। तथापि, प्रतिस्थापन मांग का पूर्वानुमान बैंकनोटों की मूल्यवर्ग-वार आकलित जीवन-अवधि के आधार पर किया जाता है। बैंकनोटों की प्रतिस्थापन दरों का अभिकलन औसत जीवन-अवधि (वर्षों में) के व्युत्क्रम के रूप में किया जाता है। अंततः कुल मांग का पूर्वानुमान आकस्मिक

मांग (आपातकाल के मामले में) का समायोजन करते हुए किया जाता है, जिसके लिए आरबीआई और सीसी में उपलब्ध करेंसी के मौजूदा स्टॉक को ध्यान में रखा जाता है। सिक्कों की मांग पूर्वानुमान अलग से (स्वप्रतिगामी एकीकृत चल औसत (एआरआईएमए) मॉडल का उपयोग करते हुए किया जाता है। सिक्कों के मामले में केवल वृद्धिशील मांग पर विचार करना जरूरी होता है।

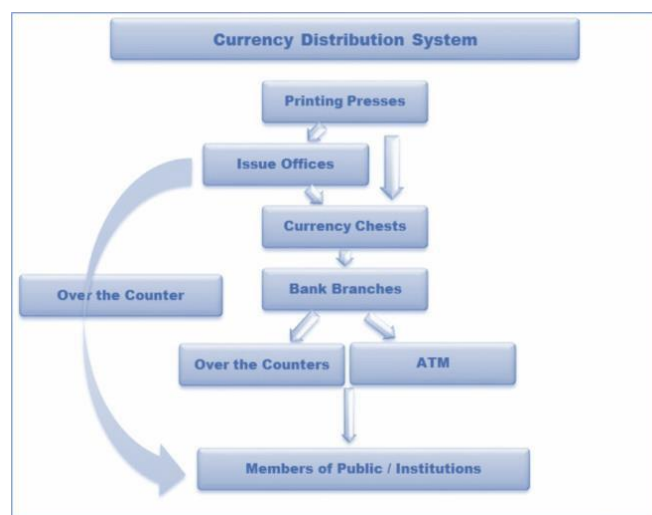
मुद्रा का संवितरण

विश्व के विभिन्न देशों में मुद्रा वितरण के निम्नलिखित तीन मॉडल प्रचलन में हैं:

- थोक मॉडल - ऑस्ट्रेलिया में प्रचलित इस मॉडल में बैंक सीधे ही केंद्रीय बैंक से नोट खरीदते हैं। पूरे ऑस्ट्रेलिया में स्थित अनुमोदित नकदी केंद्रों में बैंकों द्वारा ये नोट ले जाए जाते हैं और उनका भंडारण किया जाता है।
- खुदरा मॉडल चीन और फ्रांस में प्रचलित इस मॉडल के अनुसार जनता और अन्य सस्थाओं की मुद्रा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, केंद्रीय बैंक खुद अपने भंडारण केंद्र खोलता है।
- अर्ध-खुदरा मॉडल अधिकांश केंद्रीय बैंकों की तरह भारत में भी अर्ध-खुदरा मॉडल को अपनाया गया है, जिसमें बैंकों की मुद्रा तिजोरी शाखाओं के दरवाजे तक मुद्रा नोट उपलब्ध कराए जाते हैं। उनके परिवहन की तथा लाने-ले जाने संबंधी अन्य लागतें केंद्रीय बैंक द्वारा वहन की जाती हैं। बैंकों से मुद्रा तिजोरी बनाए रखने की स्थिर लागत वहन करने की ही अपेक्षा की जाती है।

अर्ध-खुदरा मॉडल में नोटों और सिक्कों का सवितरण भारिबैं के निर्गम कार्यालयों, मुद्रा तिजोरियों। छोटे सिक्का डिपो, बैंक शाखाओं तथा एटीएम द्वारा यहाँ नीचे दर्शाए तरीके से किया जाता है –

देश भर में बैंक नोटों और रुपये के सिक्कों के वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए, आरबीआई ने चुनिंदा बैंकों/बैंकों की शाखाओं को करेंसी चेस्ट स्थापित करने के लिए अधिकृत किया है। ये करेंसी चेस्ट, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, स्टोरहाउस हैं जहाँ आरबीआई की ओर से बैंक नोट और रुपये के सिक्के रखे जाते हैं। यह सुनिश्चित किया जाता है कि बैंक शाखाओं में मुद्रा तिजोरियों में पर्याप्त मात्रा में नोट और सिक्के हों ताकि देश के सभी भागों में जनता के लिए मुद्रा आसानी से



उपलब्ध हो सके। इन करेंसी चेस्ट की आपूर्ति रिज़र्व बैंक के निर्गम कार्यालयों से/सीधे बैंक नोट प्रेस से ताजे/पुन जारी करने योग्य बैंकनोटों और रुपये के सिक्कों के आवधिक प्रेषण के साथ की जाती है। एजेंसी बैंक/लिंग्ड बैंक शाखाएं स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनसे संपर्क करती हैं। अधिशेष और जारी न करने योग्य नोट (₹ 1 नोट और सिक्कों सहित) मुद्रा तिजोरियों में जमा किए जाते हैं। नोटों और सिक्कों को भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्गम कार्यालयों और विभिन्न

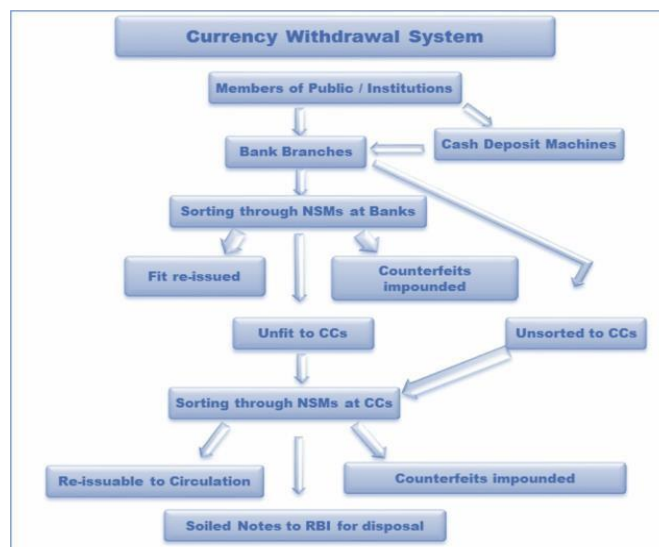
मुद्रा तिजोरियों के माध्यम से प्रचलन में भेज दिया जाता है अथवा प्रचलन से बाहर कर दिया जाता है। मुद्रा तिजोरियों का पर्यवेक्षण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ऑनसाइट/ऑफसाइट पर्यवेक्षी ढांचे के अंतर्गत किया जाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक निकटवर्ती बैंक शाखाओं के माध्यम से ग्राहकों को विनिमय सुविधाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करके मुद्रा के खुदरा वितरण से धीरे-धीरे पीछे हट रहा है। बैंकों को अपने वितरण तंत्र को मजबूत करने की सलाह दी गई है ताकि आम जनता के लिए मुद्रा की बढ़ती जरूरतों को पूरा किया जा सके।

स्वच्छ नोट नीति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऐसे नोटों को चलन से बाहर निकालने की सुनियोजित व्यवस्था की हुई है जो बहुत अधिक उपयोग के कारण गंदे हो जाते हैं या कट-फट जाते हैं। भारिबैं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत भारिबैं को यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है कि केवल स्वच्छ नोट ही संचलन में रहें। इस दायित्व की पूर्ति के लिए गंदे और कटे-फटे नोटों को चलन से बाहर निकाला जाता है और आगे की प्रक्रिया तथा नष्ट करने के लिए निर्गम कार्यालयों को लौटा दिया जाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक मशीन से ऑनलाइन जांच, प्रमाणीकरण, गिनती, छंटाई और प्राप्त नोटों को नष्ट करने के लिए मुद्रा सत्यापन और प्रसंस्करण प्रणाली (सीवीपीएस) का उपयोग करता है। प्रसंस्करण के बाद, गैर-जारी करने योग्य नोट स्वचालित



रूप से सीवीपीएस से श्रेडिंग और ब्रिकेटिंग सिस्टम (एसबीएस) में भेजे जाते हैं। एसबीएस नोटों को काटने के बाद, उन्हें ब्रिकेट में परिवर्तित किया जाता है। जिस तंत्र में गंदे या फटे नोटों को सिस्टम से पुनर्प्राप्त और संसाधित किया जाता है, वह निम्नानुसार दर्शाया गया है:

नोटों का विनिमय

यह सुनिश्चित करने के अपने अधिदेश के भाग के रूप में कि केवल स्वच्छ नोट ही परिचालन में हों, भारतीय रिज़र्व बैंक अपने निर्गम कार्यालयों के साथ-साथ उन बैंक शाखाओं, जिन्हें यह कार्य सौंपा किया गया है, वहां से भी गंदे और फटे बैंक नोटों को बदलने की जिम्मेदारी लेता है। मूल रूप से, नोटों की दो श्रेणियां हैं जो बैंकों और आरबीआई द्वारा बदली जाती हैं – गंदे नोट और कटे-फटे नोट। गंदे नोट वे नोट हैं जो अत्यधिक उपयोग के कारण गंदे और पुराने हो गए हैं और इसमें एक साथ चिपकाए गए दो-टुकड़े नोट भी शामिल हैं और जब प्रस्तुत किए जाते हैं तो दोनों टुकड़े एक ही नोट के होते हैं, और पूरे नोट

का आकार लेते हैं, जबकि कटे-फटे नोट का अर्थ है एक नोट जिसका एक हिस्सा गायब है या जो दो से अधिक टुकड़ों से बना है। गंदे नोटों को सभी बैंक शाखाओं में देकर विनिमय किया जा सकता है। इसी प्रकार, भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली (एनआरआर, 2009), (भारतीय रिज़र्व बैंक नोट वापसी नियम, 2018 में यथा संशोधित) के अंतर्गत कटे-फटे/अपूर्ण नोट (ऐसा नोट जो पूर्णतः या आंशिक रूप से विलोपित, सिकुड़ा हुआ, धुला हुआ, परिवर्तित या अस्पष्ट नोट मुटिलियेटड नोट में शामिल नहीं है) को बदलने की सुविधा जनवरी, 2013 से सभी बैंक शाखाओं में यह सुविधा उपलब्ध है। बैंकों की सभी शाखाओं को कटे-फटे/दोषपूर्ण नोटों के विनिमय के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (नोट वापसी) नियमावली, 2009 के नियम 2(ज) के अंतर्गत शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। लघु वित्त बैंक (अपने बैंकिंग कारोबार शुरू होने से दो साल तक) और भुगतान बैंक अपने विकल्प पर कटे-फटे और दोषपूर्ण नोटों का विनिमय कर सकते हैं। इस तरह के विनिमय की प्रक्रिया में 2018 में संशोधन किया गया है। नेट रन रेट (मूल्य) 2009 के निर्णय के बाद 20 रुपये तक के मूल्यवर्ग के नोटों के लिए या तो पूर्ण मूल्य का भुगतान किया जाएगा या कोई मूल्य नहीं दिया जाएगा, जबकि 50 रुपये और उससे अधिक के नोटों को पूर्ण, आधा या कोई मूल्य नहीं मिलेगा, जो दिए किए गए नोट के सबसे बड़े अविभाजित नोट के क्षेत्र पर निर्भर होगा। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्गम कार्यालयों में विशेष प्रक्रिया के अंतर्गत ऐसे नोटों के लिए न्यायनिर्णयन मौजूद है जो अत्यधिक टूटे हुए हैं अथवा बुरी तरह जल गए हैं, जले हुए हैं अथवा अविभाज्य रूप से एक साथ चिपके हुए हैं और इसलिए सामान्य रख-रखाव सह नहीं पाते हैं।

भारतीय जाली /नकली नोटों मुद्रा नोटों (एफआईसीएन) से निपटना

नकली धन, नकली या नकली मुद्रा को संदर्भित करता है जो धोखा देने के उद्देश्य से तैयार किया जाता है। मुद्रा की जालसाजी एक अपराध है जो लगातार किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा पैदा करता है और अपने नागरिकों के लिए वित्तीय नुकसान का स्रोत बना हुआ है।

नकली धन का समाज पर पड़ने वाले कुछ बुरे प्रभावों में वास्तविक धन के मूल्य में कमी, अर्थव्यवस्था में अधिक धन परिचालित होने के कारण कीमतों में वृद्धि (मुद्रास्फीति) - मुद्रा आपूर्ति में अनधिकृत कृत्रिम वृद्धि, कागजी धन की स्वीकार्यता में कमी और जनता के सदस्यों के लिए नुकसान जिनका नकली धन जब्त किया जाता है, शामिल हैं। उन देशों में जहां कागजी धन प्रचलन में कुल धन का एक छोटा सा अंश है, मुद्रा की जालसाजी के व्यापक आर्थिक प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं हो सकते हैं, बल्कि, आर्थिक प्रभाव, जैसे मुद्रा में विश्वास, गंभीर हो सकते हैं।

भारत में, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 178 – 182 जाली मुद्रा नोटों या बैंक नोटों से संबंधित है। कानून के तहत, जालसाजी, तस्करी और यहां तक कि जानबूझकर नकली नोट रखने पर भी सजा हो सकती है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 में 'जालसाजी' की परिभाषा में एक विदेशी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए मुद्रा नोट भी शामिल हैं। भारत सरकार ने विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यूएपीए), 1967 के अंतर्गत उच्च गुणवत्ता वाले जाली भारतीय मुद्रा अपराध नियमावली, 2013 की जांच भी तैयार की है। अधिनियम की तीसरी अनुसूची उच्च गुणवत्ता वाले नकली भारतीय मुद्रा नोट को परिभाषित करती है अर्थात् वॉटरमार्क, सुरक्षा धागे और निम्नलिखित विशेषताओं में से किसी एक का होना: (i) गुप्त छवि; (ii) सी थ्रू रेजिस्ट्रेशन; (iii) प्रिंट गुणवत्ता तीक्ष्णता; (iv) राइजड ईफेक्ट; (ई) फ्लोरोसेंट विशेषताओं; (च) सबस्ट्रेट गुणवत्ता; (छ) पेपर टैगेंट; (ज) ओवीआई में रंग बदलाव प्रभाव; (i) सुरक्षा धागे में रंग बदलाव प्रभाव। भारतीय कागजी मुद्रा के उत्पादन या तस्करी या संचलन की गतिविधि को भारतीय न्याय संहिता, 2023 के दायरे में लाया गया है।

जाली नोटों की घटनाओं से निपटने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार के परामर्श से जालसाजी को रोकने के लिए बैंक नोटों की सुरक्षा विशेषताओं की निरंतर और आवधिक रूप से समीक्षा और उन्नयन करता है। यह जालसाजी के मुद्दे को हल करने के लिए विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ जानकारी भी साझा करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक नोटों की सुरक्षा विशेषताओं के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करने और जाली अथवा जाली नोटों के परिचालन को रोकने में सहायता करने के लिए आम जनता को शिक्षित करने हेतु कतिपय उपाय किए हैं। इंडियन बैंक नोटों की विशेषताओं पर मूल सूचना इस समय <https://paisaboltahai.rbi.org.in> पर उपलब्ध करायी गई है।

इसके माध्यम से बैंकों को जाली नोटों का पता लगाने और उन्हें जब्त करने के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसके द्वारा बैंकों को यह भी अनुदेश दिया गया है कि:

- काउंटर पर दिए गए बैंक नोट/सीधे बैंक ऑफिस पर प्राप्त/अधिक मात्रा में प्राप्त को करेंसी चेस्ट में मशीनों के माध्यम से प्रामाणिकता की जांच की जानी चाहिए।
- काउंटर पर या बैंक-ऑफिस/करेंसी चेस्ट पर प्राप्त जाली नोटों, यदि कोई हो, के लिए ग्राहक के खाते में क्रेडिट नहीं दिया जाना चाहिए।
- किसी भी स्थिति में जाली नोटों को न तो जमाकर्ता को लौटाया जाना चाहिए या न ही बैंक शाखाओं/ट्रेजरी द्वारा नष्ट नहीं किया जाना चाहिए।
- एक ही लेन-देन में चार जाली नोटों का पता लगाने के मामलों में, संदिग्ध जाली नोटों के साथ महीने के अंत में पुलिस अधिकारियों को एक समेकित रिपोर्ट दी जानी चाहिए।
- एक ही लेन-देन में पांच या उससे अधिक जाली नोट के टुकड़ों का पता लगाने के मामलों में, नोटों को एफआईआर दर्ज करके जांच के लिए तुरंत पुलिस स्टेशन को भेजा जाना चाहिए।

भारतीय बैंक नोट्स की सुरक्षा विशेषताएं

जालसाजी करेंसी, नोट जारीकर्ताओं के लिए चिंता का विषय है। कंप्यूटर प्रौद्योगिकियों और फोटोग्राफी में नवीनतम वृद्धि, कम लागत वाले उपकरणों तक पहुंच के साथ, नकली धन के निर्माण के कार्य को अपेक्षाकृत आसान बना दिया है। इस खतरे को रोकने और जालसाजों से हमेशा एक कदम आगे रहने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक बैंक नोटों में सुरक्षा विशेषताओं को जोड़कर नियमित रूप से अपनी मुद्रा को अद्यतन कर रहा है। ये सुरक्षा विशेषताएं बैंक नोटों को कम जालसाजी प्रवण बनाती हैं। नई एमजी श्रृंखला के बैंक नोटों की विभिन्न सुरक्षा विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- १) वॉटरमार्क: इसमें एक छवि होती है जो तब दिखाई देती है जब बैंक नोट को प्रकाश के सामने रखा जाता है, जो निर्माण प्रक्रिया के दौरान बनाया जाता है जैसे कि यह कागज का एक अभिन्न अंग है। बैंक नोटों में मूल्यवर्ग अंक (इलेक्ट्रोटाइप) वॉटरमार्क के साथ महात्मा गांधी का चित्र होता है।
- २) सुरक्षा धागा: रंग बदलने वाली खिड़की वाली सुरक्षा धागा ₹100 और उससे अधिक के मूल्यवर्ग में मौजूद है, जिसका रंग नोट को झुकाने पर हरे से नीले रंग में बदल जाता है। शिलालेख 'भारत' 'RBI' ₹100, 200 और 500 के मूल्यवर्ग में मौजूद है। ₹2000 में शिलालेख 'भारत', 'आरबीआई', '2000' हैं। ₹10, 20 और 50 मूल्यवर्ग के लिए, 'भारत' और 'RBI' शिलालेखों के साथ विंडो डिमेटलाइज्ड सुरक्षा धागा मौजूद है।
- ३) गुप्त छवि: गुप्त छवि एक सुरक्षा विशेषता है जिसे नोट के भीतर छुपाया जाता है। यह तभी दिखाई देता है जब इसे

आंखों के स्तर पर क्षैतिज रूप से रखा जाता है। ₹100 और उससे अधिक मूल्यवर्ग के नोटों में, मूल्यवर्ग के अंक के साथ गुप्त छवि निचले बाएं कोने पर दिखाई देती है, जब नोट को आंख के स्तर से 45 डिग्री के कोण पर रखा जाता है।

४) माइक्रो लेटरिंग: माइक्रो लेटरिंग मिनट शिलालेख हैं जिन्हें केवल उच्च क्षमता के माइक्रोस्कोप / आवर्धक लेंस के तहत पढ़ा जा सकता है। यह सुविधा महात्मा गांधी के चित्र के बाएं कंधे पर शिलालेख 'इंडिया' और 'भारत' के साथ दिखाई देती है। नोटों के पीछे की ओर रूपांकनों पर सूक्ष्म अक्षर भी देखे जा सकते हैं।

५) इंटैग्लियो प्रिंटिंग: उठी हुई छपाई जो स्याही के जमा होने के कारण होती है और स्पर्श पर महसूस की जा सकती है, इंटैग्लियो प्रिंटिंग कहलाती है। 100 रुपये और उससे अधिक के मूल्यवर्ग के नोटों में, महात्मा गांधी का चित्र, अशोक स्तंभ का प्रतीक, गारंटी खंड, राज्यपाल के हस्ताक्षर, वचन पत्र, आरबीआई का प्रतीक, ब्लीड लाइन्स और पहचान चिह्न इंटैग्लियो में हैं।

६) रजिस्टर के माध्यम से देखें: सी-थ्रू रजिस्टर एक डिज़ाइन है जो नोट के दोनों किनारों पर आंशिक रूप से मुद्रित होता है, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत, और प्रकाश के खिलाफ देखे जाने पर एक एकल डिज़ाइन जैसा दिखता है।

७) प्रतिदीप्ति: यह एक विशेष सुरक्षा विशेषता है जिसमें ऑप्टिकल फाइबर और फ्लोरोसेंट स्याही का उपयोग किया जाता है जो पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में आने पर चमकता है। नोटों के नंबर पैनल फ्लोरोसेंट स्याही में मुद्रित होते हैं और नोट में ऑप्टिकल फाइबर भी होते हैं, जो दोनों पराबैंगनी लैंप के नीचे नोट रखने पर चमकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर दोहरे रंग के होते हैं (यानी, प्रत्येक फाइबर दो रंग दिखाता है) और लाल/पीले और नीले/हरे रंग के संयोजन में होते हैं।

८) रंग बदलने वाली स्याही: रुपये का प्रतीक और ₹200 और उससे अधिक मूल्यवर्ग के बैंक नोटों में मूल्यवर्ग नोट के अग्रभाग में रंग बदलने वाली स्याही (हरे से नीले) में लिखा गया है।

ix) संख्याओं का आरोही फ्रॉन्ट: यह एक नई सुविधा है जिसमें संख्या पैनल में संख्या (उपसर्ग को छोड़कर) का फ्रॉन्ट आकार बाएं से दाएं बढ़ रहा है।

x) कोणीय ब्लीड लाइन्स: यह सुविधा 2016 से जारी किए गए नोटों में देखी जाती है। यह अशोक प्रतीक से थोड़ा ऊपर नोट के बाएं कोने में उभरे हुए प्रिंटों में लाइनों का एक सेट है। इन पंक्तियों की संख्या और ब्लॉक/सेट मूल्यवर्ग के अनुसार भिन्न होते हैं - ₹100 के नोटों में 4 लाइनें (2 के 2 सेट में), ₹200 के नोटों में 4 लाइनें (दो सर्कल द्वारा अलग किए गए 2 के सेट में), ₹500 में 5 लाइनें (2-1- 2 के सेट), ₹2000 में 7 लाइनें (1-2-1-2-1 के सेट)।

xi) पहचान चिह्न: ये ऐसी विशेषताएं हैं जो उच्च मूल्यवर्ग के नोटों पर दिखाई देती हैं ताकि दृष्टिबाधित नोटों के मूल्यवर्ग की पहचान कर सकें। यह ₹100 के नोटों में एक त्रिभुज (), ₹200 में एक 'H' आकार (), ₹500 में एक वृत्त () और ₹ 2000 में एक आयत () है।

बैंक नोट की मुख्य विशेषताएं

सुरक्षा विशेषताओं के अलावा, बैंक नोट की कुछ प्रमुख/आवश्यक विशेषताएं हैं। वो हैं:

- जारीकर्ता का नाम – जारीकर्ता का नाम, नोट के शीर्ष पर हिंदी और अंग्रेजी में भारतीय रिज़र्व बैंक।
- गारंटी क्लॉज - वह खंड जिसमें कहा गया है कि नोट की गारंटी भारत सरकार द्वारा दी जाती है।

- वचन खंड - वह खंड जिसके द्वारा नोट का हस्ताक्षरकर्ता वाहक को नोट में उल्लिखित राशि का भुगतान करने का वादा करता है।
- जारीकर्ता के हस्ताक्षर – आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर।
- संख्या पैनल - प्रत्येक नोट के लिए अद्वितीय संख्या जो छह अंकों की होती है, जिसके पहले तीन अल्फा संख्यात्मक अंक होते हैं। एक विशेष विशिष्ट फ्रॉन्ट का उपयोग किया जाता है और संख्याओं के बीच रिक्त स्थान समान रूप से वितरित किए जाते हैं।
- संप्रदाय - अंकों में मुद्रा का मूल्यवर्ग।
- महात्मा गांधी का चित्र – केंद्र में महात्मा गांधी का चित्र।
- भाषा पैनल - नोट के पीछे 15 भाषाओं में लिखा गया मूल्यवर्ग।

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, रिज़र्व बैंक बैंक नोटों के लिए नई/उन्नत सुरक्षा विशेषताओं को लागू करने की प्रक्रिया को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है। रिज़र्व बैंक के आदेश पर, बीआरबीएनएमपीएल मुद्रा के क्षेत्र में उन्नत अनुसंधान करने के लिए अपने मैसूरू परिसर में एक मुद्रा अनुसंधान और विकास केंद्र (सीआरडीसी) की स्थापना भी कर रहा है। इसके प्रथम चरण के रूप में, बीआरबीएनएमपीएल के मैसूरू परिसर में एक विरोधात्मक विश्लेषण प्रयोगशाला प्रचालित की गई है ताकि वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध सामग्रियों और उपकरणों का उपयोग करके प्रशिक्षित विशेषज्ञों/तकनीशियनों द्वारा बैंक नोट विशेषताओं के इन-हाउस अनुकरण के माध्यम से नकली निवारण प्रतिरोध का आकलन करने के लिए बैंक नोटों पर अत्याधुनिक अनुसंधान किया जा सके।

विमुद्रीकरण

विमुद्रीकरण एक मुद्रा इकाई को उसकी वैध मुद्रा की स्थिति से वंचित करने का कार्य से जुड़ा है। यह, मुद्रा इकाई की वैध स्थिति को हटाने का कार्य या प्रक्रिया है। विमुद्रीकरण की तिथि से, विमुद्रीकृत की गई सभी मुद्राएँ वैध मुद्रा नहीं रह जाती हैं। ऐसी मुद्रा अब धन नहीं रह जाती है और इसका उपयोग किसी भी लेन-देन के लिए नहीं किया जा सकता है। कई देशों ने अति मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाने के लिए, काले धन पर अंकुश लगाने, आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने, नकली मुद्रा को हटाने आदि के लिए विमुद्रीकरण की इस प्रक्रिया को अपनाया है।

भारत में, पहली बार विमुद्रीकरण वर्ष 1946 में हुआ था, जब 12 जनवरी, 1946 को ₹ 500, ₹ 1000 और ₹ 10000 नोटों के उच्च मूल्यवर्ग के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था। हालांकि, बाद में ₹5000 पेश किए गए और ₹1000 और ₹10000 के नोटों को फिर से शुरू किया गया। हालांकि, इन तीन संप्रदायों को बाद में 16 जनवरी, 1978 को विमुद्रीकृत कर दिया गया था।

बाद में 2016 में ₹ 500 और ₹ 1000 मूल्यवर्ग में बैंक नोटों की कानूनी निविदा विशेषता, जिसे निर्दिष्ट बैंक नोट्स (एसबीएन) के रूप में संदर्भित किया गया था, को भारत सरकार द्वारा 8 नवंबर 2016 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 3407 (ई) के माध्यम से वापस ले लिया गया था। विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (देयताओं की समाप्ति) पर एक अध्यादेश 30 दिसंबर 2016 को प्रख्यापित किया गया था (जिसे बाद में अधिनियम बनाया गया) जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि एसबीएन आरबीआई अधिनियम की धारा 34 के तहत आरबीआई की देनदारियां नहीं रहेंगी और 31 दिसंबर से अधिनियम की धारा 26 की उप-

धारा (1) के तहत केंद्र सरकार की गारंटी नहीं रहेगी। तथापि, अनिवासी भारतीयों और निवासी भारतीयों द्वारा इन नोटों के आदान-प्रदान के लिए रियायती अवधि प्रदान की गई थी, जो विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान देश से बाहर थे, विभिन्न राजपत्र अधिसूचनाओं के तहत उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन थे। भारत सरकार ने विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा 30 दिसंबर 2016 से पहले जब्त/जब्त किए गए विनिर्दिष्ट बैंक नोट (जब्त किए गए नोटों की जमाराशि) नियम, 2017 दिनांक 12 मई 2017 को भी जारी किए हैं।

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी)

आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 22ए के अनुसार, अधिनियम की धारा 24 में निर्धारित मूल्यवर्ग डिजिटल रूप में बैंक नोटों पर लागू नहीं होते हैं। तदनुसार, डिजिटल रुपया-रिटेल (ईर-आर) का लाइव-पायलट 50 पैसे, ₹1, ₹2, ₹5, ₹10, ₹20, ₹50, ₹100, ₹200, ₹500 और ₹2000 के मूल्यवर्ग में लॉन्च किया गया है, जबकि ईर-थोक (ईर-डब्ल्यू) का कोई विशिष्ट मूल्यवर्ग नहीं है। 1 दिसंबर, 2022 को शुरू किए गए ईर-आर के लाइव पायलट ने वर्ष 2023-24 के दौरान गति पकड़ी और 31 मार्च, 2024 तक ईर-आर के 237.8 लाख टुकड़े प्रचलन में हैं और प्रचलन में ₹ 5.70 करोड़ ईर-डब्ल्यू (जिसका कोई मूल्यवर्ग नहीं होगा) के मूल्य के साथ, प्रचलन में ईर का कुल मूल्य ₹ 234.04 करोड़ है।

हाल की गतिविधियां

(मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर) (एमएएनआई)

एमजी सीरीज और एमजी (न्यू) सीरीज दोनों के समवर्ती प्रचलन को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने बैंक नोटों के मूल्यवर्ग की पहचान करने में नेत्रहीनों की मदद करने के लिए वैकल्पिक तकनीकी समाधानों की खोज शुरू की। तदनुसार, जनवरी 2020 में, इसने मोबाइल एप्लिकेशन "MANI मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर" लॉन्च किया, जिससे भारतीय बैंकनोटों को दृष्टिबाधित लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाया गया और उनके दिन-प्रतिदिन के लेनदेन की सुविधा मिली। 2023-24 में, मणि ऐप पर प्रचार करने के लिए आकाशवाणी/विविध भारती/निजी एफएम रेडियो चैनलों के माध्यम से एक अखिल भारतीय रेडियो अभियान आयोजित किया गया था। आरबीआई द्वारा विकसित मोबाइल एप्लिकेशन में निम्नलिखित विशेषताएं हैं:

अ) महात्मा गांधी श्रृंखला और महात्मा गांधी (नई) श्रृंखला के बैंक नोट के मूल्यवर्ग की पहचान करने में सक्षम नोट के सामने या पीछे की तरफ/भाग की जांच करके, जिसमें विभिन्न होलिंग कोणों पर आधे मुड़े हुए नोट और प्रकाश की व्यापक रेंज (सामान्य प्रकाश / दिन की रोशनी / कम रोशनी / आदि) शामिल हैं।

आ) हिंदी / अंग्रेजी और गैर-ध्वनि मोड जैसे कंपन (दृष्टि और श्रवण हानि वाले लोगों के लिए उपयुक्त) में ऑडियो अधिसूचना के माध्यम से संप्रदाय की पहचान करने की क्षमता। इसे बाद में 2022-23 में सुधार किया गया ताकि ऐप हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 11 क्षेत्रीय भाषाओं में बैंकनोट मूल्यवर्ग को सूचित कर सके।

इ) स्थापना के बाद, मोबाइल एप्लिकेशन को इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है और ऑफ़लाइन मोड में काम करता है।

ई) एप्लिकेशन सुविधाओं तक पहुँचने के लिए वॉयस कंट्रोल के माध्यम से मोबाइल एप्लिकेशन को नेविगेट करने की क्षमता जहां भी अंतर्निहित डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम संयोजन आवाज सक्षम नियंत्रणों का समर्थन करता है।

उ) एप्लिकेशन मुफ्त है और इसे एंड्रॉइड प्ले स्टोर और आईओएस ऐप स्टोर से बिना किसी शुल्क/भुगतान के डाउनलोड किया जा सकता है।

ऊ) यह मोबाइल एप्लिकेशन किसी नोट को वास्तविक या नकली होने के रूप में प्रमाणित नहीं करता है।

मुद्रा प्रबंधन कार्यों का कोर बैंकिंग सोल्यूशन के साथ एकीकरण

रिज़र्व बैंक और मुद्रा तिजोरी में पहले से मौजूद एकीकृत कम्प्यूटरीकृत करेंसी परिचालन एवं प्रबंधन प्रणाली (आईसीसीओएमएस) को बैंक के कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) में एक नए करेंसी प्रबंधन मॉड्यूल (सीवाईएम) से प्रतिस्थापित किया है। नए मॉड्यूल की कुछ प्रमुख विशेषताओं में बेहतर इन्वेंट्री प्रबंधन, करेंसी चेस्ट लेनदेन का लगभग वास्तविक समय में लेखा-जोखा, पारगमन लेखा-जोखा और सीआईसी की बेहतर ट्रेकिंग शामिल हैं। एकीकरण परियोजना को तीन चरणों में लागू किया जाना है। चरण I और चरण II जिसमें सभी 19 क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ-साथ सीवाईएम में सभी सक्रिय मुद्रा तिजोरियों की ऑन बोर्डिंग शामिल है, पहले ही पूरा हो चुका है और इसके साथ ही करेंसी लेनदेन का लेखा-जोखा रिज़र्व बैंक की बहियों में लगभग वास्तविक समय के आधार पर परिलक्षित होता है।

सिक्कों के वितरण के लिए प्रोत्साहन बढ़ाना

बैंकों के लिए मुद्रा वितरण और विनिमय योजना (सीडीईएस) की समीक्षा की गई जिसमें सिक्कों के वितरण के लिए प्रोत्साहन को ₹ 25 से बढ़ाकर ₹ 65 प्रति बैग कर दिया गया। ग्रामीण एवं अर्धनगरीय क्षेत्रों में सिक्का वितरण हेतु 10 रुपये प्रति बैग की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देय होगी। जहां बैंकों द्वारा सिक्कों के वितरण के लिए व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) और कैश इन ट्रांजिट (सीआईटी) कंपनियों को नियुक्त करने की आवश्यकता पर पुन बल दिया गया, वहीं बैंकों को थोक ग्राहकों को सिक्के प्रदान करने को भी सूचित किया, जिसकी पहले अनुमति नहीं थी।

नई श्रेडिंग और ब्रिकेटिंग सिस्टम (एसबीएस) की खरीदारी

प्रोसेसिंग की गति बढ़ाने, चार-तरफा ओरिएंटेशन और अन्य लाभ प्राप्त होने की दृष्टि से मौजूदा सीवीपीएस मशीनों को नए सीवीपीएस मशीनों में बदलने के बाद, आरबीआई अब 21 क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए नए श्रेडिंग और ब्रिकेटिंग सिस्टम की खरीदारी की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए उचित निविदा प्रक्रिया के तहत आदेश दिए जाएंगे। इन एसबीएस मशीनों की आपूर्ति और स्थापना (डिलीवरी और इंस्टॉलेशन) Q1:2024-25 से शुरू होगी और सभी कार्यालयों के लिए अगले दो वर्षों में यह प्रक्रिया पूरी की जाने की उम्मीद की जा रही है।

कार्यालयों के लिए नई श्रेडिंग और ब्रिकेटिंग सिस्टम की खरीद की ओर बढ़ रहा है। इन एसबीएस मशीनों की डिलीवरी और स्थापना Q1: 2024-25 से शुरू होगी और सभी कार्यालयों के लिए अगले दो वर्षों में पूरा होने की संभावना है।

एटीएम की पुनःपूर्ति न करने पर के लिए दंड की योजना

2021-22 में बैंकों/व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटरों (डबल्यूएलएओ) के लिए एटीएम की पुनःपूर्ति न होने पर दंड का एक योजना शुरू की गई, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एटीएम के माध्यम से जनता को पर्याप्त नकद उपलब्ध हो।

नकद विनिमय और सिक्कों की स्वीकृति पर जागरूकता अभियान

ग्राहक सेवाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने और जानकारी प्रसारित करने के लिए, 'नकद विनिमय' पर एक अभियान एसएमएस, एफएम रेडियो और डिजिटल मीडिया (वेबसाइट) के माध्यम से चलाया गया। जनता द्वारा सिक्कों की व्यापक स्वीकृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान विभिन्न डिजाइन के समान मूल्यवर्ग के सिक्कों के प्रति भ्रांतियों को दूर करने और डर को कम करने के लिए एक अभियान चलाया।

मोबाइल सिक्का वैन (एमसीवी) द्वारा सिक्कों का वितरण – भौगोलिक पहुंच और परिचालन क्षेत्र का विस्तार

सिक्कों के वितरण को बढ़ाने के लिए, 1 अक्टूबर 2022 से कुछ चुनिंदा राज्यों में पायलट आधार पर (प्रायोगिक आधार पर) मोबाइल सिक्का वैन (एमसीवी) योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका फैलाव, अब पूरे देश में किया गया है। इसके अतिरिक्त, सेवा क्षेत्र को इस प्रकार बढ़ाया गया है कि वे उन कम मूल्यवर्ग के नोटों का विनिमय भी कर सकें जो चलन के लिए अनुपयुक्त हैं। ये एमसीवी वैन विशेष रूप से अर्ध-शहरी, ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में स्थित जनता को सिक्के और बैंक नोट वितरित करती हैं।

क्यूआर कोड-आधारित सिक्का वितरण मशीन पर पायलट परियोजना

जनता के लिए सिक्कों की पहुंच बढ़ाने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2022-23 में क्यूआर कोड-आधारित सिक्का वितरण मशीन (क्यूसीवीएम) पर एक पायलट परियोजना का विचार किया, जो यूपीआई का उपयोग करने वाला एक कैशलेस सिक्का वितरण प्रणाली है।

“मुद्रा नेटवर्क डिज़ाइन, यांत्रिकीकरण और स्वचालन, और शेड्यूलिंग और इन्वेंटरी प्रबंधन पर रिपोर्ट”

मुद्रा प्रबंधन में उच्च दक्षता प्राप्त करने के उद्देश्य से मुद्रा प्रबंधन संरचना को नेटवर्क अनुकूलन, तकनीकी समाधानों, स्वचालन और बिसनेस प्रोसेसिंग रीइंजिनियरिंग का उपयोग करते हुए पुनः डिजाइन और आधुनिक बनाने की कार्ययोजना तैयार की गई है। यह परियोजना विभिन्न हितधारकों के सहयोग से चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित की जाएगी।

₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को वापस लिया जाना

₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोट को नवंबर 2016 में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (RBI अधिनियम) की धारा 24(1) के तहत इस उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया था कि उस समय प्रचलन में मौजूद ₹500 और ₹1000 के सभी बैंक नोटों को वैध मुद्रा का दर्जा वापस लिए जाने के बाद अर्थव्यवस्था की मुद्रा की आवश्यकता को शीघ्रता से पूरा किया जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति और अन्य मूल्यवर्गों के पर्याप्त मात्रा में बैंक नोटों की उपलब्धता के बाद, ₹2000 बैंक नोटों की छपाई 2018-19 में बंद कर दी गई थी। ₹2000 के अधिकांश बैंक नोट मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे और अब उनके जीवनकाल (4-5 साल) समाप्ति के कगार पर हैं। यह भी देखा गया कि यह मूल्यवर्ग सामान्य रूप से लेन-देन के लिए उपयोग नहीं किया जाता था।

इसको ध्यान में रखते हुए और भारतीय रिज़र्व बैंक की “स्वच्छ नोट नीति” के अनुरूप, यह निर्णय लिया गया कि ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को प्रचलन से वापस लिया जाए। प्रारंभ में, ₹2000 बैंक नोटों के जमा करने और / या विनिमय की सुविधा 7 अक्टूबर 2023 तक सभी बैंक शाखाओं के साथ-साथ देश भर में आरबीआई के निर्गम कार्यालयों में उपलब्ध थी। 9 अक्टूबर 2023 से, आरबीआई के निर्गम कार्यालय भी व्यक्तियों / संस्थाओं से ₹2000 बैंक नोटों को उनके बैंक खातों में जमा करने के

लिए स्वीकार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, देशभर में स्थित लोग ₹2000 बैंक नोटों को भारत पोस्ट के माध्यम से किसी भी पोस्ट ऑफिस से भेज सकते हैं, ताकि ये नोट आरबीआई के निर्गम कार्यालयों में उनके बैंक खातों में जमा किया जा सके। जब ₹2000 के बैंक नोटों की वापसी की घोषणा की गई थी, तब संचालन में मौजूद ₹2000 के बैंक नोटों का कुल मूल्य 19 मई 2023 के कारोबार समय की समाप्ति पर ₹3.56 लाख करोड़ रहा। यह मूल्य 31 जुलाई 2024 को ₹7409 करोड़ तक घटकर रह गया। इस प्रकार, 19 मई 2023 को संचालन में मौजूद ₹2000 के बैंक नोटों का 97.92% हिस्सा अब वापस किया जा चुका है।

स्टार सीरीज के बैंक नोट

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अगस्त 2006 तक जारी किए गए नए बैंक नोटों को क्रमांकित किया जाता था। इन बैंक नोटों पर एक विशिष्ट क्रमांक होता है, जिसमें संख्याएँ और एक या अधिक अक्षर वाले प्रिफिक्स होते हैं। बैंक नोटों को 100 पीसेस के पैकटों में जारी किया जाता है। इसके बाद, रिज़र्व बैंक ने "स्टार सीरीज" क्रमांक प्रणाली अपनाई, जो कि 100 टुकड़ों के पैकट में अनुक्रमित बैंक नोटों में दोषपूर्ण छाप वाले नोटों के प्रतिस्थापन के लिए थी।

स्टार सीरीज के बैंक नोट्स अन्य सामान्य बैंक नोट्स के समान होते हैं, लेकिन इनमें एक अतिरिक्त तत्व होता है, यानी संख्या पैनल में प्रिफिक्स के बीच एक स्टार (★) प्रतीक होता है। हाल ही में, रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया कि स्टार (★) प्रतीक उस बैंक नोट पर डाला जाता है जो 100 पीसेस के पैकट में दोषपूर्ण रूप से मुद्रित किसी बैंक नोट के प्रतिस्थापन के रूप में जारी किया जाता है। स्टार (★) प्रतीक के साथ एक बैंक नोट अन्य कानूनी बैंक नोट्स के समान होता है, सिवाय इसके कि संख्या पैनल में एक स्टार (★) प्रतीक प्रिफिक्स और अनुक्रमों के बीच डाला जाता है। स्टार (★) प्रतीक से पता चलता है कि यह एक प्रतिस्थापित या पुनर्मुद्रित बैंक नोट है।

नोट और सिक्कों के उपयोग पर सर्वेक्षण

रिटेल डिजिटल भुगतान में वृद्धि के साथ-साथ नकदी की मांग में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए 2023 में नकद, सिक्कों के उपयोग और प्राथमिकता, मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों, तथा नकदी और सिक्कों की कमी/अधिकता का आकलन करने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया। कुल मिलाकर, सर्वेक्षण में यह पाया गया कि, यद्यपि, नकदी का उपयोग बरकरार रहा, डिजिटल भुगतान के माध्यम आम जनता के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे थे। बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 में इस सर्वेक्षण पर एक बॉक्स आइटम प्रकाशित किया गया।

अध्याय 15: बैंकों और सरकारों के बैंकर

केंद्रीय बैंकों की शक्तियां और कार्य सीमा अलग-अलग देशों में भिन्न होती है। लेकिन बैंकों के प्रति बैंकर और सरकारों के प्रति बैंकर जैसे कतिपय कार्य हैं जो सामान्यतः केन्द्रीय बैंकों द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। हमारे देश में भी, भारतीय रिज़र्व बैंक 'बैंकों के बैंकर' और 'सरकारों के बैंकर' के रूप में कार्य करता है।

बैंकों को बैंकर

व्यक्तिगत उपभोक्ताओं, व्यवसायों और सभी प्रकार के संगठनों की तरह, बैंकों को धन हस्तांतरित करने और अंतर-बैंक लेनदेन को निपटाने के लिए अपने स्वयं के तंत्र की आवश्यकता होती है। बैंकों के बैंकर के रूप में, रिज़र्व बैंक इस भूमिका को पूरा करता है। इस भूमिका का निर्वहन करते समय, RBI निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करता है

- अंतर-बैंक लेनदेनों के सुगम, तेज और निर्बाध समाशोधन और निपटान को सक्षम करना
- बैंकों के लिए धन हस्तांतरण का एक कुशल साधन प्रदान करना
- बैंकों को सांविधिक नकदी आरक्षित आवश्यकताओं के लिए रिज़र्व बैंक के साथ अपने खातों का रखरखाव करने में सक्षम बनाना
- आवश्यकता के मामले में अंतिम उपाय के ऋणदाता के रूप में कार्य करना

अंतिम उपाय के ऋणदाता के रूप में, यह एक ऐसे बैंक के बचाव में आ सकता है जो विलायक है, लेकिन इसे बहुत आवश्यक तरलता के साथ आपूर्ति करके अस्थायी तरलता समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब कोई और उस बैंक को ऋण देने के लिए तैयार नहीं होता है। रिज़र्व बैंक बैंक के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने और बैंक की संभावित विफलता को रोकने के लिए इस सुविधा का विस्तार करता है, जो बदले में अन्य बैंकों और संस्थानों को भी प्रभावित कर सकता है और वित्तीय स्थिरता और इस प्रकार अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

कानूनी प्रावधान

- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 – वह व्यवसाय जिसे बैंक बैंकों के साथ लेनदेनों सहित कर सकता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 – भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बैंकों द्वारा आरक्षित नकदी का रखरखाव।

बैंकों के चालू खातों का रखरखाव

बैंक और वित्तीय संस्थाएं जो बैंक में खाता खोलने के लिए पात्र हैं, सामान्यतः केवल एक ही चालू खाता खोल सकती हैं। चालू खाता रखने वाली संस्थाओं को न्यूनतम शेष राशि बनाए रखना आवश्यक है। बैंक में खाता रखने वाली संस्थाएं निम्नलिखित श्रेणियों में से एक में आती हैं:

- बैंक अर्थात्, अनुसूचित बैंक और गैर-अनुसूचित बैंक।

- भारतीय वित्तीय संस्थाएं अर्थात् प्राथमिक डीलर, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड, भारतीय रिजर्व बैंक अधिकारी/स्टाफ ऋण सहकारी समितियां आदि।
- विदेशी संस्थाएं, जैसे, विदेशी केंद्रीय बैंक, सुपरनैशनल संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, आदि।
- बैंक द्वारा अनुमोदित कोई अन्य संस्थाएं।

लक्ष्य

चालू खाते भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में ई-कुबेर प्रणाली (सीबीएस) में खोले जाते हैं, जहां संस्था का प्रधान कार्यालय/कॉर्पोरेट कार्यालय स्थित होता है। चालू खातों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है:

- बैंकों द्वारा सीआरआर का रख-रखाव
- भारतीय रिजर्व बैंक के साथ चालू खाते रखने वाली संस्थाओं के बीच अंतरबैंक निपटान और अन्य अंतर-संस्थागत निधि अंतरण
- भारतीय रिजर्व बैंक और सरकारी विभागों को भुगतान करना।

प्रतिबंध

चालू खातों में तृतीय पक्ष लेन-देन की अनुमति नहीं है। चालू खातों में इंटर-डे ओवरड्राफ्ट सहित ओवरड्राफ्ट की भी अनुमति नहीं है।

विशेष प्रयोजन खाते

भारतीय रिजर्व बैंक के पास चालू खाता रखने वाले वित्तीय संस्थाएं/बैंक किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए अतिरिक्त खाते की आवश्यकता कर सकते हैं। ऐसे विशेष प्रयोजन खाते अनुरोध के आधार पर और संबंधित केंद्रीय कार्यालय विभाग के अनुमोदन से किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय में खोले जा सकते हैं।

RTGS सेटलमेंट खाते

चालू खाते के अलावा, बैंक एक अलग **निपटान खाता भी रखते हैं**

आरटीजीएस प्रणाली में आरटीजीएस लेनदेनों के लिए जो केंद्रीय रूप से मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय (एमआरओ) द्वारा रखा जाता है।

भारत के बाहर निगमित संस्थानों के खाते

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(13) के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक भारत के बाहर निगमित बैंकों और संस्थाओं के एजेंट/प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत है और उनके लिए रुपया खाता खोल सकता है। ऐसे खाते किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय में खोले जाते हैं। ऐसे खाते खोलने, न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने, डेबिट और क्रेडिट आदि के प्रकार के संबंध में नीति संबंधित केंद्रीय कार्यालय विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है, जिसके अनुरोध पर ऐसे खाते खोले जाने हैं। निम्नलिखित कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं जो आरबीआई के साथ चालू खाता बनाए रखते हैं।

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)

- पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक (IBRD)
- अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए)
- एशियाई विकास बैंक (ADB)
- अफ्रीकी विकास कोष (ADF)

विदेशी केंद्रीय बैंकों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, सुपरनैशनल संस्थानों के चालू खातों में परिचालन संबंधित केंद्रीय कार्यालय विभाग के निर्देशों द्वारा निर्देशित किया जाएगा।

बैंकों और अन्य लोगों को ऋण और अग्रिम प्रदान करना

बैंक अनुसूचित बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और विभिन्न अन्य संस्थानों के ऋण देने, अग्रिम देने और छूट बिल देने के लिए अधिकृत है, जिसका विवरण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 और 18 के विभिन्न उप-वर्गों में दिया गया है। ऋण और अग्रिम के प्रकार जो दिए जा सकते हैं और जिन संस्थाओं को इस तरह के ऋण और अग्रिम दिए जा सकते हैं, उनका विवरण आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 17 और 18 में दिया गया है। तदनुसार, बैंक संपार्श्विक के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों के खिलाफ रेपो / मीयादी रेपो / सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत आरबीआई से तरलता सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इस सुविधा के अलावा, बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान जैसे नाबार्ड, एक्जिम, सिडबी, आदि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 के विभिन्न प्रावधानों के तहत ऋण और अग्रिम के लिए पात्र हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के पास चालू खाते रखने वाले प्राथमिक डीलर भी नकदी सहायता सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और रेपो/मीयादी रेपो का लाभ उठा सकते हैं।

सरकारों को बैंकर

सरकार का बैंकर होना आरबीआई के प्रमुख कार्यों में से एक है। व्यक्तियों, व्यवसायों और बैंकों की तरह, सरकारों को अपने वित्तीय लेनदेन को कुशल और प्रभावी तरीके से करने के लिए एक बैंकर की आवश्यकता होती है, जिसमें जनता से संसाधन जुटाना भी शामिल है। अपनी स्थापना के बाद से, आरबीआई ने सरकार के बैंकिंग लेनदेन के प्रबंधन के पारंपरिक केंद्रीय बैंकिंग कार्य किए हैं। केंद्रीय बैंक सरकार के एजेंट और सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है। सरकार के एजेंट के रूप में, इसे सार्वजनिक ऋण के प्रबंधन और सरकार की ओर से नए ऋण और ट्रेजरी बिल जारी करने का कार्य सौंपा गया है। सरकार के वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करके, यह सरकार को आर्थिक नीति के महत्वपूर्ण मामलों जैसे घाटे की वित्तपोषण, मुद्रा का अवमूल्यन, व्यापार नीति, विदेशी मुद्रा नीति आदि पर सलाह देता है। सरकारी कार्य का संचालन केंद्र सरकार के ट्रेजरी नियमों, राज्य सरकार के ट्रेजरी नियमों और महालेखा नियंत्रक, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) और केंद्र और राज्य सरकारों के अन्य विभागों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों द्वारा भी शासित होता है।

कानूनी प्रावधान RBI अधिनियम की धारा 20 और 21 के तहत, RBI के पास क्रमशः केंद्र सरकार के खाते के लिए धन स्वीकार करने और अपने खाते में जमा राशि तक भुगतान करने और संघ के सार्वजनिक ऋण के प्रबंधन सहित अपने विनिमय, प्रेषण और अन्य बैंकिंग कार्यों को करने का दायित्व और अधिकार होगा। अधिनियम की धारा 21क के अनुसार,

भारतीय रिजर्व बैंक संबंधित राज्य सरकारों के साथ करार के माध्यम से राज्य सरकार के बैंकिंग कारोबार का संचालन कर सकता है। सिक्किम राज्य को छोड़कर सभी राज्य सरकारों ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ करार किए हैं और भारतीय रिजर्व बैंक इन सरकारों के बैंकर की भूमिका निभाता है। सिक्किम के लिए, उसके सार्वजनिक ऋण के प्रबंधन के लिए एक सीमित समझौता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 भारतीय रिजर्व बैंक को सरकारी कारोबार करने के लिए एजेंसी बैंकों को नियुक्त करने का अधिकार देती है क्योंकि आरबीआई की देश भर में सीमित उपस्थिति है।

केंद्र सरकार के बैंकर

प्रशासनिक व्यवस्थाओं के तहत, केंद्र सरकार को आरबीआई के साथ न्यूनतम नकद शेष बनाए रखना आवश्यक है। केन्द्र सरकार के निम्नलिखित खाते भारतीय रिजर्व बैंक के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में ई-कुबेर (सीबीएस) प्रणाली में रखे जाते हैं और इन खातों के मुख्य खाते केंद्रीय लेखा अनुभाग (सीएएस), भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर में रखे जाते हैं।

- केंद्र सरकार - सिविल;
- रेलवे फंड;
- पोस्ट फंड;
- दूरसंचार कोष;
- रक्षा निधि;
- विभागीय मंत्रालय;
- एजेंसी लेनदेन खाता

सभी प्राप्तियां, भुगतान/संवितरण, समाशोधन/प्रेषण लेनदेन इन खातों के माध्यम से होते हैं।

राज्य सरकारों को बैंकर

सिक्किम को छोड़कर सभी राज्य सरकारों का प्रधान लेखा कैस, नागपुर में सरकारी जमा खाता-राज्य नामक खाते के अंतर्गत रखा जाता है। प्रत्येक राज्य द्वारा बनाए रखा जाने वाला न्यूनतम शेष राज्य बजट के सापेक्ष आकार और आथक कार्यकलाप के आधार पर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों के लिए एक मानकीकृत ई-रसीद और ई-भुगतान मॉडल शुरू किया गया है जिसकी चर्चा इस अध्याय के अंत में की गई है। 31 जुलाई, 2024 तक, 25 राज्य सरकारों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को ई-भुगतान के लिए ई-कुबेर के साथ एकीकृत किया गया है और 18 राज्य सरकारों को एजेंसी बैंक रिपोर्टिंग मॉडल और/या प्रत्यक्ष एनईएफटी/आरटीजीएस मॉडल के तहत ई-रसीदों के लिए ई-कुबेर के साथ एकीकृत किया गया है।

बनाए गए खातों के प्रकार

सरकारी विभाग आरबीआई के साथ निम्नलिखित प्रकार के खातों में से एक या अधिक बनाए रखेंगे।

- **वैयक्तिक खाता खाता** : ये चालू खाते की प्रकृति के होते हैं। ऐसे खाते उनकी ओर से रसीदों और आहरणों की बुकिंग के उद्देश्य से निर्दिष्ट सरकारी अधिकारियों के नाम पर खोले जाएंगे। आवश्यक शर्त यह है कि आहरण को खाते में उपलब्ध शेष राशि की सीमा तक अनुमति दी जाएगी।

- **आहरण खाता:** ये खाते उन सरकारी अधिकारियों के लिए रखे जाएंगे जिन्हें राशि की सीमा के बिना सरकारी शेष राशि पर काम करने की अनुमति है। बैंक के साथ बनाए गए अधिकांश सरकारी खाते इस श्रेणी से संबंधित हैं।
- **समनुदेशन लेखा / साख पत्र लेखा:** ये केवल आहरण खाते हैं, जिनका रख-रखाव कार्यालयों द्वारा उन सरकारी अधिकारियों के लिए किया जाएगा जिन्हें एक निश्चित राशि संबंधित वेतन एवं लेखा अधिकारी/लेखा परीक्षा कार्यालय द्वारा एक विनिदष्ट अवधि के लिए आबंटित की जाती है। निर्दिष्ट अवधि के दौरान आहरण और संवितरण अधिकारियों की ओर से भुगतान असाइनमेंट या क्रेडिट पत्र की राशि से अधिक नहीं होगा।

एजेंसी बैंकों की नियुक्ति

आरबीआई के परिचालन (1 अप्रैल, 1935) के शुरू होने से ही, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ने पहले दिन (1 अप्रैल, 1935) से पहले दो दशकों तक उन केंद्रों पर आरबीआई के एजेंट के रूप में कार्य किया जहां आरबीआई की प्रत्यक्ष उपस्थिति नहीं थी। जुलाई 1955 में अस्तित्व में आने के बाद एजेंसी की भूमिका भारतीय स्टेट बैंक को सौंप दी गई। 1976 में शुरू की गई एक योजना के तहत, केंद्र सरकार के प्रत्येक मंत्रालय और विभाग को अपने लेनदेन को संभालने के लिए एक विशिष्ट सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक आवंटित किया गया है। अतः रिज़र्व बैंक सरकार के दैनंदिन लेनदेनों का निपटान नहीं करता है, सिवाय उन मामलों के जहां इसे किसी विशेष मंत्रालय अथवा विभाग के बैंकर के रूप में नामित किया गया हो।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 के अनुसार, जब तक किसी स्थान के संदर्भ में केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्यथा निदेश न दिया जाए, भारतीय रिज़र्व बैंक, लोकहित, बैंकिंग की सुविधा, बैंकिंग विकास और ऐसे अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए, जो उसकी राय में इस संबंध में प्रासंगिक हैं, बैंकारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय बैंक या स्टेट बैंक या तदनुसूची नए बैंक की नियुक्ति कर सकेगा। 1970, या बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3 के तहत गठित एक संबंधित नया बैंक, या भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 में परिभाषित किसी भी सहायक बैंक को सभी स्थानों पर, या भारत में किसी भी स्थान पर ऐसे उद्देश्यों के लिए एजेंट के रूप में जो बैंक निर्दिष्ट कर सकता है। भारत सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45(1) के अनुसार 17 अप्रैल 2000 को अधिसूचित किया था कि रिज़र्व बैंक भारत में किसी भी स्थान पर किसी अनुसूचित बैंक या स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को अपने एजेंट के रूप में नियुक्त कर सकता है। तदनुसार, सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों और गैर-सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों को अपना कारोबार करने के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के खातों का रख-रखाव करने के लिए एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 2021 में, RBI ने वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से अनुसूचित भुगतान बैंकों और अनुसूचित लघु वित्त बैंकों को सरकारी एजेंसी व्यवसाय करने के लिए पात्र बनाने का निर्णय लिया। आज की तारीख तक रिज़र्व बैंक ने सरकारी बैंकिंग कारोबार करने के लिए 12 सरकारी क्षेत्र के बैंकों, 20 गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों और 01 विदेशी क्षेत्र के बैंक (डब्ल्यूओएस) को अपने एजेंसी बैंकों के रूप में नियुक्त किया है।

जबकि केन्द्र सरकार के खातों के लेन-देन की सूचना एजेंसी बैंकों द्वारा सीधे कैस, नागपुर और मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय को दी जाती है। (ख) भारतीय रिज़र्व बैंक ने विभिन्न प्रकार अर्थात् जीएसटी, आइसगेट (भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई गेटवे), टिन 20 (प्रत्यक्ष कर), एनटीआरपी (गैर-कर रसीद पोर्टल संग्रह) आदि, राज्य सरकार के लेन-देनों की सूचना संबंधित राज्य के भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों को दी जाती है जो लेखा शीर्ष एजेंसी संव्यवहार लेखा-राज्य के अंतर्गत खाता

ब्यौरे रखते हैं। इन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खातों में शेष राशि वार्षिक समापन को छोड़कर (अर्थात् अप्रैल के महीने में, जैसा कि सरकार के निर्देशों के अनुसार किया जाना है) को छोड़कर हर महीने की क्रमशः 1 और 5 तारीख को कैस, नागपुर में बनाए गए उनके संबंधित पीजीडीए खातों में स्थानांतरित कर दी जाती है।

एजेंसी बैंकों को उनके द्वारा संचालित सरकारी कारोबार के लिए कमीशन का भुगतान किया जाता है। सरकारी कारोबार के संचालन संबंधी अनुदेशों के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आवधिक अंतरालों पर इन एजेंसी बैंकों का निरीक्षण भी किया जाता है। रिजर्व बैंक केंद्र और राज्य सरकारों के लिए सामान्य बैंकिंग कार्यों को करने के लिए अपनी ब्याज-मुक्त न्यूनतम शेष राशि रखने के अलावा कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करता है।

सरकारी एजेंसियों की भूमिका

भारत सरकार और राज्य सरकारों के पास बैंकिंग के संचालन के लिए जिम्मेदार विभिन्न एजेंसियां हैं और इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ लगातार बातचीत करती हैं। इस संबंध में दो मुख्य संस्थान लेखा महानियंत्रक (सीजीए) के कार्यालय और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) हैं। गैर-सिविल मंत्रालयों (रेलवे, रक्षा, डाक और दूरसंचार) के लेखांकन संबंधी कार्य संबंधित लेखा प्राधिकरणों जैसे रेलवे बोर्ड, रक्षा लेखा महानियंत्रक, डाक बोर्ड और दूरसंचार बोर्ड द्वारा किए जाते हैं। सीजीए और सी एंड एजी कार्यालय के कार्यालय क्रमशः केंद्र सरकार में सिविल मंत्रालयों की लेखांकन और लेखा परीक्षा आवश्यकताओं और राज्य सरकारों की संपूर्ण बैंकिंग गतिविधियों का ध्यान रखते हैं। इसे मैट्रिक्स के अनुसार विभाजित किया गया है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

	केंद्र सरकार (सिविल)	केंद्र सरकार (गैर-सिविल)	राज्य सरकार
लेखांकन	लेखा महानियंत्रक (CGA)	संबंधित लेखा प्राधिकरण (रेलवे, रक्षा, डाक और दूरसंचार)	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C & AG) अपने AG कार्यालयों के माध्यम से
लेखा-परीक्षण	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C & AG)	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C & AG)	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (C & AG) अपने AG कार्यालयों के माध्यम से

वस्तुओं की सुरक्षित अभिरक्षा का प्रावधान

सुरक्षित जमा के लिए वस्तुएं केंद्र/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के सरकारी मंत्रालयों/विभागों से भी स्वीकार की जाती हैं जो आरबीआई के साथ बैंकिंग कर रहे हैं। छोटे बक्से/सीलबंद पैकेट सुरक्षित अभिरक्षा के लिए स्वीकार किए जाते हैं और इस प्रयोजन के लिए तिजोरी स्थान में भंडारित किए जाते हैं। सुरक्षित अभिरक्षा के लिए लेख शुरू में छह साल की अवधि के लिए स्वीकार किए जाएंगे। हालांकि, यदि कोई सरकारी विभाग वस्तु को लंबी अवधि के लिए सुरक्षित रखना चाहता है, तो वे छह साल की निर्धारित अवधि की समाप्ति पर या उससे पहले लेख वापस ले सकते हैं और छह वर्ष की समाप्ति से

पहले इसे पुन जमा करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय को आवेदन करें। क्षेत्रीय कार्यालय अपने विवेक पर पुनः जमा की अनुमति दे सकता है। वस्तुओं की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

सरकारी बैंकिंग प्रभाग के कार्य

सरकारी बैंकिंग प्रभाग (जीबीडी) सरकार के बैंकर होने का मुख्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य करता है। तदनुसार, यह केंद्र और राज्य सरकारों के जमा खातों को बनाए रखता है। प्रभाग मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यों में भाग लेता है:

(a) प्राप्तियाँ

- समाशोधन के माध्यम से या सरकारी खाते में जमा करने के लिए हस्तांतरण द्वारा नकद में धन की प्राप्ति;
- प्रत्येक सरकारी खाते के प्रमुख शीर्षों के तहत वर्गीकरण और रिकॉर्डिंग;
- रसीद चालान के रूप में रसीद जारी करना; और
- दिन के अंत में खातों का संतुलन।

(b) भुगतान

- चेक, ब्याज वारंट आदि का नकद भुगतान, समाशोधन या अंतरण के माध्यम से।
- प्रत्येक सरकारी खाते के लिए मुख्य शीर्षों के तहत उनका वर्गीकरण और रिकॉर्डिंग;
- ड्राइंग, असाइनमेंट और व्यक्तिगत खाता बही खातों का रखरखाव; और
- दिन के अंत में खातों का संतुलन।

(c) धन का संग्रह

चेक ट्रंक्शन सिस्टम (सीटीएस) ग्रिड में भाग लेने वाले क्लियरिंग बैंकों पर आहरित चेकों आदि के साथ दिए गए चालान भारतीय रिज़र्व बैंक में स्वीकार किए जाएंगे ताकि चेक की वसूली हो सके और संबंधित सरकारी खाते में जमा हो सके। रिज़र्व बैंक या इसके उप-सदस्यों पर आहरित चेक, ब्याज वारंट और अन्य लिखत और बैंक स्थित स्थान पर देय आवक समाशोधन लिखतों के रूप में प्राप्त किए जाएंगे और सीटीएस के अंतर्गत चेकों की छवि वाली फाइल सीबीएस में अपलोड की जाएगी और भुगतान के लिए पारित किए जाने से पहले चेक की छवि की जांच की जाएगी।

(d) धन का प्रेषण

- **अंतर्देशीय** - बैंकिंग विभाग के प्रेषण और समाशोधन सेवा अनुभाग के माध्यम से
- **विदेशी** - भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों के माध्यम से।

(ड) लेखा विवरण: सात मुख्य खातों अर्थात् राज्य, केंद्रीय (सिविल), रेलवे, डाक, दूरसंचार, रक्षा और विभागीय मंत्रालयों के खातों के तहत खातों के विवरण तैयार करना और उन्हें संबंधित लेखा परीक्षा/नियंत्रण कार्यालयों को प्रस्तुत करना और संबंधित अधिकारियों को आवधिक विवरण प्रस्तुत करना।

(च) सरकारी जमा खातों में मासिक अंत शेष का केन्द्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर को अंतरण।

(छ) एजेंसी बैंकों में सरकारी बैंकिंग कारोबार का निरीक्षण करना।

(ज) भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी निवेश और प्रचालन विभाग) द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार विदेश स्थित भारतीय मिशनो के लिए वित्तीय व्यवस्था करना, विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक को प्रतिपूत करना, आदि।

(i) सरकारी बैंकिंग/विभिन्न योजनाओं के संचालन के लिए एजेंसी बैंकों को एजेंसी कमीशन का भुगतान।

(ज) न्यायालयों में साक्ष्य के रूप में दस्तावेजों को प्रस्तुत करना और अन्य संबद्ध मामले, न्यायालयों द्वारा तामील किए गए निषेधाज्ञा/कुर्की आदेशों पर ध्यान देना, आदि सरकारी शेष राशियां संलग्न करना।

क्षेत्रीय कार्यालयों में जीबीडी, सरकारों की ओर से प्राप्तियों और भुगतान से संबंधित कार्य को संभालते हैं। इस प्रकार, वे सरकारी बैंकिंग को संभालने के लिए श्रृंखला के सबसे अंत में हैं। राज्यों के संबंध में, जीबीडी राज्य सरकार के खातों के आंशिक विकेन्द्रीकरण की योजना के तहत एजेंसी बैंकों द्वारा सूचित लेनदेनों का निपटान करते हैं। हालांकि, आरबीआई के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (ई-कुबेर) की शुरुआत और ई-भुगतान/ई-रसीदों के लिए मानकीकृत मॉडल के कार्यान्वयन के साथ, जीबीडी ने सरकारी प्राप्तियों/भुगतानों को सीधे सरकारी प्रणालियों और आरबीआई की ई-कुबेर प्रणाली के बीच एकीकरण के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से संभालना शुरू कर दिया है।

सरकारों के लिए ई-रसीदें और ई-भुगतान

राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक सरकारी बैंकिंग की प्रक्रिया को निरंतर उन्नत और उन्नत करने का प्रयास करता है ताकि उन्हें सहज और दक्ष बनाया जा सके। इन प्रयासों के भाग के रूप में, राज्य सरकारों की ई-प्राप्तियों/ई-भुगतानों की प्रक्रियाओं/डेटा संरचना में एकरूपता और मानकीकरण लाने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया गया था, जिसने फरवरी 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रत्येक राज्य में ट्रेजरी पोर्टल स्थापित करने और बैंकों के साथ कार्यात्मक एकीकरण के लिए, सरकार को प्रेषण करने के लिए ई-चालान की शुरुआत, ई-स्कॉल के साथ भौतिक स्कॉल के प्रतिस्थापन, बैंकों और ट्रेजरी के बीच स्वचालित और ऑनलाइन सामंजस्य का विकास, ऐसे लेनदेन की कानूनी स्थिति को मजबूत करने के लिए ऑनलाइन प्रवाह करने वाली सूचना के डिजिटल हस्ताक्षर, से संबंधित प्रमुख सिफारिशें, दूसरों के बीच में। इसके परिणामस्वरूप मई, 2015 से विभिन्न राज्यों सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए मानकीकृत ई-रसीदें और ई-भुगतान मॉडल लागू किया जा रहा है। वस्तु एवं सेवा कर (जुलाई 2017 में लागू) सहित केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के साथ एकीकरण मोटे तौर पर इसी मॉडल का अनुसरण करता है।

मानकीकृत ई-भुगतान मॉडल में भारतीय रिज़र्व बैंक के कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) के साथ इंटरफेस स्थापित करके राज्य सरकारों के इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों की सीधी प्रक्रिया (एसटीपी) के माध्यम से पूर्ण करने की परिकल्पना की गई है। राज्य सरकारों को ई-कुबेर के साथ सुरक्षित एकीकरण स्थापित करने के लिए अपेक्षित बुनियादी ढांचे के साथ एक केंद्रीकृत ट्रेजरी प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है। इस मॉडल में पूरी तरह से स्वचालित प्रक्रिया प्रवाह स्कॉल के एंड-टू-एंड संदेश प्रसंस्करण, लेखा, पीढ़ी और प्रेषण को निर्बाध रूप से सुनिश्चित करता है, और सिस्टम-आधारित सामंजस्य की सुविधा भी प्रदान करता है। यह राज्य सरकारों को समय-समय पर भुगतान करने की अनुमति देता है और इस प्रकार अपनी निधियों की स्थिति पर बेहतर नियंत्रण को सक्षम करता है। इसी प्रकार, ई-कुबेर ई-भुगतान प्रणाली का उपयोग सीजीए के तत्वावधान में सार्वजनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) द्वारा अन्य बैंकों में खाता रखने वाले लाभार्थियों (एनईएफटी/आरटीजीएस भुगतान मोड का उपयोग करके) के साथ-साथ आरबीआई के साथ खाते रखने वाले लाभार्थियों (आंतरिक अंतरण मोड) को केंद्र सरकार के भुगतान (वर्तमान में गैर-सिविल मंत्रालयों को छोड़कर) करने के लिए भी किया जाता है। रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए) ने नवंबर 2020 से रक्षा पेंशन भुगतान की प्रक्रिया के लिए ई-कुबेर के साथ

पेंशन प्रशासन (रक्षा) (एसपीएआरएसएच) प्रणाली के लिए अपनी प्रणाली को भी एकीकृत किया है।

मानकीकृत ई-रसीद मॉडल में निम्नलिखित के माध्यम से राजस्व संग्रह की परिकल्पना की गई है -

- एजेंसी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को संग्रहण/प्राप्तियों की ऑनलाइन सूचना देने के साथ राज्य सरकारों को विभिन्न एजेंसी बैंकों से अलग-अलग रसीद स्कॉल के बजाय आरबीआई से समेकित रसीद स्कॉल प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं।
- भुगतान का एनईएफटी/आरटीजीएस मोड जहां संग्रह सीधे आरबीआई के साथ बनाए गए सरकार के खाते में टी+0 आधार पर टी+0 आधार पर प्राप्त किया जाता है, जो करदाता द्वारा कार्य दिवस पर किए गए भुगतान के अधीन है। इससे संबंधित राज्य सरकारों को एजेंसी बैंक संग्रहण और रिपोर्टिंग के माध्यम से प्रणाली की तुलना में निधियों के शीघ्र क्रेडिट की सुविधा मिलती है।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)

करदाता जीएसटी पोर्टल से कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर (सीपीआईएन) जनरेट करने के बाद ऑनलाइन भुगतान मोड (इंटरनेट बैंकिंग/डेबिट/क्रेडिट कार्ड/यूपीआई) या सीधे एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से जीएसटी भुगतान कर सकते हैं या ओवर द काउंटर (ओटीसी) भुगतान विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। भुगतान प्राप्त होने के बाद, संबंधित बैंकों द्वारा एक चालान पहचान संख्या (सीआईएन) उत्पन्न की जाती है जिसे करदाता और जीएसटी पोर्टल के साथ साझा किया जाता है। लेन-देन (चालान) विवरण के साथ आरबीआई के साथ एजेंसी बैंकों द्वारा टी+1 आधार पर निधियों का निपटान किया जाता है। आरबीआई जीएसटी से संबंधित सभी लेनदेन का एकमात्र एग्रीगेटर है।

जीएसटी के अलावा, ई-कुबेर के ई-रसीद मॉड्यूल को केंद्र सरकार की अन्य प्रणालियों/प्लेटफार्मों जैसे कि सीबीआईसी के तत्वावधान में आने वाले उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क आदि जैसे अन्य अप्रत्यक्ष करों के लिए आईसीईजीएटीई, सीबीडीटी के तत्वावधान में प्रत्यक्ष करों के लिए टिन 2.0 और एनईएफटी/आरटीजीएस भुगतान विकल्पों के माध्यम से सरकारी खाते में गैर-कर देय/राजस्व के ऑनलाइन संग्रह के लिए सीजीए कार्यालय के तत्वावधान में गैर-कर रसीद पोर्टल (एनटीआरपी) के साथ एकीकृत किया गया है।

केंद्रीय लेखा अनुभाग (सीएएस), नागपुर के कार्य

सीएएस, नागपुर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्रमुख खातों का रखरखाव करता है और दिन के अंत में विभिन्न खातों में शेष राशि को समेकित करता है जिसे दैनिक स्थिति (डीपी) कहा जाता है। सीएएस, नागपुर द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्य हैं:

- डीपी के बाद दैनिक शेष सूचना ई-मेल के माध्यम से केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों और आरबीआई के साथ खातों का रखरखाव करने वाली राज्य सरकारों को भेजना। ये सूचनाएं चुनिंदा केंद्रीय कार्यालय विभागों को भी भेजी जाती हैं।
- न्यूनतम शेष राशि पर नजर रखना, जिसे केंद्र सरकार और बैंक के साथ खाता रखने वाली सभी राज्य सरकारों द्वारा उनके संबंधित समझौतों की शर्तों के तहत रखा जाना आवश्यक है।
- न्यूनतम शेष बनाए रखने में कमी के मामले में केंद्र सरकार को तरीके और साधन अग्रिम और OD और विशेष

आहरण सुविधा (SDF), WMA और OD राज्य सरकारों को प्रदान करना।

- भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में निर्धारित न्यूनतम शेष राशि के ऊपर केंद्र सरकार के अधिशेष निधियों का निवेश।
- राज्य सरकारों की अधिशेष निधियों को 14 दिन के मध्यवर्ती ट्रेजरी बिलों में निवेश करना और निर्धारित न्यूनतम शेष राशि में कमी के मामले में उसकी पुनर्गणना करना।
- ओएलटीएस-एनएसडीएल पोर्टल में आरबीआई के विभिन्न कार्यालयों द्वारा प्रत्यक्ष कर संग्रह वाले डेटा अपलोड करना।
- विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी अधिदेशों का पंजीकरण (आरआईडीएफ, एमआईएफ आदि के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने के लिए)
- प्राप्त अधिदेशों के आधार पर संबंधित हितधारकों से बैंकों/वित्तीय संस्थानों को आवर्ती भुगतान सुनिश्चित करना।
- एजेंसी बैंकों और केंद्र सरकार के बीच निधियों का दैनिक निपटान।
- संबंधित राज्य सरकारों के खातों से राज्य विकास ऋणों पर फ्लोटेशन प्रभार और प्रबंधन कमीशन की वसूली। (यह फ़ंक्शन अब वित्त वर्ष 2024-25 से पीडीओ, मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया है)।
- केंद्र सरकार के कारोबार का संचालन करने वाले एजेंसी बैंकों को तिमाही आधार पर टर्नओवर कमीशन का भुगतान।
- अंतर सरकारी सलाह के माध्यम से अंतर-सरकारी लेनदेन की मंजूरी।
- राज्य सरकारों के लिए ²⁸समेकित सिंकिंग फंड और गारंटी रिडेम्पशन फंड का प्रशासन।
- ओडिशा राज्य सरकार के लिए बजट स्थिरीकरण कोष का प्रशासन।
- एजेंसी बैंकों और केंद्र सरकार के बीच राहत बांड और बचत बांड के लिए निधियों का निपटान।
- भारत सरकार के राहत बांड/बचत बांड कारोबार करने के लिए एजेंसी बैंकों को ब्रोकरेज और हैंडलिंग कमीशन का भुगतान करना।
- अन्य गतिविधियां, जो नियमित प्रकृति की नहीं हैं, लेकिन एक बार की गतिविधि के रूप में या सीमित अवधि के लिए की जानी हैं। उदाहरण के लिए, द्विभाजित राज्यों के संबंध में निर्वहन मूल्य और ब्याज भुगतान का विभाजन करना, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमआईटीवाई) आदि से जनादेश प्राप्त होने पर मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) प्रतिपूर्ति योजना के तहत अधिग्रहण करने वाले बैंकों को भुगतान करना।
- सरकारी कार्य पर नीतिगत मामलों पर केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्रीय कार्यालय विभागों को इनपुट प्रदान करना।
- प्रत्यक्ष कर संग्रह (टिन 2.0), सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क से संबंधित लेनदेन अब मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा संभाले और प्रशासित किए जा रहे हैं

नई पहल

²⁸ राज्य सरकारों द्वारा किए गए योगदान से सार्वजनिक ऋण कार्यालय, आरबीआई, नागपुर में बनाए रखा गया। जबकि समेकित सिंकिंग निधि का उपयोग राज्य सरकारों द्वारा आवश्यकता के मामले में अपने ऋण की अदायगी के लिए किया जाएगा, गारंटी मोचन निधि का उपयोग राज्य सरकारों और उनके उपक्रमों के गारंटी दायित्वों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

केंद्र प्रायोजित योजना निधियों को जारी करने के लिए SNA SPARSH तंत्र का कार्यान्वयन- SNA SPARSH (समयोचित प्रणाली एकीकृत शीघ्र हस्तांतरण) एक वैकल्पिक निधि प्रवाह तंत्र है, जिसे 1 अगस्त, 2023 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS), राज्य एकीकृत वित्तीय प्रबंधन और सूचना प्रणाली (IFMIS) और RBI की ई-कुबेर प्रणाली के एकीकृत ढांचे के माध्यम से केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर केंद्र प्रायोजित योजना निधि जारी करने के लिए लागू किया गया है। इस मॉडल में, RBI एजेंसी बैंक की भागीदारी के बिना सरकारों के लिए प्राथमिक बैंकर के रूप में कार्य करता है। इस तंत्र के माध्यम से सरकारी निधियों के संबंध में जस्ट टाइम रिलीज से सरकारी नकदी प्रबंधन में और अधिक दक्षता आएगी।

निष्कर्ष:

हालांकि आरबीआई बैंकों और सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करके केंद्रीय बैंक के पारंपरिक कार्यों को पूरा करता है, लेकिन यह इन सेवाओं को सुचारू रूप से और कुशलता से वितरित करने में सुधार लाने के लिए लगातार प्रयास करता है। इस उद्देश्य के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की प्रणालियों को एकीकृत करके ई-कुबेर की क्षमताओं का लाभ उठा रहा है ताकि सरकार की प्राप्तियों के संग्रहण और भुगतानों के संवितरण में दक्षता लाई जा सके। नीति स्तर पर, विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्शी दृष्टिकोण के माध्यम से व्यवसाय और परिचालन दक्षताओं की भी शुरुआत की जाती है।

अध्याय 16: आंतरिक ऋण प्रबंधन

पृष्ठभूमि

संप्रभु ऋण प्रबंधन सरकार के ऋण के प्रबंधन के लिए एक कार्यनीति स्थापित करने और निष्पादित करने की प्रक्रिया है ताकि आवश्यक मात्रा में निधि जुटाया जा सके, अपने जोखिम और लागत उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके, और सरकार द्वारा निर्धारित किसी भी अन्य संप्रभु ऋण प्रबंधन लक्ष्यों को पूरा किया जा सके, जैसे कि एक तरल और अच्छी तरह से काम करने वाले घरेलू सरकारी प्रतिभूति बाजार का विकास करना। एक ऋण प्रबंधक के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को जारी करता है और केंद्र सरकार के मामले में सांविधिक प्रावधानों के आधार पर और राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ करार के अनुसार सरकारों की ओर से सरकारी ऋण का प्रबंधन करता है। नकदी प्रबंधन कार्य के भाग के रूप में, बैंक सरकारों को उनकी प्राप्तियों और भुगतानों में अस्थायी विसंगतिया को पूरा करने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) प्रदान करता है। बैंक सरकारों के अधिशेष नकद शेष का निवेश भी करता है। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से लोक ऋण के प्रबंधन में सरकारी प्रतिभूतियों को जारी करना, ब्याज का भुगतान, प्रतिभूतियों का पुनर्भुगतान, और अन्य परिचालन मामले जैसे ऋण प्रमाण पत्र और उनका पंजीकरण शामिल है। लोक ऋण प्रबंधन कार्य केंद्रीय कार्यालय में आंतरिक ऋण प्रबंधन विभाग (आईडीएमडी) और बैंक के कार्यालयों में लोक ऋण कार्यालय (पीडीओ) द्वारा किया जाता है।

सांविधिक आधार

संविधान के अनुच्छेद 292 में भारत की समेकित निधि प्रतिभूति पर भारत सरकार द्वारा ऋण जारी करने का प्रावधान है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 20 और 21 के अनुसार, यह केंद्र सरकार के लिए अनिवार्य है कि वह भारतीय रिज़र्व बैंक को अपने ऋण और नकदी प्रबंधन कार्यों को सौंपे, और यह भारतीय रिज़र्व बैंक की जिम्मेदारी है कि वह भारत सरकार के ऋण और नकदी प्रबंधन कार्यों का संचालन करे। सरकारी ऋण के निर्गम और भुगतान से संबंधित मामलों पर सरकारी प्रतिभूति अधिनियम (जीएस अधिनियम) 2006 और उसके अंतर्गत बनाए गए सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 293 राज्य सरकारों को वित्तीय उधार लेने की शक्तियां प्रदान करता है। यह राज्यों को उनके समेकित निधि की सुरक्षा पर भारत के भीतर उधार लेने की अनुमति देता है, जो उनके संबंधित विधानसभाओं द्वारा निर्धारित सीमाओं के अधीन है। इसके अतिरिक्त, इसके लिए केंद्र सरकार से बकाया ऋण वाले राज्यों को आगे उधार लेने के लिए अपनी सहमति लेने की आवश्यकता होती है। राज्य सरकारें अपने बैंकिंग और ऋण प्रबंधन कार्यों के लिए आरबीआई अधिनियम की धारा 21 ए के संदर्भ में आरबीआई के साथ एक करार कर सकती हैं। आज की तारीख में, पुडुचेरी और जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्रों के साथ-साथ सभी राज्य सरकारों ने अपनी ऋण गतिविधियों का प्रबंधन करने के लिए आरबीआई के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। बैंकिंग करार के संबंध में, सिक्किम को छोड़कर, सभी राज्य सरकारों पुडुचेरी और जम्मू तथा कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंकिंग करार हैं।

मध्यम अवधि ऋण प्रबंधन कार्यनीति (एमटीडीएस)

वर्षों से, सरकारी ऋण प्रबंधन को मध्यम अवधि के ऋण प्रबंधन कार्यनीति (एमटीडीएस) के तीन स्तंभों द्वारा निर्देशित किया गया है, अर्थात् लागत अनुकूलन, जोखिम शमन और बाजार विकास। एमटीडीएस का उद्देश्य मध्यम से लंबी अवधि में लागत प्रभावी तरीके से बाजार उधार को सुरक्षित करना है, जबकि विवेकपूर्ण स्तरों पर जोखिम बनाए रखना है ताकि एक स्थिर ऋण संरचना सुनिश्चित हो सके और एक तरल और अच्छी तरह से काम करने वाला घरेलू सरकारी प्रतिभूति बाजार विकसित हो सके। आईडीएमडी घरेलू और वैश्विक वित्तीय बाजार के विकास को ध्यान में रखते हुए एमटीडीएस ढांचे के भीतर लोक ऋण प्रबंधन करता है। सरकारी ऋण पोर्टफोलियो की स्थिरता में सुधार करने के लिए, बकाया ऋण का समेकन निष्क्रिय और सक्रिय दोनों तरीकों से किया जाता है। निष्क्रिय समेकन मुख्य रूप से पुनः जारी करने के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जो लगभग 95 प्रतिशत बॉन्ड जारी करने के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि सक्रिय समेकन स्विच और बाय-बैक के माध्यम से किया जाता है।

नकदी और ऋण प्रबंधन पर निगरानी समूह (एमसीजीडीएम)

भारत सरकार के आर्थिक मामलों के सचिव और आईडीएमडी, आरबीआई के प्रभारी उप गवर्नर की सह-अध्यक्षता वाली स्थायी समिति, नकद और ऋण प्रबंधन पर निगरानी समूह (एमसीजीडीएम) समय-समय पर बैठक करता है और छमाही उधार कैलेंडर के निर्माण सहित सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम के प्रबंधन से संबंधित विभिन्न नीतियों और योजनाओं पर निर्णय लेता है। इस व्यवस्था को वित्त मंत्रालय और भारतीय रिज़र्व बैंक के बीच नियमित विचार-विमर्श द्वारा आगे बढ़ाया जाता है।

ऋण प्रबंधक के रूप में आरबीआई की भूमिका

आईडीएमडी केंद्र के साथ-साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के बाजार उधार कार्यक्रम (एमबीपी) का प्रबंधन करता है और इन परिचालनों से संबंधित लेखा/रिपोर्टिंग का रखरखाव करता है। इसमें निर्गम और सर्विसिंग पहलू अर्थात् रुपया ऋण पूर्ण भुगतान, ऋणों पर ब्याज का भुगतान और ऋण प्रमाणपत्रों तथा उनके पंजीकरण से संबंधित प्ररिचालनात्मक मुद्दों पर कार्रवाई करना शामिल है। बाजार की मांग के आकलन, भारत सरकार की बजटीय और नकदी प्रबंधन आवश्यकताओं, वित्तपोषण अंतर और बाजार विकास, विचारों को ध्यान में रखते हुए, साप्ताहिक नीलामियों का एक कैलेंडर तैयार किया जाता है। छमाही अंतराल पर साप्ताहिक नीलामियों का कैलेंडर जारी करने से संस्थागत और खुदरा निवेशक अपने निवेश की कुशलतापूर्वक योजना बना सकते हैं जिससे जारी करने की प्रक्रिया के पारदर्शिता में सुधार होता है और सरकारी प्रतिभूति बाजार की स्थिरता में वृद्धि होती है। ट्रेजरी बिल (टी-बिल) और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के जारी करने के मामले में, सांकेतिक उधार कैलेंडर क्रमशः तिमाही और छमाही आधार पर जारी किया जाता है। राज्य सरकारों की दिनांकित प्रतिभूतियों (मंगलवार), ट्रेजरी बिलों (बुधवार) और केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों (शुक्रवार) को टी+1 आधार पर निपटान के साथ जारी करने के लिए साप्ताहिक नीलामी आयोजित की जाती है।

बाजार उधार के साधन

आरबीआई बाजार की मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न रूपों में विपणन योग्य प्रतिभूतियों को जारी करके सरकार की

और से बाजार उधार का प्रबंधन करता है। इन उधार साधनों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

- **फिक्स्ड रेट बॉन्ड** – यह वे ऋण प्रतिभूतियां हैं जो अपनी पूरी अवधि में एक निश्चित ब्याज दर का भुगतान करती हैं। ब्याज को कूपन के रूप में जाना जाता है, समय-समय पर आमतौर पर छमाही या वार्षिक भुगतान किया जाता है। परिपक्वता पर, बॉन्डधारक को मूल राशि प्राप्त होती है, जो एक अनुमानित आय स्ट्रीम प्रदान करती है और निवेशकों के लिए ब्याज दर जोखिम को कम करती है। एक निश्चित दर बांड का विशिष्ट नाम होगा, उदाहरण के लिए 7.10% जीएस 2034 (वर्ष 2034 में परिपक्वता के साथ 7.10% का 10-वर्षीय भारत सरकार दिनांकित प्रतिभूति कूपन)।
- **फ्लोटिंग रेट बॉन्ड** (एफआरबी) - ये बॉन्ड कुछ बेंचमार्क दर (आमतौर पर 182- ट्रेजरी बिल की उपज से जुड़ा हुआ) के आधार पर कूपन का भुगतान करते हैं और कूपन को आवधिक अंतराल पर रीसेट किया जाता है।
- **शून्य कूपन बांड** (ट्रेजरी बिल, नकद प्रबंधन बिल) - शून्य कूपन बांड कोई आवधिक कूपन का भुगतान नहीं करते हैं, छूट पर जारी किए जाते हैं और पूर्ण अंकित मूल्य पर भुनाए जाते हैं। डिस्काउंटेड इश्यू की कीमत और फेस वैल्यू में अंतर इन बॉन्ड पर रिटर्न का प्रतिनिधित्व करता है। भारत सरकार द्वारा जारी ट्रेजरी बिल और कैश मैनेजमेंट बिल इस प्रकार के मनी मार्केट इंस्ट्रुमेंट हैं।
- **सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड** (एसजीबी) - ये सरकार द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियां हैं जो सोने के ग्राम में अंकित होती हैं, जो भौतिक सोने के निवेश का विकल्प प्रदान करती हैं। वे आवधिक ब्याज भुगतान प्रदान करते हैं और भुगतान मूल्य परिपक्वता पर सोने के प्रचलित बाजार मूल्य से जुड़ा होता है। एसजीबी भंडारण और शुद्धता की चिंताओं के बिना, ब्याज अर्जित करते हुए सोने में निवेश करने का एक सुरक्षित तरीका प्रदान करते हैं।
- **फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड**, (2020) कर योग्य- एफआरएसबी 2020 (टी) - ये ब्याज वाले, गैर-व्यापार योग्य बांड हैं जो जारी होने की तारीख से सात साल की समाप्ति पर चुकाने योग्य हैं। कूपन/ब्याज दर निर्धारित नहीं है और एनएससी दर से (+) 35 बीपीएस के स्प्रेड के साथ प्रचलित राष्ट्रीय बचत (एनएससी) दर से जुड़ी हुई है/आंकी गई है। कूपन को हर साल 01 जुलाई और 01 जनवरी को छमाही आधार पर रीसेट किया जाएगा।
- **मुद्रास्फीति सूचकांक बांड** (खुदरा और थोक) - ऐसे बांड मुद्रास्फीति के कारण वास्तविक रिटर्न के क्षरण से सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिसमें मुद्रास्फीति को मुद्रास्फीति सूचकांक जैसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) और थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के माध्यम से मापा जाता है। ये बॉन्ड कभी-कभी जारी किए जाते हैं।
- **कॉल / पुट विकल्पों के साथ बांड** - कॉल और पुट विकल्प के साथ बांड ब्याज दर जोखिम को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए क्रमशः जारीकर्ता और निवेशक को अतिरिक्त लचीलापन प्रदान करते हैं। भारत सरकार ऐसे बांड बहुत कम ही जारी करती है।
- **विशेष प्रतिभूतियां** - विशेष प्रतिभूतियां, जैसे तेल बांड, उर्वरक बांड, उदय पुनर्पूजीकरण बांड आदि भारत सरकार द्वारा विशिष्ट उद्देश्यों के लिए विशिष्ट संस्थाओं को जारी किए गए थे। उदाहरण के लिए, पावर बॉन्ड (या उदय बॉन्ड) राज्यों द्वारा देयता के आंशिक अधिग्रहण के माध्यम से डिस्कॉम के ऋणों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप जारी किए जाते हैं। इसी तरह, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों और उर्वरक कंपनियों को भारत सरकार द्वारा सब्सिडी भुगतान के बदले तेल बांड और उर्वरक बांड जारी किए गए थे।
- **सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड** (एसजीबी) - ये हरित बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी

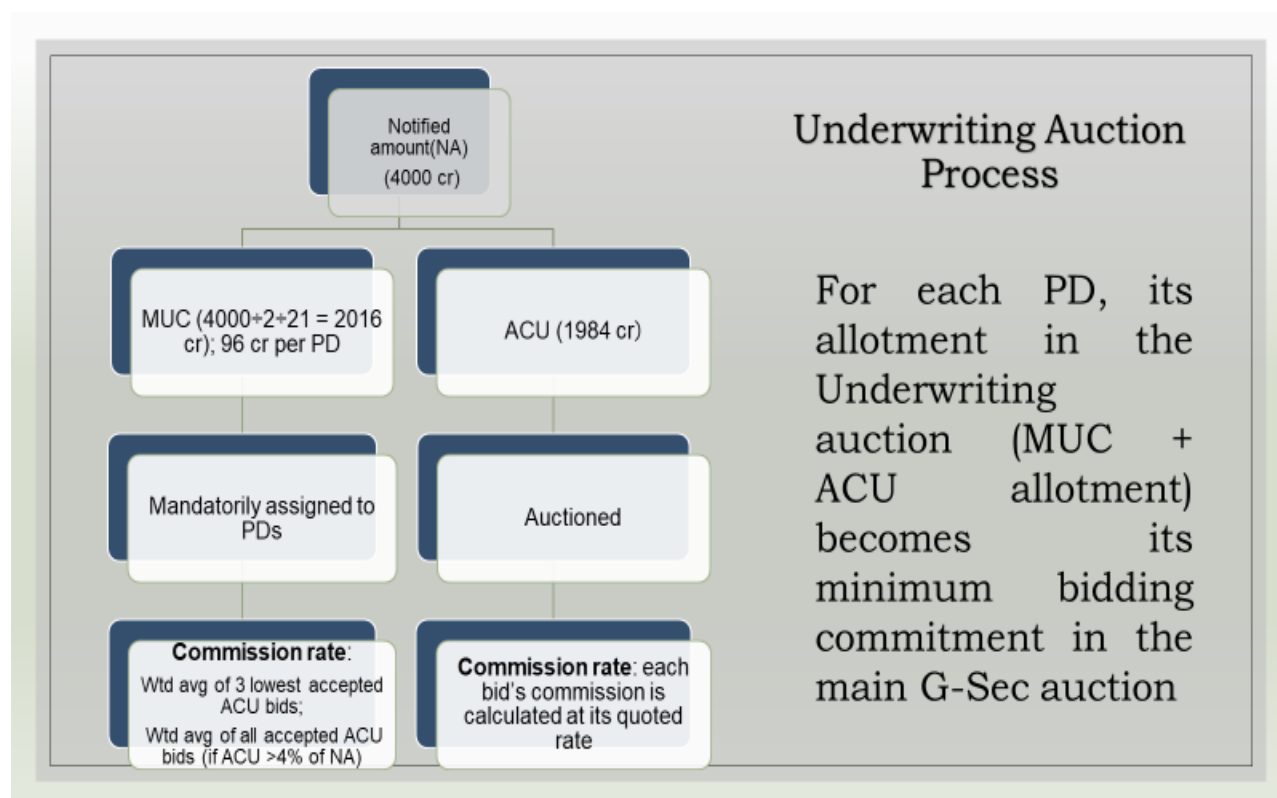
किए गए ऋण साधन हैं। इन बॉन्डों से प्राप्त आय सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में तैनात की जाती है जो अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कम करने में मदद करती हैं।

प्राथमिक डीलर

1995 में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूति बाजार में प्राथमिक डीलरों (पीडी) की प्रणाली शुरू की। पीडी प्रणाली का उद्देश्य सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार में अवसंरचना को मजबूत करना, सरकारी प्रतिभूतियों के लिए हामीदारी और बाजार निर्माण क्षमताओं का विकास करना, द्वितीयक बाजार व्यापार प्रणाली में सुधार करना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को खुले बाजार प्रचालनों के लिए एक प्रभावी माध्यम बनाना है। 01 सितंबर, 2024 तक, सात स्टैंडअलोन पीडी (स्टैंडअलोन पीडी को आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के तहत एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत करना आवश्यक है) और चौदह बैंक पीडी हैं जो विभागीय रूप से प्राथमिक डीलरशिप गतिविधियां करते हैं।

आशा की जाती है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली केंद्र सरकार की प्राथमिक नीलामी की हामीदारी करने, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की प्रधानता, सरकारी प्रतिभूतियों में बाजार निर्माण, न्यूनतम द्वितीयक बाजार कारोबार अनुपात प्राप्त करने और भारतीय रिज़र्व बैंक के खुदरा प्रत्यक्ष पोर्टल पर खुदरा निवेशकों को दर उपलब्ध कराने जैसे विभिन्न दायित्वों को पूरा करके प्राथमिक और द्वितीयक बाजार दोनों क्षेत्रों में सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार में सक्रिय भूमिका निभाएंगी। हामीदारी नीलामी प्रक्रिया का एक उदाहरण चार्ट¹ में दिया गया है।

चार्ट 1: हामीदारी नीलामी प्रक्रिया का चित्रण



सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशक

भारत में वाणिज्यिक बैंक सरकारी प्रतिभूतियों में सबसे बड़े निवेशक वर्ग हैं, इसके बाद बीमा कंपनियां, भविष्य निधि, पेंशन फंड और म्यूचुअल फंड हैं। आरबीआई एफपीआई निवेश प्रवाहों में संभावित अस्थिरता से जुड़े जोखिमों को कम करते हुए सरकारी प्रतिभूतियों के निवेशक आधार को व्यापक बनाने के उद्देश्य से धीरे-धीरे और कैलिब्रेटेड तरीके से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए जी-सेक बाजार खोलने की नीति का अनुसरण करता रहा है। एफपीआई को भारत में विभिन्न ब्याज दर डेरिवेटिव उत्पादों में हेजिंग या अन्यथा के लिए व्यापार करने की भी अनुमति दी गई है।

Participation of Foreign Portfolio Investors

Medium Term Framework

Introduced in October 2015

- G-secs: up to 6% of the outstanding stock; SGSs: up to 2% of the outstanding
- Macro prudential short term limit viz., not more than 30 per cent of investments in government securities can have a residual maturity of less than one year.

Voluntary Retention Route

Introduced in March 2019 – combined investment limit is ₹2,50,000 crore with effect from April 01, 2022

- Minimum Retention period is three years – any G-Sec/SGS
- Exemptions from macro-prudential limits and facility of Repo (up to 10%)

Fully Accessible Route

Introduced in April 2020

- Invest without any macro-prudential limits in certain specified securities (including new issuances) – 5, 7, 10, 14 and 30 year
- New issuances in 14-yr and 30-yr tenor have been excluded from FAR from July 29, 2024.

सरकारों के नकदी प्रबंधन के रूप में आरबीआई की भूमिका

रिज़र्व बैंक भारत सरकार के नकदी प्रबंधन परिचालनों को संभालता है, यह सुनिश्चित करता है कि समग्र राजकोषीय अनुशासन बनाए रखते हुए सरकार के पास अपने दैनिक व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता है। आरबीआई राज्य सरकारों के नकदी परिचालन का प्रबंधन भी करता है। 01 जुलाई, 2024 तक, नकदी प्रबंधन और प्रणालीगत चलनिधि प्रबंधन उद्देश्यों के लिए, सरकार के नकदी शेष में दैनिक उतार-चढ़ाव की निगरानी की जाती है और ऐसे बदलावों और मौजूदा राजकोषीय परिदृश्यों में ऐतिहासिक रुझानों को ध्यान में रखते हुए अनुमान लगाए जाते हैं। सरकार के राजस्व और व्यय के बीच अस्थायी विसंगतिया को बैंक के अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) और ओवरड्राफ्ट सुविधाओं के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है। अधिशेष नकदी शेष के मामले में, राशि का निवेश केंद्र सरकार के मामले में बैंक की परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) और/या नियत दर रिवर्स रेपो (एफआरआरआर) में और राज्य सरकारों के मामले में 14-दिवसीय मध्यवर्ती ट्रेजरी बिलों (रिवर्स रेपो दर-2% पर गैर-नीलाम रियायती लिखत) में किया जाता है।

अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)

सरकार की प्राप्तियों और भुगतानों में अस्थायी विसंगतियों को दूर करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 17(5) भारतीय रिज़र्व बैंक को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम प्रदान करने की शक्ति प्रदान करती है, जो सम्बद्ध अग्रिमों के स्वरूप की होती है। डब्ल्यूएमए सरकारों (केंद्र/राज्य) द्वारा आवश्यकता पड़ने पर प्रदान किया जाता है।

- **केंद्र सरकार के लिए डब्ल्यूएमए** - डब्ल्यूएमए सीमा आरबीआई द्वारा केंद्र सरकार के परामर्श से प्रत्येक छमाही के लिए अलग से तय की जाती है। यदि सरकार इस सीमा से अधिक उधार लेती है, तो यह ओवरड्राफ्ट (ओडी) के बराबर है। जब सरकार डब्ल्यूएमए सीमा के 75 प्रतिशत का उपयोग करती है तो रिज़र्व बैंक बाजार ऋणों के नए फ्लोटेशन को ट्रिगर कर सकता है। बैंक मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सरकार के परामर्श से किसी भी

समय सीमा को संशोधित करने की सुविधा रखता है। तीन महीने के लिए रेपो दर पर ब्याज लिया जाता है और जब डब्ल्यूएमए सीमा पार हो जाती है, तो केंद्र सरकार एक ओवरड्राफ्ट (ओडी) में प्रवेश करती है जिसे लगातार 10 कार्य दिवसों के भीतर चुकाना होता है। ओडी पर ब्याज दर वर्तमान में रेपो दर प्लस 2% है।

- **राज्य सरकारों के लिये डब्ल्यूएमए** - डब्ल्यूएमए की सीमा अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है और इसे अंतिम बार 28 जून, 2024 को रिज़र्व बैंक द्वारा गठित समूह और चुनिंदा राज्य वित्त सचिवों की सिफारिशों के आधार पर संशोधित किया गया था। डब्ल्यूएमए के अतिरिक्त, राज्य सरकारें विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) के लिए भी पात्र हैं, जो राज्य सरकारों द्वारा धारित सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के प्रति प्रदान की जाती है। एसडीएफ का लाभ समेकित सिंकिंग फंड (सीएसएफ)/गारंटी रिडेम्पशन फंड (जीआरएफ) में निवेश के बदले रेपो दर-2% पर और नीलामी ट्रेजरी बिलों (एटीबी) के प्रति रेपो दर-1% पर लिया जा सकता है। चूंकि एसडीएफ एक संपार्श्विक अग्रिम है, इसलिए एसडीएफ के लिए ब्याज दर डब्ल्यूएमए की तुलना में कम है। राज्य सरकारों को डब्ल्यूएमए का लाभ उठाने से पहले एसडीएफ सीमा को समाप्त करना होगा। डब्ल्यूएमए के मामले में, ब्याज अधिकतम तीन महीने की अवधि के लिए रेपो दर पर होगा, साथ ही तीन महीने से अधिक की अवधि के मामले में एक प्रतिशत जमा होगा। जब राज्य सरकारों को अग्रिम उनकी एसडीएफ और डब्ल्यूएमए सीमाओं से अधिक हो जाते हैं, तो ओवरड्राफ्ट (ओडी) सुविधा शुरू हो जाती है। राज्य सरकारें अधिकतम लगातार 14 कार्य दिवसों और एक तिमाही में 36 दिनों के लिए ओडी में रह सकती हैं।

कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड (सीएसएफ) और गारंटी रिडेम्पशन फंड (जीआरएफ)

राज्य सरकारें अपनी देनदारियों के पुनर्भुगतान के लिए रिज़र्व बैंक के पास समेकित ऋणदायित्व निधि (सीएसएफ) और गारंटी भुगतान निधि (जीआरएफ) को बफर के रूप में रखती हैं। इन रिजर्वों का उद्देश्य भविष्य में चुकौती दायित्वों को पूरा करने में राज्य सरकारों को एक सहारा प्रदान करना है। समेकित सिंकिंग फंड का रखरखाव राज्यों द्वारा बैंकों से ऋण, एनएसएसएफ के कारण देनदारियों आदि सहित सभी ऋणों के परिशोधन के लिए किया जाता है। "गारंटी" आकस्मिक देनदारियां हैं जिन्हें गारंटी द्वारा कवर की गई घटना होने पर लागू करना पड़ सकता है। चूंकि गारंटियों के परिणामस्वरूप आकस्मिक देयता में वृद्धि होती है, इसलिए जब कभी ऐसी गारंटियां लागू की जाती हैं, राज्य सरकारें गारंटियों के भुगतान के लिए गारंटी भुगतान निधि रखती हैं। इन दोनों फंडों का रखरखाव आरबीआई द्वारा किया जाता है। वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ सीएसएफ और जीआरएफ में निवेश स्वैच्छिक है।

इन दो निधियों के अलावा, ओडिशा सरकार से प्राप्त अनुरोध पर एक बजट स्थिरीकरण निधि की स्थापना की गई है जो राज्य बजट पर राजस्व आघात के जोखिम को कम करने में राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करेगी। फंड का उद्देश्य राज्य की अर्थव्यवस्था पर अस्थिर राजस्व के प्रभाव को कम करना है।

आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम

आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम 12 नवंबर, 2021 को खुदरा निवेशकों को प्राथमिक और द्वितीयक सरकारी प्रतिभूति बाजार में सीधे भाग लेने की अनुमति देकर सरकारी प्रतिभूति बाजार में खुदरा निवेशकों की पहुंच को और आसान बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। यह पहल व्यक्तिगत निवेशकों को आरबीआई के साथ अपने रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पर

अपना रिटेल डायरेक्ट गिल्ट (आरडीजी) खाता खोलने और बिचौलियों की भागीदारी को दरकिनार करते हुए आरबीआई के रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने में सक्षम बनाती है। यह पारदर्शिता, खुदरा निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए आसान पहुंच प्रदान करता है, जिसमें सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड (एफआरएसबी) में निवेश शामिल है, और खुदरा निवेशकों को अपने निवेश का प्रबंधन करने के लिए लचीलापन देता है। यह योजना सरकारी प्रतिभूति बाजार के निवेशक आधार को व्यापक बनाने के आरबीआई के व्यापक लक्ष्य का समर्थन करती है। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट को पोर्टल (<https://rbiretaildirect.org.in>) या मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। मोबाइल ऐप को एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं के लिए प्ले स्टोर और आईओएस उपयोगकर्ताओं के लिए ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। खुदरा निवेशकों के लिए द्वितीयक बाजार में तरलता प्रदान करने के लिए, प्राथमिक डीलरों को बाजार के घंटों के दौरान नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम - ऑर्डर मैचिंग (एनडीएस-ओएम) प्लेटफॉर्म (ऑड-लॉट और दर खंड के लिए अनुरोध) पर प्रस्तुत करने और आरडीजी खाताधारकों से खरीद/बिक्री अनुरोधों का जवाब देने की आवश्यकता थी।

अध्याय 17: आरबीआई के तुलन-पत्र को समझना

"आरबीआई का तुलन-पत्र अर्थव्यवस्था में विकास को दर्शाती है और एक तरह से उसे प्रभावित करता है -

विदेशी क्षेत्र, राजकोषीय और निश्चित रूप से, मौद्रिक क्षेत्रों को

प्रभावित करता है - डॉ वाई वी रेड्डी: आरबीआई के पूर्व गवर्नर"

केंद्रीय बैंक के तुलन-पत्र का स्वरूप कई मायनों में अनूठा होता है और वह बैंकों सहित अन्य वाणिज्यिक संगठनों से अलग होता है। यह एक अर्थव्यवस्था में अपनी विविध भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के वित्तीय परिणाम को चित्रित करता है। मौद्रिक प्राधिकरण होने के नाते केंद्रीय बैंक का तुलन-पत्र मौद्रिक देयताओं को संभालने के साथ ही आस्ति सृजन करने की अनन्य विशेषता को दर्शाता है। एक केंद्रीय बैंक आम तौर पर न केवल किसी देश का एकमात्र मुद्रा जारी करने वाला प्राधिकरण होता है, बल्कि अर्थव्यवस्था में मूल्य और विनिमय दर स्थिरता के लिए भी जिम्मेदार होता है और अक्सर इसे सरकार के बैंकर और वित्तीय स्थिरता के हित में बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली के विनियामक के रूप में विशेष जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। एक केंद्रीय बैंक का तुलन-पत्र आम तौर पर तीन पारंपरिक केंद्रीय बैंकिंग कार्यों के इर्दगिर्द केंद्रित होती है (क) मुद्रा निर्गमकर्ता, (ख) सरकार का बैंकर और (ग) बैंकों के बैंकर। केंद्रीय बैंक का एक प्रारूपिक तुलन पत्र नीचे सारणी-1 में दर्शाया गया है।

सारणी-1: केंद्रीय बैंक का एक प्रारूपिक बैलेंस शीट

देयताएं	आस्ति
मुद्रा	सोना
सरकारी बैंक की जमा राशियां	और अग्रिम सरकारी बैंक
ऋण (प्रतिभूतियों सहित)	सरकारी प्रतिभूतियां विदेशी आस्तियों में निवेश
अन्य देयताएं	अन्य आस्तियां
पूंजी खाता चुकता पूंजी रिज़र्व	
कुल देयताएं	कुल आस्तियां

स्रोत: आईएमएफ (2001)

आरबीआई का तुलन-पत्र

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) देश का केंद्रीय बैंक होने के नाते भारत का मौद्रिक प्राधिकरण है और मुद्रा नोटों का निर्गम

करने, मौद्रिक व मूल्य स्थिरता को संवृद्धि के उद्देश्यों के अनुरूप बनाए रखने की दृष्टि से अर्थव्यवस्था में मुद्रा और क्रेडिट की आपूर्ति को विनियमित करने का एकमात्र प्राधिकार प्राप्त है। इसे वित्तीय स्थिरता और वित्तीय समावेशन को हासिल करने पर निगरानी रखने के साथ बैंकिंग क्षेत्र के विनियमन और पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए कार्यकलाप इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हैं जो साप्ताहिक कार्य विवरण (डब्ल्यूएसए), तुलन पत्र और आय विवरण में परिलक्षित होते हैं। ये आरबीआई के सामान्य प्रयोजन की वित्तीय स्थिति की प्रकृति के अनुरूप हैं, जो स्टैकहोल्डरों और पाठकों को आस्ति व देयताओं की प्रकृति के साथ-साथ इसकी आय और व्यय के स्रोतों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। हालांकि, एक वाणिज्यिक संस्था के विपरीत, आरबीआई का परिचालन किसी भी लाभ कमाने के लिए नहीं किया जाता है।

कानूनी प्रावधान

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 53(1) के अनुसार, बैंक से अपेक्षित है कि वह निर्गम विभाग और बैंकिंग विभाग का एक साप्ताहिक लेखा तैयार करके केंद्र सरकार को उस रूप में प्रेषित करे, जैसा कि केंद्र सरकार, भारत के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विहित करती हो। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 53(2) के अनुसार, बैंक से अपेक्षित है कि वह बैंक की वार्षिक लेखाबंदी की तारीख से दो माह के भीतर पूरे वर्ष में बैंक के कार्यसंचालन के संबंध में केंद्रीय बोर्ड की रिपोर्ट सहित वार्षिक लेखों की एक प्रति केंद्र सरकार को प्रेषित करे।

रिज़र्व बैंक के वित्तीय विवरणों की विषय-वस्तु मुख्य रूप से उन गतिविधियों पर आधारित होती है जिन्हें बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के विभिन्न प्रावधानों के तहत निर्वहन कर सकता है। जबकि डब्ल्यूएसए का प्रारूप आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 53 (1) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है; तुलन-पत्र और आय विवरण का प्रारूप भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य विनियमावली, 1949 में निर्धारित किया गया है। डब्ल्यूएसए के नवीनतम प्रारूप को 29 सितंबर, 2020 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया; जबकि तुलन-पत्र और आय विवरण के नवीनतम प्रारूपों को 11 नवंबर, 2020 की राजपत्र अधिसूचनाओं के माध्यम से अधिसूचित किया गया। इनके परिणामस्वरूप 2020 में आरबीआई सामान्य विनियमावली, 1949 के विनियम 22(ए), (बी) और 23(वी) में संशोधन भी हुए। भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य विनियमावली, 1949 के विनियम 22(क) में तुलन-पत्र के स्वरूप और विषय-वस्तु का उल्लेख है, जबकि विनियम 22(ख) में लाभ और हानि लेखे का स्वरूप और विषय-वस्तु निर्धारित की गई है, जिसका नाम तकनीकी समिति-1 (अध्यक्ष: वाई एच मालेगाम) की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2014-15 में 'आय विवरण' के रूप में बदल दिया गया। उक्त समिति का गठन आरबीआई के वार्षिक लेखों के विभिन्न पहलुओं, जिनके अंतर्गत आरबीआई के वित्तीय विवरणों का रूप और प्रस्तुतिकरण भी शामिल हैं, का परीक्षण करने के लिए किया गया। विनियम 23(v) में भारतीय रिज़र्व बैंक के वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति की इकाई निर्धारित की गई है।

तुलन-पत्र और आय विवरण का फॉर्मेट

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 23(1) में कहा गया है कि बैंक नोटों का निर्गम बैंक द्वारा निर्गम विभाग में किया जाएगा जिसे अलग किया जाएगा और बैंकिंग विभाग से पूर्णतः पृथक रखा जाएगा तथा निर्गम विभाग की आस्तियां निर्गम विभाग की देयताओं के अलावा किसी अन्य दायित्व के अध्वधीन नहीं होंगी। इस प्रावधान ने दो अलग-अलग तुलन-

पत्रों और डब्ल्यूएसए को जन्म दिया - एक विशेष रूप से मुद्रा कार्यकलाप (निर्गम विभाग) के लिए और दूसरा आरबीआई (बैंकिंग विभाग) के शेष कार्यों के लिए। निर्गम विभाग के लिए विशिष्ट तुलन-पत्र रखने के पीछे मुख्य रूप से जनता के मन में केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले करेंसी नोटों के प्रति विश्वास पैदा करना था, जिसमें धारक को उसमें उल्लिखित राशि का भुगतान करने का स्पष्ट वचन दिया जाता है। इस प्रकार, बैंक 2013-14 तक दो तुलन-पत्र अर्थात् निर्गम विभाग (नोट निर्गम से संबंधित) और बैंकिंग विभाग (अन्य कार्य) के लिए अलग-अलग तैयार कर रहा था। फिर, तकनीकी समिति-1 की सिफारिशों के आधार पर, डब्ल्यूएसए के रूप और विषय-वस्तु, तुलन पत्र और आय विवरण को वर्ष 2014-15 से संशोधित किया गया। आरबीआई सामान्य विनियमावली, 1949 को केंद्र सरकार के अनुमोदन से संशोधित किया गया और आरबीआई ने एकल तुलन-पत्र तैयार करना शुरू कर दिया है। जबकि डब्ल्यूएसए शुक्रवार को समाप्त होने वाले प्रत्येक सप्ताह के लिए तैयार किया जाता है, तुलन-पत्र और आय विवरण हर साल 31 मार्च के अंत में तैयार किया जाता है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2020-21 से शुरू होकर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपना लेखा वर्ष जुलाई-जून से अप्रैल-मार्च में बदल दिया। आरबीआई के तुलन-पत्र और आय विवरण का वर्तमान संयुक्त फॉर्मेट नीचे सारणी-II और सारणी-III में दिया गया है:

सारणी-II: आरबीआई के तुलन-पत्र का फॉर्मेट

देयताएं	आस्तियां
पूंजी	नोट, रुपये सिक्का, छोटा सिक्का
आरक्षित निधि	गोल्ड - बी.डी.
अन्य रिज़र्व	निवेश-विदेशी- बी.डी.
जमाराशियां	निवेश-घरेलू- बी.डी.
जोखिम प्रावधान	खरीदे गए और भुनाए गए बिल
आकस्मिकता निधि	
आस्ति विकास निधि	
पुनर्मूल्यांकन खाते	ऋण और अग्रिम
अन्य देयताएं	सहायक संस्थाओं में निवेश
	अन्य आस्तियां
निर्गम विभाग की देयताएं	निर्गम विभाग (आईडी) की आस्तियां (निर्गम किए गए नोटों के समर्थन के रूप में)
निर्गम किए गए नोट	सोना - आईडी
	रुपया सिक्का
	निवेश-विदेशी-आईडी

	निवेश-घरेलू-आईडी
	विनिमय बिल और अन्य वाणिज्यिक पत्र
कुल देयताएं	कुल आस्तियां

*बी.डी. - बैंकिंग विभाग; आईडी - निर्गम विभाग

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 33 के अनुसार, निर्गम विभाग की आस्तियां निर्गम विभाग की देयताओं के अधीन होंगी और अधिनियम की धारा 34 में कहा गया है कि निर्गम विभाग की देयताएं उस समय संचलन में रहने वाले भारत सरकार के करेंसी नोटों और बैंक नोटों की कुल राशि के बराबर राशि होगी। इसलिए, निर्गम विभाग की देयताओं और संबंधित मिलान आस्तियों को बैंक के संयुक्त तुलन पत्र में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाता है।

सारणी-III: आय विवरण का फॉर्मेट

आय
ब्याज
अन्य आय
व्यय
नोटों की छपाई
मुद्रा के विप्रेषण पर व्यय
एजेंसी प्रभार
कर्मचारी लागत
ब्याज
डाक और दूरसंचार प्रभार
मुद्रण और लेखन सामग्री
किराया, कर, बीमा, लाइटिंग, आदि।
मरम्मत और रखरखाव
निदेशकों और स्थानीय बोर्ड के सदस्यों के शुल्क और खर्च
लेखापरीक्षकों के शुल्क और खर्च
कानूनी प्रभार
मूल्यहास
विविध व्यय
प्रावधान
उपलब्ध शेष राशि
घटाएं: सांविधिक निधियों में अंशदान
केंद्र सरकार को देय अधिशेष

जहां कहीं आवश्यक हो, तुलन पत्र और आय विवरण में अलग-अलग मदों को तुलन-पत्र और आय विवरण की संगत अनुसूचियों में और स्पष्ट किया जाता है।

तुलन-पत्र के घटक

रिज़र्व बैंक के तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली आस्तियों और देयताओं के प्रमुख शीर्षों को प्रासंगिक सांविधिक प्रावधान (जहां लागू हो) के साथ नीचे सारणी-IV में समझाया गया है:

सारणी – IV: आरबीआई के तुलन-पत्र के घटक

मद	आरबीआई अधिनियम के तहत सांविधिक प्रावधान	टिप्पणियां
पूंजी	धारा 4	रिज़र्व बैंक का गठन 1935 में ₹5 करोड़ की प्रारंभिक चुकता पूंजी के साथ एक निजी शेयरधारकों के बैंक के रूप में किया गया था। 1 जनवरी, 1949 को बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसका संपूर्ण स्वामित्व भारत सरकार में निहित है। चुकता पूंजी ₹ 5 करोड़ बनी हुई है।
आरक्षित निधि	धारा 46	₹ 5 करोड़ की मूल आरक्षित निधि का सृजन रिज़र्व बैंक द्वारा अधिगृहीत तत्कालीन सॉब्रिन सरकार की मुद्रा देयता के लिए अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में केंद्र सरकार के अंशदान के रूप में किया गया। इसके बाद, अक्टूबर 1990 तक सोने के आवधिक पुनर्मूल्यांकन पर लाभ में से इस निधि में 6,495 करोड़ रुपये की राशि जमा की गई, जिससे यह 6,500 करोड़ रुपये हो गया। तब से यह निधि स्थिर रही है क्योंकि स्वर्ण ोर् विदेशी मुद्रा के मूल्यांकन के कारण प्राप्त लाभ/हानि को मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यांकन खाते (सीजीआरए) में दर्ज किया जा रहा है जो 'पुनर्मूल्यांकन लेखा' शीर्ष के अंतर्गत आता है।
अन्य रिज़र्व		
राष्ट्रीय औद्योगिक क्रेडिट (दीर्घकालिक परिचालन) निधि	धारा 46ग	वित्तीय संस्थाओं को सहायता प्रदान करने के लिए ₹ 10 करोड़ के प्रारंभिक कोष के साथ 1964 में बनाया गया। वर्ष 1992-93 से इस निधि में प्रत्येक वर्ष

		1 करोड़ रुपए की सांकेतिक राशि का अंशदान किया जा रहा है।
राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घकालिक परिचालन) निधि	धारा 46घ	राष्ट्रीय आवास बैंक को वित्तीय आवास प्रदान करने के लिए ₹ 50 करोड़ के प्रारंभिक कोष के साथ 1989 में बनाया गया। वर्ष 1992-93 से इस निधि में प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ रुपए की सांकेतिक राशि का अंशदान किया जा रहा है।
जमाराशियां		
केंद्र सरकार	धारा 20 और धारा 21	आरबीआई के लिए केंद्र सरकार का बैंकर होना अनिवार्य है। इसमें दैनिक आधार पर 10 करोड़ रुपये और शुक्रवार को 100 करोड़ रुपये की न्यूनतम राशि जमा की जा सकती है। 31 मार्च के लिए, आरबीआई और केंद्र सरकार के बीच सहमत न्यूनतम शेष राशि ₹5,000 करोड़ रुपये है।
राज्य सरकारें	धारा 21ए	भारतीय रिज़र्व बैंक आपसी समझौतों के माध्यम से राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में कार्य करता है। दैनिक आधार पर न्यूनतम शेष राशि बनाए रखना आवश्यक है।
बैंक	धारा 42	आरक्षी नकदी निधि अनुपात बनाए रखने और भुगतान एवं निपटान दायित्वों को पूरा करने के लिए कार्यशील निधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
भारत के बाहर वित्तीय संस्थाएं	धारा 17(12एबी)	भारत के बाहर वित्तीय संस्थाओं के साथ रेपो उधार और ऋण 2016-17 में शुरू किया गया था। रेपो उधार और रिवर्स रेपो पर मार्जिन इस शीर्ष के अंतर्गत परिलक्षित होते हैं।
अन्य		इसमें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, विदेशी केंद्रीय बैंकों, म्यूचुअल फंडों और बैंकों की जमाराशियां शामिल हैं, जिन्हें 'रिवर्स रेपो', 'स्थायी जमा सुविधा', 'जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता

		फंड' आदि के तहत आरबीआई के पास रखा गया है।
जोखिम प्रावधान		
आकस्मिकता निधि (सीएफ)		अप्रत्याशित और अनपेक्षित आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए 1997-98 में बनाया गया, जिसमें प्रतिभूतियों के मूल्य में मूल्यहास, मौद्रिक/ विनिमय दर के नीतिगत परिचालनों से उत्पन्न जोखिम, प्रणालीगत जोखिम और केंद्रीय बैंक पर विशेष जिम्मेदारियों के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी जोखिम शामिल हैं।
एसेट डेवलपमेंट फंड (एडीएफ)		आंतरिक पूंजीगत व्यय को पूरा करने और सहायक संस्थाओं और संबद्ध संस्थाओं में निवेश करने के लिए 1997-98 में बनाया गया।
पुनर्मूल्यांकन खाते		
मुद्रा और स्वर्ण पुनर्मूल्यांकन खाता		विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए) ² और सोने के मूल्यांकन पर अप्राप्त लाभ/हानि इस खाते में दर्ज की जाती है।
निवेश पुनर्मूल्यांकन खाता (आईआरए)		रुपया प्रतिभूति और तेल बांड और विदेशी दिनांकित प्रतिभूतियों के मार्क-टू-मार्केट मूल्यांकन पर अप्राप्त लाभ/हानि क्रमशः आईआरए-आरएस और आईआरए-एफएस में दर्ज की जाती है
विदेशी मुद्रा वायदा संविदा मूल्यांकन खाता (एएफसीवीए)		बकाया वायदा संविदाओं के मार्क-टू-मार्केट मूल्यांकन पर अप्राप्त लाभ/हानि इस खाते में दर्ज की जाती है
अन्य देयताएं		
वायदा संविदा मूल्यांकन खाते		एफसीवीए पर अप्राप्त हानियों की प्रति प्रविष्टि

(पीएफसीवीए) के लिए प्रावधान		
देय राशियों के लिए प्रावधान		यह किए गए ऐसे व्यय के संबंध में वर्षांत में किए गए प्रावधानों को दर्शाता है, जो चुकाया नहीं गया है और अग्रिम तौर पर प्राप्त आय/ देय राशि, यदि कोई हो।
केंद्र सरकार को अंतरण की जाने वाली अधिशेष राशि	धारा 47	अशोध और संदिग्ध ऋणों, आस्तियों में मूल्यहास, स्टाफ और सेवानिवृत्ति निधियों में अंशदान की बाबत किए गए सभी प्रावधानों के बाद और उन सभी मामलों के लिए जिनके लिए अधिनियम द्वारा या इसके तहत प्रावधान किए जाने हैं या जिसका प्रावधान आम तौर पर बैंकों द्वारा किया जाता है, जिनके बाद केंद्र सरकार को अंतरण किए जाने वाले अधिशेष की राशि को यह दर्शाती है।
देय बिल		इस शीर्ष के अंतर्गत शेष राशि बैंक द्वारा जारी मांग ड्राफ्ट/ भुगतान आदेशों से संबंधित बकाया/ अदावाकृत राशियों को दर्शाती है।
फुटकर		यह एक अवशिष्ट राशि संबंधी शीर्ष है जो निर्धारित प्रतिभूतियों पर अर्जित ब्याज, छुट्टी के नकदीकरण पर देय राशि, कर्मचारियों के लिए चिकित्सा प्रावधान, ग्लोबल प्रावधान, विमुद्रीकरण के कारण विनिर्दिष्ट बैंक नोटों के लिए देय राशि आदि जैसी मदों को दर्शाया जाता है।
निर्गम विभाग की देयता		
जारी किए गए नोट	धारा 34	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिगृहित भारत सरकार के करेंसी नोटों की कुल राशि और 1 अप्रैल, 1935 से आरबीआई द्वारा जारी किए गए नोट। इस राशि में विभिन्न विभागों की दैनंदिन आवश्यकताओं के लिए बैंकिंग विभाग को निर्गम किए गए और उसके पास रखे गए नोटों का मूल्य भी शामिल है।
बैंकिंग विभाग की आस्तियां		

नोट, रुपये सिक्का और छोटा सिक्का		बैंकिंग विभाग में रखे गए नोटों और सिक्कों का मूल्य जो दैनिक आवश्यकताओं के लिए रखा जाता है। यहां नोटों पर शेष राशि भी निर्गम विभाग की देयताओं का हिस्सा है।
सोना – बी.डी.		इसमें विदेशों में रखे गए भौतिक सोने और सोने की जमाराशियों में बैंक के निवेशों को दर्शाया जाता है। यह भौतिक सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस), स्विट्जरलैंड की सुरक्षित अभिरक्षा में विदेशों में रखा गया है और भारत में रखा गया है। यह देश के विदेशी मुद्रा भंडार का भी हिस्सा होता है।
निवेश-विदेशी- बी.डी.		इसमें विदेशी प्रतिभूतियों में बैंक का निवेश, विदेशी केंद्रीय बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों, बीआईएस, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) और सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन (स्विफ्ट) में रखे गए शेयर शामिल हैं। इसमें भारत सरकार से प्राप्त विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर-आईएमएफ खाते की एक इकाई) भी शामिल है जो देश के विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा है।
निवेश-घरेलू- बी.डी.		भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिलों और विशेष तेल बांडों, जिन्हें मुख्य रूप से मौद्रिक नीति परिचालनों के दौरान अधिगृहीत किया जाता है, में बैंक का निवेश।
खरीदे गए और भुनाए गए बिल		बैंक विनिमय बिलों और वचन पत्रों की खरीद, बिक्री और पुनर्भुनाई कर सकता है। हालांकि, यह गतिविधि नहीं की जा रही है।
ऋण और अग्रिम		

केंद्र सरकार को	धारा 17(5)	अपनी प्राप्तिओं और भुगतानों में अस्थायी अंतर से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) और ओवरड्राफ्ट (ओडी) के रूप में दिया जाता है। भारत सरकार के परामर्श से समय-समय पर डब्ल्यूएमए सीमा निर्धारित की जाती है। डब्ल्यूएमए प्रणाली के अंतर्गत अग्रिम पारस्परिक रूप से सहमत ब्याज दर पर दिए जाते हैं और सरकार द्वारा तीन माह के भीतर पूर्ण रूप से चुकौती की जानी होती है। डब्ल्यूएमए के अलावा, भारत सरकार को ओवरड्राफ्ट (ओडी) सुविधा भी दी जाती है।
राज्य सरकारों को	धारा 17(5)	अपनी प्राप्तिओं और भुगतानों के नकदी प्रवाह में असंतुलन से निपटने के लिए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ), डब्ल्यूएमए और ओडी के रूप में दिया जाता है। अलग-अलग राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए डब्ल्यूएमए सीमा इस उद्देश्य के लिए गठित परामर्शदात्री समिति/ समूह की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित की जाती है। जबकि डब्ल्यूएमए और ओडी सुविधाएं केंद्र सरकार के समान हैं, एसडीएफ एक ऐसी सुविधा है जिसका लाभ वे सरकारी प्रतिभूतियों की संपार्श्विक आस्तियों पर उठा सकती हैं।
वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों को	धारा 17 (12) (एबी) / 17 (3ए) / (3बी) / (4)	मुख्य रूप से एलएएफ रेपो और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के माध्यम से दिया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक ऐसे बैंक के वचनपत्र के एवज में ऋण और अग्रिम प्रदान कर सकता है, जो मांग पर या आरबीआई अधिनियम में निर्धारित निश्चित अवधि की समाप्ति पर देय है।
नाबार्ड को	धारा 17 (4ई)	मांग पर देय प्रतिभूतियों/ स्टॉक पर अल्पावधि ऋण के रूप में या अधिकतम 18 माह की नियत अवधि के लिए दिया जाता है।

अन्यों को	धारा 17 (4)	इसमें एनएचबी, सिडबी, डीआईसीजीसी को दिए गए सभी ऋण और अग्रिम, प्राथमिक डीलरों (पीडी) को प्रदान की गई चलनिधि सहायता और पीडी के लिए संचालित बकाया रेपो/मीयादी रेपो शामिल हैं।
भारत के बाहर स्थित वित्तीय संस्थाओं को	धारा 17(12एबी)	भारत के बाहर स्थित वित्तीय संस्थाओं के लिए रिवर्स रेपो उधार देना और रेपो मार्जिन 2016-17 में शुरू किया गया था।
सहायक कंपनियों में निवेश	धारा 17(8एए)	इसमें आरबीआई की सहायक कंपनियों में निवेश शामिल है। डीआईसीजीसी, बीआरबीएनएमपीएल, रेबिट, आईएफटीएस और आरबीआईएच पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं, वहीं राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) एक सहयोगी संस्था है।
अन्य आस्तियां		इसमें अचल आस्तियां (मूल्यहास को घटाने के बाद), कर्मचारियों को दिए गए ऋणों और अग्रिमों पर उपार्जित आय, वायदा संविदा खाते के पुनर्मूल्यांकन में धारित शेष, कर्मचारी ऋण, प्रतिभूति जमाराशियां, लंबित परियोजनाओं पर व्यय की गई राशि और अन्य विविध मदें शामिल हैं।
निर्गम विभाग की आस्तियां (जारी किए गए नोटों के समर्थन के रूप में)		
सोना - आईडी	धारा 33	यह जारी किए गए नोटों के समर्थन के रूप में भारत में रखे गए भौतिक सोने में बैंक के निवेश को दर्शाता है।
रुपये सिक्के	धारा 33	एक छोटा हिस्सा धारित किया जाता है जिसे भारत सरकार से खरीदा गया था।
निवेश-विदेशी-आईडी	धारा 33	इसमें विदेशी प्रतिभूतियों में बैंक का निवेश, विदेशी केंद्रीय बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों, बीआईएस, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) और बीआईएस और स्विफ्ट में रखे गए शेयर में बैंक द्वारा किए गए निवेश शामिल हैं। इसमें भारत सरकार से प्राप्त विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर - आईएमएफ

		खाते की एक इकाई) भी शामिल है जो देश के विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा है।
निवेश-घरेलू-आईडी	धारा 33	भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिलों और विशेष तेल बांडों, जिन्हें मुख्य रूप से मौद्रिक नीति परिचालनों के दौरान अधिगृहीत किया जाता है, में बैंक द्वारा किया गया निवेश शामिल है।
घरेलू विनिमय बिल और अन्य वाणिज्यिक पत्र	धारा 33	हालांकि बैंक घरेलू विनिमय बिल और वाणिज्यिक पत्र खरीद सकता है, लेकिन यह गतिविधि लंबे समय से नहीं की गई है।

नोट:

1. अन्य आरक्षित निधियों के अंतर्गत सूचीबद्ध दो निधियों के अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक प्रत्येक वर्ष दो अन्य निधियों अर्थात् राष्ट्रीय ग्रामीण क्रेडिट (दीर्घावधिक परिचालन) निधि और राष्ट्रीय ग्रामीण क्रेडिट (स्थिरीकरण) निधि में प्रत्येक को 1 करोड़ रुपये का अंशदान भी करता है जिसका गठन आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 46क के तहत किया गया था। इन दोनों निधियों की स्थापना 1956 में कृषि ऋण के क्षेत्र में शीर्ष संस्थाओं की वित्त पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई थी और नाबार्ड द्वारा इसका रखरखाव किया जाता है। अतः ये फंड आरबीआई के तुलन-पत्र में परिलक्षित नहीं होते हैं।
2. हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार (एफईआर) आईएमएफ के पास विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसीए), स्वर्ण, एसडीआर और आरक्षित ट्रांच स्थिति (आरटीपी) का कुल योग है। इनमें से, भारत सरकार से अधिगृहीत एफसीए, स्वर्ण और एसडीआर का लेखा-जोखा भारतीय रिज़र्व बैंक के तुलन पत्र में किया जाता है, जबकि भारत सरकार के पास शेष एसडीआर होल्डिंग्स और आरटीपी, जो विदेशी मुद्रा में आईएमएफ में भारत के कोटा अंशदान का प्रतिनिधित्व करते हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक के तुलन पत्र का हिस्सा नहीं हैं।
3. राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)
4. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)
5. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)
6. भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल)
7. रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (रेबिट)
8. भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाएं (आईएफटीएस)
9. रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच)

आय विवरण के घटक

किसी इकाई का लाभ और हानि लेखा या आय विवरण लेखांकन/ वित्तीय वर्ष के दौरान इकाई द्वारा किए गए कार्यों का शुद्ध परिणाम है। केंद्रीय बैंक विशिष्ट होते हैं, और लाभ कमाना उनका उद्देश्य नहीं है। उस संबंध में वे वाणिज्यिक संस्थाओं के साथ तुलनीय नहीं हैं। तथापि, केंद्रीय बैंक का लाभ/ लाभांश सरकार के लिए राजकोषीय राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। चूंकि लाभ अर्जित करना केंद्रीय बैंकों का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है, इसलिए 'लाभ और हानि लेखा' नामकरण एक मिथ्या नाम है और इसलिए वर्ष 2014-15 से 'लाभ और हानि लेखा' का नामकरण बदलकर 'आय विवरण' कर दिया गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक की आय और व्यय की प्रमुख मदों को नीचे सारणी-V में स्पष्ट किया गया है।

सारणी- V: आय विवरण के घटक

शीर्ष	विषय-वस्तु
आय के शीर्ष	
ब्याज	विदेशी स्रोतों से प्राप्त ब्याज में विदेशी प्रतिभूतियों के धारित होने पर अर्जित ब्याज, विदेशी रिपो/ रिवर्स रेपो लेन-देन पर निवल ब्याज और विदेशों में रखी जमाराशियों पर ब्याज शामिल है। घरेलू स्रोतों से प्राप्त ब्याज में रुपया प्रतिभूतियों से अर्जित ब्याज के बाद एलएएफ (रेपो और रिवर्स रेपो) परिचालनों पर निवल ब्याज, एसडीएफ पर ब्याज, एमएसएफ परिचालनों पर ब्याज और ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज शामिल है।
अन्य आय	विदेशी स्रोतों से प्राप्त आय में विदेशी प्रतिभूतियों के प्रीमियम/ डिस्काउंट के परिशोधन से उत्पन्न आय, विदेशी प्रतिभूतियों की बिक्री और उन्मोचन पर लाभ/हानि, विदेशी मुद्रा लेनदेन से विनिमय लाभ/हानि और विविध आय शामिल हैं। घरेलू स्रोतों से प्राप्त आय में शामिल हैं (i) डिस्काउंट, (ii) विनिमय, (iii) कमीशन, (iv) रुपये प्रतिभूतियों के प्रीमियम / डिस्काउंट का परिशोधन (v) रुपया प्रतिभूतियों की बिक्री और उन्मोचन पर लाभ/हानि (vi) वसूल किया गया किराया (vii) बैंक की संपत्ति की बिक्री पर लाभ या हानि, और (viii) ऐसे प्रावधान जिनकी अब आवश्यकता नहीं है और विविध आय। उपर्युक्त में से, कमीशन आय में मुख्य रूप से ऋण जारी किए जाने और सार्वजनिक ऋण के प्रबंधन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से प्राप्त कमीशन शामिल है।
व्यय के शीर्ष	

नोटों की छपाई	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नए नोटों की छपाई पर किया गया व्यय ।
खजाने के प्रेषण पर खर्च	मुद्रणालयों/टकसालों से प्राप्त मुद्रित नोटों और सिक्कों को मुद्रा तिजोरियों (सीसी)/छोटे सिक्का डिपो तक पहुंचाने के लिए किया गया व्यय; सीसी से भारतीय रिज़र्व बैंक को गंदे नोटों के विप्रेषण पर व्यय; विपथन आदि पर व्यय।
एजेंसी प्रभार	इसमें केन्द्र/राज्य सरकारों की प्राप्तियों और भुगतानों के लिए एजेंसी बैंकों को कमीशन का भुगतान; केंद्र और राज्य सरकारों के लोक ऋण जारी करते समय प्राथमिक डीलरों को अंडरराइटिंग कमीशन का भुगतान; राहत/बचत बांडों के लिए बैंकों को भुगतान किए गए हैंडलिंग प्रभार और अभिरक्षकों को भुगतान किए गए शुल्क आदि शामिल हैं।
ब्याज	डॉ. बी. आर. अंबेडकर निधि और कर्मचारी हितकारी निधि की शेष राशि पर ब्याज का भुगतान। भारतीय रिज़र्व बैंक के कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति देने के लिए डॉ. बी आर अंबेडकर निधि की स्थापना की गई है, वहीं हितकारी निधि की स्थापना कर्मचारियों के अंशदान से की जाती है ताकि सेवाकाल में जिन कर्मचारियों की मृत्यु होती है, उनके परिवारों की सहायता की जा सके।
कर्मचारी लागत	इसमें सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वेतन, भत्ते, छुट्टी और सेवानिवृत्ति किराया रियायत, चिकित्सा व्यय आदि का भुगतान और बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेच्युटी और सेवानिवृत्ति निधि और अन्य निधियों की उपार्जित देनदारियों के लिए किया जाने वाला अंशदान शामिल है।
डाक-शुल्क और दूरसंचार प्रभार	डाक/कूरियर शुल्क, दूरसंचार शुल्क, स्विफ्ट/स्मार्टकार्ड शुल्क, आरबीआई की वेबसाइटों का रखरखाव, रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग आदि जैसी ऑनलाइन डेटा सेवाओं के अंशदान की राशि इस शीर्ष के तहत बुक की जाती है।
छपाई और लेखन सामग्री	इसमें लेखन सामग्री की खरीद, रजिस्ट्रों की छपाई, कंप्यूटर कन्स्यूमबल, भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रकाशनों की छपाई आदि पर किया गया व्यय शामिल है।
किराया, कर, बीमा, लाइटिंग व्यवस्था, आदि।	इसमें कार्यालय और रिहायशी भवनों के लिए भुगतान किया गया किराया, लाइसेंस शुल्क और नगरपालिका कर तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के परिसरों और चल आस्तियों के संबंध में ली गई बीमा पालिसियो, बिजली के प्रभार आदि शामिल हैं।
मरम्मत और रखरखाव	इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक के स्वामित्व वाली संपत्ति की मरम्मत और रख-रखाव पर किया गया व्यय शामिल है।

निदेशकों और स्थानीय बोर्ड के सदस्यों के शुल्क और खर्च	केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों और स्थानीय बोर्ड के सदस्यों को अदा किया जाने वाला शुल्क और बोर्ड की बैठकें आयोजित करने के लिए किए गए व्यय को इस शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किया जाता है।
लेखापरीक्षकों के शुल्क और खर्च	भारतीय रिज़र्व बैंक के लेखों की सांविधिक लेखापरीक्षा, इसके सभी कार्यालयों/शाखाओं की समवर्ती लेखापरीक्षा और किसी भी लेखापरीक्षा के संबंध में किए गए लेखापरीक्षा शुल्क और व्यय
कानूनी प्रभार	वकीलों को भुगतान किए गए शुल्क और बैंक की ओर से कानूनी कार्यवाही शुरू करने और प्रतिवाद करने के लिए किए गए खर्च को इस शीर्ष के तहत दर्ज किया जाता है।
मूल्याहान	निर्धारित दरों पर विभिन्न अचल संपत्तियों पर मूल्याहान इस शीर्ष के तहत दर्ज किया जाता है।
फुटकर खर्च	उपर्युक्त व्यय शीर्षों के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए अन्य सभी विविध व्यय यहां दर्शाए जाते हैं।
प्रावधान	आकस्मिकता निधि और आस्ति विकास निधि में अंशदान के लिए किया गया प्रावधान इस शीर्ष में दर्शाया जाता है।

भारत सरकार को अंतरित की जाने वाली अधिशेष राशि

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 47 के अनुसार, व्यय को समायोजित करने, आय के संबंध में आवश्यक प्रावधान करने और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रखी जा रही दो सांविधिक निधियों और नाबार्ड द्वारा रखी जा रही दो निधियों के अंशदान के लिए विनियोजन करने के पश्चात् भारत सरकार को अंतरित की जाने वाली अधिशेष की राशि की गणना की जाती है। यह अधिशेष बैंक के केंद्रीय बोर्ड द्वारा प्रत्येक वर्ष मई में आयोजित अपनी बैठक में बैंक के लेखों को अनुमोदित किए जाने के बाद भारत सरकार को अंतरित किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 48 के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक को आयकर या अतिकर या आय पर किसी भी कर से पूरी तरह छूट प्राप्त है।

लेखांकन सिद्धांत और नीतियां

यद्यपि दोहरी प्रविष्टि बहीखाता पद्धति, जिसमें वास्तविक और वित्तीय आस्तियों को अलग दर्शाया जाता है, जैसे बुनियादी लेखांकन सिद्धांतों का पालन, केंद्रीय बैंकों सहित सभी संस्थाओं द्वारा सार्वभौमिक रूप से किया जाता है, तथापि, केंद्रीय बैंक विशिष्ट संस्था होते हैं। ऐसे कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत लेखा मानक नहीं हैं जिनका सभी केंद्रीय बैंक पालन करते हैं। बैंक के लेखों का आधार बनने वाले लेखांकन सिद्धांतों व नीतियों का प्रकटीकरण 'महत्वपूर्ण लेखा नीतियों' के

तहत प्रत्येक वर्ष बैंक के वार्षिक लेखों के भाग के रूप में किया जाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक की लेखा बहियों की लेखापरीक्षा

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 50 के अनुसार, कम से कम दो लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और उनका पारिश्रमिक केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। वर्तमान में बैंक की बहियों की लेखापरीक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा पांच लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की जा रही है- दो सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक और तीन सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 51 के अनुसार, केंद्र सरकार बैंक के लेखों की जांच करने और भारत सरकार को रिपोर्ट देने के लिए किसी भी समय भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की नियुक्ति कर सकती है।

निष्कर्ष

(i) ओएमओ, एलएएफ, एमएसएस, आदि के माध्यम से मौद्रिक नीति परिचालन (ii) मुद्रा प्रबंधन (iii) बैंक और सरकारों के बैंकर के रूप में इसकी भूमिका और (iv) विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन जैसे आरबीआई के प्रमुख कार्यकलाप आरबीआई के तुलन-पत्र को काफी हद तक प्रभावित करते हैं। केंद्रीय बैंकों को बदलते आर्थिक परिदृश्यों के साथ तालमेल रखना होगा और बदलती परिस्थितियों का सामना उपर्युक्त प्रमुख कार्यकलापों में वर्णित साधनों का प्रयोग करते हुए करना पड़ता है। इस प्रकार प्रयुक्त उपकरण अंततः सेंट्रल बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हैं और कालांतर में उसकी वित्तीय स्थिति में होने वाले परिवर्तन केंद्रीय बैंक की बढ़ती भूमिका को दर्शाते हैं।

अध्याय 18: विदेशी मुद्रा प्रबंधन

विदेशी मुद्रा नियंत्रण से विदेशी मुद्रा प्रबंधन की ओर

- ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण उद्देश्यों के लिए विदेशी मुद्रा को नियंत्रित करने के उद्देश्य से अपने युद्ध के प्रयासों के तौर पर 3 सितंबर, 1939 को डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत भारत में विदेशी मुद्रा नियंत्रण लागू किया। इसके बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा), 1947 पेश किया गया था, ताकि सभी बाह्य भुगतानों के लिए दुर्लभ विदेशी मुद्रा को नियंत्रित किया जा सके। यह मुख्य रूप से भारत में विदेशी पूंजी के प्रवाह के विनियमन और आयातित पूंजी के निर्दिष्ट उपयोग से जुड़ा रहा।
- भारत को 1960 के दशक में एक बड़ा विदेशी मुद्रा संकट का सामना करना पड़ा और उस समय विदेशी मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग खाद्यान्न के आयात के लिए हुआ करता था। इस पृष्ठभूमि में, फेरा, 1947 को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य (अधिनियम की प्रस्तावना में यथानिहित) था ".... देश की प्रारक्षित निधि को बनाएं रखना और सामान्य रूप से देश के हित में उसका उचित उपयोग", और बशर्ते कि अधिनियम के प्रावधान के उल्लंघन को एक आपराधिक अपराध माना जाएगा जो कारावास के साथ-साथ दंडनीय हो सकता है। इस अधिनियम ने रिज़र्व बैंक और कुछ मामलों में केंद्र सरकार को अन्य लेन-देनों के साथ-साथ भारत के बाहर विदेशी मुद्रा भुगतान, करेंसी नोटों और बुलियन के निर्यात और आयात, निवासियों और अनिवासियों के बीच प्रतिभूतियों के अंतरण, विदेशी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण और भारत में और उसके बाहर अचल संपत्ति के अधिग्रहण में लेन-देन को नियंत्रित और विनियमित करने की शक्ति प्रदान की। यह नियंत्रण प्रधान ढांचा अनिवार्य रूप से लेन-देन आधारित था जिसके संदर्भ में निवासियों और अनिवासियों के बीच विदेशी मुद्रा में सभी लेन-देन निषिद्ध थे, जब तक कि इसके लिए विशेष रूप से अनुमति न दी गई हो।
- हालांकि, 1970 के दशक के अंत तक हरित क्रांति ने आयातित खाद्यान्न पर हमारी निर्भरता का समाधान कर दिया था और प्रवासी भारतीयों से उत्साहजनक विप्रेषण ने विदेशी मुद्रा की कमी के कारण होने वाली तात्कालिकता की स्थिति का शमन कर दिया था। विनियम नियंत्रण व्यवस्था का उदारीकरण 1980 के मध्य में शुरू किया गया था और 1990 के दशक में इसने गति पकड़ी थी। 1991 के भुगतान संतुलन संकट के बाद, कई उदारीकरण उपाय शुरू किए गए थे और विदेशी मुद्रा को नियंत्रित करने वाले नियमों में व्यापक छूट दिया जाना प्रारंभ कर दिया गया था। इस सुधार प्रक्रिया में लचीली विनियम दर की शुरुआत भी शामिल थी, जो जुलाई 1991 में विनियम दर समायोजन के साथ शुरू हुई, मार्च 1992 में उदारीकृत विनियम दर प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत के साथ जारी रही और मार्च 1993 तक पूरी तरह से बाजार निर्धारित विनियम दर प्रणाली का कार्यान्वयन किया गया। 1 जून 2000 से फेरा, 1973 को प्रतिस्थापित करने के लिए 1999 में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) लागू किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विदेशी मुद्रा कानून या विनियम उभरती आर्थिक स्थिति के अनुकूल कार्यशील हैं। इस अधिनियमन ने विदेशी मुद्रा लेन-देन के नियंत्रण/प्रतिबंध की बजाय उसके संबंध में सुविधा दिए जाने की ओर बदलाव का संकेत दिया।

- बदलते समय को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने (31 जनवरी 2004 से) विदेशी मुद्रा लेन-देन से संबंधित अपने विभाग के नाम में संशोधन करते हुए इसे विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग (ईसीडी) से बदलकर विदेशी मुद्रा विभाग (एफईडी) किया।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999

उद्देश्य

जैसा कि अधिनियम की प्रस्तावना में निहित है, फेमा, 1999 का उद्देश्य विदेशी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और उसके रखरखाव को प्रोत्साहित करना है।

प्रयोज्यता

फेमा, 1999 पूरे भारत में लागू है। यह भारत के बाहर स्थित सभी शाखाओं, कार्यालयों और एजेंसियों पर भी लागू होता है, जिनका स्वामित्व और नियंत्रण भारत में निवासी व्यक्ति के पास है और जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किए गए किसी भी उल्लंघन पर प्रयोज्य है।

लेन-देन के प्रकार

फेमा, 1999 सभी विदेशी मुद्रा लेन-देन को दो व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत करता है अर्थात् चालू खाता और पूंजी खाता लेन-देन। जैसा कि फेमा के तहत परिभाषित किया गया है, "पूंजी खाता लेन-देन" वह लेन-देन है जो :

- भारत में निवासी किसी व्यक्ति की भारत के बाहर संपत्ति और देनदारियों में परिवर्तन लाता है या
- भारत के बाहर निवासी व्यक्ति की भारत में संपत्ति और देयताओं में बदलाव लाता है।
- इन देयताओं में आकस्मिक देयताएं भी शामिल हैं।
- उदाहरण - प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, बाह्य वाणिज्यिक उधार, अनिवासी जमा, अचल संपत्ति में निवेश, गारंटी आदि।

"चालू खाता लेन-देन" किसी पूंजी खाता लेन-देन से अलग प्रकार का लेन-देन है जो ज्यादातर राजस्व प्रकृति का होता है। उदाहरण के लिए - निर्यात, आयात, व्यक्तिगत विप्रेषण, उपहार, आय आदि।

व्यक्तियों के प्रकार

फेमा, 1999 की प्रयोज्यता सामान्यतः किसी व्यक्ति की आवासीय स्थिति और किए गए लेन-देन की प्रकृति पर निर्भर करती है। कोई 'व्यक्ति' एक व्यक्ति, एक एचयूएफ, एक कंपनी, एक फर्म, व्यक्तियों का एक संघ आदि हो सकता है। फेमा, 1999 के अंतर्गत कोई 'व्यक्ति' या तो 'भारत में निवासी व्यक्ति' होता है अथवा 'भारत से बाहर अनिवासी व्यक्ति' होता है। किसी व्यक्ति की आवासीय स्थिति न केवल भारत में रहने की अवधि पर आधारित होती है, बल्कि लंबी/अनिश्चित अवधि के लिए रहने के इरादे पर भी आधारित होती है। हालांकि, आवासीय स्थिति किसी व्यक्ति की नागरिकता से स्वतंत्र है।

भारत में निवासी व्यक्ति (निवासी): फेमा, 1999 के अनुसार निवासी की परिभाषा में मोटे तौर पर पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 182 दिनों से अधिक समय तक भारत में रहने वाला व्यक्ति; भारत में पंजीकृत/निगमित कोई व्यक्ति या निकाय; भारत में भारत से बाहर निवासी व्यक्ति के स्वामित्व या नियंत्रण में कोई कार्यालय, शाखा या एजेंसी; कोई कार्यालय, भारत से बाहर की

शाखा या एजेंसी जिसका स्वामित्व या नियंत्रण भारत में निवासी किसी व्यक्ति के पास हो ।

भारत से बाहर निवास करने वाला व्यक्ति (अनिवासी): एक व्यक्ति जो निवासी की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है उसे अनिवासी माना जाता है। और इसमें वे व्यक्ति शामिल हैं जो या तो रोजगार लेने या व्यवसाय करने या छुट्टी मनाने या किसी अन्य उद्देश्य के लिए भारत से बाहर रहते हैं जो अनिश्चित अवधि के लिए भारत से बाहर रहने के उनके इरादे को इंगित करता है। अनिवासी की परिभाषा में अनिवासी भारतीय (एनआरआई) और भारत के पारदेशीय नागरिक (ओसीआई) शामिल हैं।

प्राधिकृत व्यक्ति (एपी)

फेमा, 1999 में यह निर्धारित किया गया है कि सभी विदेशी मुद्रा लेन-देन को केवल उसी व्यक्ति के माध्यम से निष्पादित किया जाना अपेक्षित है जो ऐसे लेन-देन को करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत है। फेमा, 1999 की धारा 10(1) के अनुसार, रिज़र्व बैंक प्राधिकृत व्यक्तियों के रूप में नामित संस्थाओं को विदेशी मुद्रा में लेन-देन करने के लिए प्राधिकृत करता है जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* प्राधिकृत डीलर अथवा मनी चेंजर शामिल होता है। फेमा, 1999 के तहत निर्धारित विनियामक ढांचा " प्राधिकृत व्यक्तियों" पर एक बड़ी जिम्मेदारी डालता है जो किसी विदेशी मुद्रा लेन-देन के लिए प्रत्येक भागीदार के तत्काल और आवश्यक काउंटरपार्टी हैं।

रिज़र्व बैंक, वर्तमान में, फेमा 1999 की धारा 10(1) के अंतर्गत निम्नलिखित के लिए प्राधिकार जारी करता है:

- चुनिंदा बैंक (प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी- I के रूप में)
- चुनिंदा संस्थाएं (प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी- II के रूप में)
- वित्तीय और अन्य संस्थानों का चयन करें (प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी- III के रूप में)
- चुनिंदा पंजीकृत कंपनियां संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक (एफएफएमसी) के रूप में

वर्गीकरण से संबंधित तालिका

क्र.सं.	लाइसेंस श्रेणी	पात्र निकाय	अनुमेय कार्यकलाप
1	प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी-I	वाणिज्यिक बैंक, राज्य सहकारी बैंक, शहरी सहकारी बैंक	सभी चालू खाता लेन-देन (जब तक कि वह आरबीआई के परामर्श से सरकार द्वारा प्रतिबंधित न हो) और अनुमत पूंजी खाता लेन-देन
2	प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी- II	मौजूदा एफएफएमसी, शहरी सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक,	निर्दिष्ट गैर-व्यापार संबंधी चालू खाता लेन-देन और संपूर्ण मुद्रा

		भुगतान बैंक, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण - जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – निवेश और ऋण कंपनियां (एनडीएसआई- एनबीएफसी- आईसीसी)	परिवर्तकों (एफएफएमसी) को अनुमत सभी कार्यकलाप रिज़र्व बैंक द्वारा तय किया गया कोई अन्य कार्यकलाप
3	प्राधिकृत व्यापारी (एडी) श्रेणी- III	चुनिंदा वित्तीय और अन्य संस्थान	विशिष्ट विदेशी मुद्रा लेन-देन करना जो उनके व्यवसाय/कार्यकलापों से संबंधित हों।
4	संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक (एफएफएमसी)	चुनिंदा पंजीकृत कंपनियां	विदेशी मुद्रा की खरीद और विदेशों में निजी और व्यावसायिक यात्राओं के लिए विदेशी मुद्रा की बिक्री

रिज़र्व बैंक एडी श्रेणी – I. बैंकों, एडी श्रेणी - II. संस्थाओं और एफएफएमसी को अनुमत मनी-चेंजिंग का व्यवसाय अर्थात् विदेशी मुद्रा नोटों, सिक्कों या ट्रेवलर्स चेक को भारतीय रुपये में बदलने के लिए अपने विकल्प पर फ्रेंचाइजी (एजेंसी के रूप में भी संदर्भित) करार करने की अनुमति देता है।

उल्लंघनों का कंपाउंडिंग

फौजदारी या आपराधिक मामले की बजाय दीवानी या सिविल मामले के रूप में उल्लंघन का वर्गीकरण फेमा, 1999 और फेरा, 1973 के बीच महत्वपूर्ण अंतरों में से एक है। फेमा, 1999 के किसी प्रावधान या फेमा, 1999 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए किसी भी नियम/ विनियम/ अधिसूचना/निदेश/आदेश या किसी भी शर्त जिसके अधीन आरबीआई द्वारा प्राधिकार जारी किया जाता है, का पालन करने में विफलता को फेमा, 1999 के तहत ऐसे प्रावधान का उल्लंघन माना जाता है। फेमा, 1999 की धारा 13 के अनुसार न्यायनिर्णयन के बाद फेमा, 1999 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति मौद्रिक दंड का भागी होगा। शमन (कंपाउंडिंग) एक ऐसा तंत्र है जिसमें उल्लंघन करने वाले व्यक्ति द्वारा स्वैच्छिक स्वीकारोक्ति और लगाई गई राशि के भुगतान के माध्यम से उल्लंघन को नियमित किया जाता है। कोई भी उल्लंघन [फेमा की धारा 3 (ए) को छोड़कर], इस तरह का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर, फेमा, 1999 की धारा 15 के तहत प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करते हुए आरबीआई के अधिकारियों द्वारा शमन (कंपाउंडिंग) किया जा सकता है। तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक ऐसे उल्लंघनों को 'संवेदनशील' के रूप में वर्गीकृत किसी उल्लंघन का शमन नहीं करता है जो जानबूझकर, दुर्भावनापूर्ण और धोखाधड़ीपूर्ण लेन-देन हों। उल्लंघन का शमन (कंपाउंडिंग) करने की प्रक्रिया भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग कार्यवाही) नियम के आधार पर की जाती है। जहां रिज़र्व बैंक द्वारा उल्लंघन का शमन (कंपाउंडिंग) कर दिया गया है, वहां इस प्रकार का शमन (कंपाउंडिंग) किए गए उल्लंघन के संबंध में, उस धारा के अधीन ऐसा उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध यथास्थिति, कोई कार्यवाही या आगे की कार्यवाही आरंभ या जारी नहीं रखी जाएगी।

फेमा 1999 के तहत विनियामक ढांचा

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत, जनहित में और भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को छोड़कर, चालू खाता पूर्णतः परिवर्तनीय होने के कारण, विदेशी मुद्रा लेनदेनों के लिए विनियामक ढांचे का फोकस अधिकांशतः पूंजी खाता लेन-देन पर रहा है।

चालू खाता लेन-देन: आईएमएफ के अनुच्छेद VIII को स्वीकार करने और चालू खाते के तहत परिवर्तनीयता घोषित करने के बाद, किसी भी व्यक्ति पर प्राधिकृत व्यक्ति से विदेशी मुद्रा खरीदने या को बेचने के लिए न्यूनतम प्रतिबंध है, यदि लेन-देन चालू खाता लेन-देन से संबंधित है। फेमा सरकार को जनहित में और रिज़र्व बैंक के परामर्श से चालू खाता लेन-देन के लिए युक्तिसंगत प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्रदान करता है। सरकार ने इस प्रयोजन के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेन-देन) नियमावली, 2000 निर्धारित की है। नियमों में तीन अनुसूचियां संलग्न हैं।

- **अनुसूची I** – यह उन लेन-देन को निर्दिष्ट करती है जिनके लिए विदेशी मुद्रा का आहरण निषिद्ध है जैसे लॉटरी जीतने वालों का प्रेषण, रेसिंग / राइडिंग आदि से आय, लॉटरी टिकटों की खरीद, प्रतिबंधित पत्रिकाएं, घुड़दौड़ की बाज़ी आदि।
- **अनुसूची II** – यह उन लेन-देन को निर्दिष्ट करती है जिनके लिए विदेशी मुद्रा के आहरण के लिए सरकार की पूर्ण स्वीकृति की आवश्यकता होती है जैसे कि सांस्कृतिक पर्यटन, पीएसयू द्वारा चार्टर्ड जहाज के माल का प्रेषण, आदि।
- **अनुसूची III** – उन लेन-देन को निर्दिष्ट करती है जिनके लिए विदेशी मुद्रा के आहरण के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्ण अनुमोदन आवश्यक है। व्यक्तियों के लिए, इन लेन-देन में एक निश्चित मौद्रिक सीमा से ऊपर विदेशी मुद्रा का आहरण शामिल है जैसे कि किसी भी देश (नेपाल और भूटान को छोड़कर) की निजी यात्राएं, उपहार या दान, उत्प्रवास, विदेश में करीबी रिश्तेदारों का रखरखाव, विदेश में अध्ययन आदि। व्यक्तियों के लिए यह सीमा उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) से जुड़ी हुई है। गैर-व्यक्तियों के लिए, मौद्रिक सीमाएं परामर्श सेवाओं, दान आदि के लिए विदेशी मुद्रा भेजने के लिए हैं।

अनुसूची I में उल्लिखित लेन-देन के अलावा, नेपाल या भूटान की यात्रा या नेपाल या भूटान में निवासी व्यक्ति के साथ लेन-देन के लिए विदेशी मुद्रा का आहरण भी निषिद्ध है।

पूंजी खाता लेन-देन : 1991 से उदारीकरण और संरचनात्मक समायोजन के बाद, भारत ने सावधानीपूर्ण तरीके से पूंजी प्रवाह को प्रोत्साहित करने की नीति शुरू की है। पूंजी प्रवाह (फ्लो) के स्रोतों और प्रकारों में एक पदानुक्रम स्थापित किया

जाता है। इसे अंतर्गत प्राथमिकता बहिर्वाह (आउटफ्लो) के सापेक्ष अंतर्वाह (इनफ्लो) को उदार बनाने की रही है। अंतर्वाहों(इनफ्लो) के बीच, दीर्घावधिक पूंजी अंतर्वाहों (इनफ्लो) को प्रोत्साहित करने और ऋण की तुलना में इक्विटी को अधिक तरजीह देते हुए अल्पावधिक और अस्थिर प्रवाहों को हतोत्साहित करने की कार्यनीति रही है। निवासियों और अनिवासियों के बीच अंतर किया जाता है। निवासियों के बीच, कॉर्पोरेट्स, व्यक्तियों और वित्तीय मध्यस्थों के बीच अंतर किया गया है। अनिवासियों के मामले में, अभिशासन अपेक्षाकृत उदार है यानी, अंतर्वाह (इनफ्लो) से जुड़े अंतर्वाह या बहिर्वाह के संबंध में कम प्रतिबंध। निवासियों के मामले में, नीति ने कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए एक अधिक उदार ढांचा, मध्यस्थों के लिए एक विवेकपूर्ण ढांचा और विदेशी निवेश के लिए एक खिड़की और एलआरएस के तहत व्यक्तियों द्वारा पोर्टफोलियो के विविधीकरण का प्रावधान किया है। पूंजी प्रवाह के कुछ प्रकारों का वर्णन नीचे किया गया है:

- **अनिवासी जमा** – प्रवासी भारतीयों के लिए जमा खाते पूंजी प्रवाह को मजबूत करने के शुरुआती उपायों में से एक था। जब पूंजी प्रवाहों के अन्य रूप या तो अस्तित्वहीन थे या अपेक्षाकृत कमजोर थे, तब इसने अच्छी तरह से कार्य किया है। हालांकि एनआरआई जमाराशियों के महत्व में समय के साथ अपेक्षाकृत गिरावट आई है, लेकिन योजनाओं का एक सेट डायस्पोरा को अपनी बैंकिंग के साथ-साथ बचत जरूरतों के लिए भारतीय बैंकिंग प्रणाली का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना जारी रखता है। अनिवासियों द्वारा खोले जा सकने वाले विभिन्न खाते हैं:
- **एनआरआई खाता** – एनआरआई या अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता एनआरआई और पीआईओ / ओसीआई द्वारा खोला जा सकता है। यह खाता बचत, चालू, आवर्ती और सावधि जमा के रूप में खोला जा सकता है और भारतीय रुपये के मूल्यवर्ग में रखा जा सकता है। ये खाते आसानी से प्रत्यावर्तनीय हैं।
- **एनआरओ खाता** – एनआरओ या अनिवासी साधारण रुपया खाता किसी भी अनिवासी द्वारा खोला जा सकता है। यह खाता बचत, चालू, आवर्ती और सावधि जमा के रूप में खोला जा सकता है और भारतीय रुपये के मूल्यवर्ग में रखा जा सकता है। इस खाते से प्रत्यावर्तन केवल प्रति वित्तीय वर्ष 1 मिलियन अमरीकी डालर की सीमा तक स्वीकार्य है।
- **एसएनआरआर खाता** – विशेष अनिवासी रुपया (एसएनआरआर) खाता किसी भी अनिवासी द्वारा खोला जा सकता है, जिसका भारत में व्यावसायिक हित है, जो रुपये में वास्तविक लेन-देन के माध्यम से करता है। खाता बिना किसी ब्याज भुगतान के चालू खाते के रूप में खोला जा सकता है और भारतीय मुद्रा में होता है। खाते में नाम और जमा खाताधारक द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित कारोबार के लिए विशिष्ट/प्रासंगिक होंगे।
- **एफसीएनआर (बी) खाता** – एफसीएनआर (बी) या विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) एनआरआई और पीआईओ / ओसीआई द्वारा खोला जा सकता है। यह खाता सावधि जमा के रूप में और किसी भी स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में खोला जा सकता है। एनआरआई खातों में अनुमत सभी जमा और नाम इन खातों में भी अनुमत होंगे।
- **निवासी व्यक्तियों द्वारा विदेशी मुद्रा खाते** – निवासी भारत में विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्ग के खाते खोल सकते हैं जैसे विनिमय अर्जक विदेशी मुद्रा खाता (ईईएफसी), निवासी विदेशी मुद्रा (घरेलू) खाता [आरएफसी (डी)], निवासी विदेशी मुद्रा खाता (आरएफसी) आदि। कोई विदेशी मुद्रा खाता भारत या नेपाल या भूटान की मुद्रा के अलावा अन्य मुद्रा में धारित या रखा गया खाता है।

- **विदेशी निवेश:** भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा किसी भारतीय कंपनी के इक्विटी इंस्ट्रुमेंट में प्रत्यावर्तनीय आधार पर या एलएलपी (सीमित देयता भागीदारी) की पूंजी में किए गए किसी भी निवेश को विदेशी निवेश के रूप में जाना जाता है। सभी विदेशी निवेश प्रत्यावर्तनीय (लागू करें का निवल) हैं, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां निवेश गैर-प्रत्यावर्तन आधार पर किया जाता है या रखा जाता है। भारत के बाहर रहने वाला व्यक्ति किसी भी भारतीय कंपनी में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) या विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) के रूप में विदेशी निवेश कर सकता है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश: विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) का अर्थ है पूंजीगत इंस्ट्रुमेंट के माध्यम से भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा एक गैर-सूचीबद्ध भारतीय कंपनी में या सूचीबद्ध भारतीय कंपनी में डाल्यूटेड आधार पर 10 प्रतिशत या उससे अधिक पोस्ट इश्यू पेड-अप इक्विटी पूंजी में निवेश। पूर्णतः डाल्यूटेड आधार का अर्थ है उन शेयरों की कुल संख्या जो रूपांतरण के सभी सम्भावित स्रोतों का प्रयोग किए जाने पर बकाया होंगे। एक बार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में निवेश किए जाने के बाद, इसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में माना जाता रहेगा, भले ही निवेश का स्तर दस प्रतिशत से कम हो। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई), जिसकी विशेषता स्थायी ब्याज और निवेशक द्वारा कुछ हद तक प्रबंधन नियंत्रण है, पूंजी प्रवाह के पदानुक्रम में उच्च स्थान पर होता है क्योंकि इससे संसाधनों को वृद्धिशील बनाता है और आमतौर पर बेहतर प्रौद्योगिकी और अधिक कुशल प्रबंधन और व्यवसाय प्रथाओं को भी लाता है। एफडीआई के लिए ढांचा, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से फेमा, 1999 के तहत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 के तहत कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। एफडीआई पर एकमात्र प्रतिबंध-रणनीतिक या सामाजिक-आर्थिक विचारों से प्रेरित, सेक्टरल सीमाओं से संबंधित है - इसमें नियंत्रण की श्रेणी को हटाकर रक्षा, प्रिंट मीडिया, बीमा, बैंकिंग, पेंशन, वस्तु और पावर एक्सचेंज आदि जैसे क्षेत्रों में एक अनिवासी को सौंपी जा सकती है और भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से एफडीआई प्राप्त करने के लिए नियंत्रण है। विनिर्माण और अवसंरचना में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अपनाई गई एफडीआई नीति का पालन किया गया है। जुआ, सट्टेबाजी, निधि कंपनियों, लॉटरी व्यवसाय आदि में निवेश जैसी मुट्ठी भर गतिविधियों को छोड़कर, जो विदेशी निवेश के लिए निषिद्ध हैं, भारत के बाहर निवासी व्यक्ति या भारत के बाहर एक निगमित इकाई या तो भारत सरकार की विशिष्ट पूर्व स्वीकृति के साथ या स्वचालित रुट के तहत निवेश कर सकती है। निर्धारित सेक्टरल सीमा के अधीन सरकार अथवा रिजर्व बैंक के अनुमोदन के बिना स्वचालित मार्ग के अंतर्गत निवेश की अनुमति है। एफडीआई नीति ढांचा वास्तव पूर्णतः स्थिर नहीं है बल्कि समीक्षा के लिए खुला होती है।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) इक्विटी इंस्ट्रुमेंट के माध्यम से भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी निवेश को संदर्भित करता है, जहां इस तरह का निवेश सूचीबद्ध भारतीय कंपनी में पूर्णतः डाल्यूटेड आधार पर पोस्ट इश्यू पेड-अप शेयर पूंजी का 10 प्रतिशत से कम है या सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के इक्विटी इंस्ट्रुमेंट की प्रत्येक श्रृंखला के पेड-अप मूल्य के दस प्रतिशत से कम है। सेक्टरल कैप वह अधिकतम निवेश है जिसमें किसी कंपनी के इक्विटी इंस्ट्रुमेंट्स या एलएलपी की पूंजी में भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्यावर्तन आधार पर विदेशी निवेश और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश दोनों शामिल हैं। यह भारतीय निवेशी इकाई के लिए समग्र सीमा होगी। अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश का

अर्थ है किसी भारतीय इकाई द्वारा किसी अन्य भारतीय इकाई (आईई) से प्राप्त डाउनस्ट्रीम निवेश, जिसने विदेशी निवेश प्राप्त किया है, और जिसका स्वामित्व और नियंत्रण निवासी भारतीय नागरिकों के पास नहीं है और जिसका स्वामित्व या नियंत्रण भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों के पास है। डाउनस्ट्रीम निवेश का अर्थ है किसी भारतीय इकाई या निवेश वेहिकल द्वारा किसी अन्य भारतीय इकाई के इक्विटी इंस्ट्रुमेंट या पूंजी में किया गया निवेश। कुल विदेशी निवेश का अर्थ है कुल विदेशी निवेश और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसकी गणना पूर्णतः डाल्यूटेड आधार पर की जाती है।

सेबी के साथ पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) और अनिवासी भारतीय भारत में स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के इक्विटी इंस्ट्रुमेंट खरीदने के लिए पात्र हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कुछ अस्थिरता प्रदर्शित करते हैं और इसलिए कुछ सीमाओं के अधीन हैं।

- वैयक्तिक एफपीआई द्वारा निवेश पूरी तरह से डाल्यूटेड आधार पर भारतीय कंपनी की चुकता पूंजी के 10 प्रतिशत से कम होना चाहिए। एफपीआई द्वारा निवेश के लिए समग्र सीमा भारतीय कंपनी के लिए उसकी चुकता इक्विटी पूंजी के संबंध में पूरी तरह से डाल्यूटेड आधार पर लागू सेक्टरल सीमा के अधीन होगी। इस समग्र सीमा को भारतीय कंपनी के निदेशक मंडल के अनुमोदन से निम्नतर सीमा तक घटाया जा सकता है।
- अनिवासी भारतीय (एनआरआई) पोर्टफोलियो निवेश योजना के तहत स्टॉक एक्सचेंजों पर भारतीय कंपनियों के इक्विटी इंस्ट्रुमेंट की खरीद या बिक्री कर सकते हैं। एक एनआरआई पूरी तरह से डाल्यूटेड आधार पर एक भारतीय कंपनी की चुकता पूंजी के 5 प्रतिशत तक शेयर खरीद सकता है। सभी एनआरआई मिलकर कंपनी की चुकता वैल्यू के 10 फीसदी से ज्यादा की खरीद नहीं कर सकते हैं। दस प्रतिशत की कुल सीमा को भारतीय कंपनी की निदेशक मंडल द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके चौबीस प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।
- **भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों के लिए अन्य निवेश के अवसर:** भारत के बाहर के निवासी को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा विनियमित रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आईआईटी), इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट्स) और वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ) जैसे निवेश वेहिकल की इकाइयों में निवेश करने की अनुमति है।
- **बाहरी वाणिज्यिक उधार:** बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) अनिवासी पात्र उधारदाताओं से उगाहे गए ऋण और बांड हैं। ये वाणिज्यिक ऋण पात्र निवासी संस्थाओं द्वारा मान्यता प्राप्त अनिवासी कंपनियों से लिए गए हैं जो न्यूनतम परिपक्वता, अनुमत और गैर-अनुमत अंतिम उपयोग, अधिकतम ऑल-इन-कॉस्ट सीमा आदि जैसे मानदंडों के अनुरूप हैं। इन उधारों के लिए नीति निर्धारण यह रहा है कि चूंकि अर्थव्यवस्था की बाह्य देयता में अत्यधिक बढ़ोतरी की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, इसलिए ईसीबी को उनके सर्वाधिक उत्पादक उपयोग के लिए आबंधित किए जाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य को एक विनियामक व्यवस्था के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है जिसमें ऋण की मात्रा, अन्त्य उपयोग, अवधि, ऋणदाता प्रत्यय-पत्र और उधार की लागत के संबंध में प्रतिबंध शामिल हैं। ईसीबी को विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग ईसीबी या रुपया मूल्यवर्ग ईसीबी के रूप में निष्पादित किया जा सकता है। ईसीबी को एफसीसीबी (विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड) और एफसीईबी (विदेशी मुद्रा विनिमय बांड) के रूप में भी जुटाया जा सकता है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त करने के लिए पात्र सभी संस्थाएं ईसीबी जुटाने के लिए पात्र हैं। विदेशी मुद्रा में अंकित ईसीबी की मुद्रा को एक विदेशी मुद्रा से किसी अन्य विदेशी मुद्रा के साथ-साथ भारतीय रुपये

में बदलने की स्वतंत्र अनुमति है। हालांकि, भारतीय रुपया में अंकित ईसीबी के लिए, मुद्रा को भारतीय रुपये से किसी भी विदेशी मुद्रा में बदलने की अनुमति नहीं है। ईसीबी से प्राप्त आय को निर्धारित विशिष्ट शर्तों के साथ विदेश या देश में भी रखा जा सकता है।

- नई पारदेशीय निवेश (ओआई) व्यवस्था:** नई पारदेशीय निवेश व्यवस्था – 22 अगस्त, 2022 को विदेशी मुद्रा प्रबंधन (पारदेशीय निवेश) नियम, 2022 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (पारदेशीय निवेश) विनियम, 2022 की अधिसूचना द्वारा, व्यापक आर्थिक गतिविधि को कवर करने के लिये भारत में निवासी व्यक्तियों द्वारा पारदेशीय निवेश के लिये ढाँचे को सरल बनाती है और विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता को प्रभावी रूप से कम करती है। इसका उद्देश्य अनुपालन के बोझ और संबंधित अनुपालन लागत को कम करना है। नए नियमों और विनियमों द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों में विभिन्न अवधारणाओं की परिभाषाओं जैसे 'पारदेशीय पोर्टफोलियो निवेश', 'निवल मूल्य', 'स्टेप डाउन सब्सिडियरी' आदि के संबंध में बढ़ी हुई स्पष्टता, राष्ट्रीय हित के क्षेत्रों में पारदेशीय निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए 'रणनीतिक क्षेत्र' की अवधारणा की शुरुआत, विलंबित रिपोर्टिंग को रिकॉर्ड पर लेने के लिए 'विलंब से प्रस्तुत करने के लिए शुल्क (एलएसएफ)' का तंत्र आदि शामिल हैं।
- पारदेशीय निवेश (ओआई):** पारदेशीय निवेश का अर्थ है भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा वित्तीय प्रतिबद्धता और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। वित्तीय प्रतिबद्धता (एफसी) ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (ओडीआई) के माध्यम से भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा किए गए निवेश की समग्र राशि को संदर्भित करता है, एक विदेशी संस्था में ओवरसीज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट (ओपीआई) के अलावा अन्य ऋण, जिसमें ओडीआई किया गया है और इसमें ऐसे व्यक्ति द्वारा या ऐसी विदेशी संस्था और विदेशों में विस्तारित गैर-फंड-आधारित सुविधा (सुविधाएं) शामिल होंगी।
- निवासियों द्वारा पारदेशीय प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई):** ओडीआई में वह निवेश शामिल है जो या तो स्वचालित मार्ग (रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना) या अनुमोदन मार्ग (रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से) के तहत, किसी विदेशी संस्था की गैर-सूचीबद्ध इक्विटी पूंजी के अधिग्रहण के माध्यम से, या किसी विदेशी संस्था के संस्था के अंतर्नियम के एक भाग के रूप में अभिदान, या किसी सूचीबद्ध विदेशी संस्था की प्रदत्त इक्विटी पूंजी का दस प्रतिशत या अधिक में निवेश या नियंत्रण के साथ निवेश, जहां निवेश किसी सूचीबद्ध विदेशी संस्था की प्रदत्त इक्विटी पूंजी का दस प्रतिशत से कम है। ओडीआई का मामला भारतीय उद्यमियों को विदेशों में लाभदायक निवेश के रास्ते तलाशने की अनुमति देने पर टिका हुआ है। पारदेशीय प्रत्यक्ष निवेश भारतीय अर्थव्यवस्था के रणनीतिक हितों को पूरा करते हुए विश्व अर्थव्यवस्था के साथ भारत के प्रगतिशील एकीकरण का एक अविभाज्य हिस्सा रहा है।
- निवासियों द्वारा पारदेशीय पोर्टफोलियो निवेश (ओपीआई):** ओपीआई का अर्थ है विदेशी प्रतिभूतियों में ओडीआई के अलावा ऐसा अन्य निवेश, जिसमें एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड और डिपॉजिटरी रसीदों की इकाइयां शामिल हैं, जो भारत के बाहर किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं, लेकिन भारत में निवासी व्यक्ति (आईएफएससी के बाहर) द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में सूचीबद्ध नहीं हैं। किसी सूचीबद्ध विदेशी संस्था की इक्विटी पूंजी में भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा ओपीआई, डीलिंग के बाद, ओपीआई के रूप में तब तक माना जाता रहेगा जब तक कि ऐसी विदेशी संस्था में कोई और निवेश नहीं किया जाता है।
- निवासियों द्वारा एफसी/ओपीआई के लिए सीमाएं:** भारतीय इकाई के लिए कुल एफसी अंतिम लेखापरीक्षित

तुलन पत्र की तारीख को अपने निवल मूल्य के 400% से अधिक नहीं होगा। एक सूचीबद्ध भारतीय कंपनी अपने अंतिम लेखापरीक्षित तुलन पत्र की तारीख को अपने निवल मूल्य के 50 प्रतिशत की सीमा के भीतर पुनर्निवेश के माध्यम से ओपीआई बना सकती है। निवासी व्यक्ति उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के लिए समग्र सीमा के भीतर ओडीआई और ओपीआई बना सकते हैं।

- **अचल संपत्ति में निवेश:** भारत में निवासी कोई व्यक्ति भारत के बाहर स्थित किसी भी अचल संपत्ति में धारिता, स्वामित्व, हस्तांतरण या निवेश कर सकता है, यदि ऐसी संपत्ति का अधिग्रहण, धारण, या स्वामित्व उसके द्वारा तब किया गया था, जब वह भारत के बाहर निवासी था या भारत के बाहर निवासी व्यक्ति से विरासत में मिला था। निवासी व्यक्ति भारत के बाहर अचल संपत्ति खरीदने के लिए एलआरएस के तहत प्रेषण भेज सकता है।

अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों/ओसीआई द्वारा भारत में अचल संपत्ति के अधिग्रहण के लिए भुगतान बैंकिंग चैनलों के माध्यम से या एनआरआई/भारतीय मूल के व्यक्तियों के एनआरआई/एफसीएनआर (बी)/एनआरओ खातों में रखी गई निधियों के माध्यम से भारत को विप्रेषित निधियों के रूप में प्राप्त किया जाना है। वे शर्तों के अधीन भारत में किसी प्राधिकृत डीलर या आवास वित्त संस्थान से रुपये में आवास ऋण भी प्राप्त कर सकते हैं। भारत में निवासी गैर-भारतीय मूल के विदेशी नागरिक (कुछ निर्दिष्ट देशों को छोड़कर) भारत में अचल संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। भारत के बाहर के निवासी गैर-भारतीय मूल के विदेशी नागरिक भारत में अचल संपत्ति अधिग्रहण/अंतरित कर सकते हैं, जो पांच वर्ष से अनधिक पट्टे पर होगी और किसी निवासी से विरासत के रूप में भारत में अचल संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति शर्तों के अधीन भारत में अचल संपत्ति (कृषि भूमि/फार्महाउस/बागान संपत्ति को छोड़कर) की बिक्री आय का विप्रेषण कर सकते हैं।

किसी अनिवासी द्वारा भारत में शाखाओं, कार्यालयों या व्यवसाय के अन्य प्रतिष्ठानों की स्थापना: भारत में किसी अनिवासी द्वारा भारत में शाखाओं, कार्यालयों या व्यवसाय के अन्य प्रतिष्ठानों की स्थापना रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित गतिविधि है। कोई विदेशी संस्था भारत में संपर्क कार्यालय, शाखा कार्यालय अथवा परियोजना कार्यालय के रूप में अपना कारोबार स्थापित कर सकती है।

- i. संपर्क कार्यालय का अर्थ है कारोबार के प्रमुख स्थान या प्रधान कार्यालय या भारत में किसी भी नाम से और संस्थाओं के बीच संचार चैनल के रूप में कार्य करने के लिए व्यवसाय का एक प्रतिष्ठान, लेकिन जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई वाणिज्यिक/व्यापार/औद्योगिक गतिविधि नहीं करता है, और सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से विदेश से प्राप्त आवक प्रेषण से खुद को बनाए रखता है।
- ii. एक कंपनी के संबंध में एक शाखा कार्यालय का अर्थ है कि कंपनी द्वारा इस तरह के रूप में वर्णित किसी भी प्रतिष्ठान।
- iii. परियोजना कार्यालय का अर्थ है भारत में कारोबार का एक ऐसा स्थान जो भारत में परियोजना निष्पादित करने वाली विदेशी कंपनी के हितों का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन संपर्क कार्यालय शामिल नहीं है।

उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस)

उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत, प्राधिकृत डीलर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित सीमा तक निवासी व्यक्तियों द्वारा विप्रेषण की स्वतंत्र रूप से अनुमति दी जा सकती है। वर्तमान में, 2,50,000 अमरीकी डालर प्रति वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) किसी भी अनुमत चालू या पूंजी खाता लेन-देन या दोनों के संयोजन के लिए सीमा है। यह योजना नाबालिगों सहित सभी निवासी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। योजना के तहत प्रेषण को परिवार के सदस्यों के संबंध में समेकित किया जा सकता है बशर्ते कि परिवार के सदस्य व्यक्तिगत रूप से कुछ नियमों और शर्तों का पालन करते हों। हालांकि, परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा पूंजी खाता लेन-देन जैसे बैंक खाता खोलने/निवेश के लिए क्लबिंग की अनुमति नहीं है यदि वे विदेशी बैंक खाते/निवेश के सह-स्वामी/ सह-भागीदार नहीं हों। एक निवासी एलआरएस के तहत विदेश में धारित विदेशी मुद्रा खाते में क्रेडिट के लिए विदेशी मुद्रा में किसी अन्य निवासी को उपहार नहीं दे सकता है। इस सीमा में चालू खाता लेनदेनों (अर्थात् निजी यात्रा, उपहार/दान; रोजगार पर विदेश जाना; उत्प्रवास; विदेश में संबंधियों का रखरखाव; व्यापार यात्रा; विदेश में चिकित्सा उपचार; विदेश में अध्ययन) के लिए निवासी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध विप्रेषण भी शामिल हैं/ सम्मिलित हैं। सीमा से अधिक विदेशी मुद्रा जारी करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है।

योजना के तहत अनुमत पूंजी खाता लेन-देन विदेशी मुद्रा प्रबंधन (पारदेशीय निवेश) नियम, 2022 और इसके संबंधित नियमों और निर्देशों के अनुसार विदेशी निवेश हैं - विदेश में विदेशी मुद्रा खाता खोलना, विदेश में अचल संपत्ति खरीदना और एनआरआई रिश्तेदारों को ऋण प्रदान करना। इसके अलावा, इस योजना के तहत प्रेषण भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) को आईएफएससी के भीतर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अनुसार वित्तीय सेवाओं या वित्तीय उत्पादों का लाभ उठाने के लिए और आईएफएससी में आयोजित विदेशी मुद्रा खाते के माध्यम से किसी अन्य विदेशी क्षेत्राधिकार (आईएफएससी के अलावा) में सभी अनुमत चालू या पूंजी खाता लेन-देन के लिए भी किया जा सकता है।

पूंजी खाता परिवर्तनीयता

रिज़र्व बैंक मुद्रास्फीति जैसे आंतरिक आधातों का प्रबंधन करने और विकास में तेजी लाने के लिए वास्तविक क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पूंजी खाता लेनदेनों के क्रमिक उदारीकरण का दृष्टिकोण अपनाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक का नीतिगत दृष्टिकोण पूंजी खाता उदारीकरण को एक प्रक्रिया के रूप में मानने तथा अर्थव्यवस्था की सुभेद्यताओं तथा आधात की संभावना को ध्यान में रखते हुए इसका प्रबंधन किए जाने के प्रति लक्षित है। यद्यपि भारत में पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता अभी प्राप्त की जानी है, पूंजी खाते का प्रबंधन इस तरह से किया जाता है कि अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को सहज तरीके से पूरा किया जा सके।

भारतीय रुपये (INR) में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटान

भारतीय रुपये में व्यापार भुगतान और निपटान को प्रोत्साहित करने के लिए मौजूदा तंत्र में भारतीय रुपये में व्यापार लेन-देन के निष्पादन के लिए एक अतिरिक्त तंत्र जुलाई 2022 में इनवायसिंग के लिए पेश किया गया था, और विशेष रुपया वोस्ट्रो खाता (SRVA) खोलकर भारतीय रुपये में निर्यात/आयात के भुगतान और निपटान को प्रभावित किया गया था।

भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण

आर्थिक उदारीकरण सुधारों को गति देने के बाद पिछले तीन दशकों में भारत के बाह्य क्षेत्र ने उल्लेखनीय प्रगति दिखाई है। पिछले कुछ वर्षों में, व्यापार और पूंजी प्रवाह के संदर्भ में शेष विश्व के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। इस बीच, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली बहुध्रुवीय होने की ओर अग्रसर हुई है, जैसा कि देशों के विदेशी मुद्रा भंडार में अमरीकी डालर की लगातार घटती हिस्सेदारी, व्यापार इनवायसिंग और निपटान में अन्य मुद्राओं के बढ़ते उपयोग और विभिन्न द्विपक्षीय और क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग समझौतों के उद्भव में परिलक्षित होता है। इन कारकों ने, हाल के भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के साथ, अंतरराष्ट्रीय लेन-देन में उपयोग के लिए संभावित मुद्राओं के रूप में भारतीय रुपये सहित विभिन्न अन्य मुद्राओं के उद्भव के लिए मंच तैयार किया है। एक अंतर-विभागीय समूह (आईडीजी), जिसे भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण की संभावनाओं की जांच करने के लिए स्थापित किया गया था, ने समयबद्ध उपायों के एक सेट के माध्यम से इसे प्राप्त करने के लिए एक रोडमैप की सिफारिश की थी।

आगे की राह

फेमा के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के सांविधिक अधिदेश को ध्यान में रखते हुए, विदेशी मुद्रा विभाग एक सरल विनियामक ढांचे के माध्यम से विदेश व्यापार को बढ़ावा देना जारी रखने के लिए प्रयासशील है जिससे व्यापार करने में आसानी होगी और साथ ही अनुपालन लागत में कमी आएगी। उदारीकरण के भाग के रूप में, प्राधिकृत व्यक्तियों (एपी) से फेमा के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है जहां बैंक द्वारा विनियमन की व्यापक रूपरेखा निर्धारित की जाती है और प्राधिकृत व्यक्ति अनुपालन और व्यवसाय संवर्धन के दोहरे उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इसकी व्याख्या करेंगे। विभाग का व्यापक दृष्टिकोण उन नियमों और निर्देशों के प्रति सिद्धांत-आधारित दृष्टिकोण अपनाना होगा जिन्हें एपी द्वारा लागू किया जाएगा।

अध्याय 19: विदेशी मुद्रा भंडार

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 में इस आशय का एक सक्षमीकरण प्रावधान है जो रिज़र्व बैंक को विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों के अभिरक्षक के रूप में काम करने तथा सुपरिभाषित उद्देश्यों के साथ उन आरक्षित निधियों का प्रबंध करने का दायित्व सौंपता है। देश का विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां वैश्विक वित्तीय सुरक्षा नेट के चार मुख्य घटकों में से एक होती है, जिनमें से अन्य तीन हैं- द्विपक्षीय स्वेप लाइन, क्षेत्रीय वित्तपोषण व्यवस्थाएं और आईएमएफ जो आर्थिक संकटों के लिए बीमा प्रदान करता है। विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां प्रमुख अंतरणीय मुद्राओं में रखा जाती हैं और उसका निवेश क्रमानुसार सुरक्षा, चलनिधि और प्रतिफल पर विचार किए जाने के आधार पर अत्यंत उच्च गुणवत्ता की आस्तियों में किया जाता है। विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों का प्रबंध ऐसी प्रक्रिया है जो इस बात को सुनिश्चित करती है कि सरकारी क्षेत्र की पर्याप्त आधिकारिक विदेशी आस्तियां संबंधित प्राधिकारियों को तत्काल उपलब्ध हो पाएं और वे किसी देश अथवा संघ के लिए उद्देश्यों के परिभाषित दायरे को पूरा करने के लिए उन राशियों को नियंत्रित कर पाएं। इस परिप्रेक्ष्य में विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों का प्रबंधन करने वाली संस्था को अक्सर विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों के प्रबंधन और उससे जुड़े जोखिमों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है।

संकल्पनात्मक रूप से, विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों की कोई एकमात्र परिभाषा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उसमें शामिल की जाने वाली मदों, आस्तियों के स्वामित्व, चलनिधि से संबंधित पहलू तथा स्वामित्वाधीन और गैर-स्वामित्वाधीन विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों के संबंध में अलग-अलग दृष्टिकोण हैं। तथापि, नीति और परिचालन के प्रयोजनों के लिए बहुत से देशों ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष [आईएमएफ] द्वारा सुझाई गयी परिभाषा को अपनाया है [बैलेस ऑफ़ पेमेंट्स मैनुअल एंड गाइडलाइन्स ऑन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, 2001] इसमें विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों की परिभाषा इस प्रकार की गई है :

“ ऐसी विदेशी आस्तियां, जो मौद्रिक प्राधिकारियों को विदेशी भुगतानों के असंतुलनों का प्रत्यक्ष वित्तपोषण करने के लिए तत्काल उपलब्ध रहती हैं, और जिन पर उनका नियंत्रण होता है, वह मौद्रिक प्राधिकारी विदेशी मुद्रा के बाज़ारों में अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करते हुए उन आस्तियों का मुद्रा की विनिमय दरों को प्रभावित करने के लिए और/ अथवा अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग कर सकता है।”

विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों की अभिवृद्धि

विदेशी मुद्राएं चालू तथा पूंजी खाते की गतिविधियों का अंतिम परिणाम हैं। विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन के मुकाबले विदेशी मुद्रा के आगमन में स्थित अंतराल के कारण विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधियों के स्तर में चालू खाते और पूंजी खाते दोनों ही के लेन-देन के लिए अंतर पड़ सकता है। जहां विदेशी मुद्रा के अतिरिक्त प्रवाह के आगमन से आरक्षित निधियों का स्तर बढ़ जाता है, वहीं उसके अतिरिक्त बहिर्गमन से उनका स्तर कम हो जाता है। परिचालन की दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा बाज़ार में किए गए हस्तक्षेप को विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधियों में वृद्धि अथवा घट के लिए प्राथमिक तौर पर जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। स्वतंत्रता के बाद, अगर कुछ छोटी सी अवधियों को छोड़ भी दें तो भारत में चालू खाते में हमेशा घाटे की स्थिति बनी रही। इस घाटे का वित्तपोषण प्राप्त हो चुके पूंजी प्रवाहों के माध्यम से किया गया था। चालू खाते में

हुए घाटे का वित्तपोषण करने के लिए जितनी विदेशी मुद्रा आवश्यक है उससे अधिक राशि के पूंजी प्रवाहों का आगमन हो जाने पर बची हुई विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में जमा हो जाती है। विदेशी मुद्रा की परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के तरीके में परिवर्तन किये जाने के बाद और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास स्थित विदेशी परिसंपत्तियों के नियोजन से प्राप्त आय के कारण भी विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधियों के स्तर में परिवर्तन आते हैं।

विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधियों का प्रबंधन – भारतीय रिज़र्व बैंक का दृष्टिकोण

भारतीय रिज़र्व बैंक को देश की विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधियों के अभिरक्षक के रूप में उन राशियों के निवेश का प्रबंधन करने का दायित्व सौंपा गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधियों के प्रबंधन पर लागू कानूनी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।

वर्ष 1991 में भुगतान संकट पैदा होने तक विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधियों के बारे में भारत का दृष्टिकोण अनिवार्यतः आयात के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध रखने का था। डॉ. सी रंगराजन की अध्यक्षता में भुगतान शेष पर गठित उच्च स्तरीय समिति [वर्ष 1993] की सिफारिशें मिलने के बाद इस दृष्टिकोण में एकदम बदलाव आया। इस समिति ने इस बात की आवश्यकता पर बल दिया कि सभी बाहरी देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त आरक्षित निधियां उपलब्ध रखी जाएं, भारत की समस्त देयताएं चुकाने की भारत की क्षमताओं के बारे में अंतरराष्ट्रीय समुदाय को पर्याप्त भरोसा दिलाया जाए और विदेशी मुद्रा बाज़ार में सट्टेबाजी की प्रवृत्तियों पर रोक लगाई जाए। वर्ष 1993 से पहले केंद्रीय बैंक बाज़ार की विनिमय दरों को तय करता था। वर्ष 1993 में बाज़ार आधारित विनिमय दर तय करने की प्रणाली लागू किये जाने के बाद विनिमय दरों की उथल-पुथल की तीव्रता को कम करना ही एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया। विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधियों के प्रबंधन के प्रति समग्र दृष्टिकोण में भुगतान शेष [बीओपी] का बदलता स्वरूप [कम्पोज़ीशन] और विभिन्न प्रकार के पूंजी प्रवाहों के साथ जुड़ी चलनिधि संबंधी जोखिमें प्रतिबिंबित होती हैं।

आरक्षित निधियों की पर्याप्तता 1990 के दशक से ही बहस का विषय बना हुआ है। वर्ष 1997 में श्री एस.एस.तारापोर की अध्यक्षता में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता के संबंध में गठित समिति की रिपोर्ट में आरक्षित निधियों की पर्याप्तता के लिए वैकल्पिक मापन का सुझाव दिया गया है। इस समिति ने व्यापार आधारित संकेतकों के अतिरिक्त मुद्रा आधारित और ऋण आधारित संकेतकों का उपयोग करने का भी सुझाव दिया है। पूंजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता के बारे में भी समिति ने इसी प्रकार के विचार व्यक्त किये हैं [एस.एस.तारापोर, जुलाई 2006]। आयात कवर के रूप में आरक्षित निधियों की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने वाले पारंपारिक दृष्टिकोण को अब व्यापक बनाया गया है और उसमें अब विभिन्न प्रकार के पूंजी प्रवाहों, जैसे, आकार, रचना, और उनके जोखिम प्रोफाइल जैसे अन्य कई सारे मापदंड शामिल किये गए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक भी विदेशी मुद्रा चलनिधि के संबंध में लगनेवाले झटकों सहित सभी बाहरी झटकों पर नज़र रखता है जिनके प्रति अर्थव्यवस्था की स्थिति कुछ नाजुक बनी हुई है। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि आरक्षित निधियों की मात्रा अर्थव्यवस्था की संवृद्धि की क्षमता, जोखिम समायोजित पूंजी प्रवाहों के आकार और सुरक्षा संबंधी राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों का प्रबंध

भारत में विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों का प्रबंध भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है। इन विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में विदेशी मुद्रा की परिसंपत्तियां [एफसीए], विशेष आहरण अधिकार [एसडीआर], अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष [आईएमएफ] के साथ रिज़र्व ट्रेन्च की स्थिति और सोना शामिल है। विदेशी मुद्रा की परिसंपत्तियों का प्रबंध पोर्टफोलियो प्रबंधन के तत्वों के अनुसार ही किया जाता है। विदेशी मुद्रा की परिसंपत्तियों में अलग-अलग मुद्राओं में परिसंपत्तियां शामिल होती हैं जिन्हें मौजूदा मानदंडों के अनुसार अलग-अलग परिसंपत्ति पोर्टफोलियो में रखा जाता है, जो आदर्श अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों के अनुरूप हैं।

आरक्षित निधियों का नियोजन करते समय उससे जुड़े मुख्य जोखिमों में ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम, और चलनिधि या तरलता जोखिम शामिल हैं और इन जोखिमों की वजह से ही रिज़र्व बैंक मुद्रा की रचना [कंपोज़ीशन], ब्याज दर जोखिम, और चलनिधि या तरलता की आवश्यकताओं पर बारीकी से ध्यान देता है। विदेशी मुद्रा की परिसंपत्तियों का निवेश सर्वोच्च ऋण गुणवत्ता वाली परिसंपत्तियों में किया जाता है और उसका एक बड़ा भाग अल्प अवधि में नकदी में परिवर्तन योग्य होता है। ऐसे नियोजन से होने वाली आय का मूल्यांकन करते समय कुल आय [ब्याज और पूंजीगत लाभ, दोनों ही] पर विचार किया जाता है। विदेशी मुद्रा के विदेशी बाज़ारों में निवेश की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र इस प्रक्रिया में स्थित जोखिम में हैं, जिसके ब्योरे इस अध्याय के अंत में प्रस्तुत किए गए हैं।

विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों के प्रबंधन की नीति के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मूलभूत मानदंड हैं सुरक्षा, चलनिधि या तरलता की उपलब्धता, और उन पर होने वाली आय। जहां सुरक्षा, चलनिधि या तरलता की उपलब्धता आरक्षित निधियों के दो स्तंभ हैं वहीं उनपर होने वाली इष्टतम आय इस ढाँचे के भीतर उसी में निहित रणनीति है। रिज़र्व बैंक ने आरक्षित निधियों की सुरक्षा और चलनिधि या तरलता को बढ़ाने के लिए नीतिगत दिशानिर्देश तैयार किये हैं जिनमें जारीकर्ताओं, प्रतिपक्षों, और इन राशियों में किये जाने वाले निवेशों के लिए सख्त पात्रता मानदंड निर्धारित किये गए हैं। रिज़र्व बैंक, सरकार के साथ परामर्श करते हुए आरक्षित निधियों के प्रबंध संबंधी रणनीति की निरंतर समीक्षा करता रहता है।

रिज़र्व बैंक का आरक्षित निधियों के प्रबंधन का काम उसके महत्त्व और उसकी परिष्कृतता दोनों की ही दृष्टि से दो कारणों से बहुत बढ़ गया है। पहला कारण है विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधियों का हिस्सा रिज़र्व बैंक के तुलनपत्र में पर्याप्त रूप से बढ़ गया है। और दूसरा कारण यह है कि वैश्विक बाज़ारों में प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की ब्याज दरों में आ रही तीव्र गिरावट सहित विनिमय और ब्याज दरों में हो रही उथल पुथल के साथ, आरक्षित निधियों के मूल्य के परिरक्षण का और उन पर यथोचित आय कमाने का कार्य अब बहुत चुनौती भरा बन गया है।

आरक्षित निधियों के प्रबंधन के समग्र ढाँचे में रिज़र्व बैंक निम्नलिखित बातों पर ध्यान केंद्रित करता है :

- मौद्रिक और विनिमय दर की नीतियों में बाज़ारों का विश्वास बनाए रखना।
- विदेशी मुद्रा बाज़ारों में अगर अनुचित उथल-पुथल आ जाती है तो ऐसी स्थितियों में रिज़र्व बैंक की हस्तक्षेप करने की क्षमता बढ़ाना।

- राष्ट्रीय आपदा अथवा आपातकाल सहित संकट के समय झटकों को बर्दाश्त करने के लिए विदेशी मुद्रा की चलनिधि या तरलता बनाए रखते हुए बाहरी नाजुक स्थितियों को सीमित रखना।
- विदेशी निवेशकों को यह भरोसा दिलाना कि सभी विदेशी दायित्वों को पूरा किया जाएगा। और इस प्रकार जिस लागत पर विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां बाज़ार के सहभागियों के लिए उपलब्ध हैं उस लागत को घटाना।
- विदेशी परिसंपत्तियों के माध्यम से घरेलू मुद्रा का प्रदर्शन करते हुए बाज़ार के सहभागियों की सुविधा को बढ़ाना।

निवेश के अवसर

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 विभिन्न मुद्राओं, लिखतों, उसके जारीकर्ताओं और प्रतिपक्षों के व्यापक मापदंडों के भीतर विभिन्न विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और सोने की आरक्षित निधियों के नियोजन के लिए व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 के अनुसार विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों का निवेश निम्नलिखित में किया जाता है :

- बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट और अन्य केंद्रीय बैंकों की जमाराशियों में
- विदेशी वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियों में
- सार्वभौम देयतावाले अथवा 10 वर्षों से अनधिक परिपक्वता अवधि वाले सार्वभौम रूप से गारंटीकृत देयता वाले ऋण लिखतों में
- रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित अन्य लिखतों अथवा संस्थाओं में
- कुछ विशिष्ट प्रकार की डेरीवेटिव्स में

आरक्षित निधियों के प्रबंधन में जोखिम प्रबंधन

मुद्राओं की रचना [कंपोज़ीशन] और निवेश की नीति सहित आरक्षित निधियों के प्रबंधन के लिए व्यापक रणनीति भारत सरकार के साथ परामर्श करते हुए तय की जाती है। जोखिम प्रबंधन के कार्यकलापों का उद्देश्य है आदर्श अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप, बेहतर उत्तरदायित्व के साथ, समस्त परिचालनों में जोखिम संबंधी जागरूकता लाते हुए, संसाधनों के आबंटन तथा आंतरिक कौशल और विशेषज्ञता को बढ़ावा देते हुए गवर्नेंस के मजबूत ढांचे को सुनिश्चित करना। आरक्षित निधियों के नियोजन पर जो जोखिम मौजूद हैं जैसे ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम, चलनिधि जोखिम और परिचालन जोखिम, तथा उनके प्रबंधन के लिए लागू की गयी प्रणालियों का नीचे के पैराग्राफों में ब्योरेवार उल्लेख किया गया है :

क्रेडिट जोखिम

रिज़र्व बैंक अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों का जो निवेश करता है उसके लिए पैदा होने वाले जोखिमों के प्रति बहुत संवेदनशील है। बॉण्डों / खज़ाना बिलों में किए गए रिज़र्व बैंक के निवेश उच्च स्तरीय सरकारों, केंद्रीय बैंकों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में किए गए निवेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही, ये जमाराशियां केंद्रीय बैंकों, बीआईएस और विदेशी वाणिज्यिक बैंकों की विदेशों में स्थित शाखाओं में भी रखी जाती हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने आरक्षित निधियों की सुरक्षा तथा चलनिधि या तरलता संबंधी पहलुओं को देखते हुए जारीकर्ताओं / प्रतिपक्षों [काउन्टर पार्टी] के चयन के लिए दिशानिर्देश जारी किये हैं। रिज़र्व बैंक ने इन प्रतिपक्षों के चयन के लिए सख्त मानदंड लागू करना जारी रखा है। अनुमोदित प्रतिपक्षों के

संबंध में मंजूर ऋण सीमाओं के मुकाबले ऋण प्रकटीकरण पर निरंतर निगरानी रखी जाती है। प्रतिपक्षों की गतिविधियों पर सतत नज़र रखी जाती है। इस प्रकार निरंतर चल रही कवायद का मूल उद्देश्य इस बात का मूल्यांकन करना है कि क्या किसी प्रतिपक्ष के क्रेडिट की गुणवत्ता पर कोई खतरा तो नहीं मंडरा रहा।

बाज़ार जोखिम

बहुविध मुद्रा पोर्टफोलियो के लिए बाज़ार जोखिम वित्तीय बाज़ार की कीमतों में हो रही हलचल के परिणामस्वरूप मूल्यांकन में होनेवाले संभावनीय बदलावों का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए ब्याज दरों में, विदेशी मुद्रा दरों में इक्विटी की कीमतों में और वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन। केंद्रीय बैंकों के लिए बाज़ार जोखिम के प्रमुख स्रोतों में मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम, और सोने की कीमत में हलचल शामिल हैं। विनिमय दरों में होने वाली हलचल के कारण विदेशी मुद्रा की परिसंपत्तियों [एफसीए] और सोने के मूल्यांकन पर होनेवाले लाभ / हानि और / अथवा सोने की कीमत को मुद्रा और सोने का पुनर्मूल्यांकन खाता [सीजीआरए] शीर्ष के अंतर्गत तुलन पत्र में दर्शाया जाता है। इस खाते [सीजीआरए] में स्थित शेष राशियाँ, विनिमय दरों / सोने की कीमतों में होनेवाले उतार-चढ़ावों के लिए बफर प्रदान करती हैं जिसमें हाल ही में बहुत तीव्र उथल-पुथल देखी गयी थी। विदेशी दिनांकित प्रतिभूतियों का मूल्यांकन हर माह के अंतिम कारोबारी दिन में प्रचलित बाज़ार कीमतों पर किया जाता है और उससे जो मूल्य वर्धन / मूल्य हास पैदा होता है उसे निवेश पुनर्मूल्यांकन खाते में [आईआरए] में अंतरित किया जाता है। इस आईआरए में रखी गयी शेष राशियाँ उनकी धारिता अवधि के दौरान प्रतिभूति की कीमतों में होनेवाले परिवर्तनों के लिए गुंजाइश प्रदान करती हैं।

- **मुद्रा जोखिम:** मुद्रा जोखिम विनिमय दरों में हो रही हलचल के कारण पैदा होता है। विनिमय दरों में होने वाली संभाव्य हलचल के आधार पर और मध्यावधि और दीर्घावधियों में अन्य बातों के आधार पर विभिन्न मुद्राओं के बारे में दीर्घावधि प्रकटीकरणों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। निर्णय लेने की इस प्रक्रिया को नियमित आधार पर रणनीतिगत समीक्षाएं करते हुए समर्थन प्रदान किया जाता है।
- **ब्याज दर जोखिम:** ब्याज दर जोखिम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पहलू है ब्याज दरों में हो रही हलचल के प्रतिकूल परिणामों से निवेश के मूल्य का यथा संभव बचाव करना। किसी पोर्टफोलियो की ब्याज दर संवेदनशीलता को बेंचमार्क की अवधि में और बेंच मार्क से हटने की अनुमत सीमा से अभिनिर्धारित किया जाता है।

चलनिधि या तरलता जोखिम

तरलता जोखिम में महत्वपूर्ण लागतों का सामना किए बिना किसी उपकरण को नहीं बेच पाने या किसी खुली स्थिति को बंद नहीं कर पाने की जोखिम शामिल है। आरक्षित निधियों में किसी भी समय उच्च स्तर की तरलता होना जरूरी है ताकि किसी भी अप्रत्याशित और आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति पैदा हो जाती है तब आरक्षित निधियों के माध्यम से ही उससे निपटा जा सकता है। और इसीलिए निवेश की रणनीति में अत्यंत तरलता वाले पोर्टफोलियो का होना एक अत्यावश्यक बंधन है। लिखतों का चुनाव किसी पोर्टफोलियो की तरलता को निर्धारित करता है। उदाहरण के तौर पर कुछ बाज़ारों में खज़ाना प्रतिभूतियों को भारी मात्रा में कीमतों में कोई भारी बदलाव किये बिना परिसमापित किया गया था। और इस प्रकार उन्हें तरल माना जा सकता है। बीआईएस के पास रखी गयी मीयादी जमाराशियों को छोड़ कर

वाणिज्यिक बैंकों की विदेशी शाखाएं और केंद्रीय बैंक तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय देशों द्वारा जारी प्रतिभूतियों को छोड़ दें तो लगभग अन्य सभी प्रकार के निवेश सर्वाधिक तरल लिखत हैं जिन्हें अल्प अवधि में ही किसी भी अप्रत्याशित आकस्मिक आवश्यकता के लिए नकदी में रूपांतरित किया जा सकता है।

परिचालनगत जोखिम और नियंत्रण प्रणाली

वैश्विक प्रवृत्तियों के अनुसार तालमेल बिठाते हुए परिचालनगत जोखिमों की नियंत्रण व्यवस्था को मजबूत बनाने पर बारीकी से ध्यान दिया जाता है। इसके लिए महत्वपूर्ण परिचालनगत क्रियाविधियों का दस्तावेज तैयार किया जाता है। आंतरिक रूप से फ्रंट कार्यालय के कामकाज और बैक कार्यालय के कामकाज को पूरी तरह से अलग कर दिया जाता है और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में लेन-देन प्राप्त करने के समय, उस पर प्रक्रिया करते समय और उनके निपटान के समय कई सारी जांच किये जाने को सुनिश्चित किया जाता है। भुगतान अनुदेश बनाने सहित लेन-देन पर प्रक्रिया और निपटान प्रणाली को भी एक बिंदु डेटा प्रविष्टि के सिद्धांतों के आधार पर आंतरिक नियंत्रण दिशानिर्देशों से गुजरना पड़ता है। आंतरिक नियंत्रण संबंधी समस्त दिशानिर्देशों के बारे में अनुपालन पर निगरानी करने के लिए समवर्ती लेखापरीक्षा की प्रणाली भी लागू की गयी है। इसके अलावा, खातों का समाधान नियमित रूप से किया जाता है। आंतरिक वार्षिक निरीक्षणों के अलावा बाहरी सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा भी खातों की लेखापरीक्षा की जाती है। आरक्षित निधियों के प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों / परिचालनों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल करते हुए व्यापक रिपोर्टिंग प्रणाली भी स्थापित की गयी है। ये रिपोर्टें उनके स्वरूप तथा संवेदनशीलता के आधार पर आवधिक रूप से जैसे दैनिक, मासिक, त्रैमासिक, छमाही और वार्षिक अंतरावाधियों में वरिष्ठ प्रबंध तंत्र को प्रस्तुत की जाती हैं। रिज़र्व बैंक अपने व्यापार निपटाने के लिए और अपने प्रतिपक्षों, जिन बैंकों के पास नोस्ट्रो खाते बनाए रखे गए हैं उनको, प्रतिभूतियों के अभिरक्षकों को और अन्य कारोबारी सहभागियों को संदेश भेजने के लिए स्विफ्ट जैसे संदेश प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है। स्विफ्ट के बारे में समस्त अंतरराष्ट्रीय आदर्श पद्धतियों का उपयोग सुनिश्चित किया जाता है।

पारदर्शिता और प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिक पारदर्शिता लाने के लिए तथा प्रकटीकरण के स्तर को बढ़ाने के लिए विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों के बारे में छमाही रिपोर्टें प्रकाशित करता है। ये रिपोर्टें हर वर्ष मार्च के अंत और सितंबर के अंत की छमाही की स्थिति के आधार पर तैयार की जाती हैं। साथ ही, रिज़र्व बैंक भारत में विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों के स्रोतों में आने वाले परिवर्तनों पर त्रैमासिक आधार पर रिपोर्टें भी प्रकाशित करता है।

इसके अलावा, रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों, विदेशी मुद्रा के बाजारों में उनके परिचालनों, देश की बाहरी परिसंपत्तियों और देयताओं की स्थिति, और विदेशी मुद्रा की परिसंपत्तियों और सोने के नियोजन से होने वाली आय के बारे में जानकारी सार्वजनिक डोमेन पर अपनी आवधिक प्रेस विज्ञप्तियों, साप्ताहिक पूरक विवरणियों, मासिक बुलेटिन, वार्षिक रिपोर्टों आदि के माध्यम से डालता रहता है। पारदर्शिता और प्रकटीकरण के बारे में रिज़र्व बैंक का दृष्टिकोण इस बारे में अंतरराष्ट्रीय आदर्श प्रथाओं का अनुपालन करता है। रिज़र्व बैंक ने अन्य बहुत से केंद्रीय बैंकों के साथ मिलकर विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों के बारे में ब्योरेवार आंकड़ों के प्रकाशन के लिए आईएमएफ के विशेष जानकारी प्रसारण मानकों के [एसडीडीएस] टेम्पलेट

को अपनाया है। ऐसे आंकड़े रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर मासिक आधार पर प्रकाशित किए जाते हैं।

आईएमएफ द्वारा विशेष आहरण अधिकारों का सामान्य आबंटन

एसडीआर होल्डिंग्स किसी देश के एफडीआर के घटकों में से एक है। आईएमएफ अपने सदस्यों को फंड में उनके मौजूदा कोटा के अनुपात में सामान्य एसडीआर आबंटन करता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 23 अगस्त, 2021 को भारत को 12.57 बिलियन (नवीनतम विनिमय दर के अनुसार लगभग 17.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर) विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) का आबंटन किया है। 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार भारत की कुल एडीआर होल्डिंग अब एसडीआर 13.69 बिलियन (नवीनतम विनिमय दर के अनुसार लगभग 18.13 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर) है।

आरबीआई ने 2024 से 2027 तक की अवधि के लिए सार्क मुद्रा स्वेप फ्रेमवर्क की घोषणा की

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार की सहमति से 2024 से 2027 तक की अवधि के लिए सार्क देशों के लिए मुद्रा स्वेप व्यवस्था पर एक संशोधित फ्रेमवर्क तैयार करने का निर्णय लिया है। इस फ्रेमवर्क के तहत, रिज़र्व बैंक ऐसे सार्क केंद्रीय बैंकों के साथ द्विपक्षीय स्वेप करार करेगा, जो स्वेप सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं। उल्लेखनीय है कि सार्क मुद्रा स्वेप सुविधा का परिचालन 15 नवंबर, 2012 को शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य सार्क देशों की अल्पावधि विदेशी मुद्रा चलनिधि आवश्यकताओं या सार्क देशों के भुगतान संतुलन के संकट के लिए दीर्घकालिक व्यवस्थाएं किए जाने तक वित्तपोषण की बैकस्टॉप लाइन उपलब्ध कराना था।

2024-27 के फ्रेमवर्क के तहत, भारतीय रुपये में स्वेप सपोर्ट के लिए विभिन्न रियायतों के साथ एक अलग *आईएनआर* स्वेप विंडो शुरू की गई है। 27 जून, 2024 की स्थिति के अनुसार रुपये सपोर्ट का कुल कार्पस ₹250 बिलियन तय किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक एक पृथक अमेरिकी डॉलर/यूरो स्वेप विंडो के तहत अमेरिकी डॉलर और यूरो में स्वेप व्यवस्था की पेशकश करना जारी रखेगा, जिसका समग्र कॉर्पस 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।

मुद्रा स्वेप सुविधा सभी सार्क सदस्य देशों के लिए उपलब्ध होगी, बशर्ते वे भारत के साथ द्विपक्षीय स्वेप करारों पर हस्ताक्षर करते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक का रिज़र्व प्रबंधन कार्य बाहरी निवेश और परिचालन विभाग (डीईआईओ) द्वारा संभाला जाता है।

अध्याय 20: उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण

ग्राहक केंद्रीयता का तात्पर्य है ग्राहकों की आवश्यकताओं, वरीयताओं और व्यवहारों (विश्व बैंक, 2014) को समझकर समाधान प्रदान करना। ग्राहक के परिप्रेक्ष्य (विश्व बैंक, 2020) से छह सामान्य मुख्य परिणाम उभरकर आते हैं: (क) समुचितता और उपयुक्तता (यानी, ऐसी उच्च स्तरीय सेवाओं की उपलब्धता जो किफायती और उपयुक्त हों); (ख) विकल्प (यानी, विभिन्न उत्पादों/सेवाओं की उपलब्धता); (ग) सुरक्षा और संरक्षा (अर्थात्, धनराशि और सूचना का सुरक्षित रूप से रखा जाना, और सेवा प्रदाताओं द्वारा सूचना की गोपनीयता का सम्मान किया जाना); (घ) औचित्य और सम्मान (यानी, ग्राहकों के हितों का सम्मान और रक्षा करना); (ङ) वाणी (यानी, आसान तरीके से सूचना का आदान-प्रदान, साथ ही, कम लागत पर समस्याओं को जल्दी से दूर करना); और (च) उद्देश्यों को पूरा करना (यानी, वित्तीय उत्पादों या झटके का प्रबंधन करने या अन्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बेहतर स्थिति में होना)। इन मुख्य परिणामों के अनुरूप, ओईसीडी/जी20 'वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण संबंधी उच्च-स्तरीय सिद्धांत' को 2022 में अद्यतन किया गया और सरकार, निगरानीकर्ता निकाय और वित्तीय सेवा प्रदाताओं (ओईसीडी, 2024) के लिए 12 सिद्धांतों की सिफारिश की गई।

भारतीय रिज़र्व बैंक उपभोक्ता संरक्षण के अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू के विषय में प्रतिबद्ध है। उपभोक्ताओं की सुरक्षा तथा वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के बारे में रिज़र्व बैंक का मिशन और मूल उद्देश्य उपभोक्ताओं के संरक्षण को उसके प्रयासों के केंद्र में रखता है। भारतीय रिज़र्व बैंक को, अन्य बातों के साथ-साथ, विधि के अंतर्गत (बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949) ऐसा दायित्व सौंपा गया है जिसमें " *भारतीय रिज़र्व बैंक को जनहित में अथवा बैंकिंग नीति के हित में निदेश देने की शक्तियां; अथवा किसी बैंकिंग कंपनी का कारोबार जमाकर्ताओं के हितों के विपरीत चलाया जा रहा हो तो उसपर रोक लगाने की शक्तियां* " प्रदान की गयी हैं। आरबीआई को इसी प्रकार की शक्तियां गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध में आरबीआई अधिनियम, 1934 और प्रणालीगत सहभागियों से संबंधित संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत प्रदान की गई हैं।

यह उत्तरदायित्व 'उपभोक्ताओं और जमाकर्ताओं' के हितों के सर्वोपरी संरक्षण को स्पष्टतया भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यकलापों के केंद्र में रखता है। रिज़र्व बैंक विनियामक हस्तक्षेप, पर्यवेक्षी नज़र रखने, नैतिक प्रोत्साहन, उपभोक्ता शिक्षण और विनियमित संस्थाओं के उपभोक्ताओं को अपनी शिकायतें रिज़र्व बैंक के हस्तक्षेप के माध्यम से सुलझाने के अवसर प्रदान करते हुए अपना यह कार्य संपन्न करता है। पिछले कुछ वर्षों में रिज़र्व बैंक ने इन उपायों के माध्यम से तथा साथ ही, इस क्षेत्र के विशेषज्ञों का अनुभव और उनके ज्ञान का लाभ उठाने के लिए विभिन्न समितियां गठित करते हुए उपभोक्ता सेवा और बैंक उपभोक्ता संरक्षण का बेहतर तालमेल बिठाया है। इसका इतिहास आर.के.तलवार समिति [1975] गोईपोरिया समिति [1990] और नरसिम्हम समिति [1991] तक पहुंचता है। नरसिम्हम समिति की रिपोर्ट ने अविनियमन के माध्यम से और निजी क्षेत्र के बैंकों को प्रवेश देते हुए बैंकिंग क्षेत्र में न केवल प्रतिस्पर्धा ला दी, बल्कि उपभोक्ताओं के लिए बेहतर उपभोक्ता सेवा को भी सुनिश्चित कर लिया। साथ ही, तारापोर समिति [2003] और दामोदरन समिति [2010] ने बैंकों में उपभोक्ता सेवा के ढांचों को फिर से नए आकार में ढाला। दामोदरन समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशों का इस अध्याय के अंत में बॉक्स -1 में उल्लेख किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक [भा.रि.बैंक] उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए, उपभोक्ता सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए

और बैंकों में तथा रिज़र्व बैंक में भी शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत बनाने के लिए निरंतर आधार पर प्रयास करता रहा है। विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा में लगातार सुधार लाने के प्रयास में मार्च, 2022 में श्री बीपी कानूनगो, पूर्व उप गवर्नर, आरबीआई की अध्यक्षता में "आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओं में ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा संबंधी समिति" गठित की गई। इस समिति ने अप्रैल 2023 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और यह बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वर्तमान में, सिफारिशों पर अमल किया जा रहा है।

बैंकों में ग्राहक सेवा और संरक्षण के लिए उनके बोर्ड स्तर से शुरू करके एक विस्तृत संस्थागत तंत्र को अधिदेशित किया गया है। इस मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक की महत्वपूर्ण पहलें निम्नानुसार हैं क) बैंकों के बोर्ड को ग्राहक सेवा पहलुओं पर विचार-विमर्श करने और छमाही आधार पर विनियामक अनुदेशों के कार्यान्वयन के लिए अधिदेशित करना, ख) बैंकों को बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति गठित करने और आमंत्रित सदस्यों के रूप में ग्राहकों के प्रतिनिधियों को शामिल करने हेतु सूचित करना ताकि बैंक नीतियां तैयार कर सके और बैंकिंग में कॉर्पोरेट शासन संरचना को मजबूत करने के लिए अनुपालन का आकलन कर सके ग) बैंकों को विभिन्न विभागों में ग्राहक सेवा पर स्थायी समिति स्थापित करने के लिए अनिवार्य करना जो कार्यान्वयन प्रक्रिया को चलाने और प्रासंगिक प्रतिक्रिया प्रदान करने वाली सूक्ष्म स्तरीय कार्यकारी समिति के रूप में कार्य कर सकती है, जबकि बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति पहल की देखरेख और समीक्षा/संशोधन करेगी, घ) शाखा स्तर पर ग्राहकों और बैंक के बीच संचार के एक औपचारिक चैनल को प्रोत्साहित करने के लिए शाखाओं में ग्राहक सेवा समितियों की स्थापना के लिए बैंकों को सूचित करना, ङ) बैंकों के लिए अपेक्षित बनाना कि वे ग्राहकों की सेवा और ग्राहकों की शिकायतों को संभालने के लिए बैंक में नोडल विभाग और नोडल अधिकारी नामित करें, च) ग्राहक सेवा, ग्राहक अधिकार, जमाराशियां, चेक संग्रह, ग्राहक क्षतिपूर्ति और ग्राहक शिकायत निवारण पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों को अनिवार्य बनाना।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों तथा भा.रि.बैंक में उपभोक्ता सेवा से संबंधित गतिविधियों का केंद्रीकरण किया जो अब तक रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों द्वारा संपन्न की जाती थीं और उपभोक्ता संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में उसके द्वारा किये जा रहे प्रयासों में और तेजी लाने के लिए दिनांक 01 जुलाई 2006 को '**उपभोक्ता सेवा विभाग**' नामक एक विभाग का गठन किया गया। नवंबर 2014 में रिज़र्व बैंक का फिर से संगठनात्मक ढांचा तैयार करते समय इस उपभोक्ता सेवा विभाग का नाम बदल कर "**उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग**" [सीईपीडी] कर दिया गया और इसे बैंक के "**पर्यवेक्षण और समावेशन क्लस्टर**" में शामिल किया गया। पूर्ववर्ती उपभोक्ता सेवा विभाग के प्रमुख कार्यकलापों में ये बातें शामिल थीं: (i) बैंकों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान की जा रही उपभोक्ता सेवा और शिकायत निवारण से संबंधित अनुदेशों / जानकारी का प्रसारण; (ii) भा.रि.बैंक के विभिन्न कार्यालयों / विभागों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के संबंध में शिकायत निवारण तंत्र की देखरेख करना; (iii) बैंकिंग लोकपाल योजना [बीओ] 2006 चलाना; (iv) बैंकों में उपभोक्ता सेवा पर भारतीय रिज़र्व बैंक में सीधे ही प्राप्त शिकायतों के निवारण को सुनिश्चित करना; (v) उपभोक्ता सेवा और शिकायतों के निवारण से संबंधित मामलों पर बैंक, भारतीय बैंक संघ, बीसीएसबीआई, बैंकिंग लोकपाल के कार्यालय और रिज़र्व बैंक के विनियामक विभागों के बीच संपर्क स्थापित करना तथा (vi) लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट को संपादित करके प्रकाशित करना। विभाग पूर्ववर्ती भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड [बीसीएसबीआई] के लिए नोडल कार्यालय के रूप में कार्य करता रहा।

उपर्युक्त सूचीबद्ध कार्यों के अलावा और कालांतर में सीईपीडी को रिज़र्व बैंक के आरई के ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए

नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करने का कार्य सौंपा गया है जिसके अंतर्गत आरई के आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र के कामकाज की निगरानी करना; लोकपाल कार्यालयों के कार्यनिष्पादन पर निगरानी रखने के साथ-साथ 'रिज़र्व बैंक-एकीकृत लोकपाल योजना, 2021' (आरबी-आईओएस) का नियंत्रण करना; और सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं के साथ-साथ ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के विकल्पों पर जन जागरूकता पैदा करना शामिल हैं।

बैंकिंग लोकपाल योजना [बीओएस]: भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक उपभोक्ताओं के लिए यथोचित उपभोक्ता संरक्षण प्रदान करने की अनिवार्य आवश्यकता को पहचानते हुए भारत में बैंकिंग सेवाओं में स्थित कमियों के बारे में उपभोक्ताओं से प्राप्त हो रही शिकायतों के शीघ्र और सस्ते तरीके से निपटान के लिए वर्ष 1995 में बैंकिंग लोकपाल योजना प्रारंभ की। यह एक वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र है। पिछले वर्षों के दौरान बैंक उपभोक्ताओं के बीच इस योजना को व्यापक स्वीकार्यता मिली है। आरबी-आईओएस, 2021 में शामिल होने से पहले नवंबर 2021 तक इस योजना में इसकी स्थापना के बाद से पांच संशोधन हुए थे, अंतिम संशोधन जुलाई 2017 में किया गया था।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना : गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों [एनबीएफसी] के उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ता संरक्षण उपायों को व्यापक आधार प्रदान करने के लिए जरूरत और आवश्यकताओं के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के उपभोक्ताओं के लिए लोकपाल योजना के स्वरूप में एक ऐसा सस्ता, शीघ्र और वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने के लिए विचार कर रहा है जिस तक आसानी से पहुंचा जा सके । आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45-एल में अधिसूचित इस योजना को प्रारंभ में जमाराशियां स्वीकार करनेवाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-डी) पर लागू की गई तथा बाद में गैर जमा राशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी) जिनकी परिसंपत्तियों का आधार 1 बिलियन रुपये या उससे अधिक है, उपभोक्ताओं के साथ इंटर फेस रखती हैं, पर 26 अप्रैल 2019 तक उक्त योजना की लागू हुई। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की कुछ श्रेणियां, अर्थात परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी, इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण कंपनियां, इन्फ्रास्ट्रक्चर ऋण निधियां, कोर निवेश कंपनियां और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - फैक्टर्स को प्रारंभिक चरणों में शामिल नहीं किया जाएगा। नवंबर 2021 में, इस योजना को आरबी-आईओएस, 2021 में शामिल कर लिया गया।

डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना, 2019: आरबीआई ने उक्त योजना में परिभाषित प्रणालीगत सहभागियों के विरुद्ध ग्राहक शिकायतों के निवारण के लिए 31 जनवरी, 2019 की अधिसूचना के माध्यम से डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना (ओएसडीटी) शुरू की। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 18 के तहत शुरू की गई इस योजना ने आरबीआई द्वारा विनियमित गैर-बैंक संस्थाओं के माध्यम से आयोजित डिजिटल लेनदेन में ग्राहक सेवाओं में कमी से संबंधित निःशुल्क और त्वरित शिकायत निवारण तंत्र प्रदान किया। बैंकों के माध्यम से की जाने वाली डिजिटल लेनदेन से संबंधित शिकायतों को बैंकिंग लोकपाल योजना के तहत नियंत्रित किया जाएगा। बैंकों के माध्यम से किए गए डिजिटल लेनदेनों से संबंधित शिकायतों पर बीओएस 2006 के अंतर्गत कार्रवाई करना जारी रहा। डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल के कार्यालय, बैंकिंग लोकपाल के मौजूदा कार्यालयों के माध्यम से कार्य करते हैं और संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों का निपटारा करते हैं। इस योजना को भी आरबी-आईओएस, 2021 में शामिल कर लिया गया।

रिज़र्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना, 2021: आरबीआई में वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र को आरबीआईआरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओं के ग्राहकों के लिए सरल और अधिक प्रतिक्रियाशील बनाने की दृष्टि से ऊपर चर्चा की गई तीन लोकपाल योजनाओं (बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018; और डिजिटल लेनदेन के लिए लोकपाल योजना, 2019) को रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 में एकीकृत किया गया है। इस योजना की शुरुआत माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 12 नवंबर, 2021 को की गई।

इस योजना ने पूर्ववर्ती लोकपाल योजनाओं के क्षेत्राधिकार-आधारित दृष्टिकोण के विपरीत "वन नेशन वन ओम्बड्समैन" दृष्टिकोण अपनाया। शिकायत की परिभाषा के अंतर्गत सेवा में रहने वाली वे कमियां शामिल हैं, जो कि एक छोटी/ सीमित सूची में समाविष्ट नहीं हैं, शामिल हैं, जबकि पूर्ववर्ती दृष्टिकोण में परिभाषित कारणों को ही शिकायत माना गया। आरबी-आईओएस, 2021 के एक अंग के रूप में किसी भी भाषा में भौतिक रूप से या ई-मेल के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतों की प्राप्ति और प्रारंभिक संसाधन के लिए आरबीआई, चंडीगढ़ में एक केंद्रीकृत प्राप्ति और संसाधन केंद्र (सीआरपीसी) स्थापित किया गया है। इस योजना के तहत लोकपाल के अलावा अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी के रूप में एक अतिरिक्त स्तर का प्रावधान किया गया है, जो उप लोकपाल के नाम से जाने जाते हैं। उन्हें ऐसे प्रकार की शिकायतों, जो कि स्वीकार्य कोटि में नहीं आती हों, को बंद करने का अनुमोदन करने और सुकर के माध्यम से शिकायतों का समाधान करने का अधिकार दिया गया है।

पूर्ववर्ती योजनाओं में शामिल संस्थाओं के अलावा, आरबी-आईओएस, 2021 ने अपने अधिकार क्षेत्र में, ऐसे गैर-अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को भी शामिल किया है, जिनकी जमाराशि पिछले वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षित तुलन-पत्र की तारीख को 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 01 सितंबर, 2022 के प्रभाव से इस योजना को संशोधित करते हुए इसके अंतर्गत क्रेडिट आसूचना कंपनियां (विनियमन) अधिनियम, 2005 में यथा-परिभाषित क्रेडिट सूचना कंपनी को भी इस योजना के प्रयोजन से 'विनियमित संस्था' के रूप में शामिल कर लिया गया है। बैंक की वेबसाइट पर अद्यतन योजना उपलब्ध है।

ग्राहक के अधिकारों का चार्टर : भारतीय रिज़र्व बैंक ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों को बढ़ावा देने के प्रयास के रूप में वर्ष 2014-15 में " उपभोक्ताओं के अधिकारों का चार्टर " बनाया था जिसका स्वरूप उपभोक्ता संरक्षण के व्यापक सिद्धांतों जैसा है और वह प्रथमतः बैंक उपभोक्ताओं के लिए लागू है । इस चार्टर में पांच अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार हैं:

(क) निष्पक्ष व्यवहार का अधिकार

(ख) पारदर्शिता, उचित और प्रामाणिक लेनदेन का अधिकार

(ग) उपयुक्तता का अधिकार

(घ) निजता का अधिकार; और

(ङ) शिकायत निवारण और क्षतिपूर्ति का अधिकार

बैंकों को भी सूचित किया गया है कि वे अपने बोर्ड के अनुमोदन से इन पांच मूलभूत अधिकारों को शामिल करते हुए एक नीति तैयार कराएं और उसमें अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए 'निगरानी तंत्र' को भी शामिल कराएं।

भारतीय रिज़र्व बैंक (विनियमित संस्थाओं के लिए आंतरिक लोकपाल) निदेश, 2023

रिज़र्व बैंक ने आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से 2018 में बैंकों, 2019 में गैर-बैंक प्रणालीगत सहभागियों, 2021 में चुनिंदा एनबीएफसी और 2022 में सीआईसी के लिए आंतरिक लोकपाल (आईओ) तंत्र की स्थापना की। विभिन्न श्रेणी की विनियमित संस्थाओं के आंतरिक लोकपाल संबंधी दिशानिर्देशों में परिचालनगत मामलों को छोड़कर अन्य सभी विशेषताएं समान रूप से शामिल थीं। आईओ के मौजूदा दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन से मिली सीख के आधार पर, उक्त निदेशों में सामंजस्य स्थापित करने का निर्णय लिया गया और तदनुसार, 29 दिसंबर, 2023 को 'भारतीय रिज़र्व बैंक (विनियमित संस्थाओं के लिए आंतरिक लोकपाल), 2023' पर मास्टर निदेश जारी किया गया। इसके अंतर्गत निम्नलिखित बातें शामिल हैं- आंतरिक लोकपाल को प्रस्तुत की जाने वाली शिकायतों की समय-सीमा में एकरूपता लाया गया है; आंतरिक लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत न करने योग्य शिकायतें; आंतरिक लोकपाल की अस्थायी अनुपस्थिति; आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यताएं; रिपोर्टिंग फॉर्मों का अद्यतन किया जाना। इसके अलावा, आंतरिक लोकपाल की सहायता के लिए उप आंतरिक लोकपाल के पद की शुरुआत भी की गई है ताकि शिकायतों के निपटान की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सके। इन अनुदेशों से यह अपेक्षा की जा रही है कि इनसे आंतरिक लोकपाल तंत्र सुदृढ़ बनेगा और आगे विनियमित संस्थाओं में आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली भी सुदृढ़ होगी। ये निदेश निम्नलिखित पर लागू होते हैं:

- अ. भारत में 10 या अधिक बैंकिंग आउटलेट रखने वाले बैंक, चाहे ऐसा बैंक भारत में निगमित हो या भारत के बाहर;
- आ. निम्नलिखित एनबीएफसी: 10 या अधिक शाखाएं रखने वाली जमाराशि स्वीकार करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-डी); ₹ 5,000 करोड़ और उससे अधिक की आस्ति का आकार वाली जमा स्वीकार न करने वाली एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी) और जिनका ग्राहक के साथ सार्वजनिक इंटरफेस हो;
- इ. सभी गैर-बैंकिंग प्रणालीगत सहभागी जिनके पास 31 मार्च, 2023 या उसके बाद बकाया एक करोड़ से अधिक प्री-पेड भुगतान लिखत हैं। हालांकि, यह योजना तब भी लागू रहेगी जब बकाया प्रीपेड भुगतान लिखतों की संख्या बाद की तारीख में निर्धारित सीमा से कम हो जाती है;
- ई. सभी क्रेडिट सूचना कंपनियां।

क्षेत्रीय कार्यालयों में उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण कक्ष : वर्ष 2015-16 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक के समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों में रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं में उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण को आसान बनाने की दृष्टि से उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण कक्ष [सीईपी कक्ष] गठित किए गए थे। इन सीईपी कक्षों के गठन के साथ वित्तीय सेवाओं के उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया गया है जो बैंकिंग लोकपाल [बीओ] योजना के अंतर्गत शामिल न की गई शिकायतों के निवारण के लिए भी एक तंत्र उपलब्ध कराते हैं। आरबी-आईओएस, 2021 के लागू किए जाने के साथ ही सीईपीसी ऐसी संस्थाओं के विरुद्ध शिकायतों पर कार्रवाई करेंगे जो आरबी-आईओएस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। वर्तमान में आरबीआई के विभिन्न कार्यालयों में 32 सीईपीसी कार्य कर रहे हैं।

उपभोक्ता संरक्षण: बैंकिंग के उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण [शिकायत निवारण] तंत्र की उपलब्धता के बारे में तथा जनता को बैंक के नाम में दिए जा रहे अनपेक्षित जाली प्रस्तावों के बारे में चेतावनी देने का रिज़र्व बैंक प्रयास करता रहा है।

टाउन हाल कार्यक्रमों, जागरूकता अभियान, महत्वपूर्ण मेलों, प्रदर्शनियों, व्यापारी मेलों आदि में भाग लेते हुए उपभोक्ताओं में जागरूकता लाने के प्रयास किए जाते हैं। बैंकिंग लोकपाल कार्यालय बैंकिंग लोकपाल योजना, बैंकिंग से संबंधित पहलुओं विशेषतः एटीएम कार्ड, नेट बैंकिंग के उपयोग के बारे में, निधि अंतरण, शिकायत निवारण के अवसरों, शिक्षा ऋणों के बारे में, मुद्रा नोटों की सुरक्षा विशेषताओं के आदि के बारे में जनता के बीच जागरूकता लाने की दृष्टि से टाउन हाल कार्यक्रमों का आयोजन करता है। ये सारे कार्यक्रम स्थानीय भाषाओं में और हिंदी में आयोजित किए जाते हैं।

बैंकिंग लोकपाल अपने-अपने कार्यक्षेत्रों में जागरूकता अभियान आयोजित करते हैं। भारी तादाद में ग्रामीण जनता, स्कूलों और कॉलेजों के छात्र, बैंक उपभोक्ता, सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों के अधिकारी, पेंशनर्स एसोसिएशन, जमाकर्ताओं का एसोसिएशन, आदि ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। बैंकिंग लोकपाल योजना की महत्वपूर्ण विशेषताओं, उनकी प्रयोज्यता के बारे में सहभागियों को जानकारी दी जाती है। ऐसे कार्यक्रम मुख्यतः ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा, बैंकिंग लोकपाल विभिन्न मेलों में, व्यापार प्रदर्शनियों में और अन्य प्रदर्शनों में बैंकिंग लोकपाल योजना की जानकारी देने वाले स्टाल्स और दस्तावेजों का प्रदर्शन तथा जानकारी देनेवाले ब्रोशर आदि लगाते हुए भाग लेते हैं।

जागरूकता पुस्तिकाएं : रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट बी(ए)वेयर पर एक पुस्तिका प्रकाशित की है, जिसमें धोखेबाजों द्वारा प्रयोग की जाने वाली सामान्य कार्यप्रणाली और विभिन्न वित्तीय लेनदेन करते समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दी गई है। 'राजू और चालीस चोर' नामक दूसरी पुस्तिका वित्तीय धोखाधड़ी की कार्यप्रणाली की झलक प्रदान करने के लिए विमोचित की गई, जिसमें ऐसी घटनाओं के संबंध में सुरक्षा उपायों के रूप में क्या करें और क्या न करें के बारे में सरल सुझाव दिए गए हैं। 'एक जागरूक परिवार' नामक तीसरी जागरूकता पुस्तिका मार्च 2024 में प्रकाशित की गई। इस पुस्तिका में वित्तीय धोखाधड़ियों के संबंध में जनसाधारण को मार्गदर्शन प्रदान किया गया है और विभिन्न बैंकिंग सेवाओं व सुविधाओं को लेकर आम तौर पर रहने वाली गलतफहमियों को भी दूर किया गया है। ये पुस्तिकाएं हिंदी और अंग्रेजी के अलावा अनेक क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध हैं।

उपभोक्ता शिक्षा के एक भाग के रूप में सस्ती निधियों/लॉटरी के फर्जी प्रस्तावों, भारतीय रिज़र्व बैंक के ग्राहक संरक्षण विनियमों, सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग और शिकायत निवारण के अवसरों के बारे में आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से प्रिंट मीडिया, रेडियो और टेलीविजन में विज्ञापन अभियान भी चलाए जाते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक सहित सरकारी प्राधिकरणों के नाम पर किए जाने वाले जाली प्रस्तावों के संबंध में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के महत्वपूर्ण पहलुओं की भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समीक्षा की गई है और बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अपने प्रमुख विज्ञापनों की विषय-वस्तु से ध्यान विचलित किए बिना अपने सभी प्रचार विज्ञापनों में मानक संदेशों को भी शामिल करें। बैंक द्वारा परिकल्पित उपभोक्ता शिक्षण पहलों को बढ़ावा देने के लिए, लोकपाल और आरबीआई के वरिष्ठ अधिकारी देश भर में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के विभिन्न पहलुओं के संबंध में जनता/बैंकों के ग्राहकों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं।

आरबीआई कहता है - जन जागरूकता के लिए रिज़र्व बैंक की एक पहल : उपभोक्ता शिक्षण संबंधी पहलों को बढ़ावा देने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक द्वारा एक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत एसएमएस संदेशों के

माध्यम से आम जनता को बैंकिंग विनियमों एवं उन्हें उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं से अवगत कराया जाता है। शुरुआती तौर पर , रिज़र्व बैंक ने ई मेल / एसएमएस / फोन कॉल के ज़रिए आम जनता को अनपेक्षित और जाली प्रस्तावों से बचने के बारे में चेतावनी संदेश भेजना शुरू किया। यह सावधानी संदेश आरबीआईसे के सेंडर आईडी से भेजा गया है।

वर्ष 2022 में सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं, रिज़र्व बैंक के एजीआर तंत्र और उपभोक्ता के हित संरक्षण संबंधी मौजूदा विनियमों के बारे में वित्तीय उपभोक्ता जागरूकता के व्यापक प्रचार-प्रसार को साकार करने के लिए एक अखिल भारत स्तरीय जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान को 'आज़ादी के अमृत महोत्सव' के अवसर पर बहु-आयामी वित्तीय जागरूकता अभियान के रूप में कई चरणों में चलाया गया। इस अभियान के चीन चरण थे, नामतः लोकपाल स्पीक कार्यक्रम, उच्च प्रबंध तंत्र का टॉकाथॉन, और पूर्ण मासिक राष्ट्र-व्यापी गहन जागरूकता कार्यक्रम (एनआईएपी)।

लोकपाल स्पीक: वर्ष 2022 से रिज़र्व बैंक विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस (15 मार्च) को देश भर के क्षेत्रीय मल्टी-मीडिया चैनलों में "लोकपाल स्पीक" कार्यक्रम आयोजित करता रहा है ताकि रिज़र्व बैंक शिकायत निवारण तंत्र के साथ-साथ डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी संबंधी सुरक्षा उपायों के बारे में दूरदराज के इलाकों में उपभोक्ताओं/ग्राहकों को जागरूक बनाया जा सके।

शीर्ष प्रबंधन का टॉकाथॉन: आरबीआई के वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा 29 अगस्त, 2022 को नई दिल्ली कार्यालय में टॉकाथॉन/मीडिया इंटरैक्शन आरबीआई के एजीआर ढांचे पर जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजित किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आरबी-आईओएस, 2021 की मुख्य विशेषताओं, शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया, शिकायत दर्ज करने के लिए क्या करें और क्या न करें, शिकायतों के समाधान के विभिन्न तरीके आदि शामिल थे।

राष्ट्रव्यापी गहन जागरूकता कार्यक्रम (एनआईएपी): एनआईएपी के अंतर्गत विनियमित संस्थाओं के सहयोग से 1 से 30 नवंबर, 2022 तक महीने भर चलने वाले जागरूकता कार्यक्रमों को शामिल किया गया ताकि देश के कोने-कोने में उनका लाभ उठाया जा सके। अभियान के दौरान आम जनता के साथ विभिन्न संवादमूलक/इंटरफेस कार्यक्रमों के अलावा प्रिंट, मल्टीमीडिया चैनलों, आरबीआई वेबसाइट, 'आरबीआई सेस', इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पॉंस सिस्टम और 'आरबीआई कहता है' आदि के माध्यम से जागरूकता संदेश प्रसारित किए गए। जनता तक पहुंचने के लिए नियमित जन जागरूकता अभियानों के साथ-साथ कई नवीन रणनीतियां अपनाई गईं, जिनके अंतर्गत लोक कला, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो, स्किट, जादू शो, नुक्कड़ नाटक, खेलकूद प्रतियोगिताएं, फ्लैश मॉब, रैलियां, हाफ-मैराथन, साइकिलथॉन, मानव श्रृंखला का गठन, वर्ग पहेली आदि शामिल थे। रिज़र्व बैंक समय-समय पर प्रेस विज्ञप्तियों (<https://www.rbi.org.in/Scripts/RBICautions.aspx>) के माध्यम से फर्जी प्रस्तावों के प्रति जनता को सचेत भी करता रहा है। 'आरबीआईसे' की पहल के साथ, यह उसी मीडिया (एसएमएस और ईमेल) का उपयोग कर रहा है जो धोखेबाजों द्वारा उपयोग किया जाता है। जनसाधारण के सदस्य 14440 पर मिस्ड कॉल देकर फर्जी कॉल/ईमेल पर इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पॉंस सिस्टम (आईवीआरएस) के माध्यम से अधिक जानकारी प्राप्त करने के साथ ही, चिट फंड में किस प्रकार समझदारी व सावधानी से निवेश किया जा सकता है, इसकी भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वे ई-मेल के माध्यम से इस अभियान के संबंध में फीड बैक दे सकते हैं।

शिकायत प्रबंध प्रणाली: भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए प्राप्त हो रही शिकायतों की मात्रा का प्रबंध करने के लिए 24 जून 2019 को वेब आधारित शिकायत प्रबंध प्रणाली [सीएमएस] की शुरुआत की है। इस वेब आधारित शिकायत प्रबंध प्रणाली ने पूर्ववर्ती शिकायत ट्रेकिंग प्रणाली (सीटीएस) का स्थान ले लिया है, जो लगभग एक दशक से अधिक अवधि के लिए काम कर रही थी। सीएमएस प्रणाली रिज़र्व बैंक को न केवल शिकायतों का प्रबंध करने में सहायता प्रदान करती है बल्कि मजबूत शिकायत प्रबंध सूचना प्रणाली भी उपलब्ध कराती है। साथ ही, वह आंकड़ों की विश्लेषिकी भी उपलब्ध कराती है और शिकायतों की प्रवृत्ति का अध्ययन करना भी संभव बनाएगी। साथ ही, यह सुचारु सूचना प्रवाह को साकार करते हुए शिकायतों के दक्षतापूर्ण प्रबंधन के लिए सीएमएस प्लेटफॉर्म पर लोकपाल कार्यालयों, सीईपी कक्षों और बैंकों को एक साथ लाकर बैंक में शिकायत निवारण तंत्र को एकीकृत करती है। इससे बैंकिंग सेवाओं के शिकायत प्रवण क्षेत्रों में कार्रवाई करने के प्रयासों को सक्रिय बल मिलता है जिससे शिकायत निवारण की प्रक्रिया में गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। सीएमएस ने शिकायत प्रबंधन और निवारण के क्षेत्र में विनियमित संस्थाओं के कार्यनिष्पादन पर निगरानी व्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाया है। सीएमएस की 24x7 उपलब्धता और संपूर्ण डिजिटलीकरण (एंड-टु-एंड डिजिटाइजेशन) ने लोकपाल और सीईपी कक्षों का निर्बाध और दक्षतापूर्वक कार्यसंचालन लगातार सुनिश्चित किया जाता है, यहां तक कि महामारी की अवधि में लगाए गए लॉकडाउन में भी कार्यसंचालन जारी रहा। आरबी-आईओएस, 2021 को समर्थन प्रदान करने के लिए 2021 में सीएमएस को नवीकृत किया गया। विशेष रूप से दृष्टिबाधित उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से 2024 में सीएमएस प्लेटफॉर्म में अतिरिक्त ऑडियो कैप्चा का विकल्प उपलब्ध कराया गया है।

बैंकों को अपने शिकायत निवारण तंत्र में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु हतोत्साहन सह प्रोत्साहन ढांचे की स्थापना

बैंकों के आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र की प्रभावकारिता को सुदृढ़ करने और उसमें सुधार लाने तथा बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से, कतिपय उपायों को शामिल करते हुए एक व्यापक ढांचा तैयार किया गया है। इन उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें शामिल हैं: ग्राहकों की शिकायतों पर बैंकों और रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकटीकरण के स्तर को बेहतर बनाना; बैंकों से शिकायत निवारण की लागत की वसूली उस स्थिति में करना जब स्वीकार्य स्वरूप की शिकायतों की संख्या उनके प्रतिस्पर्धी बैंकों के औसत स्तर से बढ़ जाती हो; शिकायत निवारण तंत्र की गहन समीक्षा; तथा ऐसे बैंकों के विरुद्ध पर्यवेक्षी/ विनियामकीय कार्रवाइयां करना जो समयबद्ध तरीके से शिकायत निवारण तंत्र में सुधार करने में विफल रहते हों।

केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र: इस केंद्र की स्थापना, ई-मेल, डाक या दस्ती सुपुर्दगी द्वारा प्राप्त होने वाली शिकायतों की प्राप्ति के लिए एकल केंद्र के रूप में कार्य करने हेतु चंडीगढ़ में एकीकृत लोकपाल योजना की शुरुआत के पूर्वगामी के रूप में की गई। सीआरपीसी भौतिक शिकायतों को डिजिटल रूप में तैयार करता है और भौतिक रूप से एवं शिकायत प्रबंध प्रणाली में सीआरपीसी को ई-मेल के माध्यम से शिकायतों के प्रारंभिक प्रसंस्करण और पंजीकरण करता है, जबकि वर्तमान ये शिकायतें ओआरबीआईओ और सीईपीसी में प्राप्त की जा रही हैं।

आरबीआई में शिकायत निवारण तंत्र के संबंध में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने और आरबीआई की जागरूकता संबंधी पहलकदमियों को बढ़ाने की दृष्टि से शिकायतों के संबंध में आने वाले कॉलों का प्रबंधन करने के लिए सीआरपीसी (14448) पर एक संपर्क केंद्र स्थापित किया गया है। वर्तमान में इस संपर्क केंद्र द्वारा अंग्रेजी, हिंदी और दस स्थानीय भाषाओं में कॉलों

का उत्तर दिया जा रहा है। इसके अलावा, ग्राहक के कॉलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रिज़र्व बैंक के संपर्क केंद्र में एक कार्यनीतिपरक प्रगति हुई है जिसका उद्देश्य ग्राहक की संतुष्टि के स्तर और परिचालनगत दक्षता को बढ़ाना है। चंडीगढ़ में स्थित मौजूदा एकल संपर्क केंद्र को तकनीकी तौर पर उन्नत बनाया गया है, साथ ही, भुवनेश्वर और कोच्चि में अतिरिक्त सुविधों से युक्त डीआर और बीसीपी सुविधाएं स्थापित की गई हैं। ये उन्नत संपर्क केंद्र रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण के अंतर्गत आउटसोर्स किए हुए एजेंटों के साथ हाईब्रिड तरीके से परिचालन कर रहे हैं। गुणवत्ता विश्लेषक और संपर्क केंद्र प्रबंधक जैसी विशिष्ट भूमिकाएं ग्राहकों के साथ संपर्क व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर देते हुए सेवा की गुणवत्ता को और बढ़ाने में योगदान करती हैं।

आरबी-आईओएस, सीआरपीसी और संपर्क केंद्र पर संतुष्टि सर्वेक्षण

विभाग ने अप्रैल-मई 2022 के दौरान ऐसे ग्राहकों के लिए एक संतुष्टि सर्वेक्षण कराया, जिन्होंने अपने वित्तीय सेवा प्रदाताओं, जो रिज़र्व बैंक की विनियमित संस्था हैं, द्वारा अपनी शिकायतों पर संतोषजनक तरीके से निपटान नहीं किए जाने के संबंध में अपनी शिकायतों के निवारण के लिए आरबीआईओ से संपर्क किया था। साथ ही, सीआरपीसी और चंडीगढ़ में स्थित संपर्क केंद्र के संबंध में संतुष्टि के स्तर का पता लगाने के लिए उन्हें शामिल किया गया था। लगभग 60 प्रतिशत उत्तरदाता रिज़र्व बैंक लोकपाल द्वारा प्रदान किए गए समग्र समाधान से संतुष्ट थे और 58.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बताया कि संपर्क केंद्र के कार्यपालक तक पहुंचने में लगने वाला प्रतीक्षा समय/ प्रयास औचित्यपूर्ण हैं। सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार, 60.1 प्रतिशत उत्तरदाता आरबी-आईओएस के तहत पंजीकरण, शिकायत को संभालने और समाधान के समय सहित समग्र प्रक्रिया से संतुष्ट थे।

गुप्त निरीक्षण: रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से देश में बैंक शाखाओं में गुप्त निरीक्षण किए जाते हैं। तत्काल डेटा उपलब्धता और बेहतर डेटा विश्लेषण के लिए रिपोर्ट प्रस्तुतीकरण को डिजिटल किया गया है। प्रभावी आंकड़ा संग्रहण के लिए गुप्त निरीक्षणों की जांच सूचियों को भी नियमित रूप से संशोधित किया जा रहा है। इन निरीक्षणों के निष्कर्षों का उपयोग अब सक्रिय रूप से पर्यवेक्षी और विनियामक इनपुटों के लिए फीडबैक के रूप में किया जा रहा है।

अध्याय 21: वित्तीय समावेशन और विकास

वित्तीय समावेशन को “वंचित वर्गों जैसे कमजोर वर्गों और निम्न-आय समूहों के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने, समय पर और उचित लागत पर पर्याप्त क्रेडिट उपलब्ध कराने की प्रक्रिया” के रूप में परिभाषित किया गया है। (वित्तीय समावेशन पर समिति - अध्यक्ष: डॉ. सी. रंगराजन, आईबीआई, 2008)। “वित्तीय समावेशन की मध्यकालिक मार्गदर्शिका समिति” (अध्यक्ष: श्री दीपक मोहंती, आरबीआई, 2015) ने वित्तीय समावेशन के लिए दृष्टिकोण निर्धारित किया है, जो इस प्रकार है, छोटे और सीमांत किसानों और निम्न-आय वाले परिवारों के लिए बुनियादी वित्तीय उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध कराना, जैसे – उचित लागत पर बचत, धन-प्रेषण, ऋण, सरकारी समर्थन प्राप्त बीमा और पेंशन उत्पाद, पर्याप्त सुरक्षा के साथ सामाजिक नकद हस्तांतरण सुविधा। इसके अलावा छोटे और सीमांत उद्यमों की औपचारिक वित्त तक पहुँच बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी पर अधिक निर्भरता लाना, ताकि लागतों को कमी की जा सके और सेवा वितरण में सुधार हो सके।”

वित्तीय समावेशन को दुनिया भर में आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के एक महत्वपूर्ण चालक के रूप में तेजी से पहचाना जा रहा है। औपचारिक वित्त तक पहुँच नौकरी सृजन को बढ़ावा दे सकती है, आर्थिक झटकों के प्रति संवेदनशीलता को कम कर सकती है और मानव संसाधन में निवेश को बढ़ा सकती है। यदि औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पर्याप्त पहुँच नहीं होती, तो व्यक्तियों और व्यवसायों को अपनी सीमित संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ता है या फिर अपने वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने और विकास के अवसरों का लाभ उठाने के लिए महंगे अनौपचारिक वित्तीय स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। समग्र स्तर पर, अधिक वित्तीय समावेशन सभी के लिए सतत और समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास का समर्थन कर सकता है। एक सतत और समावेशी वित्तीय विकास के लिए, वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता को जुड़ी हुई दो मुख्य स्तंभ माना जाता है। वित्तीय समावेशन आपूर्ति पक्ष पर काम करता है, यानी पहुँच निर्माण के लिए, और वहीं, वित्तीय साक्षरता मांग पक्ष पर काम करती है, अर्थात् वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के लिए मांग उत्पन्न करती है। उपभोक्ता सुरक्षा, सतत और समावेशी वित्तीय विकास का तीसरा स्तंभ है, और इसे इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के उपभोक्ताओं को अहम वित्तीय मामलों के बारे में सोच-समझकर निर्णय लेने के लिए उचित वित्तीय शिक्षा की आवश्यकता है।

वित्तीय समावेशन की आवश्यकता

वित्तीय समावेशन वित्तीय प्रणाली के संसाधन आधार को व्यापक बनाता है, बड़े जनसंख्यक वर्ग में बचत की संस्कृति विकसित करके और आर्थिक विकास की प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाता है। इसके अलावा, कम आय वाले समूहों को औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र के दायरे में लाकर, वित्तीय समावेशन उनके वित्तीय संपत्ति और अन्य संसाधनों को आपातकालीन परिस्थितियों में सुरक्षित रखता है। यह उच्च ब्याज दरों वाले साहूकारों द्वारा कमजोर वर्गों का शोषण भी कम करता है, क्योंकि यह औपचारिक क्रेडिट तक आसान पहुँच प्रदान करता है। वित्तीय समावेशन भारत में एक बहुप्रत्याशित नीति उद्देश्य है और आर्थिक नीति हमेशा सतत और समावेशी विकास के अंतर्निहित उद्देश्य से प्रेरित रही है।

वित्तीय समावेशन²⁹ 2030 के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का एक महत्वपूर्ण संवर्धक है, जहाँ यह गरीबी उन्मूलन, लिंग समानता, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और असमानता को कम करने सहित सात समृद्ध लक्ष्यों में एक लक्ष्य के रूप में शामिल है। भारत में भी नीति निर्माताओं, जैसे कि भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक, ने गरीबी के वित्तीय स्थिरता पर प्रभाव को पहले ही पहचान लिया था और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए हैं कि गरीबी को उसके सभी रूपों में संबोधित किया जाए और आर्थिक विकास के लाभ समाज के गरीब और बहिष्कृत वर्गों तक पहुंचें।³⁰

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

हालांकि वित्तीय समावेशन एक नया शब्द है, भारत में बैंकिंग क्षेत्र के माध्यम से समावेशी आर्थिक विकास की कोशिशों का लंबा इतिहास रहा है। सरकार या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग क्षेत्र में उठाए गए कदमों में आदेशों, वैकल्पिक संरचनाओं और नवाचारों के रूप में पहल की गई। बैंकिंग के समावेशी विकास की दिशा में शायद पहला कदम 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण और बाद में 1980 में हुआ। 1969 में “लीड बैंक योजना” शुरू की गई, और 1972 में प्राथमिक क्षेत्र ऋण दिशानिर्देश जारी किए गए। 1975 तक, ग्रामीण बैंकिंग के लिए जमीनी स्तर पर नई संरचनाओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कृषि और ग्रामीण वित्त के लिए एक उच्चतम एजेंसी के रूप में की गई। 1988 में बैंकों को सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। 1990 के दशक में स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों (LAB) की स्थापना और स्वयं सहायता समूह-बैंक लिंक योजना की शुरुआत हुई। सदी की शुरुआत में कई पहलों की शुरुआत हुई, जिसमें वित्तीय समावेशन (FI) को एक मुख्य बैंकिंग उद्देश्य के रूप में शामिल करना और “बिजनेस कॉर्रेस्पोंडेंट” (BC) मॉडल भी था। इसके साथ ही, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को वित्तीय समावेशन के लिए एक संरचित और योजनाबद्ध दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें उच्चतम स्तर पर प्रतिबद्धता दिखाई गई, इसके तहत बोर्ड-स्वीकृत वित्तीय समावेशन योजनाओं की तैयारी की गई। 2010-13 और 2013-16 के दौरान पहले दो चरणों में FIPs का कार्यान्वयन किया गया, जो 2014-15 में प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के कार्यान्वयन के साथ हुआ, जिससे आपूर्ति पक्ष के प्रयासों को पर्याप्त बढ़ावा मिला। वित्तीय समावेशन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए गति बनाए रखने के लिए, बैंकों के लिए FIP लक्ष्य निर्धारित करते हुए वित्तीय समावेशन योजनाओं का तीसरा चरण 2016-19 में बैंकों की प्रगति की अधिक सूक्ष्म निगरानी पर केंद्रित था। भारत में वित्तीय समावेशन योजनाओं का चौथा चरण (2022-2024) डिजिटल वित्तीय सेवाओं को बढ़ावा देने, कम सेवा प्राप्त क्षेत्रों में पहुंच को गहरा करने, वित्तीय साक्षरता में सुधार करने और समग्र वित्तीय समावेशन के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर केंद्रित था। भारत में वित्तीय समावेशन योजनाओं का पांचवां चरण (2024-2026) सार्वभौमिक बैंकिंग पहुंच प्राप्त करने, डिजिटल वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने, कम सेवा प्राप्त क्षेत्रों को ऋण उपलब्धता बढ़ाने, वित्तीय साक्षरता और उपभोक्ता सुरक्षा में सुधार करने, प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा देने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और समावेशी विकास के लिए बैंकों, फिनटेक कंपनियों और अन्य संबंधित पक्षों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। भारतीय रिज़र्व बैंक के भीतर, इस कार्य को बाहरी पर्यावरण और राज्य सार्वजनिक नीति उद्देश्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित किया

²⁹ <https://www.uncdf.org/financial-inclusion-and-the-sdgs?ref=hackernoon.com>

³⁰ श्री एसएस मुंद्रा, पूर्व उप गवर्नर, आरबीआई, भारत में वित्तीय समावेशन – अब तक की यात्रा और आगे का राह, सितंबर 2016

गया है। कृषि ऋण विभाग 1982 में नाबार्ड के गठन के बाद ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग (आरपीसीडी) के रूप में विकसित हुआ। बैंक के फोकस को ध्यान में रखते हुए, इस विभाग का नाम पुनः बदलकर 2014 में वित्तीय समावेशन और विकास विभाग (एफआईडीडी) रखा गया।

कानूनी ढांचा

RBI अधिनियम 1934 की धारा 54 के तहत, भारतीय रिज़र्व बैंक को ग्रामीण ऋण और विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ कर्मचारियों को बनाए रखने का अधिकार है और विशेष रूप से यह नाबार्ड को विशेषज्ञ मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर सकता है तथा उन क्षेत्रों में विशेष अध्ययन कर सकता है, जिन्हें यह आवश्यक समझे, ताकि एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा दिया जा सके। इस भूमिका के तहत RBI की प्रमुख भूमिका और कार्यों का सारांश इस प्रकार है:

- ग्रामीण ऋण और प्राथमिक क्षेत्र ऋण से संबंधित नीतियों का निर्माण, जिसमें विशेष रूप से कृषि, सूक्ष्म और लघु उद्यमों और कमजोर वर्गों को ऋण प्रवाह बढ़ाने पर जोर दिया गया है।
- व्यावसायिक बैंकों के प्राथमिक क्षेत्र ऋण में मात्रा और गुणवत्ता प्रदर्शन का मूल्यांकन।
- नाबार्ड/एनएचबी/सिडबी/मुद्रा लिमिटेड द्वारा प्रशासित विभिन्न फंड्स में वाणिज्यिक बैंकों का योगदान से संबंधित नीतियों से निपटना, खासकर प्राथमिक क्षेत्र ऋण लक्ष्यों को प्राप्त न करने पर।
- वित्तीय समावेशन पहलों का संचालन और वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों की निगरानी।
- लीड बैंक योजना का कार्यान्वयन और निगरानी।
- एमएसएमई क्षेत्र को ऋण प्रवाह के मार्गदर्शन और नीतियों का निर्माण।
- विभिन्न कानूनी प्रावधानों के आधार पर NABARD से संबंधित कार्य।
- वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 54 के अनुसार, बैंक ग्रामीण ऋण और विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ स्टाफ रख सकता है और विशिष्टता नाबार्ड को विशेषज्ञ मार्गदर्शन और सहायता दे सकता है तथा एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए ऐसे क्षेत्रों में विशेष अध्ययन कर सकता है, जो वह ऐसा करना आवश्यक समझे।

इस भूमिका के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रमुख भूमिका और कार्यों का सारांश निम्नानुसार है:-

- कृषि, सूक्ष्म और लघु उद्यमों और कमजोर वर्गों के लिए ऋण प्रवाह बढ़ाने पर विशेष जोर देने के साथ ग्रामीण ऋण और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण से संबंधित नीति निर्माण।
- प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण में वाणिज्यिक बैंकों के मात्रात्मक और गुणात्मक प्रदर्शन का आकलन।
- प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार लक्ष्यों की प्राप्ति न होने के कारण नाबार्ड/एनएचबी/सिडबी/मुद्रा लिमिटेड द्वारा नियंत्रित विभिन्न निधियों में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा योगदान से संबंधित नीतियों से निपटना।
- वित्तीय समावेशन पहल और वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों की निगरानी

- अग्रणी बैंक योजना का कार्यान्वयन और निगरानी
- नीतियां बनाना और एमएसएमई क्षेत्र को ऋण के प्रवाह का मार्गदर्शन करना
- विभिन्न सांविधिक प्रावधानों के आधार पर नाबार्ड के साथ व्यवहार
- वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना

वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत तंत्र

चूंकि प्रभावी वित्तीय समावेशन के लिए एक बहु-हितधारक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, RBI के वित्तीय समावेशन प्रयासों में वित्तीय क्षेत्र के नियामकों, सरकार, विकासात्मक वित्तीय संस्थाओं (जैसे NABARD और SIDBI) और विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय शामिल है। यह कार्य की विशालता को ध्यान में रखते हुए आवश्यक है, विशेष रूप से देश के आकार और जनसंख्या के संदर्भ में। संस्थागत संरचना में शामिल हैं:

- वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी), जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है और इसमें सभी वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के प्रमुख शामिल होते हैं। इस परिषद का एक महत्वपूर्ण कार्य वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है।
- वित्तीय समावेशन क्षेत्र में प्रमुख हितधारकों के बीच प्रभावी समन्वय की अत्यधिक महत्ता को देखते हुए, वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता पर तकनीकी समूह (टीजीएफआईएफएल), जो आरबीआई के उप गवर्नर की अध्यक्षता में कार्य करता है, यह सुनिश्चित करता है कि वित्तीय समावेशन पहलों के लिए केंद्रित और समन्वित दृष्टिकोण अपनाया जाए, लक्ष्यों की निगरानी की जाए और वित्तीय समावेशन की अंतरराष्ट्रीय रणनीतियों पर कार्य किया जाए। टीजीएफआईएफएल की स्थापना नवंबर 2011 में वित्तीय विकास परिषद की उपसमिति के निर्णय पर की गई थी, और इसमें सभी वित्तीय क्षेत्र के नियामकों, भारत सरकार के आर्थिक मामलों और वित्तीय सेवाओं विभागों तथा नाबार्ड के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
- देश भर में बैंकों के स्तर पर एक मजबूत संस्थागत तंत्र की स्थापना की गई है, जिसमें सभी राज्यों में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी), सभी जिलों में जिला परामर्श समिति (डीसीसी) और जिला स्तर समीक्षा समिति (डीएलआरसी), और सभी ब्लॉकों में ब्लॉक स्तरीय बैंकर्स समिति (बीएलबीसी) शामिल हैं।
- वित्तीय समावेशन पहलों के लिए फोकस्ड फंडिंग समर्थन की बात करें तो, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट फंड (पीआईडीएफ), जिसे 2021 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लागू किया गया, देश के तीसरे से छठे श्रेणी के केंद्रों और उत्तर-पूर्वी राज्यों में पॉइंट्स ऑफ सेल (पीओएस) इंफ्रास्ट्रक्चर (भौतिक और डिजिटल मोड्स) की तैनाती के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। वित्तीय समावेशन फंड (एफआईएफ), जो नाबार्ड द्वारा प्रशासित किया जाता है, विकासात्मक और प्रचारात्मक गतिविधियों का समर्थन करता है, जिसमें देश भर में वित्तीय समावेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, विभिन्न हितधारकों की क्षमता निर्माण, और मांग पक्ष के मुद्दों को संबोधित करने के लिए जागरूकता निर्माण करना शामिल है।
- वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) और वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफ़ेल), जो बैंकों द्वारा स्थापित किए गए हैं और

वित्तीय समावेशन फंड (एफआईएफ) और डिपोजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस (डीईए) फंड के सहारे स्थापित किए गए हैं, वित्तीय समावेशन उपायों को पूरा करने के लिए वित्तीय साक्षरता प्रदान कर रहे हैं और इसे बढ़ावा दे रहे हैं।

- स्टैंडिंग एडवाइजरी कमेटी (एसएसी), जो एमएसएमई क्षेत्र को संस्थागत ऋण प्रवाह की समीक्षा करती है, एक उच्च स्तरीय मंच है जिसे 1986 में आरबीआई द्वारा उप-गवर्नर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। इस समिति में वित्त मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, सिडबी, खादी और ग्राम उद्योग आयोग (केवीआईसी), चयनित बैंक, आईबीए और एमएसएमई संघों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
- एमएसएमई पर सशक्त समितियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थापित की जाती हैं, जिनकी अध्यक्षता क्षेत्रीय निदेशकों द्वारा की जाती है और इसमें एसएलबीसी के संयोजक, वरिष्ठ बैंक अधिकारी, सिडबी, राज्य सरकार और राज्य के एमएसएमई संघों के प्रतिनिधि होते हैं। ये समितियाँ एमएसएमई वित्तपोषण में प्रगति की नियमित समीक्षा करती हैं और तनावग्रस्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों के पुनर्जीवन और पुनर्वास पर भी ध्यान केंद्रित करती हैं। समिति अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं और राज्य सरकार के साथ समन्वय करती है, ताकि किसी भी अड़चन को दूर किया जा सके और इस क्षेत्र को ऋण का सहज प्रवाह सुनिश्चित हो सके।

व्यापार संवाददाता

वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और बैंकिंग क्षेत्र की पहुंच को बढ़ाने के उद्देश्य से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2006 में बैंकों को वित्तीय और बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए बिचौलियों को व्यापार सहयोगी (बीएफ) या व्यापार प्रतिनिधि (बीसी) के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी। इसके अनुसार, बैंक और उनके विस्तारित अंग, जैसे व्यापार प्रतिनिधि, अपनी व्यापक पहुंच और लोगों से जुड़ाव के कारण वित्तीय समावेशन के तहत उठाए गए उपायों के मुख्य केंद्र बने। व्यापार प्रतिनिधियों की नियुक्ति के लिए दिशा-निर्देश समय-समय पर अपडेट किए गए हैं³¹।

अब BCs को बैंकों के एजेंट के रूप में बैंक परिसर के बाहर बैंकिंग कार्य करने की अनुमति दी गई है। उन संस्थाओं की श्रेणियों को भी स्पष्ट किया गया है जो बीसी के रूप में कार्य कर सकती हैं। बीसी की गतिविधियों का दायरा निम्नलिखित कार्यों तक विस्तृत हो सकता है: उधारकर्ताओं की पहचान करना, ऋण आवेदन पत्रों का संग्रह और प्रारंभिक प्रसंस्करण, जिसमें प्राथमिक जानकारी/डेटा का सत्यापन शामिल है, बचत और अन्य उत्पादों के बारे में जागरूकता फैलाना धन प्रबंधन और ऋण परामर्श के संबंध में शिक्षा और सलाह देना बैंकों को आवेदन प्रसंस्करण और प्रस्तुत करना, स्व-सहायता समूह / संयुक्त देयता समूह / क्रेडिट समूह/अन्य का प्रचार, पोषण और निगरानी, ऋण स्वीकृति के बाद निगरानी और वसूली के लिए अनुवर्तन किया जाना शामिल है। बीसी को उनके कार्यों के लिए बैंक द्वारा कमीशन/फीस का भुगतान किया जाता है।

BC संरचना को मजबूत करने के लिए, भारतीय बैंक संघ (IBA) ने एक वेब पोर्टल (बीसी रजिस्ट्रि) विकसित किया है, जिसमें BCs का विवरण शामिल है। इसमें जनता के उपयोग के लिए एक अलग टैकर भी है। यह न केवल BCs के कार्यों पर अधिक

³¹ शाखा प्राधिकार पर मास्टर परिपत्र - डीबीओडी नहीं। बीएपीडी। ईसा पूर्व। 7/22.01.001/2014-15 दिनांक 01 जुलाई, 2014 (पैरा 8)

निगरानी सुनिश्चित करेगा, बल्कि अंतिम उपभोक्ताओं को अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल जानकारी भी प्रदान करेगा। वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने और अंतिम छोर तक वित्तीय सेवाओं की प्रभावी पहुंच में बीसी की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में, BCs के कौशल को उन्नत करना आवश्यक है ताकि वे विकसित होती आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने IBA के माध्यम से BCs के लिए एक समान प्रमाणन प्रक्रिया के तहत क्षमता निर्माण कार्यक्रम की परिकल्पना की और इसे लागू किया। BC प्रमाणन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में प्रशिक्षण को अनिवार्य कर दिया गया है।

शाखाओं को फिर से परिभाषित करना और आउटरीच के अनुमेय तरीके

वित्तीय समावेशन को सुविधाजनक बनाने और वितरण चैनल के चयन में लचीलापन प्रदान करने के उद्देश्य से, शाखाओं और अनुमेय पहुंच विधियों को 2017⁴ में पुनर्परिभाषित किया गया। यह पुनर्परिभाषा बैंकों की विभिन्न विशेषताओं और प्रदान की जाने वाली सेवाओं के प्रकार को ध्यान में रखते हुए की गई।

निर्देशों में "बैंकिंग आउटलेट - पूर्णकालिक/अंशकालिक" की परिभाषा दी गई है।

डोमेस्टिक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक के लिए 'बैंकिंग आउटलेट' एक स्थायी सेवा वितरण इकाई है, जिसे बैंक के कर्मचारी या उसके बिजनेस कॉरिस्पॉन्डेंट द्वारा संचालित किया जाता है। इस आउटलेट पर निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जाती हैं:

- जमा स्वीकार करना,
- चेक/नकद निकासी का भुगतान, या
- धन उधार देना।

यह सेवाएं न्यूनतम 4 घंटे प्रतिदिन और सप्ताह में कम से कम 5 दिन उपलब्ध कराई जाती हैं।

बैंकिंग आउटलेट पर एक समान साइनबोर्ड होता है, जिसमें बैंक का नाम और अधिकृत जानकारी, नियंत्रण प्राधिकरणों का संपर्क विवरण और शिकायत समाधान तंत्र की जानकारी दी जाती है। जो बैंकिंग आउटलेट प्रतिदिन न्यूनतम 4 घंटे और सप्ताह में कम से कम 5 दिन सेवाएं प्रदान नहीं करता है, उसे "अंशकालिक बैंकिंग आउटलेट" माना जाएगा। बैंक को "बैंकिंग आउटलेट" की नियमित रूप से ऑन-साइट और ऑफ-साइट निगरानी करनी चाहिए ताकि उचित पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जा सके, सेवाओं में बाधा न आए (सिवाय दूरसंचार कनेक्टिविटी जैसी अस्थायी रुकावटों के), और ग्राहकों की शिकायतों का समय पर समाधान हो। कार्य समय/दिन की जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जानी चाहिए।

राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति (एनएसएफआई)

राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति 2019-2024⁵, जो भारत में वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया का विस्तार और इसे टिकाऊ बनाने के लिए वित्तीय समावेशन नीतियों की दृष्टि और प्रमुख उद्देश्यों को प्रस्तुत करती है, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) के तत्वावधान में विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श करके तैयार की गई। इस रणनीति का उद्देश्य औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक सस्ती पहुंच प्रदान करना, वित्तीय समावेशन को व्यापक और गहरा बनाना, और वित्तीय साक्षरता एवं उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देना है।

पचारिक वित्तीय सेवाओं के एक बुनियादी समूह तक पहुंच सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए, एनएसएफआई प्रौद्योगिकी का उपयोग करने और वित्तीय समावेशन को टिकाऊ बनाने के लिए बहु-हितधारक दृष्टिकोण अपनाने पर जोर देती है। एनएसएफआई के छह रणनीतिक उद्देश्य हैं:

1. वित्तीय सेवाओं की वैश्विक स्तर पर पहुंच, 2. वित्तीय सेवाओं के एक बुनियादी समूह की उपलब्धता, आजीविका और कौशल विकास तक पहुंच। 4. वित्तीय साक्षरता और शिक्षा 5. ग्राहक संरक्षण और शिकायत निवारण 6. प्रभावी समन्वय। एनएसएफआई में विशिष्ट समय-सीमाओं के साथ लक्ष्य तय किए गए हैं। यह रणनीति वांछित उद्देश्यों की दिशा में कार्यों को चिह्नित करने और वित्तीय समावेशन की ओर बहु-हितधारक नेतृत्व वाले दृष्टिकोण को मुख्यधारा में लाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है।

वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन सूचकांक

वित्तीय समावेशन की सफलता को तीन प्रमुख आयामों - पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता - के आधार पर मापा जाता है। 1. पहुंच: यह वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता पर केंद्रित है, जैसे कि पहुंच बिंदु, लागत, उत्पादों और सेवाओं का समूह आदि, और यह मुख्य रूप से आपूर्ति के दृष्टिकोण से देखा जाता है। 2. उपयोग: यह वित्तीय सेवाओं के उपयोग की मात्रा और सीमा को दर्शाता है। 3. गुणवत्ता: यह वित्तीय समावेशन पहलों की प्रभावशीलता को मापता है, जैसे भौगोलिक और जनसांख्यिकीय असमानताओं, शिकायत निवारण तंत्र, वित्तीय साक्षरता और जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करता है। वित्तीय समावेशन की पहलों की प्रभावशीलता के लिए इन तीनों आयामों - पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता में सफलता आवश्यक है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने देशभर में वित्तीय समावेशन के स्तर को मापने के लिए एक समग्र वित्तीय समावेशन सूचकांक का निर्माण किया है। यह सूचकांक एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ तैयार किया गया है, जिसमें बैंकिंग, निवेश, बीमा और पेंशन से संबंधित जानकारी को शामिल किया गया है। इसे सरकार और संबंधित क्षेत्रीय नियामकों के परामर्श से तैयार किया गया है। वित्तीय सूचकांक का मूल्य, मार्च 2017 (इंसेप्शन के दौरान) की स्थिति के अनुसार 43.4 रहा। जबकि मार्च 2024 में उप-सूचकांकों में वृद्धि करते हुए यह बढ़कर 64.2 तक पहुंच गया।

डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और गहनता (EDDPE)

देश में डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के विस्तार और गहनता के लिए, सभी राज्य स्तरीय बैंकर्स' समितियों (SLBCs) और केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय बैंकर्स' समितियों (UTLBCs) को सलाह दी गई कि वे अपने संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में जिलों की पहचान करें और उन्हें उस बैंक को आवंटित करें, जिसका उस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव हो। यह बैंक उस जिले को 100 प्रतिशत डिजिटल रूप से सक्षम बनाने का प्रयास करेगा ताकि जिले के प्रत्येक व्यक्ति को डिजिटल तरीके से सुरक्षित, तेज, सुलभ और सुविधाजनक तरीके से भुगतान करने/प्राप्त करने में सहायता मिल सके। स्थिति (30 जून, 2024 तक की स्थिति के अनुसार) देश के सभी जिलों (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के दो जिलों को छोड़कर) को इस उद्देश्य के लिए पहचाना जा चुका है। भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा रिपोर्ट के अनुसार, 192 जिले 100 प्रतिशत डिजिटल रूप से सक्षम हो चुके हैं।

वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड – अंतर्दृष्टि

वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड – अंतर्दृष्टि को जून 2023 में लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन की प्रगति का आकलन और निगरानी करना है। यह डैशबोर्ड वित्तीय समावेशन के तीन आयामों - पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता के अंतर्गत व्यापक मानकों को शामिल करते हुए नीति अंतर्दृष्टि को मजबूत बनाता है। डैशबोर्ड का उद्देश्य, राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक मानकों की प्रगति की निगरानी करना, क्षेत्रीय, राज्य और जिला स्तर की जानकारी के लिए विश्लेषण की सुविधा प्रदान करना है। डैशबोर्ड द्वारा कैप्चर किए जा रहे कुछ मानक, क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात, किसानों और स्व-सहायता समूहों का क्रेडिट लिंकिंग, प्राथमिक क्षेत्रों में ऋण वितरण, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों में प्रगति। डैशबोर्ड की विशेषताएं रंग-कोडित हीट मैप्स, त्वरित सूचक और ट्रेंड चार्ट, क्षेत्रीय असमानताओं, बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता और कई आयामों में क्रेडिट प्रवाह का आकलन। यह डैशबोर्ड न केवल प्रभावी प्रबंधन सूचना उपकरण के रूप में कार्य करता है, बल्कि अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि भी प्रदान करता है।

प्राथमिक क्षेत्र ऋण

प्राथमिक क्षेत्रों का विवरण 1972 में उस रिपोर्ट के आधार पर औपचारिक रूप से निर्धारित किया गया, जो मई 1971 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित प्राथमिक क्षेत्रों से संबंधित अग्रिमों पर एक अनौपचारिक अध्ययन समूह द्वारा प्रस्तुत की गई थी। प्रारंभ में, प्राथमिक क्षेत्र उधारी के संबंध में कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था, लेकिन नवंबर 1974 में बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे अपने कुल अग्रिमों में से प्राथमिक क्षेत्रों के लिए 33 1/3 प्रतिशत तक अग्रिमों का हिस्सा बढ़ाएं, जिसका समय सीमा मार्च 1979 था। इसके बाद, सभी वाणिज्यिक बैंकों को 1985 तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधारी का लक्ष्य कुल बैंक अग्रिमों के 40 प्रतिशत तक प्राप्त करने के लिए सूचित किया गया।

प्राथमिक क्षेत्र उधारी (PSL) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना रहा है कि समाज के कमजोर वर्गों को क्रेडिट तक पहुंच प्राप्त हो और उन क्षेत्रों में संसाधनों का पर्याप्त प्रवाह हो, जिनमें उच्च रोजगार क्षमता है और जो गरीबी उन्मूलन में मदद कर सकते हैं। इस प्रकार, वे क्षेत्र जो बड़ी जनसंख्या, कमजोर वर्गों और रोजगार-प्रधान क्षेत्रों जैसे कृषि और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों पर प्रभाव डालते हैं, उन्हें प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया गया है। आर्थिक कारणों से कुछ क्षेत्रों/उधारकर्ताओं को पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिल पाती है। किसी भी समय, संस्थाओं के पास जो ऋण देने योग्य संसाधन होते हैं, वे सीमित होते हैं और हमेशा एक व्यापारिक समीकरण होता है कि कितना समय और प्रयास लगाया जा सकता है और नए व्यवसायों से किस प्रकार की टॉप लाइन और बॉटम लाइन उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार के व्यापारिक परिप्रेक्ष्य में, यह संभव है कि जिन क्षेत्रों को बैंक ऋण की आवश्यकता है, वे बाहर हो जाएं। यही प्राथमिक क्षेत्र उधारी नियमों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है। ये दिशा-निर्देश राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और देश के वित्तीय समावेशन लक्ष्यों के साथ इसे पुनः-संरचित करने के लिए समय-समय पर समीक्षा की जाती हैं। पिछली व्यापक समीक्षा 2020 में की गई थी। प्राथमिक क्षेत्र के तहत श्रेणियाँ निम्नलिखित हैं:

1. कृषि
2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
3. निर्यात ऋण
4. शिक्षा

5. आवास
6. सामाजिक बुनियादी ढांचा
7. नवीकरणीय ऊर्जा
8. अन्य

भारतीय रिज़र्व बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) और शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए प्राथमिक क्षेत्र के लिए कुल लक्ष्य और कुछ प्राथमिक क्षेत्र की श्रेणियों के उप-लक्ष्य निर्धारित करता है।

क्षेत्रीय असमानताओं को संबोधित करने के लिए, 2020 की व्यापक समीक्षा के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि प्राथमिक क्षेत्र क्रेडिट के प्रवाह के आधार पर जिलों को रैंक किया जाएगा और जिन जिलों में क्रेडिट का प्रवाह तुलनात्मक रूप से कम है, उनके लिए एक प्रोत्साहन ढांचा और जिन जिलों में क्रेडिट का प्रवाह तुलनात्मक रूप से अधिक है, उनके लिए एक प्रतिकूल ढांचा तैयार किया जाएगा। जिलों की सूची को वित्तीय वर्ष 2024-25 में पुनः समीक्षा किया गया। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2024-25 से प्रभावी रूप से, उन पहचाने गए जिलों में जहां क्रेडिट प्रवाह तुलनात्मक रूप से कम है (प्रति व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्र ऋण ₹9,000 से कम है), उनके लिए वृद्धिशील प्राथमिक क्षेत्र क्रेडिट को 125% का अधिकतम भारांक दिया जाएगा, और जिन जिलों में क्रेडिट प्रवाह तुलनात्मक रूप से अधिक है (प्रति व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्र ऋण ₹42,000 से अधिक है), उनके लिए 90% का भारांक दिया जाएगा। अन्य जिलों के लिए मौजूदा भारांक 100% ही बना रहेगा।

इसके अतिरिक्त, बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के बीच संयुक्त रूप से क्रेडिट प्रदान करने के लिए सहयोग को सक्षम बनाने हेतु एक संरचित ढांचा बनाने के उद्देश्य से, बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र को सह-उधार (को-लेंडिंग) प्रदान करने पर 5 नवंबर, 2020 को दिशानिर्देश जारी किए गए थे। ये दिशानिर्देश मास्टर निदेशों के रूप में जारी किए गए हैं, जिन्हें नीचे दिए गए लिंक पर देखा जा सकता है।

https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewMasDirections.aspx?id=11959.

प्राथमिक क्षेत्र के लक्ष्य की प्राप्ति में विफलता

जो बैंक प्राथमिक क्षेत्र को ऋण देने में किसी भी प्रकार की कमी पाते हैं, उन बैंकों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णय अनुसार, नाबार्ड के तहत स्थापित ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) और नाबार्ड/एनएचबी/सिडबी/मुद्रा लिमिटेड के अन्य निधियों में अंशदान करने के लिए राशि आवंटित की जाती है।

प्राथमिक क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (पीएसएलसी)

बैंकों को प्राथमिक क्षेत्र ऋण (पीएसएल) लक्ष्यों और उप-लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता देने और साथ ही साथ विभिन्न प्राथमिक क्षेत्र श्रेणियों में अपने ऋण देने में अधिशेष वाले बैंकों को प्रोत्साहित करने के लिए अप्रैल 2016 में प्राथमिक क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) में ट्रेडिंग प्रारंभ किया गया। पीएसएलसी चार विभिन्न श्रेणियों में होते हैं: पीएसएलसी -सामान्य, पीएसएलसी कृषि, पीएसएलसी -छोटे और सीमांत किसान, और पीएसएलसी -सूक्ष्म उद्यम। ये चार प्रमाणपत्र प्राथमिक क्षेत्र

श्रेणियों के तहत समग्र और निर्दिष्ट उप-लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मान्य होते हैं। पात्र विक्रेता / खरीदारों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्रीय बैंक, छोटे वित्त बैंक और शहरी सहकारी बैंक शामिल हैं। सामान्यतः, पीएसएलसी को अंतर्निहित संपत्तियों की जमानत पर जारी किया जाता है। हालांकि, पीएसएलसी के लिए एक मजबूत और गतिशील बाजार विकसित करने के उद्देश्य से, एक बैंक को अपनी पिछली वर्ष की पीएसएल प्राप्ति करने पर अपनी बहियों में बिना किसी अंतर्निहित संपत्तियों के 50 प्रतिशत तक पीएसएलसी जारी करने की अनुमति है। इन प्रमाणपत्रों का व्यापार करने के लिए आरबीआई के ई-कुबेर बैंकिंग सिस्टम पर पीएसएलसी मॉड्यूल के माध्यम से एक मंच प्रदान किया गया है। वे बैंक जो लक्ष्य प्राप्ति में कमी का सामना कर रहे हैं, इन पीएसएलसी को एक बाजार निर्धारित प्रीमियम पर खरीद सकते हैं। प्रमाणपत्र के खरीदार को जोखिम या ऋण संपत्तियों का कोई हस्तांतरण नहीं होगा। सभी पीएसएलसी उस वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक वैध होंगे, जिसमें इन्हें जारी किया गया था, और 1 अप्रैल को समाप्त हो जाएंगे। वस्तुतः, पीएसएलसी विशिष्ट ऋणों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, बल्कि केवल पीएसएल के तहत प्राप्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं।

ब्याज सबवेंशन योजनाएं

भारत सरकार के अनुमोदन से, भारतीय रिज़र्व बैंक, कृषि से संबंधित ब्याज सबवेंशन योजनाओं की घोषणा करता है। इस प्रकार की ब्याज सहायता योजनाओं का उद्देश्य समाज के कुछ वर्गों को औपचारिक बैंकिंग चैनलों में लाना है, ताकि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिल सके।

केसीसी के माध्यम से कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए अल्पावधि ऋण के प्राप्त करने के लिए भारत सरकार की संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना (एमआईएस)

एमआईएसएस का उद्देश्य कृषि और संबंधित गतिविधियों, जिनमें पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन आदि शामिल हैं, के लिए ₹3 लाख तक के अल्पावधि ऋण प्रदान करना है, जो सस्ते ब्याज दर पर उपलब्ध हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक इस योजना का कार्यान्वयन करने के लिए नोडल एजेंसी है, जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, छोटे वित्त बैंकों और कंप्यूटरीकृत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) के माध्यम से लागू किया जा रहा है, जो निर्धारित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के साथ जुड़े हैं। यह योजना यह सुनिश्चित करती है कि किसानों को औपचारिक उधारी के दायरे में लाया जाए और वे उन साहूकारों से बच सकें जो अत्यधिक ब्याज दरें चार्ज करते हैं। नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और राज्य सहकारी बैंकों (आरसीबी) के लिए नोडल एजेंसी है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एमआईएसएस की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

- ऋण देने वाली संस्थाएँ किसानों को 7% प्रति वर्ष के दर पर अल्पावधि ऋण प्रदान करती हैं। ऋण राशि पर ब्याज सबवेंशन 1.5% की दर पर उस तारीख से लागू होता है जब ऋण का वितरण/निकासी किया जाता है, और तब तक जारी रहता है जब तक ऋण का पुनर्भुगतान नहीं किया जाता या बैंकों/पैक्स द्वारा निर्धारित ऋण की नियत तिथि तक, जो भी पहले हो अधिकतम एक वर्ष के अवधि की शर्त पर उपलब्ध होगी।
- जो किसान समय पर अपना ऋण चुकाते हैं, उन्हें 3% प्रति वर्ष की प्रोत्साहन राशि (पीआरआई) प्रदान की जाती है, यानी वितरण की तारीख से लेकर वास्तविक पुनर्भुगतान की तारीख तक या बैंक/पैक्स द्वारा पुनर्भुगतान के लिए

निर्धारित तिथि तक, जो भी पहले हो, अधिकतम एक वर्ष की अवधि तक। इसका मतलब है कि ऐसे किसानों के लिए प्रभावी ब्याज दर 4% प्रति वर्ष होती है।

- किसानों द्वारा प्राकृतिक आपदाओं के कारण मजबूरन बिक्री को रोकने और उन्हें प्रमाणित गोदामों में अपनी उपज जमा करने के लिए प्रेरित करने हेतु, छोटे और सीमांत किसानों को परक्राम्य भंडाराण ससीदों के प्रति ऋण प्रदान करने के लिए बैंकों को 6 महीने तक ब्याज सबवेंशन का लाभ दिया जाता है।
- प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए, पुनर्संरचित ऋण राशि पर पहले वर्ष के लिए बैंकों को उस वर्ष के लिए लागू ब्याज सहायता दर उपलब्ध कराई जाती है। ऐसे पुनर्संरचित ऋणों पर दूसरे वर्ष से सामान्य ब्याज दर लागू होती है।
- हालाँकि, गंभीर प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए, उस वर्ष के लिए लागू ब्याज सबवेंशन दर बैंकों को पहले तीन वर्षों/पूरी अवधि (अधिकतम पाँच वर्षों तक) तक उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा, ऐसे प्रभावित किसानों को प्रोत्साहन राशि 3% की दर पर प्रति वर्ष भी प्रदान की जाती है। गंभीर प्राकृतिक आपदाओं के मामलों में इस लाभ का निर्धारण उच्चस्तरीय समिति (एचएलसी) द्वारा केंद्रीय मंत्रीमंडल टीम (आईएमसीटी) और राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एससी-एनईसी) की उपसमिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा।

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपाय

वर्तमान में, भारत सरकार का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ढांचा प्राकृतिक आपदाओं के 12 प्रकारों को अपनी परिधि में शामिल करता है, अर्थात् चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीट हमला और शीतलहर/बर्फबारी। इसके अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में राहत उपायों के रूप में ऋण पुनर्संरचना की अनुमति देता है, जिससे संपत्ति वर्गीकरण में कोई गिरावट नहीं होती हो और नए ऋणों की मंजूरी दी जाती हो। ये राहत उपाय सुनिश्चित करते हैं कि आपदा से उत्पन्न अतिरिक्त तनाव के कारण उधारकर्ताओं की कठिनाइयों को प्रभावी और त्वरित तरीके से निवारण किया जाए, इसके लिए राज्य प्राधिकरणों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों जैसे राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी)/जिला परामर्श समितियाँ (डीसीसी) के साथ समन्वय किया जाता है।

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना

केसीसी योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी जोत के आधार पर बैंकों से पर्याप्त और समय पर ऋण सहायता प्रदान करना है, ताकि वे कृषि संबंधी इनपुट जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि खरीद सकें, उत्पादन की आवश्यकताओं के लिए धन निकाल सकें और आवधिक ऋणों के माध्यम से दीर्घकालिक संपत्ति निर्माण के लिए ऋण प्राप्त कर सकें। केसीसी एक एकल खिड़की प्रणाली है, जहाँ सभी लघु-अवधि फसल ऋण और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋणों के लिए क्रेडिट सीमा का निर्धारण वित्त के पैमाने के माध्यम से किया जाता है, परिणामस्वरूप, उत्पादन गतिविधि से ऋण को जोड़ा जाता है। फरवरी 2019 में इस योजना का विस्तार पशुपालन और मत्स्य पालन (संबद्ध गतिविधियाँ) के कार्यशील पूंजी की

आवश्यकता को कवर करने के लिए किया गया। नाबार्ड, नाबार्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए केसीसी योजना लागू करने वाली कार्यान्वयन एजेंसी है।

वित्तीय समावेशन क्षेत्र में नई बैंकिंग संस्थाओं को अनुमति प्रदान किया जाना

आरबीआई ने कुछ संस्थाओं को लघु वित्त बैंक (एसएफबी) और भुगतान बैंक (पीबी) स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है, ताकि देश में वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके। एसएफबी और पीबी को बचत के लिए वाहन के रूप में काम करने के अलावा, छोटे व्यापारिक इकाइयों, छोटे और सीमांत किसानों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों और अनौपचारिक क्षेत्र की अन्य संस्थाओं को क्रेडिट की आपूर्ति बढ़ाने की अपेक्षा की जाती है, और ये क्रमशः सुरक्षित और प्रौद्योगिकी-आधारित वातावरण में लागत-कुशल रेमिटेंस सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। स्मॉल फाइनेंस बैंक को वित्तीय वर्ष 2018-19 से लीड बैंक योजना के तहत विभिन्न मंचों में, जैसे * एलएलबीसी डीसीसी/डीएलआरसी और बीएलबीसी में उनके संबंधित स्थानों पर नियमित सदस्य के रूप में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। साथ ही यह क्रेडिट योजना अभ्यास का हिस्सा भी बने थे, जबकि पेमेंट्स बैंक, अपनी भिन्न और सीमित मंजूरी (जैसे कि लाइसेंस की शर्तों के कारण उधारी की अनुमति नहीं है) के कारण, मई 2019 से लीड बैंक योजना के तहत वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता संबंधित पहलों को और बढ़ावा देने के लिए शामिल किए गए थे, लेकिन वे लीड बैंक योजना के तहत वार्षिक क्रेडिट योजना (एसीपी) अभ्यास में भाग नहीं लेते हैं। इसके अलावा, वित्तीय समावेशन और भुगतान प्रणालियों के बीच मजबूत संबंध को ध्यान में रखते हुए, आरबीआई ने कई कदम उठाए हैं। इनमें मोबाइल बैंकिंग, प्री-पेड उपकरणों के रूप में डिजिटल वॉलेट्स और मोबाइल वॉलेट्स का उपयोग प्रोत्साहित करना, आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम (एबीपीएस) और आधार-एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (ईपीएस) आदि का संचालन शामिल हैं।

वित्तीय साक्षरता

ओईसीडी वित्तीय साक्षरता को एक ऐसा संयोजन मानता है जिसमें वित्तीय जागरूकता, ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और व्यवहार शामिल हैं, जो सही वित्तीय निर्णय लेने और अंततः व्यक्तिगत वित्तीय कल्याण प्राप्त करने के लिए आवश्यक होते हैं। लोग वित्तीय शिक्षा की प्रक्रिया के माध्यम से वित्तीय साक्षरता प्राप्त करते हैं। ओईसीडी वित्तीय शिक्षा को इस प्रकार परिभाषित करता है: "वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वित्तीय उपभोक्ता/निवेशक वित्तीय उत्पादों, अवधारणाओं और जोखिमों को समझने में सुधार करते हैं और सूचना, मार्गदर्शन और/या उद्देश्यपूर्ण सलाह के माध्यम से, वे वित्तीय जोखिमों और अवसरों के प्रति अधिक जागरूक होने, सूचित विकल्प बनाने, सहायता प्राप्त करने के स्थान को जानने, और अन्य प्रभावी कदम उठाने के लिए कौशल और आत्मविश्वास विकसित करते हैं, ताकि उनका वित्तीय कल्याण सुधार सके।"

वित्तीय साक्षरता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वित्तीय सेवा उपभोक्ताओं को सूचित विकल्प बनाने में सक्षम बनाती है और इस प्रकार उनके वित्तीय कल्याण को बढ़ावा देती है। इसे पहचानते हुए, FSDC उप-समिति का तकनीकी समूह (TGFIPL) वित्तीय समावेशन और साक्षरता के प्रयासों को नीति स्तर पर समन्वित करने के लिए गठित किया गया था। इस समूह की अध्यक्षता भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर द्वारा की जाती है और इसमें सभी नियामकों और वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने देश में वित्तीय साक्षरता को मजबूत करने के लिए विभिन्न नीतियों को लागू किया है।

आरबीआई द्वारा किए गए महत्वपूर्ण पहलों के मुख्य अंश निम्नलिखित हैं:

- (i) बैंकों को वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) खोलने और संचालन में लाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं और साथ ही ग्रामीण बैंक शाखाओं के माध्यम से वित्तीय साक्षरता कार्य भी किए जा रहे हैं। इसके लिए वित्तीय सहायता भी नाबार्ड द्वारा प्रबंधित वित्तीय समावेशन फंड से उपलब्ध कराई जाती है। इस पहल का लक्ष्य समूह में एसएचजी, किसान, छोटे उद्यमी, वरिष्ठ नागरिक और स्कूल के बच्चे शामिल हैं।
- (ii) वित्तीय शिक्षा साहित्य का निर्माण किया गया है, जिसे RBI की वित्तीय शिक्षा वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। यह सामग्री 13 भाषाओं में उपलब्ध है, जिसे बैंक और अन्य हितधारक वित्तीय उत्पादों और सेवाओं, अच्छे वित्तीय प्रथाओं, डिजिटल जाने और उपभोक्ता संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ लक्षित समूहों के लिए विशेष सामग्री भी तैयार की गई है जैसे कि स्कूल के बच्चे, SHGs, किसान, छोटे उद्यमी और वरिष्ठ नागरिक। FAME (Financial Awareness Messages) पुस्तिका भी विकसित की गई है, जिसका उद्देश्य सामान्य जनता को बुनियादी वित्तीय साक्षरता संदेश प्रदान करना है।
- (iii) राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (NCFE) को चार वित्तीय क्षेत्र के नियामकों द्वारा एक धारा 8 (नफा-नुकसान से मुक्त) कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा रणनीति (NSFE) के अनुसार भारत में सभी वर्गों के लोगों के बीच वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देना है। NCFE पूरे देश में सेमिनार, कार्यशालाओं, सम्मेलन, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अभियानों आदि के माध्यम से वित्तीय साक्षरता अभियानों का संचालन करता है ताकि लोग अपने पैसे को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सकें और इस प्रक्रिया में वित्तीय भलाई प्राप्त कर सकें। NCFE, भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के शिक्षा विभाग के साथ वित्तीय शिक्षा को स्कूल पाठ्यक्रम में एकीकृत करने की कोशिश भी करता है। 31 जुलाई, 2024 तक 22 राज्यों ने आंशिक/पूर्ण रूप से वित्तीय शिक्षा को अपने स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया है।

वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए मास मीडिया अभियानों का संचालन।

- 0) वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफएलडबल्यू) का हर साल 2016 से आयोजन किया जा रहा है, ताकि देशभर में एक विशिष्ट विषय पर वित्तीय शिक्षा संदेश फैलाए जा सकें।
- 0) वित्तीय साक्षरता में सुधार के लिए समुदाय-आधारित अभिनव और भागीदार दृष्टिकोण लाने के उद्देश्य से, CFL पायलट परियोजना 2017 में बैंकों और NGOs के सहयोग से शुरू की गई थी। पायलट परियोजना से प्राप्त अनुभव के आधार पर और ग्रामीण स्तर पर वित्तीय साक्षरता को स्थायी और भागीदार तरीके से बढ़ावा देने के लिए, इस परियोजना को 31 जुलाई 2024 तक 2,421 CFLs स्थापित करके और 7,225 ब्लॉकों में फैलाकर बढ़ाया गया है। तीन वर्षों की अवधि में, CFLs को पहचाने गए ब्लॉकों के 50% गांवों में कम से कम 30% जनसंख्या को लक्षित करने और मुख्य रूप से 18-60 वर्ष आयु वर्ग के ग्रामीणों के लिए वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित करने की आवश्यकता है, जबकि स्थानीय बैंकिंग अधिकारियों और/या व्यवसायी प्रतिनिधियों (BCs) की मदद से वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने की सुविधा प्रदान करनी है।

- (i) एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमियों से निपटते समय बैंकों के मानसिकता में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए एक विशेष क्षमता निर्माण कार्यक्रम 'बैंकर्स के लिए राष्ट्रीय मिशन' आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य बैंकों को एमएसएमई क्षेत्र के सभी ऋण संबंधी मुद्दों से परिचित कराना और उनमें उद्यमिता के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना है। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आयोजित कार्यशालाओं में एमएसएमई शाखाओं और एमएसएमई वित्त से संबंधित केंद्रीय बैंक के एमएसएमई शाखाओं और केंद्रीय प्रसंस्करण कक्षों में नियुक्त बैंक अधिकारियों द्वारा भाग लिया जाता है।
- (ii) एनएएमसीएबीएस कार्यक्रम में एक ट्रेन-द-ट्रेनर मॉड्यूल भी शामिल है, जिसमें पुणे स्थित कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग (सीएबी) बैंक प्रशिक्षण संस्थानों और आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों में नियुक्त अधिकारियों को ऋण से संबंधित पहलुओं से परिचित कराता है। यह कार्यक्रम एक प्रशिक्षित पेशेवरों का एक समूह तैयार करने का लक्ष्य रखता है ताकि वे एमएसएमई से संबंधित बैंक अधिकारियों को एमएसएमई के विविध आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद कर सकें और उनके बीच उद्यमिता संवेदनशीलता को बढ़ावा दे सकें। टीओटी मॉड्यूल की पाठ्य सामग्री में विशेष रूप से एमएसएमई के लिए ऋण मूल्यांकन विधियों, जोखिम प्रबंधन रणनीतियों, सरकारी योजनाओं और आरबीआई के प्रोत्साहन नियमों का गहरा विवरण शामिल है। इसके अलावा, प्रशिक्षण में एमएसएमई उद्यमियों के साथ सक्रिय संवाद के महत्व को भी बताया जाता है ताकि उनके विशिष्ट आवश्यकताओं, चुनौतियों और विकास की आकांक्षाओं को समझा जा सके।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने 9 मई 2023 को एक 'उद्यम सहायता प्लेटफॉर्म' (यूएपी) लॉन्च किया, ताकि वे असंगठित माइक्रो उद्यम (आईएमई) जो पैन या जएसटीआईएन जैसे अनिवार्य दस्तावेजों की कमी के कारण उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कर पा रहे थे, उनकी औपचारिकता में मदद की जा सके। तदनुसार, एमएसएमई को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण वर्गीकरण के अंतर्गत लाने के लिए एक परिपत्र जारी किया गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि उद्यम सहायक प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यम (IMEs) को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के तहत सूक्ष्म उद्यमों के रूप में माना जाएगा।

- (ix) 25 अप्रैल 2023 को 'सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) सुविधा - समीक्षा' पर एक संशोधित परिपत्र जारी किया गया। इसमें प्रावधान किया गया है कि जीसीसी उन व्यक्तियों/संस्थाओं को जारी किया जा सकता है, जिन्हें गैर-कृषि उद्यमशील गतिविधियों के लिए वर्किंग कैपिटल सुविधाएं स्वीकृत की जाती हैं, जो प्राथमिकता क्षेत्र दिशा-निर्देशों के तहत वर्गीकरण के लिए पात्र हैं। दिनांक 21 अप्रैल 2022 के 'मास्टर डायरेक्शन - क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड - जारी करने और संचालन निर्देश' (समय-समय पर अद्यतित) के प्रावधानों के अनुरूप जीसीसी को एक क्रेडिट कार्ड के रूप में जारी किया जाएगा।
- (x) भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय प्रत्येक वर्ष 2-3 टाउन हॉल बैठकों का आयोजन करते हैं, खासकर अविकसित/कम बैंकिंग सुविधा वाले क्षेत्रों में। इन बैठकों का उद्देश्य है: बैंकों की सुविधाओं के प्रति उद्यमियों को जागरूक बनाना, उन्हें औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना, बैंक ऋण प्राप्त करने में उद्यमियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं पर फीडबैक लेना। इन बैठकों के लिए चयनित क्लस्टर/क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाता है और बैठक के बाद उद्यमियों को ऋण से जोड़ने के लिए बैंकों के साथ अनुवर्तन किया जाता है।

वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति (एनएसएफई)

ओईसीडी के अनुसार, वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति का ढांचा नियामकों और हितधारकों के बीच बेहतर और स्थायी सहयोग को बढ़ावा देता है। यह संसाधनों की पुनरावृत्ति को रोकता है और राष्ट्रीय मूल्यांकन के आधार पर मापने योग्य और यथार्थवादी उद्देश्यों के साथ अनुकूलित योजनाओं के विकास को सक्षम बनाता है।

भारत में, पहली एनएसएफई (2013-2018) की अवधि समाप्त होने के बाद, एनएसएफई ने चार वित्तीय क्षेत्र नियामकों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करके संशोधित एनएसएफई (2020-2025) तैयार की है।

यह दस्तावेज़ भारत सरकार और वित्तीय क्षेत्र नियामकों की दृष्टि का समर्थन करने का उद्देश्य रखता है, ताकि जनसंख्या के विभिन्न वर्गों को पर्याप्त ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और व्यवहार विकसित करने में सक्षम बनाया जा सके, जिससे वे अपने पैसे का बेहतर प्रबंधन कर सकें और अपने भविष्य की योजना बना सकें।

वित्तीय रूप से जागरूक और सशक्त भारत बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित रणनीतिक उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं:

- i. वित्तीय शिक्षा के माध्यम से विभिन्न वर्गों में वित्तीय साक्षरता अवधारणाओं को विकसित करना और इसे एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल बनाना।
- ii. सक्रिय बचत व्यवहार को प्रोत्साहित करना।
- iii. वित्तीय लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वित्तीय बाजारों में भागीदारी को बढ़ावा देना।
- iv. ऋण अनुशासन विकसित करना और आवश्यकता के अनुसार औपचारिक वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने को प्रोत्साहित करना।
- v. डिजिटल वित्तीय सेवाओं का सुरक्षित और संरक्षित तरीके से उपयोग बढ़ाना।
- vi. जीवन के विभिन्न चरणों में जोखिम प्रबंधन के लिए उपयुक्त बीमा कवर प्राप्त करना।
- vii. वृद्धावस्था और सेवानिवृत्ति के लिए उपयुक्त पेंशन उत्पादों के माध्यम से योजना बनाना।
- viii. शिकायत निवारण के लिए अधिकारों, कर्तव्यों और साधनों की जानकारी प्राप्त करना।
- ix. वित्ती

य शिक्षा में प्रगति का आकलन करने के लिए अनुसंधान और मूल्यांकन पद्धतियों में सुधार करना।

10. रणनीति प्राप्त करने के लिए रणनीति में '5C' दृष्टिकोण अपनाने की सिफारिश की गई है, जिसके माध्यम से वित्तीय शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया जा सकता है।

यह दृष्टिकोण निम्नलिखित क्षेत्रों पर केंद्रित है - **सामग्री:** प्रासंगिक सामग्री का विकास, जिसमें विद्यालयों, कॉलेजों और प्रशिक्षण संस्थानों में पाठ्यक्रम शामिल है। **क्षमता:** वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में शामिल बिचौलियों की क्षमता को बढ़ाना, **समुदाय:** वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक नेतृत्व वाले मॉडल के सकारात्मक प्रभाव का उपयोग करना

संचार: उपयुक्त संचार रणनीतियों के माध्यम से वित्तीय शिक्षा संदेशों का प्रभावी प्रसार, **सहयोग:** विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।

'5C' के अंतर्गत सिफारिशें

1. सामग्री:

- विद्यालयी पाठ्यक्रम और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों सहित बच्चों, शिक्षकों, युवाओं, महिलाओं, कामकाजी पेशेवरों/उद्यमियों (एमएसएमई), वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग व्यक्तियों और अशिक्षित लोगों के लिए वित्तीय साक्षरता सामग्री का विकास।

2. क्षमता:

- वित्तीय साक्षरता प्रदान करने वाले बिचौलियों की क्षमता विकसित करना।
- वित्तीय शिक्षा प्रदाताओं के लिए 'आचार संहिता' (Code of Conduct) तैयार करना।

3. समुदाय:

- वित्तीय साक्षरता के प्रसार के लिए सामुदायिक नेतृत्व वाले मॉडल विकसित करना और इसे स्थायी रूप से लागू करना।

4. संचार:

- वित्तीय साक्षरता संदेशों के प्रसार के लिए तकनीक, जनसंचार माध्यमों और नवाचार का उपयोग।
- वित्तीय साक्षरता संदेशों को बड़े पैमाने पर फैलाने के लिए वर्ष के एक विशिष्ट समय का चयन।
- बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थानों पर वित्तीय साक्षरता संदेशों को प्रभावी ढंग से प्रसारित करना।

5. सहयोग:

- एक सूचना डैशबोर्ड तैयार करना।
- वित्तीय साक्षरता सामग्री को विद्यालयी पाठ्यक्रम और व्यावसायिक/पेशेवर पाठ्यक्रमों (जैसे, कौशल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम) में एकीकृत करना।
- वित्तीय साक्षरता को अन्य चल रहे कार्यक्रमों का हिस्सा बनाना।
- वित्तीय साक्षरता के लिए अन्य हितधारकों के प्रयासों को सुव्यवस्थित करना।

निगरानी और मूल्यांकन ढांचा

रणनीति यह भी सुझाती है कि इसके तहत की गई प्रगति का आकलन करने के लिए एक मजबूत 'निगरानी और मूल्यांकन ढांचा' अपनाया जाए।

अध्याय 22: संस्थाओं का विकास

रिज़र्व बैंक उन कुछ केंद्रीय बैंकों में से एक है जिसने अपने देश में विकासात्मक गतिविधियों का समर्थन करने में प्रत्यक्ष और सक्रिय भूमिका निभाई है। आरबीआई की विकासात्मक भूमिका में अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को ऋण सुनिश्चित करना, वित्तीय बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए संस्थाओं का निर्माण करना और सस्ती वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करना शामिल है। वर्षों से, इसकी विकासात्मक भूमिका देश के भीतर विविध वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने के लिए संस्था निर्माण तक बढ़ गई है। अर्थव्यवस्था के विकास की बदलती आवश्यकताओं के साथ, भारतीय रिज़र्व बैंक, यदि कुछ क्रियाकलापों का उल्लेख किया जाए तो, संस्थाओं के निर्माण, समस्त बैंकिंग उद्योग में दक्ष ग्राहक सेवा को प्रोत्साहित करने, वित्तीय समावेशन पर बल देते हुए बैंकिंग सेवाएं सभी को उपलब्ध कराने जैसी गतिविधियों के माध्यम से अपनी विकासात्मक भूमिका की परिभाषा दोबारा तय कर रहा है।

विकासशील अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए संस्थाएं

किसी परिपक्व अर्थव्यवस्था की विशेषता न केवल एक सक्षम केंद्रीय बैंक बल्कि विभिन्न क्रियाकलापों को समर्थन प्रदान करने के लिए बनायी गयी संस्थाओं का ढांचा उपलब्ध कराना होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक जो अनेक गतिविधियाँ निष्पादित करता है उनमें से एक अद्वितीय गतिविधि है नयी संस्थाओं के अंकुरण के लिए माहौल पैदा करना और विभिन्न भूमिकाएं निभाने के लिए बाज़ार उन्मुख संस्थाओं के विकास को संभव बनाना। विशेषतः अविकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में यह बात अत्यधिक महत्वपूर्ण बन गयी थी। सुविकसित पूंजी बाज़ार के अभाव में रिज़र्व बैंक ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर कई सारी विशेषीकृत संस्थाओं के गठन में सक्रिय भूमिका अदा किया ताकि उद्योगों के लिए मीयादी वित्त की उपलब्धता को और व्यापक बनाया सके और बचत को संस्थागत रूप प्रदान किया जा सके जो किसी केंद्रीय बैंक के लिए अपने क्रियाकलापों से हट कर कुछ नया करने का एक उदाहरण मात्र है।

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी संस्था

वर्ष 1962 में निक्षेप बीमा निगम की स्थापना की गई थी और 1971 में प्रत्यय गारंटी निगम की स्थापना की गई थी। इन दोनों संस्थाओं को 1978 में निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) बनाने के लिए विलय कर दिया गया, जो आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था है।

वित्तीय संस्थाओं का विकास

देश में स्थित कई सारी विकासात्मक वित्त संस्थाओं की जड़ें भारतीय रिज़र्व बैंक में तलाशी जा सकती हैं। वर्ष 1964 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया का गठन किया गया था। इसके पीछे उद्देश्य था छोटे निवेशकों को शेयर बाज़ार में निवेश करने के लिए एक चैनल उपलब्ध कराना। उसी वर्ष, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक [आईडीबीआई] की स्थापना की गई थी। इस बैंक को बाद में सर्व सेवा बैंक के रूप में रूपांतरित किया गया था। अर्थव्यवस्था के दो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को समर्थन प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक [नाबार्ड] और निर्यात आयात बैंक [एक्जिम बैंक] की वर्ष 1982 में स्थापना की गयी

थी। नाबार्ड कृषि और ग्रामीण विकास के लिए शीर्षस्थ संस्था के रूप में कार्य करता है।

नाबार्ड ने वर्ष 1963 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित कृषि पुनर्वित्त निगम नामक दूसरी संस्था के कामकाज को अपना लिया था। निर्यातकों को रियायती दरों पर बैंक ऋण उपलब्ध कराने के प्रयोजन से एक्जिम बैंक की स्थापना की गयी थी। साथ ही, आवास क्षेत्र तथा एमएसएमई क्षेत्र को वित्तीय समर्थन प्रदान करने के लिए वर्ष 1988 में क्रमशः राष्ट्रीय आवास बैंक और वर्ष 1990 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गयी थी।

नैबफिड की स्थापना, भारत में दीर्घकालिक बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के विकास का समर्थन करने के लिए एक विकास वित्तीय संस्था (डीएफआई) के रूप में राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (नैबफिड) अधिनियम, 2021 के माध्यम से की गई। बैंक ने 09 मार्च 2022 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से अधिसूचित किया कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल और 45एन के अंतर्गत नैबफिड का, एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्था (एआईएफआई) के रूप में रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमन व पर्यवेक्षण किया जाएगा।

अनुसंधान और अध्ययन संस्थाएं

अनुसंधान और अध्ययन को बढ़ावा देने में रिज़र्व बैंक की भूमिका को अकसर कम आंका जाता है। वर्ष 1969 में बैंक ने पुणे में राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान [एनआईबीएम] की स्थापना की। भारतीय बैंक प्रबंध संस्थान (आईआईबीएम), गुवाहाटी की स्थापना बैंकों और वित्तीय संस्थाओं, विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में, की क्षमता निर्माण की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्ष 1980 में की गई, जिसमें आरबीआई भी एक प्रायोजक है। वर्ष 1987 में इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान [आईजीआईडी आर] की स्थापना की गई। यह संस्था अब आर्थिक और विकास अनुसंधान के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध संस्था बनकर उभरी है। बैंकिंग टेक्नोलॉजी में स्थित अंतराल को देखते हुए बैंकिंग टेक्नोलॉजी विकास और अनुसंधान संस्थान की वर्ष 1996 में स्थापना की गई। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की उभरती भूमिका की पृष्ठभूमि में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एक स्वतंत्र चिंतन केंद्र [थिंक टैंक] के रूप में उच्चस्तरीय वित्तीय अनुसंधान तथा अध्ययन केंद्र के रूप में [कैफरल] का वर्ष 2011 में गठन किया गया ताकि वह बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में अनुसंधान और उन्नत अध्ययन के लिए उत्कर्ष सार्वभौमिक केंद्र के रूप में उभर सके।

बाज़ार संबंधी संस्थाएं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मुद्रा बाज़ार के विकास के लिए एवं मुद्रा बाज़ार की लिखतों को तरलता प्रदान करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के साथ मिलकर मार्च 1988 में डिस्काउंट एंड फायनांस हाउस ऑफ़ इंडिया [डीएफएचआई] का गठन किया था। मई 1994 में रिज़र्व बैंक ने भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम [एसटीसीआई] का गठन किया था। इसके पीछे भारत सरकार की प्रतिभूतियों एवं सरकारी क्षेत्र के बांडों में सक्रिय गौण बाज़ार को बढ़ावा देने का उद्देश्य था। एसटीसीआई में भारतीय रिज़र्व बैंक के स्टैक को बाद में हटा लिया गया और अब यह संस्था एसटीसीआई फाइनेन्स लि. के नाम के अंतर्गत एक मध्य स्तरीय एनबीएफसी के रूप में परिचालन कर रही है।

वित्तीय बाज़ार अवसंरचना

भुगतान और निपटान प्रणाली को सुगम और सुविधाजनक बनाने के लिए एकरूप संरचना प्रदान करने की आवश्यकता थी जिसके लिए भारतीय रिज़र्व के निर्देशन पर दो संस्थाओं का गठन किया गया। भारतीय समाशोधन निगम [सीसीआईएल] का गठन अप्रैल 2001 में किया गया ताकि मुद्रा, सरकारी प्रतिभूतियाँ, विदेशी मुद्रा और डेरीवेटिव्स बाज़ार के लेन-देन के लिए गारंटी के साथ समाशोधन और निपटान के कार्यकलापों को अंजाम दिया जा सके। भारत में समस्त खुदरा भुगतानों के लिए छत्रक संगठन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम [एनपीसीआई] का गठन वर्ष 2008 में किया गया। इसकी स्थापना आरबीआई और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के मार्गदर्शन और समर्थन में की गई।

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) से संबंधित सेवाओं के लिए संस्थाएं

रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (रेबिट) की स्थापना वर्ष 2016 में रिज़र्व बैंक और इसकी विनियमित संस्थाओं की साइबर सुरक्षा आवश्यकताओं सहित आईटी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की गई। रेबिट वित्तीय क्षेत्र की आईटी और साइबर सुरक्षा (संबंधित अनुसंधान सहित) पर ध्यान केंद्रित करेगा और आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओं के आईटी सिस्टम ऑडिट और आकलन में सहायता करेगा। साथ ही, आरबीआई और रेबिट के बीच पारस्परिक रूप से तय किए गए अनुसार रिज़र्व बैंक की आंतरिक या सिस्टम-व्यापी आईटी परियोजनाओं (मौजूदा और नई दोनों) के संबंध में परामर्श देगा, लागू करेगा और प्रबंधन करेगा।

भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाएँ (IFTAS), जो पहले IDRB की सहायक कंपनी थी, को वर्ष 2019 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ले लिया गया था। इसे भारतीय रिज़र्व बैंक और देश के सभी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए आईटी से संबंधित सेवाओं का अभिकल्प तैयार करने, डिप्लॉय करने और समर्थन कार्य सौंपा गया है। इफ्टास की स्थापना बैंकों के सुचारु कार्यसंचालन को साकार करने, उन्हें नवाचार करने और अप्रतिम डिजिटल बैंकिंग अनुभव उपलब्ध कराने में सहायता करने की दृष्टि से की गई।

मुद्रा प्रबंध संस्था

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में बैंक नोटों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए तथा बैंक नोटों की मांग और आपूर्ति के बीच की दूरी को कम करने की दृष्टि से वर्ष 1995 में पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड [बीआरबीएनएमपीएल] की स्थापना की। यह कंपनी दो मुद्रा प्रेस का प्रबंध करती है, पहला कर्नाटक में स्थित मैसूर मुद्रणालय का तथा दूसरा पश्चिम बंगाल में स्थित सालबोनी मुद्रणालय। बैंक नोटों के लिए लगने वाले कागज़ के उत्पादन में स्वावलंबी बनने के लिए बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड [बीएनपीएमआईपीएल] को वर्ष 2010 में कर्नाटक के मैसूर में निगमित करते हुए उसको रजिस्टर किया गया है। यह कंपनी भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड और भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम है और वह 12000 टीपीए की क्षमता के साथ बैंक नोटों के लिए लगने वाले कागज़ का उत्पादन करती है।

वित्तीय शिक्षा संस्था

नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन (एनसीएफई) धारा 8 (जिसका उद्देश्य लाभार्जन नहीं है) के अंतर्गत कंपनी है

जिसे आरबीआई, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा संयुक्त रूप से संवर्धित किया जाता है। इसका विशन है भारत को वित्तीय रूप से जागरूक और सशक्त बनाना। कंपनी के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

- वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति के अनुसार आबादी के सभी वर्गों के लिए पूरे भारत में वित्तीय शिक्षा को बढ़ावा देना।
- संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों, प्रशिक्षणों, कार्यक्रमों, अभियानों, चर्चा मंचों के माध्यम से आबादी के सभी तबकों के लिए देशभर में वित्तीय शिक्षा अभियान स्वयं चलाते हुए या अन्य संस्थाओं, संगठनों की सहायता से बिना शुल्क लिए/ सशुल्क चलाकर वित्तीय जागरूकता पैदा करना और सशक्तीकरण करना। इसके अलावा, वित्तीय शिक्षण में प्रशिक्षण दिलाना तथा इलेक्ट्रानिक और इलेक्ट्रानिक से इतर फॉर्मेटों में वित्तीय शिक्षण सामग्री, अभ्यास पुस्तकें, अभ्यास पत्रक, साहित्य, पैम्फलेट, पुस्तिकाएं, फ्लायर, तकनीकी सहायक सामग्री तैयार करना। साथ ही, वित्तीय साक्षरता की उन्नति के लिए वित्तीय बाजारों और वित्तीय डिजिटल प्रकारों पर लक्ष्यबद्ध सहभागियों के लिए समुचित वित्तीय साहित्य तैयार करना।

नवाचार संस्था

समूचे वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को गति प्रदान करने वाले वातावरण को बढ़ावा देने और सुकर बनाने की दृष्टि से 2022 में भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्वाधीन रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) नामक संस्था स्थापित की गई। इसकी स्थापना वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने और प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से की गई है ताकि करोड़ों भारतवासियों को उपयुक्त, सतत वित्तीय उत्पाद सुरक्षित व निर्बाध रूप से उपलब्ध हो सकें। इसके अतिरिक्त, आरबीआईएच नवीनतम प्रौद्योगिकी में अनुप्रयुक्त अनुसंधान व विशेषज्ञता का निर्माण करते हुए आंतरिक क्षमता का सृजन करेगा। यह हब वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं, नीति-निर्माता निकायों, प्रौद्योगिकीय उद्योग, तथा शैक्षणिक संस्थाओं के साथ सहयोगी व्यवस्था करेगा। साथ ही, विचार-विनिमय के लिए तथा वित्तीय नवाचार से संबंधित प्रतिदर्शों के विकास के लिए समेकित प्रयास करेगा।

अध्याय 23: अनुसंधान, सर्वेक्षण और डेटा प्रसार

अनुसंधान और ज्ञान का प्रसार

मूल्य स्थिरता, वित्तीय स्थिरता और समग्र व्यापक आर्थिक स्थिरता (कभी-कभी अस्थायी उतार-चढ़ाव के साथ) को बनाए रखना आधुनिक केंद्रीय बैंकों के प्राथमिक उद्देश्य हैं। इस दिशा में, मौद्रिक नीति और वित्तीय स्थिरता के क्षेत्र के नीति निर्माता पर्याप्त विश्लेषणात्मक और अभिनव अनुसंधान के साथ समय पर, प्रासंगिक और विश्वसनीय डेटा की धारा पर गहराई से निर्भर हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अर्थशास्त्र, वित्त और सांख्यिकी के क्षेत्र में अपनी स्वयं की अनुसंधान दक्षताएं विकसित की हैं और नियमित रूप से कई शोध पत्र और अनुभवजन्य अध्ययन तैयार करता है। किए गए अनुसंधान अधिकांशतः भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालने वाले समसामयिक मुद्दों से संबंधित हैं। अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्रों में समष्टि आर्थिक चरों का आकलन/पूर्वानुमान लगाना, मौद्रिक नीति के मुद्दे और चुनौतियाँ, इसके संचरण तंत्र, समकालीन वित्तीय स्थिरता के मुद्दे, सूचना प्रबंधन के लिए अभिनव तरीके और बिग डेटा एनालिटिक्स सहित नई विश्लेषणात्मक तकनीकों का उपयोग शामिल है। इनके साथ-साथ, कुछ मामलों में सूक्ष्म स्तरों के साथ अनुसंधान आउटपुट और सांख्यिकी का सक्रिय प्रसार बैंक की विभिन्न नियामक और मौद्रिक नीति कार्यों पर पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बढ़ाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अपने कर्मचारियों द्वारा किए गए अनुसंधान विश्लेषण का प्रसार भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन, भारतीय रिज़र्व बैंक के सामयिक पत्रों और भारतीय रिज़र्व बैंक वर्किंग पेपर श्रृंखला के माध्यम से करता है। विकास अनुसंधान समूह (डीआरजी) अध्ययनों के अंतर्गत, बाह्य विशेषज्ञों और भारतीय रिज़र्व बैंक के स्टाफ के सहयोग से अनुसंधान प्रकाशित किए जाते हैं ताकि वर्तमान हित के विषयों पर पेशेवर अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं के बीच रचनात्मक संवाद उत्पन्न किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की क्रमशः धारा 45-जेडके, धारा 45-जेडएल और धारा 45-जेडएम के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के संकल्प, कार्यवाहियों के कार्यवृत्त और व्यापक मौद्रिक नीति रिपोर्टें जारी करता है। आरबीआई प्रतिवर्ष दो अन्य रिपोर्टें प्रकाशित करने के लिए कानूनी दायित्व के तहत है - वार्षिक रिपोर्ट और भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट। वार्षिक रिपोर्ट, जो बैंक के कामकाज और संचालन पर विस्तृत विवरण प्रदान करती है, आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 53 (2) के अनुसार केंद्र सरकार को प्रस्तुत की जाती है। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36(2) के अंतर्गत प्रस्तुत भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के परिचालनों और कार्यनिष्पादन के संबंध में विस्तृत विवरण दिए जाते हैं। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट भारत की वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और वैश्विक और घरेलू कारकों से उत्पन्न जोखिमों के प्रति इसकी आघात-सहनीयता पर समग्र मूल्यांकन को दर्शाती है। रिपोर्ट में वित्तीय क्षेत्र के विकास और विनियमन से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की जाती है।

इन प्रकाशनों के अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक अनेक आवधिक और सामयिक प्रकाशन जारी करता है। सामयिक प्रकाशनों में मैनुअल, विजन दस्तावेज, दिशानिर्देश, कार्य समूह/समिति रिपोर्ट आदि शामिल हैं। शीर्ष प्रबंधन की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियां, अधिसूचनाएं, लेख, भाषण और साक्षात्कार, जो अर्थव्यवस्था के आकलन और दृष्टिकोण पर आरबीआई के विचारों को स्पष्ट करते हैं, आम जनता के लिए जारी किए जाते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक विशिष्ट विषयों की जांच करने के लिए नियुक्त विभिन्न समितियों की रिपोर्टें और अपने आंतरिक विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए चर्चा पत्र भी प्रकाशित करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक दोतरफा संचार के लिए अपनी वेबसाइट का प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहा है अर्थात् नीति में कोई भी बड़ा परिवर्तन, उदाहरण के लिए, पहले अपनी वेबसाइट पर मसौदे के रूप में डाला जाता है और सभी हितधारकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद बैंकों को अंतिम अनुदेश के रूप में जारी किया जाता है।

डेटा प्रसार नीति और तरीके

बैंक अपने नियामक और पर्यवेक्षी कार्यों के साथ-साथ अपनी नीति निर्माण प्रक्रियाओं के लिए इनपुट के रूप में विभिन्न स्रोतों से बड़ी जानकारी प्राप्त करता है। इसके अलावा, लेनदेन और अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से काफी डेटा प्राप्त किया जाता है। चूंकि डेटा सार्वजनिक नीति के लिए उपयोग की जाने वाली एक मूल्यवान संपत्ति है, इसलिए इसे सार्वजनिक डोमेन में एकत्रीकरण के स्तर तक प्रसारित करने की आवश्यकता है जो वाणिज्यिक विश्वास और अन्य वैधानिक नुस्खों के लिए गैर-संवेदनशील है।

अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के अनुसार अनुसंधानकर्ताओं, बाजार भागीदारों और आम जनता के लिए समष्टि-आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र के आंकड़ों की बड़ी मात्रा को संकलित और प्रसारित करने की भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वोत्तम की लंबी परंपरा रही है। आरबीआई के भीतर, सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम) को बैंकिंग, मौद्रिक, कॉर्पोरेट और बाहरी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ मौद्रिक नीति निर्माण के लिए समर्पित सर्वेक्षणों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले व्यापक आर्थिक और वित्तीय आंकड़ों को संकलित और प्रसारित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बैंक द्वारा सृजित मौद्रिक और भुगतान संतुलन (बीओपी) आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के विशेष डेटा प्रसार मानकों (एसडीडीएस) और सामान्य डेटा प्रसार प्रणाली (जीडीडीएस) के अनुरूप हैं। डीएसआईएम सूचना प्रबंधन के साथ-साथ अनुप्रयुक्त अनुसंधान के माध्यम से बैंक के विभिन्न कार्यों के लिए सांख्यिकीय और विश्लेषणात्मक सहायता भी प्रदान करता है। इस प्रयास में, विभाग बैंक के लिए एक केंद्रीकृत डेटाबेस (भारतीय अर्थव्यवस्था पर डेटाबेस - डीबीआई) और डेटा अंतराल को भरने के लिए अन्य संरचित सर्वेक्षण करने के अलावा सूचना प्रबंधन से संबंधित सहायता सेवाओं की एक श्रृंखला रखता है। रिज़र्व बैंक द्वारा संकलित आंकड़ों के अलावा, पोर्टल अन्य आधिकारिक एजेंसियों (जैसे, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संकलित राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी और मूल्य सूचकांक) द्वारा संकलित कुछ व्यापक आर्थिक चर पर डेटा का प्रसार भी करता है। सांख्यिकीय डेटा और मेटाडेटा eXchange (SDMX)-आधारित व्यावसायिक तत्वों पर केरी कार्यक्षमता सार्वजनिक डेटा प्रसार पोर्टल में उपलब्ध कराई गई है। केरी फ़ंक्शंस में आयाम, समय सीमा और आवृत्ति चयन शामिल हैं, साथ ही पूर्ण और सापेक्ष परिवर्तन जैसे उन्नत विकल्प लागू करना शामिल है। कई तत्वों की एक साथ तुलना की जा सकती है और अंतिम डेटा को लघु प्रारूप या लंबे प्रारूप (क्रॉस-अनुभागीय प्रारूप) में देखा जा सकता है।

बैंक सांविधिक और अन्य विवरणियों के माध्यम से विनियमित और गैर-विनियमित संस्थाओं से सूक्ष्म स्तर के आंकड़े एकत्र करता है और ऐसे आंकड़ों को अधिकांशतः समग्र स्तर पर सार्वजनिक क्षेत्र में प्रसारित करता है। एक सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में, बैंक सक्रिय रूप से सार्वजनिक डोमेन में समग्र और उपयुक्त अलग-अलग स्तर की जानकारी का प्रसार करता

है जो व्यापक आर्थिक, मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र के विकास की निगरानी के लिए उपयोगी होते हैं और सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 [धारा 43], बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 [धारा 28] और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अनुसार अन्य जानकारी भी उपलब्ध कराता है। बदलते समय के अनुरूप, परिवारों के मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण (आईईएसएच) और उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस) के इकाई स्तर के आंकड़े भी अनुसंधानकर्ताओं और विश्लेषकों द्वारा इन आंकड़ों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तरदाताओं की पहचान को उपयुक्त रूप से छिपाने के बाद जारी किए जाते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक विभिन्न प्रकाशनों के रूप में नियमित आवधिकता पर आंकड़ों का प्रसार करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिनमें से कुछ का विवरण नीचे दिया गया है:

- आरबीआई बुलेटिन एक मासिक प्रकाशन है जिसमें आरबीआई बैलेंस शीट, मुद्रा और बैंकिंग, सार्वजनिक वित्त, वित्तीय बाजार, बाहरी क्षेत्र आदि से संबंधित महत्वपूर्ण लेख, भाषण और आंकड़े शामिल हैं। बुलेटिन के सांख्यिकी भाग में लगभग 50 तालिकाएं हैं।
- साप्ताहिक सांख्यिकीय अनुपूरक (डब्ल्यूएसएस) में 14 तालिकाएं शामिल हैं, जो हर हफ्ते जारी की जाती हैं, जिसमें आरबीआई बैलेंस शीट मर्दाने, मौद्रिक सांख्यिकी, आरक्षित निधि स्थिति, वाणिज्यिक बैंक बैलेंस शीट मर्दाने, प्रमुख दरें आदि जैसे क्षेत्रों को कवर करने वाले उच्च आवृत्ति आंकड़े शामिल हैं।
- भारतीय अर्थव्यवस्था पर बैंक की वार्षिक हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स 240 तालिकाओं में प्रस्तुत अधिकांश समष्टि आर्थिक समय श्रृंखला डेटा के लिए एकल संदर्भ प्रकाशन के रूप में कार्य करती है। इस प्रकाशन का लगभग वास्तविक समय ऑनलाइन संस्करण डीबीआईई पोर्टल पर भी उपलब्ध कराया जाता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक वार्षिक रूप से भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी की पुस्तिका और राज्य वित्त बजट का अध्ययन भी प्रकाशित करता है।
- 'भारतीय राज्यों पर सांख्यिकी पुस्तिका': इस प्रकाशन के माध्यम से, भारत की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं पर एक व्यापक डेटा प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकाशन में 1951 से शुरू होने वाली विभिन्न समयावधियों में भारतीय राज्यों में सामाजिक-जनसांख्यिकी, स्वास्थ्य, राज्य घरेलू उत्पाद, कृषि, पर्यावरण, मूल्य और मजदूरी, उद्योग, बुनियादी ढांचे, बैंकिंग और राजकोषीय संकेतकों पर उप-राष्ट्रीय आंकड़े शामिल हैं। रिपोर्ट में 150 से अधिक तालिकाओं में डेटा शामिल है।
- 'राज्य वित्त: बजट का एक अध्ययन' प्राथमिक राज्य स्तरीय आंकड़ों के आधार पर राज्य सरकारों की राजकोषीय स्थिति की जानकारी और विश्लेषण प्रदान करता है।

मौद्रिक सांख्यिकी

आरबीआई के पास जुलाई 1935 से मौद्रिक आंकड़ों के संकलन और प्रसार की एक लंबी परंपरा है। मौद्रिक संकलित राशियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकांश प्रमुख प्रकाशनों जैसे वार्षिक रिपोर्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका, बुलेटिन, साप्ताहिक सांख्यिकीय अनुपूरक आदि में नियमित आधार पर प्रकाशित किए जाते हैं। वर्तमान में मौद्रिक आंकड़े बैंकिंग क्षेत्र और डाक प्राधिकरणों से लिए गए आंकड़ों के साथ बैलेंस शीट ढांचे पर संकलित किए जाते हैं। मौद्रिक संकलित

राशियों के संकलन के पीछे तर्क और विश्लेषणात्मक नींव विभिन्न रिपोर्टों के माध्यम से जनता को प्रदान की गई है, विशेष रूप से विभिन्न कार्य समूहों की रिपोर्टों के माध्यम से, जैसे कि मुद्रा आपूर्ति पर पहला कार्य समूह (एफडब्ल्यूजी) (1961), दूसरा कार्य समूह (एसडब्ल्यूजी) (1977) और "मुद्रा आपूर्ति पर कार्य समूह: संकलन की विश्लेषिकी और कार्यप्रणाली" (डब्ल्यूजीएमएस) (अध्यक्ष: डॉ. वाई.वी. रेड्डी)(1998)।

बैंकिंग सांख्यिकी

भारत में बैंकिंग प्रणाली में वाणिज्यिक, सहकारी बैंक और भुगतान बैंकों एवं लघु वित्तीय बैंकों की उभरती हुई श्रेणियां शामिल हैं। केंद्रीय बैंकिंग गतिविधियों के एक भाग के रूप में, देश की बैंकिंग प्रणाली के समग्र आर्थिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, आरबीआई विभिन्न सांविधिक और गैर-सांविधिक रिटर्न के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली पर विशाल मात्रा में डेटा एकत्र करता है। गैर-सांविधिक सांख्यिकीय विवरणियों में जमाराशियों और ऋण का स्थानिक वितरण, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण आदि जैसे बैंकिंग सूचना के पहलू शामिल हैं।

- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के अनुसार, प्रत्येक अनुसूचित बैंक (वाणिज्यिक और सहकारी बैंक) को रिपोर्टिंग शुक्रवार को कारोबार की समाप्ति पर भारत में अपनी आस्तियों और देयताओं की प्रमुख मदों को दर्शाने वाली पाक्षिक विवरणी प्रस्तुत करनी होती है। इन आंकड़ों के आधार पर, प्रणाली-स्तरीय बैंकिंग संकलित राशियाँ पाक्षिक आधार पर जारी की जाती हैं।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के वार्षिक लेखाओं पर आधारित विस्तृत बैंकिंग आंकड़े भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय तालिकाएं नामक प्रकाशन में जारी किए जाते हैं, जिसमें विभिन्न निष्पादन संकलित राशियाँ और अनुपात शामिल होते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) बैंकिंग सांख्यिकी समिति की सिफारिशों के बाद दिसंबर 1972 में स्थापित बुनियादी सांख्यिकीय रिटर्न (बीएसआर) प्रणाली के तहत बैंकिंग क्षेत्र द्वारा वित्तीय मध्यस्थता के प्रमुख मापदंडों पर व्यवस्थित रूप से सूक्ष्म डेटा एकत्र करता है। यह प्रणाली, जो पहले की यूनिफॉर्म बैलेंस बुक (यूबीबी) प्रणाली से विकसित हुई थी, भारत में बैंक ऋण के अनुभागीय और क्षेत्रीय प्रवाह में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।

बीएसआर प्रणाली के प्रमुख पहलू:

वार्षिक वेब प्रकाशन:

- आरबीआई वार्षिक आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था (डीबीआईई) पोर्टल पर अपने डेटाबेस पर "भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा क्रेडिट पर बुनियादी सांख्यिकीय रिटर्न" जारी करता है। यह प्रकाशन बीएसआर-1 प्रणाली के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) सहित एससीबी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों पर आधारित है। यह बैंक क्रेडिट की विभिन्न विशेषताओं पर विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, जैसे कि खाता प्रकार, संगठन, उधारकर्ता व्यवसाय / गतिविधि, जिला, जनसंख्या समूह, ब्याज दर, क्रेडिट सीमा और बकाया राशि।
- वार्षिक बीएसआर-2 विवरणी में जमा प्रकारों (चालू, बचत, अवधि), संस्थागत क्षेत्र-वार स्वामित्व, वैयक्तिक जमाराशियों का आयु-वार वितरण, सावधि जमाराशियों के आकार और ब्याज दर-वार वर्गीकरण और कर्मचारी

संख्याओं के संबंध में शाखा-वार आंकड़ों के विभिन्न आयामों पर विस्तृत आंकड़े शामिल होते हैं। यह डेटा, जो पहले 2018 तक बीएसआर-4 सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्र किया गया था, बैंकिंग क्षेत्र के भीतर जमा प्रवाह की गतिशीलता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।

त्रैमासिक डेटा प्रकाशन (आरआरबी को छोड़कर):

- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया ऋण पर तिमाही बीएसआर-1 में बैंक ऋण की विभिन्न विशेषताओं जैसे खाता प्रकार, संगठन, उधारकर्ता व्यवसाय/गतिविधि, जिला, जनसंख्या समूह, ब्याज दर, ऋण सीमा और बकाया राशि को शामिल किया गया है।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) में जमाराशियों के संबंध में तिमाही बीएसआर-2 में जमाराशियों के प्रकारों (चालू, बचत, मीयादी), संस्थागत क्षेत्र-वार स्वामित्व, वैयक्तिक जमाराशियों का आयु-वार वितरण, मीयादी जमाओं के आकार और ब्याज दर-वार वर्गीकरण और कर्मचारी संख्याओं के शाखा-वार आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं।

ये प्रकाशन हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण संसाधन हैं, जो भारत में बैंकिंग क्षेत्र की क्रेडिट और जमा गतिविधियों का गहन विश्लेषण और निगरानी प्रदान करते हैं। वैश्विक वित्तीय क्षेत्र के अंतर-संबंधों का अध्ययन करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी (आईबीएस) प्रणाली के अंतर्गत बैंकिंग प्रणाली के अंतर्राष्ट्रीय दावों और देयताओं पर विस्तृत सूचना भी एकत्र करता है, जिसका समन्वय बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) द्वारा किया जाता है। आईबीएस प्रणाली बैंकों की अंतर्राष्ट्रीय देयताओं (जैसे, अनिवासी जमाराशियों, विदेशी मुद्रा उधारों, बैंकों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बांड जारी करने) और दावों (जैसे, अनिवासियों को ऋण, निवासियों को विदेशी मुद्रा ऋण, पास में विदेशी मुद्रा, विदेशी निवेश) के बारे में जानकारी एकत्र/संकलन/प्रदान करती है।

बैंक द्वारा संकलित अधिकांश आंकड़े डीबीआईई के माध्यम से जारी किए जाते हैं और उपयोगकर्ता स्प्रेडशीट / पीडीएफ फॉर्म में संबंधित प्रकाशनों के इन पूर्व-स्वरूपित डेटा तालिकाओं तक पहुंच सकते हैं।

रिज़र्व बैंक 1972 से भारत में सभी बैंक शाखाओं/कार्यालयों/गैर-प्रशासनिक रूप से स्वतंत्र कार्यालयों (एनएआईओ) [जिन्हें पहले "मास्टर ऑफिस फाइल" (एमओएफ) प्रणाली के रूप में जाना जाता था] की निर्देशिका का रखरखाव करता है। शाखा लाइसेंसिंग और वित्तीय समावेशन नीतियों की उभरती जरूरतों के साथ-साथ अतिरिक्त आयामों/विशेषताओं के अपेक्षित कवरेज के अनुरूप, बैंकिंग बुनियादी ढांचे के लिए व्यापक केंद्रीय सूचना प्रणाली (सीआईएसबीआई) को विरासत वाले एमओएफ प्रणाली को बदलने के लिए जून 2019 में परिचालन किया गया है। वाणिज्यिक बैंकों के अलावा, सीआईएसबीआई सहकारी बैंकों, एटीएम और फिक्स्ड-लोकेशन बीसी को भी कवर करता है। सभी बैंक अपने बैंकिंग आउटलेट विवरण (जैसे, स्थान, संपर्क विवरण) पर ऑनलाइन जानकारी प्रस्तुत करते हैं और उचित सत्यापन के बाद मैनुअल हस्तक्षेप के बिना बीएसआर कोड आवंटित किए जाते हैं। यह प्रणाली बीएसआर, आईएफएससी और एमआईसीआर की मैपिंग प्रदान करती है और बैंक अपनी स्वयं की जानकारी प्राप्त करने के लिए सीआईएसबीआई पोर्टल का भी उपयोग कर सकते हैं। यह प्रणाली कई आयामों के साथ विभिन्न बैंकिंग आंकड़े उत्पन्न करने के लिए एक धुरी के रूप में भी कार्य करती है। इन आंकड़ों का उपयोग अद्यतन करने के लिए किया जाता है, आम नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए

डीबीआई पर बैंकिंग आउटलेटों का विवरण देने वाला एक "शाखा लोकेटर" पोर्टल भी प्रदान किया जाता है।

विदेशी क्षेत्र संबंधी सांख्यिकी

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संकलित एवं प्रसारित विदेशी क्षेत्र के आंकड़ों में भुगतान संतुलन (बीओपी), सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी ऋण, विदेशी निवेश अंतर्वाह, एनआरआई जमाराशियां, अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति (आईआईपी), विदेशी मुद्रा भंडार आदि शामिल हैं। इन घटकों में से प्रत्येक पर डेटा अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं (विशेष रूप से, आईएमएफ के भुगतान संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति मैनुअल - छठे संस्करण (बीपीएम 6) में निहित दिशानिर्देश) के अनुपालन में संकलित किया जाता है। एक वेब-आधारित विदेशी मुद्रा लेनदेन इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सिस्टम (एफईटीईआरएस) अधिकृत डीलरों (एडी) से देश में सभी विदेशी मुद्रा बिक्री / खरीद लेनदेन का उद्देश्य-वार विवरण एकत्र करता है, जिसका उपयोग भुगतान संतुलन (बीओपी) आंकड़े उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। (क) विदेशी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) और (ख) अनिवासी जमाराशियों [अनिवासी जमाराशियों पर आधारित - समेकित एकल प्रतिफल (एनआरडी-सीएसआर)] के कुल प्रवाह और स्टॉक का रख-रखाव समर्पित प्रणालियों के अंतर्गत किया जाता है और इनका उपयोग बीओपी तथा विदेशी ऋण सांख्यिकी के संकलन के लिए किया जाता है। इस प्रणाली को क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के साथ-साथ उनके आर्थिक वर्गीकरण (मर्चेन्ट श्रेणी कोड - एमसीसी) का उपयोग करके 'फेटर्स-कार्ड्स' नामक एक नए रिटर्न के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के अधिक विवरण एकत्र करने के लिए बनाया गया है।

विदेशी देयताओं और भारतीय कंपनियों की आस्तियों (एफएलए) पर वार्षिक गणना को 2011 से फेमा 1999 के तहत अधिसूचित किया गया है और इसे अनिवार्य रूप से उन सभी भारतीय निवासी कंपनियों/एलएलपी/अन्य [सेबी पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ), साझेदारी फर्मों, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी)] द्वारा प्रस्तुत किया जाना है, जिन्होंने पिछले किसी भी वर्ष (वर्षों) में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्राप्त किया है और/या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई) किया है। जिसमें चालू वर्ष भी शामिल है। यह आईएमएफ के समन्वित प्रत्यक्ष निवेश सर्वेक्षण (सीडीआईएस) और अर्ध-वार्षिक समन्वित पोर्टफोलियो निवेश सर्वेक्षण (सीपीआईएस) में भारत की भागीदारी को सुविधाजनक बना रहा है और साथ ही बीओपी और आईआईपी को संकलित करने के लिए मदद प्रदान करता है। यह विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के माध्यम से सीमा-पार वित्तीय सहयोग पर ध्यान केन्द्रित करता है और इसमें वैश्विक नुस्खों के अनुसार विदेशी संबद्ध व्यापार सांख्यिकी (एफएटीएस) की मदद शामिल हैं। इनके अलावा, यह कंपनियों के मानकीकृत वित्तीय मानदंडों पर भी सूचना एकत्र करता है और आंकड़े वेब आधारित विदेशी देयताओं और आस्तियों की सूचना रिपोर्टिंग (प्लेयर) पोर्टल के माध्यम से एकत्र किए जाते हैं।

बीओपी आंकड़े कुल स्तर के डेटा प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें अक्सर अतिरिक्त आयामों की जानकारी के लिए सर्वेक्षणों के माध्यम से पूरक होने की आवश्यकता होती है। चूंकि सॉफ्टवेयर से संबंधित निर्यात, सीमा-पार बैंकिंग सेवाएं और विदेशी तकनीकी सहयोग महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकिंग सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं (आईटीईएस)/बीपीओ सेवा निर्यात, म्यूचुअल फंड कंपनियों की विदेशी देयताओं और आस्तियों तथा विदेशी तकनीकी सहयोग (एफसीएस) पर सर्वेक्षण करता है। सर्वेक्षण के परिणाम भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर प्रसारित किए जाते हैं और इनके आधार पर लेख बुलेटिन में भी प्रकाशित किए जाते हैं। आरबीआई सूचना के

प्रमुख स्रोत के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन रिपोर्टिंग सिस्टम (आईटीआरएस) का उपयोग करते हुए, मासिक आधार पर आईएमएफ परिभाषा के अनुसार विदेशी निवेश प्रवाह की रिपोर्ट करता है।

अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को विशेष जमा योजनाओं के तहत भारत में बैंक खाता खोलने और बनाए रखने की अनुमति है - रुपये मूल्यवर्ग, और विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग (ऐसी जमा को एनआरआई जमा कहा जाता है) दोनों में। वर्तमान में एफसीएनआर (बी), एनआरआई और एनआरओ प्रकार के खातों के तहत एनआरआई जमाराशियों की बकाया स्थितियों और प्रवाह को आरबीआई द्वारा संकलित और प्रसारित किया जाता है।

आरबीआई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के सदस्य के रूप में सांविधिक और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार पर डेटा प्रकाशित करता रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित घटक शामिल हैं – (i) विदेशी मुद्रा संपत्ति (ii) सोना (iii) विशेष आहरण अधिकार और (iv) आईएमएफ में आरक्षित अंश स्थिति। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन पर अर्धवार्षिक रिपोर्ट नामक रिपोर्ट जारी की। फरवरी 2004 से भारतीय रिज़र्व बैंक अर्धवार्षिक रिपोर्टों को संकलित करने और उन्हें सार्वजनिक डोमेन में रखने की प्रक्रिया का अनुसरण कर रहा है ताकि देश के विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन के संबंध में अधिक पारदर्शिता लाई जा सके और प्रकटन के स्तर को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा, आरबीआई विदेशी मुद्रा बाजार से संबंधित जानकारी जैसे विनिमय दर, बाजार कारोबार और आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्रा की बिक्री और खरीद भी प्रकाशित करता है।

कॉर्पोरेट सांख्यिकी

आरबीआई गैर-सरकारी, गैर-वित्तीय कंपनियों और गैर-सरकारी एनबीएफसी संबंधी कॉर्पोरेट आंकड़ों का संकलन और प्रसार करता है। कॉर्पोरेट सांख्यिकी के लिए आंकड़ों के स्रोतों में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की एमसीए-21 प्रणाली के माध्यम से कंपनियों द्वारा दायर लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण शामिल हैं जिनमें परस्पर अनन्य दो प्रणालियां अर्थात् एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) और फार्म एओसी-4 (गैर-एक्सबीआरएल) प्लेटफार्म शामिल हैं। एक्सबीआरएल आधारित प्रणाली के अंतर्गत, प्रदत्त पूंजी (पीयूसी)/टर्नओवर के थ्रेशहोल्ड स्तर से ऊपर की सभी सूचीबद्ध कंपनियां और गैर-सूचीबद्ध कंपनियां अपने पूर्ण वार्षिक लेखे प्रस्तुत करती हैं, जबकि शेष कंपनियां फार्म एओसी-4 प्रणाली के माध्यम से सीमित आंकड़े प्रस्तुत करती हैं।

सूचीबद्ध गैर-सरकारी गैर-वित्तीय (एनजीएनएफ) कंपनियों के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों के आधार पर, आरबीआई अपनी वेबसाइट पर निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के प्रदर्शन पर नियमित (तिमाही और वार्षिक) डेटा रिलीज तैयार करता है और प्रकाशित करता है। राष्ट्रीय लेखा योगों के लिए एनएसओ, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र पर डेटा का उपयोग किया जाता है। कॉर्पोरेट प्रदर्शन अध्ययन मौद्रिक नीति के लिए इनपुट भी प्रदान करते हैं। निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र के निवेश इरादों का नियमित विश्लेषण और उनके परिकल्पित पूंजीगत व्यय का वार्षिक पूर्वानुमान परियोजना वित्तपोषण में लगे बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा उनके परियोजना प्रस्तावों की प्रत्याशित चरणबद्धता के आधार पर प्रसारित किया जाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) भारत में वर्तमान क्रेडिट सूचना प्रणाली में सुधार करने और अर्थव्यवस्था के भीतर क्रेडिट संस्कृति को मजबूत करने के लिए एक पहल कर रहा है। इस प्रयास में एक व्यापक क्रेडिट सूचना रिपोजिटरी

(सीसीआईआर) का चरणबद्ध विकास शामिल है, जो सूक्ष्म क्रेडिट जानकारी के विस्तृत और सत्यापित डेटाबेस के रूप में काम करेगा। अंततः, सीसीआईआर आरबीआई को उसके नीति निर्माण, नियामक कार्यों और पर्यवेक्षी गतिविधियों में सहायता करेगा जिससे समग्र क्रेडिट सूचना परिदृश्य में वृद्धि होगी।

मौद्रिक नीति सर्वेक्षण

सांविधिक अथवा सांख्यिकीय (गैर-सांविधिक) विवरणियों और वृहत आर्थिक संकेतकों के माध्यम से बैंकों और अन्य संस्थाओं द्वारा नियमित रिपोर्टिंग आर्थिक पैरामीटरों पर व्यक्तिगत/उद्योग धारणाओं द्वारा संपूरित की जाती है, जिन्हें संरचित सर्वेक्षणों के माध्यम से एकत्र किया जाता है। मौद्रिक नीति के प्रसारण में सुविधित अंतरालों, बढ़ते वैश्वीकरण और घरेलू वित्तीय प्रणाली के अधिक उदारीकरण को देखते हुए, त्वरित और भविष्योन्मुखी सूचना का महत्व बढ़ गया है। मौद्रिक नीति समिति उपभोक्ता विश्वास, परिवारों की मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं, कॉर्पोरेट क्षेत्र के प्रदर्शन, ऋण स्थितियों, औद्योगिक, सेवा और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के लिए दृष्टिकोण, उद्योग संघों से प्रतिक्रिया और पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं के अनुमानों को मापने के लिए घरेलू और उद्यम सर्वेक्षणों के परिणामों की समीक्षा करती है। मौद्रिक नीति निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली ऐसी सूचना एमपीसी संकल्प के तुरंत बाद सार्वजनिक डोमेन में जारी की जाती है ताकि निर्णय प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

समष्टि-आर्थिक संकेतकों पर पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं का सर्वेक्षण

विभिन्न प्रमुख आर्थिक संकेतकों का पूर्वानुमान एक दूरदर्शी व्यापक आर्थिक नीति के लिए एक पूर्व-आवश्यकता है। इन संकेतकों के भविष्य के मार्ग का अनुमान, जैसे आउटपुट वृद्धि, मुद्रास्फीति दर और विनिमय दर न केवल सेंट्रल बैंक के लिए, बल्कि सरकार, निजी व्यवसायों और व्यक्तिगत घरों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। बैंक आंतरिक विश्लेषण और व्यापक आर्थिक पूर्वानुमान अभ्यासों के पूरक के लिए सितंबर 2007 से व्यावसायिक पूर्वानुमानकर्ताओं (एसपीएफ) का सर्वेक्षण कर रहा है। एसपीएफ पैनलिस्ट विकास, मुद्रास्फीति, बैंकिंग क्षेत्र संकेतक, बाहरी क्षेत्र चर जैसे लगभग 20 प्रमुख व्यापक आर्थिक संकेतकों के वार्षिक और त्रैमासिक पूर्वानुमान प्रदान करते हैं।

औद्योगिक आउटलुक सर्वेक्षण (आईओएस)

आईओएस 1998 से संचालित किया जा रहा एक अग्रगामी त्रैमासिक सर्वेक्षण है, जो विभिन्न आकार और उद्योग-समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाली विनिर्माण कम्पनियों के एक पैनल को लक्ष्य करता है जिसमें भागीदारी स्वैच्छिक होती है। इसमें मांग की स्थितियों, वित्तीय स्थितियों, रोजगार स्थितियों और मूल्य स्थिति से संबंधित मापदंडों के समूह पर गुणात्मक प्रतिक्रियाओं के आधार पर चालू तिमाही के लिए कारोबारी मनोभावों और आगामी तिमाही के लिए अपेक्षाओं को शामिल किया जाता है। चुनिंदा मापदंडों पर बाद की दो तिमाहियों के दृष्टिकोण को भी 2020-21 से कैप्चर किया जा रहा है।

ऑर्डर बुक, इन्वेंट्री और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण

यह तिमाही सर्वेक्षण 2008 से आयोजित किया जा रहा है ताकि भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता उपयोग, ऑर्डर बुक और इन्वेंट्री पर डेटा अंतर को पूरा किया जा सके। इस सर्वेक्षण में नए आर्डरों की वास्तविक मात्रा, आदेशों का बैकलॉग, लंबित

आदेश, प्रगति पर चल रहे कार्य का ब्रेकअप, कुल माल-सूची में तैयार माल और कच्चा माल तथा संस्थापित क्षमता की तुलना में मात्रा और मूल्य दोनों के संदर्भ में मदवार उत्पादन एकत्र किया जाता है। ये आंकड़े क्षमता उपयोग (सीयू) का अनुमान प्रदान करते हैं।

मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण

मुद्रास्फीति प्रत्याशाएं लोगों के व्यवहार को प्रभावित करती हैं जैसे कि बचत और क्रय शक्ति उन तरीकों से जिनका दीर्घकालिक आर्थिक प्रभाव पड़ता है; वे मुद्रा, ब्याज दरों और कीमतों के बीच संबंध को प्रभावित कर सकती हैं और प्रभावित हो सकती हैं। मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं के उपाय केंद्रीय बैंकों के लिए महत्वपूर्ण हैं, विशेष रूप से मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे को अपनाने वालों के लिए। बैंक सितम्बर, 2005 से परिवारों का मुद्रास्फीति प्रत्याशा-सर्वेक्षण (आईईएसएच) कर रहा है। इस सर्वेक्षण में चुनिंदा परिवारों से तीन माह और एक वर्ष की अवधि में प्रत्याशित मूल्य परिवर्तनों (खाद्य, गैर-खाद्य, घरेलू टिकाऊ वस्तुओं, आवास और सेवाओं की लागत के मूल्यों) पर उनके अपने उपभोग बास्केट के आधार पर वर्तमान मुद्रास्फीति के उनके आकलन के अलावा गुणात्मक और मात्रात्मक प्रतिक्रियाएं प्राप्त होती हैं। उत्तरदाताओं में गृहिणी, वित्तीय क्षेत्र के कर्मचारी, अन्य वेतनभोगी कर्मचारी, स्व-नियोजित, सेवानिवृत्त व्यक्ति, दैनिक कर्मचारी और अन्य शामिल हैं। सर्वेक्षण आवधिकता द्विमासिक मौद्रिक नीति के अनुरूप होती है। सर्वेक्षण दो चरण के संभाव्यता नमूने डिजाइन का अनुसरण करता है और प्रत्येक दौर में 19 शहरों में 6,100 घरों को लक्षित करता है। सर्वेक्षण दौर के परिणाम बैंक की वेबसाइट पर जारी किए जाते हैं और सर्वेक्षण के यूनिट-स्तरीय डेटा पॉलिसी जारी होने के एक महीने बाद बैंक के डीबीआईई पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाते हैं।

उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण

उपभोक्ता विश्वास में परिवर्तन व्यावसायिक भावनाओं में बदलाव के माध्यम से वास्तविक आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। बैंक 2010 से अपना उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण आयोजित कर रहा है ताकि सामान्य आर्थिक स्थिति, कीमतों, रोजगार, वित्तीय स्थिति और चालू वर्ष के लिए उनकी अपनी आय और व्यय के साथ-साथ आगामी वर्ष के लिए अपेक्षाओं पर उपभोक्ताओं की धारणाओं का पता लगाया जा सके। सर्वेक्षण को दो-चरण संभाव्यता नमूनाकरण का उपयोग करके डिज़ाइन किया गया है। सर्वेक्षण में 19 शहरों के प्रत्येक दौर में 6100 परिवारों को लक्षित किया गया है और इसकी आवधिकता द्वि-मासिक मौद्रिक नीति के साथ संरेखित है। सर्वेक्षण दौर के परिणाम बैंक की वेबसाइट पर जारी किए जाते हैं और सर्वेक्षण के यूनिट-स्तरीय डेटा पॉलिसी जारी होने के एक महीने बाद बैंक के डीबीआईई पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाते हैं।

सेवाएं और अवसंरचना आउटलुक सर्वेक्षण

भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के महत्व को ध्यान में रखते हुए, इन क्षेत्रों के लिए एक भविष्योन्मुखी गुणात्मक सर्वेक्षण (आईओएस के अनुरूप) 2014 में शुरू किया गया था। इस सर्वेक्षण में तिमाही आधार पर सेवा और अवसंरचना क्षेत्रों में कार्यरत भारतीय कंपनियों के गुणात्मक मूल्यांकन और अपेक्षाओं को मांग की स्थितियों, मूल्य स्थिति और अन्य व्यावसायिक स्थितियों से संबंधित व्यावसायिक मापदंडों के एक सेट पर कैप्चर किया जाता है।

बैंक ऋण सर्वेक्षण

बैंक ऋण सर्वेक्षण (बीएलएस), जिसे पहले ऋण शर्तों का सर्वेक्षण (सीआरसीएस) कहा जाता था, प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों के लिए ऋण मापदंडों (अर्थात् ऋण मांग के साथ-साथ ऋण के नियम और शर्तों) पर तिमाही आधार पर किए गए प्रमुख अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी कुल बकाया ऋण के 90 प्रतिशत से अधिक को कवर करने वाले शीर्ष 30 बैंक) के गुणात्मक मूल्यांकन और अपेक्षाओं को कैप्चर करने वाला एक भविष्योन्मुखी सर्वेक्षण है। सर्वेक्षण भारत में एससीबी (आरआरबी को छोड़कर) के क्रेडिट विभाग में वरिष्ठ अधिकारी को संबोधित किया जाता है।

तदर्थ सर्वेक्षण

भारतीय स्थिति के लिए प्रासंगिक उभरते क्षेत्रों में डेटा अंतराल को भरने और नए आर्थिक क्षेत्रों में गतिविधि और मनोभावना को मापने के लिए अभिनव सर्वेक्षण करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, बैंक आर्थिक एजेंटों के व्यवहार के संबंध अधिक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए कई एक-बार/अनुवर्ती सर्वेक्षण आयोजित करता है। इनमें शामिल हैं:

- भारतीय स्टार्ट-अप सेक्टर (एसआईएसएस) पर एक पायलट सर्वेक्षण का उपयोग भारत में स्टार्ट-अप सेक्टर की प्रोफाइल बनाने के लिए किया जाएगा, जिसमें कारोबार, लाभप्रदता और कार्यबल से संबंधित आयाम शामिल हैं।
- नकद लेनदेन के क्षेत्रीय भिन्नता का आकलन करने के लिए तदर्थ सर्वेक्षण: परिवार और उद्यम।
- भुगतान के डिजिटल तरीकों का अंदाजा लगाने के लिए भुगतान प्रणालियों के विभिन्न पहलुओं पर ग्राहकों की आदतों का पता लगाने के लिए व्यक्तियों की खुदरा भुगतान आदतों (एसआरपीएचआई) पर सर्वेक्षण।
- भारत में बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग (एआई-एमएल) के अनुप्रयोगों पर पायलट सर्वेक्षण।
- भारत में बैंकों और एनबीएफसी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग (एआई-एमएल) के अनुप्रयोगों पर अनुवर्ती सर्वेक्षण।

विभाग मासिक रूप से गैर-पारंपरिक डेटा स्रोतों का उपयोग करके संगठित बाजार खाद्य मूल्य सूचकांक (ओएमएफपीआई) और श्रम बाजार के रुझानों को संकलित करता है। संगठित बाजार खाद्य मूल्य सूचकांक (ओएमएफपीआई) का संकलन खाद्य और पेय पदार्थों की लागत को ट्रैक करने के लिए एक पूरक है। ओएमएफपीआई डेटा के आधार पर, मासिक समीक्षा शीर्ष प्रबंधन को प्रस्तुत की जाती है। ओएमएफपीआई संकलन का उद्देश्य उपभोक्ता कीमतों पर उन्नत जानकारी प्रदान करना है जिसका उपयोग मुद्रास्फीति विश्लेषण और बैंक के नीतिगत उद्देश्यों के लिए इनपुट के रूप में किया जा सकता है। विभाग विभिन्न जॉब पोर्टलों से उच्च-कुशल और कम-कुशल नौकरी चाहने वालों से नौकरी पोस्टिंग डेटा भी एकत्र करता है। नौकरी पोस्टिंग डेटा का विश्लेषण करने का उद्देश्य ऑनलाइन नौकरी बाजार डेटा के आधार पर उपयोगी आंकड़े तैयार करना है जिसका उपयोग नीति निर्माण के लिए इनपुट के रूप में किया जा सकता है।

सूचकांक संकलन और प्रसार

घर की कीमत सूचकांक

आवास की कीमतों में परिवर्तन अचल संपत्ति गतिविधियों, क्रेडिट बाजार, घरेलू बैलेंस शीट से संबंधित हैं और इसलिए, व्यापक आर्थिक नीति और वित्तीय स्थिरता के रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण हैं। रिज़र्व बैंक अखिल भारतीय स्तर पर और दस प्रमुख शहरों (यथा अहमदाबाद, बंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, कानपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई) के लिए तिमाही आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई) (आधार 2010-11=100) संकलित करता है। यह सूचकांक दस प्रमुख शहरों में पंजीकरण प्राधिकरणों से प्राप्त लेनदेन-स्तर के आंकड़ों पर आधारित है। यह सूचकांक लैस्पेयर्स मूल्य सूचकांक फार्मूले का उपयोग करके संकलित किया जाता है तथा दो महीने के अंतराल पर आरबीआई की वेबसाइट के माध्यम से प्रसारित किया जाता है।

बैंकिंग सेवा मूल्य सूचकांक (बीकेएसपीआई)

भारत में कारबार सेवा मूल्य सूचकांक (बीएसपीआई) के विकास पर भारत सरकार की विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष प्रोफेसर सी.पी.चंद्रशेखर; अप्रैल 2007 में गठित) की सिफारिश पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, रिज़र्व बैंक प्रयोगात्मक बैंकिंग सेवा मूल्य सूचकांक (बीकेएसपीआई) का संकलन कर रहा है। बैंकिंग क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को दो व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, अर्थात्, प्रत्यक्ष सेवाएं (जैसे, शुल्क, कमीशन, ब्रोकरेज) और वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं अप्रत्यक्ष रूप से मापी जाती हैं – एफआईएसआईएम (जमाकर्ताओं और उधारकर्ताओं पर लागू दरों के बीच मार्जिन के रूप में अनुमानित)। वर्तमान में, सूचकांक को आधार वर्ष 2017-18 के साथ मासिक आवृत्ति पर लैस्पेयर्स के फार्मूले का उपयोग करके संकलित किया जाता है और आर्थिक सलाहकार कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को भेजा जाता है।

अनुसंधान और विश्लेषण

गुणवत्ता अनुसंधान प्रदान करने की खोज में, डीएसआईएम मौद्रिक नीति के मुद्दों पर व्यापक आर्थिक संकेतकों और मीडिया भावनाओं के विश्लेषण के आकलन के लिए उन्नत पूर्वानुमान और नाउकास्टिंग तकनीकों का उपयोग करके विभिन्न शोध और विश्लेषण करता है, विशेष रूप से बिग डेटा एनालिटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग तकनीकों का उपयोग करते हुए। मुद्रास्फीति और वृद्धि पर अंतर-विभागीय समूह (आईडीजी) के समग्र दायरे में वृहत आर्थिक विकास पर नीति-उन्मुख अनुसंधान जारी है। बैंक के परिचालन कार्यों का समर्थन करने के लिए निगरानी और डोमेन विशिष्ट प्रारंभिक चेतावनी पहचान क्षमताओं के लिए बिग डेटा एनालिटिक्स की शक्ति का उपयोग करने के लिए डेटा साइंस लैब (डीएसएल) की स्थापना की गई है। अनुसंधान का समर्थन करने के लिए सूक्ष्म स्तर के डेटा तक निर्बाध पहुंच के लिए केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) के तहत एक सूक्ष्म डेटा एक्सेस लैब (जीडीएएल) की स्थापना की जा रही है।

समन्वय और सूचना साझाकरण

सूचना का प्रसार करने, आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर अनुसंधान को सुविधाजनक बनाने, सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में सहायता करने और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) देशों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक द्वारा स्वचालित डेटा अपलोड सुविधा के साथ एक समर्पित सार्कफाइनेंस डेटाबेस (एसएफडीबी)

पोर्टल का प्रबंधन किया जा रहा है और डीबीआई पोर्टल के माध्यम से होस्ट किया जा रहा है। एसएफडीबी में समय श्रृंखला डेटा संबंधित राष्ट्रीय मुद्राओं और अमेरिकी डॉलर दोनों में सेक्टर-वार और आवृत्ति-वार प्रस्तुत किए जाते हैं।

- डीएसआईएम समय पर और आवधिक आधार पर सरकार और अन्य बाहरी एजेंसियों के साथ डेटा विनिमय का समन्वय करता है। बैंक नियमित आधार पर विभिन्न आवृत्ति के साथ बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) को विभिन्न डोमेन पर लगभग 175 डेटा श्रृंखला की रिपोर्ट जारी करता है।
- डीएसआईएम समितियों/कार्य समूहों में भागीदारी और राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता के माध्यम से आधिकारिक सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन और तकनीकी मार्गदर्शन में पद्धतिगत और अन्य विकास में योगदान देता है।

चूंकि देश की अर्थव्यवस्था बाह्य कारकों पर अधिकाधिक निर्भर होती जा रही है, इसलिए वैश्विक स्तर पर सूचना की उपलब्धता और सांख्यिकीय अंतरालों पर नए सिरे से ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। डीएसआईएम, आरबीआई हमारे वित्तीय आंकड़ों को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने में आईएमएफ, जी20, बीआईएस और एफएसबी जैसे अन्य अंतरराष्ट्रीय निकायों के साथ सक्रिय रूप से भागीदारी करता है। विभाग नीति उपयोग के लिए विश्वसनीय और समय पर आंकड़ों के नियमित संग्रह और प्रसार को लागू करने के उद्देश्य से जी20 डेटा गैप इनिशिएटिव्स (डीजीआई) द्वारा निर्धारित विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की दिशा में प्रगति की निगरानी के लिए समन्वय करता है।

अध्याय 24: फिनटेक और भारतीय रिज़र्व बैंक

सामान्यतः, फिनटेक का अर्थ वित्तीय प्रौद्योगिकी से होता है, जो तकनीकी रूप से सक्षम वित्तीय नवाचारों का वर्णन करता है। वित्तीय स्थिरता बोर्ड (Financial Stability Board) इसे इस प्रकार परिभाषित करता है: "तकनीकी रूप से सक्षम वित्तीय नवाचार, जो नए व्यावसायिक मॉडलों, अनुप्रयोगों, प्रक्रियाओं या उत्पादों का परिणाम हो सकता है, जिसका वित्तीय बाजारों, संस्थानों और वित्तीय सेवाओं के प्रावधान पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।" इसलिए, फिनटेक वित्त और प्रौद्योगिकी के संगम का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य वित्तीय सेवाओं के लिए नवाचारी समाधान विकसित करना है।

भारत में फिनटेक के विकास की शुरुआत 2000 के दशक के प्रारंभिक वर्षों से देखी जा सकती है, जब देश में डिजिटल भुगतान और मोबाइल बैंकिंग समाधानों में वृद्धि हुई। स्मार्टफोन की पहुंच और डिजिटल-उपभोक्ताओं के उदय के साथ फिनटेक क्षेत्र ने और अधिक गति पकड़ी। विभिन्न क्षेत्रों में फिनटेक स्टार्टअप्स का उदय हुआ, जिसमें डिजिटल ऋण, संपत्ति प्रबंधन, बीमा प्रौद्योगिकी (इंश्योरटेक), और ब्लॉकचेन आधारित समाधान शामिल थे। वर्ष 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI/एनपीसीआई) द्वारा यूनिकाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI/यूपीआई) की शुरुआत भारत की फिनटेक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई, जिसने बैंक खातों के बीच निर्बाध और त्वरित धन हस्तांतरण को सक्षम किया।

भारत में फिनटेक इकोसिस्टम ने वित्तीय सेवाओं की डिलीवरी को अधिक तीव्र, किफायती, दक्ष और व्यापक रूप से सुलभ बनाकर उल्लेखनीय सुधार किया है। वर्तमान में, फिनटेक इकाइयों की संख्या के मामले में, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा फिनटेक इकोसिस्टम है। भारत में फिनटेक अपनाने की दर 87 प्रतिशत है, जो वैश्विक औसत 67 प्रतिशत से कहीं अधिक है। भारत का फिनटेक बाजार वर्ष 2025 तक 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो वर्ष 2021 के 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से एक महत्वपूर्ण प्रगति है।

भारत में फिनटेक के विकास में भारतीय रिज़र्व बैंक की भूमिका

भारत में, फिनटेक द्वारा किए गए तकनीकी नवाचारों का परिणाम तीन मुख्य तत्वों के आपसी प्रभाव का परिणाम है: (i) डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, (ii) संस्थागत व्यवस्थाएँ, और (iii) नीति पहलकदमियाँ। जहाँ इंडिया स्टैक और जैम त्रयी (जन धन योजना, आधार और मोबाइल) ने एक मजबूत डिजिटल अवसंरचना और नवाचार के लिए सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान कर भारत में फिनटेक के विकास को प्रोत्साहित किया, वहीं भारतीय रिज़र्व बैंक ने संस्थागत व्यवस्थाओं और नीति पहलकदमियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसा कि नीचे विस्तृत किया गया है:

संस्था निर्माण

भारतीय रिज़र्व बैंक का फिनटेक विभाग 4 जनवरी 2022 से अस्तित्व में आया, लेकिन यह भारतीय रिज़र्व बैंक की फिनटेक संस्था निर्माण में पहली कोशिश नहीं थी, जो 1996 में बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसन्धान संस्थान (IDRBT/आईडीआरबीटी) की स्थापना के साथ शुरू हुई थी। इसके अलावा, स्वयं संगठन के भीतर एक वित्तीय प्रौद्योगिकी इकाई 2018

में स्थापित की गई थी, जो बाद में डीपीएसएस, केंद्रीय कार्यालय के फिनटेक विभाग के रूप में विकसित हुई और अंततः 2022 में एक अलग विभाग के रूप में उभर कर सामने आई।

इस प्रकार, भारतीय रिज़र्व बैंक की फिनटेक क्षेत्र के लिए संस्था निर्माण की पहलकदमियाँ निम्नलिखित हैं:

- (i) बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसन्धान संस्थान (IDRBT/आईडीआरबीटी) की स्थापना, जो 6 मार्च 1996 से भारतीय बैंकिंग उद्योग के डिजिटल परिवर्तन को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है;
- (ii) वर्ष 2008 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI/एनपीसीआई) का गठन, जिसने भारत में खुदरा डिजिटल भुगतान के परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण संगठन के रूप में उभर कर अपनी भूमिका निभाई है;
- (iii) IDRBT के तहत 2015 में भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवा (IFTAS) की स्थापना, RBI, बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा आवश्यक IT से संबंधित सेवाओं को डिजाइन, तैनात और प्रदान करने के लिए और 2019 में इसे अधिग्रहित किया;
- (iv) वर्ष 2016 में रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी लिमिटेड (ReBIT/रेबिट) की स्थापना, जिसका उद्देश्य रिज़र्व बैंक और बैंकिंग क्षेत्र की साइबर लचीलापन को मजबूत करना है;
- (v) वर्ष 2022 में वित्तीय सेवाओं में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (RBIH/ आरबीआईएच) की स्थापना;
- (vi) वर्ष 2022 में रिज़र्व बैंक के फिनटेक विभाग का गठन।

नीतिगत पहल

समय पर और उपयुक्त नीतिगत पहलों ने फिनटेक क्षेत्र के विकास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपने संस्थान निर्माण के व्यापक प्रयासों के मद्देनज़र, रिज़र्व बैंक ने अनेक नीतिगत पहलों की श्रृंखला को लागू किया है, जिनमें शामिल हैं:

- (i) **भुगतान बैंकों के लिए नियामक दिशा-निर्देश:** वर्ष 2014 में, रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और पिछड़े क्षेत्रों में डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भुगतान बैंकों के लिए नियामक दिशा-निर्देश जारी किए। भुगतान बैंकों को छोटे बचत खाते, भुगतान/प्रेषण सेवाएं, और अन्य बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को प्रदान करने के लिए अनिवार्य किया गया था, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी का उपयोग करके लागत को कम करना और दक्षता में सुधार करना था। इन बैंकों को उधार देने की गतिविधियों में संलिप्त होने से प्रतिबंधित किया गया, लेकिन उन्हें एटीएम/डेबिट कार्ड जारी करने और इंटरनेट बैंकिंग सहित भुगतान सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई।
- (ii) **अकाउंट एग्रीगेटरों के लिए नियामक दिशा-निर्देश:** वर्ष 2016 में, रिज़र्व बैंक ने अकाउंट एग्रीगेटरों (AA/एए) के लिए नियामक दिशा-निर्देश जारी किए ताकि वित्तीय संस्थानों और ग्राहकों के बीच वित्तीय जानकारी की आसान पहुंच और साझाकरण की जा सके। यह कदम 'ओपन बैंकिंग' की दिशा में भारत की पहल को प्रोत्साहित करने वाला साबित हुआ, जिसमें ग्राहकों की सहमति प्रबंधन के लिए जिम्मेदार एक मध्यस्थ के रूप में एए को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC/एनबीएफसी) के रूप में लाइसेंस दिया गया। एए को इस तरह के मध्यस्थ के रूप में कार्य करने का दायित्व

सौंपा गया था जो ग्राहकों की सहमति से विभिन्न स्रोतों से वित्तीय डेटा को एकत्र और समेकित कर, उसे मानकीकृत प्रारूप में बैंकों, एनबीएफसी, और अन्य वित्तीय संस्थानों जैसे अधिकृत संस्थाओं को प्रस्तुत करता है। इस पहल का उद्देश्य वित्तीय डेटा पोर्टेबिलिटी को बेहतर बनाना, ऋण मूल्यांकन प्रक्रियाओं में सुधार करना, और व्यक्तियों एवं व्यवसायों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक अधिक कुशलतापूर्वक पहुंच प्रदान करना था। दिशानिर्देशों में ग्राहकों की जानकारी की सुरक्षा के लिए सख्त डेटा गोपनीयता और सुरक्षा उपायों पर बल दिया गया था, साथ ही नियामक निगरानी की भी व्यवस्था की गई थी ताकि अनुपालन सुनिश्चित हो सके और वित्तीय तंत्र में विश्वास बना रहे।

- (iii) **प्री-पेड उपकरणों के लिए नियामक दिशा-निर्देश:** रिज़र्व बैंक ने प्री-पेड उपकरणों (PPI/पीपीआई) के लिए व्यापक नियामक दिशा-निर्देश जारी किए ताकि डिजिटल भुगतान तंत्र को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाया जा सके। इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य पीपीआई जारी करने वाली संस्थाओं, जैसे मोबाइल वॉलेट, प्री-पेड कार्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उपकरणों को विनियमित करना था, ताकि अंतर-संचालन, उपभोक्ता संरक्षण और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित हो सके। रिज़र्व बैंक ने पीपीआई उपयोगकर्ताओं के लिए केवाईसी (Know Your Customer/ अपने ग्राहक को जानिए) मानदंडों को अनिवार्य किया, जिससे धन-शोधन को रोका जा सके और वित्तीय प्रणाली की समेकता सुनिश्चित हो। इसके अतिरिक्त, दिशानिर्देशों में पीपीआई जारीकर्ताओं को एस्करो खातों को बनाए रखने और रिज़र्व बैंक को सख्त रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का पालन करने का निर्देश दिया गया, जिससे पीपीआई संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिल सके।
- (iv) **समकक्षीय उधार के लिए नियामक दिशा-निर्देश:** वर्ष 2017 में, रिज़र्व बैंक ने समकक्षीय (Peer-to-Peer/पी2पी) उधार मंचों के लिए नियामक दिशा-निर्देश प्रस्तुत किए ताकि इस वैकल्पिक ऋण खंड की निगरानी की जा सके और इसके विकास को प्रोत्साहित किया जा सके। इन दिशा-निर्देशों में पी2पी उधार मंचों को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs/एनबीएफसी) के रूप में कार्य करने और वित्तीय नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए रिज़र्व बैंक से आवश्यक पंजीकरण प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। इस ढांचे का उद्देश्य निवेशकों और उधारकर्ताओं के हितों की रक्षा करना था, जिसमें लेनदेन राशि और लीवरेज अनुपात पर सीमाएं लगाई गईं, जिससे पारदर्शिता में वृद्धि हो और प्रणालीगत जोखिमों को कम किया जा सके। इसके अतिरिक्त, सख्त पात्रता मानदंड और अनिवार्य क्रेडिट मूल्यांकन प्रक्रियाएं लागू की गईं ताकि जिम्मेदार ऋण देने की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा सके और संभावित डिफॉल्ट जोखिमों को कम किया जा सके।
- (v) **व्यापार प्राप्य बट्टाकरण के लिए नियामक दिशा-निर्देश:** वर्ष 2018 में, रिज़र्व बैंक ने व्यापार प्राप्य बट्टा प्रणाली (TReDS/ ट्रेड्स) के तहत (vii) व्यापार प्राप्य बट्टाकरण के लिए नियामक दिशा-निर्देश जारी किए, जिनका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME/एमएसएमई) द्वारा सामना की जा रही तरलता चुनौतियों का समाधान करना था। ट्रेड्स एक भुगतान प्रणाली है जिसे भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के तहत अधिकृत किया गया है। यह मंच एमएसएमई के चालान/बिलों को अपलोड करने, स्वीकार करने, डिस्काउंट करने, ट्रेडिंग और निपटान के लिए है, और इसमें प्राप्य फैक्टरिंग और देय फैक्टरिंग (reverse factoring/रिवर्स फैक्टरिंग) दोनों की सुविधा है। एमएसएमई विक्रेता, कॉर्पोरेट और अन्य खरीदार, जिनमें सरकारी विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs/पीएसयू) शामिल

हैं, और वित्तीय संस्थाएं (बैंक, एनबीएफसी-फैक्टर्स और अन्य वित्तीय संस्थान, जैसा कि अनुमत हो) ट्रेड्स में सीधे प्रतिभागी होते हैं। इस प्रणाली के तहत सभी लेन-देन एमएसएमई के लिए "बिना पुनःप्रेषण" (without recourse) होते हैं। इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य बढ़ाकर प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, एमएसएमई के लिए नकदी प्रवाह में सुधार करना और विलंबित भुगतानों की घटनाओं को कम करना था। रिज़र्व बैंक ने ट्रेड्स मंचों को कंपनियों अधिनियम के तहत पंजीकृत इलेक्ट्रॉनिक मंचों के रूप में संचालित होने की आवश्यकता तय की है, जिसमें प्रतिभागियों के लिए सख्त पात्रता मानदंड और केवाईसी (KYC) मानकों का पालन अनिवार्य किया गया है।

(vi) **विनियामक सैंडबॉक्स ढांचा:** वर्ष 2019 में विनियामक सैंडबॉक्स (RS/आरएस) ढांचे की स्थापना की गई ताकि वित्तीय सेवाओं में जिम्मेदार नवाचार को प्रोत्साहित किया जा सके, दक्षता में वृद्धि हो, और उपभोक्ताओं को लाभ प्राप्त हो। इस सैंडबॉक्स के भीतर, पात्र इकाइयां अपने नवीन उत्पादों या सेवाओं का नियंत्रित वातावरण में लाइव परीक्षण कर सकती हैं, जिसके लिए नियामक केवल परीक्षण के सीमित उद्देश्य से कुछ विनियामक छूट प्रदान (या न प्रदान) कर सकते हैं। आरएस ने वित्तीय समावेशन, भुगतान और ऋण, डिजिटल केवाईसी आदि पर केंद्रित कुछ विषयगत इकाइयों (कोहोर्टों) का संचालन किया है। इसका उद्देश्य इन नवाचारों की व्यवहार्यता और संभावित लाभों का मूल्यांकन करना है, और साथ ही उपभोक्ताओं और वित्तीय प्रणाली के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना है। 'खुदरा भुगतान', 'सीमापारीय भुगतान', 'एमएसएमई उधार' और 'वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम' जैसे चार थीम-आधारित कोहोर्ट पूरे किए जा चुके हैं। इसके अलावा, अनुभव और हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर अक्टूबर 2023 में बैंक द्वारा 'विषय तटस्थ' पांचवां कोहोर्ट शुरू किया गया है। विषय तटस्थ कोहोर्ट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विविध प्रकार के विचारों को सैंडबॉक्स के भीतर पोषक वातावरण मिले। साथ ही, आरएस के तहत 'ऑन टैप' सुविधा भी खोली गई है, जहां पहले बंद किए गए कोहोर्टों के लिए आवेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं। एक इंटर-ऑपरेबल विनियामक सैंडबॉक्स (IoRS/आईओआरएस) भी स्थापित है, जो ऐसे संकर उत्पादों/सेवाओं के परीक्षण को सुविधाजनक बनाता है जो एक से अधिक वित्तीय क्षेत्र विनियामकों के विनियामक दायरे में आते हैं।

(vii) **डिजिटल ऋण दिशानिर्देश:** वर्ष 2022 में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने तेजी से बढ़ते डिजिटल ऋण क्षेत्र की निगरानी और विनियमन के लिए डिजिटल ऋण दिशानिर्देश (Digital Lending Guidelines) पेश किए। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य डिजिटल ऋण पारिस्थितिकी तंत्र में पारदर्शिता, उपभोक्ता संरक्षण और प्रणालीगत स्थिरता को बढ़ाना था। प्रमुख पहलुओं में डिजिटल ऋणदाताओं का अनिवार्य पंजीकरण, सख्त डेटा सुरक्षा आवश्यकताएँ, और उधारकर्ताओं को शोषणकारी प्रथाओं से बचाने के लिए निष्पक्ष उधारी प्रथाओं पर दिशानिर्देश शामिल थे। वर्ष 2023 में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने डिजिटल ऋण दिशानिर्देशों को और अधिक परिष्कृत किया ताकि डिजिटल ऋण परिदृश्य में उभरती चुनौतियों का समाधान करते हुए निगरानी को मजबूत किया जा सके। जिम्मेदार ऋण प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए नए प्रावधान पेश किए गए, जिनमें ऋण वसूली प्रक्रियाओं के लिए सख्त मानदंड और ऋण की शर्तों और नियमों के लिए वर्धित प्रकटीकरण आवश्यकताएँ शामिल थीं। दिशानिर्देशों ने उधारकर्ताओं को डिजिटल ऋण क्षेत्र में सुविज्ञ वित्तीय निर्णय लेने के लिए आवश्यक ज्ञान से सशक्त बनाने हेतु ग्राहक शिक्षा और जागरूकता के महत्व पर भी जोर दिया।

(viii) **एचएआरबीआईएनजीआईआर (HaRBInger):** रिज़र्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र में मौजूदा चुनौतियों के लिए अभिनव समाधान खोजने के उद्देश्य से अपना ग्लोबल हैकथॉन "एचएआरबीआईएनजीआईआर" (HaRBInger) शुरू किया। पहला

HaRBInger वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था, और यह पहल निरंतर विकसित होती रही है, जो वित्तीय नवाचार के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसके अलावा, भारत की जी20 अध्यक्षता के अंतर्गत, 4 मई 2023 को, भारतीय रिज़र्व बैंक और बीआईएस इनोवेशन हब (BIS Innovation Hub) ने संयुक्त रूप से जी20 टेकस्प्रींट (TechSprint) के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया। यह एक वैश्विक दीर्घकालिक हैकाथॉन श्रृंखला है, जिसे बीआईएस इनोवेशन हब हर साल जी20 अध्यक्षता के साथ सह-मेजबानी करता है, और इसका उद्देश्य 'प्रौद्योगिकी समाधानों के माध्यम से सीमापारीय भुगतान' में सुधार को बढ़ावा देना है।

(ix) **स्व-विनियामक संगठन के लिए रूपरेखा:** भारतीय रिज़र्व बैंक की फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति नीति सहायक रही है, जिसका उद्देश्य नैतिक आचरण, प्रभावी शासन, जोखिम प्रबंधन सुनिश्चित करना और फिनटेक कंपनियों द्वारा स्वयं-नियमन को प्रोत्साहित करना है। इसके लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 मई 2024 को फिनटेक क्षेत्र के लिए स्व-नियामक संगठनों (SRO-FI/एसआरओ-एफटी) को मान्यता देने हेतु रूपरेखा जारी की। इस रूपरेखा का उद्देश्य यह है कि एसआरओ-एफटी नवाचार और नियामक अनुपालन के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखे, जिससे उपभोक्ता हितों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

(x) **यूनिफ़ाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (यूपीआई):** यूपीआई प्लेटफॉर्म स्मार्टफोन के माध्यम से पंजीकृत वर्चुअल पते का उपयोग करके भुगतान भेजने या प्राप्त करने के लिए एक एप्लिकेशन आधारित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है। यह प्रणाली फिनटेक के क्षेत्र में भुगतान का एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में उभर कर सामने आया है। इसने मोबाइल भुगतान के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किया है। यूपीआई ने अपनी सरलता, सुरक्षा और वास्तविक समय में लेन-देन करने की सुविधा के साथ भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली को पूरी तरह से बदल दिया है। यूपीआई जैसी फास्ट पेमेंट प्रणाली, जिसमें त्वरित फंड ट्रांसफर (24X7), वर्चुअल पेमेंट पते का उपयोग, और पीयर-टू-पीयर (P2P) व पीयर-टू-मर्चेन्ट (P2M) लेन-देन की सुविधा जैसे गुण हैं, उपयोगकर्ताओं के लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध हुई है। नवाचारों की निरंतर धारा ने इसकी उपयोगिता और सुगमता को बढ़ाया है, जिसके परिणामस्वरूप यूपीआई लेन-देन की मात्रा के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा खुदरा भुगतान प्रणाली बन गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूपीआई में कई नई सुविधाओं के समावेश का प्रोत्साहन किया है ताकि उत्पादों की पेशकश को समृद्ध किया जा सके। उदाहरण के लिए, यूपीआई123पे, यूपीआई लाइट ऑन-डिवाइस वॉलेट, यूपीआई से रुपये क्रेडिट कार्ड लिंक करना, और सिंगल-ब्लॉक-एंड-मल्टीपल-डेबिट्स के माध्यम से अधिदेशों को प्रोसेस करना। यूपीआई में एक अभिनव भुगतान मोड, यानी 'संवादी भुगतान' (Conversational Payments) को सक्षम किया गया है, जो उपयोगकर्ताओं को एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI/ एआई) संचालित प्रणाली के साथ संवाद करते हुए सुरक्षित वातावरण में लेन-देन प्रारंभ और पूर्ण करने की सुविधा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, बैंकों में पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइनों के साथ-साथ जमा खातों में से लेन-देन करने की अनुमति देकर यूपीआई के दायरे को और व्यापक बनाया गया। दूसरे शब्दों में, यूपीआई नेटवर्क अब बैंकों से क्रेडिट के माध्यम से वित्तपोषित भुगतान को भी सुगम बनाएगा।

(xi) **एटीएम पर इंटरऑपरेबल कार्ड-रहित नकद निकासी (ICCW/आईसीसीडब्ल्यू):** भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों, एटीएम नेटवर्क और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटरों (WLAO/ डब्ल्यूएलएओ) को अपने एटीएम पर इंटरऑपरेबल कार्ड-रहित नकद निकासी की सुविधा प्रदान करने की अनुमति दे दी है। इस सुविधा के तहत, एटीएम लेन-देन के दौरान

ग्राहक प्रमाणीकरण के लिए यूपीआई का उपयोग किया जाता है, जबकि निपटान नेशनल फाइनेंशियल स्विच (NFS/एनएफएस) अथवा एटीएम नेटवर्क्स के माध्यम से किया जाता है। कार्ड की आवश्यकता के बिना नकदी निकासी लेन-देन शुरू करने से स्किमिंग, कार्ड क्लोनिंग और डिवाइस टैम्परिंग जैसे धोखाधड़ी को रोकने में मदद मिलेगी।

- (xii) **इंटरनेट बैंकिंग लेन-देन के लिए इंटरऑपरेबल भुगतान प्रणाली:** इंटरनेट बैंकिंग लेन-देन जो पेमेंट एग्रीगेटर्स (PA/पीए) के माध्यम से संसाधित होते हैं, वे इंटरऑपरेबल नहीं होते हैं, अर्थात् अर्थात्, एक बैंक को विभिन्न ऑनलाइन व्यापारियों के प्रत्येक पीए के साथ अलग से जुड़ने की आवश्यकता होती है। इसका परिणाम यह होता है कि व्यापारियों को भुगतान की वास्तविक प्राप्ति में देरी होती है, जिससे निपटान जोखिम उत्पन्न हो सकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने एनपीसीआई भारत बिलपे लिमिटेड (NBBL/ एनबीबीएल) को इंटरनेट बैंकिंग लेन-देन के लिए इंटरऑपरेबल भुगतान प्रणाली लागू करने की मंजूरी दे दी है। यह नई प्रणाली व्यापारियों के लिए धन के त्वरित निपटान की सुविधा प्रदान करेगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा फिनटेक को अपनाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय समावेशन, दक्षता और भारत के वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में विनियामक पर्यवेक्षण को बढ़ाने के लिए फिनटेक नवाचारों को महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में स्वीकार किया है। विशेष रूप से, भारतीय रिज़र्व बैंक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC/ सीबीडीसी) के अन्वेषण में अग्रणी रहा है, जिसका उद्देश्य मुद्रा निर्गमन और लेन-देन का अंकुरण करना है। इसी के साथ, एकीकृत ऋण इंटरफेस (जो पूर्व में 'घर्षण रहित ऋण के लिए सार्वजनिक तकनीकी मंच' के रूप में जाना जाता था), एक ऐसा मंच है जो ऋणदाताओं को आवश्यक डिजिटल जानकारी के निर्बाध प्रवाह की सुविधा प्रदान करके घर्षण रहित ऋण संवितरण में सक्षम बनाता है। इस तरह यह उधार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (DPI/डीपीआई) के रूप में उभर रहा है। इसके अतिरिक्त, पर्यवेक्षी प्रौद्योगिकी (SupTech/ सुपटेक) के माध्यम से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने उन्नत विश्लेषिकी और डेटा-संचालित उपकरणों का उपयोग करके अपने पर्यवेक्षण ढांचे को मजबूत किया है, जो उद्विकासी तकनीकी परिदृश्यों के बीच वित्तीय संस्थानों की सशक्त निगरानी सुनिश्चित करता है।

केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC/ सीबीडीसी)

वर्ष 2022 में पायलट आधार पर केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC/सीबीडीसी) की शुरुआत नवीनतम नवाचार है जो 'अधिक कुशल और किफायती मुद्रा प्रबंधन प्रणाली' प्रदान करेगी³²।

सीबीडीसी का उद्देश्य डिजिटल मुद्राओं के लाभ, जैसे तेज और सुरक्षित लेनदेन, को पारंपरिक कागजी मुद्राओं की विश्वास और स्थिरता के साथ जोड़ना है। उम्मीद है कि यह नकदी और मौजूदा भुगतान प्रणालियों के पूरक के रूप में काम करेगी। 'डिजिटल मुद्रा' भारत की मुद्रा, रुपया, का डिजिटल रूप है और यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी की गई वैध मुद्रा है। इसे मूल्य संचित करने हेतु रखा जा सकता है या लेनदेन करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। उपयोग के आधार पर, सीबीडीसी को थोक (CBDC-W / सीबीडीसी-डब्ल्यू) और खुदरा (CBDC-R / सीबीडीसी-आर) में वर्गीकृत किया जा सकता है। जहाँ थोक सीबीडीसी (सीबीडीसी-डब्ल्यू) वित्तीय बाजार के संस्थागत प्रतिभागियों के लिए है, वहीं खुदरा सीबीडीसी (सीबीडीसी-आर)

³² (GOI, 2022; RBI, 2022c)

खुदरा उपभोक्ताओं के लिए जोखिम-मुक्त डिजिटल विनिमय माध्यम है। पायलट में सीबीडीसी-आर के प्रारंभिक उपयोग व्यक्ति से व्यक्ति (P2P/पी2पी) और व्यक्ति से व्यापारी (P2M/पी2एम) लेनदेन शामिल थे। खुदरा पायलट ने प्रोग्राम करने योग्य और ऑफलाइन कार्यक्षमताओं का उपयोग करते हुए अतिरिक्त अवसर भी पेश किये हैं। थोक सीबीडीसी पायलट में सरकारी प्रतिभूतियों के द्वितीयक बाजार लेनदेन और कॉल मनी लेनदेन शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, सीबीडीसी को सीमा-पार लेनदेन को सुगम और सुधारने के अवसर के रूप में देखा जा रहा है। सीबीडीसी अंतरराष्ट्रीय प्रेषण की लागत को कम करके, कई मध्यस्थों से जुड़े जोखिमों को न्यूनतम करके, तेजी से निपटान समय के माध्यम से दक्षता बढ़ाकर, 24x7 उपलब्धता प्रदान करके और भुगतान की स्थिति में अधिक पारदर्शिता लाकर लाभ प्रदान कर सकती है (Auer et al., 2021)। भारतीय रिज़र्व बैंक सीमा-पार सीबीडीसी के लिए कई उपयोग मामलों का परीक्षण कर रहा है, जिसमें द्विपक्षीय साझेदारियाँ और बहुपक्षीय बीआईएस (BIS) परियोजनाओं में भागीदारी शामिल है।

एकीकृत ऋण इंटरफेस (यूएलआई/ULI)

एकीकृत ऋण इंटरफेस (जो पूर्व में 'घर्षण रहित ऋण के लिए सार्वजनिक तकनीकी मंच' के रूप में जाना जाता था), एक ऐसा मंच है जो निर्बाध ऋण वितरण को सक्षम बनाता है।

एकीकृत ऋण इंटरफेस की परिकल्पना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की गई थी और इसे रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) द्वारा विकसित किया गया था। 'घर्षण रहित ऋण के लिए सार्वजनिक तकनीकी मंच' (PTPFC/पीटीपीएफसी) के विकास की घोषणा दिनांक 10 अगस्त 2023 को जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के भाग के रूप में की गई थी। इसके बाद, 17 अगस्त 2023 से इसका पायलट शुरू हुआ।

यूएलआई एक उद्यम-ग्रेड ओपन आर्किटेक्चर मंच है, जो ऋण पारिस्थितिकी तंत्र के संचालन में केंद्रीय भूमिका निभाता है। यह विभिन्न डेटा स्रोतों से डिजिटल रूप से जानकारी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे यह ऋण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (DPI/डीपीआई) के रूप में उभर रहा है। यूएलआई वित्तीय सेवा प्रदाताओं और कई डेटा प्रदाताओं को एक मानकीकृत, प्रोटोकॉल-आधारित आर्किटेक्चर और एक ओपन एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) के माध्यम से एक साथ लाता है। प्लग-एंड-प्ले मॉडल पर काम करने वाला यह मंच ऋणदाताओं और डेटा प्रदाताओं के बीच जटिल एकैक एकीकरण (इंटीग्रेशन) की आवश्यकता को समाप्त करता है। इससे ऋणदाता मंच से केवल एक बार जुड़कर, प्रभावी ऋण मूल्यांकन और निर्णय लेने के लिए आवश्यक व्यापक डेटा पा सकते हैं। इस सुव्यवस्थित प्रक्रिया का सीधा लाभ उपभोक्ताओं को मिलता है, क्योंकि इसके द्वारा उन्हें कागजी दस्तावेज़ीकरण या बैंक शाखाओं में शारीरिक रूप से उपस्थित हुए बिना ही उनके अनुरूप ऋण विकल्प उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे समय और लागत दोनों में कमी आती है।

वर्तमान में, 16 ऋणदाता एकीकृत ऋण इंटरफेस (यूएलआई) के माध्यम से 50 से अधिक डेटा सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। इन सेवाओं में विभिन्न राज्यों के डिजिटल भूमि रिकॉर्ड, जीएसटीएन डेटा, अकाउंट एग्रीगेशन (अकाउंट एग्रीगेटरों द्वारा), घर/संपत्ति खोज डेटा, ऋण गारंटी (CGTMSE/ सीजीटीएमएसई के माध्यम से) आदि शामिल हैं। ये डेटा स्रोत 12 डिजिटल ऋण प्रक्रियाओं को सुगम बनाते हैं, जिनमें किसान क्रेडिट कार्ड, डिजिटल मवेशी ऋण, एमएसएमई (अरक्षित) ऋण, आवास ऋण, व्यक्तिगत ऋण, ट्रैक्टर ऋण, माइक्रो बिजनेस ऋण, वाहन ऋण, डिजिटल गोल्ड ऋण, ई-मुद्रा ऋण, पेंशन और डेयरी रखरखाव ऋण शामिल हैं।

यूएलआई का विस्तार निरंतर जारी है, जिसमें अतिरिक्त ऋणदाताओं, डेटा सेवा प्रदाताओं और नई ऋण प्रक्रियाओं को जोड़ा जा रहा है। वर्तमान में यह मंच व्यापार से व्यापार (B2B/बी2बी) इको-सिस्टम के अंतर्गत संचालित होता है। जब मंच स्थिर हो जाएगा, तब इसका दूसरा चरण बी2बी मॉडल से व्यापार से ग्राहक (B2C/बी2सी) मॉडल में परिवर्तन के लिए डिज़ाइन किया जाएगा।

पर्यवेक्षी प्रौद्योगिकी (SupTech/ सुपटेक)

पर्यवेक्षी प्रौद्योगिकी (सुपटेक) समाधान डेटा एनालिटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मशीन लर्निंग (ML) का उपयोग करके बड़े पैमाने पर वित्तीय डेटा का विश्लेषण करते हैं, जिससे बैंकिंग, प्रतिभूति और बीमा क्षेत्रों में अनियमितताओं का पता लगाने और संभावित जोखिमों की पहचान की जा सके। इन समाधानों को वित्तीय क्षेत्र की निगरानी और पर्यवेक्षण को सुदृढ़ करने के लिए नियामक प्राधिकरण तेजी से अपना रहे हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक में सुपटेक का उपयोग डेटा संग्रहण और विश्लेषण के लिए हो रहा है, जैसे आयात डाटा प्रोसेसिंग और निगरानी प्रणाली (IDPMS/ आईडीपीएमएस), निर्यात आँकड़ों की प्रक्रिया और निगरानी प्रणाली (EDPMS/ ईडीपीएमएस) और केंद्रीय सूचना भंडार (CRILC/क्रिलक) जैसे मंचों का उदाहरण है। इसके साथ ही, बैंकों की जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण बड़े पैमाने पर डेटा-चालित होती है, जो सुपटेक का एक उदाहरण है। हाल ही में, एडवांस्ड सुपरवाइजरी एनालिटिक्स ग्रुप (ASAG/एसएसजी) की स्थापना की गई है, जो सोशल मीडिया एनालिटिक्स, केवाईसी अनुपालन और शासन प्रणाली की प्रभावशीलता मापने के लिए एमएल मॉडल का उपयोग करता है। इसके अतिरिक्त, "दक्ष" नामक एक उन्नत परोक्ष पर्यवेक्षी निगरानी प्रणाली की स्थापना की गई है, जो पर्यवेक्षण प्रक्रियाओं को डिजिटलाइज करने में मदद कर रहा है। एकीकृत अनुपालन प्रबंधन एवं ट्रेकिंग प्रणाली (ICMTS/आईसीएमटीएस) और केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (CIMS/सीआईएमएस) दो प्रमुख सुपटेक पहल हैं, जिन्हें क्रमशः पर्यवेक्षित संस्थानों द्वारा रिपोर्टिंग को आसान बनाने और डेटा प्रबंधन व डेटा विश्लेषण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए लागू किया जा रहा है।

सीमापार भुगतान की सुविधा

- i. प्रोजेक्ट नेक्सस - भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल होकर तत्काल सीमापार खुदरा भुगतान सक्षम करने के लिए देशी तेज़ भुगतान प्रणाली (FPS/एफपीएस) को आपस में जोड़ने की एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल में भाग लिया है। नेक्सस, अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (BIS/बीआईएस) के इनोवेशन हब द्वारा परिकल्पित है, जिसका उद्देश्य चार एसियान देशों (मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड) और भारत के एफपीएस को जोड़ना है। ये देश इस मंच के संस्थापक सदस्य और पहले प्रस्तावक देश होंगे। भविष्य में इस प्लेटफॉर्म को और अधिक देशों में विस्तारित किया जा सकता है। इस प्लेटफॉर्म के 2026 तक लाइव होने की आशा है। एक बार कार्यात्मक होने के बाद, नेक्सस खुदरा सीमापारीय भुगतान को कुशल, तेज़ और अधिक लागत प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- ii. भारतीय रिज़र्व बैंक और सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण (MAS/ एमएस) ने 21 फरवरी 2023 को अपने एफपीएस, एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (UPI) और PayNow की सहबद्धता का शुभारंभ किया, जिससे इन दोनों प्रणालियों के उपयोगकर्ता पारस्परिक आधार पर त्वरित और कम लागत में सीमापार व्यक्ति से व्यक्ति (P2P/पी2पी) भुगतान कर

सकते हैं। UPI-PayNow सहबद्धता से दोनों देशों के बीच व्यापार, यात्रा और प्रेषण प्रवाह को और अधिक सुदृढ़ करने की उम्मीद है।

इसके अतिरिक्त, भूटान, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में क्यूआर कोड के माध्यम से यूपीआई की स्वीकृति सक्षम कर दी गई है। इन देशों की यात्रा करने वाले भारतीय पर्यटक अपने यूपीआई ऐप्स का उपयोग करके व्यापारी स्थलों पर भुगतान कर सकते हैं। फरवरी 2024 में भारत और मॉरीशस के बीच यूपीआई संबद्धता शुरू की गई। इस संबद्धता के साथ, मॉरीशस जाने वाला एक भारतीय यात्री यूपीआई का उपयोग करके मॉरीशस में एक व्यापारी को भुगतान करने में सक्षम होगा। इसी प्रकार, मॉरीशस का यात्री मॉरीशस के इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम (आईपीएस) ऐप का उपयोग करके भारत में भी ऐसा कर सकेगा। साथ ही, फरवरी 2024 में भारत और श्रीलंका के बीच भी यूपीआई संबद्धता शुरू की गई, जिससे भारतीय पर्यटकों को श्रीलंका में यूपीआई ऐप्स का उपयोग करके क्यूआर कोड आधारित भुगतान करने की सुविधा प्राप्त हुई है।

निष्कर्षतः, भारतीय रिज़र्व बैंक के फिनटेक प्रयास इसकी संस्थागत निर्माण और नीतिगत नवाचार में भूमिका को रेखांकित करते हैं। सीबीडीसी जैसी तकनीकों को अपनाकर, सुपटेक के माध्यम से पर्यवेक्षी ढांचे को मजबूत करते हुए, डिजिटल मंचों के जरिए सुगम ऋण वितरण को सक्षम बनाते हुए और अधिक प्रभावी क्रॉस-बॉर्डर भुगतान को सुगम बनाकर, भारतीय रिज़र्व बैंक एक ऐसे भविष्य-तैयार वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र की दिशा में अग्रसर हो रहा है, जो नवाचार और स्थिरता के बीच संतुलन बनाता है।

अध्याय 25: अंतरराष्ट्रीय संबंध

पिछले कुछ दशकों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि, वैश्विक मूल्य शृंखलाओं के माध्यम से वितरित उत्पादन प्रक्रियाओं और सीमा पार वित्तपोषण के कारण बढ़ते अंतरराष्ट्रीय आर्थिक एकीकरण के कारण वैश्विक वित्तीय संरचना को पहले की तुलना में अब अंतरसंबद्धता काफी बढ़ गई है। जबकि इस प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप वैश्विक पूंजी प्रवाह में वृद्धि हुई है और वैश्विक नियामक मानकों का लगातार विकास हुआ है, बढ़ती परस्पर संबद्धता ने वित्तीय प्रणालियों को वित्तीय अस्थिरता की चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूर किया है।

प्रथम विश्व युद्ध और 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद जर्मनी पर लगाए गए रेपरेशन भुगतानों के निपटाने के लिए 1930 में बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) की स्थापना के बाद से आधुनिक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक कूटनीति का एक लंबा इतिहास रहा है। इसके कारण अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक (डब्ल्यूबी) समूह संस्थानों की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य आर्थिक स्थिरता (आईएमएफ) को फिर से स्थापित करना और अर्थव्यवस्थाओं के युद्ध के बाद पुनर्निर्माण (डब्ल्यूबी) करना था। इसके अलावा, व्यापार और टैरिफ पर सामान्य समझौता (जो बाद में विश्व व्यापार संगठन में विकसित हुआ) 1947 में स्थापित किया गया था, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, जिसे युद्ध के बाद की अवधि में आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण चालक के रूप में देखा गया था।

जबकि ब्रेटन वुड्स संस्थानों की स्थापना के शुरुआती तीन दशकों में आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया कुछ हद तक धीरे-धीरे आगे बढ़ी, दुनिया भर में आर्थिक विकास असमान रहा, उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप जैसे अधिक उदार अर्थव्यवस्था वाले देशों में तेजी से विकास देखा गया। इसके अलावा, 1973 के तेल संकट और ब्रेटन वुड्स प्रणाली के पतन के बाद आर्थिक सहयोग में दरारें पड़ने लगीं, जिसके बाद आईएमएफ द्वारा सुझाई गई निश्चित विनिमय दर व्यवस्था को बंद कर दिया गया। इसके बाद, आईएमएफ ने स्वतंत्र रूप से अस्थायी विनिमय दर व्यवस्थाओं और अन्य आर्थिक उदारीकरण उपायों (कम राजकोषीय व्यय और व्यापार पर कम सरकारी नियंत्रण सहित) में बदलाव की पैरवी करना शुरू कर दिया, जिन्हें अधिक उन्नत अर्थव्यवस्था नीतियों के रूप में देखा गया। इसने आईएमएफ के नीतिगत परामर्श को लेकर असंतोष पैदा किया, विशेष रूप से 1990 के दशक के अंत में उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) से जुड़े ऋण संकटों की एक शृंखला जो मैक्सिकन पेसो संकट से शुरू हुआ और उसके बाद 1997 एशियाई वित्तीय संकट और 1998 में रूसी वित्तीय संकट पैदा हुए।

इन घटनाओं के कारण 1999 में आईएमएफ-विश्व बैंक की बैठकों के अलावा दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों (एफएमसीबीजी) की अनौपचारिक बैठकें हुईं, ताकि उनके बीच नीतिगत सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा की जा सके। यह अनौपचारिक समूह बाद में ग्रुप ऑफ ट्वेंटी (जी20) में विकसित हुआ। दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की इसी तरह की अनौपचारिक बैठक भी 1998 में शुरू हुई थी, जो बाद में सार्क फाइनेंस समूह में विकसित हुई। इन घटनाओं से पता चला है कि तेजी से वैश्वीकृत हो रही दुनिया में, जी-7 की तुलना में प्रमुख विश्व अर्थव्यवस्थाओं का एक व्यापक और स्थायी समूह, जिसमें प्रमुख ईएमडीई शामिल हैं, वैश्विक प्रकृति के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अधिक उपयुक्त मंच होगा।

इसके बाद, 2007-08 में, वैश्विक वित्तीय प्रणाली ने वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) का सामना किया। जीएफसी के दौरान,

अमेरिकी बंधक बाजार में उथल-पुथल शीघ्रता से अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में फैल गई और इन स्पिलओवर के कारण वास्तव में विश्व स्तर पर वित्तीय संकट के रूप में उभर गया। जीएफसी ने यह भी प्रदर्शित किया कि वित्तीय अस्थिरता वास्तविक आर्थिक गतिविधि में तेजी से संक्रमण का कारण बन सकती है, और इसलिए, स्थिर आर्थिक विकास को प्राप्त करने में एक मजबूत वित्तीय प्रणाली की आवश्यकता को रेखांकित किया। इसने विकास को मजबूत स्तर पर फिर से स्थापित करने के लिए कुछ हद तक राजनीतिक रूप से कठिन संरचनात्मक सुधारों के कार्यान्वयन की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला, और जो कई बार वित्त मंत्रालयों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के दायरे से परे थे। तदनुसार, जीएफसी के बाद, जी 20 एफएमसीजी, जो अब तक एफएमसीजी का एक अनौपचारिक समूह था, को राष्ट्रीय नेताओं के एक औपचारिक समूह के रूप में गठित किया गया, जो वित्त ट्रेक के तहत एफएमसीजी के दायरे से परे मुद्दों पर सहयोग पर चर्चा करने के लिए एक अलग ट्रेक (शेरपा ट्रेक) है।

इसके अलावा, वास्तविक आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने में वित्तीय स्थिरता की भूमिका को मिली मान्यता को देखते हुए वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) को तीसरे जी20पिट्सबर्ग शिखर सम्मेलन के बाद 2009 में वित्तीय स्थिरता फोरम (एफएसएफ) के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया। इसी तरह, सबसे बड़े ईएमडीई के बीच सहयोग की आवश्यकता भी महसूस की गई और इसके परिणामस्वरूप ब्रिक्स समूह की स्थापना हुई³³। जीएफसी के दौरान संक्रमण की गति और पैमाने ने यह स्पष्ट कर दिया कि वैश्विक वित्तीय प्रणाली की परस्पर प्रकृति को देखते हुए, वैश्विक प्रकृति के उभरते जोखिमों की पहचान करने, वैश्विक नियामक मानकों को विकसित करने और उनके निरंतर कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय प्राधिकरणों के बीच घनिष्ठ सहयोग, वैश्विक महत्व के संकट की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अनिवार्य था। इस प्रकार, जीएफसी के बाद की अवधि में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय कूटनीति पर अधिक महत्व दिया गया, जिसमें केंद्रीय बैंकों, वित्तीय क्षेत्र के नियामकों और पर्यवेक्षकों ने वित्तीय स्थिरता के संरक्षण पर चर्चा की।

जीएफसी के बाद वैश्विक चर्चाओं की इस पृष्ठभूमि में और बहुपक्षीय और क्षेत्रीय संस्थानों के साथ बढ़ती भागीदारी को और बढ़ावा देने के लिए, 03 नवंबर 2014 को बैंक में विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय विभाग (आईडी) की स्थापना की गई। विभाग भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय कूटनीति के लिए बैंक के नोडल बिंदु के रूप में कार्य करता है और अंतरराष्ट्रीय समन्वय और वैश्विक नियामक मानक-निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहता है।

विभाग का उद्देश्य विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अंतरराष्ट्रीय समष्टि आर्थिक नीति के मुद्दों पर बैंक के रुख को स्पष्ट करके वैश्विक नीति एजेंडा में भारतीय परिप्रेक्ष्य को आगे बढ़ाना और राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के अंतिम उद्देश्य के साथ वैश्विक नियामक मानकों के विकास और कार्यान्वयन में योगदान देना है।

विभाग वर्तमान में जी20और ब्रिक्स (ब्रिक्स) जैसे विभिन्न देशों के समूहों, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस), वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) और क्षेत्रीय संघों जैसे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के साथ संपर्क करने के लिए बैंक का नोडल बिंदु है। इसके बाद की धारा 1-7 विभिन्न अंतरराष्ट्रीय समूहों की प्रेरणाओं को सामने लाती है जिनमें विभाग बैंक का प्रतिनिधित्व करता है और बैंक के हितों को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे समूहों में विभाग की भूमिका स्पष्ट करता है। धारा 8 अन्य केंद्रीय बैंकों/सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत

³³ ब्रिक्स का मतलब ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है।

करने में विभाग के प्रयासों का विवरण देती है।

1. जी-20:

बीस देशों का समूह (जी20) 19 देशों और यूरोपीय संघ के समूह के रूप में शुरू हुआ और सभी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक नीति सहयोग को आकार देने और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। जी-20 के सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लगभग 85 प्रतिशत, वैश्विक व्यापार के 75 प्रतिशत से अधिक और विश्व की लगभग दो-तिहाई आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद, 2023 में भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को शामिल करने के लिए जी20 का विस्तार किया गया है।

जीएफसी के मद्देनजर जी-20 में भागीदारी को राष्ट्रों/ सराकारों के प्रमुखों के स्तर तक बढ़ा दिया गया और 2009 में, इसने "अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख मंच" की भूमिका ग्रहण की। जी-20 ने प्रारंभ में व्यापक व्यापक आर्थिक मुद्दों पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया, लेकिन इसके बाद इसने व्यापार, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोधी जैसे मुद्दों को शामिल करने के लिए अपने एजेंडे का विस्तार किया है।

जी20 की अध्यक्षता बारी-बारी से सौंपी जाती है, और प्रेसीडेंसी एक वर्ष के लिए जी20एजेंडा को आगे बढ़ाती है और शिखर सम्मेलन की मेजबानी करती है। जी20 में दो समानांतर ट्रैक होते हैं: फाइनेंस ट्रैक और शेरपा ट्रैक। एफएमसीबीजी वित्त ट्रैक का नेतृत्व करते हैं जबकि सदस्य देशों के शेरपा शेरपा ट्रैक का नेतृत्व करते हैं। शेरपा ट्रैक कृषि, व्यापार, स्वास्थ्य, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, प्रौद्योगिकी और ऐसे सभी मुद्दों जैसे मुद्दों पर नीतिगत सहयोग पर चर्चा करता है जो सदस्यों द्वारा महत्वपूर्ण महसूस किए जाते हैं।

जी20 वित्त ट्रैक एफएमसीबीजी, उनके प्रतिनिधियों और विभिन्न कार्य समूहों की अपनी बैठकों के माध्यम से वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करता है। वित्त ट्रैक द्वारा निपटाए गए कुछ प्रमुख मुद्दों में वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण और जोखिमों की निगरानी; अधिक स्थिर और लचीली वैश्विक वित्तीय संरचना के लिए सुधार; गुणवत्ता बुनियादी ढांचे का वित्तपोषण; स्थायी वित्त; वित्तीय समावेशन और वित्तीय क्षेत्र में सुधार शामिल है।

जी-20 कार्य में विभाग की भूमिका

जी20 प्रेसीडेंसी: भारत ने 1 दिसंबर, 2022 को "एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य" विषय के साथ इंडोनेशिया से जी20 की अध्यक्षता संभाली, जो "वसुधैव कुटुम्बकम्" के सदियों पुराने विश्वास पर आधारित है। शेरपा और फाइनेंस ट्रैक वर्किंग ग्रुप्स सहित सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 60 भारतीय शहरों में 200 से अधिक बैठकों के साथ, भारत की जी-20 प्रेसीडेंसी का आकार, पैमाना और दायरा अभूतपूर्व था।

भारत की अध्यक्षता के दौरान जी-20 शिखर सम्मेलन का मूल केंद्रबिंदु नई दिल्ली जी-20 नेताओं की घोषणा (एनडीएलडी) थी, जिसे शिखर सम्मेलन के पहले दिन सभी जी-20 देशों द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया था। एनडीएलडी एक कार्रवाई-उन्मुख, निर्णायक, समावेशी और महत्वाकांक्षी घोषणा थी, जो मौजूदा वैश्विक चुनौतियों की एक विस्तृत शृंखला पर आगे की राह तय करती है।

भारत के वित्त मंत्रालय ने बैंक (विभाग द्वारा प्रतिनिधित्व) के साथ समन्वय में, वित्त ट्रैक बैठकों और चर्चाओं की मेजबानी की।

वित्त ट्रैक के भीतर, विभाग ने भारतीय जी-20 की अध्यक्षता के दौरान विभिन्न कार्य समूहों/कार्य क्षेत्रों की चर्चाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय जी-20 की अध्यक्षता की समग्र सफलता में विभाग के योगदान को संक्षेप में बॉक्स-1 में संक्षेपित किया गया है।

बॉक्स-1: भारतीय जी-20 की अध्यक्षता के दौरान विभाग का योगदान

प्रेसीडेंसी से संबंधित कार्यों में विभाग की भूमिका जी20फाइनेंस ट्रैक (एफटी) के लिए प्राथमिकताओं और डिलिवरेबल्स को अंतिम रूप देने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा जनवरी 2022 में स्थापित परामर्शदाता समूह की बैठकों में योगदान के साथ शुरू हुई। इसके अलावा, भारतीय जी-20 की अध्यक्षता के दौरान, विभाग ने बैंक के कई डोमेन विभागों के साथ समन्वय में, वित्तीय क्षेत्र के मुद्दों (एफएसआई), अंतरराष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला (आईएफए), वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक साझेदारी (जीपीएफआई) कार्य क्षेत्रों के तहत बैंक से संबंधित जी-20 वित्त ट्रैक प्राथमिकताओं पर काम किया।

जीपीएफआई ने वित्तीय समावेशन कार्य योजना (एफआईएपी) 2020 को पूरा करने के अलावा, वित्तीय समावेशन और उत्पादकता लाभ बढ़ाने के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) का लाभ उठाने को प्राथमिकता दी, जो छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के लिए डिजिटल वित्तीय समावेशन और वित्त पर केंद्रित था। विभाग ने एफआईएपी 2023 की तैयारी के लिए इनपुट प्रदान किए, जिसमें वित्तीय सेवाओं तक गुणवत्तापूर्ण पहुँच प्रदान करने पर जोर दिया गया। आईएफए वर्किंग ग्रुप में, विभाग ने डोमेन विभागों के सहयोग से, (i) केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं (सीबीडीसी) के मैक्रो-फाइनेंशियल निहितार्थ का आकलन करने पर काम किया; और (ii) स्थायी पूंजी प्रवाह के माध्यम से वित्तीय आघात-सहनीयताओं को मजबूत करने पर कार्य किया।

वित्तीय क्षेत्र के विनियमन के भीतर, विभाग ने क्रिप्टो-संपत्तियों, स्थिर सिक्कों और विकेंद्रीकृत वित्त (डीईएफआई) के लिए जी20में एक समन्वित और व्यापक नीति दृष्टिकोण को आकार देने पर चर्चा में योगदान दिया; बिगटेक और फिनटेक से उत्पन्न होने वाले तीसरे पक्ष के जोखिमों और आउटसोर्सिंग का प्रबंधन करने के लिए वित्तीय संस्थानों की क्षमता को मजबूत करना; और वित्तीय क्षेत्र के साइबर संवेदनशीलताओं को मजबूत करने के लिए वैश्विक सहयोग के लिए एक रिपोर्टिंग ढांचा तैयार करना। इसके अलावा, विभाग निधियों के निर्बाध प्रवाह के लिए राष्ट्रीय तेजी से भुगतान प्रणालियों की अंतर-संचालनीयता पर राष्ट्रीय अनुभवों और अंतरराष्ट्रीय पहलों पर जानकारी साझा करने पर संबंधी चर्चाओं में निकटता से शामिल था।

इसके अलावा, जी-20 एफटी बैठकों के अलावा, विभाग ने डोमेन विभागों के साथ समन्वय में, विभिन्न विषयों पर कई सेमिनार/पैनल चर्चाएं आयोजित कीं, जिनमें अन्य के साथ-साथ, हरित वित्तपोषण, सीबीडीसी, सीमा पार भुगतान, वैश्विक वित्तीय सुरक्षा नेट को मजबूत करना, पूंजी प्रवाह, जी-20 प्रतिनिधियों के लिए तीसरे पक्ष के जोखिम प्रबंधन शामिल हैं। जन-केंद्रित दृष्टिकोण का पालन करते हुए, विभाग ने बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) के साथ निकट सहयोग में, भारत की जी-20 प्रेसीडेंसी वित्त ट्रैक प्राथमिकताओं के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए "जन भागीदारी" और घरेलू कार्यक्रमों के आयोजन का बीड़ा उठाया, जिससे देश भर में व्यापक सार्वजनिक भागीदारी पैदा हुई। इन गतिविधियों में अन्य बातों के साथ-साथ स्कूलों/विश्वविद्यालयों में विशेष जी-20 सत्र, प्रमुख उत्सवों में जी-20 पवेलियन, क्रिज प्रतियोगिताएं, सेल्फी प्रतियोगिताएं, कार्यशालाएं, मैराथन, जागरूकता रैलियां और स्वच्छता अभियान शामिल थे।

जी20 कार्य समूहों में योगदान: जी20 के भीतर, विभाग बैंक के संबंधित डोमेन विभागों के सहयोग से विचार-विमर्श के तहत मुद्दों का विश्लेषण करके और एफएमसीबीजी और एफसीबीडी बैठकों में उनकी भागीदारी के लिए शीर्ष प्रबंधन के लिए अपेक्षित जानकारी और संक्षिप्त विवरण तैयार करके योगदान देता है। यह जी-20 में वैश्विक मुद्दों पर बैंक के विचारों को उचित रूप से व्यक्त करने में शीर्ष प्रबंधन का समर्थन करता है ताकि बैंक के परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से नीतिगत एजेंडा को प्रभावी ढंग से चलाया जा सके। विभाग जी-20 डिलिवरेबल्स के मसौदा संस्करणों और एफएमसीबीजी बैठकों की विज्ञप्ति पर प्रासंगिक इनपुट और टिप्पणियां प्रदान करने में भी शामिल है, जो इन बैठकों के परिणामों को दर्शाता है।

इसके अलावा, वित्त मंत्रालय के साथ विभाग जी-20 की कई कार्य समूह बैठकों में भाग लेता है, जिसका उद्देश्य मुद्दों पर बैंक के विचारों के प्रति चर्चाओं का अनुकूल मार्गदर्शन करना है। जी-20 कार्य समूहों/कार्य क्षेत्रों द्वारा किए गए कार्यों का संक्षिप्त विवरण जिसमें विभाग लगातार योगदान दे रहा है, नीचे दिया गया है:

- (अ) प्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप (एफडबल्यूजी) – एफडबल्यूजी की सह-अध्यक्षता भारत द्वारा की जाती है और वर्तमान प्रासंगिकता के वैश्विक व्यापक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करता है, वैश्विक जोखिमों और अनिश्चितताओं की निगरानी करता है, और जी20 में मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास (SSBIG) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीति समन्वय के संभावित क्षेत्रों की पहचान करता है।
- (आ) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह (आईएफए डब्ल्यूजी) - आईएफए डब्ल्यूजी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना से संबंधित मुद्दों जैसे वैश्विक वित्तीय सुरक्षा नेट (जीएफएसएन); विकास वित्त से संबंधित मामले; ऋण कमजोरियों का प्रबंधन और ऋण पारदर्शिता बढ़ाने; पूंजी प्रवाह प्रबंधन और स्थानीय मुद्रा बांड बाजारों को बढ़ावा देने से संबंधी मुद्दों से संबंधित है।
- (इ) सतत वित्त कार्य समूह (एसएफडबल्यूजी) - एसएफडबल्यूजी इस बात पर विचार-विमर्श करता है कि स्थायी वित्त एजेंडा की प्रमुख प्राथमिकताओं पर जी20, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और अन्य हितधारकों का ध्यान केंद्रित करने और किए जाने वाले प्रमुख कार्यों पर आम सहमति बनाने में कैसे मदद की जाए।
- (ई) वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी (जीपीएफआई) – जीपीएफआई भारत की सह-अध्यक्षता में है और विश्व स्तर पर वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। इसके लिए, यह वित्तीय प्रणाली के बुनियादी ढांचे में सुधार करने, उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के लिए अनुकूल नीतियों को आगे बढ़ाने, प्रेषण प्रवाह को सुविधाजनक बनाने और प्रेषण हस्तांतरण की लागत को कम करने, वित्तीय साक्षरता और उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने, डिजिटल वित्तीय साक्षरता और डिजिटल विभाजन को पाटने के तरीकों पर चर्चा करता है।
- (उ) वित्तीय क्षेत्र के मुद्दे (एफएसआई) - एफएसआई पर सीधे जी20, एफसीबीडी और एफएमसीबीजी के स्तर पर चर्चा की जाती है और वित्त ट्रेक के तत्वावधान में एफएसआई पर कोई औपचारिक कार्य समूह नहीं है। वित्तीय क्षेत्र के मुद्दों के तहत चर्चा किए गए प्रमुख क्षेत्रों में वैश्विक वित्तीय प्रणाली की आघात सहनीयता को मजबूत करना, विवेकपूर्ण निरीक्षण, जोखिम प्रबंधन में सुधार, सीमा पार भुगतान को बढ़ाना, गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता (एनबीएफआई) में संरचनात्मक कमजोरियों को संबोधित करना, जलवायु से संबंधित वित्तीय जोखिम, क्रिप्टो-परिसंपत्तियों से जोखिमों का आकलन शामिल हैं।

2. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ)

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, आईएमएफ और विश्व बैंक (डब्ल्यूबी) की स्थापना 1944 में भारत सहित 44 देशों द्वारा की गई थी। तब से आईएमएफ के सदस्यों की संख्या बढ़कर 190 हो गई है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) वित्तीय स्थिरता और मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने वाली आर्थिक नीतियों का समर्थन करके अपने सभी सदस्य देशों के लिए सतत विकास और समृद्धि प्राप्त करने के लिए काम करता है, जो उत्पादकता, रोजगार सृजन और आर्थिक कल्याण को बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं। आईएमएफ का लक्ष्य इन उद्देश्यों को प्राप्त करना है: (i) सदस्य देशों में आर्थिक और वित्तीय विकास की निगरानी करना और आवश्यकतानुसार नीति विकल्पों पर उन्हें सलाह देना; (ii) भुगतान संतुलन दबाव की समस्याओं पर देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना; और (iii) सदस्य देशों को ठोस आर्थिक नीतियों को लागू करने में मदद करने के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना।

आईएमएफ की एक मुख्य जिम्मेदारी, इसके समझौते के अनुच्छेद IV के तहत, सदस्य देशों की आर्थिक और वित्तीय नीतियों की निगरानी करना और उन्हें नीतिगत सलाह प्रदान करना है। इस प्रक्रिया के भाग के रूप में, आईएमएफ संभावित जोखिमों की पहचान करता है और आर्थिक विकास को बनाए रखने और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए उचित नीति समायोजन की सिफारिश करता है। आईएमएफ की निगरानी में आम तौर पर सदस्य देशों की वार्षिक यात्राएं शामिल होती हैं, जिसके दौरान आईएमएफ कर्मचारी विनिमय दर, मौद्रिक, राजकोषीय और वित्तीय नीतियों के साथ-साथ संरचनात्मक सुधारों के बारे में सरकार और केंद्रीय बैंक के अधिकारियों के साथ चर्चा करते हैं।

इसके अलावा, अपने वित्तीय स्थिरता मूल्यांकन कार्यक्रम (एफएसएपी) के तहत, आईएमएफ किसी देश के वित्तीय क्षेत्र का व्यापक और गहन मूल्यांकन करता है, जिसमें इसकी आघात सहनीयता, इसके विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचे की गुणवत्ता और वित्तीय संकटों का प्रबंधन और समाधान करने की क्षमता का आकलन करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। एफएसएपी की स्थापना 1999 में हुई थी और यह बेसल कोर सिद्धांतों, सपीएपीएमआई-आओएससीओ³⁴ कोर सिद्धांतों और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स (आईएआईएस) बीमा कोर सिद्धांतों आदि जैसे वैश्विक मानकों के साथ देश की वित्तीय प्रणाली के अनुपालन का आकलन करता है। जीएफसी के बाद, 2010 में 25 व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण न्यायालयों के लिए हर 5 साल में एफएसएपी से गुजरना अनिवार्य कर दिया गया था। वर्तमान में 32 प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्राधिकारों (भारत सहित) के लिए हर पाँच वर्ष में एफएसएपी के तहत वित्तीय स्थिरता आकलन से गुजरना अनिवार्य है, जबकि अन्य 15 को हर 10 वर्षों में अनिवार्य एफएसएपी से गुजरना पड़ता है। विकासशील और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में, एफएसएपी के आयोजन विश्व बैंक के साथ संयुक्त रूप से किए जाते हैं, जो वित्तीय विकास का मूल्यांकन करता है।

आईएमएफ कार्य में विभाग की भूमिका:

विभाग मुख्य रूप से आरबीआई में आईएमएफ अनुच्छेद IV और एफएसएपी मिशनों का प्रबंधन करता है और अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्त समिति (आईएमएफसी) में अपनी बैठकों के लिए शीर्ष प्रबंधन को संक्षिप्त एवं अपेक्षित जानकारी प्रदान करता है।

अनुच्छेद IV परामर्श: विभाग बैंक के अन्य विभागों के समन्वय से आईएमएफ के अनुच्छेद IV परामर्शों की बैठकों का प्रबंधन

³⁴ भुगतान और बाजार अवसंरचना पर समिति-प्रतिभूति आयोगों का अंतरराष्ट्रीय संगठन

करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन बैठकों में बैंक के विचारों को प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व किया जा सके। विभाग अनुच्छेद IV रिपोर्ट के मसौदे, मसौदा समापन विवरण, बफ स्टेटमेंट, आदि पर बैंक की टिप्पणियों को संकलित करता है और भारत सरकार और आईएमएफ में कार्यपालक निदेशक-भारत (ओईडीआईएन) के कार्यालय को सूचित करता है।

वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम (एफएसएपी): भारत में दो बार, वर्ष 2011 और वर्ष 2017 में एफएसएपी आकलन किया गया है और भारत का तीसरा एफएसएपी मूल्यांकन वर्ष 2024 में किया जा रहा है। विभाग बैठकों का आयोजन करके और एफएसएपी टीम द्वारा किए गए प्रश्नावली/डेटा अनुरोधों पर प्रतिक्रिया प्रदान करके संबंधित हितधारकों के साथ आईएमएफ-विश्व बैंक टीम की चर्चाओं की सुविधा प्रदान करता है। विभाग बैंक के संबंधित विभागों से प्राप्त इनपुट के आधार पर एफएसएपी रिपोर्टों और तकनीकी नोट्स पर बैंक की टिप्पणियां तैयार करता है और भारत सरकार और आईएमएफ/डब्ल्यूबी टीम को सूचित करता है।

वर्ष 2017 में भारत के लिये आयोजित अंतिम एफएसएपी में देखा गया कि भारत ने एफएसएपी 2011 की लगभग सभी सिफारिशों को लागू कर दिया है। 2017 एफएसएपी ने अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ भारत के उच्च अनुपालन की पुष्टि की, जो भारत में एक सुदृढ़ और सक्रिय वित्तीय प्रणाली का प्रमाण देता है। वास्तव में, भारत को, सभी बेसल कोर सिद्धांतों (बीसीपी), केवल दो को छोड़कर, के साथ पूरी तरह या काफी हद तक अनुपालन करने वाला देश माना गया।

अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति (आईएमएफसी) की बैठकें: आईएमएफ का आईएमएफसी अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली के पर्यवेक्षण और प्रबंधन पर आईएमएफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को सलाह देता है और रिपोर्ट करता है, जिसमें सिस्टम को बाधित करने वाली घटनाओं के जवाब शामिल हैं। यह आमतौर पर वर्ष में दो बार आईएमएफ/डब्ल्यूबी वार्षिक और स्प्रिंग बैठकों में मिलता है, जिसमें बैंक का शीर्ष प्रबंधन भाग लेता है। विभाग इन बैठकों के दौरान बैंक के शीर्ष अधिकारियों को ब्रीफ और इनपुट तैयार करके सहायता करता है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन बैठकों के दौरान बैंक के रुख पर पर्याप्त बल दिया जाए।

कार्यकारी बोर्ड के कागजात: आईएमएफ का कार्यकारी बोर्ड आईएमएफ के दिन-प्रतिदिन के कारोबार के संचालन के लिए जिम्मेदार है। यह पूरे वर्ष अधिक लगातार अंतराल पर मिलता है और आईएमएफ कोटा और शासन, निगरानी, उधार, पूंजी प्रवाह प्रबंधन, मौद्रिक नीति के मुद्दों, वित्तीय क्षेत्र विनियमन आदि जैसे नीतिगत मुद्दों पर आईएमएफ कर्मचारियों द्वारा तैयार किए गए कागजात के आधार पर बड़े पैमाने पर अपना काम करता है / विभाग इन कागजातों पर बैंक का रुख प्रदान करता है जिन पर इन बैठकों में चर्चा की जाती है।

3. अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस)

1930 में स्थापित, बीआईएस सबसे पुरानी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था है, जिसे 1930 में हेग सम्मेलन में यंग प्लान के संदर्भ में स्थापित की गई थी। हेग सम्मेलन का उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्सालीस की संधि द्वारा जर्मनी पर लगाए गए रिपरेशन भुगतान को एकबारगी निपटान के रूप में किया जाना था और बीआईएस ने रिपरेशन भुगतानों के निपटान की सुविधा प्रदान की।

1930 के दशक की महामंदी के परिणामस्वरूप, पुनर्मूल्यांकन का मुद्दा शीघ्र ही समाप्त हो गया। रिपरेशन के मुद्दे के साथ, बीआईएस ने केंद्रीय बैंकों (आरक्षित प्रबंधन, विदेशी मुद्रा लेनदेन, अंतरराष्ट्रीय डाक भुगतान, सोना जमा और स्वैप सुविधाओं

सहित) के बीच तकनीकी सहयोग और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों और अधिकारियों की नियमित बैठकों के लिए एक मंच प्रदान करने पर अपनी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया।

बीआईएस आज चर्चा के लिए एक मंच है और मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता की खोज में केंद्रीय बैंकों और अन्य वित्तीय अधिकारियों के बीच सहयोग के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है। बीआईएस द्विमासिक बैठकों और अन्य नियमित परामर्श के माध्यम से वरिष्ठ मौद्रिक और वित्तीय अधिकारियों की नियमित उच्च स्तरीय बैठकों के माध्यम से कार्य करता है। यह बीआईएस समितियों और संघों के माध्यम से वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए प्रयासरत अंतरराष्ट्रीय समूहों के लिए समर्थन और सहयोग भी प्रदान करता है।

बीआईएस की तीन प्रमुख द्विमासिक बैठकें वैश्विक अर्थव्यवस्था बैठक (जीईएम), आर्थिक सलाहकार समिति (ईसीसी) और सभी गवर्नरों की बैठक हैं, जो विश्व अर्थव्यवस्था और वैश्विक वित्तीय प्रणाली में विकास, जोखिम और अवसरों की निगरानी और आकलन करती हैं, और बेसल स्थित केंद्रीय बैंक समितियों को मार्गदर्शन प्रदान करती हैं³⁵।

बीआईएस कार्य में विभाग की भूमिका:

बैंक 09 सितंबर, 1996 से बीआईएस का सदस्य बन गया और 2015 में, बैंक के पूर्व गवर्नर डॉ. रघुराम राजन, बीआईएस निदेशक मंडल के उपाध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय बने। विभाग अपनी स्थापना के बाद से, अपनी निम्नलिखित गतिविधियों के माध्यम से बीआईएस में बैंक का प्रतिनिधित्व करने में शामिल रहा है।

बीआईएस की द्वि-मासिक बैठकें: बीआईएस द्वि-मासिक बैठकों के तत्वावधान में, बैंक का शीर्ष प्रबंधन जीईएम, ईसीसी और सभी गवर्नरों की बैठकों में भाग लेता है। विभाग इन मंचों पर विचार-विमर्श किए जा रहे मुद्दों पर शीर्ष प्रबंधन के लिए संक्षिप्त विवरण और इनपुट तैयार करता है। इसके अतिरिक्त, द्विमासिक बैठकों के साथ-साथ, शीर्ष प्रबंधन भारतीय मानक ब्यूरो के तत्वावधान में विभिन्न अंतरालों पर आयोजित विभिन्न बैठकों में भी भाग लेता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ केंद्रीय बैंक के गवर्नरों और पर्यवेक्षण प्रमुखों (जीएचओएस) की बैठक, उभरते बाजार (ईएम) गवर्नरों की बैठक और एशियाई परामर्शदात्री परिषद (एसीसी) की बैठक शामिल हैं। विभाग इन बैठकों के लिए ब्रीफ और इनपुट के रूप में शीर्ष प्रबंधन को सहायता भी प्रदान करता है।

कंट्री पेपर्स: विभाग कंट्री पेपर्स कागजात तैयार करता है, जिन्हें नियमित अंतराल पर विषयगत मुद्दों पर बीआईएस द्वारा बुलाया जाता है। ये दस्तावेज चयनित मुद्दों पर देश-विशिष्ट अनुभवों को उजागर और विस्तार करते हैं, जिन्हें बाद में बीआईएस द्वारा समेकित और प्रकाशित किया जाता है।

सीजीएफएस सचिवालय: बीआईएस के तहत, वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर समिति वित्तीय क्षेत्र के विकास की निगरानी करती है और वित्तीय स्थिरता और केंद्रीय बैंक नीति के लिये उनके निहितार्थों का विश्लेषण करती है। विभाग सीजीएफएस गतिविधियों के लिए बैंक के भीतर सचिवालय के रूप में कार्य करता है और बैंक के डोमेन विभागों के सहयोग से, प्रकाशन से पहले सीजीएफएस द्वारा परिचालित विभिन्न अंतरिम और अंतिम रिपोर्टों पर टिप्पणियां प्रदान करता है।

बीआईएस इनोवेशन हब : बीआईएस इनोवेशन हब केंद्रीय बैंकों का समर्थन करने और वित्तीय प्रणाली के कामकाज में सुधार

³⁵ ये समितियां वैश्विक वित्तीय प्रणाली समिति (सीजीएफएस), भुगतान और बाजार अवसंरचना पर बीआईएस समिति (सीपीएमआई) और बाजार समिति (एमसी), सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ग्रुप (सीबीजीजी) और सेंट्रल बैंक सांख्यिकी पर इरविंग फिशर समिति हैं।

के लिये प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सार्वजनिक वस्तुओं का विकास करता है। बैंक के प्रतिनिधि बीआईएसआईएच की विभिन्न परियोजनाओं में भाग लेते रहे हैं और विभाग इन बीआईएसआईएच से संबंधित गतिविधियों के लिए बैंक के अंतर्गत समन्वय करने के लिए नोडल बिंदु है।

4. वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी)

वित्तीय स्थिरता बोर्ड एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है जिसे जी20 द्वारा राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरणों और अंतरराष्ट्रीय मानक-निर्धारण निकायों के काम का समन्वय करके अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी दी गई है।³⁶ लिए अनिवार्य किया गया है, क्योंकि वे मजबूत नियामक, पर्यवेक्षी और अन्य वित्तीय क्षेत्र की नीतियों को विकसित करने और क्षेत्रों और न्यायालयों में इन नीतियों के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम करते हैं। जीएफसी के बाद, जी20 के पिट्सबर्ग शिखर सम्मेलन में, वित्तीय स्थिरता बोर्ड को वित्तीय स्थिरता फोरम के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था³⁶, जिसमें वित्तीय स्थिरता फोरम की तुलना में विस्तारित सदस्यता थी, जिसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की बढ़ती अंतर्संबंधता को देखते हुए दिया गया था।

एफएसबी वित्तीय क्षेत्र में प्रणालीगत जोखिम की पहचान की दिशा में काम करता है; वित्तीय क्षेत्र की नीतिगत सिफारिशों को तैयार करता है जो इन जोखिमों को संबोधित कर सकते हैं; और उन सिफारिशों को कार्यान्वित करता है। एफएसबी की संरचना में एक पूर्ण समिति होती है, जो एकमात्र निर्णय लेने वाली संस्था है; पूर्ण बैठकों के बीच परिचालन कार्य को आगे बढ़ाने के लिए एक संचालन समिति; और स्थायी समितियों/क्षेत्रीय समितियों के गठन, निम्नानुसार हैं:

- अ. कमजोरियों के आकलन पर स्थायी समिति (एसीएवी), जो वित्तीय प्रणाली में जोखिमों की पहचान और आकलन करने के लिए एफएसबी का मुख्य तंत्र है।
- आ. पर्यवेक्षी और नियामक सहयोग (एसआरसी) पर स्थायी समिति, जिस पर एससीएवी द्वारा पहचानी गई सामग्री संवेदनशीलता के लिए आगे पर्यवेक्षी विश्लेषण करने या नियामक या पर्यवेक्षी नीति प्रतिक्रिया तैयार करने का कार्य सौंपा गया है; और
- इ. मानक कार्यान्वयन पर स्थायी समिति (एससीएसआई), जो सहमत एफएसबी नीतिगत पहलों और अंतरराष्ट्रीय मानकों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जिम्मेदार है।
- ई. बजट और संसाधन पर स्थायी समिति (एससीबीआर), जो एफएसबी के संसाधनों और बजट की निगरानी करती है।
- उ. क्षेत्रीय सलाहकार समूह (आरसीजी), जो एफएसबी और गैर-एफएसबी दोनों सदस्यों के देश समूह हैं और अपनी सदस्यता से परे आउटरीच गतिविधियों का विस्तार करने और उन्हें औपचारिक रूप देने के लिए एफएसबी द्वारा अपनायी गई एक व्यवस्था है।

एफएसबी की स्थायी समितियों को मुद्दा-विशिष्ट कार्य समूहों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जो संबंधित स्थायी समिति द्वारा निर्धारित अधिदेश से संबंधित मुद्दों का विश्लेषण और विचार-विमर्श करते हैं। ऐसे विश्लेषणों और विचार-विमर्श के परिणामों को प्रकाशन से पूर्व पूर्ण/संचालन समिति/स्थायी समितियों के अनुमोदन के लिए उनके समक्ष रखा जाता है। कुछ कार्य समूह

³⁶ एफएसएफ की स्थापना 1999 में जी7 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।

सर्वेक्षण करते हैं या सदस्य क्षेत्राधिकारों को प्रश्नावली भेजते हैं और सदस्य प्रतिक्रियाएं उनकी मसौदा रिपोर्टों में फीड होती हैं। एफएसबी के प्रमुख कार्यों ने हाल ही में इस तरह के विविध कार्य-क्षेत्रों जैसे कि वित्तीय नवाचार और फिनटेक, वित्त में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संकल्प सुधार, जलवायु परिवर्तन, सीमा पार भुगतान, क्रिप्टो-संपत्ति और वैश्विक स्थिर सिक्कों, साइबर खतरों और गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता (एनबीएफआई) से उत्पन्न जोखिमों और कमजोरियों को कम करने के लिए विश्लेषण और नीतिगत सिफारिशों पर ध्यान केंद्रित किया है।

एफएसबी कार्य में विभाग की भूमिका:

एफएसबी बैठकें: विभाग, प्लेनरी स्टीयरिंग समिति, एससीएवी, एसआरसी और आरसीजी-एशिया बैठकों में विचार-विमर्श किए जा रहे मुद्दों पर शीर्ष प्रबंधन के लिए संक्षिप्त विवरण और अपेक्षित जानकारी तैयार करने के लिए बैंक का नोडल बिंदु है। बैंक के डोमेन विभागों के सहयोग से संक्षिप्त विवरण और अपेक्षित जानकारी तैयार की जाती हैं और विभिन्न कार्य समूहों द्वारा तैयार की गई मसौदा रिपोर्टों ध्यान केंद्रित किया जाता है; और स्थायी समितियों का कार्य कार्यक्रम; और वित्तीय स्थिरता दृष्टिकोण और उभरती कमजोरियों पर एफएसबी सचिवालय द्वारा प्रस्तुत आवधिक विश्लेषण पर ध्यान दिया जाता है।

सर्वेक्षण और प्रश्नावली: विभाग, बैंक के संबंधित डोमेन विभागों के सहयोग से, विभिन्न सर्वेक्षणों और प्रश्नावली के संबंध में बैंक की स्थिति के साथ एफएसबी कार्य समूहों को जवाब देने में भी शामिल है, जिसे अंततः एफएसबी द्वारा प्रकाशित अंतिम रिपोर्टों में फीड किया जाता है। एफएसबी की कुछ प्रमुख वार्षिक रिपोर्टें, जैसे, वैश्विक निगरानी रिपोर्ट; ओटीसी डेरिवेटिव बाजार सुधार; एनबीएफआई सुधारों के लचीलेपन को बढ़ाने पर प्रगति रिपोर्ट; और जलवायु संबंधी प्रकटीकरण, आदि पर प्रगति रिपोर्ट, सदस्य न्यायालयों के डेटा/प्रतिक्रियाओं का उपयोग करके प्रकाशित की जाती है।

एफएसबी कंट्री पीयर रिव्यू: एफएसबी एक विशिष्ट एफएसबी सदस्य क्षेत्राधिकार में वांछित परिणाम प्राप्त करने में नियामक, पर्यवेक्षी या अन्य वित्तीय क्षेत्र की नीतियों के कार्यान्वयन और प्रभावशीलता का आकलन करने के लिये देश की पंचवर्षीय समीक्षा आयोजित करता है। वे आईएमएफ-डब्ल्यूबी एफएसएपी सिफारिशों के साथ-साथ एफएसएपी में शामिल नहीं किए गए नीतिगत मुद्दों को संबोधित करने के लिए राष्ट्रीय अधिकारियों द्वारा उठाए गए या नियोजित कदमों की जांच करते हैं, लेकिन जो अधिकार क्षेत्र के लिए और व्यापक एफएसबी सदस्यता के लिए समय पर और सामयिक हैं।

एफएसबी ने 2016 में भारत की 2 विषयों पर समीक्षा की थी- (i) मैक्रोप्रूडेंशियल पॉलिसी फ्रेमवर्क, और (ii) नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (एनबीएफसी) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) का रेगुलेशन और पर्यवेक्षण। विभाग सहकर्म समीक्षा के दौरान एफएसबी के साथ समन्वय के लिए केंद्र बिंदु था और बैंक के डोमेन विभागों के सहयोग से, उसी के लिए बैठकों की मेजबानी की। पीयर रिव्यू रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया कि 'हालांकि हाल के वर्षों में मैक्रोप्रूडेंशियल पॉलिसी फ्रेमवर्क विकसित करने और एनबीएफसी और एचएफसी के विनियमन और पर्यवेक्षण को मजबूत करने में प्रगति हुई है, दोनों क्षेत्रों में अतिरिक्त काम किया जाना बाकी है। भारत की अगली एफएसबी सहकर्म समीक्षा 2026 में होने वाली है।

5. दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)

सार्क के तत्वावधान में, सार्क फाइनेंस (एसएफ) की स्थापना 1998 में सार्क देशों के प्रमुखों के शिखर सम्मेलन में केंद्रीय बैंक के गवर्नरों और सार्क क्षेत्र के वित्त सचिवों के नेटवर्क के रूप में की गई थी। एसएफ का गठन एशियाई वित्तीय संकट की

पृष्ठभूमि के खिलाफ किया गया था, जिसका उद्देश्य क्षेत्र की व्यापक आर्थिक नीतियों पर बातचीत शुरू करना और आपसी अनुभवों और विचारों को साझा करना था। बैंक एसएफ में अपनी भागीदारी के माध्यम से अन्य केंद्रीय बैंकों के साथ क्षेत्रीय सहयोग की दिशा में अपने प्रयासों को आगे बढ़ाता है।

लघु राष्ट्रों के अंतर्गत सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में *अन्य बातों के साथ-साथ* निम्नलिखित शामिल हैं (i) सार्क देशों के लिए मुद्रा विनिमय व्यवस्था की रूपरेखा; (ii) क्षमता निर्माण प्रयास; (iii) एसएफ डाटाबेस; और (iv) वित्तीय समावेशन पर काम करना।

सार्क वित्त कार्य में विभाग की भूमिका:

सार्क देशों के लिए मुद्रा विनिमय व्यवस्था पर ढांचा: सार्क देशों ने नवंबर 2012 में सार्क देशों के लिए मुद्रा विनिमय व्यवस्था पर फ्रेमवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया, ताकि अल्पकालिक विदेशी मुद्रा तरलता की जरूरतों या सदस्य देशों की भुगतान आवश्यकताओं के संतुलन को संबोधित करने के लिए बैंक-स्टॉप लाइन प्रदान की जा सके। फ्रेमवर्क के तहत, बैंक प्रत्येक सार्क सदस्य देश को दो बिलियन अमेरिकी डालर के समग्र कोष के भीतर अलग-अलग आकार के स्वेप की पेशकश करेगा। फ्रेमवर्क सदस्य देशों को अमेरिकी डॉलर, यूरो या भारतीय रुपये में स्वेप आकर्षित करने की अनुमति देता है।

इस ढांचे के तहत, विभाग ने बैंक के डोमेन विभागों के सहयोग से, विभिन्न सदस्य देशों को 6.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समग्र स्वेप समर्थन के प्रावधान का संचालन किया है। इनमें से श्रीलंका का हिस्सा 62 प्रतिशत (3.8 अरब अमेरिकी डॉलर), भूटान का हिस्सा 26 प्रतिशत (1.6 अरब अमेरिकी डॉलर) और मालदीव का 12 प्रतिशत (0.7 अरब अमेरिकी डॉलर) है। कोविड-19 महामारी (2020-22) के दौरान, विभाग भूटान, मालदीव और श्रीलंका को कुल 2.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर की स्वेप सहायता के प्रावधान में शामिल था, जिससे इन सदस्य देशों को अपने बाहरी क्षेत्र के दबावों का प्रबंधन करने में महत्वपूर्ण मदद मिली।

एसएफ गवर्नर ग्रुप मीटिंग (एसएफजीजीएम): एसएफ, एसएफजीजीएम निर्णयों द्वारा नियंत्रित है। एसएफजीजीएम उनके विभाग शीर्ष प्रबंधन को ब्रीफ और इनपुट के रूप में सहायता प्रदान करता है, ताकि विचार-विमर्श के तहत मुद्दों पर बैंक की स्थिति उचित रूप से स्पष्ट हो।

एसएफ डेटाबेस: वर्ष 2014 में आयोजित 29वें एसएफजीजीएम के दौरान, बैंक ने सार्क क्षेत्र पर एक सांख्यिकीय डेटाबेस विकसित करने और होस्ट करने पर सहमति व्यक्त की। एसएफ डेटाबेस को मुंबई में 26 मई, 2016 को 32वें एसएफजीजीएम के साथ आयोजित एसएफ गवर्नर्स संगोष्ठी में लॉन्च किया गया था। विभाग एसएफ डेटाबेस की अवधारणा में शामिल था, जो सदस्य देशों के लिए एक विस्तृत डेटा भंडार के रूप में कार्य करता है। वर्तमान में, डेटाबेस में सामाजिक-आर्थिक चर और इंटर-सार्क क्षेत्र व्यापार चर सहित 136 चर शामिल हैं, जो मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक आवृत्तियों में एकत्र किए जाते हैं। डेटाबेस पोर्टल को हाल ही में बैंक की अगली पीढ़ी के डेटा वेयरहाउस 'केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली' में पुनर्गठित किया गया है।

क्षमता निर्माण: बैंक सभी सार्क केंद्रीय बैंकों को प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और एक्सपोजर विजिट प्रदान करता है और विभाग ऐसी क्षमता निर्माण पहलों के लिए बैंक के भीतर नोडल बिंदु है। विभाग द्वारा व्यवस्थित क्षमता निर्माण उपायों में बैंक के प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में अध्ययन दौरे, कार्यशालाएं, इंटरशिप, सेकेंडमेंट और प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं।

तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण के अलावा, विभाग उच्च अध्ययन के लिए एसएफ छात्रवृत्ति योजना भी शुरू करता है, जिसे 2013 में बैंक द्वारा शुरू किया गया था, ताकि केंद्रीय बैंकिंग की प्रासंगिकता के मुद्दों में अनुसंधान और क्षमता निर्माण को

प्रोत्साहित किया जा सके। इस योजना का उद्देश्य सार्क क्षेत्र में केंद्रीय बैंकों और वित्त मंत्रालयों के अधिकारियों के कौशल को बढ़ाना है। इस योजना के अंतर्गत, *अन्य बातों के साथ-साथ* अर्थशास्त्र, बैंकिंग, वित्त, सांख्यिकी, गणित और प्रबंधन को शामिल करने वाले क्षेत्रों में प्रति वर्ष चार छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।

एसएफ सिंक पोर्टल: राज्यपाल ने 04 नवंबर, 2020 को आयोजित 40वें एसएफजीजीएम में सार्क सेंट्रल बैंकों के लिए एक बंद उपयोगकर्ता समूह संचार पोर्टल, सार्क फाइनेन्स सिंक का उद्घाटन किया। सार्क फाइनेन्स सिंक पोर्टल को सार्क केंद्रीय बैंकों द्वारा सार्कफाइनेन्स कार्यधाराओं के तहत कनेक्ट, संचार और सहयोग करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण के रूप में देखा गया है। विभाग ने पोर्टल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है क्योंकि पोर्टल की संरचना और प्रारूप की अवधारणा पोर्टल के संचालन के लिए रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (रेबिट) और भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाओं (आईएफटीएस) के साथ मिलकर काम करके की गई थी। पोर्टल में सेवानिवृत्त संसाधन व्यक्तियों की निर्देशिका और वित्तीय समावेशन मंच भी है, जो वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए सार्क केंद्रीय बैंकों द्वारा की गई पहलों का भंडार है।

एसएफ सहयोगात्मक अध्ययन: सार्क केंद्रीय बैंक केंद्रीय बैंकों से संबंधित विषयों पर सार्क वित्त जनादेश के एक भाग के रूप में सहयोगी अनुसंधान अध्ययन करते हैं। अध्ययन आमतौर पर एक टीम द्वारा आयोजित किया जाता है जिसमें सभी सार्क केंद्रीय बैंकों के प्रतिनिधि होते हैं, जिसमें एक केंद्रीय बैंक अध्ययन का नेतृत्व करता है। विभाग में सार्क वित्त प्रकोष्ठ सहयोगात्मक अध्ययनों का समन्वय करता है और प्रगति की सूचना एसएफजीजीएम की बैठकों को दी जाती है।

वित्तीय समावेशन अधिगम शृंखला (एफआईएलएस): गवर्नर ने 14 जून, 2024 को कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित 45वें एसएफजीजीएम में वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में सहयोग को गहरा करने के लिये वित्तीय समावेशन शिक्षण शृंखला (एफआईएलएस) नामक एक त्रैमासिक आभासी ज्ञान-साझाकरण शृंखला शुरू करने का प्रस्ताव रखा। इस शृंखला की परिकल्पना एक ज्ञान मंच के रूप में की गई थी जहां सार्क केंद्रीय बैंक वित्तीय समावेशन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित अनुभव, सर्वोत्तम प्रथाओं और चुनौतियों को साझा कर सकते थे। एफआईएलएस के विषयों का उद्देश्य उपभोक्ता संरक्षण, डिजिटलीकरण, लोकपाल योजनाओं और साइबर सुरक्षा मुद्दों जैसे विषयों के व्यापक स्पेक्ट्रम को कवर करना था। ये सत्र केंद्रीय बैंकों के सभी इच्छुक अधिकारियों के लिए खुले होंगे और केवल सार्क वित्त प्रकोष्ठों तक ही सीमित नहीं होंगे। FILS का उद्घाटन सत्र 21 अगस्त, 2024 को आयोजित किया गया था, जिसमें बैंक और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अनुभव साझा किए थे।

एसएफ अध्यक्ष: बैंक ने अक्टूबर 2019 से एक वर्ष की अवधि के लिए सार्कफाइनेन्स (एसएफ) की अध्यक्षता संभाली, जिसे कोविड-19 महामारी को देखते हुए मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया था। बैंक के एसएफ चेयर के तहत, विभाग विभिन्न पहलों के माध्यम से सार्क केंद्रीय बैंकों के बीच सहयोग बढ़ाने में लगा हुआ है, जिसे बॉक्स -2 में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

बॉक्स -2: भारतीय के दौरान विभाग का योगदान

सार्कफाइनेन्स (एसएफ) अध्यक्ष

बैंक के एसएफ चेयर के तहत प्रमुख पहलों में से एक एसएफ सिंक के विकास पर काम शामिल था, जो इंटर-सार्क केंद्रीय बैंकों के संचार के लिए एक बंद और सुरक्षित चैनल की सुविधा के लिए एक पोर्टल है।

इसके अलावा, सार्क देशों में केंद्रीय बैंकों और वित्त मंत्रालयों में अधिकारियों के लिए उच्च अध्ययन के लिए एसएफ छात्रवृत्ति योजना, जिसे जून 2013 में स्थापित किया गया था, को मई 2020 में बैंक की एसएफ चेयर के तहत संशोधित किया गया था। संशोधित योजना के अंतर्गत, *अन्य बातों के साथ-साथ*, पात्र पाठ्यक्रमों के दायरे का विस्तार किया गया है और छात्रवृत्ति राशि तथा एक वर्ष में प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियों की संख्या में वृद्धि की गई है। विभाग ने सहयोग के एसएफ रोडमैप के तहत सदस्य केंद्रीय बैंकों के लिए कई तकनीकी सहायता और एक्सपोजर कार्यक्रमों की व्यवस्था की। इसके अलावा, बैंक के एसएफ चेयर के तहत, विभाग एसएफ डेटाबेस को मानकीकृत करने और बढ़ाने की दिशा में काम पर महत्वपूर्ण प्रगति हासिल करने में शामिल था।

बैंक के एसएफ चेयर के तहत, 'फिनटेक और वित्तीय समावेशन' पर एक एसएफ सहयोगी अध्ययन आयोजित किया गया था, जिसने सार्क देशों के बीच फिनटेक और वित्तीय समावेशन से संबंधित कार्यों का जायजा लेने में सक्षम बनाया।

इसके अलावा, विभाग वार्षिक एसएफ ई-न्यूजलेटर के पहले अंक के प्रकाशन में शामिल था, जिसे मार्च 2021 में जारी किया गया था।

बैंक के एसएफ चेयर का फोकस क्षेत्र केंद्रीय बैंकिंग कार्यों में प्रौद्योगिकी का उपयोग था। बैंक के एसएफ चेयर का समापन 2 मार्च, 2021 को एसएफ गवर्नर्स संगोष्ठी में हुआ, जिसमें 'सेंट्रल बैंकों में सुपरटेक उपयोग' पर एक मुख्य सत्र और 'सेंट्रल बैंकों में साइबर-सुरक्षा' पर एक पैनल चर्चा हुई।

6. ब्रिक्स

सितम्बर, 2006 में ब्रिक (ब्राजील, रूस, भारत, चीन) समूह को पहली ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान औपचारिक रूप दिया गया था, जो न्यूयार्क शहर में संयुक्त राष्ट्र सभा की आम बहस के अवसर पर मिली थी। सितंबर 2010 में न्यूयार्क में ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक में दक्षिण अफ्रीका को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किए जाने के बाद ब्रिक समूह का नाम बदलकर ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) कर दिया गया। इसके अलावा ईरान, मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स में शामिल हुए।

ब्रिक्स देश हाल के दशकों में वैश्विक आर्थिक विकास के मुख्य इंजन रहे हैं। यह समूह दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है, जिसमें विश्व की आबादी का 41% शामिल है, विश्व सकल घरेलू उत्पाद का 24% और विश्व व्यापार में 16% से अधिक हिस्सा है³⁷।

ब्राजील, रूस, भारत और चीन के वित्त मंत्रियों ने जीएफसी के कारणों पर विचार करने और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और वैश्विक शासन से संबंधित मुद्दों और सुधारों को संबोधित करने के साथ-साथ वित्तीय विकास के लिए ब्रिक्स देशों के अनुभवों और नीतिगत प्रतिक्रियाओं को संबोधित करने के लिए 2009 में अपनी पहली बैठक आयोजित की। अर्थव्यवस्था और वित्त में ब्रिक्स सहयोग ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग के सबसे प्रमुख स्तंभों में से एक है और वित्तीय सहयोग के तहत पहल वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स द्वारा वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स (एफएमसीबीजी) की बैठकों में की जाती है।

³⁷ विश्व बैंक (2019) के आंकड़े।

ब्रिक्स कार्य में विभाग की भूमिका:

वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स (एफएमसीबीजी) और वित्त और सेंट्रल बैंक डेप्युटीज (एफसीबीडी) की बैठकें: विभाग इन प्रमुख बैठकों में उनकी भागीदारी में शीर्ष प्रबंधन का समर्थन करता है, ब्रीफ और इनपुट के रूप में जो विचार-विमर्श के तहत मुद्दों पर बैंक के रुख को उपयुक्त रूप से स्पष्ट करता है।

ब्रिक्स आकस्मिक रिज़र्व व्यवस्था (सीआरए): ब्रिक्स सीआरए इसके आर्थिक और वित्तीय सहयोग ट्रैक के तहत एक प्रमुख पहल है। फोर्टालेजा में 2014 में हुए छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स देशों ने सीआरए पर हस्ताक्षर किए थे, जो सदस्य देशों की अल्पकालिक तरलता जरूरतों को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर-क्षेत्रीय वित्तपोषण व्यवस्था है। जुलाई 2015 में सभी ब्रिक्स देशों द्वारा सीआरए की स्थापना के लिए संधि के अनुसमर्थन और बाद में अंतर-केंद्रीय बैंक समझौते (आईसीबीए) पर हस्ताक्षर करने पर सीआरए लागू हुआ।

विभाग ब्रिक्स सीआरए के डिजाइन और परिचालन में शामिल रहा है। सीआरए एक ऐसा तंत्र है जिसमें ब्रिक्स देशों ने पारस्परिक स्वैप समर्थन प्रदान करके भुगतान संकट के अल्पकालिक संतुलन को दूर करने में मदद करने के लिए एक स्व-प्रबंधित आकस्मिक आरक्षित पूल स्थापित किया है। ब्रिक्स देशों ने सीआरए के तहत 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल संसाधन के लिए प्रतिबद्धता जताई है। वर्तमान में, सीआरए अमेरिकी डॉलर आधारित स्वैप तंत्र है।

ब्रिक्स सीआरए की शासन संरचना में एक शासी परिषद (जीसी) और एक स्थायी समिति (एससी) शामिल है, जहां बैंक का शीर्ष प्रबंधन भाग लेता है। विभाग ब्रिक्स सीआरए की जीसी और एससी बैठकों में बैंक के रुख को उचित रूप से स्पष्ट करने के उद्देश्य से शीर्ष प्रबंधन के लिए ब्रीफ और इनपुट तैयार करता है।

भले ही अब तक सीआरए के तहत स्वैप समर्थन का लाभ कभी नहीं उठाया गया है, सीआरए के तहत विभिन्न जुड़ाव ने ब्रिक्स केंद्रीय बैंकों के बीच सहयोग को तेज करने में मदद की है। दिसंबर 2017 से, ब्रिक्स केंद्रीय बैंकों ने सीआरए की परिचालन तत्परता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए सात परीक्षण किए हैं, जिसमें विभाग निकटता से शामिल रहा है।

ब्रिक्स कार्य समूह: ब्रिक्स वित्त ट्रैक के तहत, विभिन्न कार्य समूहों का गठन किया गया है, जैसे, ब्रिक्स भुगतान कार्य बल (बीपीटीएफ), ब्रिक्स सूचना सुरक्षा परिषद (बीआरआईएससी), संक्रमण वित्त और फिनटेक। विभाग डिलिवरेबल्स में योगदान देता है और इन कार्य समूहों में विचार-विमर्श किए जा रहे मुद्दों पर बैंक के रुख को तैयार करने के लिए बैंक के संबंधित विभागों के साथ समन्वय करता है।

ब्रिक्स इंडिया चेयर: विभाग के गठन के बाद, भारत ने 2016 और 2021 में ब्रिक्स चेयर का पदभार संभाला और बैंक ने अपनी अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स केंद्रीय बैंक कार्यधाराओं का नेतृत्व किया। ब्रिक्स चेयर के दौरान विभाग के योगदान का एक संक्षिप्त सारांश

2021 में बॉक्स-3 में प्रदान किया गया है।

बॉक्स-3: 2021 में भारत ब्रिक्स चेयर के दौरान विभाग का योगदान

भारत ब्रिक्स चेयर के तहत, विभाग ने वित्त मंत्रालय के समन्वय से, वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों (एफएमसीबीजी), वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों (एफसीबीडी), सीआरए गवर्निंग काउंसिल (जीसी), सीआरए स्थायी समिति (एससी) की कई ब्रिक्स उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित कीं।

इसके अलावा, विभाग ने ब्रिक्स आर्थिक बुलेटिन 2021 में 'नेविगेटिंग द ऑनगोइंग पैडेमिक: द ब्रिक्स एक्सपीरियंस ऑफ रेजिलिएंस एंड रिकवरी' विषय के साथ योगदान दिया, जिसे ब्रिक्स सीआरए रिसर्च ग्रुप के तत्वावधान में प्रकाशित किया गया था।

'वित्त में सूचना सुरक्षा विनियम' पर ब्रिक्स ई-बुकलेट, 'सूचना सुरक्षा जोखिमों पर ब्रिक्स सर्वोत्तम प्रथाओं का संग्रह: पर्यवेक्षण और नियंत्रण', और 'ब्रिक्स डिजिटल वित्तीय समावेशन रिपोर्ट' 2021 के दौरान महत्वपूर्ण प्रकाशन थे, जिनमें विभाग ने योगदान दिया।

विभाग ने वित्त मंत्रालय के सहयोग से दिसंबर 2021 में 'सूचना सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण' पर ब्रिक्स संगोष्ठी का आयोजन किया। ब्रिक्स ने साइबर खतरों पर सूचना के आदान-प्रदान और वित्तीय क्षेत्र में साइबर हमलों का मुकाबला करने में अनुभव साझा करके अपने सहयोग को गहरा किया है।

विभाग 'कोविड-19: ब्रिक्स के भुगतान संतुलन के लिए हेडविंड्स और टेलविंड्स' पर ब्रिक्स सहयोगात्मक अध्ययन की बैंक की पहल और ब्रिक्स सीआरए के तहत आईएमएफ के साथ एक संवाद में शामिल था।

ब्रिक्स इंडिया चेयर के तहत, ब्रिक्स पेमेंट्स टास्क फोर्स (बीपीटीएफ) वार्षिक रिपोर्ट 2021 और सीआरए मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें विभाग ने योगदान दिया।

7. क्षेत्रीय क्षमता निर्माण व्यवस्था

(अ) एसएआरटीटीएसी

आईएमएफ के दक्षिण एशिया प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता केंद्र (एसएआरटीटीएसी) का उद्घाटन 13 फरवरी, 2017 को नई दिल्ली में किया गया था। एसएआरटीटीएसी आईएमएफ, सदस्य देशों और विकास भागीदारों के बीच एक सहयोगी उद्यम है³⁸। इसका रणनीतिक लक्ष्य अपने सदस्य देशों को व्यापक आर्थिक और वित्तीय नीतियों को डिजाइन और कार्यान्वित करने के लिए अपनी संस्थागत और मानवीय क्षमता को मजबूत करने में मदद करना है जो विकास को बढ़ावा देते हैं और सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के अनुरूप गरीबी को कम करते हैं। यह सदस्य देशों को व्यापक आर्थिक और वित्तीय क्षेत्रों की एक शृंखला पर तकनीकी सलाह प्रदान करता है और सदस्य देशों के अधिकारियों को प्रभावी व्यापक आर्थिक और वित्तीय नीतियों को तैयार करने के लिए अपने कौशल को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण देता है।

एसएआरटीटीएसी में विभाग की भूमिका

विभाग शीर्ष प्रबंधन का समर्थन करता है, जो एसएआरटीटीएसी की संचालन समिति में एक सदस्य के रूप में बैंक का प्रतिनिधित्व करता है, ब्रीफ और इनपुट तैयार करके। एसएआरटीटीएसी के शासन में संचालन समिति की सलाहकार की भूमिका है। संचालन समिति की प्रमुख भूमिका नीतियों और प्राथमिकताओं की स्थापना में योगदान करके और एक सांकेतिक वार्षिक कार्य योजना का समर्थन करके एसएआरटीटीएसी को रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करना है। संचालन समिति एसएआरटीटीएसी द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता के समन्वय पर व्यापक आर्थिक और

³⁸ एसएआरटीटीएसी के सदस्य देशों में बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका शामिल हैं।

वित्तीय विश्लेषण और नीति डिजाइन पर चर्चा करने के लिए एक मंच भी है, जिसमें राजकोषीय, मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र की नीतियां और व्यापक आर्थिक आंकड़े शामिल हैं।

(आ) दक्षिण पूर्व एशियाई केंद्रीय बैंक (एसईएसीईएन) अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (एसईएसीईएन केंद्र)

1982 में, एसईएसीईएन केंद्र को एक कानूनी इकाई के रूप में स्थापित किया गया था और तब से इसने केंद्रीय बैंकिंग ज्ञान में क्षमता निर्माण के लिए अपने शिक्षण कार्यक्रमों, अनुसंधान कार्य और नेटवर्किंग और सहयोग प्लेटफार्मों के माध्यम से एशिया-प्रशांत क्षेत्र में केंद्रीय बैंकों की सदस्यता प्रदान की है। एसईसीईएन केंद्र के कार्यक्रम प्रसाद वर्तमान में तीन केंद्रीय बैंकिंग ज्ञान क्षेत्रों में केंद्रित हैं: मैक्रोइकॉनॉमिक और मौद्रिक नीति प्रबंधन; वित्तीय स्थिरता पर्यवेक्षण और भुगतान और निपटान प्रणाली; और नेतृत्व और शासन।

एसईएसीईएन केंद्र में विभाग की भूमिका:

विभाग अपनी क्षमता निर्माण अभ्यासों पर एसईसीईएन केंद्र के साथ समन्वय के लिए बैंक के भीतर नोडल बिंदु है। इसके अलावा, एसईसीईएन केंद्र के लिए प्रशासनिक निर्णय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी) और कार्यकारी समिति (एक्सको) द्वारा लिए जाते हैं, जिसमें बैंक का शीर्ष प्रबंधन भाग लेता है। विभाग इन बैठकों में शीर्ष प्रबंधन के हस्तक्षेप के लिए संक्षिप्त विवरण और इनपुट तैयार करता है। इसके अतिरिक्त, बैंक 2024 के लिए एसईएसीईएन केंद्र का अध्यक्ष है और विभाग एसईएसीईएन केंद्र की बीओजी और ईएक्सीओ बैठकों के सफलतापूर्वक आयोजन में शामिल रहा है।

8. द्विपक्षीय समझौते

जैसे-जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का प्रभाव बढ़ रहा है, बहुपक्षीय वित्तीय कूटनीति के अलावा इसकी द्विपक्षीय वित्तीय समझौते से यह सुनिश्चित होगा कि वैश्विक आर्थिक बिरादरी द्वारा भारत की प्राथमिकताओं को अच्छी तरह से मान्यता दी जाए। विभाग अन्य केंद्रीय बैंकों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के प्राधिकरणों के साथ द्विपक्षीय समझौता करने के लिए बैंक में नोडल बिंदु रहा है, जिसका उद्देश्य विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर देश की स्थिति को समझने के साथ-साथ अन्य प्राधिकरणों के साथ क्षमता निर्माण उपायों का आदान-प्रदान करना है। इस कार्य क्षेत्र के तहत, विभाग भारत सरकार को अन्य संप्रभुओं के साथ अपनी द्विपक्षीय चर्चाओं और वार्ताओं का समर्थन करने के लिए मुद्दा-आधारित इनपुट भी प्रदान करता है। विभाग प्रासंगिकता के सामान्य मुद्दों पर अन्य केंद्रीय बैंकों के साथ बैंक के समझौता ज्ञापन (एमओयू) के निर्माण का भी समर्थन करता है। द्विपक्षीय संबंधों के कुछ विशिष्ट माध्यम, जिनमें विभाग योगदान देता है, इस प्रकार हैं:

भारत-अमरीका आर्थिक एवं वित्तीय भागीदारी (ईएफपी) और भारत-यूके आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता (ईएफडी) विभाग, वित्त मंत्रालय के सहयोग से ईएफपी और ईएफडी की कार्यसूची तैयार करने में लगा हुआ है, जो इन द्विपक्षीय मंचों से भारत की अपेक्षाओं को उपयुक्त रूप से परिलक्षित करता है। ये मंत्रिस्तरीय द्विपक्षीय मंच हैं जिनमें बैंक का शीर्ष प्रबंधन भाग लेता है, और विभाग बैंक के शीर्ष प्रबंधन के लिए ब्रीफ और इनपुट का मसौदा तैयार करके सहायता प्रदान करता है। विभाग, बैंक के डोमेन विभागों के सहयोग से, संयुक्त वक्तव्यों के प्रारूपण के कई दौरों में भी शामिल है, जो इन बैठकों के परिणाम दस्तावेज हैं।

संयुक्त तकनीकी समन्वय समिति (जेटीसीसी): विभाग बैंक और नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी) के बीच संयुक्त तकनीकी समन्वय

समिति (जेटीसीसी) की बैठकों का आयोजन करता है, जो द्विपक्षीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दोनों पक्षों के कार्यपालक निदेशकों (ईडी) की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति है। विभाग जेटीसीसी के सचिवालय के रूप में कार्य करता है और इस भूमिका में, चर्चा में उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए बैंक के डोमेन विभागों के साथ समन्वय करता है। जेटीसीसी के तहत, विभाग *एनआरबी अधिकारियों के लिए* प्रशिक्षण कार्यक्रम, अवलोकन दौरे आदि आयोजित करता है।

और बैंक और एनआरबी के बीच सहयोगात्मक अध्ययन का समन्वय करता है। जेटीसीसी के तहत, विभाग ने बैंक और एनआरबी के बीच मानव संसाधन सहयोग पर समझौते की शर्तों (टीओई) के निर्माण का संचालन किया है, जिस पर 23 अप्रैल, 2024 को हस्ताक्षर किए गए थे। टीओई में अन्य बातों के साथ-साथ अल्पकालिक सेकेंडमेंट और प्रशिक्षण पर अधिकारियों का आदान-प्रदान शामिल है। दोनों केंद्रीय बैंक तीन महीने से छह महीने तक की अवधि के लिए पारस्परिक रूप से सहमत विषयों पर परियोजनाओं पर काम करने के लिए पारस्परिक रूप से अधिकारियों का आदान-प्रदान करने पर सहमत हुए हैं।

बैंक ऑफ जापान (बीओजे) के साथ वरिष्ठ स्तरीय वार्ता (एसएलडी): 4 नवंबर, 2019 को बैंक ऑफ जापान (बीओजे) और बैंक द्वारा हस्ताक्षरित समझौते की शर्तों (टीओई) के तहत, एक वार्षिक वरिष्ठ स्तरीय संवाद (एसएलडी), बैंक और बीओजे द्वारा बारी-बारी से आयोजित किया जाता है जिसका उद्देश्य संबंधों को गहरा करना और केंद्रीय बैंकिंग के क्षेत्र में सूचना और सहयोग के आदान-प्रदान को मजबूत करना है। इसके अलावा, मैक्रो-आर्थिक, वर्तमान और विकसित वित्तीय बाजार स्थितियों और आपसी हित के सामयिक मुद्दों पर विचार-विमर्श शामिल हैं।

द्विपक्षीय व्यापार वार्ता: विभाग विभिन्न द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं, जैसे भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए), भारत-यूके एफटीए वार्ता आदि में चर्चा के लिए मुद्दों पर बैंक की टिप्पणियां प्रदान करके भारत सरकार का समर्थन करता है। समझौता ज्ञापन/समझौते की शर्तें: ज्ञान साझा करने और क्षमता निर्माण के मुद्दों पर, विभाग ने 2022 में बैंक इंडोनेशिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और 2024 में, किर्गिज़ गणराज्य के नेशनल बैंक के साथ समझौते की शर्तों (टीओई) पर हस्ताक्षर किए गए।

द्विपक्षीय समझौते के इन विशिष्ट चैनलों के अलावा, विभाग अनुरोध पर अन्य केंद्रीय बैंक अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी आयोजित करता है। इनमें बैंक के शीर्ष प्रबंधन और अन्य केंद्रीय बैंकों के शीर्ष स्तर के अधिकारियों के बीच बैठकें और साथ ही अन्य केंद्रीय बैंकों और बैंक के डोमेन विभागों के वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के बीच बैठकें शामिल हैं। ये द्विपक्षीय जुड़ाव विभिन्न बकाया मुद्दों पर अन्य केंद्रीय बैंकों के रुख की बेहतर समझ सुनिश्चित करते हैं और बैंक के अधिकारियों को अन्य केंद्रीय बैंकों में अपने समकक्षों के साथ विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर प्रदान करते हैं।

विभिन्न देशों की प्रोफाइल: विभाग बैंक के शीर्ष प्रबंधन की द्विपक्षीय चर्चाओं में उपयोग के लिए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के लिए देश प्रोफाइल तैयार और अद्यतन करता है।

क्षमता निर्माण प्रयास: सार्क जैसे बहुपक्षीय मंचों के अंतर्गत क्षमता निर्माण प्रयासों के अलावा, विभाग केंद्रीय बैंकिंग की सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने के उद्देश्य से विदेशी और घरेलू विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए अध्ययन दौरे और विदेशी केंद्रीय बैंकों और विदेशी वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के लिए एक्सपोजर दौरे/ अटैचमेंट/ तकनीकी सहायता भी आयोजित करता है/ उपलब्ध कराता है।



रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय

359-360, अण्णा सालै, तेनांपेट, चेन्नै - 600 018. दूरभाष : +91 44 2430 2700